Important Monthly Current Affairs Capsule in Hindi – August 2023

Monthly Current Affairs-August

S. No.	Contents	Page No
1.	महत्वपूर्ण दिन और विषय	02
2.	बैंकिंग और अर्थव्यवस्था	03
3.	व्यापार	68
4.	नेशनल करेंट अफेयर्स	77
5.	इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स	143
6.	स्टेट करेंट अफेयर्स	158
7.	रैंक और सूचकांक	185
8.	समझौता और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर	190
9.	राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार	203
10.	नियुक्तियां	210
11.	डिफेन्स	223
12.	स्पोर्ट्स	234
13.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	257
14.	अधिग्रहण और विलय	270
15.	शोक सन्देश	273

Click Here to Subscribe Our Yearly Mock Test Package

महत्वपूर्ण दिन और विषय

तारीख	दिन	थीम
1 अगस्त	वर्ल्ड वाइड वेब	
1-7 अगस्त	विश्व स्तनपान सप्ताह	एनेब्लिंग ब्रेस्टफीडिंग: मेकिंग ए डिफरेंस फॉर वर्किंग पेरेंट्स
6 अगस्त	हिरोशिमा दिवस	
7 अगस्त	राष्ट्रीय हथकरघा दिवस	
8 अगस्त	भारत छोड़ो आंदोलन	
9 अगस्त	नागासाकी दिवस	
9 अगस्त	विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस	इंडिजेनस युथ एज एजेंट्स ऑफ़ चेंज फॉर सेल्फ-डेटर्मिनेशन
10 अगस्त	विश्व जैव ईंधन दिवस	
12 अगस्त	विश्व हाथी दिवस	
12 अगस्त	अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस	ग्रीन स्किल्स फॉर युथ: टुवर्ड्स ए सस्टेनेबल वर्ल्ड
13 अगस्त	अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी दिवस	स्पोर्ट्स में लेफ्ट हैंडर्स
13 अगस्त	विश्व अंग दान दिवस	"स्टेप अप टू वालंटियर; नीड मोर ऑर्गन डोनर्स टू फील द लकुनै"
15 अगस्त	भारत में स्वतंत्रता दिवस	
19 अगस्त	विश्व फोटोग्राफी दिवस	
20 अगस्त	सद्भावना दिवस	
20 अगस्त	विश्व मच्छर दिवस	
23 अगस्त	दास व्यापार और उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस	
26 अगस्त	महिला समानता दिवस	#EmbraceEquity
29 अगस्त	राष्ट्रीय खेल दिवस	
30 अगस्त	लघु उद्योग दिवस	

Click Here to Subscribe Our Yearly Mock Test Package

बैंकिंग और अर्थव्यवस्था

भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने राजस्थान में शहरी सेवाओं को बढ़ाने के लिए 200 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए

भारत सरकार (GoI) और एशियाई विकास बैंक (ADB) ने जल आपूर्ति और स्वच्छता प्रणालियों का विस्तार करने और चयनित शहरों में शहरी लचीलेपन और विरासत को बढ़ाने के लिए चल रहे राजस्थान माध्यमिक शहर विकास क्षेत्र परियोजना के लिए अतिरिक्त वित्तपोषण के रूप में 200 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए।

ऋण समझौते पर आर्थिक मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव वुमलुनमांग वुअलनाम और एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंडिया रेजिडेंट मिशन के कंट्री डायरेक्टर ताकेओ कोनिशी के बीच हस्ताक्षर किए गए।

परियोजना के बारे में:

यह परियोजना बुनियादी शहरी सेवाओं के विस्तार के लिए विभिन्न नवीन और जलवायु-लचीले समाधानों को शामिल करेगी और निजी क्षेत्र की भागीदारी को गहरा करने के लिए राज्य के जल और स्वच्छता क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी को संचालित करने के अलावा विरासत संरचनाओं के पुनर्वास के लिए प्रकृति-आधारित समाधानों को शामिल करेगी।

इससे सभी भूजल स्रोतों को सतही जल में परिवर्तित करके, और 1400 किलोमीटर नई जल आपूर्ति पाइपलाइन स्थापित करके और 77,000 घरों में पानी के मीटर के साथ कनेक्शन प्रदान करके कम से कम 7 कस्बों में जल आपूर्ति प्रणालियों में सुधार किया जाएगा।

कम से कम 580 किमी लंबे सीवरों का पुनर्वास करके, मल कीचड़ और सेप्टेज को संसाधित करने के लिए सह-उपचार इकाइयों के साथ सात सीवेज उपचार संयंत्रों का निर्माण करके और कम से कम 54,000 घरों को सीवेज सिस्टम से जोड़कर स्वच्छता प्रणालियों में सुधार के लिए कम से कम 8 शहरों को कवर किया जाएगा।

साथ ही, रहने के माहौल को बेहतर बनाने और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कम से कम 20 विरासत या विरासत जैसी संरचनाओं का पुनर्वास किया जाएगा।

नवीनतम समाचार:

जून 2023 में, एशियाई विकास बैंक (ADB) ने भारत में बिहार राज्य में परिवहन कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए लगभग 265 किलोमीटर राज्य राजमार्गों को चौड़ा करने और उन्नत करने के लिए 295 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी।

ADB के बारे में:

स्थापना: 19 दिसंबर 1966
मुख्यालय: मांडलुयॉन्ग, मेट्रो मनीला, फिलिपींस
अध्यक्ष: मासात्सुगु असकावा

राजस्थान के बारे में:

राज्यपाल: कलराज मिश्र
मुख्यमंत्री: अशोक गेहलोत
पूंजी: जयपुर
राष्ट्रीय उद्यान: केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान
वन्यजीव अभ्यारण्य: बस्सी वन्यजीव अभयारण्य, कुम्भलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य

सेबी ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को कानूनी इकाई पहचानकर्ता (LEI) कोड का खुलासा करने का आदेश दिया है

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सभी गैर-व्यक्तिगत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) के लिए कानूनी इकाई पहचानकर्ता (LEI) विवरण जमा करना अनिवार्य कर दिया है।

वर्तमान में, एफपीआई को कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म ("CAF") में अपने LEI विवरण प्रदान करने की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग स्वैच्छिक आधार पर FPI के पंजीकरण, KYC और खाता खोलने के लिए किया जाता है।

अब सभी गैर-व्यक्तिगत FPI के लिए LEI विवरण प्रदान करने की आवश्यकता को अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया है।

LEI क्या है?

LEI, वित्तीय लेनदेन में भाग लेने वाली कानूनी संस्थाओं के लिए एक अद्वितीय वैश्विक पहचानकर्ता, एक वैश्विक संदर्भ डेटा प्रणाली बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो किसी भी क्षेत्राधिकार में प्रत्येक कानूनी इकाई को विशिष्ट रूप से पहचानता है, जो वित्तीय लेनदेन का पक्ष है।

यह एक अद्वितीय 20-अक्षर वाला कोड है जो वित्तीय लेनदेन में शामिल विशिष्ट संस्थाओं की पहचान करता है।

मुख्य विचार:

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के निर्देशों में 25 करोड़ रुपये से अधिक के कुल एक्सपोजर वाले गैर-व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को LEI कोड प्राप्त करना अनिवार्य है।

सभी मौजूदा FPI (नवीनीकरण के लिए आवेदन करने वालों सहित) जिन्होंने पहले से ही अपने DDP को अपनी LEI प्रदान नहीं की है, उन्हें इस परिपत्र के जारी होने की तारीख से 180 दिनों के भीतर ऐसा करना होगा, ऐसा न करने पर उनके खाते को LEI प्रदान किए जाने तक आगे की खरीदारी के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा।

नवीनतम समाचार:

जुलाई, 2023 में पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) कॉर्पोरेट ऋण बाजार विकास कोष (CDMDF) के लिए एक विस्तृत रूपरेखा लेकर आया।

सेबी के बारे में:

स्थापना: 12 अप्रैल 1988 को एक कार्यकारी निकाय के रूप में और सेबी अधिनियम, 1992 के माध्यम से 30 जनवरी 1992 को वैधानिक शक्तियां दी गईं।

मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र

अध्यक्ष: माधबी पुरी बुच (सेबी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला)

SEBI भारत में प्रतिभूति और कमोडिटी बाजारों के लिए नियामक निकाय है जो वित्त मंत्रालय (MoF), भारत सरकार के स्वामित्व के तहत है।

RBI का डिजिटल भुगतान सूचकांक सितंबर में 377.46 से बढ़कर मार्च में 395.57 पर पहुंच गया

भारतीय रिजर्व बैंक का डिजिटल भुगतान सूचकांक (RBI-DPI), जो देश भर में भुगतान के डिजिटलीकरण की सीमा को मापता है, सितंबर 2022 में 377.46 और मार्च 2022 में 349.30 से बढ़कर मार्च 2023 में 395.57 हो गया।

ऑनलाइन लेनदेन को अपनाने को मापने वाले RBI के सूचकांक के अनुसार, देश भर में डिजिटल भुगतान में मार्च 2023 तक एक वर्ष में 13.24% की वृद्धि दर्ज की गई।

"इस अवधि के दौरान देश भर में भुगतान बुनियादी ढांचे और भुगतान प्रदर्शन में महत्वपूर्ण वृद्धि के कारण RBI-DPI सूचकांक सभी मापदंडों में बढ़ा है।

RBI-DPI के बारे में:

RBI ने भुगतान के डिजिटलीकरण पर पकड़ बनाने के लिए जनवरी 2021 में मार्च 2018 को आधार मानकर समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक (RBI-DPI) पेश किया।
तब से सूचकांक लगातार बढ़ रहा है, सितंबर 2021 में 300 अंक का आंकड़ा पार कर गया।
सूचकांक में 5 व्यापक पैरामीटर शामिल हैं जो विभिन्न अवधियों में देश में डिजिटल भुगतान की गहराई और पैठ को मापने में सक्षम बनाते हैं।
ये पैरामीटर हैं
भुगतान सक्षमकर्ता (वजन 25%)
भुगतान अवसंरचना मांग-पक्ष कारक (10%)
भुगतान अवसंरचना आपूर्ति-पक्ष कारक (15%)
भुगतान प्रदर्शन (45%)
उपभोक्ता केन्द्रितता (5%)।

मुख्य विचार:

आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, वैश्विक औसत 64% की तुलना में भारत में जनता के बीच फिनटेक अपनाने की दर 87% सबसे अधिक है।
इसके अलावा, भारत ने डिजिटल भुगतान में संयुक्त राज्य अमेरिका (US) और चीन के बाद तीसरा स्थान हासिल किया है।
वित्त वर्ष 2019 और वित्त वर्ष 22 के बीच UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) लेनदेन में मूल्य के संदर्भ में औसतन 121% और मात्रा के संदर्भ में 115% की वृद्धि हुई है।
मई 2023 में, UPI लेनदेन प्रति माह 900 करोड़ के बेंचमार्क को पार कर गया था, जिसमें 14.89 लाख करोड़ रुपये के 941 करोड़ लेनदेन के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर थे।

RBI के बारे में:

स्थापना: 1 अप्रैल 1935
मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र, भारत
राज्यपाल: शक्तिकांत दास
उप राज्यपाल: स्वामीनाथन जानकीरमन, माइकल पात्रा,एम. राजेश्वर राव, टी रबी शंकर

अंतर्राष्ट्रीय बैंक हस्तांतरण पर 50% की बचत करने के लिए रेज़रपे ने भारतीय निर्यातकों के लिए मनीसेवर एक्सपोर्ट खाता लॉन्च किया

व्यवसायों के लिए भुगतान और बैंकिंग प्लेटफ़ॉर्म रेज़रपे ने विशेष रूप से छोटे और मध्यम आकार के निर्यातकों के लिए एक मनीसेवर निर्यात खाता लॉन्च किया।
इस उत्पाद के साथ, भारतीय निर्यातक अब अपनी पसंद के किसी भी देश में एक स्मार्ट खाता खोलेंगे और रेज़रपे प्लेटफॉर्म पर बैंक हस्तांतरण के माध्यम से स्थानीय स्तर पर भुगतान प्राप्त करेंगे।
यह भारतीय निर्यातकों के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंक हस्तांतरण पर 50% बचत की पेशकश करने वाला भारत का पहला स्मार्ट खाता होगा।

उद्देश्य:

उच्च स्थानांतरण लागत, चार्जबैक और भुगतान विफलताओं के बोझ को कम करने के लिए, इसे निर्यातकों के लिए एक मूल्यवान संपत्ति बनाना।

यह सुविधा निर्यातकों को उच्च स्थानांतरण लागत, चार्जबैक और भुगतान विफलताओं से बचाने के लिए किसी भी देश (160 से अधिक देशों में से) में खाता खोलने और रेज़रपे प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से स्थानीय स्तर पर भुगतान प्राप्त करने की अनुमति देती है।

मुख्य विचार:

बिना किसी अतिरिक्त कागजी कार्रवाई के रेजरपे डैशबोर्ड के माध्यम से खाता खोला और एक्सेस किया जा सकता है।
खाता सिंगल-क्लिक इलेक्ट्रॉनिक फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस स्टेटमेंट (FIRS) के साथ आता है, जिसे सीधे रेज़रपे डैशबोर्ड से एक्सेस किया जा सकता है।
विशेष रूप से निर्यातकों के लिए बनाया गया यह खाता व्यापारियों को ACH, SWIFT, SEPA, BACS और Fedwire जैसे वायर ट्रांसफर के माध्यम से आसानी से अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्राप्त करने की अनुमति देता है।

रूस का सबसे बड़ा ऋणदाता सबैंक बेंगलुरु, कर्नाटक में आईटी केंद्र स्थापित करेगा

रूस के सबसे बड़े ऋणदाता सबैंक की भारत में शाखा को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से बेंगलुरु, कर्नाटक में एक सूचना प्रौद्योगिकी (IT) इकाई स्थापित करने की अनुमति मिल गई है, जहां वह 200 आईटी विशेषज्ञों को रोजगार देने की योजना बना रही है।
नए आईटी कार्यालय में सबैंक का इन-हाउस डेटा प्रोसेसिंग सेंटर होगा।
यह भारतीय शाखा की तकनीकी जरूरतों को भी संभालेगा।
बेंगलुरु भारत का तीसरा सबसे बड़ा शहर और देश का अग्रणी वैज्ञानिक और औद्योगिक केंद्र है, जो अन्य चीजों के अलावा, एयरोस्पेस, इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों और आईटी उत्पादों के विकास में विशेषज्ञता रखता है।
जबकि सबैंक की भारतीय शाखा 2010 से नई दिल्ली में सक्रिय है और वित्तीय सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है, बेंगलुरु कार्यालय पूरी तरह से सूचना प्रौद्योगिकी विकसित करने पर केंद्रित होगा।

सबैंक के बारे में:

मुख्यालय: मास्को, रूस
सबैंक एक रूसी बहुमत राज्य के स्वामित्व वाली बैंकिंग और वित्तीय सेवा कंपनी है।

IIM अहमदाबाद के सेंटर फॉर इनोवेशन, इनक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप इनक्यूबेटर में सिडबी एक्सेलेरेटर फंड स्थापित किया जाएगा

देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए प्रमुख वित्तीय संस्थान, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद (IIM-A) के स्टार्टअप इनक्यूबेटर सेंटर फॉर इनोवेशन, इनक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप (CIIE) के साथ 20 करोड़ रुपये के प्रारंभिक कोष के साथ इनक्यूबेटर में सिडबी एक्सेलेरेटर फंड स्थापित करने के लिए अपनी साझेदारी की घोषणा की।

उद्देश्य:

बीज पूंजी तक पहुंच की सुविधा प्रदान करके डीप टेक और विज्ञान आधारित नवाचार को बढ़ावा देना।
यह कार्यक्रम भारत के 2047 के लक्ष्यों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ उच्च गुणवत्ता/उच्च प्रवेश बाधा उत्पादों/सेवाओं में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने के लिए महत्वपूर्ण मेधावी विचारों और प्रौद्योगिकियों के साथ स्टार्टअप का समर्थन करने पर केंद्रित है।

Click Here to Subscribe Our Yearly Mock Test Package

नवीनतम समाचार:

जुलाई 2023 में, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने दो किस्तों में 700 करोड़ रुपये के कुल लक्ष्य कोष के साथ विवृति एसेट मैनेजमेंट द्वारा प्रबंधित प्रॉमिसिंग लेंडर्स फंड (PLF) में एक एंकर निवेशक के रूप में भाग लिया।

जून 2023 में SIDBI ने ग्लोबल एलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप (GAME) के सहयोग से NBFC ग्रोथ एक्सेलेरेटर प्रोग्राम भी लॉन्च किया, जो छोटे NBFC को संभालने के लिए एक बड़े पैमाने पर उद्यमिता सक्षम मंच है, जिनका कम से कम 60% जोखिम MSME में है।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के बारे में:

स्थापना: 2 अप्रैल 1990

मुख्यालय: लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत

अध्यक्ष और MD: शिवसुब्रमण्यम रामन

सिडबी भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम वित्त कंपनियों के समग्र लाइसेंसिंग और विनियमन के लिए शीर्ष नियामक निकाय है।

यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में है।

IRDAI की राज्य बीमा योजना के तहत मैक्स लाइफ को उत्तर प्रदेश के लिए प्रमुख बीमाकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया

मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (मैक्स लाइफ) भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य (यूपी) के लिए "प्रमुख बीमाकर्ता" के रूप में नियुक्त किया गया है।

राज्य बीमा योजना के तहत, IRDAI ने वित्तीय जागरूकता बढ़ाने और बीमा समावेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक बीमाकर्ता को दो राज्यों को नियुक्त करके बीमाकर्ताओं के साथ एक सहयोगी मंच शुरू किया है।

मैक्स लाइफ को अरुणाचल प्रदेश के लिए प्रमुख बीमाकर्ता के रूप में भी नियुक्त किया गया है और इसका लक्ष्य चरणबद्ध तरीके से राज्य के भीतर अपनी उपस्थिति का विस्तार करना है।

मुख्य विचार:

इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए, मैक्स लाइफ का लक्ष्य पूरे उत्तर प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से जागरूकता पैदा करना, पहुंच बढ़ाना और किफायती बीमा कवरेज बढ़ाना है।

मैक्स लाइफ ने पहले चरण में चंदौली और वाराणसी में डिजिटल बीमा जागरूकता गतिविधियाँ शुरू की हैं, जो 1,45,000 से अधिक व्यक्तियों तक पहुँची हैं।

यह अगले 6 महीनों में बलरामपुर, बहराईच, चित्रकूट, फ़तेहपुर, कौशांबी, सिद्धार्थनगर और श्रावस्ती के अन्य जिलों में भी इसी तरह की पहल शुरू करने की योजना बना रहा है।

ये जिले भारत सरकार के 'आकांक्षी जिला कार्यक्रम' का भी हिस्सा हैं जिसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन और कौशल विकास को बढ़ाना है।

ग्रामीण भारत में जीवन बीमा को अपनाने और जागरूकता बढ़ाने के लिए, मैक्स लाइफ ने हाल ही में 113 गांवों में इंडिया प्रोटेक्शन कोशिएंट (IPQ)* ग्रामीण संस्करण नामक एक सर्वेक्षण भी आयोजित किया, जो कि KANTAR के सहयोग से आयोजित किया गया, जो शहरी-ग्रामीण वित्तीय सुरक्षा विभाजन पर प्रकाश डालता है।

निष्कर्षों से पता चलता है कि शहरी भारत के 43 अंक की तुलना में ग्रामीण भारत में सुरक्षा भागफल पैमाने पर 12 अंकों का काफी कम स्कोर है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के अवसर और आवश्यकता को दर्शाता है।

नवीनतम समाचार:

जुलाई 2023 में, लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस, भारत में अग्रणी गैर-जीवन बीमा कंपनियों में से एक, को भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) द्वारा दिल्ली के लिए "लीड बीमाकर्ता" के रूप में नियुक्त किया गया था।

जुलाई 2023 में, गैर-जीवन बीमाकर्ता चोलामंडलम एमएस इंश्योरेंस को भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) द्वारा पश्चिम बंगाल के लिए प्रमुख बीमाकर्ता नियुक्त किया गया था।

मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बारे में:

स्थापित: 2001

मुख्यालय: नई दिल्ली, दिल्ली, भारत

MD और CEO: श्री प्रशांत त्रिपाठी

यह मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और एक्सिस बैंक लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम है।

IRDAI के बारे में:

स्थापना: 1999

मुख्यालय: हैदराबाद, तेलंगाना

अध्यक्ष: देबाशीष पांडा

IRDAI वित्त मंत्रालय (MoF), भारत सरकार (GoI) के अधिकार क्षेत्र के तहत एक वैधानिक निकाय है और इसे भारत में बीमा और पुनर्बीमा उद्योगों को विनियमित और लाइसेंस देने का काम सौंपा गया है।

फिनो पेमेंट्स बैंक लघु वित्त बैंक लाइसेंस के लिए आवेदन करेगा

फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने लघु वित्त बैंक (SFB) में परिवर्तन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

हालाँकि, परिवर्तन आवश्यक अनुमोदन के अधीन है।

पेमेंट्स बैंक को समूह कॉर्पोरेट पुनर्गठन प्रस्ताव के संबंध में अपनी होल्डिंग कंपनी फिनो पेटेक से एक पत्र भी मिला है।

इसके बाद बोर्ड ने समूह कॉर्पोरेट पुनर्गठन की संभावना तलाशने के लिए एक समिति का गठन किया है।

इसके साथ, फिनो लघु वित्त बैंक (SFB) बनने की दिशा में आगे बढ़ने वाली पहली ऐसी इकाई बन गई है क्योंकि 2019 में भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान बैंकों को 5 साल के संचालन के बाद एसएफबी में रूपांतरण के लिए आवेदन करने की अनुमति दी थी।

अतिरिक्त जानकारी:

भुगतान बैंकों और लघु वित्त बैंकों के बीच अंतर यह है कि भुगतान बैंकों को केवल मांग जमा स्वीकार करने और रुपये तक रखने की अनुमति है। प्रति व्यक्ति 2 लाख, दूसरी ओर, छोटे वित्त बैंकों को सभी प्रकार की जमा स्वीकार करने की अनुमति है।

RBI के अनुसार, 6 पेमेंट बैंक और 12 छोटे वित्त बैंक हैं।

फिनो पेमेंट्स बैंक के बारे में:

परिचालन प्रारंभ किया गया; 2017

मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र, भारत

MD और CEO: ऋषि गुप्ता
फिनो पेमेंट्स बैंक फिनो पेटेक लिमिटेड (FPL) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।
यह वर्तमान में सबसे अधिक मुनाफा कमाने वाला भुगतान बैंक है।
FY24 की जून तिमाही में पेमेंट बैंक ने शुद्ध लाभ दर्ज किया₹18.7 करोड़, साल-दर-साल 85% अधिक।
हालाँकि, लाभ में क्रमिक रूप से 15% की गिरावट आई।
मुंबई स्थित बैंक ने कहा कि उसका राजस्व सालाना आधार पर 21% बढ़कर 348 करोड़ रुपये हो गया।

2021 और 2022 के बीच भारत में वित्तीय धोखाधड़ी 65% बढ़ी- वित्त मंत्रालय

वित्त मंत्रालय के अनुसार, ATM और अन्य धोखाधड़ी के मामलों में 2021 की तुलना में 2022 में 65% से अधिक की वृद्धि देखी गई है।
धोखाधड़ी में शामिल रकम लगभग दोगुनी हो गई है

मुख्य विचार:

नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के मुताबिक, साइबर धोखाधड़ी के कारण हर महीने औसतन 2000 ग्राहक प्रभावित होते हैं।
'साइबर सुरक्षा और साइबर/सफेदपोश अपराधों की बढ़ती घटनाओं' पर संसदीय समिति की रिपोर्ट हाल ही में इसके अध्यक्ष जयंत सिन्हा द्वारा संसद में पेश की गई थी।
समिति ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की तर्ज पर साइबर सुरक्षा पर केंद्रित एक केंद्रीकृत नियामक प्राधिकरण स्थापित करने की सिफारिश की।

इतिहास:

2021 में, एटीएम और अन्य धोखाधड़ी के लिए रिपोर्ट किए गए कुल धोखाधड़ी की संख्या लगभग 10.80 लाख थी और मूल्य ₹1,119 करोड़ था।
2021 में प्रत्येक 67,000 लेनदेन के लिए एक धोखाधड़ी की गई।
2022 में, एटीएम और अन्य धोखाधड़ी के लिए रिपोर्ट की गई कुल धोखाधड़ी की संख्या लगभग 17.80 लाख थी और मूल्य ₹2,113 करोड़ था।
2022 में प्रत्येक 64,000 लेनदेन के लिए एक धोखाधड़ी की गई।
समिति ने बैंकिंग क्षेत्र में धोखाधड़ी की रोकथाम और पता लगाने में सुधार के लिए एक केंद्रीय नकारात्मक रजिस्ट्री की स्थापना की भी सिफारिश की।
समिति ने सिफारिश की कि आरबीआई को एक स्वचालित मुआवजा प्रणाली तैयार करनी चाहिए।

वित्त मंत्रालय के बारे में:

कैबिनेट मंत्री: निर्मला सीतारमण
राज्य मंत्री: भागवत कराड, पंकज चौधरी

पेटीएम ने भारत की छोटी दुकानों की मदद के लिए 2 नए इनोवेटिव डिवाइस - पेटीएम पॉकेट साउंडबॉक्स और पेटीएम म्यूजिक साउंड बॉक्स लॉन्च किए

भारत की प्रमुख भुगतान और वित्तीय सेवा कंपनी पेटीएम की मूल कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड (OCL) ने गैर-प्रचार के दौरान व्यापारियों के लिए बेहतर भुगतान अनुभव प्रदान करने के लिए दो भुगतान उपकरण - पेटीएम पॉकेट साउंडबॉक्स और पेटीएम म्यूजिक साउंड बॉक्स लॉन्च किए।

पेटीएम पॉकेट साउंडबॉक्स के बारे में:

पेटीएम पॉकेट साउंडबॉक्स अपनी तरह का पहला मेड इन इंडिया पोर्टेबल डिवाइस है, जो डेबिट कार्ड जितना छोटा है, जो चलते-फिरते व्यापारियों की जेब में आसानी से फिट हो जाता है।

4जी कनेक्टिविटी के साथ, यह डिवाइस व्यापारियों को तत्काल ऑडियो भुगतान अलर्ट के साथ सशक्त बनाता है, जिससे लेनदेन अधिक कुशल हो जाता है।

यह कम रोशनी की स्थिति में भी निर्बाध उपयोग के लिए 5 दिन की बैटरी लाइफ और एक अंतर्निहित टॉर्च प्रदान करता है।

यह विभिन्न मोबाइल व्यापारियों, जैसे कैब और ऑटो चालक, इलेक्ट्रीशियन, डिलीवरी एजेंट, पार्किंग शुल्क लेने वाले और गाड़ी विक्रेताओं को सेवा प्रदान करता है।

पेटीएम म्यूजिक साउंडबॉक्स के बारे में:

पेटीएम ने पेटीएम म्यूजिक साउंडबॉक्स पेश किया है, जो एक अनूठा उपकरण है जो व्यापारियों को ब्लूटूथ के माध्यम से अपने मोबाइल फोन से संगीत का आनंद लेते हुए भुगतान लेनदेन का प्रबंधन करने में सक्षम बनाता है।

यह एक मजबूत 4W स्पीकर, 4G कनेक्टिविटी और प्रभावशाली 10 दिन की बैटरी लाइफ से लैस है।

इसका अनोखा वॉयस ओवरले फ़ंक्शन यह सुनिश्चित करता है कि व्यापारी पृष्ठभूमि में संगीत बजने पर भी भुगतान सूचनाएं प्राप्त कर सकें।

पेटीएम के बारे में:

स्थापित: अगस्त 2010

मुख्यालय: नोएडा, उत्तर प्रदेश, भारत

संस्थापक और CEO: विजय शेखर शर्मा

जून 2023 में बैंकों का गैर-खाद्य ऋण 16.3% बढ़ा - RBI डेटा

बैंक क्रेडिट सेवा, खुदरा और कृषि और संबद्ध गतिविधियों जैसे क्षेत्रों से ऋण की मजबूत मांग के कारण जून 2023 में साल-दर-साल (वर्ष-दर-वर्ष) 16.3% की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई, जबकि एक साल पहले यह 15% थी।

मुख्य विचार:

ऋण की क्षेत्रीय तैनाती पर RBI के आंकड़ों के अनुसार, सेवा क्षेत्र में ऋण वृद्धि

जून 2023 में एक साल पहले के 12.8% से बढ़कर 26.7% (वर्ष-दर-वर्ष) हो गया, जिसका मुख्य कारण 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC)' और 'व्यापार' के लिए बेहतर ऋण उठाव है।

जून 2023 में व्यक्तिगत ऋण में 20.9% (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि एक साल पहले यह 18.1% थी, जिसे मुख्य रूप से 'आवास' और 'वाहन' ऋण द्वारा समर्थित किया गया।

कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण जून 2022 में 12.9% से बढ़कर जून 2023 में 19.7% (वर्ष-दर-वर्ष) हो गया।

जून 2022 में 9.5% की तुलना में जून 2023 में उद्योग क्षेत्र को ऋण घटकर 8.1% (वर्ष-दर-वर्ष) हो गया।

आकार के लिहाज से, बड़े उद्योगों को ऋण 6.4% (एक साल पहले 3.2%) बढ़ गया।

मध्यम उद्योगों के साथ-साथ सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए ऋण में वृद्धि घटकर क्रमशः 13.2% (47.8%) और 13% (29.2%) हो गई।

जून 2023 के महीने के लिए बैंक ऋण की क्षेत्रीय तैनाती पर डेटा 40 चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCB) से एकत्र किया गया है, जो सभी SCB द्वारा तैनात कुल गैर-खाद्य ऋण का लगभग 93% है।

RBI के बारे में:

स्थापना: 1 अप्रैल 1935
मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र, भारत
राज्यपाल: शक्तिकांत दास
उप राज्यपाल: स्वामीनाथन जानकीरमन, माइकल पात्रा, एम. राजेश्वर राव, टी रबी शंकर

SBI ने 7.54% की कूपन दर पर 15 साल के इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपये जुटाए

भारत के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने 7.54% की कूपन दर पर 15 साल के बुनियादी ढांचा बांड जारी करने के बाद 10,000 करोड़ रुपये जुटाए हैं।
इस आय को महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण और किफायती आवास खंड का समर्थन करने के लिए दीर्घकालिक संसाधनों को बढ़ाने के लिए निर्देशित किया जाएगा।
चालू वित्त वर्ष में किसी भी बैंक द्वारा इस अवधि का दीर्घकालिक बांड जारी करना यह पहला है।
बैंक ने मानक सरकारी बांडों द्वारा दी गई ब्याज दर से थोड़ी बेहतर ब्याज दर पर बांड की पेशकश की।
जनवरी 2023 में, SBI ने रुपये के बुनियादी ढांचे बांड का एक और सेट जुटाया। मानक सरकारी बांड दरों पर 17 BPS के अंतर पर 9,718 करोड़ रुपये।
बुनियादी ढांचा बांड का प्राथमिक उद्देश्य बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए दीर्घकालिक पूंजी जुटाना है, जिसमें पर्याप्त निवेश की आवश्यकता होती है।

नवीनतम समाचार:

जुलाई 2023 में, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने 8.1% के कूपन पर अतिरिक्त टियर I बांड (एटी1) या स्थायी बांड के माध्यम से 3,101 करोड़ रुपये की पूंजी जुटाई।

SBI के बारे में:

स्थापना: 1 जुलाई 1955
मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र, भारत
अध्यक्ष: दिनेश कुमार खरा
CFO: कामेश्वर राव कोदावंती

भारत की प्रति व्यक्ति महिला जमा पिछले 5 वर्षों में 4,618 रुपये बढ़कर 42,503 रुपये हो गई

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के आर्थिक अनुसंधान विभाग (ERD) के अनुसार, प्रति व्यक्ति महिला जमा पिछले 5 वर्षों में 4,618 रुपये बढ़कर वित्त वर्ष 2019 में 37,885 रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में 42,503 रुपये हो गई।

मुख्य विचार:

ERD की 'इकोरैप' रिपोर्ट के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में सबसे अधिक 9,758 रुपये की वृद्धि दर्ज की गई है, जहां प्रति व्यक्ति महिला जमा 51,980 रुपये से बढ़कर 61,738 रुपये हो गई है।
महानगरीय क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति महिला जमा राशि वित्त वर्ष 2023 में सबसे अधिक 83,434 रुपये रही, जो वित्त वर्ष 2019 के 84,320 रुपये की तुलना में 886 रुपये अधिक है।

अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति महिला जमा राशि क्रमशः 29,563 रुपये (वित्त वर्ष 2019 में 25,942 रुपये) और 18,563 रुपये (15,976 रुपये) थी।

RBI की नवीनतम रिपोर्ट 'अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ जमा - मार्च 2023 (बीएसआर 2)' के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCB) की कुल जमा में 10.2% की वृद्धि हुई, 17.6 लाख करोड़ रुपये की वृद्धिशील जमा हुई।

व्यक्तियों को घरेलू ऋण में महिला उधारकर्ताओं की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2013 में बकाया ऋण में 22.9% तक बढ़ गई, जो वित्त वर्ष 2015 में 18.3% थी।

इसके अलावा, व्यक्तियों को घरेलू ऋण में महिला उधारकर्ताओं की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2013 में वृद्धिशील ऋण में 24.9% तक बढ़ गई, जो वित्त वर्ष 2015 में 8.9% थी।

ईआरडी ने आकलन किया कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) महिला जमा हिस्सेदारी में वृद्धि में प्रमुख योगदानकर्ता बने हुए हैं।

बैंक समूहवार वितरण:

वित्त वर्ष 2019 और वित्त वर्ष 23 के दौरान RRB में वृद्धिशील जमा में महिला जमा की हिस्सेदारी 50% थी।

सभी बैंक समूहों में, कुल जमा में महिला जमा की हिस्सेदारी RRB के मामले में सबसे अधिक 34% (वित्त वर्ष 19 में 27% से अधिक) थी।

निजी क्षेत्र के बैंकों और छोटे वित्त बैंकों के मामले में कुल जमा में महिला जमा की हिस्सेदारी बढ़कर क्रमशः 18% (वित्त वर्ष 2019 में 13% से) और 27% (वित्त वर्ष 2019 में 20%) हो गई।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मामले में कुल जमा में महिला जमा की हिस्सेदारी 23% (21%) थी।

आयु-वार वितरण:

RBI द्वारा दिए गए कुल जमा के आयु-वार वितरण से पता चलता है कि 40-60 वर्ष के आयु वर्ग के ग्राहकों के पास व्यक्तियों (हिंदू अविभाजित परिवार/ HUF को छोड़कर) द्वारा 94.7 लाख करोड़ रुपये की जमा राशि का 37% (या 34.7 लाख करोड़ रुपये) है।

इस बीच, वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष और उससे अधिक आयु) द्वारा कुल जमा राशि 36.2 लाख करोड़ रुपये थी, जो वर्ष के दौरान व्यक्तियों की जमा राशि का 38% और कुल जमा का 19.6% का प्रतिनिधित्व करती है।

इसमें व्यक्तिगत जमा राशि में महिलाओं की हिस्सेदारी 39 प्रतिशत (या 37 लाख करोड़ रुपये) है।

राज्यवार वितरण:

9 राज्यों - गोवा, कर्नाटक, हरियाणा, केरल, उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र में 5 साल की अवधि में प्रति व्यक्ति महिला जमा में 10,000 रुपये से अधिक की वृद्धि देखी गई।

गोवा के मामले में प्रति व्यक्ति महिला जमा 26,229 रुपये बढ़कर 1,05,191 रुपये हो गई। इसके बाद कर्नाटक (14,849 रुपये से 55,537 रुपये) का स्थान है। हरियाणा (14,542 रुपये से 72,649 रुपये); केरल (11,945 रुपये से 43,543 रुपये); उत्तराखंड (11,492 रुपये से 57,027 रुपये); गुजरात (11,409 रुपये से 59,751 रुपये); हिमाचल प्रदेश (11,274 रुपये से 66,123 रुपये); पंजाब (11,252 रुपये से 62,099 रुपये) और महाराष्ट्र (10,205 रुपये से 61,404 रुपये) तक।

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 575 करोड़ रुपये मूल्य की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के लिए सेबी के पास ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस दाखिल किया

जन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (जन SFB) ने प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) के लिए पूंजी बाजार नियामक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दाखिल किया है।

महामारी के कारण अपनी पिछली योजना को वापस लेने के 2 साल बाद बैंक ने कागजात फिर से जमा किए हैं, और 2022 में यह स्थानीय बाजार नियमों के अनुसार निजी रह सकता है।

मुख्य विचार:

जन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (जन SFB) ने प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) के लिए पूंजी बाजार नियामक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दाखिल किया है।

फिच रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च, 2023 तक जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड AUM के मामले में चौथा सबसे बड़ा लघु वित्त बैंक और जमा आकार के मामले में चौथा सबसे बड़ा लघु वित्त बैंक है।

ऋणदाता योग्य संस्थागत बोलीदाताओं को 50% शेयर आवंटित करेगा, जबकि गैर-संस्थागत निवेशकों को 15% आवंटन मिलेगा।

शेष 35% शेयर खुदरा निवेशकों के लिए आवंटित किए जाएंगे।

एक्सिस कैपिटल, ICICI सिक्योरिटीज और SBI कैपिटल मार्केट्स इस इश्यू के बुक-रनिंग लीड मैनेजर हैं, जबकि केफिन टेक्नोलॉजीज को रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त किया गया है।

ऋणदाता ने मार्च 2018 में एक लघु वित्त बैंक के रूप में परिचालन शुरू किया।

अप्रैल 2021 में, जना ने IPO के लिए आवेदन किया, लेकिन महामारी के कारण उसे धन उगाहने की योजना में देरी करनी पड़ी।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) का आदेश है कि सभी छोटे वित्त बैंकों को परिचालन शुरू करने के 5 साल के भीतर सूचीबद्ध होना होगा।

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में:

स्थापित: 2018

मुख्यालय: बैंगलोर, कर्नाटक, भारत

CEO: अजय कंवल

भारत की खाद्य वितरण कंपनी स्विगी ने HDFC बैंक के साथ सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया

फूडटेक की दिग्गज कंपनी स्विगी ने ग्राहकों को लुभाने और अपने प्रतिद्वंद्वी जोमैटो पर बढ़त हासिल करने के लिए HDFC बैंक के साथ साझेदारी में एक सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है।

क्रेडिट कार्ड, जिसे मास्टरकार्ड के भुगतान नेटवर्क पर होस्ट किया जाएगा, अगले 7-10 दिनों में चरणबद्ध तरीके से लॉन्च किया जाएगा।

इस कदम के साथ, स्विगी सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड प्रदान करने के मामले में फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और पेटीएम में शामिल हो गई है।

स्विगी के प्रतिस्पर्धी ज़ोमैटो भी RBL बैंक के साथ सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पेश करते थे

हालाँकि, ज़ोमैटो और RBL बैंक ने 2023 में अपनी साझेदारी को बंद करने का फैसला किया।

सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के बारे में:

स्विगी का सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं को भोजन वितरण, किराने की डिलीवरी और बाहर खाने जैसी सेवाओं पर 10% कैशबैक प्रदान करेगा।

इसके अलावा, यूजर्स Amazon, Flipkart, Myntra जैसे अन्य ईकॉमर्स प्लेटफॉर्म पर 5% कैशबैक का लाभ उठा पाएंगे।

यह पहली बार नहीं है कि HDFC बैंक ने सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड की पेशकश करने के लिए किसी अन्य प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है, यह पहले से ही टाटा न्यू, आईआरसीटीसी, इंडिगो और अन्य कंपनियों के साथ सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड प्रदान करता है।

HDFC बैंक के बारे में:

स्थापित: 1 जुलाई 2023 (HDFC-HDFC बैंक के बीच विलय के माध्यम से)
मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र, भारत
MD एवं CEO: शशिधर जगदीशन
टैगलाइन: वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड

फिनटेक कंपनी CRED ने RuPay क्रेडिट कार्ड-आधारित UPI भुगतान लॉन्च किया

फिनटेक फर्म CRED नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के सहयोग से, अपने सदस्यों के लिए रुपे क्रेडिट कार्ड-आधारित यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) भुगतान की शुरुआत की।
CRED HDFC बैंक, ICICI बैंक, यस बैंक, एक्सिस बैंक, BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, केनरा बैंक, इंडियन बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक सहित बैंकों द्वारा जारी किए गए RuPay क्रेडिट कार्ड का समर्थन करता है।

मुख्य विचार:

क्रेडिट-ऑन-यूपीआई का लॉन्च CRED के सदस्यों को UPI के माध्यम से भुगतान करने के लिए अपने RuPay क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने के लिए सशक्त बनाएगा।
उपयोगकर्ता अपने UPI से जुड़े RuPay क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके, किसी भी UPI QR कोड को स्कैन करके व्यवसायों या व्यापारियों को भुगतान कर सकते हैं।
यह एकीकरण सदस्यों को उनके लिंक किए गए RuPay क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके एक साधारण स्कैन के साथ लेनदेन को तेजी से और सुरक्षित रूप से पूरा करने में सक्षम बनाता है।

विशेषताएँ:

क्रेडिट कार्ड का बढ़ता उपयोग: के उपयोग को सक्षम बनाता हैUPI के लिए क्रेडिट कार्डलेन-देन, उनके खर्चों को संभालने के लिए ऋण के उपयोग की पेशकश और उनके बैंक खातों में पैसे के जीवन का विस्तार करना।
सुविधाजनक: भौतिक कार्ड ले जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, सहेजे गए कार्ड का उपयोग करके निर्बाध भुगतान सक्षम हो जाता है और सीधे CRED ऐप पर बिलों को ट्रैक करने और साफ़ करने की सुविधा मिलती है।
पुरस्कृत: क्रेडिट कार्ड के माध्यम से यूपीआई लेनदेन करने से ग्राहकों को अपने क्रेडिट कार्ड और सीआरईडी पर अधिक पुरस्कार अर्जित करने की अनुमति मिलती है।

CRED के बारे में:

स्थापित: 2018
मुख्यालय: बैंगलोर, कर्नाटक
CEO: कुणाल शाह

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की FY24 GDP वृद्धि का अनुमान 20 आधार अंक बढ़ाकर 6.1% कर दिया

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने 2022 की चौथी तिमाही में देश की अपेक्षा से अधिक मजबूत वृद्धि के बाद वित्तीय वर्ष 2023-24 (FY24) के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान 20 आधार अंक बढ़ाकर 6.1% कर दिया है, जो पहले 5.9% था।

IMF ने 2023 के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि के पूर्वानुमान को 20 आधार अंकों से संशोधित कर 3% कर दिया है।

मुख्य विचार:

FY23 की मार्च तिमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि 6.1% बढ़ी।

जून 2023 में, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) ने वित्त वर्ष 24 के लिए अपने पूर्वानुमान को संशोधित कर 6% कर दिया।

RBI को उम्मीद है कि FY24 में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.5% की दर से बढ़ेगी।

IMF ने FY24 के लिए मुद्रास्फीति 4.9% रहने का अनुमान लगाया है।

IMF ने अमेरिका के लिए अपने विकास पूर्वानुमानों को 20 आधार अंक और यूके के लिए 70 आधार अंक तक संशोधित किया।

IMF ने कहा कि विश्व व्यापार वृद्धि 2022 में 5.2% से घटकर 2023 में 2% हो जाएगी।

इसके बाद 2024 में यह बढ़कर 3.7% हो जाएगी।

यह 2000-19 के औसत 4.9% से नीचे रहेगा।

डेलॉइट इंडिया ने अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 24 में भारत की GDP 6-6.3% बढ़ने की संभावना है।

IMF के बारे में:

मुख्यालय: वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका

प्रबंध निदेशक: क्रिस्टालिना जॉर्जीवा

सदस्यता: 190 देश (189 संयुक्त राष्ट्र देश और कोसोवो)

RBI ने विदेशी निवेश की देर से जानकारी देने पर 4 सार्वजनिक उपक्रमों पर जुर्माना लगाया

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ONGC विदेश लिमिटेड (OVL), इंडियन ऑयल कॉर्प लिमिटेड, गेल (इंडिया) लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड जैसे प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर अपने विदेशी निवेश की देरी से रिपोर्टिंग के लिए 2,000 करोड़ रुपये का लेट सबमिशन शुल्क (LSF) लगाया है।

22 अगस्त 2022 की RBI अधिसूचना के अनुसार, आगे के प्रेषण या हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसमें अधिकृत डीलर बैंक भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किसी विदेशी इकाई के प्रति किसी भी बाहरी प्रेषण/वित्तीय प्रतिबद्धता की सुविधा नहीं देंगे, जब तक कि रिपोर्टिंग में देरी नियमित न हो जाए।

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) इन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (PSU) के विदेशी लेनदेन के लिए अधिकृत डीलर (AD) बैंक है। अपेक्षित समयसीमा के भीतर अपने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (ODI) की रिपोर्ट करना और उनका समाधान करना AD बैंक का काम है।

RBI के बारे में:

स्थापना: 1 अप्रैल 1935

मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र, भारत

राज्यपाल: शक्तिकांत दास

उप राज्यपाल: स्वामीनाथन जानकीरमन, माइकल पात्रा, एम. राजेश्वर राव, टी रबी शंकर

RuPay क्रेडिट कार्ड पर 'क्रेडिट ऑन UPI' पहुंच को बढ़ाने के लिए एक्सिस बैंक ने कीवी के साथ साझेदारी की

भारत में निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंकों में से एक एक्सिस बैंक ने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) और कीवी के साथ साझेदारी की है, जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) प्लेटफॉर्म पर क्रांतिकारी क्रेडिट है, जो एक्सिस बैंक क्विक क्रेडिट कार्ड लॉन्च करता है जो क्रेडिट कार्ड पुरस्कार और UPI के तेज और सुरक्षित भुगतान की सुविधा प्रदान करता है। एंड-टू-एंड डिजिटल भुगतान समाधान का उद्देश्य ग्राहकों के लिए भुगतान अनुभव को बढ़ाना है।
यह साझेदारी कीवी उपयोगकर्ताओं को ऐप के माध्यम से RuPay लाइफटाइम फ्री वर्चुअल एक्सिस बैंक KWIK क्रेडिट कार्ड तक निर्बाध रूप से पहुंचने में सक्षम बनाती है।
इसकी नवीन सुविधाओं के साथ, उपयोगकर्ता UPI के माध्यम से अपने क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके किवी ऐप के भीतर व्यापारी भुगतान कर सकते हैं, जो एक आभासी भुगतान अनुभव प्रदान करता है और भौतिक कार्ड की आवश्यकता को समाप्त करता है।

एक्सिस बैंक क्विक क्रेडिट कार्ड की विशेषताएं:

UPI सक्षम निःशुल्क वर्चुअल क्रेडिट कार्ड
प्रति 200 रुपये खर्च करने पर 2 एज रिवॉर्ड।
"कीवी" द्वारा संचालित, स्कैन और भुगतान लेनदेन (यूपीआई पर सीसी का उपयोग करके) पर 1% कैशबैक
1% ईंधन अधिभार छूट

एक्सिस बैंक के बारे में:

स्थापना: 3 दिसंबर 1993
मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र, भारत
MD एवं CEO: अमिताभ चौधरी
टैगलाइन: बढ़ती का नाम जिंदगी

RBI ने राजधानी को-ऑप अर्बन बैंक के साथ नवनिर्माण को-ऑप अर्बन बैंक के समामेलन को मंजूरी दे दी

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नवनिर्माण सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना के साथ राजधानी सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना के समामेलन की योजना को मंजूरी दे दी है।
RBI के पास बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पढ़ी गई धारा 44ए के प्रावधानों के तहत शहरी सहकारी बैंकों (UCB) के स्वैच्छिक एकीकरण को मंजूरी देने की विवेकाधीन शक्तियां हैं।

वित्त वर्ष 2013 में केंद्र सरकार का कर्ज सकल घरेलू उत्पाद का 57.1% है

केंद्र सरकार का कर्ज वित्त वर्ष 2011 में GDP के 61.5% से घटकर वित्त वर्ष 2013 में GDP का 57.1% हो गया।
31 मार्च 2023 तक केंद्र सरकार का कर्ज 155.6 लाख करोड़ रुपये था।
वित्त वर्ष 2013 के अंत में राज्य सरकारों का कर्ज सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 28% होने का अनुमान है।
सकल स्थिर पूंजी निर्माण (GFCF) वित्त वर्ष 2019 में ₹45.41 लाख करोड़ (वित्त वर्ष 2012 की स्थिर कीमतें) से बढ़कर वित्त वर्ष 23 में ₹54.35 लाख करोड़ (अनंतिम अनुमान) हो गया है।
पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना' (FY21 और FY22) सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।
सरकार 'पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना' (FY23 और FY24) भी लागू कर रही है।
इसने पूंजीगत परियोजनाओं पर पूंजीगत व्यय के लिए 50-वर्षीय ब्याज-मुक्त ऋण के रूप में ऋण जारी किया।

वित्त वर्ष 24 के दौरान, पूंजीगत व्यय/निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के तहत ₹84,883.90 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।
केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 2011 में सकल घरेलू उत्पाद के 2.15% से बढ़कर वित्त वर्ष 2013 में सकल घरेलू उत्पाद का 2.7% हो गया है।
पूंजी निवेश परिव्यय 33% बढ़कर ₹10 लाख करोड़ (GDP का 3.3%) हो गया है।

मास्टरकार्ड ने टोकनयुक्त लेनदेन के लिए सीवीवी-मुक्त भुगतान सुविधा लॉन्च की

भुगतान की दिग्गज कंपनी मास्टरकार्ड ने अपने डेबिट और क्रेडिट कार्डधारकों के लिए कार्डधारक सत्यापन मूल्य (CVV)-रहित ऑनलाइन लेनदेन की शुरुआत की घोषणा की, जिन्होंने अपने कार्ड को मर्चेंट प्लेटफॉर्म पर टोकन दिया है।

उद्देश्य:

चेकआउट समय को कम करने और आभासी लेनदेन को परेशानी मुक्त और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए।

मुख्य विचार:

CVV डेबिट और क्रेडिट कार्ड के पीछे छपा हुआ 3 अंकों का नंबर है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के टोकनाइजेशन दिशानिर्देशों के अनुसार, जो व्यापारी टोकन भुगतान अपनाते हैं, वे केवल एक बार CVV एकत्र करेंगे, जो कि कार्ड को टोकन करते समय होगा।
दूसरे लेनदेन के बाद से, कार्डधारकों को चेकआउट पृष्ठ से अपना टोकनयुक्त कार्ड चुनना होगा, वन-टाइम पासवर्ड (OTP) की पुष्टि करनी होगी और CVV दर्ज किए बिना लेनदेन पूरा करना होगा।
मास्टरकार्ड ने दावा किया कि कैश फ्री पेमेंट और ज़ोमैटो जैसी भारतीय कंपनियां पहले ही सीवीवी-कम भुगतान को अपना चुकी हैं।

नवीनतम समाचार:

मई 2023 में, वीज़ा ने भारत में एक नई सुविधा CVV-मुक्त भुगतान लॉन्च की, जो उपयोगकर्ताओं को सीवीवी नंबर की आवश्यकता के बिना ऑनलाइन भुगतान करने की अनुमति देती है।

मास्टरकार्ड के बारे में:

स्थापित: 1966
मुख्यालय: न्यूयॉर्क, यू.एस
CEO: माइकल माइबैक

केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने एएमसी रेपो क्लियरिंग लिमिटेड (ARCL) और कॉरपोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड (CDMDF) लॉन्च किया

केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कॉरपोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड (CDMDF) का उद्घाटन किया और मुंबई, महाराष्ट्र में AMC रेपो क्लियरिंग लिमिटेड (ARCL) नामक सीमित प्रयोजन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन (LPCC) तंत्र पर व्यापार शुरू किया।
दोनों पहलों का उद्देश्य कॉर्पोरेट ऋण बाजारों के कामकाज को गहरा करना है।

CDMDF के बारे में:

CDMDF बाजार में अव्यवस्था के दौरान निर्दिष्ट ऋण निधियों के लिए एक बैकस्टॉप सुविधा है।
इस फंड का उद्देश्य वित्तीय संकट की स्थिति में तरलता सहायता प्रदान करना है।

यह एक वैकल्पिक निवेश कोष (AIF) के रूप में होगा, जिसका उद्देश्य कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार में प्रतिभागियों के बीच विश्वास पैदा करना है।
फंड में म्यूचुअल फंड के लिए 33,000 करोड़ रुपये की बैकस्टॉप सुविधा है।
33,000 करोड़ रुपये में से 30,000 करोड़ रुपये सरकार से आएंगे, जबकि शेष 3,000 करोड़ रुपये का योगदान परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों (AMC) द्वारा किया जाएगा।
फंड में योगदान निर्दिष्ट ऋण-उन्मुख म्यूचुअल फंड योजनाओं और म्यूचुअल फंड की परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों द्वारा किया जा सकता है।
इस फंड की गारंटी नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी (NCGTC) द्वारा दी जाती है और बैकस्टॉप सुविधा का प्रबंधन एसबीआई म्यूचुअल फंड द्वारा किया जाएगा।
यहां निर्दिष्ट ऋण-उन्मुख म्यूचुअल फंड योजनाएं 'ओपन-एंडेड ऋण उन्मुख म्यूचुअल फंड योजनाएं हैं, जिनमें ओवरनाइट फंड और गिल्ट फंड को छोड़कर और रूढ़िवादी हाइब्रिड फंड शामिल हैं।'
ये निर्दिष्ट ऋण-उन्मुख योजनाएं CDMDF इकाइयों में प्रबंधन के तहत अपनी संपत्ति (AUM) का 25 आधार अंक (0.25%) निवेश करेंगी और उनका AUM बढ़ने पर अपना योगदान बढ़ाएंगी और हर 6 महीने में इसकी समीक्षा करेंगी।
हालाँकि, यदि उनका AUM कम हो जाता है तो CDMDF से कोई रिडेम्प्शन नहीं होगा।
AMC को एकमुश्त योगदान के रूप में अपनी निर्दिष्ट ऋण-उन्मुख योजनाओं के AUM का 2% योगदान देना भी आवश्यक है।
इस उद्देश्य के लिए प्रारंभिक योगदान म्यूचुअल फंड की निर्दिष्ट योजनाओं में 31 दिसंबर, 2022 तक एयूएम पर आधारित होगा।

ARCL के बारे में:

AMC रेपो क्लियरिंग लिमिटेड (ARCL) एक संस्था है जिसे कॉर्पोरेट बॉन्ड रेपो लेनदेन के समाशोधन और निपटान के उद्देश्य से स्थापित किया गया है।
सरकारी प्रतिभूतियों में रेपो का बाजार देश में सबसे अधिक तरल बाजारों में से एक है।
कॉरपोरेट बॉन्ड में रेपो बढ़ने का कारण केंद्रीय प्रतिपक्ष की कमी है।
यह एक प्रकार का सीमित प्रयोजन समाशोधन निगम (LPCC) है जो कॉर्पोरेट बांड बाजारों को गहरा करने का कार्य करता है।
इसे एक सक्रिय रेपो बाजार के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार में तरलता में सुधार होगा।
यह कॉरपोरेट बॉन्ड रेपो बाजार को व्यापक और गहरा करेगा।
यह बाजार निर्माताओं को उनकी इन्वेंट्री के लिए लागत प्रभावी फंडिंग तक पहुंचने की अनुमति देगा।
यह बांड धारकों को उनकी परिसंपत्तियों को नष्ट किए बिना उनकी अल्पकालिक तरलता जरूरतों को पूरा करने की अनुमति देगा।
अल्पकालिक अधिशेष को संस्थाओं द्वारा सुरक्षित और कुशल तरीके से तैनात किया जा सकता है।
यह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर सूचीबद्ध सभी ट्रेडों के लिए समाशोधन और निपटान सेवाएं प्रदान करता है।
यह बाजार संस्थानों के निर्माण की दिशा में उद्योग, नियामक और सरकार का एक सहयोग है जहां ऋण बाजार में जारीकर्ता और निवेशक दोनों लाभान्वित होते हैं।
बांड बाजार में LPCC, ट्राई पार्टी रेपो सेवाएं और ARCL की केंद्रीय प्रतिपक्ष सेवाएं अपने सदस्यों के लिए संपार्श्विक और निपटान में बेहतर दक्षता प्रदान करेंगी।

ट्राई-पार्टी रेपो एक प्रकार का रेपो अनुबंध है जहां एक तीसरी इकाई (उधारकर्ता और ऋणदाता के अलावा), जिसे ट्राई-पार्टी एजेंट कहा जाता है, दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करती है।
यह लेनदेन के जीवनकाल के दौरान संपार्श्विक चयन, भुगतान और निपटान, हिरासत और प्रबंधन जैसी सेवाओं की सुविधा प्रदान करता है।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि लॉन्च के दिन, कुल कारोबार मूल्य 480 करोड़ रुपये था।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चेन्नई में दक्षिणी क्षेत्र के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की

केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने चेन्नई, तमिलनाडु (TN), भारत में दक्षिणी क्षेत्र के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) के अध्यक्षों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की।
बैठक में वित्तीय सेवा विभाग के सचिव और भारतीय रिजर्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया, जिसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, पुडुचेरी और कर्नाटक के वित्त विभाग के वित्त/विशेष सचिवों/वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया।

मुख्य विचार:

दक्षिणी क्षेत्र के आरआरबी का सीडी अनुपात, सकल NPA और प्रावधान कवरेज अनुपात (PCR) राष्ट्रीय औसत से बेहतर था।
हालाँकि, आरआरबी को चालू और बचत खाता (CASA) अनुपात में सुधार करना होगा, उन्होंने चेन्नई में दक्षिणी क्षेत्र के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरआरबी के अध्यक्षों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा।
उन्होंने दक्षिणी क्षेत्र में आरआरबी से राज्य भर में अपनी भौतिक उपस्थिति में सुधार के लिए RBI और संबंधित राज्य प्राधिकरणों के साथ मिलकर काम करने का भी आग्रह किया।
उन्होंने पीएम स्वनिधि के तहत स्ट्रीट वेंडरों को ऋण देने के अलावा, विशेष रूप से मत्स्य पालन और पशुपालन जैसे संबद्ध कृषि क्षेत्र को ऋण देने के लिए अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क का लाभ उठाने पर भी प्रकाश डाला।

वित्त मंत्रालय के बारे में:

कैबिनेट मंत्री: निर्मला सीतारमण
राज्य मंत्री: भागवत कराड, पंकज चौधरी

भारतीय स्टेट बैंक Q1 परिणाम: शुद्ध लाभ 178% बढ़कर 16,884 करोड़ रुपये और शुद्ध ब्याज आय 25% बढ़ी

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) का एकल शुद्ध लाभ पहली तिमाही में सालाना आधार पर 178 फीसदी बढ़कर 16,884 करोड़ रुपये हो गया, जो अन्य आय में 5 गुना वृद्धि, मजबूत शुद्ध ब्याज आय और ऋण हानि प्रावधानों में गिरावट से प्रेरित है।
Q1FY24 का शुद्ध लाभ लगातार चौथी तिमाही में SBI का अब तक का सबसे अधिक शुद्ध लाभ है।
कंपनी का मुनाफा ब्रोकिंग कंपनियों के अनुमान को पार कर गया, जो 13,200 करोड़ रुपये से लेकर 16,500 करोड़ रुपये तक था।

मुख्य विचार:

भारत के सबसे बड़े बैंक ने एक साल पहले की तिमाही में 6,068 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया था।
शुद्ध ब्याज आय (NII) सालाना आधार पर 25 प्रतिशत बढ़कर 38,905 करोड़ रुपये (31,196 करोड़ रुपये) रही।
SBI प्रमुख ने जोर देकर कहा कि बैंक सामान्य व्यवसाय वृद्धि का समर्थन करने के लिए अच्छी तरह से पूंजीकृत (पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CAR): 14.56%) है और CAR का यह स्तर 7 लाख करोड़ रुपये की ऋण वृद्धि का समर्थन कर सकता है।

सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (GNPA) मार्च 2023 के 2.78% से जून-अंत 2023 तक सकल अग्रिमों का 2.76% तक सुधार हुआ।
शुद्ध NPA शुद्ध अग्रिम 0.67% से मामूली बढ़कर 0.71% हो गया।
बैंक को मार्च 2024 के अंत तक शुद्ध एनपीए 0.50% होने का अनुमान है।

SBI के बारे में:

स्थापना: 1 जुलाई 1955
मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र, भारत
अध्यक्ष: दिनेश कुमार खरा

नवीनतम समाचार:

मई 2023 में, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने उच्च ब्याज आय और कम प्रावधान के कारण वित्त वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही के लिए शुद्ध लाभ में 83% की वृद्धि दर्ज की, जो 16,694.51 करोड़ रुपये था।

IRDAI बीमाकर्ताओं को परिपक्वता तक HDFC निवेश रखने की अनुमति देता है

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने पूर्ववर्ती हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन (HDFC) में बीमा कंपनियों की बॉन्ड होल्डिंग्स को परिपक्वता तक 'आवास और बुनियादी ढांचे' निवेश के रूप में मानने की अनुमति दी है।
विलय से पहले तक, HDFC बॉन्ड बाजार में सबसे बड़ा जारीकर्ता था, जिसने वित्त वर्ष 2022 और वित्त वर्ष 2023 में लगभग 64,000 करोड़ रुपये जुटाए, जो EBP (इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग प्लेटफॉर्म) के माध्यम से जुटाए गए कुल धन का 10% था।
इसके अलावा, बीमा कंपनियों को 30 जून, 2024 तक विलय के बाद HDFC बैंक के शेयरों के संबंध में एकल निवेशिती इक्विटी एक्सपोजर और निवेश विनियमन मानदंडों का पालन करने से छूट दी गई है।
1 जुलाई से प्रभावी HDFC बैंक के साथ मूल HDFC के विलय के बाद, बीमाकर्ताओं ने मांग की थी कि IRDAI HDFC के बांड में निवेश को वर्गीकृत करने की अनुमति दे।
उन्होंने HDFC बैंक के शेयरों में निवेश के संबंध में यूलिप (यूनिट-लिंक्ड बीमा योजनाओं) के अलग-अलग फंडों के लिए निर्धारित एकल इकाई एक्सपोजर सीमा से छूट की भी मांग की थी।
अप्रैल 2022 में, IRDAI ने वित्तीय और बीमा कंपनियों में बीमाकर्ताओं के निवेश की सीमा पहले के 25% से बढ़ाकर 30% कर दी थी।
विलय के बाद बॉन्डधारक HDFC में अपनी हिस्सेदारी को लेकर चिंतित थे, उन्हें उम्मीद थी कि बॉन्ड को 'बैंकिंग बॉन्ड' के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, जहां बीमाकर्ताओं के पास पहले से ही निर्धारित सीमा के भीतर मौजूदा होल्डिंग्स हैं।

नाबार्ड ने 2023-24 के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास निधि के लिए राजस्थान सरकार को 1,974 करोड़ रुपये मंजूर किए

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) 2023-24 के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास निधि (RIDF) के तहत राजस्थान सरकार को 1,974.07 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।
930.44 करोड़ रुपये अजमेर, जालौर और कोटा जिलों में 3 ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।
926.48 करोड़ रुपये राजस्थान के रेगिस्तानी और आदिवासी क्षेत्रों में 676 ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए मंजूरी दी गई है।
यह राज्य के सभी जिलों में 104 पशु अस्पतालों और 431 उप-केंद्रों के निर्माण के लिए 117.15 करोड़ रुपये मंजूर किए जाने के बाद आया है।

मुख्य विचार:

पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं से 2,500 गांवों के 2.87 लाख घरों को स्वच्छ और पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने की उम्मीद है, जबकि ग्रामीण सड़क परियोजनाओं से 12 जिलों के 1,229 गांवों में कनेक्टिविटी में सुधार होगा।

नाबार्ड सूक्ष्म सिंचाई निधि से 740 करोड़ रुपये की सहायता से 4.28 लाख हेक्टेयर भूमि को सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत लाने में भी राज्य सरकार का समर्थन कर रहा है।

नाबार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट असिस्टेंस के तहत 623.38 करोड़ रुपये की सहायता के बाद कोटा और बूंदी जिलों में 450 किलोमीटर लंबी मिट्टी की नहरों की लाइनिंग निर्माणाधीन है।

नाबार्ड के बारे में:

मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र, भारत

अध्यक्ष: श्री. शाजी के.वी

इसकी स्थापना राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 को लागू करने के लिए 12 जुलाई 1982 को बी शिवरामन समिति (संसद के अधिनियम 61, 1981 द्वारा) की सिफारिशों पर की गई थी।

नाबार्ड भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और शीर्ष सहकारी बैंकों के समग्र विनियमन के लिए एक शीर्ष नियामक निकाय है। यह वित्त मंत्रालय (MoF), भारत सरकार (GoI) के अधिकार क्षेत्र में है।

इंडसइंड बैंक ने सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए टाइगर फिनटेक के साथ साझेदारी की

इंडसइंड बैंक और बजाज कैपिटल ग्रुप की कंपनी टाइगर फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड ने वीज़ा द्वारा संचालित एक सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, इंडसइंड बैंक टाइगर क्रेडिट कार्ड के लॉन्च की घोषणा की।

इस लॉन्च के साथ, ग्राहकों को अपनी जीवनशैली की जरूरतों को पूरा करने के लिए सर्वोत्तम श्रेणी के क्रेडिट कार्ड तक पहुंच मिलेगी।

इंडसइंड बैंक टाइगर क्रेडिट कार्ड के बारे में:

क्रेडिट कार्ड 'शानदार पुरस्कार कार्यक्रम' सहित लाभ के साथ आता है जहां ग्राहक 6 गुना तक त्वरित पुरस्कार अर्जित करते हैं।

कार्डधारक अपने रिवॉर्ड पॉइंट को हवाई मील में परिवर्तित करने और अंतर्राष्ट्रीय खर्चों पर 1.5% की छूट वाली विदेशी मुद्रा मार्क-अप का आनंद लेने में भी सक्षम होंगे।

यह सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड 24x7 द्वारपाल सुविधा, हवाई अड्डों पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय लाउंज का उपयोग, गोल्फ के खेल/पाठ, सुनिश्चित मूवी टिकट और कई अन्य मनोरंजन लाभ जैसे मानार्थ लाभों तक पहुंच प्रदान करता है।

इंडसइंड बैंक के बारे में:

स्थापना: अप्रैल 1994

मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र, भारत

MD और CEO: सुमंत कठपालिया

टैगलाइन: वी मेक यू फील रिचर

सेबी स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से निजी तौर पर सूचीबद्ध InvITs की इकाइयों के लिए बिक्री की पेशकश की अनुमति देता है

पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने स्टॉक एक्सचेंज तंत्र के माध्यम से निजी सूचीबद्ध इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InvIT) की इकाइयों के लिए बिक्री की पेशकश (OFS) की अनुमति दी है।
यह परिपत्र प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करने और प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देने और विनियमित करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 11(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है।

InvITs के बारे में:

निवेशकों को पूलिंग व्यवस्था के माध्यम से जोखिमों के विविधीकरण के साथ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश हासिल करने का अवसर प्रदान करने के लिए भारत में InvITs की शुरुआत की गई थी।
निजी तौर पर रखे गए InvITs निर्माणाधीन संपत्तियों के साथ-साथ पूर्ण और राजस्व पैदा करने वाली संपत्तियों में निवेश कर सकते हैं और सार्वजनिक InvITs पूर्ण और राजस्व पैदा करने वाली संपत्तियों में प्रमुख रूप से निवेश कर सकते हैं।

मुख्य विचार:

बाजार सहभागियों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर, निजी सूचीबद्ध इनविट्स की इकाइयों के लिए OFS की अनुमति देने के लिए ढांचे को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है।
सूचीबद्ध ReiT की इकाइयों में प्रायोजक या प्रायोजक समूह संस्थाओं और अन्य यूनिट धारकों द्वारा ReiT और इनविट की इकाइयों की बिक्री के लिए ओएफएस की अनुमति है।
सूचीबद्ध इनविट के लिए OFS के मामले में, ट्रेडिंग लॉट सेबी के इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट नियमों के तहत द्वितीयक बाजार में ऐसे इनविट के लिए निर्धारित ट्रेडिंग लॉट के समान होगा।

OFS क्या है?

ऑफर फॉर सेल का मतलब है कि प्रमोटर (मालिक) कंपनी के लिए अतिरिक्त फंड जुटाने के लिए अपने शेयर बेचते हैं। बाहरी निवेशकों को शेयर बेचने का प्राथमिक उद्देश्य विकास और विस्तार सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए धन तक पहुंच प्राप्त करना है।

सेबी के बारे में:

स्थापना: 12 अप्रैल 1988 को एक कार्यकारी निकाय के रूप में और 30 जनवरी 1992 को सेबी अधिनियम, 1992 के माध्यम से वैधानिक शक्तियां दी गईं।
मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र
अध्यक्ष: माधबी पुरी बुच (सेबी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला)
सेबी भारत में वित्त मंत्रालय (MoF), भारत सरकार के स्वामित्व के तहत प्रतिभूतियों और कमोडिटी बाजारों के लिए नियामक निकाय है।

स्विस इन्वेस्टर रिस्पॉन्सएबिलिटी ने इलेक्ट्रॉनिका फाइनेंस को $15 मिलियन का फंड देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए

वित्तीय समावेशन और ऊर्जा कुशल मशीन वित्तपोषण पर ध्यान देने के साथ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के वित्तपोषण में विशेषज्ञता रखने वाली पुणे स्थित एक अग्रणी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) इलेक्ट्रॉनिका फाइनेंस लिमिटेड (EFL) ने अपने स्थिरता लक्ष्य के हिस्से के रूप में भारत में हरित वित्तपोषण को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल क्लाइमेट पार्टनरशिप फंड (GCPF) से 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं।

मुख्य विचार:

इलेक्ट्रॉनिका फाइनेंस लिमिटेड ऊर्जा-कुशल मशीनों के वित्तपोषण के लिए धन का उपयोग करेगा और छत पर सौर स्थापना को बढ़ावा देगा।

NBFC को जुलाई 2023 में रिस्पॉन्सिबिलिटी से $7.5 मिलियन प्राप्त हुए, और शेष राशि को बाद में 2023 में निकालने की योजना है।

फंड 11.4% यील्ड पर जुटाया गया था।

इलेक्ट्रॉनिका फाइनेंस लिमिटेड के बारे में:

MD और CEO: शिल्पा पोफले

यह भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) द्वारा समर्थित है।

सेबी और APMI ने संयुक्त रूप से पीएमएस खिलाड़ियों के प्रदर्शन ऑडिट के लिए मानक निर्धारित किए हैं

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) और एसोसिएशन ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर्स इन इंडिया (APMI) संयुक्त रूप से 01 अक्टूबर, 2023 से प्रभावी पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं (PMS) खिलाड़ियों के प्रदर्शन ऑडिट के लिए मानक निर्धारित करेंगे।

एकरूपता रखने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि APMI, सेबी के परामर्श से, फर्म-स्तरीय प्रदर्शन डेटा के उपरोक्त ऑडिट के लिए मानकीकृत संदर्भ की शर्तें ('TOR') निर्दिष्ट करेगा।

मानक TOR में पोर्टफोलियो प्रबंधकों के लिए फर्म-स्तरीय प्रदर्शन डेटा के ऑडिट के उद्देश्य से सभी सेवाओं के तहत ग्राहकों के पोर्टफोलियो पर विचार करने की आवश्यकता शामिल होगी।

पोर्टफोलियो प्रबंधकों को वार्षिक आधार पर फर्म-स्तरीय प्रदर्शन डेटा का ऑडिट करना और प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 60 दिनों के भीतर मानक टीओआर के अनुरूप फर्म-स्तरीय प्रदर्शन डेटा के वार्षिक ऑडिट की आवश्यकता के अनुपालन की पुष्टि प्रस्तुत करना आवश्यक है।

बजाज फाइनेंस ने मोटर बीमा पॉलिसियों की पेशकश के लिए ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की

भारतीयगैर-बैंकिंग वित्तीय सेवाएँकंपनी, बजाज फाइनेंस लिमिटेड (BFL) ने बजाज फाइनेंस इंश्योरेंस मॉल प्लेटफॉर्म पर कार और दोपहिया बीमा योजनाएं प्रदान करने के लिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के साथ-साथ अन्य भागीदारों के साथ साझेदारी की है।

मुख्य विशेषताएं और लाभ:

व्यापक कवरेज प्रदान करता है: बीमित वाहन के साथ-साथ तीसरे पक्ष के लिए भी पूर्ण कवरेज प्राप्त करें।

स्वयं के नुकसान का कवर प्रदान करता है: ये पॉलिसियाँ बीमाकृत वाहन को दुर्घटनाओं, चोरी, प्राकृतिक आपदाओं और आग से होने वाले नुकसान को कवर करती हैं।

तृतीय-पक्ष कवर प्रदान करता है: तृतीय-पक्ष देनदारियों के लिए वित्तीय कवरेज प्राप्त करें।

व्यक्तिगत दुर्घटना कवर प्रदान करता है: यह कवर किसी दुर्घटना के परिणामस्वरूप मालिक/चालक की चोट या मृत्यु की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करता है और 15 लाख रुपये तक का व्यक्तिगत दुर्घटना कवर प्राप्त करता है।

नो क्लेम बोनस (NCB): पिछले पॉलिसी वर्ष में कोई दावा न करने के लिए NCB की पेशकश।

पॉलिसीधारक संचित बोनस के आधार पर नवीनीकरण प्रीमियम पर छूट प्राप्त करके NCB से लाभ उठा सकता है।

BFL के बारे में:

मुख्यालय: पुणे, महाराष्ट्र, भारत

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक: संजीव बजाज

ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के बारे में:

मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र, भारत

MD: भार्गव दासगुप्ता

जुलाई में UPI लेनदेन 44% बढ़कर ₹15 लाख करोड़ हो गया

जुलाई 2023 में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) लेनदेन 44% बढ़कर 15.34 लाख करोड़ रुपये हो गया है।

जुलाई 2023 में UPI लेनदेन मात्रा और मूल्य दोनों के मामले में रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया।

इसमें महीने दर महीने 4% (m-o-m) और साल दर साल (वर्ष दर वर्ष) 44% की वृद्धि हुई है।

मुख्य विचार:

जुलाई 2023 में लेनदेन की संख्या 996 करोड़ के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई।

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के आंकड़ों के अनुसार, यह संख्या पिछले महीने से 6.6% और जुलाई 2022 की तुलना में 58% अधिक थी।

मई 2023 में मासिक लेनदेन की संख्या 900 करोड़ के पार पहुंच गई।

UPI लेनदेन की मात्रा में वृद्धि साल-दर-साल 50% से ऊपर रही है।

2022-23 के लिए RBI की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, UPI के नेतृत्व वाले खुदरा डिजिटल भुगतान ने वित्त वर्ष 2017 और वित्त वर्ष 2012 के बीच मात्रा में 50% और मूल्य में 27% की CAGR में वृद्धि देखी है।

PWC इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 27 तक UPI लेनदेन प्रति दिन 100 करोड़ लेनदेन तक पहुंचने की संभावना है।

UPI के बारे में:

यूनिफ़ाइड पेमेंट इंटरफ़ेस (UPI) एक ऐसी प्रणाली है जो कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लिकेशन में शक्ति प्रदान करती है।

इसे नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा विकसित किया गया है।

इसे अप्रैल 2016 में पेश किया गया था।

स्टार हेल्थ ने अपने बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ 'रणनीतिक कॉर्पोरेट गठबंधन' पर हस्ताक्षर किया

निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य बीमा प्रदाता स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने ग्राहकों को अपने बीमा उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ एक "रणनीतिक कॉर्पोरेट बैंकएश्योरेंस" पर हस्ताक्षर किए हैं।

यह साझेदारी देश भर के 42 शहरों में मौजूद निजी बैंक की 100 शाखाओं में स्वास्थ्य बीमा समाधान प्रदान करने के लिए है।

ग्राहकों को अब व्यापक पॉलिसियों की आवश्यकता है जो उनकी चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करें, जिसमें ओपीडी देखभाल, हॉस्पी कैश और गंभीर बीमारी कवर जैसे लाभ शामिल हों।

स्टैंडर्ड चार्टर्ड की 2022 की वेल्थ एक्सपेक्टेंसी रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 54% से अधिक उत्तरदाताओं ने महामारी के बाद स्वास्थ्य और कल्याण को प्राथमिकता दी है।

बैंकएश्योरेंस क्या है?

बैंकएश्योरेंस एक बैंक और एक बीमा कंपनी के बीच एक संबंध है जिसका उद्देश्य बैंक के ग्राहकों को बीमा उत्पाद या बीमा लाभ प्रदान करना है।
यह साझेदारी व्यवस्था दोनों कंपनियों के लिए लाभदायक हो सकती है।

स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बारे में:

स्थापना: 2006
मुख्यालय: चेन्नई, तमिलनाडु, भारत
MD और CEO: आनंद रॉय

स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इंडिया के बारे में:

स्थापना: 18 नवंबर 1969
मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र, भारत
CEO: ज़रीन दारूवाला

RBI ने विदेशी निवेश की देर से रिपोर्टिंग के लिए ONGC विदेश, इंडियन ऑयल, गेल और ऑयल इंडिया पर जुर्माना लगाया

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ONGC विदेश लिमिटेड (OVL), इंडियन ऑयल कॉर्प लिमिटेड, गेल (इंडिया) लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड पर अपने विदेशी निवेश की देरी से रिपोर्टिंग के लिए 2,000 करोड़ रुपये का लेट सबमिशन फीस (LSF) लगाया है।
RBI ने अपने विदेशी निवेश की देरी से रिपोर्टिंग के लिए प्रत्येक पर 500 करोड़ रुपये का लेट डिपॉजिट शुल्क लगाया है।
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) इन सार्वजनिक उपक्रमों के विदेशी लेनदेन के लिए अधिकृत डीलर बैंक है।
PSU परिचालन में किसी भी व्यवधान से बचने और अपनी विदेशी सहायक कंपनियों के सुचारू कामकाज के लिए आरबीआई से समय पाने की कोशिश कर रहे हैं।
RBI के विदेशी मुद्रा प्रबंधन (विदेशी निवेश) विनियम, 2022 के अनुसार, जो लोग निर्धारित समय सीमा के भीतर निवेश साक्ष्य जमा करने में विफल रहते हैं, वे देर से जमा शुल्क के साथ ऐसा कर सकते हैं।

RBI के बारे में:

स्थापना: 1 अप्रैल 1935
मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र, भारत
गवर्नर: शक्तिकांत दास
उप गवर्नर: महेश कुमार जैन, एम. राजेश्वर राव, माइकल पात्रा और टी. रबी शंकर

बैंकों ने FY15 और FY23 के बीच ₹14.56 लाख करोड़ की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों को बट्टे खाते में डाल दिया

RBI के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, ₹14 लाख करोड़ की गैर-निष्पादित संपत्ति (NPA) FY15 और FY23 (9 वर्ष) के बीच अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) द्वारा बट्टे खाते में डाल दिए गए थे।
इनमें से लगभग आधे (₹7,40,968 करोड़/ ₹7.40 लाख करोड़) बड़े उद्योगों और सेवाओं से संबंधित थे।
SCB ने अप्रैल 2014 से मार्च 2023 तक कॉर्पोरेट ऋण सहित बट्टे खाते में डाले गए ऋणों में कुल 2,04,668 करोड़ रुपये की वसूली की है।

मुख्य विचार:

वित्त वर्ष 2018 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) में बट्टे खाते में डाले गए ऋणों (शुद्ध बट्टे खाते में) की शुद्ध वसूली 1.18 लाख करोड़ रुपये थी, जो वित्त वर्ष 2022 में घटकर 0.91 लाख करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2023 में 0.84 लाख करोड़ रुपये (RBI अनंतिम आंकड़े) रह गई।
वित्त वर्ष 2022-23 में निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा शुद्ध राइट-ऑफ ऋण 73,803 करोड़ रुपये (RBI अनंतिम डेटा) था।
वित्त वर्ष 2017-18 और वित्त वर्ष 2022-23 में निजी क्षेत्र के बैंकों में प्रारंभिक सकल ऋण और अग्रिम के प्रतिशत के रूप में शुद्ध राइट-ऑफ क्रमशः 1.25% और 1.57% था, और इसी अवधि के दौरान PSB के लिए यह 2% और 1.12% था।
भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार, मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान, बैंकों ने 2.09 लाख करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की गैर-निष्पादित संपत्ति (NPA), या खराब ऋण को बट्टे खाते में डाल दिया।
किसी ऋण को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब मूल राशि या ब्याज का पुनर्भुगतान 90 दिनों की अवधि तक बकाया रहता है।
आज तक, SCB की सूची में 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSB), 22 निजी बैंक, 12 छोटे वित्त बैंक, 4 भुगतान बैंक (जो ऋण व्यवसाय में एजेंट के रूप में कार्य करते हैं), 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और 45 विदेशी बैंक शामिल हैं।
PSB का सकल NPA 31 मार्च, 2023 तक घटकर ₹4.28 लाख करोड़ हो गया, जो 31 मार्च, 2018 को ₹8.96 लाख करोड़ था।

RBI के बारे में:

स्थापना: 1 अप्रैल 1935
मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र, भारत
गवर्नर: शक्तिकांत दास
डिप्टी गवर्नर: महेश कुमार जैन, एम. राजेश्वर राव, माइकल पात्रा और टी. रबी शंकर

FY19 और FY23 के दौरान बैंकों ने ₹10.5 लाख करोड़ से अधिक बट्टे खाते में डाले: वित्त मंत्रालय

वित्त मंत्रालय ने राज्यसभा को सूचित किया कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCB) ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त 5 वर्षों में ₹10.5 लाख करोड़ से अधिक की रकम माफ कर दी।
मंत्रालय ने कहा कि शीर्ष 10 विलफुल डिफॉल्टरों पर बैंकों का ₹43,000 करोड़ से अधिक बकाया है।
SCB ने पिछले 5 वित्तीय वर्षों के दौरान कुल ₹10,57,326 करोड़ की राशि बट्टे खाते में डाली है।

मुख्य विचार:

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों और बैंक के बोर्डों द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, NPA (गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां), जिनमें वे भी शामिल हैं जिनके संबंध में 4 वर्ष पूरे होने पर पूर्ण प्रावधान किया गया है, को बट्टे खाते में डालने के माध्यम से संबंधित बैंकों के तुलन-पत्रों से हटा दिया जाता है।
बैंक RBI दिशानिर्देशों और अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, अपनी बैलेंस शीट को साफ करने, कर लाभ प्राप्त करने और पूंजी को अनुकूलित करने के अपने नियमित अभ्यास के हिस्से के रूप में राइट-ऑफ के प्रभाव का मूल्यांकन करते हैं।
इस तरह के बट्टे खाते में डालने से उधारकर्ताओं को चुकाने की देनदारियों से छूट नहीं मिलती है।

IRDAI ने 15 बीमा कंपनियों को अप्रैल 2024 से भारतीय लेखा मानकों को अपनाने के लिए कहा

भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने शीर्ष 15 बीमा कंपनियों से 01 अप्रैल 2024 (वित्त वर्ष 2025) से नए भारतीय लेखा मानक (IND-AS) लेखा ढांचे को अपनाने को कहा है।
यह कई दशकों में बीमा उद्योग के लिए लेखांकन मानकों का पहला ऐसा आंशिक रोल-आउट है, और इस कदम का उद्देश्य भारतीय लेखा प्रथाओं को वैश्विक मानकों के करीब लाना है।
LIC समेत राज्य संचालित बीमा कंपनियों को फिलहाल नए लेखांकन नियमों को अपनाने से बाहर रखा गया है।

मुख्य विचार:

IRDAI ने ऐसी 15 कंपनियों की पहचान की है जिनके पास इस उद्देश्य के लिए विदेशी इक्विटी भागीदार और रणनीतिक सहयोग हैं।
इनमें से कुछ कंपनियां ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, ICICI लोम्बार्ड जनरल, टाटा AIG जनरल, निवा बूपा हेल्थ, HDFC लाइफ और HDFC एर्गो जनरल हैं।
140 से अधिक देशों ने जनवरी 2023 से प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (IFRS) 17 को अपनाया है।
IND-AS 117 को IFRS-17 के समन्वय से डिज़ाइन किया गया है।
नया लेखांकन मानक Ind AS 104, बीमा अनुबंध का स्थान लेगा।

IRDAI के बारे में:

स्थापना: 1999
मुख्यालय: हैदराबाद, तेलंगाना
अध्यक्ष: देबाशीष पांडा
IRDAI भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (MoF) के अधिकार क्षेत्र के तहत एक वैधानिक निकाय है और इसे भारत में बीमा और पुनर्बीमा उद्योगों को विनियमित करने और लाइसेंस देने का काम सौंपा गया है।

सेबी ने IPO नियमों में बदलाव किया और लिस्टिंग का समय 6 दिन से घटाकर 3 दिन कर दिया

पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) के बंद होने के बाद स्टॉक एक्सचेंजों पर शेयरों की लिस्टिंग की समयसीमा को वर्तमान के 6 दिनों से घटाकर 3 दिन कर दिया है।
नई लिस्टिंग समय सीमा 1 सितंबर, 2023 को या उसके बाद खुलने वाले सभी सार्वजनिक मुद्दों के लिए स्वैच्छिक होगी, और 1 दिसं के बाद आने वाले सभी मुद्दों के लिए अनिवार्य होगी।

नए दिशानिर्देशों के तहत,आईपीओइश्यू बंद होने की तारीख के 3 दिन बाद अनिवार्य रूप से सूचीबद्ध करना होगा।

जून 2023 में सेबी के बोर्ड द्वारा इस संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के बाद यह कदम उठाया गया।

मुख्य विचार:

नई समय सीमा तीन कार्य दिवसों (टी+3) पर निर्धारित की गई है, जो छह कार्य दिवसों (टी+6) की पिछली आवश्यकता से एक महत्वपूर्ण कमी है, 'टी' मुद्दे की समापन तिथि का प्रतिनिधित्व करता है।
नए नियमों के तहत कंपनियों को टी+1 दिन शाम 6 बजे से पहले आवंटन को अंतिम रूप देना होगा।
असफल आवेदकों को धनराशि का हस्तांतरण T+2 दिनों में किया जाएगा।

सेबी के मुताबिक, शेयरों की लिस्टिंग और ट्रेडिंग की समयसीमा में कमी से जारीकर्ताओं और निवेशकों दोनों को फायदा होगा। जारीकर्ताओं के पास जुटाई गई पूंजी तक तेजी से पहुंच होगी जिससे व्यापार करने में आसानी बढ़ेगी और निवेशकों को अपने निवेश के लिए शीघ्र ऋण और तरलता प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।
सेबी ने अपनी जून की बैठक में म्यूचुअल फंड हाउसों द्वारा वसूले जाने वाले कुल व्यय अनुपात को विनियमित करने के प्रस्ताव को भी स्थगित कर दिया था, जिसमें व्यापक रूप से बदलाव की उम्मीद थी। सेबी ने कहा कि ASBA आवेदन राशि को अनब्लॉक करने में देरी के लिए निवेशकों को मुआवजे की गणना टी+3 दिनों से की जाएगी।

सेबी के बारे में:

स्थापना: 12 अप्रैल 1988 को एक कार्यकारी निकाय के रूप में और 30 जनवरी 1992 को सेबी अधिनियम, 1992 के माध्यम से वैधानिक शक्तियां दी गईं।
मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र
अध्यक्ष: माधबी पुरी बुच
सेबी वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के स्वामित्व के तहत भारत में प्रतिभूतियों और कमोडिटी बाजारों के लिए नियामक निकाय है।

एक्सिस बैंक 1,612 करोड़ रुपये के निवेश के माध्यम से मैक्स लाइफ में हिस्सेदारी बढ़ाकर 16.2% करेगा

एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी 9.99% से बढ़ाकर 16.22% करने के लिए शेयरों के तरजीही आवंटन के माध्यम से 1,612 करोड़ रुपये का निवेश किया है।
एक्सिस बैंक ने अपनी संस्थाओं (एक्सिस सिक्योरिटीज और एक्सिस कैपिटल) के साथ, 2021 में मैक्स लाइफ में 12.99% हिस्सेदारी हासिल की, और इस नए निवेश के माध्यम से, उनके पास बीमाकर्ता का 19.02% हिस्सा होगा।

मुख्य विचार:

बैंक अब 113.06 रुपये के उचित बाजार मूल्य पर 10 रुपये के अंकित मूल्य के 14,25,79,161 पूरी तरह से भुगतान किए गए इक्विटी शेयरों के तरजीही मुद्दे की सदस्यता के माध्यम से प्रस्तावित अधिग्रहण के लिए मैक्स लाइफ के साथ एक शेयर सदस्यता समझौता करेगा।
वर्तमान में, मैक्स फाइनेंशियल की मैक्स लाइफ में 87% हिस्सेदारी है। प्रस्तावित पूंजी निवेश के पूरा होने पर, मैक्स फाइनेंशियल की शेयरधारिता कम होकर 80.98% रह जाएगी। प्रस्तावित लेनदेन, जिसके 4-6 महीने में पूरा होने की उम्मीद है, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI), पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण सहित शेयरधारकों और नियामकों के अनुमोदन के अधीन है।
(PFRDA) और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI)। शेयर खरीद के बाद, मैक्स लाइफ के बोर्ड में एक्सिस एंटिटीज के 5 नामित निदेशक और मैक्स फाइनेंशियल के 3 नामित निदेशक शामिल होंगे।
इसके अलावा, एक्सिस संस्थाओं के पास सकारात्मक वोटिंग आइटम (AVI) पर अंतिम अधिकार होगा, और मैक्स लाइफ के अध्यक्ष को नियुक्त करने का अधिकार होगा।

एक्सिस बैंक के बारे में:

स्थापना: 3 दिसंबर 1993
मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र, भारत
MD एवं CEO: अमिताभ चौधरी
टैगलाइन: बढ़ती का नाम जिंदगी

RBI ने UPI-लाइट भुगतान सीमा को बढ़ाकर 500 रुपये प्रति लेनदेन करने का प्रस्ताव रखा है

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए ऑफलाइन मोड में UPI लाइट के लिए लेनदेन भुगतान सीमा 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये करने की घोषणा की।

हालाँकि, छोटे मूल्य के डिजिटल लेनदेन की कुल सीमा 2,000 रुपये पर अपरिवर्तित रखी गई है।

इससे पहले, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) और UPI लाइट सहित ऑफ़लाइन मोड में छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान के लिए RBI द्वारा प्रति लेनदेन 200 रुपये की सीमा और प्रति भुगतान साधन 2,000 रुपये की कुल सीमा निर्धारित की गई थी।

मुख्य विचार:

UPI पर संवादात्मक भुगतान:

इसके अतिरिक्त, RBI ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-संचालित प्रणालियों का उपयोग करके UPI पर "संवादात्मक भुगतान" को सक्षम करने का भी प्रस्ताव रखा है।

यह एक अभिनव भुगतान मोड है जो उपयोगकर्ताओं को लेनदेन शुरू करने और पूरा करने के लिए एआई-संचालित प्रणाली के साथ बातचीत में शामिल होने में सक्षम करेगा।

स्मार्टफ़ोन और फ़ीचर फ़ोन दोनों के लिए:

RBI गवर्नर शक्तिकांत दास के मुताबिक, यह स्मार्टफोन और फीचर फोन आधारित UPI चैनल दोनों में उपलब्ध होगा।

यह सुविधा शुरुआत में हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध होगी और जल्द ही इसे अन्य भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराया जाएगा।

UPI लाइट के लिए नियर फील्ड कम्युनिकेशन (NFC) तकनीक:

RBI ने 'UPI-लाइट' ऑन-डिवाइस वॉलेट के माध्यम से नियर फील्ड कम्युनिकेशन (NFC) तकनीक का उपयोग करके UPI पर ऑफ़लाइन भुगतान शुरू करने की योजना की भी घोषणा की।

इससे उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट-प्रतिबंधित क्षेत्र या कम नेटवर्क वाले क्षेत्र में UPI के माध्यम से भुगतान करने में मदद मिलेगी।

NFC तकनीक 4 सेमी या उससे कम दूरी पर दो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बीच संचार की अनुमति देती है।

UPI-लाइट के बारे में:

UPI-लाइट एक ऑन-डिवाइस वॉलेट है जिसे UPI पर छोटे मूल्य के लेनदेन की गति बढ़ाने के लिए सितंबर 2022 में पेश किया गया था।

UPI लाइट, RBI और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के बीच एक सहयोगी पहल है।

BHIM, Paytm, PhonePe और Google Pay जैसे कई UPI प्लेटफ़ॉर्म ने तब से UPI लाइट को अपनाया है।

नवीनतम समाचार:

जुलाई 2023 में, Google Pay ने उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने के लिए UPI लाइट को एकीकृत किया, जो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (UPI) प्रणाली का एक सरलीकृत संस्करण है।

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने 2 Srei समूह फर्मों के लिए नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड की समाधान योजना को मंजूरी दे दी

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) की कोलकाता पीठ ने श्रेई समूह की 2 कंपनियों के लिए नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (NARCL) के समाधान योजना को मंजूरी दे दी है।

फरवरी, 2023 में दिवाला समाधान प्रक्रिया के माध्यम से NARCL दो श्रेई समूह फर्मों - श्रेई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड (SIFL) और श्रेई इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड (SEFL) के लिए विजेता बोलीदाता के रूप में उभरा।

NCLT ने 11 अगस्त, 2023 को मौखिक रूप से कंपनियों की कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के संबंध में NARCL द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना को मंजूरी देते हुए एक आदेश सुनाया है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शासन संबंधी चिंताओं और पुनर्भुगतान चूक के कारण अक्टूबर 2021 में SIFL और SEFL के बोर्ड को भंग कर दिया।

बाद में, RBI ने समेकित समाधान के लिए जुड़वा बच्चों के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही शुरू करने के लिए NCLT से संपर्क किया था।

NARCL के बारे में:

MD और CEO: नटराजन सुंदर

नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (NARCL) को वाणिज्यिक बैंकों की तनावग्रस्त संपत्तियों के निपटान में मदद करने के लिए जुलाई 2021 में एक 'बैड बैंक' के रूप में शामिल किया गया था।

NARCL वाणिज्यिक बैंकों की तनावग्रस्त संपत्तियों को संभालने और उनका निपटान करने के लिए गठित परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (ARC) का नाम है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) के पास NARCL का 51% स्वामित्व है।

NCLT के बारे में:

स्थापना: जून 2016

इसके तहत गठित: न्यायमूर्ति वी. बालकृष्ण इराडी समिति

अध्यक्ष: एमएम कुमार

NCLT भारत में एक अर्ध-न्यायिक निकाय है जो भारतीय कंपनियों से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेता है।

एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने भारत का पहला इको-फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया

बैंकिंग लाइसेंस के साथ बड़े पैमाने पर काम करने वाला भारत का एकमात्र लाभदायक मल्टी-सेगमेंट फिनटेक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, बचत बैंक खाते के साथ अपने नए और मौजूदा ग्राहकों के लिए पर्यावरण-अनुकूल डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है।

यह लॉन्च वित्तीय क्षेत्र के भीतर स्थिरता और पर्यावरण-अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए बैंक की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।

डेबिट कार्ड रीसायकल-पॉली विनाइल क्लोराइड (R-PVC) सामग्री में आएंगे, जो एक प्रमाणित पर्यावरण-अनुकूल सामग्री है।

एयरटेल पेमेंट्स बैंक क्लासिक वेरिएंट के तहत 2 कार्ड लेकर आ रहा है - पर्सनलाइज्ड क्लासिक कार्ड और इंस्टा क्लासिक कार्ड।

ग्राहक एयरटेल थैंक्स ऐप से पर्सनलाइज्ड कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं, जबकि इंस्टा कार्ड चालू तिमाही के अंत तक चुनिंदा पड़ोस के बैंकिंग बिंदुओं पर उपलब्ध होगा।

कार्ड 10,000 रुपये तक के ई-कॉमर्स लाभ और भारत के प्रमुख शहरों में मुफ्त वन डाइन सहित पुरस्कारों के साथ आते हैं।

मुख्य विचार:

उत्पादित 50,000 कार्डों के प्रत्येक बैच से बाजार में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक PVC कार्डों की तुलना में 350 किलोग्राम कार्बन उत्सर्जन में काफी कमी आएगी।
इसके अलावा, R-PVC कार्ड के उत्पादन से हाइड्रोकार्बन उपयोग में 43% की कमी आएगी, जिससे विनिर्माण के दौरान पेट्रोलियम खपत प्रभावी रूप से कम हो जाएगी।
बैंक का दूरदर्शी दृष्टिकोण जल संरक्षण में भी योगदान देगा, जिससे R-PVC कार्ड के प्रति बैच में 6.6 मिलियन लीटर पानी की प्रभावशाली बचत होगी।

एयरटेल पेमेंट्स बैंक के बारे में:

स्थापित: जनवरी 2017.
मुख्यालय: नई दिल्ली, दिल्ली
MD और CEO: अनुब्रत बिस्वास

ग्राहक जीवन बीमा के लिए कोटक लाइफ ने ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ समझौता किया

कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी (कोटक लाइफ) ने कहा कि उसकी कॉर्पोरेट एजेंसी ने ग्राहकों को जीवन बीमा की पेशकश करने के लिए ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक (ESAF बैंक) के साथ गठजोड़ किया है।
इस समझौते से ESAF बैंक के 68 लाख ग्राहकों को लाभ होगा, जो 21 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) में फैले ESAF बैंक के 700 बैंकिंग आउटलेट्स के माध्यम से सुरक्षा, बचत, निवेश और सेवानिवृत्ति सहित कोटक लाइफ द्वारा प्रदान किए गए जीवन बीमा उत्पादों और समाधानों की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश करेगा।

कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में:

स्थापना: 2001
मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र
प्रबंध निदेशक: महेश बालासुब्रमण्यम

ESAF लघु वित्त बैंक के बारे में:

स्थापना: 10 मार्च 2017
मुख्यालय: त्रिशूर, केरल
MD और CEO: कदम्बेलिल पॉल थॉमस

बैंक ऑफ महाराष्ट्र 2023 की पहली तिमाही में 25% की ऋण और जमा वृद्धि के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाताओं की सूची में शीर्ष पर है

बैंक ऑफ महाराष्ट्र (BOM) चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान प्रतिशत के संदर्भ में 25% की वृद्धि के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाताओं के बीच शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा है।
अप्रैल-जून तिमाही के दौरान पुणे स्थित ऋणदाता की जमा और अग्रिम राशि किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSB) द्वारा सबसे अधिक है।

मुख्य विचार:

24.98% की वृद्धि दर के साथ, जून 2023 के अंत में बैंक का सकल घरेलू अग्रिम बढ़कर 1,75,676 करोड़ रुपये हो गया। इसके बाद 20.70% की वृद्धि के साथ यूको बैंक, जबकि 16.80% की वृद्धि के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) और 16.21% की वृद्धि के साथ इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर रहे।

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) घरेलू अग्रिम वृद्धि में 15.08% की वृद्धि के साथ 5वें स्थान पर रहा।
हालाँकि, SBI का कुल ऋण 28,20,433 करोड़ रुपये पर लगभग 16 गुना अधिक था, जबकि पूर्ण रूप से BOM का 1,75,676 करोड़ रुपये था।
खुदरा-कृषि-MSME (RAM) ऋणों के मामले में, BOM में 25.44% की उच्चतम वृद्धि हुई है, इसके बाद पंजाब एंड सिंध बैंक में 19.64% और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में साल-दर-साल आधार पर 19.41% की वृद्धि हुई है।
जमा वृद्धि के संबंध में, BOM ने 24.73% की वृद्धि देखी और जून 2023 के अंत में 2,44,365 करोड़ रुपये जुटाए।
BOB जमा में 15.50% की वृद्धि (10,50,306 करोड़ रुपये) के साथ दूसरे स्थान पर था, जबकि PNB ने 13.66% की वृद्धि के साथ 12,67,002 करोड़ रुपये दर्ज की।
कम लागत वाली चालू खाता और बचत खाता (CASA) जमाओं के मामले में बीओएम ने 50.97% के साथ शीर्ष स्थान बरकरार रखा है, इसके बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 49.56% के साथ दूसरे स्थान पर है।
जून 2023 के अंत में बैंक के कुल कारोबार में 24.84% की उच्चतम वृद्धि 420,041 करोड़ रुपये दर्ज की गई, इसके बाद BoB 16.10% की वृद्धि के साथ 18,62,932 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

नवीनतम समाचार:

मई 2023 में, बैंक ऑफ महाराष्ट्र (BOM) खराब ऋणों के प्रबंधन के मामले में सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में उभरा, इसकी शुद्ध गैर-निष्पादित संपत्ति (NPA) मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान 0.25% तक गिर गई।

BOM के बारे में:

स्थापना: 16 सितंबर 1935
मुख्यालय: पुणे, महाराष्ट्र
MD और CEO: एएस राजीव
टैगलाइन: वन फैमिली वन बैंक

महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र की पेशकश करने वाले 5 बैंक, डाकघर 7.5% ब्याज दर अर्जित करने वाली योजना

वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अगस्त 2023 में महिलाओं और लड़कियों के लिए एक छोटी बचत योजना, महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र (MSSC) की शुरुआत की।
वर्तमान में महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र प्रदान करने वाले 5 बैंकों में बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB), यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया (BOI), पंजाब नेशनल बैंक (PNB) शामिल हैं।

महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र (MSSC) योजना के बारे में:

MSSC एक सरकार द्वारा गारंटीकृत सीमित अवधि की छोटी बचत योजना है जिसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और उनके वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है।
MSSC एक 2-वर्षीय जमा योजना है, जो प्रति वर्ष 7.5% की ब्याज दर प्रदान करती है।
यह एक बार का कार्यक्रम है जो अप्रैल 2023 से मार्च 2025 तक चलता है।

पात्रता:

योजना के तहत, व्यक्तिगत लड़कियां या महिलाएं खाता खोल सकती हैं, या नाबालिग लड़की की ओर से कोई अभिभावक खाता खोल सकता है।

ब्याज दर:

यह योजना प्रति वर्ष 5% की ब्याज दर प्रदान करती है, जो त्रैमासिक रूप से संयोजित होती है।

जबकि न्यूनतम निवेश 1,000 रुपये है, 100 रुपये के गुणकों में कोई भी राशि अधिकतम 2 लाख रुपये तक जमा की जा सकती है।

व्यक्ति प्रत्येक खाते के बीच 3 महीने के अंतराल के साथ कई खाते खोल सकते हैं, बशर्ते कुल निवेश सीमा 2 लाख रुपये हो।

खाता अवधि:

खाता खुलने की तारीख से 2 साल बाद परिपक्व हो जाएगा।

ग्राहक द्वारा आपातकालीन स्थिति में या अपने विवेक से खाता बंद करने का अनुरोध किया जा सकता है, खाता खोलने की तारीख से 6 महीने के बाद 2% का जुर्माना लगाया जाएगा, और लागू ब्याज दर 5.5% होगी।

विनियामक पर्यवेक्षण को बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग करने के लिए RBI ने मैकिन्से एंड कंपनी और एक्सेंचर सॉल्यूशंस के साथ साझेदारी की

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपने पर्यवेक्षी कार्यों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और मशीन लर्निंग का उपयोग करके सिस्टम विकसित करने के लिए वैश्विक परामर्श फर्म मैकिन्से एंड कंपनी इंडिया LLP और एक्सेंचर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड इंडिया का चयन किया है।

RBI एक विशाल डेटाबेस का विश्लेषण करने और बैंकों और NBFC पर नियामक पर्यवेक्षण में सुधार के लिए उन्नत एनालिटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग का उपयोग करने की योजना बना रहा है।

इसके लिए RBI बाहरी विशेषज्ञों को नियुक्त करने की योजना बना रहा है।

पृष्ठभूमि:

सितंबर 2022 में, RBI ने पर्यवेक्षी इनपुट उत्पन्न करने के लिए उन्नत एनालिटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग का उपयोग करने के लिए सलाहकारों को शामिल करने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (EOI) आमंत्रित की।

मुख्य विचार:

RBI ने सलाहकारों के चयन के लिए प्रस्ताव प्रक्रिया (RFP) के अनुरोध में भाग लेने के लिए 7 आवेदकों को शॉर्टलिस्ट किया था।

7 कंपनियां एक्सेंचर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड थीं; बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड; डेलॉइट टौचे तोहमात्सू इंडिया LLP; अर्न्स्ट एंड यंग एलएलपी; KPMG एश्योरेंस एंड कंसल्टिंग सर्विसेज LLP; मैकिन्से एंड कंपनी; और प्राइसवाटरहाउसकूपर्स प्राइवेट लिमिटेड।

7 आवेदकों में से, मैकिन्से और एक्सेंचर को अनुबंध से सम्मानित किया गया है और अनुबंध का मूल्य लगभग 91 करोड़ रुपये है।

जबकि RBI पहले से ही पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं में एआई और एमएल का उपयोग कर रहा है, अब यह यह सुनिश्चित करने के लिए इसे उन्नत करने का इरादा रखता है कि उन्नत विश्लेषण का लाभ केंद्रीय बैंक में पर्यवेक्षण विभाग को मिल सके।

RBI का पर्यवेक्षण विभाग पर्यवेक्षी परीक्षाओं के लिए रैखिक और कुछ मशीन-सीखे गए मॉडल का उपयोग कर रहा है।

RBI का पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार शहरी सहकारी बैंकों, NBFC, भुगतान बैंकों, लघु वित्त बैंकों, स्थानीय क्षेत्र के बैंकों, क्रेडिट सूचना कंपनियों और चुनिंदा सभी भारतीय वित्तीय संस्थानों तक फैला हुआ है।

RBI उनकी वित्तीय सुदृढ़ता, सॉल्वेंसी, परिसंपत्ति गुणवत्ता, शासन ढांचे, तरलता और परिचालन व्यवहार्यता का आकलन करता है।

AI और ML प्रौद्योगिकियों का उपयोग वास्तविक समय डेटा रिपोर्टिंग, प्रभावी डेटा प्रबंधन और प्रसार के लिए किया जाता है।

डेटा विश्लेषण के लिए, इनका उपयोग पर्यवेक्षित फर्म-विशिष्ट जोखिमों की निगरानी के लिए किया जा रहा है, जिसमें तरलता जोखिम, बाजार जोखिम, क्रेडिट एक्सपोजर और एकाग्रता जोखिम शामिल हैं; कदाचार विश्लेषण; और उत्पादों की गलत बिक्री।

RBI के बारे में:

स्थापना: 1 अप्रैल 1935
मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र, भारत
राज्यपाल: शक्तिकांत दास
उप राज्यपाल: महेश कुमार जैन, एम राजेश्वर राव, माइकल पात्रा और टी. रबी शंकर

SBI डेबिट कार्ड बाजार में अग्रणी है और HDFC जून 2023 में क्रेडिट कार्ड में शीर्ष पर बना हुआ है

1 लैटिस (पहले पीजीए लैब्स) के नवीनतम आंकड़ों से पता चला है कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का ऋणदाता, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) जून 2023 में 28% हिस्सेदारी के साथ डेबिट कार्ड बाजार में अग्रणी बना रहा।
शीर्ष बैंकों ने सूची में बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) का अनुसरण किया, जिसके पास लगभग 9% बाजार हिस्सेदारी थी, इसके बाद बैंक ऑफ इंडिया (BOI), केनरा बैंक, यूनियन बैंक और HDFC बैंक थे, जिनमें से प्रत्येक की लगभग 5% बाजार हिस्सेदारी थी।
डेबिट कार्ड सेगमेंट में, केनरा बैंक ने साल-दर-साल सबसे अधिक, लगभग 14% की वृद्धि दर्ज की, जबकि HDFC बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) ने 13% की वृद्धि दर्ज की।
भले ही भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने डेबिट कार्ड बाजार में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है, लेकिन जून, 2023 में इसने लगभग 2% की गिरावट दर्ज की।
ICICI बैंक सबसे अधिक 11% की गिरावट दर्ज की गई, इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में 10% की गिरावट दर्ज की गई।
पिछले 4 वर्षों में, डेबिट और क्रेडिट कार्ड लेनदेन क्रमशः 20% और 19% की CAGR से बढ़े हैं।
PWC इंडिया की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, FY22 में 71 मिलियन सक्रिय क्रेडिट कार्ड।
भारत का सबसे बड़ा निजी बैंक, HDFC बैंक 21% हिस्सेदारी के साथ क्रेडिट कार्ड बाजार में दौड़ में सबसे आगे रहा।
जून, 2023 में SBI कार्ड, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक क्रमशः 20%, 17% और 14% बाजार हिस्सेदारी के साथ सूची में दूसरे स्थान पर रहे।
1 लैटिस डेटा से आगे पता चला कि वैश्विक नेताओं ने क्रेडिट कार्ड सेगमेंट में उम्मीद से कम प्रदर्शन किया, अमेरिकन एक्सप्रेस ने 1% की गिरावट दर्ज की, 2% बाजार हिस्सेदारी हासिल की।
सिटीबैंक की बाजार हिस्सेदारी एक्सिस-सिटी डील के बाद शून्य हो गया।

बंधन बैंक और ओडिशा सरकार ने OTDC भुगतान समाधान की सुविधा के लिए साझेदारी की

भारत का प्रमुख निजी ऋणदाता बंधन बैंक ने ओडिशा पर्यटन विकास निगम (OTDC) लिमिटेड के लिए भुगतान समाधान बढ़ाने के लिए ओडिशा सरकार के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है।

उद्देश्य:

पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधा शुरू करना और भुगतान प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना।

इस साझेदारी के हिस्से के रूप में, बंधन बैंक ने पुरी, भुवनेश्वर, कोणार्क, चिल्का और गोपालपुर सहित प्रमुख पर्यटन स्थलों पर प्वाइंट ऑफ सेल (POS) मशीनें पेश की हैं।
इन POS मशीनों के एकीकरण से भुगतान संग्रह में तेजी आएगीपर्यटकों, आगंतुकों और OTDC अधिकारियों दोनों के लिए प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना।
इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर (EDC) मशीनें OTDC के लिए राजस्व हानि को रोकने में भी मदद करेंगी, जो पर्यटकों द्वारा नकदी की कमी के कारण हो सकता है। यह पहल देश के कैशलेस अर्थव्यवस्था बनने के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
2015 में बंधन बैंक भारत में यूनिवर्सल बैंक बनने वाला पहला माइक्रोफाइनेंस संस्थान बन गया।

बंधन बैंक के बारे में:

स्थापित: 2015
मुख्यालय: कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत
MD एवं CEO: चन्द्रशेखर घोष

RBI घर्षण रहित ऋण के लिए पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगा

भारत के वित्तीय परिदृश्य को बढ़ाने की दिशा में एक कदम में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने RBI की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (RBIH) द्वारा घर्षण रहित क्रेडिट के लिए सार्वजनिक तकनीकी मंच के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की है।

उद्देश्य:

ऋणदाताओं को आवश्यक डिजिटल जानकारी के निर्बाध प्रवाह की सुविधा प्रदान करके घर्षण रहित ऋण वितरण को सक्षम बनाना।
यह पहल जल्द ही 17 अगस्त, 2023 से चरणबद्ध तरीके से एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की जाएगी।
यह ढांचा बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC), फिनटेक फर्मों और स्टार्टअप्स सहित विभिन्न हितधारकों को भुगतान, क्रेडिट और अन्य वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में सहयोगात्मक रूप से समाधान बनाने और वितरित करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

मुख्य विचार:

पब्लिक टेक प्लेटफ़ॉर्म ऋणदाताओं को महत्वपूर्ण डिजिटल जानकारी के प्रवाह को सुव्यवस्थित करके ऋण वितरण में क्रांति लाने के लिए तैयार है।
एंड-टू-एंड डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ डिज़ाइन किया गया, प्लेटफ़ॉर्म एक ओपन आर्किटेक्चर पर स्थापित किया गया है, जो ओपन एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (API) और उद्योग मानकों का उपयोग करता है।
यह समावेशी ढांचा वित्तीय क्षेत्र के सभी प्रतिभागियों को सहयोगात्मक नवाचार और दक्षता को बढ़ावा देते हुए 'प्लग एंड प्ले' मॉडल में सहजता से एकीकृत होने के लिए प्रेरित करता है।
प्लेटफॉर्म के पायलट चरण में शुरू में किसान क्रेडिट कार्ड ऋण, डेयरी ऋण, संपार्श्विक-मुक्त MSME ऋण, व्यक्तिगत ऋण और गृह ऋण जैसे उत्पादों को प्राथमिकता दी जाएगी।
ये सेवाएँ भागीदार बैंकों के माध्यम से पेश की जाएंगी, जिससे विभिन्न उधारकर्ताओं की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विविध पेशकश तैयार की जाएंगी।

प्लेटफॉर्म की कार्यात्मकताओं में आधार e-KYC, चयनित राज्य सरकारों (मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र) के भूमि रिकॉर्ड, उपग्रह डेटा एकीकरण, पैन सत्यापन, लिप्यंतरण, आधार ई-हस्ताक्षर और खाता एग्रीगेटर्स (एए) द्वारा प्रदान की गई खाता एकत्रीकरण सहित महत्वपूर्ण सेवाएं शामिल होंगी।
इसके अलावा, चुनिंदा डेयरी सहकारी समितियों से दूध डालने का डेटा और संपत्ति खोज डेटा को प्लेटफॉर्म में एकीकृत किया जाएगा।

RBI के बारे में:

स्थापना: 1 अप्रैल 1935
मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र, भारत
राज्यपाल: शक्तिकांत दास
उप राज्यपाल: महेश कुमार जैन, एम राजेश्वर राव, माइकल पात्रा और टी. रबी शंकर

मार्च 2023 के अंत में क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट 1.94% बढ़कर `4,072 करोड़ हो गया

मार्च 2023 के अंत तक क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट बढ़कर 4,072 करोड़ रुपये या 1.94% हो गया।
RBI से प्राप्त इनपुट के अनुसार, क्रेडिट कार्ड में चूक के संबंध में, क्रेडिट कार्ड में सकल गैर-निष्पादित संपत्ति (GNPA) मार्च-2022 में 3,122 करोड़ रुपये और मार्च-2023 में 4,072 करोड़ रुपये थी, जबकि क्रेडिट कार्ड पर बकाया था। मार्च-2022 और मार्च-2023 में क्रमशः 1.64 लाख करोड़ रुपये और 2.10 लाख करोड़ रुपये था।
क्रेडिट कार्ड में GNPA मार्च 2021 में 3.56% से घटकर मार्च 2022 में 1.91% हो गया है, और मार्च 2023 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के GNPA 3.87% के मुकाबले मार्च 2023 में 1.94% हो गया है।
वित्त वर्ष 2013 के दौरान सहकारी बैंकों द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की कुल संख्या 964 थी, जिसमें 791.40 करोड़ रुपये की राशि शामिल थी।
वित्त वर्ष 2012 के दौरान, धोखाधड़ी की कुल संख्या 729 थी और इसमें शामिल राशि 536.59 करोड़ रुपये थी, जबकि वित्त वर्ष 2011 में 1,985.79 करोड़ रुपये की 438 धोखाधड़ी हुई थी।

RBI ने नियमों का उल्लंघन करने पर 4 सहकारी बैंकों पर आर्थिक जुर्माना लगाया

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नियमों का उल्लंघन करने के लिए 4 सहकारी बैंकों - मंगल को-ऑपरेटिव बैंक, द महाबलेश्वर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, द इस्लामपुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक और द तापिंदु अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है।

मुख्य विचार:

तापिंदु अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पटना पर ₹1,00,000 का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है।
यह जुर्माना 'एक्सपोज़र नॉर्म्स और वैधानिक / अन्य प्रतिबंध – UCB' पर RBI द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए है।
इस्लामपुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र पर 2.00 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
बैंकों ने पात्र राशि को जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष (DEAF) में स्थानांतरित नहीं किया था।
महाबलेश्वर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के कुछ प्रावधानों और भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए 2.00 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर 'जमा खातों के रखरखाव' और 'अपने ग्राहक को जानें (KYC)' पर RBI के निर्देशों का पालन न करने के लिए 1.00 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया।

इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी बेहतर ग्रामीण पहुंच के लिए लंबी दूरी की वायरलेस तकनीक-आधारित समाधान लॉन्च करेगा

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की एक शाखा, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी (IDRBT) द्वारा विकसित एक नई तकनीक अब दूरदराज के क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की अंतिम-मील कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए तैनात करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

लोरा (लॉन्ग रेंज) वायरलेस प्रोटोकॉल पर आधारित वित्तीय नेटवर्क तकनीक का फील्ड स्तर पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है और अब RBI और अन्य हितधारकों द्वारा इस पर ध्यान दिया जा रहा है।

मुख्य विचार:

वित्तीय नेटवर्क:

लोरा प्रोटोकॉल पर आधारित नए समर्पित कम लागत वाले वित्तीय नेटवर्क का उपयोग निजी तौर पर बैंकों द्वारा वित्तीय लेनदेन करने के लिए एन्क्रिप्टेड वित्तीय पैकेट भेजने के लिए किया जा सकता है।

हैदराबाद स्थित IDRBT लोरा तकनीक पर आधारित इस निजी वित्तीय नेटवर्क को विकसित करने वाला दुनिया का पहला है। इसने ऑफ़लाइन लेनदेन के लिए भी पेटेंट दाखिल करके आईपी की रक्षा की है।

लोरा वित्तीय नेटवर्क की लागत आज इस्तेमाल की जा रही वैकल्पिक नेटवर्क प्रौद्योगिकियों की तुलना में 20% सस्ती होने का अनुमान है।

बैंक तीसरे पक्ष के नेटवर्क का उपयोग करने के बजाय लोरा को अपने स्वयं के समर्पित निजी नेटवर्क के रूप में उपयोग कर सकते हैं, जो वर्तमान में या तो वायर्ड (फाइबर) या सैटेलाइट लिंक के माध्यम से होता है।

चूँकि इसका स्वामित्व निजी तौर पर बैंकों के पास हो सकता है, इसलिए साइबर हमलों से अधिक सुरक्षा होगी। अधिक सुरक्षित प्लेटफ़ॉर्म होने के अलावा, लोरा नेटवर्क आसान पुनर्प्राप्ति और उन्नयन की भी अनुमति देता है।

लोरा वित्तीय नेटवर्क के साथ बैंकिंग प्रणाली की अंतिम-मील कनेक्टिविटी को और अधिक विस्तारित किया जा सकता है। जहां बैंक की आखिरी शाखा है वहां से कनेक्टिविटी को लोरा वित्तीय नेटवर्क का उपयोग करके किसी सुदूर गांव या पहाड़ी क्षेत्र तक बढ़ाया जा सकता है।

इससे माइक्रो-ATM स्थापित करने और उनके कुशल कामकाज में भी सुविधा होगी।

ADB ने मेघालय में एकीकृत प्रारंभिक बचपन विकास कार्यक्रम और मातृ मानसिक स्वास्थ्य के लिए 40.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी

एशियाई विकास बैंक (ADB) ने मेघालय में एकीकृत प्रारंभिक बचपन विकास (ECD) और मातृ मानसिक स्वास्थ्य के लिए 40.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है।

मेघालय सरकार भी इस परियोजना में 15.27 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दे रही है।

फंडिंग संरचना:

समृद्ध और लचीले एशिया और प्रशांत के लिए जापान फंड से 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर का तकनीकी सहायता अनुदान आंगनवाड़ी कर्मचारियों और ECD शिक्षकों के लिए दिशानिर्देश और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम विकसित करने में मदद करेगा।

परियोजना के बारे में:

बच्चों की देखभाल में वृद्धि:

परियोजना का लक्ष्य 2 आयु समूहों के लिए बाल देखभाल को मजबूत करना है: 0-1.5 वर्ष (घर-आधारित) और 1.5-6 वर्ष (आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से केंद्र-आधारित)।
1,800 मौजूदा आंगनवाड़ी केंद्रों का उन्नयन और दूरदराज के क्षेत्रों में लगभग 600 नए केंद्रों का निर्माण।

पोषण देखभाल पहुंच:

यह परियोजना बच्चों की पोषण देखभाल तक पहुंच में सुधार, उनके समग्र विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
देखभाल में पिता को शामिल करने के लिए मातृ मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और समावेशी पालन-पोषण कार्यक्रमों पर जोर दिया गया।

पोषक तत्व संवर्धन:

ADB की सहायता में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं और 0.5-6 वर्ष की आयु के बच्चों के आहार में अंडे शामिल करना शामिल है।
इसका उद्देश्य पोषक तत्वों की पर्याप्तता में सुधार करना और कुपोषण संबंधी चिंताओं का समाधान करना है।

दुर्गम क्षेत्रों पर प्रभाव:

नए आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण की परियोजना दुर्गम क्षेत्रों को लक्षित करती है, जिससे बाल देखभाल और पोषण सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित होती है।

एसडीजी संरेखण:

यह पहल सतत विकास लक्ष्य (SDG) 2 (शून्य भूख) और 3 (अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली) के अनुरूप है, जो बेहतर पोषण और स्वास्थ्य में योगदान देता है।

ADB के बारे में:

स्थापना: 1966
मुख्यालय: मनीला, फिलीपींस
राष्ट्रपति: मासात्सुगु असकावा
सदस्यता: 68 सदस्य, जिनमें 49 क्षेत्रीय सदस्य (एशिया और प्रशांत क्षेत्र के देश) और 19 गैर-क्षेत्रीय सदस्य (क्षेत्र के बाहर के देश) शामिल हैं।

केनरा बैंक ने पेंशनभोगियों के लिए केनरा जीवन धारा - अनुकूलित बचत खाता लॉन्च किया

केनरा बैंक ने "केनरा जीवन धारा" नाम से एक विशेष बचत बैंक खाता पेश किया है जिसका उद्देश्य पेंशनभोगियों और संभावित पेंशनभोगियों की अनूठी वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है, जिनमें स्वैच्छिक आधार पर या सामान्य सेवानिवृत्ति के माध्यम से सेवानिवृत्त हुए लोग भी शामिल हैं।

मुख्य विचार:

खाता प्रकार:

बैंक पेंशन क्रेडिट के आधार पर दो प्रकार की पेशकश करता है।
हीरे का हिसाब 50,000 रुपये तक के लिए है और प्लैटिनम खाता 50,000 रुपये से अधिक के लिए है।

ब्याज दर:

केनरा जीवन धारा बचत खाते पर ब्याज दर नियमित बचत खाते की दर को प्रतिबिंबित करती है, जो खाते की शेष राशि के आधार पर 2.90% से 4% तक होती है।

जमा पर ऋण:

खाता जमा सुविधा के विरुद्ध ऋण प्रदान करता है, जो वरिष्ठ नागरिकों को जमा दर से 0.75% अधिक आकर्षक दर प्रदान करता है।

टॉप-अप सुविधा:

केनरा जीवन धारा के ग्राहक पेंशन ऋण पर टॉप-अप सुविधा का आनंद लेते हैं, जिससे ऋण और वित्तीय लचीलेपन तक उनकी पहुंच बढ़ जाती है।

चिकित्सा व्यय पर रियायत:

खाताधारकों को चिकित्सा व्यय पर 25% तक की छूट का लाभ मिलता है, जो समग्र ग्राहक कल्याण के लिए केनरा बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

केनरा बैंक FD ब्याज दरें:

केनरा बैंक 7 दिनों से लेकर 10 साल तक की परिपक्वता वाली सावधि जमा (FD) की एक श्रृंखला प्रदान करता है।
आम जनता के लिए ब्याज दरें 4% से 7.25% तक हैं।
वरिष्ठ नागरिकों को 4% से 7.75% तक की तरजीही दरें मिलती हैं।

केनरा बैंक के बारे में:

स्थापना: 1906
मुख्यालय: बेंगलुरु, कर्नाटक, भारत
MD एवं CEO: के सत्यनारायण राजू
टैगलाइन: टुगेदर वी कैन

SBI की चालू वित्त वर्ष में पूरे भारत में 300 शाखाएं खोलने की योजना है

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) चालू वित्त वर्ष में पूरे भारत में 300 नई शाखाएं खोलने की योजना बना रहा है।
यह वर्तमान में देश भर में 22,405 शाखाएँ संचालित करता है और इसकी 235 विदेशी शाखाएँ और कार्यालय हैं।
SBI का लक्ष्य अपने व्यवसाय संवाददाताओं के नेटवर्क को बढ़ाना है, जो वंचित क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में SBI ने 16,884 करोड़ रुपये का अब तक का सबसे अधिक तिमाही मुनाफा दर्ज किया है।
यह पिछले वर्ष की इसी तिमाही में ₹6,068 करोड़ के शुद्ध लाभ की तुलना में पर्याप्त वृद्धि है।

SBI के बारे में:

अध्यक्ष: दिनेश कुमार खारा
मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र.
टैगलाइन: द बैंकर टू एव्री इंडियन

PFRDA NPS लेनदेन विवरण को समेकित खाता विवरण के साथ एकीकृत करता है

पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंशधारकों को प्रतिभूति बाजार में उनके व्यक्तिगत निवेश के बारे में बेहतर और समेकित दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए सहयोग किया है, जिसमें एकल समेकित खाता विवरण (CAS) के तहत अद्यतन मार्क-टू-मार्केट मूल्य भी शामिल हैं।

प्रमुख बिंदु:

समेकित दृश्य में ग्राहकों की डीमैट खाता होल्डिंग्स और म्यूचुअल फंड निवेश शामिल हैं।
वर्तमान में, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (CDSL) द्वारा प्रदान किया जाने वाला समेकित खाता विवरण (CAS), प्रतिभूति बाजार में एक समेकित और अद्यतन निवेश दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।

NPS स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन (SOT) को सीएएस के साथ एकीकृत करने का PFRDA का यह नवीनतम कदम प्रत्येक व्यक्ति की वित्तीय संपत्ति का एक व्यापक रिकॉर्ड बनाने के केंद्र के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
वर्तमान में, NPS SOT को वार्षिक आधार पर या तो भौतिक रूप से या ईमेल के माध्यम से साझा किया जाता है और इसे सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (CRA) लॉगिन में ऑनलाइन भी देखा जा सकता है।
अब, PFRDA ने NPS ग्राहकों को CAS में NPS लेनदेन को शामिल करने का विकल्प प्रदान करने के लिए CRA को सेबी के साथ पंजीकृत डिपॉजिटरी के साथ एकीकृत करने में सक्षम बनाया है।
CAS होने से सरलीकृत रिकॉर्ड रखने, बेहतर सुरक्षा और समय पर जानकारी सहित कई लाभ हैं।

PFRDA के बारे में:

स्थापना: 2003
मुख्यालय: नई दिल्ली, दिल्ली
अध्यक्ष: दीपक मोहंती
PFRDA भारत में पेंशन के समग्र पर्यवेक्षण और विनियमन के लिए नियामक निकाय है।
यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में संचालित होता है।

NSDL के बारे में:

स्थापित: अगस्त 1996 में राष्ट्रीय कवरेज के साथ भारत में पहली इलेक्ट्रॉनिक प्रतिभूति डिपॉजिटरी के रूप में।
मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र

RBI ने कई बैंकों में लावारिस जमा की खोज के लिए केंद्रीकृत वेब पोर्टल UDGAM लॉन्च किया

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नागरिकों को उनकी लावारिस जमा राशि की खोज करने में मदद करने के लिए एक केंद्रीकृत वेब पोर्टल लॉन्च किया है, जिसे UDGAM (अनक्लेम्ड डिपॉजिट - गेटवे टू एक्सेस इन्फर्मेशन) के रूप में जाना जाता है।
यह पोर्टल केंद्रीय बैंक द्वारा जनता के लिए एक ही स्थान पर कई बैंकों में उनकी लावारिस जमा राशि की खोज में मदद करने के लिए विकसित किया गया है।
रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड (ReBIT), भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबद्ध सेवाएँ (IFTAS), और भाग लेने वाले बैंकों ने पोर्टल विकसित करने में सहयोग किया है।
इससे पहले, RBI ने 6 अप्रैल, 2023 को केंद्रीकृत वेब पोर्टल के विकास की घोषणा की थी।

मुख्य विचार:

पंजीकरण:

ग्राहक अपने मोबाइल नंबर का उपयोग करके 'उदगम' प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण कर सकते हैं।

खोज प्रक्रिया:

एक बार पंजीकृत होने के बाद, वे अपने नाम के तहत लावारिस जमा की खोज कर सकते हैं और स्थायी खाता संख्या (पैन), मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट नंबर जैसे अतिरिक्त इनपुट प्रदान कर सकते हैं।
इसके बाद ग्राहक अपनी शाखा में केवाईसी प्रक्रिया पूरी करके अपनी जमा राशि पुनः प्राप्त कर सकते हैं।

मृत जमाकर्ता:

यदि जमा-धारक की मृत्यु हो गई है, तो उनके नामांकित व्यक्ति को दस्तावेज़ जमा करने की आवश्यकता होगी।

प्रारंभिक उपलब्धता और कवर किए गए बैंक:

आरंभ करने के लिए, उपयोगकर्ता 7 बैंकों (भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड, साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड और) के संबंध में अपनी लावारिस जमा राशि के विवरण तक पहुंच सकेंगे। सिटीबैंक NA) वर्तमान में पोर्टल पर उपलब्ध है।
पोर्टल पर शेष बैंकों की खोज सुविधा चरणबद्ध तरीके से 15 अक्टूबर, 2023 तक उपलब्ध कराई जाएगी।

लावारिस जमा क्या हैं?

"लावारिस जमा" से तात्पर्य बचत या चालू खातों में रखे गए धन से है
10 वर्षों की अवधि के लिए निष्क्रिय रहे, या सावधि जमा (FD) के मामले में, परिपक्वता तिथि से 10 वर्षों के भीतर वापस नहीं लिया गया है।

नवीनतम समाचार:

जून 2023 में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड - ANTARDRIHSTI लॉन्च किया, जिसका हिंदी अर्थ है अंतर्दृष्टि, प्रासंगिक मापदंडों को पकड़कर वित्तीय समावेशन की प्रगति का आकलन और निगरानी करने के लिए आवश्यक अंतर्दृष्टि प्रदान करना।

RBI के बारे में:

स्थापना: 1 अप्रैल 1935
मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र, भारत
राज्यपाल: शक्तिकांत दास
उप राज्यपाल: महेश कुमार जैन, एम राजेश्वर राव, माइकल पात्रा और टी. रबी शंकर

एक्सिस बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड और MSME ऋण लॉन्च करने के लिए RBI इनोवेशन हब के साथ साझेदारी की

ऐक्सिस बैंक, भारत के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंकों में से एक ने रिज़र्व बैंक द्वारा शुरू किए गए फ्रिक्शनलेस क्रेडिट (PTPFC) के लिए पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म द्वारा संचालित 2 ऋण उत्पाद किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) और असुरक्षित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) ऋण लॉन्च किए हैं। इनोवेशन हब (RBIH), भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

मुख्य विचार:

एक्सिस बैंक मंच द्वारा संचालित छोटे व्यवसाय ग्राहकों को केसीसी और असुरक्षित MSME ऋण की पेशकश करेगा।
दोनों उत्पाद पूरी तरह से डिजिटल तरीके से पेश किए जाएंगे और ग्राहकों को कोई दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मध्य प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड की पेशकश की जाएगी और शुरुआत में यह ग्राहकों को 1.6 लाख रुपये तक में उपलब्ध होगा।
MSME ऋण देश भर में उपलब्ध होंगे और ग्राहकों को 10 लाख रुपये तक के ऋण की पेशकश करेंगे।
पायलट के हिस्से के रूप में, एक्सिस बैंक ग्राहकों के लिए सहमति और सुरक्षित तरीके से डेटा तक पहुंचने के लिए PTPFC का लाभ उठाएगा।
इनमें पैन सत्यापन, आधार इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर (eKYC), अकाउंट एग्रीगेटर डेटा, भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन और बैंक खातों को मान्य करने के लिए पेनी ड्रॉप सेवा शामिल हैं।

एक्सिस बैंक के बारे में:

स्थापना: 1993

मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र, भारत
MD और CEO: अमिताभ चौधरी
टैगलाइन: बढ़ती का नाम जिंदगी

RBIH के बारे में:

स्थापित: 2022
मुख्यालय: बैंगलोर, कर्नाटक
CEO: राजेश बंसल

RBI ने बैंकों से व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को फ्लोटिंग से निश्चित ब्याज दर पर स्विच करने का विकल्प प्रदान करने को कहा है

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों और गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों (NBFC) सहित विनियमित संस्थाओं को निर्देश दिया है कि वे व्यक्तिगत ऋण उधारकर्ताओं को ब्याज दरों को रीसेट करते समय फ्लोटिंग ब्याज दर से निश्चित दर पर स्विच करने का विकल्प प्रदान करें।
इस कदम से उधारकर्ता का लचीलापन बढ़ने और बदलती वित्तीय स्थितियों के साथ तालमेल बिठाने की उम्मीद है।
समान मासिक किस्तों (EMI) आधारित व्यक्तिगत ऋणों पर फ्लोटिंग ब्याज दर के रीसेट पर एक परिपत्र में RBI ने कहा कि उधारकर्ताओं को EMI में वृद्धि या अवधि बढ़ाने का विकल्प चुनने का विकल्प भी दिया जाएगा।
RBI ने बैंकों और ऋणदाताओं के लिए इन व्यक्तिगत ऋण निर्देशों को 31 दिसंबर, 2023 तक लागू करने की समय सीमा तय की है।
मौजूदा और नए दोनों ऋणों को इन निर्देशों का पालन करना होगा।

मुख्य विचार:

पर्सनल लोन में फिक्स्ड और फ्लोटिंग ब्याज दरों की दोनों श्रेणियां होंगी।
उधारकर्ताओं को विनियमित संस्थाओं की बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार एक निश्चित दर पर स्विच करने का विकल्प प्रदान किया जाना चाहिए।
किसी उधारकर्ता को ऋण की अवधि के दौरान कितनी बार स्विच करने की अनुमति दी जाएगी, यह पॉलिसी में निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।
RBI की परिभाषा के अनुसार, व्यक्तिगत ऋण व्यक्तियों को दिए गए ऋण हैं और इसमें उपभोक्ता ऋण, शिक्षा ऋण, अचल संपत्तियों (जैसे आवास ऋण) के निर्माण या वृद्धि के लिए दिए गए ऋण और वित्तीय संपत्तियों (शेयर) में निवेश के लिए दिए गए ऋण शामिल हैं।

फ्लोटिंग ब्याज दरें क्या हैं?

फ्लोटिंग ब्याज दर वह ब्याज दर है जो समय-समय पर बदलती रहती है।
ब्याज की दर ऊपर-नीचे होती रहती है, या "तैरती" है, जो आर्थिक या वित्तीय बाज़ार की स्थितियों को दर्शाती है।
फ्लोटिंग ब्याज दर को समायोज्य या परिवर्तनीय ब्याज दर के रूप में भी संदर्भित किया जा सकता है क्योंकि यह ऋण दायित्व की अवधि के अनुसार भिन्न हो सकती है।
फ्लोटिंग ब्याज दर आधार के रूप में संदर्भ दर का उपयोग करती है
फ्लोटिंग दर पर पहुंचने के लिए, संदर्भ दर में एक स्प्रेड (या मार्जिन) जोड़ा जाता है।
फ्लोटिंग ब्याज दर = आधार दर + स्प्रेड

इन दरों को त्रैमासिक, अर्ध-वार्षिक या वार्षिक आधार पर समायोजित किया जा सकता है।

RBI के बारे में:

स्थापना: 1 अप्रैल 1935
मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र, भारत
राज्यपाल: शक्तिकांत दास
उप राज्यपाल: महेश कुमार जैन, एम राजेश्वर राव, माइकल पात्रा और टी. रबी शंकर

यस बैंक ने उपभोक्ताओं के लिए मोबाइल बैंकिंग अनुभव को बदलने के लिए नया मोबाइल बैंकिंग ऐप 'आइरिस' पेश किया

निजी ऋणदाता यस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए डिजिटल बैंकिंग को फिर से परिभाषित करने के उद्देश्य से 'आईरिस' नाम से अपना अत्याधुनिक मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन पेश किया।

'आइरिस' के बारे में:

'आइरिस' मूल्यवान ग्राहक प्रतिक्रिया के साथ सह-निर्मित एक व्यापक वित्तीय मंच है।
ऐप को मौजूदा और नए दोनों ग्राहकों को सेवा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
यह एक ही मंच के माध्यम से 100 से अधिक कार्यात्मकताओं तक पहुंच प्रदान करते हुए सुविधाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है।

प्रमुख विशेषताऐं:

बचत खाता: उपयोगकर्ता ऐप के माध्यम से वास्तविक समय में आसानी से बचत खाता खोल सकते हैं।
क्रेडिट कार्ड: उपयोगकर्ता यस बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं और बैंक द्वारा पेश किए गए कार्ड विकल्पों की विस्तृत श्रृंखला में से चुन सकते हैं।
सेकंड में ऋण: ऐप पर ही त्वरित अनुमोदन के साथ यस बैंक के ऋण उत्पादों के समूह तक पहुंच।
जमा: आवर्ती और सावधि जमा को ऐप के माध्यम से कभी भी बुक किया जा सकता है।
आसान भुगतान: ऐप पर निर्बाध और परेशानी मुक्त भुगतान करने के लिए कई डिजिटल मोड का लाभ उठाया जा सकता है।
निवेश: निवेश विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच जिसे व्यक्तिगत जोखिम क्षमता और वित्तीय लक्ष्यों के आधार पर अनुकूलित किया जा सकता है।
बीमा: उपयोगकर्ता यस बैंक ऐप द्वारा आईरिस में एकीकृत बीमा सेवाओं की एक श्रृंखला में से चुन सकते हैं।
यह बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, सिम बाइंडिंग के साथ-साथ दो-कारक सत्यापन जैसी सर्वोत्तम श्रेणी की सुरक्षा सुविधाओं को शामिल करके ग्राहकों के वित्तीय डेटा की सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है।

यस बैंक के बारे में:

स्थापना: 2004
मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र
MD और CEO: प्रशांत कुमार
टैगलाइन: एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टीज़

RBI की मौद्रिक नीति की मुख्य बातें: रेपो दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखा गया; FY24 के लिए खुदरा मुद्रास्फीति 5.4% आंकी गई

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास घोषणा की कि मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने सर्वसम्मति से लगातार तीसरी बार रेपो दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है।

RBI की नीति दरें:

वर्ग	दर
रेपो दर	6.5%
रिवर्स रेपो रेट	3.35
स्थायी जमा सुविधा	6.25%
सीमांत खड़े होने की सुविधा	6.75%
GDP वृद्धि का अनुमान	6.5%
सी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPR) मुद्रास्फीति	5.4%
बैंक दर	6.75%
नकद आरक्षित अनुपात (CRR)	4.50%
वैधानिक तरलता अनुपात (SLR)	18%

मुख्य विचार:

2023-24 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान है, जबकि 2023-24 की पहली तिमाही 8.0% रहेगी; Q2 6.5% पर; Q3 6.0% पर; और Q4 5.7% और Q1FY25 6.6% पर।

सरकार ने RBI को दोनों तरफ 2% के मार्जिन के साथ सीपीआई मुद्रास्फीति को 4% पर सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।

बैंकिंग प्रणाली में ₹2000 के नोटों की वापसी सहित विभिन्न कारकों द्वारा उत्पन्न अधिशेष तरलता को अवशोषित करने के लिए, RBI ने बैंकों से 19 मई और 28 जुलाई, 2023 के बीच अपनी जमा में वृद्धि पर 10% का वृद्धिशील नकद आरक्षित अनुपात (ICRR) बनाए रखने के लिए कहा है।

RBI एक रूपरेखा लेकर आएगा जो उधारकर्ताओं को फ्लोटिंग ब्याज दरों से निश्चित ब्याज दरों पर स्विच करने की अनुमति देगा और इस कदम से गृह, ऑटो और अन्य ऋण उधारकर्ताओं को राहत मिलेगी।

RBI ने कहा है कि वह उदार नीतिगत रुख को वापस लेने पर ध्यान केंद्रित करेगा।

MPC के बारे में:

मौद्रिक नीति समिति (MPC) केंद्र सरकार द्वारा गठित और आरबीआई के गवर्नर के नेतृत्व वाली एक समिति है।

MPC का गठन विशेष लक्ष्य स्तर के भीतर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए बेंचमार्क नीति ब्याज दर (रेपो रेट) तय करने के मिशन के साथ किया गया था।

MPC के सदस्य:

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर - अध्यक्ष, पदेन-शक्तिकांत दास
मौद्रिक नीति के प्रभारी बैंक के उप गवर्नर-माइकल देब्रता पात्रा
मौद्रिक नीति के प्रभारी बैंक के कार्यकारी निदेशक - राजीव रंजन
आशिमा गोयल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य हैं
शशांक भिडे नई दिल्ली स्थित थिंक-टैंक नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च में वरिष्ठ सलाहकार हैं।
जयन्त वर्मा भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद में वित्त और लेखा प्रोफेसर हैं।
RBI MPC की अगली बैठक 4-6 अक्टूबर, 2023 को होगी।

RBI के बारे में:

स्थापना: 1 अप्रैल 1935
मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र, भारत
राज्यपाल: शक्तिकांत दास
उप राज्यपाल: महेश कुमार जैन, एम राजेश्वर राव, माइकल पात्रा और टी. रबी शंकर

NPCI ने सुरक्षित और आसान डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए UPI चलेगा 3.0 अभियान शुरू किया

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) UPI की ब्रांड जागरूकता को बढ़ावा देने, इसकी विशेषताओं की समझ को बढ़ाने और नए उपयोगकर्ताओं के बीच व्यापक अपनाने को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) सुरक्षा जागरूकता अभियान, "UPI चलेगा" का तीसरा संस्करण लॉन्च किया गया।
यह उपयोगकर्ताओं को UPI LITE जैसी विभिन्न सुविधाओं के बारे में भी शिक्षित करता है, जो तेजी से कम मूल्य के लेनदेन को सक्षम बनाता है; UPI ऑटोपे, जो किसी भी UPI एप्लिकेशन का उपयोग करके सुरक्षित और सुविधाजनक आवर्ती भुगतान की अनुमति देता है; और UPI इंटरऑपरेबिलिटी, जो सभी UPI-सक्षम अनुप्रयोगों के बीच निर्बाध धन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करती है।

मुख्य विचार:

यह अभियान 2020 में वित्तीय साक्षरता सलाहकार समिति (FLAC) के मार्गदर्शन के तहत शुरू किया गया था।
UPI चलेगा अभियान 1.0 और 2.0 ने UPI की पहुंच बढ़ाने, उपयोगकर्ताओं को इसकी सुरक्षा के बारे में शिक्षित करने और विभिन्न लेनदेन के लिए इसके उपयोग में आसानी को बढ़ाने, इसे पसंदीदा भुगतान विकल्प बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

NPCI के बारे में:

स्थापित: 2008
मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र, भारत
MD और CEO: दिलीप अस्बे
NPCI भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक प्रमुख संगठन है।
यह भारत में एक मजबूत भुगतान और निपटान बुनियादी ढांचा बनाने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के तहत भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और भारतीय बैंक संघ (IBA) की एक पहल है।

IIITD-IC ने भारतीय स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए यस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

IIITD इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन सेंटर (IIITD-IC), इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली (IIITD) द्वारा प्रवर्तित सेक्शन 8 कंपनी ने उद्यम बैंकिंग, व्यक्तिगत बैंकिंग और स्टार्टअप्स के लिए आवश्यक बैंकिंग समाधानों से परे सक्षम करने के उद्देश्य से यस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।

साझेदारी के बारे में:

इस साझेदारी के माध्यम से, यस बैंक बैंक के यस हेडस्टार्टअप कार्यक्रम के तहत IITD-IC में विकास के चरण में चल रहे स्टार्टअप को सर्वश्रेष्ठ-इन-क्लास बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करेगा, जो स्टार्टअप के लिए एक समर्पित कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य इस सेगमेंट को गतिशील और चुस्त पेशकशों के साथ पूरा करना है।

इनमें केवल 5 कर्मचारियों वाले स्टार्टअप के लिए वेतन खाते का प्रस्ताव, व्यवसाय और व्यक्तिगत उपयोग के लिए क्रेडिट कार्ड के लिए एक वैकल्पिक सीमा, साथ ही एक API सैंडबॉक्स सुविधा शामिल है।

यस बैंक स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (CGSS) को अपनाने वाले देश के पहले बैंकों में से एक है, जो इन उभरती संस्थाओं को IPO तक अपने विचारों की यात्रा को आगे बढ़ाने और आगे बढ़ने में मदद करेगा।

यस बैंक के बारे में:

स्थापना: 2004

मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र, भारत

MD और CEO: प्रशांत कुमार

टैगलाइन: एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टीज़

हेलिओस कैपिटल को म्यूचुअल फंड कारोबार शुरू करने के लिए सेबी से मंजूरी मिल गई है

समीर अरोड़ा-प्रवर्तित हेलिओस कैपिटल मैनेजमेंट को म्यूचुअल फंड (MF) व्यवसाय शुरू करने के लिए पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) से अंतिम मंजूरी मिल गई है।

एक बार लॉन्च होने के बाद, हेलिओस म्यूचुअल फंड 46 लाख करोड़ रुपये की प्रबंधन अधीन संपत्ति के साथ इस सबसे अधिक गुलजार उद्योग में प्रवेश करने वाली 46 वीं इकाई बन जाएगी।

इतिहास:

फरवरी 2021 में, हेलिओस कैपिटल मैनेजमेंट पीटीई लिमिटेड, जो पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं का व्यवसाय है, ने सेबी के साथ म्यूचुअल फंड लाइसेंस के लिए आवेदन किया था।

सितंबर 2022 में, हेलिओस कैपिटल को म्यूचुअल फंड व्यवसाय शुरू करने के लिए सेबी की सैद्धांतिक मंजूरी मिली।

मुख्य विचार:

इसके अलावा, ज़ेरोधा ब्रोकिंग लिमिटेड और ओल्ड ब्रिज कैपिटल मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड दो संस्थाएं हैं जो म्यूचुअल फंड लाइसेंस के लिए सेबी की अंतिम मंजूरी का इंतजार कर रही हैं।

अन्य 3 संस्थाएं - यूनिफी कैपिटल, अल्फा अल्टरनेटिव्स फंड एडवाइजर्स और विजमार्केट्स एनालिटिक्स एमएफ क्षेत्र में प्रवेश के लिए सेबी की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं।

नवीनतम समाचार:

जून, 2023 में बजाज फिनसर्व म्यूचुअल फंड 43वीं संपत्ति प्रबंधन कंपनी बन गई।

भारतीय बैंक संघ ने गिफ्ट सिटी में क्षेत्रीय समिति का गठन किया

भारतीय बैंक संघ (IBA) ने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट सिटी), गांधीनगर, गुजरात के भीतर काम करने वाले सदस्य बैंकों के लिए एक क्षेत्रीय समिति का गठन किया है।
IBA ने GIFT सिटी के भीतर परिचालन करने वाले बैंकों के अद्वितीय नियामक परिदृश्य और चुनौतियों का समाधान करने के लिए क्षेत्रीय समिति का गठन किया है।
GIFT सिटी में वर्तमान में 26 बैंक हैं।

समिति के बारे में:

समिति बैंकिंग उद्योग और नियामकों के बीच एक पुल के रूप में कार्य करेगी, यह सुनिश्चित करते हुए कि चिंताओं और दृष्टिकोणों को प्रभावी ढंग से संप्रेषित और संबोधित किया जाए।
इससे पहले, बैंकों ने व्यक्तिगत रूप से अपने सामने आने वाले मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) के समक्ष उठाया था।
सेक्टोरल कमेटी की स्थापना गिफ्ट सिटी के भीतर सभी बैंकों की सामान्य चिंताओं को सुव्यवस्थित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

IBA के बारे में:

स्थापना: सितंबर 1946
मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र
मुख्य कार्यकारी अधिकारी: सुनील मेहता

वित्त वर्ष 24 में पहली बार भारत की बैंकिंग प्रणाली की तरलता घाटे में चली गई

भारतीय रिज़र्व बैंक के अस्थायी तरलता निकासी कदम और कर बहिर्प्रवाह के बाद इस वित्तीय वर्ष में पहली बार भारत की बैंकिंग प्रणाली की तरलता घाटे में चली गई है।
RBI के आंकड़ों के मुताबिक, 21 अगस्त तक बैंकिंग प्रणाली की तरलता घाटे या 236 अरब रुपये (2.84 अरब डॉलर) पर थी। इस महीने (अगस्त 2023) की शुरुआत में अधिशेष 2.8 ट्रिलियन रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था, लेकिन तब से इसमें गिरावट आ रही है, खासकर जब RBI ने बैंकों को जमा में वृद्धि पर 10% की वृद्धिशील नकद आरक्षित अनुपात (CRR) रखने के लिए कहा था। 19 मई और 28 जुलाई को एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की निकासी हुई।

LIC ने डीमर्जर कार्रवाई के माध्यम से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में 6.66% हिस्सेदारी हासिल की

भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की अलग हुई वित्तीय इकाई जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में 6.660 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है।
बीमाकर्ता ने कहा कि कंपनी के 19 जुलाई के नोटिस के अनुसार गैर-बैंकिंग वित्तीय इकाई के डिमर्जर के माध्यम से किए गए अधिग्रहण की लागत रिलायंस इंडस्ट्रीज की पूर्व-डिमर्जर लागत का 4.68 प्रतिशत है।
इस बीच, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज (JFS) के शेयरों ने लिस्टिंग के बाद अपने पहले कारोबारी सत्र में लोअर सर्किट मारा। स्टॉक को 265 रुपये प्रति शेयर पर सूचीबद्ध किया गया था, जो कि कंपनी के अलग होने की तारीख, 20 जुलाई को इसके व्युत्पन्न मूल्य 261.85 रुपये से 1 प्रतिशत से अधिक का मामूली प्रीमियम है।
ट्रेडिंग शुरू होने पर जेएफएस का कुल बाजार पूंजीकरण 1.68 लाख करोड़ रुपये से घटकर 1.6 लाख करोड़ रुपये से कम हो गया था।

JFS के बारे में:

जियो फाइनेंशियल सर्विसेज छह कंपनियों में निवेश के साथ एक वित्तीय सेवा कंपनी है: रिलायंस इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स एंड होल्डिंग्स (RIIHL), रिलायंस पेमेंट सॉल्यूशंस, रिलायंस रिटेल फाइनेंस, जियो पेमेंट्स बैंक, जियो इंफॉर्मेशन एग्रीगेटर सर्विसेज और रिलायंस रिटेल इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड।

स्थापित: 2017

संस्थापक: मुकेश अंबानी

LIC के बारे में:

स्थापित:1 सितंबर 1956

MD: सिद्धार्थ मोहंती

मुख्यालय: मुंबई, भारत

GIFT IFSC पर कुल बैंकिंग लेनदेन जुलाई 2023 तक 508 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया

यहां GIFT इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर (IFSC) में कुल बैंकिंग लेनदेन जुलाई 2023 तक 508 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया।

गिफ्ट IFSC के कार्यकारी निदेशक दीपेश शाह ने कहा कि जुलाई 2023 तक गिफ्ट IFSC में कुल बैंकिंग परिसंपत्ति का आकार 41.20 अरब डॉलर था और बैंकों द्वारा बुक किए गए संचयी डेरिवेटिव लेनदेन 632 अरब डॉलर थे।

जुलाई 2023 तक GIFT IFSC में कुल 545 से अधिक IFSCA पंजीकृत संस्थाएँ थीं, जिनमें 25 विमान और शिपिंग इकाइयाँ शामिल थीं, और जुलाई 2023 में IFSC अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज पर मासिक कारोबार 60.33 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

IFSCA की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार, 31 मार्च, 2023 तक GIFT IFSC में कुल 20 IFSC बैंकिंग इकाइयाँ चालू थीं। 31 मार्च, 2023 से पहले लाइसेंस प्राप्त करने वाले दो और IBU के वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान परिचालन शुरू करने की उम्मीद है।

GIFT IFSC के बारे में:

स्थापित: अप्रैल 2015

मुख्यालय: गांधी नगर, गुजरात

CEO: अजय पांडे

कैशफ्री पेमेंट्स ने व्यवसायों के खरीद-से-भुगतान चक्र को कारगर बनाने के लिए 'विक्रेता भुगतान' पेश किया

कैशफ्री पेमेंट्स, भारत के अग्रणी भुगतान और API बैंकिंग समाधान प्रदाता, ने 'वेंडर पेमेंट्स' पेश किया, जो एक व्यापक मंच है जो व्यवसायों को सक्षम बनाता है।अनुकूलनऔर उनके खरीद-से-भुगतान चक्र का प्रबंधन करें, दक्षता बढ़ाएं और प्रसंस्करण समय कम करें।

'विक्रेता भुगतान' न केवल विक्रेता भुगतान को सुव्यवस्थित करता है, बल्कि उपयोगिता बिल भुगतान, अन्य व्यावसायिक व्यय और कर भुगतान जैसे अन्य खाते के भुगतान को भी सुव्यवस्थित करता है।

'विक्रेता भुगतान' उपयोगकर्ताओं को आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त चालान और अन्य खाते में देय भुगतान को मैन्युअल रूप से या लेखांकन सॉफ़्टवेयर से आयात करके आसानी से इनपुट करने की अनुमति देता है।

थोक चालान अपलोड भी समर्थित हैं, जिससे व्यवसायों को बढ़ी हुई दक्षता के लिए एक ही समय में कई चालान संसाधित करने की अनुमति मिलती है।

इसी तरह, व्यवसाय भुगतान के लिए लाभार्थी की जानकारी जोड़ने और आसानी से चालान जानकारी जमा करने में सक्षम होंगे।
चालान विवरण अपडेट हो जाने के बाद व्यवसाय अवैतनिक चालान के लिए एकल या बैच प्रतिपूर्ति शुरू कर सकते हैं।

विक्रेता भुगतान के लाभ:

यह अधिकतम लचीलेपन के लिए तत्काल भुगतान सेवा (IMPS), नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT), इंटरबैंक फंड ट्रांसफर (IFT), और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) सहित विभिन्न भुगतान विधियों को भी स्वीकार करता है।
बकाया चालान और भुगतान स्थितियों के सुचारू समन्वयन के लिए, 'विक्रेता भुगतान' टैली, टैली प्राइम और अन्य ईआरपी जैसे सामान्य लेखांकन कार्यक्रमों से जुड़ता है।
लेखांकन सॉफ्टवेयर के साथ एकीकरण के कारण भुगतान डेटा को आसानी से निर्यात किया जा सकता है और उसका समाधान किया जा सकता है।

कैशफ्री भुगतान के बारे में:

स्थापित: 2015 IIT खड़गपुर द्वारा
मुख्यालय: बेंगलुरु, कर्नाटक
CEO और सह-संस्थापक: आकाश सिन्हा

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया योग्य संस्थागत नियोजन के माध्यम से 5,000 करोड़ रुपये तक जुटाएगा

यूनियन बैंक ने शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा कि पूंजी कोष जुटाने पर निदेशकों की एक समिति ने योग्य संस्थान नियोजन (QIP) के जरिये इक्विटी शेयर जारी कर 5,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जुटाने को मंजूरी दे दी है।
एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, समिति ने "इश्यू के उद्घाटन को मंजूरी दे दी" और "91.10 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के फ्लोर प्राइस को मंजूरी दे दी।"
राज्य द्वारा संचालित ऋणदाता के अनुसार, पैनल ने "आवश्यक नियामक/वैधानिक अनुमोदन के अधीन योग्य संस्थागत प्लेसमेंट के माध्यम से इक्विटी शेयर जारी करके 5,000 करोड़ रुपये से अधिक नहीं" धन जुटाने को मंजूरी दे दी।
यूनियन बैंक ने एक अन्य एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि समिति 24 अगस्त, 2023 को फिर से बैठक करेगी, जिसमें प्रस्ताव के तहत पात्र संस्थागत खरीदारों को वितरित किए जाने वाले इक्विटी शेयरों के लिए "छूट, यदि कोई हो, सहित) जारी मूल्य पर विचार और अनुमोदन किया जाएगा"।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में:

स्थापित: 1919
मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र
CEO: ए. मणिमेखलै
टैगलाइन: गुड पीपल टू बैंक विथ

पंजाब नेशनल बैंक ने विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस पर PNB पेंशनर लाउंज का उद्घाटन किया

विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस (21 अगस्त, 2023) पर, देश के अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने "पेंशनर्स लाउंज" की शुरुआत की है, जो शाखा के भीतर एक समर्पित स्थान है जो पेंशनभोगियों और वरिष्ठ नागरिकों को उनकी सभी बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करता है।

उद्देश्य:

व्यापक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हुए पेंशनभोगियों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक विशेष और आरामदायक स्थान प्रदान करना।

पेंशनभोगी लाउंज के बारे में:

शाखा स्थान:

पेंशनर लाउंज वर्तमान में दिल्ली-NCR, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, हैदराबाद, चंडीगढ़, जयपुर, शिमला और वाराणसी सहित 11 स्थानों पर उपलब्ध है।

सेवाएं दी गईं:

लाउंज पेंशनभोगियों और वरिष्ठ नागरिकों की आवश्यकताओं के अनुरूप बैंकिंग सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है।

इसका उद्देश्य उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करते हुए एक सहज और सुविधाजनक बैंकिंग अनुभव प्रदान करना है।

पुस्तिका "स्पंदन":

इस अवसर पर, PNB के प्रबंध निदेशक और CEO, अतुल कुमार गोयल ने वरिष्ठ नागरिकों और पेंशनभोगियों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन की गई विभिन्न बैंक योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करने के लिए "स्पंदन" नामक एक सूचनात्मक पुस्तिका का अनावरण किया।

नवीनतम समाचार:

जुलाई 2023 में, पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने अपनी पर्यावरण पहल 'PNB पलाश' शुरू की, जो स्थिरता को अपनाने के लिए 8 महीने की अवधि का अभियान है।

PNB के बारे में:

स्थापना: 19 मई 1894

मुख्यालय: द्वारका, दिल्ली, भारत

MD एवं CEO: अतुल कुमार गोयल

टैगलाइन: यू कैन बैंक अपॉन

SBI लाइफ इंश्योरेंस उपभोक्ताओं को बिक्री से पहले और बाद की सेवाएं प्रदान करने के लिए 24X7 इनबाउंड संपर्क केंद्र शुरू करने वाला पहला भारतीय निजी जीवन बीमाकर्ता बन गया है

देश की सबसे भरोसेमंद निजी जीवन बीमा कंपनियों में से एक SBI लाइफ इंश्योरेंस ने कंपनी द्वारा प्रदान किए गए व्यापक बीमा समाधानों से संबंधित खरीद से पहले और बाद के प्रश्नों को संबोधित करने के लिए टोल-फ्री नंबर 18002679090 के माध्यम से अपना समर्पित 24×7 इनबाउंड संपर्क केंद्र लॉन्च किया।

इस प्रकार, SBI लाइफ इतनी व्यापक ग्राहक देखभाल सहायता वाली देश की पहली निजी जीवन बीमा कंपनी बन गई है, जो ग्राहक अनुभव को समृद्ध करने और उनकी सुविधानुसार उनकी बीमा आवश्यकताओं/प्रश्नों को संबोधित करने में कंपनी की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।

बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) द्वारा निर्धारित '2047 तक सभी के लिए बीमा' के लक्ष्य को देखते हुए, इस संख्या में आगे चलकर सकारात्मक वृद्धि देखने को मिलेगी।

SBI लाइफ के 24X7 इनबाउंड संपर्क केंद्र के बारे में:

संपर्क केंद्र मौजूदा और भावी दोनों उपभोक्ताओं के लिए वर्ष के 365 दिन उपलब्ध कराया जाता है।

24X7 ग्राहक सेवा सहायता के माध्यम से, बीमा कंपनी का लक्ष्य प्रशिक्षित पेशेवरों के साथ निर्बाध पहुंच और बातचीत को फिर से परिभाषित करना है।
ग्राहक सेवा सहायता की वर्तमान क्षमता सालाना लगभग 13 लाख कॉलों को संभालने की अनुमति देती है।
कंपनी के पास एक इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पॉन्स सिस्टम (IVRS) भी है, जिसमें 13 सेल्फ-सर्विस विकल्प हैं।

SBI लाइफ इंश्योरेंस के बारे में:

अक्टूबर 2000 में निगमित किया गया और मार्च 2001 में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) के साथ पंजीकृत किया गया।
मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र, भारत
MD और CEO: श्री महेश कुमार शर्मा
टैगलाइन: अपने लिए, अपनों के लिए

IFC ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और कम आय वाले समूहों के आवास को बढ़ावा देने में मदद के लिए IIFL होम फाइनेंस में 100 मिलियन डॉलर का निवेश किया है

विश्व बैंक समूह का एक सदस्य अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC), एक प्रमुख आवास वित्त कंपनी IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड (IIFL HFL) में $100 मिलियन तक का निवेश करने के लिए तैयार है, जिसका उद्देश्य भारत में महिला उधारकर्ताओं सहित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) और कम आय वाले समूहों (LIG) के लिए आवास वित्त तक पहुंच बढ़ाना है।
यह निवेश भारत के किफायती आवास क्षेत्र को उत्प्रेरित करने, पर्यावरण के अनुकूल निर्माण प्रथाओं को बढ़ावा देने और भारत के जलवायु उद्देश्यों में योगदान करने के लिए तैयार है।

मुख्य विचार:

ऋण निधि विवरण:

फंडिंग को गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (NCD) के रूप में संरचित किया गया है और इसकी राशि $100 मिलियन है।
इसमें 8.32% की कूपन दर के साथ 6 साल का कार्यकाल है।

साझेदारी का फोकस:

IIFL होम फाइनेंस और IFC के बीच साझेदारी में हाउसिंग फाइनेंस के विशिष्ट क्षेत्रों को बढ़ावा देने पर दोहरा फोकस है।

साझेदारी की विशेषताएं:

इस साझेदारी के अंतर्गत, 50% धनराशि महिला उधारकर्ताओं के लिए आवास वित्त का समर्थन करने के लिए निर्धारित की गई है।
शेष 50% फंडिंग खरीदारों के लिए हरित आवास के वित्तपोषण के लिए समर्पित है।
पूरी सुविधा किफायती आवास के लिए तैनात की जाएगी।
यह भारत में महिला उधारकर्ताओं सहित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) और निम्न-आय समूहों (LIG) के बीच आवास वित्त तक पहुंच बढ़ाने में मदद करेगा।
भारत के तीव्र शहरीकरण ने 2030 तक 38 मिलियन आवास इकाइयों की अनुमानित आवश्यकता के साथ किफायती आवास की मांग को तेज कर दिया है।
इस मांग में EWS और LIG सेगमेंट की हिस्सेदारी 96% से अधिक है।
IFC के अनुमान से पता चलता है कि अब से 2030 के बीच 1.25 ट्रिलियन डॉलर के अवसर का प्रतिनिधित्व करने के बावजूद, भारत का हरित भवन बाजार आवासीय भवनों का केवल 6% है।

IIFL HFL एक विविध वित्तीय सेवा कंपनी IIFL फाइनेंस लिमिटेड की सहायक कंपनी है।

IFC के बारे में:

स्थापना: 20 जुलाई, 1956
मुख्यालय: वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स
प्रबंध निदेशक: मुख्तार दीप
सदस्यता: 186 देश
IFC एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो कम विकसित देशों में निजी क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए निवेश, सलाहकार और परिसंपत्ति-प्रबंधन सेवाएं प्रदान करता है।

केंद्रीय सतर्कता आयोग ने बैंक धोखाधड़ी पर सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया

केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) ने बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्रों में धोखाधड़ी गतिविधियों को संबोधित करने के लिए नई दिल्ली मुख्यालय वाले बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी सलाहकार बोर्ड (ABBFF) का पुनर्गठन किया है।

ABBFL के कार्य:

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) जैसी एजेंसियों द्वारा जांच के लिए सिफारिशें या संदर्भ दिए जाने से पहले ABBFF बैंक धोखाधड़ी की प्रथम स्तर की जांच करता है।
सभी PSB, सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों को अब ₹3 करोड़ और उससे अधिक की धोखाधड़ी के सभी मामलों को सलाह के लिए ABBFF के पास भेजना आवश्यक है।

अध्यक्ष एवं सदस्य:

सुरेश एन पटेल पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, पुनर्गठित ABBFF के अध्यक्ष होंगे।
अध्यक्ष के अलावा, ABBFF में 4 सदस्य भी होंगे, जिनमें रविकांत, रजनीकांत मिश्रा, डेविड रसकिन्हा और पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता शामिल हैं।

अवधि अवधि:

ABBFF के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 2 साल के लिए होगा, जो 21 अगस्त 2023 से प्रभावी होगा।

CAMSfinserv ने अकाउंट एग्रीगेटर्स प्लेटफॉर्म पर 17 एसेट मैनेजमेंट कंपनियों को शामिल किया है

CAMSfinserv भारत में पहले RBI-लाइसेंस प्राप्त अकाउंट एग्रीगेटर्स (एए) में से एक, ने CAMS द्वारा सेवा प्राप्त सभी 17 एसेट मैनेजमेंट कंपनियों को एए प्लेटफॉर्म पर वित्तीय सूचना प्रदाताओं के रूप में शामिल किया है, जिससे यह म्यूचुअल फंड डेटा तक पहुंच प्रदान करने वाला उद्योग में पहला बन गया है।
ग्राहक एक ही और सुरक्षित प्लेटफॉर्म से अपने म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स और बैंक खाते के लेनदेन दोनों तक पहुंच और साझा कर सकेंगे, अपने निवेश को ट्रैक कर सकेंगे, उन क्षेत्रों की पहचान कर सकेंगे जहां वे बचत कर सकते हैं और बेहतर वित्तीय निर्णय ले सकेंगे।
इससे परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों को अपने वित्तीय डेटा की पहुंच और प्रबंधन को सरल बनाकर ग्राहकों को आकर्षित करने और बनाए रखने, जोखिम प्रबंधन में सुधार, अनुपालन सुनिश्चित करने, वित्तीय पेशकशों को निजीकृत करने और मौजूदा परिचालन प्रक्रियाओं में सुधार या नवाचार करने में मदद मिलेगी।

अकाउंट एग्रीगेटर क्या है?

अकाउंट एग्रीगेटर एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जो एक अनुबंध के तहत अपने ग्राहकों से संबंधित वित्तीय जानकारी प्राप्त करने या एकत्र करने की सेवा प्रदान करने के व्यवसाय में लगी हुई है।

CAMS के बारे में:

प्रबंध निदेशक: अनुज कुमार

CAMSfinserv बैंक, एमएफ, बीमाकर्ता, डिपॉजिटरी और जीएसटीएन सहित 54 संस्थाओं के साथ वित्तीय सूचना प्रदाता के रूप में अपने प्लेटफॉर्म पर लाइव अकाउंट एग्रीगेटर का नेतृत्व कर रहा है।

एक्सिस बैंक ने क्रेडिट कार्ड धारकों को यात्रा लाभ देने के लिए क्लियरट्रिप के साथ साझेदारी की घोषणा की

क्लियरट्रिप फ्लिपकार्ट की सहायक कंपनी ने एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्डधारकों के लिए एक अभिनव यात्रा प्रस्ताव पेश करने के लिए भारत में एक प्रमुख निजी क्षेत्र के बैंक एक्सिस बैंक के साथ हाथ मिलाया है।

उद्देश्य:

क्लियरट्रिप के माध्यम से बुकिंग करने वाले मौजूदा और नए दोनों कार्डधारकों को यात्रा लाभ की एक श्रृंखला प्रदान करना। इस सहयोग के तहत, ग्राहकों को घरेलू उड़ान बुकिंग के लिए कई विशेषाधिकार प्राप्त होंगे, जिसमें 1,200 रुपये तक की सीट बुकिंग पर छूट, 500 रुपये तक का मानार्थ भोजन, सुविधा शुल्क से छूट और सीटी फ्लेक्समैक्स के तहत 1 रुपये में उड़ानों को रद्द करने और पुनर्निर्धारित करने का विकल्प शामिल है।

एक्सिस बैंक के बारे में:

स्थापना: 3 दिसंबर 1993

मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र, भारत

MD एवं CEO: अमिताभ चौधरी

टैगलाइन: बढ़ती का नाम जिंदगी

क्लियरट्रिप के बारे में:

स्थापित: जुलाई 2006

मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र

CEO: अय्यप्पन आर

क्लियरट्रिप एक वैश्विक ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी है, जो भारत और मध्य पूर्व के देशों में उड़ानों, ट्रेन टिकटों, होटल आरक्षण और गतिविधियों की बुकिंग के लिए एक ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर वेबसाइट संचालित करती है।

BoB ने परेशानी मुक्त KYC अपडेट के लिए वीडियो री-KYC सेवा शुरू की है

बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) सरकारी स्वामित्व वाले बैंक ने ग्राहक पहचान दस्तावेजों के आवधिक अद्यतन को सरल बनाने के लिए 'वीडियो री-KYC' सेवा शुरू की है।

यह सेवा व्यक्तिगत निवासी ग्राहकों को किसी भौतिक शाखा में जाने की आवश्यकता के बिना अपने 'अपने ग्राहक को जानें' (KYC) विवरण अपडेट करने की अनुमति देती है।

पात्रता मापदंड:

वीडियो KYC सुविधा का लाभ उठाने के लिए, ग्राहकों को 18 वर्ष से अधिक आयु का भारतीय निवासी होना चाहिए और उनके पास अपना आधार नंबर और मूल पैन कार्ड होना चाहिए।

प्रक्रिया एवं समय:

वीडियो री-केवाईसी कॉल सभी कार्य दिवसों पर व्यावसायिक घंटों (सुबह 10:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक) के दौरान की जाएगी।
ग्राहकों को वीडियो कॉल के माध्यम से सत्यापित किया जाता है, जिससे उनकी पहचान और केवाईसी दस्तावेजों की सटीकता सुनिश्चित होती है।

अनिवार्य आवश्यकता:

KYC का आवधिक अद्यतनीकरण (पुनः-KYC) RBI की एक अनिवार्य आवश्यकता है और ग्राहकों को KYC अपडेट होने पर तुरंत अपने केवाईसी दस्तावेजों को बैंक में अपडेट करना होगा।

वीडियो KYC का विस्तार:

BoB ने पूर्ण डिजिटल बचत खाते खोलने के लिए 2021 में वीडियो KYC की शुरुआत की।
बैंक ने अब अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए वीडियो KYC को री-KYC सुविधा के लिए बढ़ा दिया है।

वीडियो री-KYC का महत्व:

वीडियो री-KYC बैंकिंग सेवाओं में बढ़ते डिजिटलीकरण के साथ संरेखित है।
इससे ग्राहकों को शाखाओं में भौतिक रूप से जाने की आवश्यकता कम हो जाती है, जिससे समय और प्रयास की बचत होती है।

BOB के बारे में:

स्थापना: 20 जुलाई 1908
मुख्यालय: वडोदरा, गुजरात, भारत
MD और CEO: देबदत्त चंद
टैगलाइन: इंडियाज इंटरनेशनल बैंक

भारत की बैंकिंग प्रणाली की तरलता वित्त वर्ष 24 में पहली बार घाटे में चली गई

भारतीय रिजर्व बैंक के अस्थायी तरलता निकासी कदम और कर बहिर्वाह के बाद भारत की बैंकिंग प्रणाली की तरलता इस वित्तीय वर्ष (2023) में पहली बार घाटे में फिसल गई है।

मुख्य विचार:

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, 21 अगस्त, 2023 तक, भारतीय बैंकिंग प्रणाली की तरलता 236 बिलियन रुपये ($2.84 बिलियन) बताई गई थी।
यह अगस्त 2023 की शुरुआत के परिदृश्य से एक महत्वपूर्ण प्रस्थान है जब बैंकिंग प्रणाली में 2.8 ट्रिलियन रुपये की अधिशेष तरलता थी।
हालाँकि, RBI द्वारा बैंकों को 19 मई से 28 जुलाई, 2023 के बीच जमा में वृद्धि पर 10% की वृद्धिशील नकद आरक्षित अनुपात (CRR) रखने के लिए कहने के बाद से तरलता में गिरावट आ रही है।
इससे 1 ट्रिलियन रुपये से अधिक की निकासी हुई है।

बैंकिंग प्रणाली तरलता क्या है?

बैंकिंग प्रणाली में तरलता से तात्पर्य आसानी से उपलब्ध नकदी से है जिसकी बैंकों को अल्पकालिक व्यावसायिक और वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यकता होती है।

IRDAI ने विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकता को घटाकर 50 करोड़ रुपये कर दिया है

भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने विदेशी पुनर्बीमा व्यवसायों (FRBs) के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकता को 100 करोड़ रुपये से घटाकर 50 करोड़ रुपये करने का फैसला किया है, जिसका उद्देश्य अधिक विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं को भारत में काम करने और भारतीय बीमा बाजार में भाग लेने के लिए आकर्षित करना है।
अपनी 123वीं प्राधिकरण बैठक के दौरान, IRDAI ने भारतीय बीमाकर्ताओं, भारतीय पुनर्बीमाकर्ताओं, विदेशी पुनर्बीमा शाखाओं (FRBs), और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बीमा कार्यालयों (IIOs) पर लागू मौजूदा नियमों को सुसंगत और सुव्यवस्थित करने के लिए पुनर्बीमा विनियमों में कई संशोधनों को मंजूरी दी।

मुख्य विचार:

पूंजी की आवश्यकता को कम करने के साथ-साथ, IRDAI ने मौजूदा 6 स्तरों से 4 श्रेणियों में वरीयता क्रम का पुनर्गठन भी किया है।

श्रेणी 1:

इस श्रेणी में भारतीय पुनर्बीमाकर्ता, विशेष रूप से एकमात्र पुनर्बीमाकर्ता, GIC री शामिल हैं।
पुनर्बीमा बाज़ार में उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी।

श्रेणी 2:

इसमें अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बीमा कार्यालय (IIO) और विदेशी पुनर्बीमा शाखाएं (FRB) शामिल हैं जो भारतीय बीमाकर्ताओं से प्राप्त प्रीमियम का 100% भारत के घरेलू क्षेत्र में निवेश करते हैं।
पुनर्बीमा चाहने वाले बीमाकर्ताओं के लिए ये संस्थाएँ दूसरी प्राथमिकता होंगी।

श्रेणी 3:

इसमें 'अन्य आईआईओ' शामिल हैं, जिनकी पुनर्बीमा पदानुक्रम में थोड़ी कम प्राथमिकता है।

श्रेणी 4:

इसमें अन्य भारतीय बीमाकर्ता (बीमा खंड में प्रति-जोखिम वैकल्पिक प्लेसमेंट तक सीमित) और सीमा पार पुनर्बीमाकर्ता (CBR) शामिल हैं।
इस श्रेणी में सबसे कम प्राथमिकता स्तर होगा।
दोहरी अनुपालन आवश्यकताओं को कम करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बीमा कार्यालयों (IIO) के लिए नियामक ढांचे को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) द्वारा निर्धारित नियमों के साथ जोड़ा जाएगा।

नवीनतम समाचार:

जुलाई 2023 में, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने अन्य सभी गैर-जीवन और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के सहयोग से गतिविधियाँ शुरू करने और चलाने के लिए टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को महाराष्ट्र राज्य के लिए गैर-जीवन बीमाकर्ता के रूप में चुना। अपने दृष्टिकोण "वर्ष 2047 तक सभी के लिए बीमा" के अनुरूप राज्य में बीमा पैठ बढ़ाना।

IRDAI के बारे में:

स्थापना: 1999
मुख्यालय: हैदराबाद, तेलंगाना
अध्यक्ष: देबाशीष पांडा
IRDAI वित्त मंत्रालय (MoF), भारत सरकार (GoI) के अधिकार क्षेत्र के तहत एक वैधानिक निकाय है और इसे भारत में बीमा और पुनर्बीमा उद्योगों को विनियमित और लाइसेंस देने का काम सौंपा गया है।

RBI ने जलगांव पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक के साथ अकोला मर्चेंट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के विलय को मंजूरी दे दी

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने महाराष्ट्र के अकोला में स्थित अकोला मर्चेंट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के जलगांव, महाराष्ट्र में स्थित द जलगांव पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के साथ विलय को मंजूरी दे दी है।

इस रणनीतिक कदम को RBI द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ धारा 44 ए की उप-धारा (4) के तहत अधिकृत किया गया था।

विलय के बाद, अकोला मर्चेंट को-ऑपरेटिव बैंक की शाखाएं जलगांव पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी।

इस विलय से क्षेत्र में बैंकिंग क्षेत्र मजबूत होने और दोनों बैंकों के ग्राहकों के लिए ग्राहक सेवाओं में सुधार होने की उम्मीद है।

RBI 3 शर्तों के तहत विलय और समामेलन के प्रस्तावों पर विचार करता है:

जब समामेलित बैंक का निवल मूल्य सकारात्मक हो, और अधिग्रहणकर्ता बैंक समामेलित बैंक के जमाकर्ताओं की सभी जमाओं की सुरक्षा का आश्वासन देता है।

जब समामेलित बैंक का निवल मूल्य नकारात्मक हो, और अधिग्रहण करने वाला बैंक स्वतंत्र रूप से समामेलित बैंक के सभी जमाकर्ताओं के लिए जमा की सुरक्षा की गारंटी देता है।

जब समामेलित बैंक का शुद्ध मूल्य नकारात्मक होता है, और अधिग्रहण करने वाला बैंक विलय प्रक्रिया के हिस्से के रूप में राज्य सरकार से अग्रिम वित्तीय सहायता के साथ जमाकर्ताओं की जमा राशि की रक्षा करने का वचन देता है।

नवीनतम समाचार:

अगस्त 2023 में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने क्रांति को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड के साथ ट्विन सिटीज़ को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड के समामेलन को मंजूरी दे दी।

जलगांव पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक के बारे में:

स्थापना: 1933

मुख्यालय: जलगांव, महाराष्ट्र

MD और CEO: रोहित पांडुरंग भुजबल

RBI के बारे में:

स्थापना: 1 अप्रैल 1935

मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र, भारत

राज्यपाल: शक्तिकांत दास

उप राज्यपाल: महेश कुमार जैन, एम. राजेश्वर राव, माइकल पात्रा और टी. रबी शंकर

एक्सिस बैंक ने अपने डिजिटल रुपया ऐप पर UPI इंटरऑपरेबिलिटी की शुरुआत की

भारतीय रिजर्व बैंक की चल रही सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) पहल के एक हिस्से के रूप में, एक्सिस बैंक ने अपने ग्राहकों के बीच डिजिटल रुपये के उपयोग को बढ़ाने के लिए अपने 'एक्सिस मोबाइल डिजिटल रुपया ऐप' पर एक नई UPI इंटरऑपरेबिलिटी कार्यक्षमता लॉन्च की है।

इसके साथ, बैंक का लक्ष्य ग्राहकों को UPI QR कोड पर भुगतान के लिए डिजिटल रुपये का उपयोग करने में मदद करना है।

मुख्य विशेषताएं और लाभ:

यूपीआई इंटरऑपरेबिलिटी:'एक्सिस मोबाइल डिजिटल रुपया ऐप' में अब UPI इंटरऑपरेबिलिटी शामिल है, जो ग्राहकों को व्यापारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले मौजूदा UPI QR कोड के माध्यम से भुगतान के लिए ई-रुपी का उपयोग करने में सक्षम बनाता है।

व्यापारी स्वीकृति: यह सुविधा व्यापारियों को अपने मौजूदा क्यूआर कोड के माध्यम से आसानी से डिजिटल रुपया भुगतान स्वीकार करने, प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और अनिवार्य ऑनबोर्डिंग की आवश्यकता को समाप्त करने का अधिकार देती है।

गोद लेने को बढ़ावा: डिजिटल रुपया और UPI इंटरऑपरेबिलिटी की इस महत्वपूर्ण सुविधा की शुरूआत पूरे भारत में डिजिटल मुद्रा को व्यापक रूप से अपनाने के लिए प्रेरित करेगी।

चरणबद्ध रोलआउट और पायलट शहर:

रोलआउट रणनीति: 'एक्सिस मोबाइल डिजिटल रुपी' ऐप पर UPI इंटरऑपरेबिलिटी कार्यक्षमता को एंड्रॉइड से शुरू करके चरणबद्ध तरीके से उपयोगकर्ताओं के लिए पेश किया जा रहा है, और आने वाले दिनों में सभी डिजिटल रुपी उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध होगा।

पायलट शहर: शुरुआती चरणों के दौरान, यह कार्यक्षमता 26 पायलट शहरों में श्वेतसूची वाले उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध होगी, जिससे एक नियंत्रित और कुशल रोलआउट प्रक्रिया सुनिश्चित होगी।

केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) क्या है?

CBDC, e₹ या डिजिटल रुपया, भारतीय रिज़र्व बैंक की पहल द्वारा जारी एक कानूनी निविदा है।

1 नवंबर, 2022 को, शीर्ष बैंक ने थोक खंड में सीडीबीसी पर एक पायलट शुरू किया, और 1 दिसंबर, 2022 को खुदरा परीक्षण शुरू किया।

e₹ डिजिटल मोड में भौतिक नकदी जैसे विश्वास, सुरक्षा और परमाणुता के साथ निपटान की अंतिमता (यानी लेनदेन का तत्काल निपटान) की सुविधाएँ प्रदान करता है।

नवीनतम समाचार:

जून 2023 में, देश के सबसे बड़े निजी ऋणदाता, HDFC बैंक ने भारत के डिजिटल रुपये के साथ इंटरऑपरेबल UPI QR कोड लॉन्च किया, जो एकीकरण प्रक्रिया को पूरा करने वाला भारत का पहला वाणिज्यिक बैंक बन गया।

अगस्त 2023 में, राज्य-संचालित ऋणदाता, केनरा बैंक ने 'केनरा डिजिटल रुपया' नाम से एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जो भारत के CBDC परीक्षणों को अगले महत्वपूर्ण चरण में ले जाने पर केंद्रित था, जिससे बड़े पैमाने पर अपनाया जाएगा।

अगस्त 2023 में, भारत के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंकों में से एक, एक्सिस बैंक ने RuPay क्रेडिट कार्ड पर 'क्रेडिट ऑन UPI' पहुंच को बढ़ाने के लिए UPI प्लेटफॉर्म पर क्रांतिकारी क्रेडिट कीवी के साथ साझेदारी की।

एक्सिस बैंक के बारे में:

स्थापना: 3 दिसंबर 1993
मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र, भारत
MD एवं CEO: अमिताभ चौधरी
टैगलाइन: बढ़ती का नाम जिंदगी

HDFC बैंक ने भारत का पहला सह-ब्रांडेड होटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए मैरियट इंटरनेशनल के साथ हाथ मिलाया है

HDFC बैंक मैरियट बॉनवॉय, मैरियट इंटरनेशनल के पुरस्कार विजेता यात्रा कार्यक्रम के साथ साझेदारी में भारत का पहला सह-ब्रांडेड होटल क्रेडिट कार्ड 'मैरियट बॉनवॉय HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड' लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है।

उद्देश्य:

मैरियट इंटरनेशनल के पुरस्कार विजेता यात्रा कार्यक्रम के लिए विशेष लाभ, पुरस्कार और निर्बाध पहुंच प्रदान करके हमारे मूल्यवान कार्डधारकों के यात्रा अनुभवों को बेहतर बनाना।

सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड डिस्कवर ग्लोबल नेटवर्क के हिस्से, डायनर्स क्लब पर चलेगा।

प्रमुख विशेषताऐं:

पुरस्कृत यात्रा अनुभव: HDFC बैंक मैरियट बॉनवॉय क्रेडिट कार्ड भारत के क्रेडिट कार्ड बाजार में सबसे फायदेमंद यात्रा अनुभवों में से एक प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

सिल्वर एलीट स्थिति: कार्डधारकों को मैरियट बॉनवॉय लॉयल्टी प्रोग्राम के अंतर्गत सिल्वर एलीट स्टेटस प्रदान किया जाता है।

यह कई विशेषाधिकारों के साथ आता है, जिसमें प्राथमिकता देर से चेकआउट, विशेष सदस्य दरों तक पहुंच, मैरियट बॉनवॉय के लिए बोनस अंक और बहुत कुछ शामिल हैं।

मैरियट बॉनवॉय अंक अर्जित करें: सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के उपयोगकर्ताओं के पास पात्र व्यय पर मैरियट बॉनवॉय अंक अर्जित करने का अवसर है।

इन बिंदुओं को विभिन्न यात्रा-संबंधित लाभों, जैसे होटल में ठहरने, अपग्रेड और अन्य अनुभवों के लिए भुनाया जा सकता है।

वार्षिक शुल्क: कार्ड 3000 रुपये के वार्षिक शुल्क के साथ आता है, जो ग्राहकों को सफल क्रेडिट अनुमोदन पर इसके विशेष लाभों तक पहुंच प्रदान करता है।

पात्रता:

वेतनभोगी भारतीय नागरिक:

आयु: न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 60 वर्ष

सकल मासिक आय> 1,00,000 रुपये

स्व-रोज़गार भारतीय नागरिक:

आय: आईटीआर > 15 लाख रुपये प्रति वर्ष।

HDFC बैंक लिमिटेड के बारे में:

मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र

MD और CEO: शशिधर जगदीशन

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने गैर-प्रतिदेय सावधि जमा - "सर्वोत्तम" की शुरुआत की

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) 15 लाख रुपये से अधिक की जमा राशि के लिए SBI 'सर्वोत्तम' नामक अपनी गैर-कॉल योग्य सावधि जमा लॉन्च की।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुसार, बैंक 15 लाख रुपये से अधिक की जमा राशि पर उच्च ब्याज दरों की पेशकश कर सकते हैं, जिसमें ग्राहक समय से पहले निकासी नहीं करते हैं।

गैर-प्रतिदेय जमा क्या है?

गैर-प्रतिदेय जमा एक सावधि जमा उत्पाद है जिसमें जमा अवधि के दौरान समय से पहले निकासी की अनुमति नहीं है।

SBI सर्वोत्तम FD दरें:

"सर्वोत्तम" सावधि जमा के तहत, बैंक जमाकर्ताओं को दो साल की अवधि के लिए 7.40% की ब्याज दर प्रदान कर रहा है। एक साल की अवधि के लिए जमा दर 7.10% है।

वरिष्ठ लोगों को सामान्य जमाकर्ताओं को दी जाने वाली ब्याज राशि के अलावा अतिरिक्त 50 आधार अंक (BPS) ब्याज मिलेगा।

दो साल की जमा और एक साल की जमा के लिए, वे क्रमशः 7.90% और 7.60% की ब्याज दरें अर्जित करेंगे।

SBI के बारे में:

स्थापना: 1 जुलाई 1955

मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र, भारत

अध्यक्ष: दिनेश कुमार खरा

CFO: कामेश्वर राव कोदावंती

ICC ने ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए मास्टरकार्ड के साथ साझेदारी की

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने एक एसोसिएशन की घोषणा की, जिसमें मास्टरकार्ड 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 के बीच भारत में आयोजित होने वाले ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए वैश्विक भागीदार बन गया है।

इसके साथ, मास्टरकार्ड ICC के अन्य वैश्विक साझेदारों MRF टायर्स, बुकिंग.कॉम, अरामको और एमिरेट्स से जुड़ गया है।

मुख्य विचार:

विशेष 24 घंटे की प्री-सेल विंडो के अलावा, मास्टरकार्ड कार्डधारक कई लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

इन अवसरों में क्रिकेट के दिग्गजों से मिलने, पुरुष क्रिकेट विश्व कप ट्रॉफी के करीब जाने और मैच के दिनों में अद्वितीय पहुंच का अनुभव करने का मौका शामिल है।

12-18 वर्ष की आयु के कार्डधारकों के बच्चों को भी ध्वजवाहक कार्यक्रम का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा

ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के बारे में:

2023 ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप क्रिकेट विश्व कप का 13 वां संस्करण होगा, जो पुरुषों की राष्ट्रीय टीमों द्वारा लड़ा जाने वाला और आईसीसी द्वारा आयोजित एक चतुष्कोणीय एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय (वनडे) क्रिकेट टूर्नामेंट है।

यह पहला पुरुष क्रिकेट विश्व कप होगा जिसकी मेजबानी पूरी तरह से भारत करेगा।

फाइनल 19 नवंबर 2023 को नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद में खेला जाना है।

मास्टरकार्ड के बारे में:

स्थापना: 1966

मुख्यालय: न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका

CEO: माइकल माइबैक

ICC के बारे में:

स्थापना: 15 जून 1909

मुख्यालय: दुबई, संयुक्त अरब अमीरात

CEO: ज्योफ एलार्डिस

ICC क्रिकेट के लिए वैश्विक शासी निकाय है जो 108 सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता है।

बंधन बैंक ने लेह, लद्दाख में शाखा खोली

8वें स्थापना दिवस का जश्न मनाने के लिए, बंधन बैंक ने केंद्र शासित प्रदेश (यूटी), लद्दाख के लेह जिले में अपनी शाखा खोली, जिससे भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 35 में इसकी उपस्थिति दर्ज हुई।
बंधन बैंक ने श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर (J&K) में एक और शाखा भी खोली।
HDFC बैंक के निदेशक, केकी मिस्त्री को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था और उन्होंने इस अवसर पर बात की।
बैंक देश भर में व्यापक आबादी तक पहुंचने के लिए अपने पदचिह्न का विस्तार करना जारी रखेगा।
बंधन बैंक ने अपना नया संगीत लोगो भी लॉन्च किया, जिसे भारत के प्रमुख संगीतकारों में से एक अमित त्रिवेदी ने संगीतबद्ध किया है।

बंधन बैंक के बारे में:

स्थापित: 2015
मुख्यालय: कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत
संस्थापक, MD और CEO: चंद्र शेखर घोष

एयरटेल पेमेंट्स बैंक पटना हवाई अड्डे पर फास्टैग-आधारित पार्किंग भुगतान सक्षम बनाता है

एयरटेल पेमेंट्स बैंक, डिजिटल बैंकिंग क्षेत्र के एक प्रमुख खिलाड़ी ने पटना में जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पार्किंग भुगतान के लिए फास्टैग-आधारित पार्किंग भुगतान, सुव्यवस्थित समाधान पेश किया है।

प्रमुख विशेषताएं:

स्वचालित कैशलेस भुगतान: फास्टैग-आधारित पार्किंग कार्यान्वयन हवाई अड्डे के निकास पर स्वचालित और परेशानी मुक्त कैशलेस भुगतान की अनुमति देता है।
यह हवाई अड्डे के पार्किंग क्षेत्रों के भीतर वाहन की आवाजाही की समग्र सुविधा और शीघ्रता को बढ़ाता है।
निर्बाध वाहन संचलन: वाहनों पर चिपकाए गए वैध फास्टैग का उपयोग करने से, पार्किंग शुल्क निर्बाध रूप से कट जाता है, जिससे हवाईअड्डा परिसर के भीतर वाहनों की सुचारू आवाजाही में सुविधा होती है।
यह आधुनिक दृष्टिकोण हवाईअड्डे पर भीड़भाड़ की बढ़ती समस्या के समाधान में भी योगदान देता है
राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन: एयरटेल पेमेंट्स बैंक पूरे देश में विभिन्न स्थानों पर फास्टैग-आधारित पार्किंग भुगतान का विस्तार करने के लिए कई भागीदारों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग कर रहा है, जिससे उपयोगकर्ताओं के लिए समान सुविधाजनक पार्किंग अनुभव सक्षम हो सके।
अनेक हवाई अड्डों तक विस्तार: यह प्रणाली वाराणसी, भुवनेश्वर और औरंगाबाद जैसे अन्य हवाई अड्डों पर पहले से ही चालू है, जो पूरे भारत में हवाई यात्रियों को आधुनिक और सुसंगत सेवाएं प्रदान करने के लिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
अग्रणी फास्टैग जारीकर्ता: एयरटेल पेमेंट्स बैंक देश में फास्टैग के शीर्ष 5 जारीकर्ताओं में से एक के रूप में एक विशिष्ट स्थान रखता है।
बैंक का दावा है कि उसके डिजिटल-फर्स्ट दृष्टिकोण ने उसे फास्टैग सेगमेंट में अग्रणी खिलाड़ी बनने में मदद की है।
ग्राहक एयरटेल थैंक्स ऐप के बैंकिंग सेक्शन से आसानी से फास्टैग खरीद सकते हैं।

केंद्र और एशियाई विकास बैंक दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करेंगे

एशियाई विकास बैंक (ADB) के साथ साझेदारी में भारत नई दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र खोलने के लिए तैयार है।

नई दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना, विशेष रूप से विकासशील देशों में स्वास्थ्य प्रणालियों पर जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए ज्ञान साझा करने, सहयोग और नवाचार के प्रति एक महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र के बारे में:

जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य के लिए नया केंद्र ज्ञान साझा करने, साझेदारी और नवाचारों को बढ़ावा देने और जी-20 से परे देशों, विशेष रूप से विकासशील देशों को भी मदद करेगा।

हाल ही में जारी जी-20 परिणाम दस्तावेज़ में, भारत ने यह भी नोट किया कि जलवायु परिवर्तन संक्रामक रोगों के उद्भव और पुन: उभरने और प्राकृतिक आपदाओं की गंभीरता और आवृत्ति में वृद्धि सहित स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों को बढ़ावा देना जारी रखेगा, जिससे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आवश्यक सेवाएँ प्रदान करने की सिस्टम की क्षमता।

दस्तावेज़ इसके लिए प्रतिबद्ध है:

जलवायु-लचीला स्वास्थ्य प्रणालियों के विकास को प्राथमिकता देना।

टिकाऊ और कम कार्बन/कम ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन स्वास्थ्य प्रणालियों और स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना जो उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करती हैं।

लचीली, कम कार्बन वाली टिकाऊ स्वास्थ्य प्रणालियों के लिए संसाधन जुटाना।

सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए, जिसमें WHO के नेतृत्व वाले गठबंधन फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ (ATACH) जैसी पहल शामिल है।

ADB के बारे में:

स्थापना: 19 दिसंबर 1966

मुख्यालय: मांडलुयॉन्ग, फिलिपींस

राष्ट्रपति: मासात्सुगु असकावा

सदस्यता: 68 देश

एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने भारत में 100,000 महिला-स्वामित्व वाले छोटे व्यवसायों को समर्थन देने के लिए फ्रंटियर मार्केट्स, मास्टरकार्ड के साथ साझेदारी की

एयरटेल पेमेंट्स बैंक, मास्टरकार्ड सेंटर और फ्रंटियर मार्केट्स के सहयोग से, शी लीड्स भारत: उद्यम नाम से एक परिवर्तनकारी पहल शुरू की है, जो 100,000 महिलाओं के स्वामित्व वाले छोटे व्यवसायों को ऊपर उठाने की एक पहल है।

शी लीड्स भारत: उद्यम के बारे में:

शी लीड्स भारत: उद्यम अपनी तरह की पहली पहल है जो निजी क्षेत्र, सामाजिक उद्यम और बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा क्षेत्र में परोपकार को एक साथ लाती है ताकि महिलाओं के स्वामित्व वाले छोटे व्यवसायों के लिए अपनी आय बढ़ाने के तरीकों को खोलने के लिए डिज़ाइन किए गए डिजिटल-फर्स्ट मॉडल का प्रदर्शन किया जा सके।

वित्त पोषण और समर्थन:

इस पहल को मास्टरकार्ड इम्पैक्ट फंड द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा, जबकि मास्टरकार्ड महिलाओं के स्वामित्व वाले छोटे व्यवसायों के लिए टूल, संसाधनों और नेटवर्क को अनलॉक करने के लिए अपने समावेशी विकास केंद्र की उत्प्रेरक पूंजी और वैश्विक विशेषज्ञता लाएगा।

पहला चरण:

पहले चरण में, यह पहल राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 100,000 महिला स्वामित्व वाले छोटे व्यवसायों को फ्रंटियर मार्केट्स के स्वामित्व वाले, लचीले मेरी-सहेली प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीखने और कमाने में सक्षम बनाएगी।

व्यापार बढ़ाना:

इनमें से 10,000 महिला लघु व्यवसाय मालिकों को एयरटेल पेमेंट्स बैंक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट (बीसी) बनकर अपना व्यवसाय बढ़ाने और अतिरिक्त राजस्व स्रोत खोलने में सक्षम बनाया जाएगा।

यह बैंक के 'सुलभ और समावेशी बैंकिंग के साथ भारत को सशक्त बनाने' के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

MSME में लैंगिक असमानता:

भारत में, महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) सभी MSME का 20% हिस्सा हैं, फिर भी उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रदान किए गए कुल वित्तपोषण का केवल 5% प्राप्त होता है।

सीमांत बाज़ारों से क्या तात्पर्य है?

फ्रंटियर मार्केट्स एक सामाजिक उद्यम है जो भारत में ग्रामीण और वंचित समुदायों तक उत्पाद और सेवाएँ लाने पर ध्यान केंद्रित करता है।

संगठन ग्रामीण परिवारों, विशेषकर महिलाओं को स्वच्छ ऊर्जा उत्पादों, जैसे सौर उत्पाद, कुशल कुकस्टोव और अन्य घरेलू आवश्यक वस्तुओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए समर्पित है।

नवीनतम समाचार:

अगस्त 2023 में, भारत का पहला भुगतान बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक बचत बैंक खाते वाले अपने नए और मौजूदा ग्राहकों के लिए पर्यावरण-अनुकूल डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया।

एयरटेल पेमेंट्स बैंक के बारे में:

स्थापना: 23 नवंबर 2016

मुख्यालय: नई दिल्ली, दिल्ली, भारत

MD और CEO: अनुब्रत बिस्वास

IDFC फर्स्ट बैंक को 3 साल के लिए भारत में अंतरराष्ट्रीय मैचों के अधिकार मिले

IDFC फर्स्ट बैंक ने 3 साल की अवधि के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की घरेलू अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला के खिताब अधिकार सुरक्षित कर लिए हैं।

बैंक ने प्रति अंतरराष्ट्रीय मैच 4.2 करोड़ रुपये की लागत से ये अधिकार हासिल किए।

वित्तीय व्यवस्था: BCCI को प्रत्येक अंतरराष्ट्रीय मैच के लिए 4.2 करोड़ रुपये मिलते हैं, जो प्रति मैच 3.8 करोड़ रुपये की पूर्व व्यवस्था से 40 लाख रुपये अधिक है।

मुख्य विचार:

यह सहयोग ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगले महीने शुरू होने वाली 3 मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला के साथ शुरू होगा।

IDFC फर्स्ट BCCI द्वारा आयोजित सभी अंतरराष्ट्रीय मैचों (महिला और पुरुष दोनों), घरेलू क्रिकेट मैचों जैसे ईरानी ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी के साथ-साथ सभी जूनियर क्रिकेट (अंडर 19 और 23) मैचों के लिए शीर्षक प्रायोजक होगा।

IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में:

स्थापित: अक्टूबर 2015

मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र, भारत

MD और CEO: वी. वैद्यनाथन
IDFC फर्स्ट बैंक एक भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक है जिसका गठन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी और कैपिटल फर्स्ट, एक भारतीय गैर-बैंक वित्तीय संस्थान की बैंकिंग शाखा के विलय से हुआ है।
यह बचत खातों पर मासिक ब्याज क्रेडिट, गतिशील और कम वार्षिक प्रतिशत दरों के साथ आजीवन मुफ्त क्रेडिट कार्ड प्रदान करने वाला पहला सार्वभौमिक बैंक है।

यस बैंक ने अगली पीढ़ी के कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए ज़ैगल के साथ साझेदारी की

यस बैंक खर्च प्रबंधन मंच के सहयोग से ज़ैगल ने व्यवसायों को उनकी भुगतान प्रक्रियाओं की फिर से कल्पना करने, सामंजस्य स्थापित करने और कंपनी के व्यय को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए सशक्त बनाने के लिए यस बैंक ज़ैगल कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड नाम से एक सह-ब्रांडेड कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया।

यस बैंक ज़ैगल कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड की मुख्य विशेषताएं:

उन्नत व्यय नियंत्रण: यस बैंक ज़ैगल कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड व्यवसायों को उनकी कंपनी के खर्चों पर सीधे नियंत्रण रखने का अधिकार देता है।
यह क्षमता व्यवसायों को अधिक वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करते हुए कुशलतापूर्वक खर्च का प्रबंधन और निगरानी करने में सक्षम बनाती है।
अनुकूलन योग्य व्यय नियंत्रण: कार्ड व्यवसायों को कर्मचारियों के लिए व्यक्तिगत खर्च सीमा निर्धारित करने, व्यापारी श्रेणियों के आधार पर प्रतिबंध लागू करने और विविध नियंत्रण लागू करने की सुविधा प्रदान करता है।
विशेष लाभ: कार्डधारकों को पुरस्कार कार्यक्रमों, गोल्फ विशेषाधिकारों, हवाई अड्डे के लाउंज तक पहुंच और यात्रा बीमा सहित कई विशेष लाभों तक पहुंच प्राप्त होती है।
ज़ैगल के ZatiX के साथ एकीकरण: क्रेडिट कार्ड ज़ैगल के ज़ैटीएक्स प्लेटफ़ॉर्म के साथ एकीकरण की सुविधा प्रदान करता है, जो एक व्यापक व्यय प्रबंधन और विश्लेषण समाधान है।
यह एकीकरण निगमों को बेहतर वित्तीय निर्णय लेने के लिए डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि का लाभ उठाकर नकदी बहिर्वाह को अनुकूलित करने की अनुमति देता है।

यस बैंक के बारे में:

स्थापना: 2004
मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र, भारत
MD और CEO: प्रशांत कुमार
टैगलाइन: एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टीज़

एशियन डेवलपमेंट बैंक और फोर्थ पार्टनर एनर्जी ने तमिलनाडु में सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए 14.7 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए

एशियाई विकास बैंक (ADB) और फोर्थ पार्टनर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (चौथा भागीदार), एक स्वतंत्र बिजली उत्पादक (IPP) ने वाणिज्यिक और औद्योगिक ग्राहकों को स्वच्छ और कम लागत वाली ऊर्जा आपूर्ति बढ़ाने के लिए 25 मेगावाट सौर फोटोवोल्टिक-आधारित बिजली संयंत्र के निर्माण और संचालन के लिए 1.2 बिलियन भारतीय रुपये (लगभग 14.7 मिलियन डॉलर) के दीर्घकालिक ऋण पर हस्ताक्षर किए।

भारत में तमिलनाडु राज्य के तिरुनेलवेली जिले में स्थित बिजली संयंत्र से सालाना लगभग 50.7 गीगावाट-घंटे बिजली पैदा होने की उम्मीद है और यह सीधे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपयोगकर्ताओं को बिजली बेचेगा।
यह किसी नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र के लिए ADB का पहला प्रत्यक्ष वित्तपोषण है।

मुख्य विचार:

पर्यावरणीय प्रभाव:
संयंत्र के माध्यम से प्रति वर्ष लगभग 41,700 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन से बचा जा सकेगा, जो अन्यथा पारंपरिक जीवाश्म ईंधन संयंत्रों द्वारा उत्पन्न होता।

ओपन एक्सेस ऊर्जा खरीद की भूमिका:
ओपन एक्सेस ऊर्जा खरीद व्यवसायों को उनके शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
चौथा साझेदार तमिलनाडु में ओट्टापिडारम, तूतीकोरिन और नंदीकुंडु में सौर और पवन पार्क भी बना रहा है।

नवीनतम समाचार:
अगस्त 2023 में, भारत एशियाई विकास बैंक (ADB) के साथ साझेदारी में नई दिल्ली में एक जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र खोलने के लिए तैयार है।
अप्रैल 2023 में, ADB और टाटा पावर की वितरण शाखा टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (TPDDL) ने ग्रिड संवर्द्धन के माध्यम से दिल्ली के बिजली वितरण को बढ़ाने के लिए 1.5 बिलियन रुपये ($18.2 मिलियन) के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर की सदस्यता लेने के लिए एक समझौते की घोषणा की।

चौथे साथी के बारे में:
स्थापना: 2010
मुख्यालय: हैदराबाद, तेलंगाना
फोर्थ पार्टनर भारत का अग्रणी नवीकरणीय ऊर्जा समाधान मंच है, जो वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के निर्माण और वित्तपोषण पर केंद्रित है।
यह महत्वपूर्ण सौर, पवन और बैटरी भंडारण बुनियादी ढांचे के मूल्यांकन, डिजाइन, योजना, खरीद, निर्माण, संचालन, रखरखाव और वित्तपोषण सहित शुरू से अंत तक क्षमताएं प्रदान करता है।

ADB के बारे में:
स्थापना: 19 दिसंबर 1966
मुख्यालय: मांडलुयॉन्ग, फिलिपींस
राष्ट्रपति: मासात्सुगु असकावा
सदस्यता: 68 देश

एक्सिस बैंक ने शून्य घरेलू लेनदेन शुल्क के साथ 'इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट' लॉन्च किया

ऐक्सिस बैंक, भारत में निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंकों में से एक ने डिजिटल रूप से समझदार ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी तरह का पहला नया बचत खाता संस्करण - 'इन्फिनिटी सेविंग्स अकाउंट' लॉन्च किया है, जो अक्सर सदस्यता-आधारित मॉडल को अपनाते हैं।

इन्फिनिटी बचत खाते के बारे में:
'इन्फिनिटी सेविंग्स अकाउंट' खोलना पूरी तरह से डिजिटल है, जो वीडियो नो योर कस्टमर (KYC) प्रक्रिया द्वारा सुगम है।
यह खाता 2 सदस्यता-आधारित योजनाएं पेश करता है - मासिक और वार्षिक।
दो सदस्यता-आधारित योजनाएं प्रदान करता है: मासिक और वार्षिक।

मासिक योजना:
कीमत: 150 रुपये (जीएसटी सहित)।
न्यूनतम सदस्यता अवधि: 6 महीने.
सदस्यता निरंतरता: प्रारंभिक 6 महीनों के बाद हर 30 दिन में।
सदस्यता नवीनीकरण: हर 30 दिन में 150 रुपये की कटौती
वार्षिक योजना:
लागत: 1650 रुपये (जीएसटी सहित)।
अवधि: लाभ 360 दिनों के लिए बढ़ाया गया
स्वचालित नवीनीकरण: सदस्यता 360 दिनों के बाद नवीनीकृत हो जाती है।

एक्सिस बैंक के 'इनफिनिटी सेविंग्स अकाउंट' की विशेषताएं:
न्यूनतम शेषराशि बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं
घरेलू लेनदेन शुल्क माफ कर दिया गया है
असीमित ATM निकासी के साथ निःशुल्क डेबिट कार्ड
चेक बुक के उपयोग या सीमा से अधिक लेनदेन/निकासी के लिए कोई शुल्क नहीं
लीप.एक्सिसबैंक.कॉम पर सहज डिजिटल खाता खोलना

एक्सिस बैंक के बारे में:
स्थापना: 3 दिसंबर 1993
मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र, भारत
MD एवं CEO: अमिताभ चौधरी
टैगलाइन: बढ़ती का नाम जिंदगी

RBI ने सिविल पेंशन वितरण के लिए बंधन बैंक को अधिकृत किया

एक महत्वपूर्ण कदम में, बंधन बैंक को अधिकृत पेंशन संवितरण बैंक के रूप में सेवा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से प्राधिकरण प्राप्त हुआ है।
यह अधिकार वित्त मंत्रालय के केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (CPAO) की ओर से नागरिक पेंशनभोगियों पर विशेष ध्यान देने के साथ प्रदान किया जाता है।
पेंशन वितरण प्रक्रिया को लागू करने के लिए बैंक सीपीएओ और वित्त मंत्रालय के साथ सहयोग करेगा।

योजना के तहत लाभार्थी:
बंधन बैंक का प्राधिकरण इसे कई लाभार्थियों, मुख्य रूप से केंद्र सरकार के कर्मचारियों, जो नागरिक मंत्रालयों और विभागों का हिस्सा हैं, को पेंशन वितरित करने का अधिकार देता है।
विशेष रूप से, इस योजना में रेलवे, डाक और रक्षा क्षेत्रों के पेंशनभोगियों को शामिल नहीं किया गया है।
लाभार्थियों का दायरा उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों, पूर्व संसद सदस्यों, साथ ही भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों और उपराष्ट्रपतियों तक फैला हुआ है।
यह कदम विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों और संस्थानों के लिए पेंशन भुगतान की सुविधा प्रदान करने में बैंक की भूमिका के अनुरूप है।

नवीनतम समाचार:

अगस्त, 2023 में भारत के अग्रणी निजी ऋणदाता बंधन बैंक ने ओडिशा पर्यटन विकास निगम (OTDC) लिमिटेड के लिए भुगतान समाधान बढ़ाने के लिए ओडिशा सरकार के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की।

बंधन बैंक के बारे में:

स्थापित: 2015

मुख्यालय: कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत

MD एवं CEO: चन्द्रशेखर घोष

सेबी 1 नवंबर, 2023 से FPI के लिए प्रकटीकरण मानदंड जारी करता है

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) के लिए नए प्रकटीकरण मानदंड पेश किए हैं, जिन्हें 1 नवंबर, 2023 से लागू किया जाना है।

उद्देश्य:

पारदर्शिता बढ़ाने, होल्डिंग्स की एकाग्रता को रोकने और FPI गतिविधियों की बेहतर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए। विनियामक परिवर्तन हिंडनबर्ग-अडानी मामले की प्रतिक्रिया में आए हैं, जिसने इस क्षेत्र में सख्त नियमों की आवश्यकता को रेखांकित किया है।

सेबी के नए प्रकटीकरण मानदंडों की मुख्य विशेषताएं:

FPI पर प्रभाव:

सेबी के कड़े प्रकटीकरण मानदंडों से 200 से अधिक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) प्रभावित होने की संभावना है। इन FPI को भारतीय प्रतिभूति नियमों का अनुपालन करने के लिए नए दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।

जोत में कमी:

नए नियमों के तहत, एकल भारतीय कॉर्पोरेट समूह में अपने इक्विटी एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) का 50% से अधिक रखने वाले FPI को नए मानदंडों को पूरा करने के लिए 10 ट्रेडिंग दिनों के भीतर अपनी होल्डिंग कम करने की आवश्यकता होती है।

क्रमिक कमी की समयरेखा:

भारतीय इक्विटी में ₹25,000 करोड़ से अधिक इक्विटी AUM वाले FPI को नए नियमों के अनुसार धीरे-धीरे अपनी होल्डिंग कम करने के लिए 90 कैलेंडर दिनों की विंडो दी जाएगी।

अतिरिक्त खुलासे:

FPI उन व्यक्तियों या संस्थाओं से संबंधित अतिरिक्त खुलासे प्रदान करने के लिए बाध्य हैं जिनके पास स्वामित्व, आर्थिक हित या उनके निवेश पर नियंत्रण है।

गैर-अनुपालन परिणाम:

नए प्रकटीकरण मानदंडों का पालन करने में विफल रहने वाले FPI पंजीकरण सेबी द्वारा नियामक कार्रवाइयों के अधीन अमान्य होने का जोखिम उठाते हैं।

प्रभाव आकलन:

सेबी की बढ़ी हुई प्रकटीकरण आवश्यकताओं से कुल 11,000 से अधिक FPI में से लगभग 2% पर सीधे प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।

उच्च मूल्य वाले FPI:

30 जून, 2023 तक, 6 FPI भारतीय इक्विटी में ₹25,000 करोड़ से अधिक इक्विटी AUM के साथ खड़े हैं।

इस समूह में 2 सॉवरेन वेल्थ फंड, 2 सार्वजनिक खुदरा निवेश समूह और एक एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF) शामिल हैं।

नवीनतम समाचार:

जुलाई 2023 में, पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सूचीबद्ध कंपनियों के लिए सख्त समयसीमा के साथ प्रकटीकरण मानदंडों को कड़ा कर दिया और घटनाओं की भौतिकता निर्धारित करने के लिए मानदंड पेश किए।

सेबी के बारे में:

स्थापना: 12 अप्रैल 1988 एक कार्यकारी निकाय के रूप में और सेबी अधिनियम, 1992 के माध्यम से 30 जनवरी 1992 को वैधानिक शक्तियां दी गईं

मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र

अध्यक्ष: माधबी पुरी बुच (सेबी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला)

SEBI भारत में प्रतिभूति और कमोडिटी बाजारों के लिए नियामक निकाय है जो वित्त मंत्रालय (MoF), भारत सरकार के स्वामित्व के तहत है।

भारत और सिंगापुर के बीच पहला ईबीएल लेनदेन पूरा करने के लिए डीबीएस ने मैपट्रास्को के साथ साझेदारी की

DBS बैंक लिमिटेड, सिंगापुर के कमोडिटी व्यापारी मैपट्रैस्को (खेतान इंटरनेशनल PTE लिमिटेड-KIPL) के सहयोग से, सिंगापुर और भारत के बीच शिपमेंट के लिए पहले "लाइव" इलेक्ट्रॉनिक बिल ऑफ लीडिंग (EBL) लेनदेन को सफलतापूर्वक निष्पादित करके एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है।

उद्देश्य:

इन दोनों देशों के बीच माल के वास्तविक समय शिपमेंट के लिए डिजिटल व्यापार वित्त की सुविधा प्रदान करना।

लेन-देन ट्रेडट्रस्ट ढांचे के तहत कार्यान्वित किया गया था, जो इन्फोकॉम मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (IMDA) की एक पहल और एंटरप्राइज सिंगापुर द्वारा समर्थित है।

मुख्य विचार:

ट्रेडट्रस्ट नेटवर्क विस्तार:

इस उद्घाटन लेनदेन के सफल समापन से सिंगापुर और भारत दोनों में व्यवसायों को ट्रेडट्रस्ट नेटवर्क में सक्रिय रूप से शामिल होने की अनुमति मिलती है।

यह एकीकरण ट्रेडट्रस्ट-सक्षम प्लेटफार्मों को अपनाने के माध्यम से होता है, जिससे दोनों देशों के बीच सक्रिय शिपमेंट के लिए निर्बाध डिजिटल व्यापार वित्त सक्षम होता है।

डिजिटल क्रेडिट पत्र लेनदेन:

डिजिटल लेटर ऑफ क्रेडिट लेनदेन के संदर्भ में इलेक्ट्रॉनिक बिल ऑफ लीडिंग (EBL) आयोजित करने में रुचि रखने वाले संगठन DBS के साथ संपर्क स्थापित कर सकते हैं।

संयुक्त राष्ट्र मॉडल कानून और सीमा पार आदान-प्रदान:

यह परियोजना इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरणीय रिकॉर्ड के लिए संयुक्त राष्ट्र के मॉडल कानून का लाभ उठाती है और इसका उद्देश्य सीमा पार दस्तावेज़ और शीर्षक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना है।

दक्षता और अंतरसंचालनीयता:

सफल लेन-देन अधिक कुशल और इंटरऑपरेबल डिजिटल बिल ऑफ लैडिंग के एक नए अध्याय की शुरुआत करता है और व्यापार वित्तपोषण के डिजिटल परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

लदान बिलों का महत्व:
लदान के बिल शिपिंग और लॉजिस्टिक्स में आवश्यक दस्तावेज हैं, जो पारगमन में माल के स्वामित्व के साथ-साथ माल की प्राप्ति के कानूनी प्रमाण का प्रतिनिधित्व करते हैं।
वैश्विक चुनौती और मापनीयता:
वैश्विक स्तर पर, केवल 1.2% बिल ऑफ लैडिंग इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किए जाते हैं, क्योंकि उन प्लेटफार्मों में सीमाएं हैं जो इंटरऑपरेबल नहीं हैं, या अलग-अलग नियम पुस्तिकाओं और मानकों का उपयोग करते हैं, जो स्केलेबिलिटी को चुनौतीपूर्ण बनाता है।
नवीनतम समाचार:
मार्च 2023 में, डीबीएस बैंक इंडिया ने मॉर्निंगस्टार द्वारा क्यूरेट किए गए निवेश विकल्पों का एक सेट बनाने के लिए अपने डिजीबैंक प्लेटफॉर्म पर एक अभिनव निवेश समाधान, 'डिजीपोर्टफोलियो' की घोषणा की, जो विभिन्न निवेशकों की जोखिम प्राथमिकताओं से मेल खाता है।
DBS बैंक लिमिटेड के बारे में:
स्थापना: 16 जुलाई 1968
मुख्यालय: सिंगापुर
सीईओ: पीयूष गुप्ता
टैगलाइन: लीव मोर, बैंक लेस

व्यापार

जून 2022 की तुलना में जून 2023 में आठ प्रमुख उद्योगों का संयुक्त सूचकांक 8.2 प्रतिशत (अनंतिम) बढ़ा:
आठ प्रमुख उद्योगों (ICI) का संयुक्त सूचकांक जून 2022 के सूचकांक की तुलना में जून 2023 में 8.2 प्रतिशत (अनंतिम) बढ़ गया।
स्टील, कोयला, सीमेंट, रिफाइनरी उत्पाद, प्राकृतिक गैस, उर्वरक और बिजली का उत्पादन जून 2023 में पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में बढ़ गया।
ICI आठ प्रमुख उद्योगों अर्थात कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली के उत्पादन के संयुक्त और व्यक्तिगत प्रदर्शन को मापता है।
आठ प्रमुख उद्योगों का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में शामिल वस्तुओं का भार 40.27 प्रतिशत है।
मार्च 2023 के लिए आठ प्रमुख उद्योगों के सूचकांक की अंतिम वृद्धि दर को इसके अनंतिम स्तर 3.6 प्रतिशत से संशोधित कर 4.2 प्रतिशत कर दिया गया है।
अप्रैल से जून 2023-24 की तिमाही के दौरान ICI की संचयी वृद्धि दर पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 5.8 प्रतिशत (अनंतिम) दर्ज की गई।

आठ प्रमुख उद्योगों के सूचकांक का सारांश नीचे दिया गया है:
कोयला - कोयला उत्पादन (भारांक: 10.33 प्रतिशत) जून 2023 में जून 2022 की तुलना में 9.8 प्रतिशत बढ़ गया। अप्रैल से जून 2023-24 की तिमाही के दौरान इसका संचयी सूचकांक पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 8.7 प्रतिशत बढ़ गया।
कच्चा तेल - कच्चे तेल का उत्पादन (भारांक: 8.98 प्रतिशत) जून 2023 में जून 2022 की तुलना में 0.6 प्रतिशत कम हो गया। अप्रैल से जून 2023-24 की तिमाही के दौरान इसका संचयी सूचकांक पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 2.0 प्रतिशत

कम हो गया।
प्राकृतिक गैस - प्राकृतिक गैस उत्पादन (भारांक: 6.88 प्रतिशत) जून 2023 में जून 2022 की तुलना में 3.6 प्रतिशत बढ़ गया। अप्रैल से जून 2023-24 की तिमाही के दौरान इसका संचयी सूचकांक पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 0.1 प्रतिशत बढ़ गया।
पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद - पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादन (भारांक: 28.04 प्रतिशत) जून 2023 में जून 2022 की तुलना में 4.6 प्रतिशत बढ़ गया। अप्रैल से जून 2023-24 की तिमाही के दौरान इसका संचयी सूचकांक पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 1.9 प्रतिशत बढ़ गया।
उर्वरक - उर्वरक उत्पादन (भारांक: 2.63 प्रतिशत) जून 2023 में जून 2022 की तुलना में 3.4 प्रतिशत बढ़ गया। अप्रैल से जून 2023-24 की तिमाही के दौरान इसका संचयी सूचकांक पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 11.3 प्रतिशत बढ़ गया।
इस्पात - इस्पात उत्पादन (वजन: 17.92 प्रतिशत) जून 2023 में जून 2022 की तुलना में 21.9 प्रतिशत बढ़ गया। अप्रैल से जून 2023-24 की तिमाही के दौरान इसका संचयी सूचकांक पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 15.9 प्रतिशत बढ़ गया।
सीमेंट - सीमेंट उत्पादन (भारांक: 5.37 प्रतिशत) जून 2023 में जून 2022 की तुलना में 9.4 प्रतिशत बढ़ गया। अप्रैल से जून 2023-24 की तिमाही के दौरान इसका संचयी सूचकांक पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 12.2 प्रतिशत बढ़ गया।
बिजली - बिजली उत्पादन (भारांक: 19.85 प्रतिशत) जून 2023 में जून 2022 की तुलना में 3.3 प्रतिशत बढ़ गया। अप्रैल से जून 2023-24 की तिमाही के दौरान इसका संचयी सूचकांक पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 1.0 प्रतिशत बढ़ गया।

जुलाई 2023 के लिए एकत्रित सकल GST राजस्व रु. 1,65,105 करोड़, जो साल-दर-साल 11% की वृद्धि दर्शाता है:

जुलाई 2023 में सकल GST राजस्व संग्रह 1,65,105 करोड़ रुपये है, जिसमें CGST 29,773 करोड़ रुपये, SGST 37,623 करोड़ रुपये, IGST 85,930 करोड़ रुपये (वस्तुओं के आयात पर एकत्र 41,239 करोड़ रुपये सहित) और उपकर 11,779 करोड़ रुपये (वस्तुओं के आयात पर एकत्र 840 करोड़ रुपये सहित) है।
सरकार ने IGST से CGST को 39,785 करोड़ रुपये और SGST को 33,188 करोड़ रुपये का निपटान किया है।
नियमित निपटान के बाद जुलाई 2023 के महीने में केंद्र और राज्यों का कुल राजस्व CGST के लिए 69,558 करोड़ रुपये और SGST के लिए 70,811 करोड़ रुपये है।
जुलाई 2023 महीने का राजस्व पिछले साल के इसी महीने के GST राजस्व से 11% अधिक है।
महीने के दौरान, घरेलू लेनदेन (सेवाओं के आयात सहित) से राजस्व पिछले वर्ष के इसी महीने के दौरान इन स्रोतों से प्राप्त राजस्व से 15% अधिक है।
यह पांचवीं बार है जब सकल जीएसटी संग्रह 1.60 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया है।

नवीनतम समाचार

जून 2023 के महीने में सकल GST राजस्व संग्रह 1,61,497 करोड़ रुपये है, जिसमें CGST 31,013 करोड़ रुपये, SGST 38,292 करोड़ रुपये, IGST 80,292 करोड़ रुपये (वस्तुओं के आयात पर एकत्र 39,035 करोड़ रुपये सहित) और उपकर 11,900 करोड़ रुपये (वस्तुओं के आयात पर एकत्र 1,028 करोड़ रुपये सहित) है।
केंद्र जल्द ही GST अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना के लिए नियमों को अधिसूचित करेगा और GST परिषद से मंजूरी के बाद सदस्यों की नियुक्ति करेगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST परिषद की 50वीं बैठक नई दिल्ली में चल रही है।
GST परिषद ने कैंसर से लड़ने वाली दवाओं, दुर्लभ बीमारियों के लिए दवाओं और विशेष चिकित्सा उद्देश्यों के लिए खाद्य उत्पादों को जीएसटी कर से छूट देने का फैसला किया है।

Click Here to Subscribe Our Yearly Mock Test Package

वस्तु एवं सेवा कर (GST) के बारे में:

वस्तु एवं सेवा कर (GST) उपभोग के लिए घरेलू स्तर पर बेची जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाला कर है।
कर को अंतिम कीमत में शामिल किया जाता है और बिक्री के स्थान पर उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान किया जाता है और विक्रेता द्वारा सरकार को भेज दिया जाता है।
GST पर आमतौर पर पूरे देश में एक ही दर से कर लगाया जाता है।
जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को भारत के राष्ट्रपति और भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था।

जुलाई में कोयला उत्पादन 14.11% बढ़कर 68.75 मिलियन टन हो गया

कोयला मंत्रालय ने 23 जुलाई के महीने के दौरान कुल कोयला उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हासिल की है, जो 22 जुलाई के महीने के 60.25 मिलियन टन (MT) को पार करते हुए 68.75 मिलियन टन (MT) तक पहुंच गया है, जो 14.11% की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है।
कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) का उत्पादन 13.41% की वृद्धि के साथ 22 जुलाई के 47.29 मीट्रिक टन की तुलना में 23 जुलाई माह में 53.63 मीट्रिक टन हो गया है।
वित्त वर्ष 23-24 में संचयी कोयला उत्पादन (23 जुलाई तक) में 292.12 मीट्रिक टन (अनंतिम) की बढ़ोतरी देखी गई है, जबकि वित्त वर्ष 22-23 में इसी अवधि के दौरान 265.94 मीट्रिक टन की तुलना में 9.84% की वृद्धि हुई है।
यह देश भर में कोयले के सुचारु वितरण को सुनिश्चित करने में कोयला आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता को उजागर करता है।
कोयला मंत्रालय मानसून सीजन के दौरान लगातार कोयला उत्पादन और प्रेषण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और खनन कार्यों की सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कई रणनीतियों को लागू किया है।
कोयला क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है क्योंकि कोयला उत्पादन, प्रेषण और स्टॉक की स्थिति उल्लेखनीय ऊंचाइयों पर पहुंच गई है।
कोयला सार्वजनिक उपक्रमों का अथक समर्पण असाधारण विकास को आगे बढ़ाने में सहायक रहा है।
कोयला मंत्रालय एक विश्वसनीय और लचीला ऊर्जा क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों, तकनीकी उन्नति और टिकाऊ प्रथाओं के लिए प्रतिबद्ध है।

MOIL ने जुलाई 2023 में रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन और बिक्री हासिल की

MOIL लिमिटेड भारत में मैंगनीज अयस्क के सबसे बड़े उत्पादक डी ने अपनी स्थापना के बाद से जुलाई महीने में अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन दर्ज किया है।
कंपनी ने जुलाई 2023 में 1.20 लाख टन मैंगनीज अयस्क का उत्पादन किया, जिसमें पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 71% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई।
यह MOIL द्वारा अपने इतिहास में अब तक का सबसे अधिक जुलाई उत्पादन है।
MOIL लिमिटेड ने जुलाई 2023 में 0.94 लाख टन की अपनी अब तक की सबसे अच्छी बिक्री दर्ज की है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 69% की प्रभावशाली वृद्धि है।
बिक्री प्रदर्शन घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मैंगनीज अयस्क की मजबूत मांग को दर्शाता है।

ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर 28% GST 1 अक्टूबर, 2023 से प्रभावी होगा

वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा है, कैसीनो और ऑनलाइन गेमिंग पर अंकित मूल्य पर 28 फीसदी GST लगाया जाएगा।
नई दिल्ली में 51वीं GST परिषद की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए
ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर 28 फीसदी GST 1 अक्टूबर, 2023 से लागू होने की उम्मीद है।
GST परिषद ने अपनी पिछली बैठक में सिफारिश की थी कि मामले में स्पष्टता प्रदान करने के लिए इस संबंध में कानून में संशोधन किया जा सकता है। इसने कैसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग में आपूर्ति के कराधान पर स्पष्टता प्रदान करने के लिए CGST अधिनियम 2017 और IGST अधिनियम 2017 में कुछ संशोधनों की सिफारिश की।

नवीनतम समाचार

वित्त मंत्री ने हाल ही में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC) की 27 वीं बैठक की अध्यक्षता की।
आयकर दिवस की 164वीं वर्षगांठ केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) और भारत भर में इसके सभी क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा मनाई गई।
केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में "भारत में वैश्विक रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विनिर्माण केंद्र" (GCPMH 2023) पर शिखर सम्मेलन के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया।
केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि भारत और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) 18 जुलाई, 2023 से दक्षिण एशिया के लिए कर और वित्तीय अपराध जांच पर एक पायलट कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं।
केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कॉरपोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड (CDMDF) का उद्घाटन किया और मुंबई में एएमसी रेपो क्लियरिंग लिमिटेड (ARCL) नामक सीमित प्रयोजन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन तंत्र पर मुहूर्त ट्रेडिंग की शुरुआत की।

वस्तु एवं सेवा कर (GST) के बारे में:

वस्तु एवं सेवा कर (GST) उपभोग के लिए घरेलू स्तर पर बेची जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाला कर है।
कर को अंतिम कीमत में शामिल किया जाता है और बिक्री के स्थान पर उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान किया जाता है और विक्रेता द्वारा सरकार को भेज दिया जाता है।
GST पर आमतौर पर पूरे देश में एक ही दर से कर लगाया जाता है।
GST को 1 जुलाई 2017 को भारत के राष्ट्रपति और भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था।

जून 2023 तक कोयला उत्पादन में 8.51% की वृद्धि

चालू वर्ष के दौरान जून 2023 तक घरेलू कोयला उत्पादन पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 8.51% से अधिक बढ़ गया है।
देश में कोयले की अधिकांश आवश्यकता स्वदेशी उत्पादन/आपूर्ति के माध्यम से पूरी की जाती है।
सरकार का ध्यान कोयले का घरेलू उत्पादन बढ़ाने और देश में कोयले के गैर-जरूरी आयात को खत्म करने पर है।
वर्ष 2022-23 में कोयला उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 14.77% बढ़ गया।
कोयला खदानें बंद होने पर किसी भी कर्मचारी को कोयला कंपनियों (कोल इंडिया लिमिटेड/सिंगारेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड) की सेवाओं से नहीं हटाया जाएगा।
श्रमिकों को पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ उनके प्रभावी उपयोग के लिए अन्य इकाइयों/प्रतिष्ठानों में स्थानांतरित/स्थानांतरित किया जाता है।

Click Here to Subscribe Our Yearly Mock Test Package

TDB-DST ई-कचरा, ज्वैलर्स अपशिष्ट और ऑटोमोबाइल उत्प्रेरक अपशिष्ट से कीमती धातुओं की वसूली के लिए एक एकीकृत संयंत्र के विकास के लिए मेसर्स अल्केमी रिसाइक्लर्स प्राइवेट लिमिटेड, गुजरात को समर्थन देता है

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने "कचरा मुक्त शहरों की दिशा में प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप" पहल के तहत दूसरे समझौते पर हस्ताक्षर किए।

TDB ने ई-कचरा, ज्वैलर्स वेस्ट और ऑटोमोबाइल कैटलिस्ट वेस्ट से कीमती धातुओं की रिकवरी के लिए एक एकीकृत संयंत्र के विकास के लिए मेसर्स अल्केमी आर रिसाइक्लर्स प्राइवेट लिमिटेड, गुजरात के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

सरकार का ध्यान कोयले के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने और देश में कोयले के गैर-आवश्यक आयात को समाप्त करने पर है।

प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप कॉल का उद्देश्य उन प्रस्तावों को प्रोत्साहित करना है जो न केवल भारतीय शहरों से कचरे को खत्म करेंगे बल्कि कचरे से धन उत्पन्न करने के लिए तकनीकी हस्तक्षेप का भी उपयोग करेंगे।

प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से प्रेरणा लेते हुए, स्वच्छ भारत मिशन: अर्बन 2.0 का उद्देश्य हमारे सभी शहरों को कचरे से मुक्त करना है और स्वच्छता पर जोर देना है, प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (DST, भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय) ने अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र में व्यावसायीकरण के चरण में नवीन स्वदेशी प्रौद्योगिकियों वाली भारतीय कंपनियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं।

देश में उत्पादित कुल बिजली 2021-22 में साल-दर-साल 8% से अधिक और 2022-23 में 9% से अधिक बढ़ रही है

केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 और चालू वर्ष 2023-24 (जून 2023 तक) के दौरान अक्षय और गैर-नवीकरणीय स्रोतों से देश में राज्य/केंद्रशासित प्रदेश-वार बिजली उत्पादन का विवरण प्रदान किया है।

यह जानकारी केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आरके सिंह ने दी है।

मंत्री ने यह भी बताया कि देश में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप, पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बिजली उत्पादन में वृद्धि हुई है, जैसा कि नीचे दिया गया है।

वर्ष	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन देश में		
	हाइड्रो (बड़ा) (MUs)	अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत (MUs)	कुल (MUs)
2020-21	150,299.52	147,247.51	**297,547.03**
2021-22	151,627.33	170,912.30	**322,539.63**
2022-23	162,098.77	203,552.17	**365,650.94**

कोयला आधारित बिजली संयंत्रों द्वारा उत्पादित बिजली में 2021-22 और 2022-23 के बीच 10% की वृद्धि हुई

केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने बताया कि पिछले दो वर्षों 2021-22 और 2022-23 के दौरान देश में सीओए एल-आधारित बिजली संयंत्रों द्वारा उत्पादित बिजली नीचे दी गई है।

वर्ष	उत्पादन (MUs में)

2021-22	1041487.43
2022-23	1145907.58

वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 में कोयला आधारित बिजली उत्पादन में कोई गिरावट नहीं हुई है।
2021-22 और 2022-23 के दौरान कोयले की कमी के कारण किसी भी कोयला आधारित बिजली संयंत्र के बंद होने की कोई रिपोर्ट नहीं है।

चालू वित्त वर्ष में अब तक सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 16% बढ़कर 6.53 लाख करोड़ रुपये हो गया है

सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 16 प्रतिशत बढ़कर छह लाख 53 हजार करोड़ रूपये हो गया है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, CBDT ने कहा कि प्रत्यक्ष कर संग्रह के अनंतिम आंकड़ों में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है।
रिफंड को समायोजित करने के बाद निवल प्रत् यक्ष कर संग्रह पांच लाख 84 हजार करोड़ रूपये रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 17 प्रतिशत अधिक है।
यह संग्रह 2023-24 के लिए प्रत्यक्ष कर के कुल बजट अनुमान का 32 प्रतिशत से अधिक है।
CBDT ने कहा, इस साल 1 अप्रैल से 10 अगस्त के बीच 69 हजार करोड़ रुपये के रिफंड जारी किए गए हैं, जो पिछले साल इसी अवधि के दौरान जारी किए गए रिफंड से 3.73 फीसदी ज्यादा है

IREDA ने 295 करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च त्रैमासिक PAT की रिपोर्ट की; शुद्ध NPA घटकर 1.61 प्रतिशत पर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत सरकार के मिनी रत्न (श्रेणी -1) उद्यम भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (IREDA) ने वित्तीय वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में 295 करोड़ रुपये के कर पश्चात लाभ (PAT) और 440 करोड़ रुपये के कर पूर्व लाभ (PBT) के साथ एक उल्लेखनीय मील का पत्थर हासिल किया है।
यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष 2022-23 की इसी अवधि की तुलना में क्रमशः 30% और 29% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाती है।
इरेडा ने निवल गैर-निष्पादित आस्तियों (NPA) में भी उल्लेखनीय कमी का प्रदर्शन किया है, जिससे उन्हें वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में 2.92% से वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में 1.61% तक लाया गया है, जो वर्ष-दर-वर्ष आधार पर उल्लेखनीय 45% की कमी (प्रतिशत के संदर्भ में) का प्रतिनिधित्व करता है।
कंपनी के असाधारण प्रदर्शन और लगातार विकास प्रक्षेपवक्र की सराहना करते हुए, IREDA के निदेशक मंडल ने 12 अगस्त, 2023 को आयोजित एक बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों को मंजूरी दी।
वित्त वर्ष 2022-23 की समान अवधि की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही के लिए उल्लेखनीय वित्तीय हाइलाइट्स में शामिल हैं:
परिचालन से कुल आय: 786 करोड़ रुपये (45% की वृद्धि) की तुलना में 1,143 करोड़ रुपये
कर पूर्व लाभ: 340 करोड़ रुपये (29% की वृद्धि) की तुलना में 440 करोड़ रुपये
कर पश्चात लाभ: 226 करोड़ रुपये की तुलना में 295 करोड़ रुपये (30% की वृद्धि)
ऋण वितरण: 852 करोड़ रुपये (272% की वृद्धि) की तुलना में 3,173 करोड़ रुपये
लोन बुक: 32,679 करोड़ रुपये की तुलना में 47,207 करोड़ रुपये (44% की वृद्धि)

नेटवर्थ: 5,514 करोड़ रुपये (14% की वृद्धि) की तुलना में 6,290 करोड़ रुपये
शुद्ध NPA: 2.92% के मुकाबले 1.61% (प्रतिशत के संदर्भ में 45% की कमी)
सकल NPA: 5.33% के मुकाबले 3.08% (प्रतिशत के संदर्भ में 42% की कमी)

वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद, जुलाई 2023 में भारत का कुल निर्यात 59.43 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है

जुलाई 2023* में भारत का कुल निर्यात (मर्चेंडाइज एंड सर्विसेज संयुक्त) 59.43 बिलियन अमरीकी डॉलर होने का अनुमान है, जो जुलाई 2022 की तुलना में (-) 5.06 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्शाता है।
जुलाई 2023 में कुल आयात 67.77 बिलियन अमरीकी डॉलर होने का अनुमान है, जो जुलाई 2022 की तुलना में (-) 12.92 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्शाता है।
अप्रैल-जुलाई 2023 में भारत का कुल निर्यात (माल और सेवाएँ संयुक्त) अप्रैल-जुलाई 2022 की तुलना में (-) 5.98 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित करने का अनुमान है।
अप्रैल-जुलाई 2023 में कुल आयात में अप्रैल-जुलाई 2022 की तुलना में (-)11.09 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित होने का अनुमान है।

उत्पाद का व्यापार

जुलाई 2023 में व्यापारिक निर्यात 32.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि जुलाई 2022 में यह 38.34 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
जुलाई 2023 में व्यापारिक आयात 52.92 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि जुलाई 2022 में यह 63.77 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
अप्रैल-जुलाई 2023 की अवधि के लिए व्यापारिक निर्यात 136.22 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि अप्रैल-जुलाई 2022 के दौरान 159.32 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
अप्रैल-जुलाई 2023 की अवधि के लिए व्यापारिक आयात 213.20 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि अप्रैल-जुलाई 2022 के दौरान 247.31 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
अप्रैल-जुलाई 2023 के लिए व्यापारिक व्यापार घाटा 76.98 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान लगाया गया था, जबकि अप्रैल-जुलाई 2022 के दौरान यह 87.99 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
जुलाई 2023 में गैर-पेट्रोलियम और गैर-रत्न एवं आभूषण निर्यात 25.35 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि जुलाई 2022 में यह 26.89 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
जुलाई 2023 में गैर-पेट्रोलियम, गैर-रत्न और आभूषण (सोना, चांदी और कीमती धातु) का आयात 35.65 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि जुलाई 2022 में यह 38.55 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
अप्रैल-जुलाई 2023 के दौरान गैर-पेट्रोलियम और गैर-रत्न एवं आभूषण निर्यात 102.71 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि अप्रैल-जुलाई 2022 में यह 110.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
अप्रैल-जुलाई 2023 में गैर-पेट्रोलियम, गैर-रत्न और आभूषण (सोना, चांदी और कीमती धातु) का आयात 136.49 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि अप्रैल-जुलाई 2022 में यह 148.77 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

सेवा व्यापार

जुलाई 2023* के लिए निर्यात की गई सेवाओं का अनुमानित मूल्य 27.17 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जबकि जुलाई 2022 में यह 24.26 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

जुलाई 2023* के लिए सेवाओं के आयात का अनुमानित मूल्य 14.85 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जबकि जुलाई 2022 में यह 14.06 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
अप्रैल-जुलाई 2023* के लिए निर्यात की गई सेवाओं का अनुमानित मूल्य 107.93 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जबकि अप्रैल-जुलाई 2022 में यह 100.35 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
अप्रैल-जुलाई 2023* के लिए सेवाओं के आयात का अनुमानित मूल्य 59.21 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जबकि अप्रैल-जुलाई 2022 में यह 59.09 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
अप्रैल-जुलाई 2023* के लिए सेवा व्यापार अधिशेष 48.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है, जबकि अप्रैल-जुलाई 2022 में यह 41.27 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

अगस्त में अब तक विदेशी निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजार में 13,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है

विदेशी निवेशकों ने अगस्त में अब तक भारतीय पूंजी बाजारों में 13 हजार करोड़ रूपये से अधिक का निवेश किया है।
निवेश विवरण: अगस्त 2023 में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) ने भारतीय पूंजी बाजारों में कुल 13,040 करोड़ रुपये का निवेश किया।
इक्विटी निवेश: FPI ने इस अवधि के दौरान भारतीय इक्विटी में 8,394 करोड़ रुपये आवंटित किए, जो इक्विटी बाजार में सकारात्मक शुद्ध प्रवाह को दर्शाता है।
ऋण बाजार ब्याज: इसके अतिरिक्त, FPI ने भारतीय ऋण बाजार में 4,646 करोड़ रुपये डाले, जो निश्चित आय प्रतिभूतियों में रुचि का संकेत देता है।
लगातार सकारात्मक रुझान: यह सकारात्मक शुद्ध प्रवाह का लगातार छठा महीना है, जो भारत में विदेशी निवेशकों के निरंतर विश्वास को रेखांकित करता है।
हाल के महीनों के निवेश: पिछले तीन महीनों में, FPI ने काफी निवेश किया: जुलाई में 46,618 करोड़ रुपये, जून में 47,148 करोड़ रुपये और मई में 43,838 करोड़ रुपये।

रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई-स्पीड ऑप्टिक फाइबर केबल से जोड़ने से जुड़ा काम पूरा कर लिया है

भारतीय दूरसंचार प्रमुख, रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई-स्पीड ऑप्टिक फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा कर लिया है।
ओशन कनेक्ट मालदीव-इंडिया एशिया एक्सप्रेस (OCM-IAX) सबमरीन केबल सिस्टम को लैंड करने के लिए मालदीव के हुलहुमाले में एक समारोह आयोजित किया गया था।
फरवरी 2022 में ओशन कनेक्टिविटी मालदीव के साथ समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद से 22.5 मिलियन डॉलर की परियोजना को एक वर्ष से कुछ अधिक समय में क्रियान्वित किया गया है।
IAX केबल सिस्टम मुंबई से शुरू होता है और सिंगापुर को भारत, मलेशिया और थाईलैंड में शाखाओं और लैंडिंग से जोड़ता है।
उम्मीद है कि इस साल के अंत तक केबल प्रणाली सेवा के लिए तैयार हो जाएगी।
उच्च क्षमता और उच्च गति ऑप्टिक फाइबर प्रणाली 16,000 किलोमीटर की दूरी पर 100 जीबी/एस की गति के साथ 200 टेरा बाइट प्रति सेकंड से अधिक की क्षमता प्रदान करेगी।
भारत यूरोप एक्सप्रेस केबल सिस्टम के साथ IAX इस दशक में दूरसंचार बुनियादी ढांचे में सबसे महत्वपूर्ण विकासों में से एक होगा, जो भारत, यूरोप को दक्षिण पूर्व एशिया और मालदीव से जोड़ेगा।

Click Here to Subscribe Our Yearly Mock Test Package

जुलाई 2023 के लिए अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक जुलाई 2022 की तुलना में (-) 1.36% है

अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक (WPI) के आंकड़ों पर आधारित मुद्रास्फीति की वार्षिक दर जुलाई 2023 (जुलाई 2022 की तुलना में) के लिए (-) 1.36% (अनंतिम) है, जबकि जून 2023 में (-) 4.12% दर्ज की गई थी।

जुलाई 2023 में मुद्रास्फीति की दर में गिरावट मुख्य रूप से खनिज तेल, बुनियादी धातुओं, रासायनिक और रासायनिक उत्पादों, कपड़ा और खाद्य उत्पादों की कीमतों में गिरावट से योगदान देती है।

WPI खाद्य सूचकांक (वजन 24.38%): प्राथमिक वस्तु समूह से 'खाद्य पदार्थ' और विनिर्मित उत्पाद समूह से 'खाद्य उत्पाद' युक्त खाद्य सूचकांक जून 2023 में 175.2 से बढ़कर जुलाई 2023 में 187.7 हो गया है। WPI खाद्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की वार्षिक दर जून 2023 में (-)1.24% से बढ़कर जुलाई 2023 में 7.75% हो गई।

प्रतिक्रिया की दर: जुलाई 2023 के लिए WPI को 85.2 प्रतिशत की भारित प्रतिक्रिया दर पर संकलित किया गया है, जबकि मई 2023 के लिए अंतिम आंकड़ा 94.4 प्रतिशत की भारित प्रतिक्रिया दर पर आधारित है।

मई 2023 माह के लिए अंतिम सूचकांक (आधार वर्ष: 2011-12=100): मई 2023 के महीने के लिए अंतिम थोक मूल्य सूचकांक और 'सभी वस्तुओं' के लिए मुद्रास्फीति दर (आधार: 2011-12=100) क्रमशः 149.4 और (-)3.61% थी।

EPFO ने जून 2023 में 17.89 लाख शुद्ध सदस्य जोड़े

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने जून 2023 में 17 लाख और 89 हजार शुद्ध सदस्यों की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की। यह डेटा सदस्य नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है।

लगातार अपट्रेंड: पेरोल डेटा, जब महीने-दर-महीने तुलना की जाती है, सदस्य नामांकन में निरंतर वृद्धि की प्रवृत्ति को दर्शाता है। विशेष रूप से, पिछले महीने मई 2023 की तुलना में 9.71 प्रतिशत शुद्ध सदस्यों की वृद्धि हुई।

उल्लेखनीय प्रेषण: समग्र प्रेषण डेटा भी उल्लेखनीय वृद्धि को रेखांकित करता है, जो अगस्त 2022 तक पिछले 11 महीनों में देखे गए उच्चतम आंकड़ों को दर्शाता है।

सामाजिक सुरक्षा विस्तार: डेटा आगे बताता है कि रिपोर्ट किए गए महीने के दौरान, 3,491 प्रतिष्ठानों ने अपने कर्मचारियों को EPFO द्वारा प्रदान किए गए सामाजिक सुरक्षा कवरेज के विस्तार को अपनाया। यह उनके प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न जमा करके हासिल किया गया था।

नवीनतम समाचार

केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अपने 6 करोड़ से अधिक ग्राहकों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के केंद्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा अनुशंसित 8.15% की ब्याज दर को मंजूरी दे दी है।

EPFO के बारे में:

स्थापना: 4 मार्च 1952

मुख्यालय: नई दिल्ली, दिल्ली, भारत

केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (CPFC) और CEO: नीलम शमी राव

EPFO भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत दो मुख्य सामाजिक सुरक्षा संगठनों में से एक है और भारत में भविष्य निधि के विनियमन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है, दूसरा कर्मचारी राज्य बीमा है।

L&T को ऑस्ट्रेलिया में यूरिया संयंत्र के लिए ₹2,500 करोड़ का ऑर्डर मिला

लार्सन एंड टुब्रो (L&T) ने ऑस्ट्रेलिया में पर्दमन केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए 2.3-MMTPA यूरिया संयंत्र के लिए पाइप रैक मॉड्यूल के निर्माण और आपूर्ति के लिए 2,500 करोड़ रुपये का ऑर्डर हासिल किया है।
यह ठेका L&T एनर्जी हाइड्रोकार्बन को सैपम एंड क्लो जेवी (SCJV) द्वारा दिया गया था और संयंत्र का निर्माण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कर्राथा से लगभग 20 किमी उत्तर में बुर्रूप प्रायद्वीप में किया जाएगा।
यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा यूरिया संयंत्र और दुनिया के सबसे बड़े संयंत्रों में से एक होगा।
संयंत्र का सत्तर प्रतिशत निर्माण भारत में L&T की कट्टुपल्ली मॉड्यूलर फैब्रिकेशन सुविधा में किया जाएगा।
लगभग 1,160 मीट्रिक टन उपकरण 25 महीनों में और 50,000 मीट्रिक टन मॉड्यूल 32 महीनों में वितरित किए जाएंगे।

L&T के बारे में

लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, जिसे आमतौर पर L&T के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय बहुराष्ट्रीय समूह कंपनी है, जिसकी इंजीनियरिंग, निर्माण, विनिर्माण, प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी और वित्तीय सेवाओं में व्यावसायिक रुचि है, जिसका मुख्यालय मुंबई में है।
अनिल मणिभाई नाइक लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के ग्रुप चेयरमैन हैं।

ऑस्ट्रेलिया के बारे में

राजधानी: कैनबरा
मुद्रा: ऑस्ट्रेलियाई डॉलर
प्रधान मंत्री: एंथोनी अल्बानीज़

IRDAI ने विदेशी पुनर्बीमा शाखाओं के लिए पूंजी में 50 करोड़ रुपये की कटौती की

भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने विदेशी पुनर्बीमा शाखाओं (FRB) के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकता को 100 करोड़ रुपये से घटाकर 50 करोड़ रुपये कर दिया है।
पुनर्बीमा कार्यक्रमों के प्रारूप को सरल बनाया गया है, और अधिक स्पष्टता और प्रभावशीलता के लिए नियामक रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को तर्कसंगत बनाया गया है।
इन संशोधनों का एक महत्वपूर्ण पहलू भारत को वैश्विक पुनर्बीमा केंद्र के रूप में स्थापित करने के व्यापक लक्ष्य के साथ उनका संरेखण है।
इन संशोधनों का मुख्य फोकस क्षेत्र कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर केंद्रित है।
सबसे पहले, पुनर्बीमा क्षेत्र की समग्र क्षमता को बढ़ाने के लिए एक ठोस प्रयास किया जा रहा है, जो बढ़ती मांग को समायोजित करने और बड़े जोखिमों का प्रबंधन करने में मदद कर सकता है। इसके अतिरिक्त, ये संशोधन उद्योग के भीतर तकनीकी विशेषज्ञता को बढ़ाने, उत्कृष्टता और नवाचार के माहौल को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं।
पुनर्बीमाकर्ताओं को व्यवसाय देने में वरीयता का क्रम, जो पहले छह स्तरों तक फैला हुआ था, अब चार स्तरों तक सुव्यवस्थित कर दिया गया है।
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) के साथ मिलकर काम करके, IRDAI का लक्ष्य पारंपरिक भारतीय बाजार के भीतर और बाहर दोनों जगह पुनर्बीमा गतिविधियों के विकास के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना है।

नेशनल करेंट अफेयर्स

सरकार ने एयर इंडिया लिमिटेड के लिए 470 और इंडिगो के लिए 500 विमानों के आयात को मंजूरी दे दी है:

केंद्र सरकार ने एयर इंडिया लिमिटेड को 470 विमान और इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड (इंडिगो) को 500 विमान आयात करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।
यह जानकारी नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल (डॉ.) वीके सिंह ने दी

उन्होंने कहा कि विमान को 2035 तक आयात करने का प्रस्ताव है।
पार्किंग की जगह के सवाल पर, मंत्री ने कहा कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा एयरलाइन ऑपरेटरों को पार्किंग स्लॉट की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हवाईअड्डा ऑपरेटरों के साथ अपनी प्रेरण योजना साझा करने की सलाह दी गई है।

इंडिगो के बारे में

संस्थापक: राहुल भाटिया, राकेश गंगवाल
CEO: पीटर एल्बर्स
मुख्यालय: गुरूग्राम
स्थापित: अगस्त 2006

भारत द्वारा अपनी G20 अध्यक्षता के हिस्से के रूप में आयोजित थिंक 20 शिखर सम्मेलन, कर्नाटक के मैसूर शहर में होने वाला है।

भारत के जी20 प्रेसीडेंसी के तहत थिंक20 सचिवालय के रूप में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ORF) 2 अगस्त तक मैसूर में थिंक20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
थिंक20 जी20 का आधिकारिक जुड़ाव समूह है जो जी20 से संबंधित नीतिगत मुद्दों पर चर्चा करने के लिए थिंक टैंक और उच्च-स्तरीय विशेषज्ञों को एक साथ लाकर बहुपक्षीय समूह के लिए एक 'विचार बैंक' के रूप में कार्य करता है।
तीन दिवसीय सम्मेलन में दुनिया भर के सात थिंक20 टास्क फोर्स के प्रतिष्ठित सदस्यों और नीति विशेषज्ञों का जमावड़ा होगा। यह भारत की जी-20 अध्यक्षता की प्राथमिकताओं पर सामूहिक रूप से विचारों और अंतर्दृष्टि को प्रदर्शित करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है, जिसमें सतत विकास के लिए जीवन शैली, मैक्रोइकॉनॉमिक्स और व्यापार, महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास, डिजिटल परिवर्तन, हरित संक्रमण, वैश्विक वित्तीय व्यवस्था, सतत विकास लक्ष्यों (SDG) की उपलब्धि में तेजी लाना और बहुपक्षवाद में सुधार जैसे मुद्दे शामिल हैं।
शिखर सम्मेलन में चार संबद्ध प्रकाशनों का शुभारंभ भी होगा। थिंक 20 सचिवालय के अध्यक्ष और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉ समीर सरन ने बताया है कि जी 20 और अन्य आमंत्रित देशों के 131 से अधिक सह-अध्यक्षों ने पिछले आठ महीनों में सहयोग किया है और जी 20 नेतृत्व के लिए विचार करने के लिए कुछ बहुत ही विशिष्ट और व्यापक सिफारिशें की हैं।

नवीनतम समाचार

भारत की G20 अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप20 शिखर शिखर सम्मेलन हरियाणा के गुरुग्राम में शुरू हुआ।
मुंबई जी-20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग (RIIG) शिखर सम्मेलन और अनुसंधान मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करता है।

आईटी हार्डवेयर के लिए PLI योजना 2.0 के लिए आवेदन जमा करने की समय सीमा 30 अगस्त, 2023 तक बढ़ा दी गई है:

IT हार्डवेयर के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना 2.0 को 17,000 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ 29 मई, 2023 की अधिसूचना संख्या CG-DL-E-30052023-246165 के माध्यम से अधिसूचित किया गया था।
इस योजना का उद्देश्य देश में आईटी हार्डवेयर विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को व्यापक और गहरा बनाना है।

IT हार्डवेयर के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना 2.0 के परिचालन दिशानिर्देश 14.07.2023 को अधिसूचित किए गए हैं और निम्नलिखित URL पर उपलब्ध हैं: https://www.meity.gov.in/esdm/production-linked-incentive-scheme-pli-20-IT-हार्डवेयर

IT हार्डवेयर के लिए PLI योजना 2.0 के तहत आवेदन प्राप्त करने की आवेदन विंडो 30 अगस्त, 2023 तक बढ़ा दी गई है। उपरोक्त योजना के लिए आवेदन पोर्टल लाइव कर दिया गया है और आवेदक यहां पंजीकरण/आवेदन कर सकते हैं https://2.pliithw.com/login

गांधीनगर में G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री, श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी द्वारा किया जाएगा:

जी 20 एम्पावर शिखर सम्मेलन 1 अगस्त, 2023 को गुजरात के गांधीनगर में महात्मा मंदिर में होने वाला है।

"वीमेन-लेड डेवलपमेंट: एन्सुरिन्ग ए सस्टेनेबल, इंक्लूसिव, एंड इक्वीटेबल ग्लोबल इकनोमिक ग्रोथ" विषय पर आयोजित शिखर सम्मेलन में कई वैश्विक विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और हितधारकों के अलावा जी-20 देशों, अतिथि देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों की भागीदारी देखी जाएगी।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सशक्तिकरण के लिए नोडल मंत्रालय है जो महिलाओं के सशक्तिकरण और आर्थिक प्रगति के लिए जी20 गठबंधन है।

यह शेरपा ट्रैक के तहत एक निजी क्षेत्र के नेतृत्व वाली पहल है जिसका उद्देश्य जी20 देशों में निजी क्षेत्र में महिलाओं के नेतृत्व और सशक्तिकरण में तेजी लाना है।

G20 एम्पावर 2023 के तहत, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सक्रिय सहयोग से भारत में फरवरी और अप्रैल 2023 के महीनों में दो अंतरराष्ट्रीय स्तर की बैठकें आयोजित की गई हैं, जिनके परिणाम एम्पावर विज्ञप्ति में परिलक्षित होंगे।

शिखर बैठक 1-2 अगस्त 2023 को गांधीनगर में निर्धारित है।

इन बैठकों में विषयगत चर्चाएं और विचार-विमर्श जी20 एम्पावर की विज्ञप्ति में प्रतिबिंबित होंगे और जी20 नेताओं को सिफारिशों के रूप में प्रदान किए जाएंगे।

गुजरात के बारे में

राजधानी: गांधीनगर

मुख्यमंत्री: भूपेन्द्रभाई पटेल

राज्यपाल: आचार्य देवव्रत

एनपी: गिर राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, वेलावदर राष्ट्रीय उद्यान, जम्बुघोडा वन्यजीव अभयारण्य, बरदा वन्यजीव अभयारण्य, वांसदा राष्ट्रीय उद्यान, पूर्णा वन्यजीव अभयारण्य, गागा वन्यजीव अभयारण्य

श्री धर्मेंद्र प्रधान ने NEP 2020 की तीसरी वर्षगांठ पर आधिकारिक तौर पर ULLAS: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के लिए मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया है

प्रधान मंत्री ने NEP 2020 की तीसरी वर्षगांठ पर भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 का उद्घाटन किया।

इस अवसर पर, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री, श्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में उल्लस: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का लोगो, नारा-जन जन साक्षर और मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया।

उल्लास के बारे में

ULLAS (अंडरस्टैंडिंग लाइफ़लॉन्ग लर्निंग फ़ॉर ऑल इन सोसाइटी) पहल देश भर में शिक्षा और साक्षरता में क्रांति लाने के लिए तैयार है, एक सीखने के पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देकर जो हर व्यक्ति तक पहुंचता है, बुनियादी साक्षरता और महत्वपूर्ण जीवन कौशल में अंतर को पाटता है। यह 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के उन नागरिकों को बुनियादी शिक्षा, डिजिटल और वित्तीय साक्षरता और महत्वपूर्ण जीवन कौशल प्रदान करता है, जिन्होंने स्कूल जाने का अवसर खो दिया है। इसे स्वैच्छिकता के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है।

नया लोगो और नारा, "उल्लास: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम," अभियान के उत्साह और जोश को दर्शाता है। यह देश के हर कोने में फैल रहे ज्ञान के प्रकाश, शिक्षा की शक्ति से नागरिकों को सशक्त बनाने और जन-जन साक्षर बनाने वाले प्रत्येक व्यक्ति में जिज्ञासा और सीखने की लौ जलाने का प्रतीक है।

यह योजना स्वयंसेवकों को राष्ट्र निर्माण के प्रति कर्तव्य या कर्तव्य बोध के रूप में योजना में भाग लेने के लिए प्रेरित करेगी और छात्र स्वयंसेवकों को स्कूल/विश्वविद्यालय में क्रेडिट और प्रमाण पत्र, प्रशंसा पत्र, अभिनंदन आदि जैसे अन्य माध्यमों से सराहना के माध्यम से प्रोत्साहित करेगी।

नवीनतम समाचार

शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक मुफ्त ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम, एआई फॉर इंडिया 2.0 लॉन्च किया।

स्वच्छ गंगा मिशन ने कुल 692 करोड़ रुपये की सात परियोजनाओं को मंजूरी दी है

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG)) की कार्यकारी समिति की 50वीं बैठक राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) के महानिदेशक श्री जी अशोक कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें लगभग 692 करोड़ रुपये की सात परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।

सात परियोजनाओं में से चार उत्तर प्रदेश और बिहार में सीवेज प्रबंधन से संबंधित हैं।

NMCG ने अब तक लगभग 38,126 करोड़ रुपये की कुल 452 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनमें से 254 पूरी हो चुकी हैं।

उत्तर प्रदेश में सीवेज प्रबंधन के लिए 3 करोड़ रुपये की परियोजनाएं। बैठक में 661.74 करोड़ की मंजूरी दी गयी इनमें हाइब्रिड वार्षिकी मोड (HAM) के तहत इंटरसेप्शन और डायवर्जन (I&D) कार्यों के साथ-साथ लखनऊ में 100 मिलियन लीटर प्रति दिन (MLD) STP का निर्माण शामिल है।

दरियाबाद पीपलघाट और दरियाबाद ककहराघाट नालों के संतुलन निर्वहन के I&D और प्रयागराज में 50 MLD STP के निर्माण के लिए एक और परियोजना को मंजूरी दी गई।

इस परियोजना की लागत लगभग रु. 186.47 करोड़ रुपये से प्रयागराज में सीवरेज जिला-ए में नैनी STP की मौजूदा उपचार क्षमता 80 MLD तक बढ़ जाएगी।

एक छोटी परियोजना में, हापुड में 6 MLD STP, I&D और अन्य कार्यों को भी मंजूरी दे दी गई ताकि हापुड शहर के नाले के प्रवाह को काली नदी में रोका जा सके, जो गंगा नदी की एक सहायक नदी है।

महिला सशक्तिकरण पर G20 मंत्रिस्तरीय सम्मेलन गांधीनगर, गुजरात में होगा:

जी20 भारतीय अध्यक्षता के तहत महिला सशक्तिकरण पर मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती ने की। स्मृति जुबिन ईरानी 2 से 4 अगस्त 2023 तक गांधीनगर, गुजरात में होने वाली हैं।

गांधीनगर आधुनिकता और सांस्कृतिक जीवंतता के साथ सदियों पुरानी वास्तुकला के जीवंत मिश्रण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है और यह अपनी ऐतिहासिक विरासत, कलाकृतियों, हस्तशिल्प, कला, त्योहारों, भव्य मंदिरों और संग्रहालयों और पश्चिमी तट पर पनपी एक समृद्ध सभ्यता के लिए जाना जाता है।

महिला सशक्तिकरण पर मंत्रिस्तरीय सम्मेलन सतत विकास लक्ष्यों (SDG) की दिशा में अपर्याप्त प्रगति से लेकर जलवायु परिवर्तन और असमान महामारी से उबरने से उत्पन्न चुनौतियों तक की वैश्विक चुनौतियों के बीच हो रहा है।

महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए जी20 मंत्रिस्तरीय सम्मेलन लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में उपलब्धि में तेजी लाने और एसडीजी: लक्ष्य 5 को प्राप्त करने का एक अवसर होगा।

तीन दिनों तक चलने वाली मंत्रिस्तरीय बैठक में G20 सदस्यों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों (IOs) के संबंधित प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों के नेतृत्व में 150 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे।

G20 के बारे में:

G20 या 20 का समूह एक अंतरसरकारी मंच है जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं।

यह वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख मुद्दों, जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन शमन और सतत विकास को संबोधित करने के लिए काम करता है।

स्थापित: 26 सितंबर 1999

गुजरात के बारे में

राजधानी: गांधीनगर

मुख्यमंत्री: भूपेन्द्रभाई पटेल

राज्यपाल: आचार्य देवव्रत

एनपी: गिर राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, वेलावदर राष्ट्रीय उद्यान, जम्बुघोडा वन्यजीव अभयारण्य, बरदा वन्यजीव अभयारण्य, वांसदा राष्ट्रीय उद्यान, पूर्णा वन्यजीव अभयारण्य, गागा वन्यजीव अभयारण्य

नवीनतम समाचार:

भारत की G20 अध्यक्षता के हिस्से के रूप में, तीसरी व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक केवडिया, गुजरात में शुरू हुई।

ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट 2023 पहली बार G20 या 20 के समूह कार्यक्रम के रूप में नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है।

आज़ादी का अमृत महोत्सव और G20 के कृषि कार्य समूह (AWG) के तत्वावधान में, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री परषोत्तम रूपाला ने NDDB, आनंद, गुजरात में सतत पशुधन परिवर्तन पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया।

प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के पुणे में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया

प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पुणे मेट्रो के पूर्ण खंडों के उद्घाटन के अवसर पर मेट्रो ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई।

उन्होंने पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम (PCMC) द्वारा प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत निर्मित 1280 से अधिक घर और पुणे नगर निगम द्वारा निर्मित 2650 से अधिक PMAY घर भी लाभार्थियों को सौंपे।

उन्होंने PCMC द्वारा निर्मित किए जाने वाले लगभग 1190 PMAY घरों और पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित 6400 से अधिक घरों की आधारशिला रखी।

प्रधानमंत्री ने PCMC के तहत लगभग 300 करोड़ रुपये की लागत से विकसित अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र का भी उद्घाटन किया।
प्रधानमंत्री ने पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम (PCMC) के तहत अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया।
लगभग 300 करोड़ रुपये की लागत से विकसित, यह बिजली उत्पादन के लिए सालाना लगभग 2.5 लाख मीट्रिक टन कचरे का उपयोग करेगा।

नवीनतम समाचार

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को महाराष्ट्र राज्य के लिए गैर-जीवन बीमाकर्ता के रूप में चुना है, जो अन्य सभी गैर-जीवन और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के सहयोग से गतिविधियों को शुरू और संचालित करेगा ताकि राज्य में अपनी दृष्टि "वर्ष 2047 तक सभी के लिए बीमा" के अनुरूप बीमा प्रवेश बढ़ाया जा सके।

महाराष्ट्र के बारे में

राज्यपाल: रमेश बाई
मुख्यमंत्री: एकनाथ शिंदे
राजधानी: मुंबई
राष्ट्रीय उद्यान: ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान
वन्यजीव अभयारण्य: भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य, करनाला पक्षी अभयारण्य, नागज़ीरा वन्यजीव अभयारण्य
यूनेस्को विरासत स्थल: छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई का विक्टोरियन और आर्ट डेको पहनावा, अजंता गुफाएं, एलीफेंटा गुफाएं, एलोरा गुफाएं

हर घर तिरंगे का जश्न मनाने के लिए इंडिया पोस्ट अपने 1.6 लाख डाकघरों के माध्यम से राष्ट्रीय ध्वज बेचेगा

भारत सरकार के अधीन आज़ादी का अमृत महोत्सव (AKAM) के तत्वावधान में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई।
यह अभियान 2022 में बेहद सफल रहा जब 23 करोड़ परिवारों ने अपने घरों पर भौतिक रूप से तिरंगा फहराया और छह करोड़ लोगों ने एचजीटी वेबसाइट पर सेल्फी अपलोड की।
डाक विभाग (DOP) ने इस अभियान को अंतिम छोर तक पहुंचाया और देश के सुदूर कोने तक राष्ट्रीय ध्वज की उपलब्धता सुनिश्चित की।
इसी जोश और देशभक्ति को जारी रखने के लिए सरकार 13-15 अगस्त 2023 के बीच हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन कर रही है
देश में 1.6 लाख डाकघरों के विशाल भौतिक नेटवर्क का लाभ उठाने और देश के सभी डाकघरों के माध्यम से अभियान के तहत झंडों की बिक्री सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया है।
डाकघरों में झंडों की बिक्री जल्द ही शुरू हो जाएगी और नागरिक अपने नजदीकी डाकघर में जाकर झंडा खरीद सकते हैं।
नागरिक विभाग की ई-पोस्टऑफिस सुविधा (www.epostoffice.gov.in) के माध्यम से भी राष्ट्रीय ध्वज खरीद सकेंगे।
राष्ट्रीय महत्व के इस कार्यक्रम से नागरिकों को जोड़ने के लिए डाकघर कई जागरूकता गतिविधियों (जनभागीदारी कार्यक्रम) का भी आयोजन करेगा। नागरिक इन गतिविधियों में भाग ले सकते हैं और न्यू इंडिया की इस महान पहल का हिस्सा बन सकते हैं।

नागरिक अपने घरों और कार्यालयों पर फहराए गए राष्ट्रीय ध्वज के साथ सेल्फी ले सकते हैं और उन्हें हैशटैग (#IndiaPost4Tirnga, #HarGharTirnga, #HarDilTirnga) के साथ सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकते हैं।

इंडिया पोस्ट के बारे में:

स्थापना: 1 अक्टूबर 1854

मुख्यालय: नई दिल्ली, दिल्ली, भारत

इंडिया पोस्ट भारत में एक सरकारी संचालित डाक प्रणाली है, जो संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग का हिस्सा है।

नवीनतम समाचार

इंडिया पोस्ट ई-कॉमर्स निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए दोनों देशों के बीच इंटरनेशनल ट्रैक्ड पैकेट सर्विस (ITPS) शुरू करने के लिए कनाडा पोस्ट के साथ सहमति व्यक्त की है।

इंडिया पोस्ट पहले से ही 38 भागीदार देशों के साथ ITPS सेवा प्रदान करता है और कनाडा 39वां देश होगा।

हमारे शहीद बहादुर पुरुषों और महिलाओं के सम्मान के लिए 'मेरी माटी मेरा देश' अभियान शुरू किया जाएगा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी लोकप्रिय कार्यक्रम 'मन की बात' के दौरान देश के लोगों को अपने संबोधन में उन्होंने हमेशा देश के खूबसूरत सांस्कृतिक ताने-बाने को प्रमुखता दी है और बताया है कि कैसे विविधता एक एकीकृत शक्ति के रूप में भी काम करती है।

मन की बात के अपने नवीनतम संबोधन में, प्रधान मंत्री ने कहा कि अमृत महोत्सव और 15 अगस्त के करीब आने की गूंज के बीच, देश में एक और महान अभियान शुरू होने की कगार पर है।

हमारे शहीद बहादुर पुरुषों और महिलाओं के सम्मान के लिए 'मेरी माटी मेरा देश' अभियान शुरू किया जाएगा।

उन्होंने यह भी बताया, ''इसके तहत हमारे अमर शहीदों की याद में देशभर में कई कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे

इन विभूतियों की स्मृति में देश की लाखों ग्राम पंचायतों में विशेष शिलालेख भी लगाये जायेंगे।

इस अभियान के तहत देशभर में 'अमृत कलश यात्रा' भी आयोजित की जाएगी.'

एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य/केंद्रशासित प्रदेश की जोड़ी की अवधारणा के माध्यम से विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लोगों के बीच बातचीत को बढ़ाना और आपसी समझ को बढ़ावा देना है।

नवीनतम समाचार

प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ परिषद के राष्ट्राध्यक्षों के 23वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने एफपीओ को अब तक 127 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण प्रदान किया है, जो 6,900 करोड़ रुपये के अतिरिक्त है।

प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, पोर्ट ब्लेयर के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित, किफायती, हल्का, अल्ट्राफास्ट, हाई फील्ड (1.5 टेस्ला), नेक्स्ट जेनरेशन मैग्नेटिक रेज़ोनेंस इमेजिंग (MRI) स्कैनर लॉन्च किया

केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी; PMO, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित, किफायती, हल्का, अल्ट्राफास्ट, हाई फील्ड (1.5 टेस्ला), नेक्स्ट जेनरेशन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग (MRI) स्कैनर लॉन्च किया।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह वास्तव में राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन (NBM), जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (BIRAC) और जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) के लिए एक मील का पत्थर उपलब्धि है क्योंकि हमने पहले स्वदेशी रूप से विकसित अत्याधुनिक का अनावरण किया है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के तहत वोक्सेलग्रिड्स
इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड ने देश की अधूरी जरूरत को हल करने के लिए एक कॉम्पैक्ट, हल्का, अगली पीढ़ी का एमआरआई स्कैनर विकसित किया है।
मंत्री ने रेखांकित किया कि विश्व स्तरीय एमआरआई विकसित करने के लिए खर्च किए गए 17 करोड़ रुपये में से 12 करोड़ रुपये बीआईआरएसी के माध्यम से डीबीटी द्वारा प्रदान किए गए थे।

नवीनतम समाचार

केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी; PMO, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि चंद्रयान-3 के सफल प्रक्षेपण से अंतरिक्ष स्टार्टअप और अंतरिक्ष उद्यमियों को बढ़ावा मिलेगा।
केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह 5 जुलाई 2023 को जी-20 अनुसंधान मंत्रियों की बैठक (RMM) की अध्यक्षता करेंगे।
भारत ने 2023 में अपनी अध्यक्षता के दौरान "समान समाज के लिए अनुसंधान और नवाचार" विषय के तहत अनुसंधान और नवाचार पहल (RIIG) को आगे बढ़ाया है।

केंद्र सरकार विदेश में मरने वाले भारतीयों के शवों के हस्तांतरण की सुविधा के लिए कल ई-केयर पोर्टल लॉन्च करेगी

केंद्र सरकार विदेशों में मरने वाले भारतीयों के अवशेषों के तेजी से हस्तांतरण की सुविधा के लिए ई-CARE (ई-क्लीयरेंस फॉर आफ्टरलाइफ रिशेन्स) पोर्टल लॉन्च करेगी।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार मृत मानव अवशेषों के परिवहन के दौरान देरी से बचने के लिए पोर्टल पेश किया जा रहा है।
उन्होंने कहा, इस पोर्टल के जरिए सेंट्रल इंटरनेशनल हेल्थ डिवीजन, नोडल ऑफिसर, कंसाइनीज और एयरलाइंस को ईमेल, SMS और व्हाट्सएप के जरिए सूचना भेजी जाएगी।
नामित नोडल अधिकारी जांच कर 48 घंटे के अंदर अनुमोदन प्राप्त करेंगे
आवेदन की स्थिति ई-केयर पोर्टल पर पंजीकरण संख्या के माध्यम से देखी जा सकती है।

नवीनतम समाचार

सरकार नए संसद भवन के उद्घाटन के उपलक्ष्य में 75 रुपये का एक विशेष स्मारक सिक्का जारी करेगी।
केंद्र सरकार ने देश में अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (NRF) विधेयक, 2023 लाने का फैसला किया है।
सरकार ने ऑफ-शोर पवन परियोजनाओं के लिए अंतर-राज्य ट्रांसमिशन शुल्क (ISTS) को माफ करने का निर्णय लिया है।
सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया पर छूट बढ़ा दी है।

भारत के राष्ट्रपति ने भोपाल में 'उन्मेशा' और 'उत्कर्ष' महोत्सव का उद्घाटन किया

भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने भोपाल, मध्य प्रदेश में 'उन्मेषा' - अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव और 'उत्कर्ष' - लोक और जनजातीय प्रदर्शन कला महोत्सव का उद्घाटन किया।

राष्ट्रपति ने कहा कि साहित्य लोगों को जोड़ता है और लोगों को एक-दूसरे से जोड़ता है। उन्होंने कहा कि केवल वही साहित्य और कलाएं सार्थक हैं और 'मैं' और 'मेरा' से ऊपर उठकर बनाई और प्रस्तुत की गई हैं। उन्होंने कहा कि सभी भारतीय भाषाओं की प्रमुख कृतियों का अन्य भाषाओं में अनुवाद भारतीय साहित्य को और समृद्ध करेगा।

राष्ट्रपति ने कहा कि साहित्य ने मानवता को आईना दिखाया है, बचाया भी है और आगे भी बढ़ाया है। साहित्य और कला ने संवेदना और करुणा को, यानी मनुष्य की मानवता को सुरक्षित रखा है। मानवता की रक्षा के इस परम पवित्र अभियान में भागीदार बनने के लिए लेखक एवं कलाकार प्रशंसा के पात्र हैं।

एमपी के बारे में:

राज्यपाल: मंगूभाई सी. पटेल

मुख्यमंत्री: शिवराज सिंह चौहान

राजधानी: भोपाल

राष्ट्रीय उद्यान: सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान

वन्यजीव अभयारण्य: नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य, बोरी वन्यजीव अभयारण्य

नवीनतम समाचार

प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के शहडोल में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया और लाभार्थियों को सिकल सेल आनुवंशिक स्थिति कार्ड वितरित किए।

5वें हेलीकॉप्टर और छोटे विमान शिखर सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश के खजुराहो में नागरिक उड्डयन मंत्रालय, मध्य प्रदेश सरकार, पवन हंस लिमिटेड और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) 2023 द्वारा संयुक्त रूप से किया जाना है।

श्री ज्योतिरादित्य एम.सिंधिया नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ने मध्य प्रदेश के खजुराहो में हेली शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया।

नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने मध्य प्रदेश के खजुराहो में तीन उड़ान प्रशिक्षण संगठनों (FTO) का उद्घाटन किया।

श्री धर्मेंद्र प्रधान और श्री एस. जयशंकर ने संयुक्त रूप से नई दिल्ली में स्टडी इन इंडिया (SII) पोर्टल लॉन्च किया

केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने संयुक्त रूप से नई दिल्ली में स्टडी इन इंडिया पोर्टल लॉन्च किया।

शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष सरकार; शिक्षा राज्य मंत्री, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी; शिक्षा एवं विदेश राज्य मंत्री श्री राजकुमार सिंह; संसद सदस्य, डॉ. महेश शर्मा; इस कार्यक्रम में शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और 10 से अधिक देशों के राजदूत शामिल हुए।

इस अवसर पर, रूस, थाईलैंड, जापान, इथियोपिया, इक्वाडोर, कजाकिस्तान और कोरिया गणराज्य के छात्र, जो वर्तमान में भारत में पढ़ रहे हैं, ने गणमान्य व्यक्तियों को सम्मान के प्रतीक के रूप में अपनी संस्कृति से स्मृति चिन्ह भेंट किए।

वेबसाइट स्नातक (यूजी), स्नातकोत्तर (पीजी), और डॉक्टरेट स्तर के कार्यक्रमों के साथ-साथ योग, आयुर्वेद, शास्त्रीय कला आदि जैसे भारतीय ज्ञान प्रणाली के पाठ्यक्रमों को कवर करने वाले शैक्षणिक कार्यक्रमों का वर्णन करेगी, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।

वेबसाइट पोर्टल शैक्षणिक सुविधाओं, अनुसंधान सहायता और संबंधित जानकारी के बारे में जानकारी प्रस्तुत करेगा।
नई वेबसाइट में अब छात्रों को अपनी पसंद के एक से अधिक संस्थानों/पाठ्यक्रमों में आवेदन करने का प्रावधान होगा।
नया पोर्टल छात्र पंजीकरण और वीज़ा आवेदन प्रक्रिया के लिए एक एकीकृत वन-स्टॉप समाधान प्रदान करेगा।

नवीनतम समाचार

केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली से गैबॉन की पहली कृषि-एसईजेड परियोजना को हरी झंडी दिखाई।
शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक मुफ्त ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम, एआई फॉर इंडिया 2.0 लॉन्च किया।

NHAI ने राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के लिए एक एकीकृत मोबाइल एप्लिकेशन 'राजमार्गयात्रा' लॉन्च किया

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने नागरिक-केंद्रित एकीकृत मोबाइल एप्लिकेशन 'राजमार्गयात्रा' के लॉन्च के साथ राजमार्ग उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
यह उपयोगकर्ता-अनुकूल ऐप अब Google Play Store और iOS ऐप स्टोर दोनों पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है, जो यात्रियों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्गों पर व्यापक जानकारी प्रदान करता है और साथ ही एक कुशल शिकायत निवारण प्रणाली भी प्रदान करता है।
ऐप फिलहाल हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है।

'राजमार्गयात्रा' ऐप की मुख्य विशेषताएं:

व्यापक राजमार्ग सूचना: 'राजमार्गयात्रा' राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के लिए आवश्यक जानकारी के वन-स्टॉप भंडार के रूप में कार्य करती है। वास्तविक समय की मौसम की स्थिति, समय पर प्रसारण सूचनाएं और नजदीकी टोल प्लाजा, पेट्रोल पंप, अस्पताल, होटल और अन्य आवश्यक सेवाओं के बारे में विवरण प्राप्त करें जो राष्ट्रीय राजमार्गों पर एक निर्बाध और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करते हैं।

परेशानी मुक्त शिकायत निवारण: ऐप एक इनबिल्ट शिकायत निवारण और एस्केलेशन तंत्र से सुसज्जित है। उपयोगकर्ता बेहतर स्पष्टता के लिए जियो-टैग किए गए वीडियो या फोटो संलग्न करके आसानी से राजमार्ग से संबंधित मुद्दों की रिपोर्ट कर सकते हैं। पंजीकृत शिकायतों को समयबद्ध तरीके से निपटाया जाएगा, किसी भी देरी के मामले में सिस्टम-जनरेटेड मामले को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा। उपयोगकर्ता पूर्ण पारदर्शिता के लिए अपनी शिकायतों की स्थिति को भी ट्रैक कर सकते हैं।

निर्बाध फास्टैग सेवाएँ:'राजमार्गयात्रा' अपनी सेवाओं को विभिन्न बैंक पोर्टलों के साथ एकीकृत करती है, जिससे उपयोगकर्ताओं के लिए अपने FASTags को रिचार्ज करना, मासिक पास का लाभ उठाना और अन्य FASTag-संबंधित बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच बनाना सुविधाजनक हो जाता है - यह सब एक ही मंच के भीतर।
जिम्मेदार और सुरक्षित ड्राइविंग व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए ओवर-स्पीडिंग सूचनाएं और आवाज सहायता।

केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम.सिंधिया ने एनएमडीसी के नए लोगो का अनावरण किया

केंद्रीय इस्पात एवं नागरिक उड्डयन मंत्री श्री. ज्योतिरादित्य एम.सिंधिया ने नई दिल्ली में एनएमडीसी के नए लोगो का अनावरण किया।
इस्पात मंत्रालय में सचिव श्री नागेंद्र नाथ सिन्हा, NMDC के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री अमिताव मुखर्जी और इस्पात मंत्रालय तथा NMDC के अन्य अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

Click Here to Subscribe Our Yearly Mock Test Package

मंत्री ने टीम NMDC को उनके गतिशील नए लोगो के लिए बधाई दी और कहा कि लोगो का अनावरण किसी भी संगठन की यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो उसके मूल्यों और लक्ष्यों का प्रतीक है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि NMDC का नया लोगो दर्शाता है कि कैसे भारत का लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक, एक टिकाऊ और हरित वातावरण में वैश्विक स्तर पर खनन के लिए तैयार है।
यह लोगो प्रकृति और लोगों के साथ सद्भाव में खनन, खनिज सुरक्षा सुनिश्चित करने और खनिज जवाबदेही के निर्माण और हमारे क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाने की दिशा में NMDC की जिम्मेदारियों का संचार करता है।
भारत के प्रधान मंत्री के अथक प्रयासों के कारण विश्व में भारत की स्थिति एक विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र में परिवर्तित हो गई है। भारत की स्थिति भी अनुयायी से बढ़कर नेता की हो गयी है

नवीनतम समाचार

श्री ज्योतिरादित्य एम.सिंधिया नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ने मध्य प्रदेश के खजुराहो में हेली शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया।
नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने मध्य प्रदेश के खजुराहो में तीन उड़ान प्रशिक्षण संगठनों (FTO) का उद्घाटन किया।

कोयला मंत्रालय के CPSE 2027 तक 7,281 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करेंगे

कोयला मंत्रालय ने अपने सभी CPSE को सलाह दी है कि वे कोयला खनन क्षेत्र के लिए एक निवल शून्य योजना का मसौदा तैयार करें।
राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के अनुसार, कोयला सार्वजनिक उपक्रमों ने विशिष्ट नवीकरणीय लक्ष्यों को रेखांकित करते हुए तीन साल की कार्य योजना सावधानीपूर्वक तैयार की है।
तदनुसार, कोल इंडिया लिमिटेड (CIL), इसकी सहायक कंपनियों और NLCIL ने क्रमशः 3000 मेगावाट और 3,731 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की योजना बनाई है।
SCCL ने 550MW स्थापित करने की भी योजना बनाई है।
इस महत्वाकांक्षी योजना का लक्ष्य 2027 तक 7,281 मेगावाट से अधिक की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करना है।
वर्तमान में, लगभग. मार्च 2023 तक 1600 मेगावाट नवीकरणीय क्षमता पहले ही बनाई जा चुकी है, (CIL- 11, NLCIL- 1360, SCCL-224) और इस वित्तीय वर्ष यानी 2023-24 के लिए 1,769 मेगावाट प्रदान की गई है। इसमें से CIL ने 399 मेगावाट और NLCIL ने 1370 मेगावाट का ठेका दिया है।
अतिरिक्त 2,553 मेगावाट क्षमता (NLCIL की 1110 + 1443 CIL) अगले वित्तीय वर्ष यानी 2024-25 में प्रदान की जाने वाली है।
CIL और NLCIL गुजरात और राजस्थान में बड़े सौर पार्क स्थापित करने की योजना बना रहे हैं।
CIL ने पहले ही सौर ऊर्जा में अपने पहले उद्यम के लिए GUVNL, गुजरात को 100 मेगावाट की बिक्री के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और 1190 मेगावाट के सौर पार्क की स्थापना के लिए RRVUNL के साथ एक संयुक्त उद्यम में भी प्रवेश किया है।
NLCIL ने पहले ही मेसर्स टाटा पावर लिमिटेड को 300 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र का काम सौंप दिया है और 18 महीने के भीतर पूरा होने की उम्मीद है, जिससे राजस्थान को बिजली की आपूर्ति होगी।
इसके अलावा, NLCIL ने गुजरात में स्थापित होने वाले ग्रीन शू विकल्प के तहत एक सौर पार्क और संभावित 300 मेगावाट के एक अन्य सौर पार्क के लिए 300 मेगावाट का टेंडर भी प्रदान किया है।

नवीनतम समाचार

कोयला मंत्रालय के सचिव ने कोयला मंत्रालय की डिजिटल प्रणालियों के साथ एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (यूलिप) के एकीकरण पर एक बैठक की अध्यक्षता की।

कोयला मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 33.224 मीट्रिक टन प्रति वर्ष की संचयी पीक-रेटेड क्षमता वाली 23 कोयला खदानों के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।

कोयला मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2030 तक 100 मिलियन टन (एमटी) कोयले का कोयला गैसीकरण हासिल करने का लक्ष्य रखा है। कोयला गैसीकरण की शक्ति का दोहन करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

कोयला मंत्रालय और कोयला सार्वजनिक उपक्रम प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित LiFE गतिविधियों के अनुरूप टिकाऊ और पर्यावरण-अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए कर्मचारियों और स्थानीय समुदायों को प्रोत्साहित करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

श्री सर्बानंद सोनोवाल ने व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए एक तेज़ और सरल पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम करने के लिए सागर सेतु के तहत पोर्ट हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (PHO) लॉन्च किया

केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने सागर सेतु के तहत बंदरगाह स्वास्थ्य संगठन (PHO) मॉड्यूल का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य व्यापार सुगमता (EODB) को बढ़ावा देने के लिए एक तेज और सरल पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम बनाना है।

PHO नागरिकों और बंदरगाह श्रमिकों की सुरक्षा के लिए रोग निगरानी, स्वास्थ्य निरीक्षण और संगरोध उपाय करेगा।

बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के सचिव श्री टी के रामचंद्र और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में इस डिजिटल पहल की शुरुआत की गई।

इस पोर्ट हेल्थ ऑर्गनाइजेशन मॉड्यूल की परिकल्पना PHO क्लीयरेंस प्रमाणपत्रों के लिए अनुरोध, PHO द्वारा अनुमोदन, ऑनलाइन प्रमाणन निर्माण, अनुरोध स्थिति की ट्रैकिंग आदि जैसी सुविधाओं को कवर करके 'व्यवसाय करने में आसानी' के एक भाग के रूप में की गई है।

PHO मॉड्यूल शिपिंग एजेंटों, PHOs, पोर्ट अथॉरिटीज, सीमा शुल्क आदि को ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से PHO क्लीयरेंस की कार्यात्मकताओं तक आसान पहुंच प्रदान करने में मदद करेगा।

इससे अनुमोदन आदि के अनुपालन के लिए विभिन्न विभागों और एजेंसियों के साथ सहयोग करने में मदद मिलेगी।

यह डेटा गतिशीलता भी सुनिश्चित करेगा जैसे अनुमोदन और निगरानी कागज रहित पारदर्शिता होगी।

नवीनतम समाचार

केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग और आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के नए दिशानिर्देश 'सागर सामाजिक सहयोग' लॉन्च किया।

नई दिल्ली में एक समारोह में बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा "हरित सागर" ग्रीन पोर्ट दिशानिर्देश 2023 लॉन्च किया गया है।

केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग और आयुष मंत्री, श्री सर्बानंद सोनोवाल ने डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी (राष्ट्रीय जलमार्ग 2) के तट पर, डिब्रूगढ़ के बोगीबील में विकसित किए जाने वाले अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन (IWT) टर्मिनल की आधारशिला रखी।

केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग और आयुष मंत्री, श्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट (GIMS), 2023 का उद्घाटन किया।

Click Here to Subscribe Our Yearly Mock Test Package

तमिलनाडु के कोयंबटूर में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 2000 करोड़ रुपये की सरकारी जमीन को कचरा मुक्त बनाया जाएगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए कचरे से धन की अवधारणा के तहत, कोयंबटूर स्मार्ट सिटी मिशन ने दशकों से जमा कचरे को साफ करने और उससे कमाई करने की पहल की है।

स्मार्ट सिटी मिशन के अधिकारियों का कहना है कि करीब 2,000 करोड़ रुपये की बेशकीमती सरकारी जमीन भी कचरा मुक्त हो जाएगी

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, कोयंबटूर शहर में कई सालों से 15.5 लाख क्यूबिक मीटर से ज्यादा कचरा जमा था. इस कूड़े के कारण 650 एकड़ ज़मीन भी कूड़े के ढेर में दब गयी।

स्मार्ट सिटी मिशन लिमिटेड के महाप्रबंधक भास्कर श्रीनिवासन ने बताया कि पहले चरण में हमने ढाई साल में करीब साढ़े नौ लाख घन मीटर कूड़ा साफ करने का बीड़ा उठाया है। इससे 140 एकड़ जमीन मुक्त करायी जा सकेगी

अब तक 50 एकड़ जमीन से कचरा हटाया जा चुका है और बाकी जमीन भी जल्द ही कचरा मुक्त हो जायेगी, करीब दो हजार करोड़ रुपये की इस जमीन का इस्तेमाल आईटी पार्क, उद्योगों और अन्य विकासात्मक परियोजनाओं के लिए किया जाएगा।

कोयंबटूर में रोजाना 1100 टन कचरा निकलता है, भविष्य में कूड़ा जमा न हो, इसके लिए कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों पर भी जीपीएस से नजर रखी जा रही है।

तमिलनाडु के बारे में:

राज्यपाल: आरएन रवि

मुख्यमंत्री: एमके स्टालीएन

राजधानी: चेन्नई

नृत्य: भरतनाट्यम, करकट्टम

राष्ट्रीय उद्यान: मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान,मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान, गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान

वन्यजीव अभयारण्य: कलाकाड वन्यजीव अभयारण्य, कारिकिली पक्षी अभयारण्य, वेदांथंगल पक्षी अभयारण्य

टाइगर रिजर्व: अनामलाई टाइगर रिजर्व

बायोस्फीयर रिजर्व: अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व

पीएम मोदी देशभर में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे।

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 24 हजार 470 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। शहर के दोनों किनारों के उचित एकीकरण के साथ इन स्टेशनों को सिटी सेंटर के रूप में विकसित करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किए जा रहे हैं।

यह एकीकृत दृष्टिकोण रेलवे स्टेशन के आसपास केंद्रित शहर के समग्र शहरी विकास की समग्र दृष्टि से प्रेरित है।

508 स्टेशन 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं।

इसमें उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 55-55 स्टेशन, बिहार में 49, महाराष्ट्र में 44, पश्चिम बंगाल में 37, मध्य प्रदेश में 34, असम में 32 और ओडिशा में 25 स्टेशन शामिल हैं।

पुनर्विकास आधुनिक यात्री सुविधाएं प्रदान करने के साथ-साथ अच्छी तरह से डिजाइन किए गए यातायात परिसंचरण, अंतर-मोडल एकीकरण और यात्रियों के मार्गदर्शन के लिए अच्छी तरह से डिजाइन किए गए साइनेज को सुनिश्चित करेगा।

स्टेशन भवनों का डिज़ाइन स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला से प्रेरित होगा।

केंद्र ने 6,40,000 गांवों में भारत नेट का विस्तार करने के लिए 1,39,500 करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया

देशभर के छह लाख 40 हजार गांवों तक भारत नेट पहुंचाने के लिए सरकार ने एक लाख 39 हजार 579 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं

संचार मंत्रालय ने कहा कि भारत नेट की विस्तार परियोजना लगभग दो वर्षों में हासिल की जाएगी।

मंत्रालय ने कहा कि देश भर के 60 हजार ग्राम पंचायत गांवों में एक पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद विस्तार परियोजना का निर्णय लिया गया है।

मंत्रालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पायलट प्रोजेक्ट के दौरान भारत नेट 1.94 लाख गांवों तक पहुंच गया है और अब तक 5 लाख 67 हजार घरों में सक्रिय भारत नेट कनेक्शन हैं और विस्तार कार्यक्रम लगभग दो लाख 50 हजार नौकरियां भी प्रदान करेगा।

मेक इन इंडिया पहल के तहत निर्मित, भारत नेट दुनिया के सबसे बड़े ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी कार्यक्रमों में से एक है, जिसे भारत संचार निगम लिमिटेड सहित केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

NHA ने डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना को 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ाया

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत अपनी डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना (DHIS) को इस साल 31 दिसंबर तक बढ़ाने की घोषणा की है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि यह योजना मरीजों के आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता संख्या से जुड़े और बनाए गए डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड की संख्या के आधार पर चार करोड़ रुपये तक का प्रोत्साहन प्रदान करती है।

योजना के तहत, अस्पतालों और डायग्नोस्टिक प्रयोगशालाओं और डिजिटल स्वास्थ्य समाधान प्रदाताओं को प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।

DHIS को जनवरी 2023 में लॉन्च किया गया था।

मंत्रालय ने कहा, यह योजना देश भर में स्वास्थ्य सेवा वितरण में डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों और प्रथाओं को अपनाने को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक साबित हुई।

आज तक, 567 सार्वजनिक और 638 निजी अस्पतालों सहित एक हजार 205 स्वास्थ्य सुविधाओं ने इस योजना के तहत पंजीकरण कराया है।

NHA के बारे में

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण या एनएचए भारत की प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा/आश्वासन योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। राष्ट्रीय स्तर पर PM-JAY को लागू करने के लिए NHA की स्थापना की गई है।

स्थापित: 2018

राज्य मंत्री राजीव चन्द्रशेखर IIT मद्रास द्वारा आयोजित 'डिजिटल इंडिया RISC-V' संगोष्ठी में भाग लेंगे

केंद्रीय उद्यमिता, कौशल विकास, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर 'डिजिटल इंडिया RISC-V' में हिस्सा लेंगे। संगोष्ठी, चेन्नई में IIT मद्रास और IIT-M प्रवर्तक टेक्नोलॉजीज फाउंडेशन द्वारा आयोजित की जा रही है

RISC-V पाथवे के माध्यम से भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स का भविष्य' प्रदर्शित करने वाले कार्यक्रम में छात्र, उद्योग पेशेवर, शोधकर्ता और वे सभी लोग भाग लेंगे जो भारत में बढ़ते RISC-V पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जानकारी हासिल करने के इच्छुक हैं।

श्री राजीव चन्द्रशेखर और IIT मद्रास के निदेशक प्रोफेसर वी कामकोटि अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे।

संगोष्ठी में शिक्षाविदों और उद्योग विशेषज्ञों द्वारा व्यावहारिक तकनीकी वार्ता, स्वदेशी RISC-V प्रोसेसर का प्रदर्शन करने वाले इंटरैक्टिव स्टॉल, एक आकर्षक हैकथॉन और एक विशेष निवेशक सत्र की सुविधा होगी।

RISC-V के बारे में

'RISC' का अर्थ है 'रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर' और 'V' का अर्थ है पांचवीं पीढ़ी। RISC-V परियोजना 2010 में शुरू हुई। RISC-V ISA खुले मानक सहयोग के माध्यम से प्रोसेसर नवाचार के एक नए युग को सक्षम बनाता है और इसका उद्देश्य आर्किटेक्चर पर मुफ्त, एक्स्टेंसिबल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर स्वतंत्रता का एक नया स्तर प्रदान करना है, जो अगले 50 वर्षों के कंप्यूटिंग डिजाइन और नवाचार का मार्ग प्रशस्त करता है।

प्रोफेसर कामाकोटि ने RISC-V ISA पर आधारित भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया माइक्रोप्रोसेसर 'शक्ति' विकसित किया।

IIT मद्रास के बारे में:

स्थापना: 1959

मुख्यालय: चेन्नई, तमिलनाडु

निदेशक: पवन कुमार गोयनका

नवीनतम समाचार

रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (RBIH) पूरे भारत में भाषा संबंधी बाधाओं को खत्म करने के लिए वॉयस-बैंकिंग समाधान पेश करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास रिसर्च पार्क (IITMRP) और IIT मद्रास इनक्यूबेशन सेल (IITMIC) के साथ हाथ मिलाया है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) मद्रास अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर ज़ांज़ीबार, तंजानिया में स्थापित करेगा।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास (IIT मद्रास) ने जिम्मेदार AI अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (CeRAI) की स्थापना के लिए Google के साथ साझेदारी की है।

भारत के राष्ट्रपति ने 'पुस्तकालय महोत्सव' का उद्घाटन किया

भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 'पुस्तकालय महोत्सव' का उद्घाटन किया।

यह महोत्सव पुस्तकालयों के विकास और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने और पढ़ने की संस्कृति को विकसित करने के लिए संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है।

राष्ट्रपति ने कहा कि पुस्तकालयों का विकास समाज और संस्कृति के विकास से संबंधित है।

यह सभ्यताओं की प्रगति का माप भी है। उन्होंने कहा कि इतिहास ऐसे संदर्भों से भरा पड़ा है जिसमें आक्रमणकारियों ने पुस्तकालयों को नष्ट करना आवश्यक समझा। इससे पता चलता है कि पुस्तकालयों को किसी देश या समाज की सामूहिक चेतना और बुद्धि का प्रतीक माना गया है। उन्होंने बताया कि आधुनिक युग में ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं लेकिन दुर्लभ पांडुलिपियों और पुस्तकों के गायब होने की घटनाएं होती हैं।

राष्ट्रपति ने कहा कि पुस्तकालय सभ्यताओं के बीच सेतु का काम करते हैं। प्राचीन और मध्यकाल में कई देशों के लोग भारत से पुस्तकें ले जाते थे, उनका अनुवाद करते थे और ज्ञान प्राप्त करते थे। ऐसे प्रयासों के केंद्र में यह विचार है कि किताबें और पुस्तकालय मानवता की साझी विरासत हैं।

अर्जुन राम मेघवाल ने अंतर-मंत्रालय बार और बेंच बैडमिंटन चैंपियनशिप के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया

कानून और न्याय मंत्रालय ने नई दिल्ली के त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अंतर-मंत्रालय बार और बेंच बैडमिंटन चैंपियनशिप के दूसरे संस्करण का आयोजन किया।
टूर्नामेंट में न्यायाधीशों, वकीलों और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारियों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई।
इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया।
इस कार्यक्रम में एक लघु प्रदर्शनी मैच में उनकी उत्साही भागीदारी और प्रभावशाली स्ट्रोक-मेकिंग देखी गई।
नागरिकों के बीच शारीरिक फिटनेस और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 29 अगस्त, 2019 को फिट इंडिया मिशन शुरू किया गया था।
इस आंदोलन का उद्देश्य हमारे दैनिक जीवन में प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट के लिए किसी भी खेल या फिटनेस गतिविधि को बढ़ावा देना है।
इसमें कोई भी गतिविधि शामिल है - जैसे तैराकी, बैडमिंटन, साइकिल चलाना या कोई बुनियादी फिटनेस गतिविधि जैसे सीढ़ियाँ चढ़ना या नृत्य करना - जो एक गतिहीन जीवन शैली को समाप्त करता है।

पीएम मोदी राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह में भाग लेंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वोकल फॉर लोकल एक जन आंदोलन बन गया है जिसने देश में कपड़ा क्षेत्र को नई गति दी है।
दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में 9वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कपड़ा क्षेत्र में जो योजनाएं शुरू की गई हैं, वे बुनकरों और कारीगरों को न्याय दिलाती हैं।
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर लोगों से स्थानीय उत्पादों को लोकप्रिय बनाने की प्रतिबद्धता का भी आग्रह किया।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत के जीवंत हथकरघा देश की विविधता का उदाहरण हैं।
कार्यक्रम के दौरान, श्री मोदी ने कपड़ा और शिल्प का एक भंडार 'भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोष' का ई-पोर्टल लॉन्च किया, जिसे राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट द्वारा विकसित किया गया है।
कार्यक्रम में कपड़ा और MSME क्षेत्रों के 3000 से अधिक हथकरघा और खादी बुनकरों, कारीगरों और हितधारकों ने भाग लिया।
सरकार ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाना शुरू किया, इस तरह का पहला उत्सव 7 अगस्त 2015 को आयोजित किया गया था।
इस तिथि को विशेष रूप से स्वदेशी आंदोलन के सम्मान के रूप में चुना गया था जो 7 अगस्त 1905 को शुरू किया गया था और स्वदेशी उद्योगों और विशेष रूप से हथकरघा बुनकरों को प्रोत्साहित किया गया था।

1 नवंबर से लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर के आयात के लिए वैध लाइसेंस की आवश्यकता होगी

केंद्र सरकार ने कहा है कि लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर के आयात के लिए वैध लाइसेंस इस साल 1 नवंबर (2023) से आवश्यक होगा।

विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सीमित आयात के लाइसेंस के बिना 31 अक् तूबर, 2023 तक आयात खेप को मंजूरी दी जा सकती है।
केंद्र ने कहा है कि टैबलेट और लैपटॉप जैसे आईटी हार्डवेयर के आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है क्योंकि ऐसे उपकरणों को कंपनियों या व्यापारियों द्वारा वैध लाइसेंस प्राप्त करने के बाद आयात किया जा सकता है।
DGFT ने एक पोर्टल तैयार किया है, और कंपनियां और व्यापारी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
भारत के पास आईटी हार्डवेयर उपकरणों के निर्माण और आगे उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त क्षमता और क्षमता है।
सरकार ने आईटी हार्डवेयर के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, PLI, स्कीम 2.0 को अधिसूचित किया है।
इस योजना से पांच से छह वर्षों में लगभग तीन लाख 29 हजार करोड़ रुपये मूल्य के आईटी हार्डवेयर का कुल उत्पादन और 75 हजार अतिरिक्त नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है।

NIA ने कथित राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के लिए PFI पर अपनी कार्रवाई तेज कर दी है

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने कथित राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) पर अपनी कार्रवाई तेज कर दी है।
NIA ने युवाओं को कट्टरपंथ और शिक्षा देने से जुड़े पटना मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान बिहार के पूर्वी चंपारण जिले से शाहिद रेजा के रूप में हुई है।
इससे मामले में गिरफ्तारियों की कुल संख्या 16 हो गई है।
एजेंसी ने रेजा के आवास से एक पिस्तौल, गोला-बारूद, एक एयर पिस्टल, एक तलवार और दो चाकू बरामद किए हैं।
NIA की जांच में पता चला कि PFI के सदस्य देश विरोधी एजेंडे में शामिल थे

उपराष्ट्रपति ने प्रगति मैदान, नई दिल्ली में पुस्तकालय महोत्सव के समापन समारोह को संबोधित किया

पहले 'लाइब्रेरी फेस्टिवल 2023' के दूसरे दिन समापन समारोह में भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ की गरिमामयी उपस्थिति देखी गई।
केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित महोत्सव का उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किया।
संस्कृति एवं विदेश राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी, और संस्कृति सचिव श्री गोविंद मोहन, संयुक्त सचिव, संस्कृति श्रीमती इस अवसर पर मुग्धा सिन्हा भी उपस्थित थीं।
पुस्तकालय महोत्सव, 'आजादी का अमृत महोत्सव' के दूसरे चरण का एक हिस्सा है, जो पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देते हुए भारत में पुस्तकालयों के विकास और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
पुस्तकालय महोत्सव के समापन समारोह को संबोधित करते हुए, श्री धनखड़ ने सूचित नागरिकों को किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सबसे बड़ी ताकत बताया।
इस बात पर ज़ोर देते हुए कि केवल एक जागरूक नागरिक ही राष्ट्र-विरोधी ताकतों और आख्यानों को बेअसर कर सकता है, उन्होंने कहा कि सूचित नागरिक का दर्जा प्राप्त करने के लिए पुस्तकालय अत्यंत आवश्यक हैं।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल

लोकसभा सचिवालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की निचले सदन की सदस्यता बहाल कर दी

यह फैसला उच्चतम न्यायालय द्वारा आपराधिक मानहानि के एक मामले में राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने के बाद लिया गया।
श्री गांधी केरल के वायनाड निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सदस्य हैं।
इस साल मार्च में उन्हें लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
श्री गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल होने के तुरंत बाद, वह संसद पहुंचे और संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की।

पर्यटन मंत्रालय ने 'स्वदेश दर्शन 2.0 (एसडी2.0) के तहत विकास के लिए यूपी में 'प्रयागराज' और 'नैमिषारण्य' की पहचान की है

पर्यटन मंत्रालय ने टिकाऊ और जिम्मेदार पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए 'स्वदेश दर्शन 2.0 (SD2.0) के तहत उत्तर प्रदेश में 'प्रयागराज' और 'नैमिषारण्य' को विकास स्थलों के रूप में पहचाना है।
पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा तैयार राज्य परिप्रेक्ष्य योजना (SPP) में विकास के लिए हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य को शामिल नहीं किया गया है।
उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने देश में थीम-आधारित पर्यटक सर्किट के एकीकृत विकास के लिए वर्ष 2014-15 में 'स्वदेश दर्शन योजना' (SDS) शुरू की थी और उत्तर प्रदेश में चिन्हित विषयगत सर्किट की 08 परियोजनाएं हैं।

महिला सशक्तिकरण पर WCD मंत्रालय का मंत्रिस्तरीय सम्मेलन महिला नेतृत्व वाले विकास में तेजी लाने के लिए कार्यों का जश्न मनाता है

महिला सशक्तिकरण पर G20 मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 2 से 4 अगस्त 2023 तक गांधीनगर, गुजरात में आयोजित किया गया था, जिसमें G20 और अतिथि देशों की महिला और लैंगिक समानता मंत्रियों ने भाग लिया था।
G20 एम्पावर और W20 के नोडल अधिकारी के रूप में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने महिला सशक्तिकरण के लिए मंत्रिस्तरीय सम्मेलन सहित सात अंतर्राष्ट्रीय बैठकें आयोजित कीं।
सम्मेलन में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, यूरोपीय संघ, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, कोरिया गणराज्य, सऊदी अरब, तुर्किये, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए जैसे 15 जी 20 देशों और 5 अतिथि देशों अर्थात् बांग्लादेश, मॉरीशस, नीदरलैंड, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात के 138 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन में 60 से अधिक वक्ता हैं।
सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को भारत के माननीय प्रधान मंत्री श्री द्वारा संबोधित किया गया। नरेंद्र मोदी; भारत के G20 प्रेसीडेंसी के मुख्य समन्वयक, श्री हर्ष वर्धन श्रृंगला; भारत की महिला एवं बाल विकास और अल्पसंख्यक मामलों की माननीय मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी; इंडोनेशिया की माननीय महिला सशक्तिकरण और बाल संरक्षण मंत्री, सुश्री आई गुस्टी आयु बिंटांग दारमावती; ब्राजील संघीय गणराज्य की सरकार की माननीय महिला उप मंत्री, सुश्री मारिया हेलेना गुआरेज़ी; और सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत, श्री। इंदीवर पांडे.
सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, भारत की जी-20 अध्यक्षता के मुख्य समन्वयक, भारत के माननीय महिला एवं बाल विकास और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री श्री हर्षवर्धन श्रृंगला, इंडोनेशिया की महिला सशक्तिकरण एवं बाल संरक्षण मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, माननीय महिला उपमंत्री सुश्री गुस्ती अयु बिनतांग दरमावती ने संबोधित किया। ब्राजील की संघीय गणराज्य की सरकार, सुश्री मारिया हेलेना गुआरेजी, और महिला और बाल विकास मंत्रालय, भारत के सचिव, श्री इंदेवर पांडे।

NMCG के महानिदेशक ने आगरा में एक प्रभाव मूल्यांकन बैठक के दौरान विश्व बैंक ईडी को नमामि गंगे पर एक प्रस्तुति दी

देश में बैंक की परियोजनाओं के परिवर्तनकारी प्रभाव को समझने के लिए विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशकों की यात्रा के हिस्से के रूप में आगरा, उत्तर प्रदेश में एक बैठक आयोजित की गई थी।
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) के महानिदेशक श्री जी अशोक कुमार ने दुनिया भर से विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशकों को नमामि गंगे पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी।
श्री अगस्टे कौमे इस अवसर पर विश्व बैंक, भारत के कंट्री डायरेक्टर भी उपस्थित थे।
बैठक के दौरान विश्व बैंक समूह के नौ ईडी उपस्थित थे: श्री जैक कुर्स्की, पोलैंड; श्री ख़ालिद बावज़ियर, सऊदी अरब; सुश्री ज़ैनब शमसुना अहमद, नाइजीरिया; श्री जुनहोंग चांग, चीन; श्री एरिवाल्डो गोम्स, ब्राज़ील; श्री अर्नेस्टो एसेवेडो, मेक्सिको; सुश्री सेसिलिया नोहान, अर्जेंटीना; और श्री रॉबिन टास्कर, यूनाइटेड किंगडम। श्री भास्कर दासगुप्ता, ईडी, वित्त, एनएमसीजी और श्री डीपी मथुरिया, ईडी, तकनीकी, NMCG भी उपस्थित थे।
प्रतिष्ठित ताज महल का दौरा भी आयोजित किया गया था।

IIT-हैदराबाद और काठमांडू विश्वविद्यालय अनुसंधान के सभी क्षेत्रों में PHD स्तर पर JDP की पेशकश करने पर सहमत हुए

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-हैदराबाद और काठमांडू विश्वविद्यालय (KU) अनुसंधान के सभी क्षेत्रों में पीएचडी स्तर पर एक संयुक्त डॉक्टरेट कार्यक्रम (JDP) की पेशकश करने पर सहमत हुए हैं।
IIT-H प्रतिनिधिमंडल की केयू की हालिया यात्रा के दौरान दोनों संस्थानों के बीच संबंधों को मजबूत करने के कई निर्णय लिए गए हैं।
एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, भारत और नेपाल के छात्रों को कार्यक्रम के तहत विज्ञान, प्रौद्योगिकी, डिजाइन और चिकित्सा नवाचारों के अग्रणी क्षेत्रों पर काम करने का अवसर मिलेगा।
KU में JDP में प्रवेश पाने वाले छात्रों को IIT-H में एक वर्ष तक बिताने का अवसर मिलेगा, जो IIT-H में रहने के दौरान IIT-H छात्रवृत्ति द्वारा समर्थित होगा और इसके विपरीत।
इस एसोसिएशन का उद्देश्य सामान्य हित और पूरक क्षमताओं के क्षेत्रों में सफल शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग विकसित करना है।

संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण को सरल बनाने और इसे डिजिटल बनाने के विधेयक को मंजूरी दे दी

संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023 को मंजूरी दे दी है।
राज्यसभा ने इस विधेयक को पारित कर दिया जबकि लोकसभा ने इस महीने की पहली तारीख को इसे मंजूरी दे दी।
विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, यह विधेयक जन्म और मृत्यु पंजीकरण को सरल बनाने के लिए लाया गया है और यह पूरी तरह से डिजिटल होगा।
विधेयक जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 में संशोधन करना चाहता है जो जन्म और मृत्यु के विनियमन और पंजीकरण का प्रावधान करता है।
अधिनियम भारत के रजिस्ट्रार-जनरल की नियुक्ति का प्रावधान करता है जो जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के लिए निर्देश जारी कर सकता है।

विधेयक में कहा गया है कि रजिस्ट्रार जनरल पंजीकृत जन्म और मृत्यु का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाए रखेगा।
बीजद की सुलता देव, भाजपा की सीमा द्विवेदी, YSRCP के सुभाष चंद्र बोस पिल्ली और विजयसाई रेड्डी और अन्नाद्रमुक के एम थंबीदुरई ने चर्चा में भाग लिया।

NeGD ने MeitY की पहल साइबर सुरक्षित भारत के तहत 39वें CISO डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया

साइबर अपराध के बारे में जागरूकता फैलाने के मिशन के साथ MeitY की साइबर सुरक्षित भारत पहल की संकल्पना की गई थी और बढ़ते खतरे से निपटने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी विभागों में मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों (CISO) और फ्रंटलाइन आईटी अधिकारियों की क्षमता का निर्माण करें - संगठनों को अपने डिजिटल बुनियादी ढांचे की रक्षा करने और साइबर हमलों से निपटने के लिए भविष्य के लिए तैयार होने की जरूरत है।
राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग (NeGD) ने अपनी क्षमता निर्माण योजना के तहत 7 से 11 अगस्त, 2023 तक नई दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान में केंद्रीय मंत्रालयों के 25 प्रतिभागियों के साथ 39वें सीआईएसओ डीप-डाइव प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।
कार्यक्रम का उद्घाटन IIPA के महानिदेशक एसएन त्रिपाठी, MeitY में साइबर सुरक्षा की वैज्ञानिक जी (वरिष्ठ निदेशक) और समूह समन्वयक श्रीमती सविता उत्रेजा, MeitY के NeGD में निदेशक क्षमता निर्माण एवं वित्त रजनीश कुमार और MeitY के साइबर सुरक्षा के वैज्ञानिक ई विनोद कुमार चौहान और IIPA के पाठ्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर चारु मल्होत्रा ने किया।
कार्यक्रम का उद्देश्य जागरूकता फैलाना, क्षमता निर्माण के साथ-साथ सरकारी विभागों को साइबर-लचीला पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर सक्षम बनाना है।
इस कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न सरकारी सेवाओं की एकीकृत डिलीवरी के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में साइबर सुरक्षा पर प्रतिभागियों को संवेदनशील बनाना और उन्मुख करना है। नागरिकों को सेवाएं, साइबर सुरक्षा के बारे में समग्र जानकारी और ज्ञान और समझ प्रदान करना, जागरूकता फैलाना, क्षमता निर्माण के साथ-साथ सरकारी विभागों को उनकी साइबर स्वच्छता, सुरक्षा और संरक्षा की देखभाल करने में सक्षम बनाना।

संसद ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2023 पारित किया, जो केंद्र को दिल्ली के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है

संसद ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2023 को राज्यसभा की मंजूरी के साथ पारित कर दिया है। राज्यसभा में बिल के पक्ष में 131 सांसदों ने वोट कर इसे मंजूरी दे दी, जबकि 102 सांसद बिल के विरोध में थे।
यह विधेयक पिछले सप्ताह लोकसभा में पारित किया गया था। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 में संशोधन करना चाहता है। यह केंद्र सरकार को अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यों, नियमों और सेवा की अन्य शर्तों सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मामलों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार देता है। राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के गठन में भी इसका प्रावधान है।
प्राधिकरण में दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य सचिव और दिल्ली के प्रधान गृह सचिव शामिल हैं।
प्राधिकरण अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग और अनुशासनात्मक मामलों के संबंध में दिल्ली के उपराज्यपाल को सिफारिशें करेगा।
केंद्र इस संबंध में इसी साल मई में अध्यादेश लाया था

डाक जीवन बीमा (PLI) ने बिक्री बल के लिए प्रत्यक्ष प्रोत्साहन वितरण शुरू किया: एक परिवर्तनकारी कदम

पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस (PLI), 1884 से बीमा क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित नाम, अपने ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण छलांग लगा रहा है।
अपनी बिक्री बल की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए, PLI को दिल्ली और उत्तराखंड सर्कल में "प्रत्यक्ष प्रोत्साहन संवितरण" के लिए पायलट कार्यक्रम शुरू करने पर गर्व है।
PLI की सफलता की आधारशिला हमेशा उसके बिक्री कर्मचारी रहे हैं, जो विभाग की उपलब्धियों के पीछे प्रेरक शक्ति हैं। उनका समर्पण ग्राहकों को हासिल करने और बनाए रखने की PLI की क्षमता को गहराई से प्रभावित करता है, जिससे वे अपरिहार्य ब्रांड एंबेसडर बन जाते हैं।
वैयक्तिकृत सेवाएँ प्रदान करके और मजबूत ग्राहक संबंध विकसित करके, PLI के एजेंट लगातार राजस्व की वृद्धि में योगदान करते हैं।
निरंतर सुधार के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के अनुरूप, PLI अब अपने एजेंट प्रोत्साहन कार्यक्रम में एक प्रमुख वृद्धि का अनावरण कर रहा है।
"प्रत्यक्ष प्रोत्साहन संवितरण" सुविधा के माध्यम से, एजेंटों को पिछले महीने से उनकी मेहनत की कमाई का कमीशन सीधे उनके डाकघर बचत बैंक खातों में निर्बाध हस्तांतरण का अनुभव होगा।

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने 13वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लिया

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री, श्री पीयूष गोयल ने दक्षिण अफ्रीका की ब्रिक्स प्रेसीडेंसी के तहत आयोजित 13वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लिया।
इस वर्ष ब्रिक्स का विषय "ब्रिक्स और अफ्रीका: पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी" है।
श्री पीयूष गोयल ने बैठक में WTO, आपूर्ति श्रृंखला, डिजिटलीकरण, MSME से संबंधित मुद्दों और गलत मूल्य निर्धारण और कम चालान के मुद्दे पर चर्चा की।
मंत्री ने एक महत्वाकांक्षी एजेंडा रखने और आर्थिक संपर्क समूह के तहत परिणाम-उन्मुख गतिविधियों को पूरा करने के लिए दक्षिण अफ्रीकी प्रेसीडेंसी की सराहना की।
उन्होंने समानता, खुलेपन, समावेशिता, सर्वसम्मति, आपसी सम्मान और समझ की ब्रिक्स भावना को मजबूत समर्थन दिया।
श्री पीयूष गोयल ने एक-दूसरे के बीच विश्वास कायम करने पर जोर दिया और WTO सुधार की दिशा में छोटे, प्राप्त करने योग्य, वृद्धिशील कदमों में मजबूत विश्वास व्यक्त किया।
उन्होंने यह भी व्यक्त किया कि भारत तीन दशक पूरे करने पर सशक्त, बेहतर, समावेशी WTO देखना चाहता है, '30 के लिए 30' के बारे में बात करते हुए, जो संगठन के 30 साल पूरे होने से पहले यानी 1 जनवरी 2025 तक डब्ल्यूटीओ में कम से कम 30 परिचालन सुधार लाने का एक प्रयास है।

भारत के राष्ट्रपति ने शहर में 'एस्पायरिंग फॉर सुपरमाइंड' विषय पर सम्मेलन का उद्घाटन किया

भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने ऑरोविल में 'विकसित चेतना के शहर में सुपरमाइंड की आकांक्षा' विषय पर एक सम्मेलन का उद्घाटन किया।
इससे पहले, उन्होंने मातृमंदिर और ऑरोविले में एक शहर प्रदर्शनी का भी दौरा किया।
श्री अरबिंदो का मानना था कि सुपरमाइंड मनुष्य को दिव्य प्राणियों में बदलने में सक्षम बना सकता है। उन्होंने यह दर्शन दिया कि अतिमानसिक चेतना में इस भौतिक जगत को दिव्य बनाने की शक्ति है।

राष्ट्रपति ने कहा कि महर्षि अरबिंदो द्वारा प्रतिपादित ब्रह्मांडीय सत्ता का विचार उन मुद्दों के लिए बहुत प्रासंगिक है जिनका दुनिया सामना कर रही है।
ब्रह्मांडीय चेतना की अवधारणा को समझने और अपनाने से ही आज दुनिया के सामने आने वाले कई मुद्दों को सद्भाव के साथ हल किया जा सकता है।
सर्वोच्च सत्ता और ब्रह्मांडीय मन की अवधारणाएँ जीवन के अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति की ओर ले जाती हैं।
ये आदर्श दुनिया को रहने के लिए एक सामंजस्यपूर्ण और शांतिपूर्ण जगह बनाने में मदद कर सकते हैं।

TRAI ने 'यूनिफाइड लाइसेंस (UL) के तहत डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता प्राधिकरण की शुरूआत' पर सिफारिशें जारी कीं

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने 'यूनिफाइड लाइसेंस (UL) के तहत डिजिटल कनेक्टिविटी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदाता प्राधिकरण का परिचय' पर अपनी सिफारिशें जारी की हैं।
राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति (NDCP-2018) डिजिटल बुनियादी ढांचे पर जोर देती है यह कहते हुए कि "डिजिटल बुनियादी ढाँचा और सेवाएँ देश के विकास और कल्याण के प्रमुख समर्थकों और महत्वपूर्ण निर्धारकों के रूप में तेजी से उभर रही हैं"।
वैश्विक डेटा की वृद्धि के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी इन्फ्रास्ट्रक्चर (DCI) आवश्यक है
एक मजबूत DCI उत्पादकता बढ़ाकर और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने वाली सुविधाएं प्रदान करके आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है।
DCI डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) और स्मार्ट सिटी के विकास के तहत विभिन्न सरकारी योजनाओं के सफल कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण और अग्रणी भूमिका निभाता है।
DCI के विकास चालकों में 5जी का व्यावसायीकरण, इंटरनेट और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ती मांग और IOT सेंसर और उपकरणों के साथ-साथ निजी एलटीई नेटवर्क का प्रसार शामिल है।

तीसरी G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक और G20 भ्रष्टाचार विरोधी मंत्रिस्तरीय बैठक कोलकाता में आयोजित की जाएगी

भारत की अध्यक्षता में G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह (ACWG) की तीसरी और अंतिम बैठक 9 से 11 अगस्त 2023 तक कोलकाता में आयोजित किया जाएगा।
जी20 सदस्यों, 10 आमंत्रित देशों और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों के 154 से अधिक प्रतिनिधि बैठक में भाग लेंगे।
इसके बाद 12 अगस्त 2023 को जी-20 भ्रष्टाचार विरोधी मंत्रिस्तरीय बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग और भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह करेंगे।
यह G20 ACWG की दूसरी और पहली व्यक्तिगत ACWG मंत्रिस्तरीय बैठक होगी
मंत्रियों के स्तर पर विचार-विमर्श भ्रष्टाचार से निपटने के लिए और अधिक राजनीतिक प्रोत्साहन प्रदान करेगा क्योंकि एसीडब्ल्यूजी अंतरराष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
भारत की जी-20 अध् यक्षता के तहत एसीडब्ल्यूजी भगोड़े आर्थिक अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई और संपत्तियों की वापसी के संबंध में भगोड़े आर्थिक अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई और संपत्ति की वापसी के संबंध में भगोड़े आर्थिक अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के संबंध में भ्रष् टाचार विरोधी सहयोग पर महत् वपूर्ण प्रगति हासिल करने में सक्षम रहा है।

IIFT में व्यापार और निवेश कानून केंद्र ने अपनी 6वीं वर्षगांठ मनाई

व्यापार और निवेश कानून केंद्र (CTIL), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा स्थापित भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (IIFT), नई दिल्ली में अपनी 6वीं वर्षगांठ मनाई और नई दिल्ली में CTIL पत्रिका का छठा वर्षगांठ अंक जारी किया।

इस अवसर पर भारत के अटॉर्नी जनरल श्री आर वेंकटरमानी, वाणिज्य विभाग के सचिव श्री सुनील बड़थ्वाल, वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव श्री पीयूष कुमार और IIFT के कुलपति प्रोफेसर सतिंदर भाटिया उपस्थित थे।

यह आयोजन CTIL की स्थापना के छह साल पूरे होने का प्रतीक है।

CTIL के बारे में

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश कानून के बारे में कानूनी मुद्दों पर क्षमता बढ़ाने के लिए वाणिज्य विभाग द्वारा CTIL की स्थापना की गई थी।

CTIL व्यापार और निवेश कानून पर जानकारी के भंडार के रूप में कार्य करता है और वैश्विक आर्थिक कानून के मुद्दों पर उभरते प्रवचन को शामिल करने और प्रभावित करने में एक विचारशील नेता के रूप में उभरा है।

शहीद वीर जवानों के सम्मान में 21 दिवसीय राष्ट्रव्यापी मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू

देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले बहादुरों को श्रद्धांजलि देने के लिए राष्ट्रव्यापी मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया जाएगा।

यह अभियान 30 अगस्त तक चलेगा।

इसमें राष्ट्रीय, राज्य, गांव और ब्लॉक स्तर के साथ-साथ स्थानीय शहरी निकायों के कार्यक्रम भी शामिल होंगे।

अभियान में स्वतंत्रता सेनानियों और सुरक्षा बलों को समर्पित स्मारक पट्टिकाओं या शिलाफलकम की स्थापना जैसे कार्यक्रमों के साथ-साथ पंच प्राण प्रतिज्ञा, वसुधा वंदन, वीरों का वंदन जैसी पहल शामिल होंगी, जो बहादुरों के वीरतापूर्ण बलिदानों का सम्मान करती हैं।

अभियान के तहत एक 'अमृत कलश यात्रा' भी निकाली जाएगी, जिसमें 7,500 कलशों में देश के कोने-कोने से मिट्टी लेकर दिल्ली में 'अमृत वाटिका' बनाई जाएगी।

यह 'अमृत वाटिका' 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की प्रतिबद्धता का प्रतीक होगी।

यह अभियान आज़ादी का अमृत महोत्सव का समापन कार्यक्रम है जो 12 मार्च 2021 को शुरू हुआ और इसमें व्यापक सार्वजनिक भागीदारी देखी गई, जिसमें पूरे भारत में दो लाख से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए।

संसदीय स्थायी समिति ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा संपत्ति की अनिवार्य घोषणा की सिफारिश की है

एक संसदीय समिति ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए वार्षिक आधार पर अपनी संपत्ति रिटर्न घोषित करना अनिवार्य बनाने के लिए कानून लाने की सिफारिश की है।

कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट 'न्यायिक प्रक्रियाएं और उनके सुधार' में कहा कि एक सामान्य प्रथा के रूप में, सभी संवैधानिक पदाधिकारियों और सरकारी सेवकों को अपनी संपत्ति और देनदारियों का वार्षिक रिटर्न दाखिल करना होगा।

समिति ने सिफारिश की कि केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए उचित प्राधिकारी को वार्षिक आधार पर अपनी संपत्ति रिटर्न प्रस्तुत करना अनिवार्य बनाने के लिए उचित कानून लाए।

Click Here to Subscribe Our Yearly Mock Test Package

इसमें कहा गया है कि उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों द्वारा संपत्ति की घोषणा से प्रणाली में अधिक विश्वास और विश्वसनीयता आएगी।

डॉ. पीके मिश्रा ने नई दिल्ली में भारत की जी20 अध्यक्षता पर समन्वय समिति की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की

प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पीके मिश्रा नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में भारत की G20 प्रेसीडेंसी पर कोर्डी नेशन कमेटी की सातवीं बैठक की अध्यक्षता की।
बैठक में शिखर सम्मेलन की तैयारियों के साथ-साथ तार्किक पहलुओं पर भी चर्चा हुई।
शेरपा और वित्त दोनों ट्रैक पर प्रगति और परिणामों की समीक्षा की गई।
हरित विकास, सतत विकास लक्ष्यों (SDG) में तेजी लाने, मजबूत टिकाऊ संतुलित, समावेशी विकास, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, लैंगिक समानता और बहुपक्षीय संस्थानों के सुधार सहित भारतीय राष्ट्रपति पद की प्राथमिकताओं पर चर्चा हुई।
शेरपा, अमिताभ कांत ने बताया कि अब तक देश के लगभग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करते हुए मंत्री स्तर पर 13 सहित कुल 185 बैठकें संपन्न हो चुकी हैं।
इसके अलावा, 12 परिणाम दस्तावेजों, 12 अन्य डिलिवरेबल्स को सर्वसम्मति से अपनाया गया है।
सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने मीडिया के लिए मीडिया सेंटर की स्थापना और मीडिया मान्यता जैसी व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी। समिट के लिए अब तक 3,200 से अधिक मीडिया कर्मियों ने पंजीकरण कराया है।

डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल द्वारा प्रत्येक नागरिक के व्यक्तिगत डेटा को डिजिटल डोमेन में संरक्षित किया जाना है

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल से हर नागरिक का निजी डेटा डिजिटल डोमेन में सुरक्षित रहेगा।
यह विधेयक संसद से पारित हो गया।
श्री वैष्णव ने कहा, डिजिटल दुनिया अब अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद हो जाएगी और इसका आम नागरिकों के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।
140 करोड़ देशवासी उस डिजिटल यात्रा का हिस्सा हैं, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में शुरू किया था

केंद्र ने स्वास्थ्य और कल्याण मशहूर हस्तियों, प्रभावशाली लोगों के लिए अतिरिक्त दिशानिर्देश जारी किए

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत उपभोक्ता मामले विभाग ने स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र में मशहूर हस्तियों, प्रभावशाली लोगों और आभासी प्रभावशाली लोगों के लिए अतिरिक्त दिशानिर्देश जारी किए हैं।
ये दिशानिर्देश 9 जून 2022 को जारी भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम और भ्रामक विज्ञापनों के लिए समर्थन हेतु दिशानिर्देश, 2022 का एक महत्वपूर्ण विस्तार हैं, और इसके बजाय "अनुमोदन जानकारी!" गाइड बुकलेट 20 जनवरी 2023 को जारी की गई।
स्वास्थ्य और कल्याण सेलेब्रिटीज़, प्रभावशाली लोगों और आभासी प्रभावशाली लोगों के लिए अतिरिक्त प्रभावशाली दिशानिर्देश स्वास्थ्य मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) और भारतीय विज्ञापन मानक परिषद सहित सभी हितधारकों के साथ विस्तृत चर्चा के बाद विकसित किए गए हैं।
अतिरिक्त दिशानिर्देशों का उद्देश्य भ्रामक विज्ञापनों, निराधार दावों से निपटना और स्वास्थ्य और कल्याण समर्थन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

दिशानिर्देशों के तहत, मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्रमाणन प्राप्त प्रमाणित चिकित्सा चिकित्सकों और स्वास्थ्य और फिटनेस विशेषज्ञों को जानकारी साझा करते समय, उत्पादों या सेवाओं को बढ़ावा देने या स्वास्थ्य संबंधी कोई भी दावा करते समय यह बताना होगा कि वे प्रमाणित स्वास्थ्य/फिटनेस विशेषज्ञ और चिकित्सा व्यवसायी हैं।

डॉ मनसुख मंडाविया ने लिम्फैटिक फाइलेरियासिस के लिए वार्षिक राष्ट्रव्यापी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (MDA) पहल के दूसरे चरण का उद्घाटन किया

भारत मिशन मोड, मल्टी-पार्टनर, मल्टी-सेक्टर टारगेटेड ड्राइव के माध्यम से वैश्विक लक्ष्य से तीन साल पहले 2027 तक लिम्फैटिक फाइलेरिया को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रोफेसर एस. पी. सिंह भगेल की उपस्थिति में वार्षिक राष्ट्रव्यापी जन औषधि प्रशासन (MDA) पहल के दूसरे चरण का उद्घाटन करते हुए यह बात कही।

केंद्रीय मंत्री ने आगे जोर देकर कहा कि "जनभागीदारी और 'संपूर्ण सरकार' और 'संपूर्ण समाज' दृष्टिकोण के माध्यम से, हम देश से इस बीमारी को खत्म करने में सक्षम होंगे"।

10 अगस्त, 2023 से शुरू होने वाला दूसरा चरण, 9 स्थानिक राज्यों (असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश) के 81 जिलों को कवर करेगा।

उप मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़, श्री. टीएस सिंह देव, उपमुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, श्री ब्रिजेश पाठक, श्री निरंजन पुजारी, स्वास्थ्य मंत्री, ओडिशा, श्री केशव महंत, स्वास्थ्य मंत्री, असम और श्री बन्ना गुप्ता, स्वास्थ्य मंत्री, झारखंड वर्चुअल मोड में उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए।

संसद ने केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 और एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया

संसद ने केंद्रीय वस्तु और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 और एकीकृत वस्तु और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित कर दिया।

लोकसभा ने इन विधेयकों को बिना चर्चा के ध्वनि मत से पारित कर दिया।

बाद में राज्यसभा ने भी विधेयकों को ध्वनि मत से लौटा दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये बिल पेश किए

केंद्रीय वस्तु और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम 2017 में संशोधन करना चाहता है, जबकि एकीकृत वस्तु और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 एकीकृत वस्तु और सेवा कर अधिनियम 2017 में संशोधन करना चाहता है।

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग और आभासी डिजिटल संपत्ति की अभिव्यक्तियों को परिभाषित करने का प्रयास करता है।

विधेयक के प्रावधानों के अनुसार, ऑनलाइन गेमिंग का मतलब इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर गेम की पेशकश है और इसमें मनी गेमिंग भी शामिल है।

विधेयक में कहा गया है कि ऑनलाइन मनी गेमिंग का मतलब ऑनलाइन गेमिंग है जिसमें खिलाड़ी पैसे जीतने की उम्मीद में आभासी डिजिटल संपत्तियों सहित पैसे का भुगतान या जमा करते हैं।

एकीकृत वस्तु और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 ऑनलाइन जानकारी और डेटा एक्सेस या पुनर्प्राप्ति सेवाओं की परिभाषा से ऑनलाइन मनी गेमिंग को बाहर करने के लिए एकीकृत वस्तु और सेवा कर अधिनियम 2017 में संशोधन करना चाहता है।
GST परिषद ने पिछले महीने हुई अपनी 50वीं बैठक में कैसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग में दांव के पूर्ण अंकित मूल्य पर 28 प्रतिशत कर लगाने की सिफारिश की थी।

डॉ. भारती प्रवीण पवार ने ERMED कंसोर्टियम: डिजिटल स्वास्थ्य परिवर्तन के लिए पुस्तकालयों को सशक्त बनाना पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया

डॉ भारती प्रवीण पवार केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री ने राष्ट्रीय मीडिया लाइब्रेरी में मेडिसिन में इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों (ERMED) कंसोर्टियम: डिजिटल स्वास्थ्य परिवर्तन के लिए पुस्तकालयों को सशक्त बनाने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया।
ERMED भारत के चिकित्सा परिदृश्य के भीतर सहयोगी उत्कृष्टता और परिवर्तनकारी प्रभाव के लिए और चिकित्सा बिरादरी की विविध सूचना आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता के लिए खड़ा है।
ERMED कंसोर्टियम एक्सेस सुविधा को 14 एम्स और यहां तक कि आयुष अनुसंधान कॉलेजों सहित 74 चयनित सरकारी संस्थानों तक बढ़ा दिया गया है/ इसे संस्थानों तक भी बढ़ाया गया है।
केंद्रीय राज्य मंत्री ने सुझाव दिया कि ERMED कंसोर्टियम में अधिक चिकित्सा ई-संसाधनों को शामिल किया जाना चाहिए जो सभी के लिए सुलभ हों।
अभूतपूर्व खोजों, नई तकनीकों और रोगी देखभाल में प्रगति के कारण चिकित्सा की दुनिया लगातार विकसित हो रही है। तेजी से बदलते इस परिदृश्य में, आजीवन सीखने के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता।
चिकित्सा परिशुद्धता और करुणा का क्षेत्र है, जहां व्यक्तियों का जीवन स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के ज्ञान, कौशल और विशेषज्ञता पर निर्भर करता है।

अक्षय ऊर्जा अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम 2025-26 तक लागू किया जा रहा है

केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा और बिजली मंत्री ने बताया है कि व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा लाई गई "प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2023" ने अपने "फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज रेडीनेस इंडेक्स" में भारत को 46वें स्थान पर रखा है।
मंत्री ने बताया कि हालांकि सरकार ने हरित ऊर्जा परिवर्तन की दिशा में पिछले वर्ष के दौरान अनुसंधान एवं विकास निवेश पर कोई शोध/सर्वेक्षण नहीं किया है, पहले डॉ. अनिल काकोडकर (पूर्व अध्यक्ष, परमाणु) की अध्यक्षता में विशेषज्ञों के एक बाहरी पैनल के साथ एक समिति का गठन किया गया था।
समिति ने समग्र अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम और वित्त पोषण तंत्र की समीक्षा की और देश में ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने के अंतिम उद्देश्य के साथ वर्तमान जोर वाले क्षेत्रों की पहचान की।
समिति की सिफारिशों के आधार पर, अक्षय ऊर्जा अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम (RE-RTD) को 228.00 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ 2021-22 से 2025-26 की अवधि के दौरान जारी रखा गया है।
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय नई और नवीकरणीय ऊर्जा के व्यापक अनुप्रयोगों के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकियों और विनिर्माण को कुशलतापूर्वक और लागत प्रभावी ढंग से विकसित करने के लिए विभिन्न अनुसंधान संस्थानों और उद्योगों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम लागू कर रहा है।

यह सरकारी/गैर-लाभकारी अनुसंधान संगठनों को 100% तक और उद्योग, स्टार्टअप, निजी संस्थानों, उद्यमियों और विनिर्माण इकाइयों को 70% तक वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

पीएम गतिशक्ति के तहत 53वीं राष्ट्रीय योजना समूह की बैठक में 6 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की सिफारिश की गई

53वें राष्ट्रीय योजना समूह (NPG) का आयोजन नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग में विशेष सचिव, लॉजिस्टिक्स श्रीमती सुमिता डावरा की अध्यक्षता में किया गया।

बैठक में सदस्य विभागों और मंत्रालयों अर्थात सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, रेल मंत्रालय, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय और नीति आयोग की सक्रिय भागीदारी देखी गई।

बैठक के दौरान, छह परियोजनाएं, 3 रेलवे मंत्रालय परियोजनाएं और 3 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय परियोजनाएं, जिनकी कुल परियोजना लागत रु 28,875.16 करोड़ का मूल्यांकन किया गया।

इन परियोजनाओं से भीड़भाड़ और अत्यधिक आबादी वाले क्षेत्रों को दरकिनार करके और यात्रा के समय को कम करके विभिन्न गांवों और प्रमुख औद्योगिक व्यापार केंद्रों तक कनेक्टिविटी में सुधार होने की उम्मीद है।

प्रस्तावित परियोजनाओं से व्यावसायिक अवसरों का विस्तार होने और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने की भी उम्मीद है।

एक रेलवे परियोजना, बारबिल-नयागढ़-बारसुआं और भद्रसाही- किरीबुरू, जिसकी कुल परियोजना लागत 12,532.87 करोड़ रुपये है। दक्षिण पूर्व रेलवे के मौजूदा स्टेशनों बारबिल, बारसुआन और किरीबुरु और पूर्वी तट रेलवे के नयागढ़ को जोड़ने का मूल्यांकन एनपीजी द्वारा क्षेत्र विकास दृष्टिकोण के गतिशक्ति सिद्धांतों पर किया गया था।

यह रेलवे संरेखण ओडिशा राज्य के सुंदरगढ़ और क्योंझर जिलों और झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले की प्रमुख खदानों को जोड़ता है।

संस्कृति मंत्रालय दिल्ली में सांसदों की 'हर घर तिरंगा' बाइक रैली का आयोजन करेगा

आज़ादी का अमृत महोत्सव (AKAM) के तत्वावधान में 13 अगस्त 2023 से 15 अगस्त 2023 तक पूरे देश में "हर घर तिरंगा" मनाया जाएगा, जिसमें लोगों को अपने परिसरों में झंडे फहराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

हर घर तिरंगा अभियान की व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने और उच्च जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में संसद सदस्यों और मंत्रियों के साथ एक तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया जा रहा है।

बाइक रैली को भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस अवसर पर संस्कृति, पर्यटन और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी भी उपस्थित रहेंगे।

भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ द्वारा हरी झंडी दिखाने के बाद बाइक रैली इंडिया गेट सर्कल तक पहुंचेगी।

रैली कर्तव्य पथ को पार करते हुए इंडिया गेट का एक चक्कर पूरा करेगी और मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में समाप्त होगी।

आज़ादी का अमृत महोत्सव (AKAM) के बारे में

'आज़ादी का अमृत महोत्सव (AKAM)' प्रगतिशील स्वतंत्र भारत के 75 गौरवशाली वर्षों के उपलक्ष्य में चलने वाला एक उत्सव है।

भारत सरकार की इस पहल का उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम और इस देश द्वारा हासिल किए गए मील के पत्थर पर ध्यान केंद्रित करना है।

AKAM भारत के उन लोगों को समर्पित है जिन्होंने देश के विकास और इसकी विकासवादी यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

'हर घर तिरंगा' के बारे में

नागरिकों को अपने घरों में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 13 से 15 अगस्त 2022 तक 'हर घर तिरंगा' अभियान शुरू किया गया था।

अभियान के पीछे का विचार लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना पैदा करना और भारत की यात्रा और इस महान राष्ट्र के निर्माण में योगदान देने वाले लोगों को याद दिलाना है।

मंत्रालय में सचिव श्री अल्केश कुमार शर्मा ने ग्रामीण समुदायों की विद्युत ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए नवीकरणीय ऊर्जा माइक्रोग्रिड पावर प्लांट का उद्घाटन किया

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव श्री अल्केश कुमार शर्मा ने राष्ट्रीय विद्युत इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी मिशन (NAMPET) कार्यक्रम के भाग के रूप में सी-डैक, तिरूवनंतपुरम द्वारा विकसित ग्रामीण समुदायों की विद्युत ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए हाइब्रिड ग्रीन एनर्जी माइक्रोग्रिड की स्वदेशी प्रौद्योगिकी का शुभारंभ हाथी पुनर्वास केन्द्र (ERC), कोट्टूर, तिरूवनंतपुरम में किया।

MeitY सी-डैक के माध्यम से अद्वितीय प्रौद्योगिकी विकास और तैनाती को साकार करने के लिए प्राथमिकता दे रहा है और भारी प्रयास कर रहा है।

विश्वसनीय हरित ऊर्जा-आधारित माइक्रोग्रिड ईआरसी में पशु चिकित्सा अस्पताल प्रणालियों में महत्वपूर्ण प्रणालियों के लिए बिजली समाधान प्रदान करता प्रतीत होता है।

माइक्रोग्रिड के बारे में:

नवीकरणीय ऊर्जा माइक्रोग्रिड एक स्वायत्त, स्थानीयकृत और आत्मनिर्भर ऊर्जा प्रणाली है जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपने प्राथमिक उत्पादन इनपुट के रूप में शामिल करती है।

नवीकरणीय ऊर्जा माइक्रोग्रिड के प्रमुख निर्माण खंडों में विभिन्न घटक और सिस्टम शामिल हैं जो स्थानीय और टिकाऊ तरीके से ऊर्जा उत्पन्न करने, भंडारण, प्रबंधन और वितरित करने के लिए मिलकर काम करते हैं। ईआरसी में कार्यान्वित माइक्रोग्रिड योजना में, सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग करके एक अद्वितीय 25 किलोवाट पावर कंडीशनिंग यूनिट (PCU) तकनीक, 50 किलोहर्ट्ज पर चलने वाला एक वाइड बैंड गैप (WBG) सेमीकंडक्टर डिवाइस और भारी 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर से बचने से सिस्टम बहुत कॉम्पैक्ट और कंटेनर-आधारित तैनाती बन जाता है। एक दूरस्थ स्थान में साकार होता है उपरोक्त प्रौद्योगिकी CDAC द्वारा विकसित की गई है।

सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत मार्च 2023 तक 2,900 करोड़ रुपये बांटे

सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम के तहत मार्च 2023 तक 2,900 करोड़ रुपये बांटे हैं

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) के सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा कि सरकार को योजना के तहत लाभ चाहने वाली पात्र फर्मों को लगभग 13 हजार करोड़ रुपये वितरित करने की उम्मीद है और इस संबंध में योजना में बदलाव करने की कवायद चल रही है। उन क्षेत्रों के लिए जिन्होंने अभी तक अच्छी गति नहीं पकड़ी है।

श्री सिंह ने कहा कि चालू वर्ष से वितरण संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

इस योजना की घोषणा 2021 में 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ दूरसंचार, सफेद सामान, कपड़ा, चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण, ऑटोमोबाइल, ड्रोन और फार्मा सहित 14 क्षेत्रों के लिए की गई थी।

प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के सागर में राष्ट्र विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उन्हें समर्पित किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मध्य प्रदेश के सागर में विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित किया। परियोजनाओं में 100 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनने वाले संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास जी स्मारक की आधारशिला रखना, 1580 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विकसित होने वाली दो सड़क परियोजनाएं और राष्ट्र को समर्पित करना शामिल है। 2475 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से देश के लिए कोटा-बीना रेल मार्ग विकसित किया गया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि संत रविदास जी स्मारक और संग्रहालय का शिलान्यास ऐसे समय में हो रहा है जब देश ने आजादी के 75 साल पूरे कर लिए हैं और अगले 25 साल का अमृत काल हमारे सामने है।
उन्होंने हमारे अतीत से सबक लेने के साथ-साथ भूमि की विरासत को आगे बढ़ाने पर जोर दिया।
देश ने एक हजार साल का सफर पूरा कर लिया है, प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज में बुराइयों का आना एक स्वाभाविक घटना है

DPIIT और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने संयुक्त रूप से सरस आजीविका स्टोर में 'एक जिला एक उत्पाद' दीवार लॉन्च की

एक जिला एक उत्पाद (ODOP) कार्यक्रम, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के तहत एक पहल (DPIIT), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने नई दिल्ली में ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ अपना सहयोग शुरू किया।
ग्रामीण विकास मंत्रालय में अपर सचिव श्री चरणजीत सिंह और DPIIT की निदेशक श्रीमती सुप्रिया देवस्थली ने कल सरस आजीविका स्टोर में ODOP दीवार के उद्घाटन के साथ इस रणनीतिक सहयोग का अनावरण किया।
सरस आजीविका स्टोर पर ODOP वॉल इन दो महत्वपूर्ण मंत्रालयों के बीच सामंजस्यपूर्ण साझेदारी के प्रतीक के रूप में खड़ी है।
सरस आजीविका, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय, दीनदयाल अंत्योदय (DAY-NRLM) की एक पहल है।
सरस आजीविका महिला सशक्तिकरण का एक मजबूत समर्थक है, जिसका विशेष ध्यान महिला कारीगरों और स्वयं सहायता समूहों (SHG) के उत्थान पर है।
अपने अच्छी तरह से तैयार किए गए उत्पादों के लिए एक विशेष बाज़ार बनाकर, सरस आजीविका इन महिलाओं के कौशल और प्रतिभा को बढ़ावा देती है, जिससे उन्हें स्वतंत्र उद्यमी बनने में मदद मिलती है।
एक महत्वपूर्ण सहयोग में, ODOP कार्यक्रम ने उत्पाद टैगिंग और स्टोरी कार्ड जैसी नवीन सुविधाओं को लागू करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ हाथ मिलाया है।
इन अतिरिक्तताओं का उद्देश्य उपभोक्ताओं और उत्साही लोगों को एम्पोरियम की ओर मार्गदर्शन करना है, जिससे बिक्री को बढ़ावा मिलेगा और भारत के असाधारण उत्पादों की दृश्यता बढ़ेगी।

श्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीधाम में इफको नैनो DAP (लिक्विड) प्लांट का भूमिपूजन किया और आधारशिला रखी

केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीधाम में इफको नैनो DAP (लिक्विड) प्लांट का भूमिपूजन किया और आधारशिला रखी।
इस अवसर पर इफको के अध्यक्ष श्री दिलीप संघानी सहित कई गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सहकारिता मंत्रालय का गठन कर 'सहकार से समृद्धि' की दृष्टि से देश के 15 करोड़ किसानों को समृद्ध बनाने का लक्ष्य रखा है।
गांधीधाम में आगामी संयंत्र इफको के मौजूदा 3 मिलियन टन डीएपी उत्पादन संयंत्र से अधिक उत्पादन करेगा।
केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि तरल उर्वरक देश की अर्थव्यवस्था और कृषि क्षेत्र को बहुआयामी लाभ देने वाला है।
नैनो DAP (तरल) के छिड़काव से भूमि प्रदूषित नहीं होगी, जिससे प्राकृतिक खेती में आसानी होगी, कृषि उत्पादन के साथ-साथ मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी और भूमि संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।
केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के "सहकार से समृद्धि" के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए, सहकारिता मंत्रालय ने तीन बहु-राज्य सहकारी समितियों का गठन किया है और ये तीन समितियां इन तीन लक्ष्यों को पूरा करेंगी।

श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने राष्ट्रीय संग्रहालय में भारतीय कला प्रदर्शनी में वुमेन इन फोकस: विज़ुअलाइज़िंग फेमिनिन कंस्ट्रक्शंस का उद्घाटन किया

विदेश एवं संस्कृति राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने राष्ट्रीय संग्रहालय में 'वीमेन इन फोकस: विज़ुअलाइज़िंग फेमिनिन कंस्ट्रक् चर्स' नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।
प्रदर्शनी 12 अगस्त, 2023 से अजंता हॉल, प्रथम तल, राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्ली में जनता के देखने के लिए खुली रहेगी।
यह प्रदर्शनी स्त्रीत्व के लेंस के माध्यम से शक्ति, संरक्षण और धर्मपरायणता की बहुआयामी पारंपरिक धारणाओं की जांच करने पर केंद्रित है।
ये तीन रचनाएँ पारंपरिक रूप से धार्मिक और ऐतिहासिक प्रवचनों के घिसे-पिटे खांचे में पुरुषत्व से जुड़ी हुई हैं।
यह प्रदर्शनी 'महिला आवाज' का प्रतिनिधित्व करने वाली भारतीय कला और इतिहास की पारसांस्कृतिक धारणाओं को प्रस्तुत करती है।
'वीमेन इन फोकस' नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन समारोह राष्ट्रीय संग्रहालय द्वारा प्रकाशित दो अतिरिक्त प्रकाशनों की पुस्तक विमोचन के साथ भी हुआ।
पहला है डॉ. बुद्ध रश्मि मणि और श्री सानिब कुमार सिंह की पुस्तक: बुद्ध, बौद्ध धर्म और बौद्ध कला का हिंदी अनुवाद और दूसरा संजीब कुमार सिंह और गुंजन कुमार श्रीवास्तव की सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय नामक पुस्तक का तीसरा संस्करण।

श्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत में प्रशिक्षुता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए NAPS में DBT की शुरुआत की

श्री धर्मेन्द्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री ने राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (NAPS) में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) का शुभारंभ किया।
NAPS में DBT के शुभारंभ को चिह्नित करते हुए मंत्री द्वारा एक लाख प्रशिक्षुओं को लगभग 15 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई।
सभी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के सक्रिय प्रयासों के कारण सक्रिय प्रतिष्ठानों की संख्या 2018-19 में 6,755 से बढ़कर 2023-24 में 40,655 हो गई।
सभी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के सक्रिय प्रयासों के कारण सक्रिय प्रतिष्ठानों की संख्या 2018-19 में 6,755 से बढ़कर 2023-24 में 40,655 हो गई।
राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना में डीबीटी का शुभारंभ हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के शिक्षुता कौशल को महत्वाकांक्षी बनाने के साथ-साथ एनईपी में कल्पना के अनुसार सीखने के साथ-साथ कमाई को प्रोत्साहित करने के दृष्टिकोण को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

Click Here to Subscribe Our Yearly Mock Test Package

उन्होंने DBT के माध्यम से वजीफा पाने वाले सभी 1 लाख प्रशिक्षुओं को बधाई दी

निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (IEPFA) और कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) ने दिल्ली-NCR के लिए "निवेशक सारथी" वैन लॉन्च की

निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (IEPFA) की CEO सुश्री अनीता शाह अकेला ने आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में आईईपीएफए के मुख्यालय से "निवेश सारथी" नामक दो निवेशक जागरूकता वैन लॉन्च कीं, जो "जागरूकता से वित्तीय स्वतंत्रता तक" विषय के साथ संरेखित हैं।

इस रणनीतिक पहल का उद्देश्य महत्वपूर्ण वित्तीय शिक्षा का प्रसार करना और दिल्ली NCR क्षेत्र में धोखाधड़ी वाली योजनाओं के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना है।

ये विशेष रूप से सुसज्जित वैन "हिसाब की किताब" चलाने वाली टीवी स्क्रीन से सुसज्जित हैं, जो IEPFA द्वारा सावधानीपूर्वक विकसित की गई निवेशक जागरूकता फिल्मों की एक श्रृंखला है।

इसके अलावा, वे प्रभावी संचार सुनिश्चित करने के लिए एक सार्वजनिक संबोधन प्रणाली से लैस हैं।

इन उपकरणों को पूरक करते हुए, एक सोच-समझकर डिज़ाइन किया गया ब्रोशर वित्तीय जागरूकता के सभी आवश्यक तत्वों को संकलित करता है।

"निवेशक सारथी" की यात्रा लोधी रोड पर CSC कार्यालय में समाप्त हुई, जो आगे और अधिक सत्र आयोजित करने के उद्देश्य से वित्तीय जागरूकता और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक सफल और प्रभावशाली अभियान के अंत का प्रतीक है।

IEPFA के बारे में

निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (IEPFA) की स्थापना 7 सितंबर, 2016 को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में निवेशकों को शेयरों, बिना दावे वाले लाभांश और परिपक्व जमा / डिबेंचर के रिफंड के लिए निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष के प्रशासन के लिए की गई थी।

CSC के बारे में

पूर्ववर्ती कॉमन सर्विसेज सेंटर (CSC) योजना के मूल्यांकन के आधार पर, भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया के तहत अगस्त 2015 में CSC 2.0 परियोजना शुरू की है।

CSC 2.0 परियोजना का उद्देश्य विभिन्न नागरिक-केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए देश भर में 2.50 लाख ग्राम पंचायतों (GP) में कम से कम एक CSC स्थापित करना है यह परियोजना CSC-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (CSC स्पेशल पर्पज व्हीकल, CSCSP) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

यह एक आत्मनिर्भर उद्यमिता मॉडल है जो ग्राम स्तरीय उद्यमियों (VLES) द्वारा चलाया जाता है।

MeitY सचिव श्री अलकेश कुमार शर्मा ने 'ग्राफीन-अरोड़ा कार्यक्रम' लॉन्च किया

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के सचिव श्री अलकेश कुमार शर्मा ने केरल के मेकर विलेज कोच्चि में एक समारोह में 'ग्राफीन-अरोड़ा कार्यक्रम' लॉन्च किया।

यह कार्यक्रम डिजिटल विश्वविद्यालय केरल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), भारत सरकार और केरल सरकार और उद्योग भागीदारों के संयुक्त वित्त पोषण के साथ 94.85 करोड़ रुपये के कुल बजट परिव्यय के साथ लागू किया जाएगा, जिसमें कार्बोरंडम प्राइवेट लिमिटेड मुख्य उद्योग भागीदारों में से एक के रूप में शामिल हो गया।

विकसित स्टार्टअप उत्पादों के साथ-साथ, मेकर्स विलेज, कोच्चि में स्थापित इंडिया इनोवेशन सेंटर ग्राफीन (IICG) जैसे अनुसंधान और विकास केंद्रों में विकसित प्रौद्योगिकियों और उत्पादों पर भी व्यावसायीकरण के लिए विचार किया जाएगा।

डॉ. रतन केलकर, IAS, सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी विभाग, सरकार; श्री. सुमन बिल्ला IAS, प्रमुख सचिव उद्योग विभाग, गोके; डॉ. साजी गोपीनाथ, कुलपति, डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल; श्रीमती सुनीता वर्मा, समूह समन्वयक, MeitY; प्रोफेसर एलेक्स जेम्स, सीआई, ग्राफीन अरोरा कार्यक्रम, और श्री कामेश गुप्ता, सह-सीआई, ग्राफीन अरोरा; इस अवसर पर कार्बोरंडम प्राइवेट लिमिटेड के डॉ. पीएस जयन भी उपस्थित थे।

श्री परषोत्तम रूपाला द्वारा गुजरात के नर्मदा में समावेशी विकास के तहत पशुधन के लिए 'ए-हेल्प' कार्यक्रम और बांझपन शिविर का शुभारंभ किया गया

केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री, श्री परषोत्तम रूपाला ने गुजरात राज्य में बांझपन शिविर के साथ-साथ 'ए-हेल्प' (पशुधन उत्पादन के स्वास्थ्य और विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट) कार्यक्रम का अनावरण किया है।
भारत सरकार का पशुपालन और डेयरी विभाग, समावेशी विकास के तहत पशुधन जागृति अभियान के हिस्से के रूप में इन पहलों का नेतृत्व कर रहा है।
इस अवसर पर भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग में अतिरिक्त सचिव (CDD) सुश्री वर्षा जोशी और कामधेनु विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ एनएच केलावाला भी उपस्थित थे।
केंद्रीय मंत्री श्री परषोत्तम रूपाला ने विशेषकर गुजरात में पशुधन क्षेत्र के व्यापक विकास में पशुधन और महिलाओं द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला।
'ए-हेल्प' कार्यक्रम और बांझपन शिविर महिलाओं को सशक्त बनाने, पशुधन उत्पादकता बढ़ाने और क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक हो सकता है।
'ए-हेल्प' कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को प्रशिक्षित एजेंटों के रूप में शामिल करके सशक्त बनाना है जो रोग नियंत्रण, राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM) के तहत कृत्रिम गर्भाधान, पशु टैगिंग और पशुधन बीमा में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

श्री अमित शाह ने हर घर तिरंगा अभियान के दौरान नई दिल्ली में अपने आवास पर तिरंगा फहराया और तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी साझा की

केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने हर घर तिरंगा अभियान के दौरान नई दिल्ली में अपने आवास पर तिरंगा फहराया और तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी साझा की।
ट्वीट के जरिए श्री अमित शाह ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस से पहले भारतीय आसमान में लहराते लाखों तिरंगे भारत को फिर से महानता का प्रतीक बनाने की देश की सामूहिक इच्छा का प्रतीक हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा आहूत हर घर तिरंगा अभियान पूरे देश में चल रहा है।
उन्होंने भारत के सभी नागरिकों से अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और सेल्फी अपलोड करने की अपील कीhttp://hargarhtiranga.com.
उन्होंने सभी से अपील की कि वे अपने साथी नागरिकों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें। श्री शाह ने कहा कि भारत की एकता और भाईचारे की भावना को संजोते हुए उन्होंने दिल्ली में अपने निवास पर तिरंगा फहराया है।
गृह मंत्री ने 'हर घर तिरंगा' अभियान में भाग लेने के लिए प्राप्त प्रशंसा प्रमाण पत्र भी साझा किया।

केंद्र सरकार सस्ती कीमतों पर दवाएं उपलब्ध कराने के लिए 25000 जन औषधि केंद्र खोलेगी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान कहा कि सरकार की 'जन औषधि केंद्रों' की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 करने की योजना है।

उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्र ने लोगों खासकर मध्यम वर्ग को एक नई शक्ति दी है। यदि किसी को मधुमेह का पता चलता है तो मासिक बिल रु. 3000 जमा हो जाते हैं
जन औषधि केंद्रों के माध्यम से जो दवाएं 100 रुपये में मिलती हैं, हम उन्हें 10 से 15 रुपये में दे रहे हैं।
सरकार पारंपरिक कौशल वाले लोगों के लिए अगले महीने 13,000 से 15,000 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ विश्वकर्मा योजना शुरू करेगी।
सरकार 'जन औषधि केंद्र' (सब्सिडी वाली दवा की दुकानें) की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 करने पर काम कर रही है।

सरकार ने 169 शहरों में 10,000 ई-बसों के लिए 57,613 करोड़ रुपये मंजूर किए

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिटी बस संचालन को बढ़ाने के लिए "PM-ईबस सेवा" को मंजूरी दे दी है। बिना संगठित बस सेवा वाले शहरों को प्राथमिकता दी गई है।
169 शहरों में 10,000 ई-बसें तैनात की जाएंगी, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में एक प्रेस वार्ता में कहा।
इस योजना से 45,000-55,000 प्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न होने का अनुमान है।
योजना की अनुमानित लागत 57,613 करोड़ रुपये है, जिसमें से 20,000 करोड़ रुपये केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे और शेष राज्य सरकारें प्रदान करेंगी।
PPP मोड के तहत होने वाली बसों की खरीद में प्रतिस्पर्धी बोली होगी और निजी खिलाड़ी आगे आ सकते हैं।
यह योजना 2037 तक चलेगी।
कैबिनेट ने रेल मंत्रालय की सात परियोजनाओं को मंजूरी देकर रेलवे बुनियादी ढांचे को बड़ा बढ़ावा देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी जिसकी अनुमानित लागत लगभग 32,500 करोड़ रुपये है।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये परियोजनाएं भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 2,339 किलोमीटर की दूरी जोड़ देंगी।
ये नई रेलवे परियोजनाएं नौ राज्यों अर्थात् यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना के 35 जिलों को कवर करेंगी।
प्रस्तावित परियोजनाएं मौजूदा लाइन क्षमता को बढ़ाने, ट्रेन परिचालन को सुचारू बनाने, भीड़भाड़ को कम करने और यात्रा और परिवहन को आसान बनाने में मदद करेंगी।
कैबिनेट ने 14,903 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ डिजिटल इंडिया परियोजना के विस्तार को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री ने कैबिनेट बैठक में 14,903 करोड़ रुपये के परिव्यय वाले डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है
विस्तारित डिजिटल इंडिया परियोजना के तहत, राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (NCM) के तहत नौ और सुपर कंप्यूटर जोड़े जाएंगे।

सत्यजीत रे की पाथेर पांचाली की स्क्रीनिंग के साथ G-20 फिल्म महोत्सव नई दिल्ली में शुरू होगा

जी20 फिल्म महोत्सव 16 अगस्त को नई दिल्ली में शुरू होगा।
सत्यजीत रे की "पाथेर पांचाली''ओपनिंग फिल्म होगी
महोत्सव का उद्देश्य सिनेमा के क्षेत्र में जी20 और आमंत्रित देशों के बीच मौजूद जीवंत और सहयोगात्मक साझेदारी का जश्न मनाना और प्रदर्शित करना है।
इस महोत्सव का आयोजन इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (IIC) और विदेश मंत्रालय के जी20 सचिवालय द्वारा किया जाता है।
इसका उद्घाटन दिग्गज अभिनेता विक्टर बनर्जी और भारत के जी20 शेरपा अमिताभ कांत करेंगे।
यह आयोजन 2 सितंबर तक चलेगा।

पीएम मोदी ने भारत में WHO महानिदेशक का स्वागत किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, WHO-वैश्विक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत पहुंचे विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉ. टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस का स्वागत किया।
श्री मोदी ने डॉ. टेड्रोस के लिए 'तुलसी भाई' नाम का इस्तेमाल किया, यह नाम प्रधानमंत्री ने महानिदेशक को उनकी पिछली यात्रा पर दिया था।
डॉ. टेड्रोस गुजरात के गांधीनगर में इस महीने की 17 से 18 तारीख तक पारंपरिक चिकित्सा पर WHO वैश्विक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे।
आयुष मंत्रालय ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें डॉ. टेड्रोस डांडिया करते नजर आ रहे हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनके अच्छे मित्र तुलसी भाई नवरात्रि के लिए अच्छी तरह तैयार हैं

कैबिनेट ने पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को समर्थन देने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए 13,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी

सरकार ने 13 हजार करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ ग्रामीण और शहरी भारत के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों का समर्थन करने के लिए पीएम विश्वकर्मा की योजना को मंजूरी दे दी है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए संचार और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, योजना के तहत पहली बार में अठारह पारंपरिक व्यापारों को शामिल किया जाएगा।
इनमें बढ़ई, नाव बनाने वाले, सोनार, राज मिस्त्री, खिलौना बनाने वाले, लोहार और कुम्हार शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि यह योजना कौशल उन्नयन, टूलकिट प्रोत्साहन, डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन और विपणन सहायता प्रदान करेगी।
श्री वैष्णव ने कहा, इस योजना के तहत एक लाख रुपये तक का ऋण पांच प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा
मंत्री ने कहा, इस योजना से 30 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित होंगे

जुलाई 2023 महीने के लिए DARPG द्वारा CPGRAMS पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन पर 12वीं रिपोर्ट जारी की गई

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) ने जुलाई 2023 के लिए राज्यों के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) की 12वीं मासिक रिपोर्ट जारी की।
उक्त रिपोर्ट सार्वजनिक शिकायतों के प्रकार और श्रेणियों तथा निपटान की प्रकृति का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करती है।
जुलाई 2023 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कुल 69,523 शिकायतों का निवारण किया गया।
CPGRAMS पोर्टल पर प्राप्त राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की शिकायतों की लंबितता कम होकर राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों में 1,79,077 हो गई है।
मई 2023 से, DARPG ने CPGRAMS पोर्टल पर उनके प्रदर्शन के आधार पर राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की रैंकिंग की प्रक्रिया शुरू की है।
वर्तमान में, DARPG राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को 4 श्रेणियों में रैंक करता है, यानी उत्तर पूर्वी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, साथ ही राज्यों के लिए दो अन्य श्रेणियों को शिकायतों की प्राप्तियों की संख्या के आधार पर विभाजित किया गया है।

Click Here to Subscribe Our Yearly Mock Test Package

यह रैंकिंग राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को उनकी शिकायत निवारण प्रणाली की समीक्षा और सुव्यवस्थित करने और अन्य राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के साथ तुलनात्मक मूल्यांकन करने में सहायता करने के भारत सरकार के प्रयास का हिस्सा है। शिकायत निवारण सूचकांक में 2 आयाम और 4 संकेतक शामिल हैं।

क्र.सं.	समूह	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	रैंक 1	रैंक 2	रैंक 3
1	समूह अ	उत्तर-पूर्वी राज्य	सिक्किम	असम	अरुणाचल प्रदेश
2	ग्रुप बी	केंद्र शासित प्रदेश	लक्षद्वीप	अंडमान और निकोबार	लद्दाख
3	ग्रुप सी	शिकायतों वाले राज्य >=20000	उतार प्रदेश।	झारखंड	राजस्थान Rajasthan
4	ग्रुप डी	शिकायतों वाले राज्य <20000	तेलंगाना	छत्तीसगढ	केरल

NHAI ने पुलों और अन्य

संरचनाओं के डिजाइन और निर्माण की समीक्षा के लिए डिजाइन प्रभाग की स्थापना की

NHAI ने एक डिजाइन डिवीजन की स्थापना की है जो देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों, संरचनाओं, सुरंगों और आरई दीवारों की योजना, डिजाइन, निर्माण और रखरखाव के लिए नीति और दिशानिर्देश तैयार करेगा।

प्रभाग परियोजना की तैयारी, नए पुलों के निर्माण, मौजूदा पुराने/संकटग्रस्त पुलों की स्थिति का सर्वेक्षण और पुनर्वास, और महत्वपूर्ण पुलों, संरचनाओं, सुरंगों और आरई दीवारों के स्वास्थ्य की जांच के लिए उपकरण की समीक्षा करेगा।

यह स्टैंडअलोन पुलों और विशेष संरचनाओं की भी समीक्षा करेगा, जो DPR चरण में हैं जहां DPR जून 2023 के बाद शुरू हुई थी।

इसके अलावा, प्रभाग यादृच्छिक आधार पर 200 मीटर से अधिक के विस्तार वाले चयनित पुलों और संरचनाओं और विशेष संरचनाओं के निर्माण के तरीकों, अस्थायी संरचनाओं, उठाने और लॉन्च करने के तरीकों और प्रीस्ट्रेसिंग तरीकों की समीक्षा भी करेगा।

इसके अलावा, प्रभाग सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, NHAI, NHIDCL के अधिकारियों और ठेकेदारों/सलाहकारों के कर्मियों के लिए भारतीय राजमार्ग इंजीनियर अकादमी (IAHE), नोएडा और भारतीय रेलवे सिविल इंजीनियरिंग संस्थान (IRICEL), पुणे के माध्यम से पुलों, सुरंगों और आरई दीवारों के डिजाइन, निर्माण, पर्यवेक्षण और रखरखाव के विभिन्न पहलुओं पर प्रमाणन पाठ्यक्रम आयोजित करेगा।

कैबिनेट अनुमोदन:

सिटी बस परिचालन को बढ़ाने के लिए "पीएम-ईबस सेवा"; उन शहरों को प्राथमिकता जहां कोई संगठित बस सेवा नहीं है

प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने पीपीपी मॉडल पर 10,000 ई-बसों द्वारा सिटी बस संचालन को बढ़ाने के लिए एक बस योजना "PM-ईबस सेवा" को मंजूरी दे दी है।

इस योजना की अनुमानित लागत 57,613 करोड़ रुपये होगी, जिसमें से 20,000 करोड़ रुपये का समर्थन केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा।

यह योजना 10 वर्षों तक बस संचालन का समर्थन करेगी।

यह योजना 2011 की जनगणना के अनुसार तीन लाख और उससे अधिक आबादी वाले शहरों को कवर करेगी, जिसमें केंद्र शासित प्रदेशों, उत्तर पूर्वी क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों की सभी राजधानी शामिल हैं।
इस योजना के तहत उन शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां कोई संगठित बस सेवा नहीं है।
यह योजना सिटी बस संचालन में लगभग 10,000 बसों की तैनाती के माध्यम से 45,000 से 55,000 प्रत्यक्ष रोजगार पैदा करेगी।
योजना के दो खंड हैं:

खंड ए - सिटी बस सेवाओं को बढ़ाना:(169 शहर)

स्वीकृत बस योजना सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) मॉडल पर 10,000 ई-बसों के साथ सिटी बस संचालन को बढ़ाएगी। एसोसिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डिपो इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास/उन्नयन के लिए सहायता प्रदान करेगा; और ई-बसों के लिए मीटर के पीछे बिजली के बुनियादी ढांचे (सबस्टेशन, आदि) का निर्माण।

खंड बी- हरित शहरी गतिशीलता पहल (GUMI): (181 शहर)

इस योजना में बस प्राथमिकता, बुनियादी ढांचे, मल्टीमॉडल इंटरचेंज सुविधाएं, NCMC-आधारित स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली, चार्जिंग बुनियादी ढांचे आदि जैसी हरित पहल की परिकल्पना की गई है।
संचालन के लिए सहायता: योजना के तहत, राज्य/शहर बस सेवाओं को चलाने और बस ऑपरेटरों को भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होंगे। केंद्र सरकार प्रस्तावित योजना में निर्दिष्ट सीमा तक सब्सिडी प्रदान करके इन बस संचालन का समर्थन करेगी।

₹14,903 करोड़ के परिव्यय के साथ डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का विस्तार

माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार को मंजूरी दे दी। कुल परिव्यय ₹14,903 करोड़ है।
यह निम्नलिखित को सक्षम करेगा:
फ्यूचरस्किल्स प्राइम प्रोग्राम के तहत 6.25 लाख आईटी पेशेवरों को फिर से कुशल और उन्नत किया जाएगा;
सूचना सुरक्षा और शिक्षा जागरूकता चरण (ISEA) कार्यक्रम के तहत लाख व्यक्तियों को सूचना सुरक्षा में प्रशिक्षित किया जाएगा;
यूनिफाइड मोबाइल एप्लिकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस (UMANG) ऐप/प्लेटफॉर्म के तहत 540 अतिरिक्त सेवाएं उपलब्ध होंगी। वर्तमान में उमंग पर 1,700 से अधिक सेवाएँ पहले से ही उपलब्ध हैं;
राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत 9 और सुपर कंप्यूटर जोड़े जाएंगे। यह पहले से तैनात 18 सुपर कंप्यूटरों के अतिरिक्त है;
भाषिनी, AI-सक्षम बहु-भाषा अनुवाद उपकरण (वर्तमान में 10 भाषाओं में उपलब्ध) सभी 22 अनुसूचित 8 भाषाओं में शुरू किया जाएगा;
राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (NKN) का आधुनिकीकरण जो 1,787 शैक्षणिक संस्थानों को जोड़ता है;
डिजीलॉकर के तहत डिजिटल दस्तावेज़ सत्यापन सुविधा अब MSME और अन्य संगठनों के लिए उपलब्ध होगी;
टियर 2/3 शहरों में 1,200 स्टार्टअप को समर्थन दिया जाएगा;
स्वास्थ्य, कृषि और टिकाऊ शहरों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उत्कृष्टता के 3 केंद्र स्थापित किए जाएंगे;
12 करोड़ कॉलेज छात्रों के लिए साइबर-जागरूकता पाठ्यक्रम;
साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में नई पहल जिसमें उपकरणों का विकास और राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र के साथ 200 से अधिक साइटों का एकीकरण शामिल है।

Click Here to Subscribe Our Yearly Mock Test Package

आज की घोषणा से भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, सेवाओं तक डिजिटल पहुंच बढ़ेगी और भारत के आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स पारिस्थितिकी तंत्र को समर्थन मिलेगा।

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अधिकृत आर्थिक संचालकों की पारस्परिक मान्यता व्यवस्था

प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC), राजस्व विभाग, भारत सरकार और गृह मामलों के विभाग के बीच पारस्परिक मान्यता व्यवस्था (MRA) पर हस्ताक्षर और अनुसमर्थन को मंजूरी दे दी है।

इस व्यवस्था का उद्देश्य आयातक देश के सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा माल की निकासी में दोनों हस्ताक्षरकर्ताओं के मान्यता प्राप्त और विश्वसनीय निर्यातकों को पारस्परिक लाभ प्रदान करना है।

वैश्विक स्तर पर व्यापार को उच्च सुविधा प्रदान करते हुए आपूर्ति श्रृंखलाओं की अंत-से-अंत सुरक्षा को मजबूत करने के लिए वैश्विक व्यापार को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए अधिकृत आर्थिक ऑपरेटरों की पारस्परिक मान्यता विश्व सीमा शुल्क संगठन के मानकों के सुरक्षित ढांचे का एक प्रमुख तत्व है।

इस व्यवस्था से ऑस्ट्रेलिया में हमारे निर्यातकों को लाभ होगा और इससे दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को बढ़ावा मिलेगा।

ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियाई विश्वसनीय व्यापारी कार्यक्रम और भारत में अधिकृत आर्थिक संचालक कार्यक्रम की पारस्परिक मान्यता दोनों देशों के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर करने की तारीख से लागू होगी।

प्रस्तावित पारस्परिक मान्यता व्यवस्था के पाठ को दोनों देशों के सीमा शुल्क प्रशासन की सहमति से अंतिम रूप दिया गया है।

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेलों में सहयोग पर समझौता ज्ञापन

प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत गणराज्य के युवा मामले और खेल मंत्रालय और ऑस्ट्रेलिया सरकार के स्वास्थ्य और वृद्ध देखभाल विभाग के बीच खेल में सहयोग पर समझौता ज्ञापन (MoU) को मंजूरी दे दी है।

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेल के क्षेत्र में द्विपक्षीय आदान-प्रदान कार्यक्रम खेल विज्ञान, प्रौद्योगिकियों और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में ज्ञान और विशेषज्ञता का विस्तार करने में मदद मिलेगी; एथलीट और कोच प्रशिक्षण और विकास; खेल प्रशासन और अखंडता; खेल में जमीनी स्तर की भागीदारी; प्रमुख खेल आयोजन; खेल में विविधता और समावेशन जिसके परिणामस्वरूप अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में हमारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार होगा और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे।

ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग से होने वाले लाभ जाति, पंथ, क्षेत्र, धर्म और लिंग के बावजूद सभी खिलाड़ियों पर समान रूप से लागू होंगे।

चिकित्सा उत्पाद विनियमन के क्षेत्र में भारत और सूरीनाम के बीच समझौता ज्ञापन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल को चिकित्सा उत्पाद विनियमन के क्षेत्र में सहयोग के लिए केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और सूरीनाम गणराज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच हस् ताक्षरित समझौता ज्ञापन (MoU) से अवगत कराया गया।

भारत के राष्ट्रपति की सूरीनाम यात्रा के दौरान इस पर हस्ताक्षर किये गये थे।

इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य चिकित्सा उत्पादों से संबंधित कानूनों और विनियमों के साथ-साथ अन्य प्रासंगिक मामलों पर रचनात्मक बातचीत की सुविधा प्रदान करना है।
समझौता ज्ञापन केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) और सूरीनाम गणराज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच उनकी अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारियों के अनुरूप चिकित्सा उत्पादों के विनियमन से संबंधित मामलों में उपयोगी सहयोग और सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए एक रूपरेखा स्थापित करना चाहता है।
समझौता ज्ञापन चिकित्सा उत्पादों के निर्यात की सुविधा प्रदान करेगा जिससे विदेशी मुद्रा आय होगी। यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक कदम होगा।
दोनों देशों के नियामक अधिकारियों के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन फार्मास्युटिकल उपयोग के लिए कच्चे माल, जैविक उत्पादों, चिकित्सा उपकरणों और कॉस्मेटिक उत्पादों सहित फार्मास्यूटिकल्स के बारे में चिकित्सा उत्पादों के विनियमन की बेहतर समझ की सुविधा प्रदान करेगा।
समझौता ज्ञापन पार्टियों के अधिकार क्षेत्र के भीतर चिकित्सा उत्पादों और प्रासंगिक प्रशासनिक और नियामक मामलों से संबंधित क्षेत्रों में सूचना के आदान-प्रदान और सहयोग को बढ़ावा देगा।

दवाओं के नियमन के क्षेत्र में भारत और सूरीनाम के बीच समझौता ज्ञापन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल को सूरीनाम में भारतीय भेषज संहिता आयोग (IPC), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार और सूरीनाम गणराज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच सूरीनाम में भारतीय भेषज संहिता (IP) को मान्यता देने के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (MoU) से अवगत कराया गया।
भारत के राष्ट्रपति की सूरीनाम यात्रा के दौरान इस पर हस्ताक्षर किये गये थे।
समझौता ज्ञापन चिकित्सा उत्पादों के निर्यात को सुविधाजनक बनाएगा जिससे विदेशी मुद्रा आय होगी।
यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक कदम होगा।
भारतीय फार्माकोपिया को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता! भारतीय फार्मास्युटिकल क्षेत्र के लिए मानकों के कई लाभ हैं
भारतीय फार्माकोपिया (IP) को आधिकारिक तौर पर पांच (5) देशों द्वारा मान्यता प्राप्त है: अफगानिस्तान, घाना, नेपाल, मॉरीशस और सूरीनाम गणराज्य।
मंत्रालय उन देशों का विस्तार करना चाहता है जो IP को मान्यता देते हैं।

भारतीय रेलवे में कुल 2339 किलोमीटर की सात मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाएं, जिनकी लागत लगभग 32,500 करोड़ रुपये है

प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने केंद्र सरकार से 100% वित्त पोषण के साथ लगभग 32,500 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली रेल मंत्रालय की सात परियोजनाओं को मंजूरी दी।
मल्टी-ट्रैकिंग के प्रस्तावों से परिचालन में आसानी होगी और भीड़भाड़ कम होगी, जिससे भारतीय रेलवे के सबसे व्यस्त खंडों पर आवश्यक ढांचागत विकास उपलब्ध होगा।
9 राज्यों यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के 35 जिलों को कवर करने वाली परियोजनाओं से भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 2339 किलोमीटर की वृद्धि होगी। और राज्यों के लोगों को 7.06 करोड़ मानव दिवस रोजगार देंगे।
परियोजनाएं प्रधान मंत्री के नए भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं जो क्षेत्र में बहु-कार्य कार्यबल बनाकर क्षेत्र के लोगों को "आत्मनिर्भर" बनाएगी और उनके रोजगार/स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ाएगी।

ये परियोजनाएं मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का परिणाम हैं जो एकीकृत योजना के माध्यम से संभव हुई है और लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही के लिए निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगी।

केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान और श्रीमती निर्मला सीतारमण ने भुवनेश्वर में कुवी और देसिया पुस्तकें लॉन्च कीं

केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान, और केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने भुवनेश्वर में कुवी और देसिया किताबें लॉन्च कीं।
इस कार्यक्रम में भारत सरकार के संचार मंत्रालय के डाक विभाग की ओर से विशेष कवर जारी भी किया गया।
यह ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय, कोरापुट, डाक विभाग और एनसीईआरटी के साथ एक सहयोगात्मक प्रयास का प्रतीक है।
मंत्रियों ने देश के लिए बलिदान देने वाले नायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए देश के प्रधान मंत्री के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी "मेरी माटी मेरा देश" अभियान के तहत कई कार्यक्रमों में भाग लिया।
मंत्रियों ने पुरी समुद्र तट पर पद्मश्री पुरस्कार विजेता रेत कलाकार श्री सुदर्शन पटनायक द्वारा "मेरी माटी मेरा देश" पर आधारित रेत कला का दौरा किया।
श्री प्रधान ने कहा कि यह कलाकृति देश के लिए अपना जीवन बलिदान करने वाले "नायकों" को श्रद्धांजलि देने का एक अनूठा और सराहनीय तरीका है।

केंद्रीय जल आयोग ने इंटरएक्टिव मानचित्रों का उपयोग करके जनता को वास्तविक समय में बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए मोबाइल ऐप 'फ्लडवॉच' लॉन्च किया

केंद्रीय जल आयोग (CWC) के अध्यक्ष, श्री कुशविंदर वोहरा ने जनता के लिए वास्तविक समय के आधार पर बाढ़ की स्थिति और 7 दिनों तक के पूर्वानुमान से संबंधित जानकारी प्रसारित करने के लिए मोबाइल फोन का उपयोग करने के लिए मोबाइल एप्लिकेशन, "फ्लडवॉच" लॉन्च किया।
इन-हाउस विकसित उपयोगकर्ता के अनुकूल ऐप में पठनीय और ऑडियो प्रसारण है और सभी जानकारी 2 भाषाओं, अर्थात् अंग्रेजी और हिंदी में उपलब्ध है।
ऐप की मुख्य विशेषता में वास्तविक समय में बाढ़ की निगरानी शामिल है जहां उपयोगकर्ता पूरे देश में बाढ़ की नवीनतम स्थितियों की जांच कर सकते हैं।
ऐप विभिन्न स्रोतों से लगभग वास्तविक समय के नदी प्रवाह डेटा का उपयोग करता है।
ऐप निकटतम स्थान पर बाढ़ का पूर्वानुमान भी प्रदान करता है जहां उपयोगकर्ता होम पेज पर ही अपने निकटतम स्टेशन पर बाढ़ संबंधी सलाह देख सकते हैं।
अन्य प्रमुख विशेषताओं में एक इंटरएक्टिव मैप का उपयोग करके पूर्वानुमान शामिल है जहां उपयोगकर्ता CWC बाढ़ पूर्वानुमान (24 घंटे तक) या बाढ़ सलाहकार (7 दिनों तक) की जांच कर सकते हैं या तो सीधे मानचित्र से स्टेशन का चयन करके या उपयोगकर्ता खोज बॉक्स में स्टेशन का नाम भी खोज सकते हैं।
जब ड्रॉपडाउन से स्टेशन का नाम चुना जाएगा तो स्थान मानचित्र पर ज़ूम इन हो जाएगा।
ऐप राज्य-वार/बेसिन-वार बाढ़ पूर्वानुमान (24 घंटे तक) या बाढ़ सलाह (7 दिनों तक) भी प्रदान करेगा, जिसे ड्रॉपडाउन मेनू से राज्य-वार या बेसिन-वार विशिष्ट स्टेशनों का चयन करके एक्सेस किया जा सकता है।

केंद्रीय ऊर्जा मंत्री बिहार के बाढ़ में NTPC की 660 मेगावाट की सुपर थर्मल पावर परियोजना को समर्पित करेंगे

केंद्रीय बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आरके सिंह बिहार के बाढ़ में NTPC की बाढ़ सुपर थर्मल पावर परियोजना की 660 मेगावाट की इकाई राष्ट्र को समर्पित करेंगे।
जिस 660 मेगावाट इकाई का उद्घाटन किया जा रहा है वह परियोजना के चरण। की इकाई #2 है।
इस इकाई का चालू होना देश को विश्वसनीय और सस्ती बिजली प्रदान करने के सरकार के प्रयास में एक और मील का पत्थर होगा।
केंद्रीय बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री 18 अगस्त 2023 को दिन में पावरग्रिड के 400/132 केवी लखीसराय सब-स्टेशन के विस्तार की आधारशिला भी रखेंगे।
इस सब-स्टेशन का निर्माण भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अधीन एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पावरग्रिड) द्वारा किया गया है।
परियोजना के हिस्से के रूप में, मौजूदा सब-स्टेशन परिसर में 500 एमवीए क्षमता के 2 ट्रांसफार्मर की स्थापना के साथ 220 केवी GIS का निर्माण किया जाएगा।
लखीसराय में सबस्टेशन के विस्तार से लखीसराय, शेखपुरा, मुंगेर और जमुई जिलों में बिजली की उपलब्धता में सुधार होगा और भविष्य की ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए बिजली की आपूर्ति में भी आसानी होगी।
लखीसराय सब-स्टेशन में 220 केवी वोल्टेज स्तर की अत्याधुनिक GIS तकनीक की स्थापना से क्षेत्र की राष्ट्रीय ग्रिड से कनेक्टिविटी और मजबूत होगी।
निर्बाध बिजली आपूर्ति के प्रावधान से क्षेत्र के औद्योगिक और वाणिज्यिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।

पर्यटन मंत्रालय नई दिल्ली में आजादी का अमृत महोत्सव और एक भारत श्रेष्ठ भारत फूड फेस्टिवल का आयोजन करेगा

पर्यटन मंत्रालय विभिन्न राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से राजधानी में आजादी का अमृत महोत्सव और एक भारत श्रेष्ठ भारत फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है।
इस उत्सव का उद्देश्य भारत की समृद्ध पाक विविधता का जश्न मनाना है। यह आयोजन राज्य-विशिष्ट व्यंजनों का प्रदर्शन करेगा और एकजुटता की भावना को बढ़ावा देते हुए प्रत्येक क्षेत्र के भीतर अद्वितीय पेशकशों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देगा।
फूड फेस्टिवल 23 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की उत्साही भागीदारी के साथ आयोजित किया जा रहा है। फेस्टिवल का आयोजन नई दिल्ली में भाग लेने वाले राज्यों के राज्य सदनों/भवनों में किया जाएगा।
भाग लेने वाले कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा, गुजरात, असम, मिजोरम, जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा, पंजाब, मेघालय, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, नागालैंड आदि शामिल हैं। कुछ राज्य संबंधित राज्य भवन के परिसर में खाद्य महोत्सव के साथ एक हस्तशिल्प प्रदर्शनी भी आयोजित कर रहे हैं।
यह आयोजन देखो अपना देश की अवधारणा को भी बढ़ावा देता है, जो देश के नागरिकों को अपने देश के छिपे हुए खजाने का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मंत्रालय के सफल कार्यक्रमों में से एक रहा है। यह पहल घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने और किसी की विरासत पर गर्व की भावना को बढ़ावा देने के बड़े लक्ष्य के अनुरूप है।
फूड फेस्टिवल न केवल भारत की समृद्ध संस्कृति और विरासत का उत्सव है, बल्कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाने और एक भारत, श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा देने के लिए भी है।

पर्यटन मंत्रालय, राज्य सरकारों और विभिन्न हितधारकों के सहयोगात्मक प्रयास इस समृद्ध अनुभव की सफलता सुनिश्चित करेंगे।

G20 व्यापार और निवेश मंत्रिस्तरीय बैठक जयपुर में होगी

जयपुर में G20 व्यापार और निवेश मंत्रिस्तरीय बैठक जी20 देशों और उससे बाहर के प्रतिनिधियों के बीच वैश्विक व्यापार और निवेश चर्चा पर केंद्रित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है।

यह नियम-आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के महत्व को रेखांकित करता है और भारत के समावेशी विकास और सतत विकास के उद्देश्यों का समर्थन करता है।

सहयोगी मंच का उद्देश्य चुनौतियों का समाधान करना और व्यापार और निवेश मामलों के समाधान तलाशना है।

पिछली कार्य समूह की बैठकों के दौरान चर्चा किए गए प्राथमिकता वाले मुद्दों को समझना इस प्रभावशाली घटना की अच्छी तरह से समझ के लिए आवश्यक है।

घटना अवलोकन:

G20 व्यापार और निवेश मंत्रिस्तरीय बैठक इस महीने की 24 और 25 तारीख को जयपुर में होने वाली है।

उद्देश्य और प्रतिभागी:

इसका उद्देश्य वैश्विक व्यापार और निवेश मामलों पर चर्चा को बढ़ावा देना, प्रतिनिधियों के बीच आम सहमति बनाना है।

व्यापार मंत्रियों, प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों और जी20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों सहित 300 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे।

भारतीय राष्ट्रपति पद का प्रभाव:

भारत की G20 अध्यक्षता के तहत, यह मुंबई, बैंगलोर और केवडिया में आयोजित कार्य समूह की बैठकों की श्रृंखला जारी रखता है।

बैठक में नियम-आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के महत्व पर जोर दिया गया, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विकास की चुनौतियों के सामने।

WTO-केंद्रित व्यापार प्रणाली के माध्यम से समावेशी विकास, रोजगार सृजन, नवाचार और सतत विकास के भारत के उद्देश्यों के अनुरूप।

सहयोगात्मक मंच:

वैश्विक आर्थिक नेताओं को बातचीत में शामिल होने और व्यापार और निवेश चुनौतियों के लिए सहयोगात्मक समाधान पर काम करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है।

पिछली कार्य समूह की बैठकें पाँच प्राथमिकता वाले मुद्दों पर केंद्रित थीं:

विकास और समृद्धि के लिए व्यापार करें: वैश्विक आर्थिक विकास में व्यापार के योगदान की खोज।

लचीला व्यापार और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाएँ: व्यापार और मूल्य श्रृंखलाओं में चुनौतियों का समाधान करना।

विश्व व्यापार में एसएमई को शामिल करना: वैश्विक व्यापार में छोटे व्यवसायों को शामिल करने की रणनीतियाँ।

व्यापार के लिए रसद: बेहतर लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे के माध्यम से व्यापार प्रवाह को बढ़ाना।

WTO सुधार: विश्व व्यापार संगठन के भीतर संभावित सुधारों पर चर्चा करें।

IEPFA और NCAER संयुक्त रूप से "भारत में निवेशक सुरक्षा ढांचा: चुनौतियां और आगे की राह" विषय पर एक वेबिनार का आयोजन कर रहे हैं

इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी (IEPFA) ने नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAER) के साथ साझेदारी में 'भारत में निवेशक सुरक्षा ढांचा: चुनौतियां और आगे की राह' विषय के तहत एक महत्वपूर्ण वेबिनार का सफलतापूर्वक आयोजन किया।

वेबिनार में सरकारी संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थानों और उद्योग विशेषज्ञों सहित विभिन्न हितधारकों का अभिसरण देखा गया।

मुख्य भाषण - वित्तीय शिक्षा:

IEPFA की CEO और एमसीए की संयुक्त सचिव सुश्री अनीता शाह अकेला ने तेजी से बदलते वित्तीय परिदृश्य में वित्तीय शिक्षा और निवेशक हितों की सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया।

पैनल चर्चा की मुख्य विशेषताएं:

इस कार्यक्रम में "भारत में निवेशक सुरक्षा ढांचे" पर एक प्रेरक पैनल चर्चा हुई।

विशेषज्ञों ने बीमा, डिजिटल पहल, साइबर अपराध जागरूकता, विकसित बैंकिंग प्रणाली और निवेशक जागरूकता बढ़ाने में नियामक भूमिकाओं पर अंतर्दृष्टि साझा की।

IEPFA की भूमिका:

7 सितंबर, 2016 को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत स्थापित IEPFA, निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष का प्रबंधन करता है।

इसके कार्यों में निवेशकों को शेयर, दावा न किए गए लाभांश और परिपक्व जमा/डिबेंचर वापस करना शामिल है।

NCAER का महत्व:

NCAER, 1956 से भारत का सबसे पुराना स्वतंत्र आर्थिक थिंक टैंक, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के नीतिगत निर्णयों के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक विश्लेषण प्रदान करता है।

डॉ. पूनम गुप्ता के नेतृत्व में, यह आर्थिक विश्लेषण, डेटा संग्रह और नीति आउटरीच को जोड़ती है, श्री नंदन एम. नीलेकणि इसके स्वतंत्र शासी निकाय के वर्तमान अध्यक्ष हैं।

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने गुमला, झारखंड में एससी-एसटी उद्यमियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए मेगा कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया

भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) मंत्रालय ने झारखंड के गुमला में राष्ट्रीय एससी-एसटी हब (NSSH) कॉन्क्लेव का आयोजन किया।

इसका उद्देश्य उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देना और NSSH योजना और अन्य मंत्रालय की पहल के बारे में जागरूकता पैदा करना था।

गणमान्य व्यक्ति और प्रतिभागी:

केंद्रीय एमएसएमई राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा और झारखंड सरकार में उद्योग विभाग के सचिव श्री जितेंद्र कुमार सिंह उपस्थित थे।

इस कार्यक्रम में लगभग 650 महत्वाकांक्षी और स्थापित एससी-एसटी उद्यमियों ने भाग लिया।

तकनीकी सत्र और प्रस्तुतियाँ:

एक तकनीकी सत्र आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (CPSE), बैंक और ऋण देने वाले संस्थान शामिल थे।

ONGC, BSNL और दामोदर वैली कॉरपोरेशन लिमिटेड जैसे CPSE ने अपने विक्रेता पैनलीकरण प्रक्रियाओं को प्रस्तुत किया और इसके माध्यम से उपलब्ध उत्पादों/सेवाओं का प्रदर्शन किया।
SBI, सिडबी, IFCI वेंचर कैपिटल फंड और नाबार्ड सहित वित्तीय संस्थानों ने MSME क्षेत्र के लिए विभिन्न ऋण योजनाओं पर चर्चा की।

भाग लेने वाली सरकारी संस्थाएँ:

KVIC, MSME-DFO, ट्राइफेड और GEM जैसे सरकारी निकायों ने भी MSME के लिए अपनी योजनाओं के बारे में जानकारी साझा करते हुए भाग लिया।

सुविधा और समावेशी विकास:

इस कार्यक्रम में उद्यम पंजीकरण के लिए सुविधा डेस्क, मौके पर ही SC/ST एमएसई के लिए पंजीकरण को सुव्यवस्थित करना शामिल था।
व्यापक उद्देश्य समावेशी विकास सुनिश्चित करना, एससी-एसटी समुदायों के भीतर उद्यमिता को प्रोत्साहित करना और सार्वजनिक खरीद नीति द्वारा निर्धारित 4% जनादेश को पूरा करने के लिए सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना था।

पशुपालन और डेयरी विभाग को भारत की पशु स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए महामारी निधि के तहत 25 मिलियन अमरीकी डालर का अनुदान प्राप्त होगा

जी20 महामारी कोष ने भारत में पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी (DAHD) मंत्रालय से 25 मिलियन डॉलर के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
प्रस्ताव "महामारी की तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए भारत में पशु स्वास्थ्य सुरक्षा सुदृढ़ीकरण" पर केंद्रित है।
कोविड-19 महामारी के विनाशकारी परिणामों ने मजबूत वन हेल्थ सिस्टम स्थापित करने और महामारी की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए अतिरिक्त संसाधन आवंटित करने के लिए सहयोगात्मक कार्रवाई की महत्वपूर्ण आवश्यकता को रेखांकित किया है।
यह पहल मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य के बीच अंतर्संबंध की वैश्विक मान्यता को दर्शाती है। वन हेल्थ दृष्टिकोण अपनाकर, राष्ट्रों का लक्ष्य भविष्य की महामारियों के प्रभाव को कम करना और अधिक लचीला और सहयोगात्मक वैश्विक स्वास्थ्य प्रणाली को बढ़ावा देना है।
पशु-उत्पत्ति आपात्कालीन परिस्थितियाँ: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने पहचान की है कि घोषित 6 अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों में से 5 की उत्पत्ति जानवरों से हुई है। यह वन हेल्थ दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है जो महामारी की तैयारी और प्रतिक्रिया (PPR) के एक अभिन्न पहलू के रूप में पशु स्वास्थ्य सुरक्षा पर जोर देता है।
फंड का उद्देश्य: इंडोनेशिया की जी20 प्रेसीडेंसी के तहत स्थापित, महामारी कोष वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर महामारी की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमताओं को मजबूत करने पर केंद्रित है। इसका जोर निम्न और मध्यम आय वाले देशों पर है।
वैश्विक प्रतिक्रिया: फंडिंग के लिए शुरुआती कॉल में लगभग 350 एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EOI) और 180 पूर्ण प्रस्तावों के साथ महामारी फंड को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। हालाँकि, अनुरोधित अनुदान राशि फंड के प्रारंभिक आवंटन $338 मिलियन से अधिक हो गई, जो $2.5 बिलियन से अधिक हो गई।

अनुदान एवं आवंटन: 20 जुलाई, 2023 को महामारी फंड के गवर्निंग बोर्ड ने फंडिंग वितरण के पहले दौर में 19 अनुदानों को मंजूरी दी। इन अनुदानों का लक्ष्य छह क्षेत्रों में 37 देशों में महामारी लचीलापन बढ़ाना है।

भारत का प्रस्ताव:

भारत का प्रस्ताव विभिन्न महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों पर केंद्रित है:

रोग निगरानी और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत और एकीकृत करना।

प्रयोगशाला नेटवर्क का उन्नयन और विस्तार।

जोखिम विश्लेषण और संचार में सहायता के लिए इंटरऑपरेबल डेटा सिस्टम को बढ़ाना और डेटा एनालिटिक्स के लिए क्षमता का निर्माण करना।

सीमा पार पशु रोगों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करना।

सीमा पार सहयोग के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग में भारत की भागीदारी बढ़ाना।

श्री नितिन गडकरी भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (भारत NCAP) लॉन्च करेंगे

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी बहुप्रतीक्षित भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (भारत NCAP) का अनावरण करेंगे।

यह पहल 3.5 टन वजन वाले मोटर वाहनों के सुरक्षा मानकों को बढ़ाकर सड़क सुरक्षा बढ़ाने की भारत सरकार की प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है।

भारत NCAP का लॉन्च सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और वाहन सुरक्षा की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता का संकेत देता है।

उपभोक्ताओं को जानकारी के साथ सशक्त बनाकर और निर्माताओं को सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करके, कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के ऑटोमोटिव उद्योग की वैश्विक उपस्थिति को मजबूत करते हुए सड़क सुरक्षा को बढ़ाना है।

कार्यक्रम का उद्देश्य: भारत NCAP का प्राथमिक उद्देश्य कार ग्राहकों को बाजार में उपलब्ध विभिन्न मोटर वाहनों की दुर्घटना सुरक्षा का आकलन और तुलना करने के लिए एक उपकरण प्रदान करना है।

स्वैच्छिक भागीदारी: कार निर्माता स्वेच्छा से अपने वाहनों को ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड (AIS) 197 के आधार पर परीक्षण के अधीन कर सकते हैं। ये परीक्षण दुर्घटना सुरक्षा के संदर्भ में वाहन के प्रदर्शन का मूल्यांकन करेंगे। परीक्षणों में वाहनों के प्रदर्शन के आधार पर, उन्हें वयस्क यात्रियों (AOP) और बाल यात्रियों (CoP) की सुरक्षा के लिए स्टार रेटिंग दी जाएगी।

सूचित खरीदारी: संभावित कार खरीदार विभिन्न वाहनों के सुरक्षा मानकों की तुलना करते समय सूचित निर्णय लेने के लिए इन स्टार रेटिंग का उपयोग संदर्भ के रूप में कर सकते हैं।

मांग पर प्रभाव: इस कार्यक्रम से सुरक्षित कारों की मांग बढ़ने की उम्मीद है, जिससे निर्माताओं को उन्नत सुरक्षा सुविधाओं के लिए ग्राहकों की प्राथमिकताओं के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता: उच्च सुरक्षा मानकों का पालन करने से, भारतीय कारें वैश्विक बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बन जाएंगी, जिससे संभावित रूप से भारतीय कार निर्माताओं की निर्यात क्षमता को बढ़ावा मिलेगा।

सुरक्षा के प्रति जागरूक बाज़ार विकसित करना: इस पहल से भारत में सुरक्षा के प्रति जागरूक कार बाजार के विकास में योगदान मिलने की उम्मीद है, जिसमें वाहन चालकों की भलाई को प्राथमिकता दी जाएगी।

पंचायतों में सतत विकास लक्ष्यों (LSDG) के स्थानीयकरण पर तीन दिवसीय राष्ट्रीय विषयगत कार्यशाला श्रीनगर में शुरू हुई

भारत सरकार का पंचायती राज मंत्रालय, पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग, जम्मू और कश्मीर सरकार के साथ घनिष्ठ सहयोग से, श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर में 21-23 अगस्त 2023 के दौरान विषय 8: सुशासन के साथ पंचायत पर विषयगत दृष्टिकोण अपनाने के माध्यम से ग्राम पंचायतों में सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कर रहा है।

केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा और केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल की गरिमामयी उपस्थिति में तीन दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे।

राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन पंचायती राज मंत्रालय के सचिव श्री सुनील कुमार, जम्मू-कश्मीर सरकार के मुख्य सचिव श्री अरुण कुमार मेहता, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में अपर सचिव डॉ चन्द्रशेखर कुमार, नदी विकास एवं जन सम्मेलन की आयुक्त एवं सचिव श्रीमती मनदीप कौर की उपस्थिति में किया जाएगा। इस अवसर पर जम्मू-कश्मीर सरकार, मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री विकास आनंद, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार डॉ विजय कुमार बेहरा और अन्य विशिष्ट गणमान्य व्यक्ति तथा स्थानीय जन प्रतिनिधि उपस्थित थे।

इस अवसर पर भारत सरकार और राज्य सरकारों के कई वरिष्ठ अधिकारियों, संयुक्त राष्ट्र/अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के प्रतिनिधियों और देश भर से पंचायती राज संस्थानों के लगभग 1000 निर्वाचित प्रतिनिधियों के भी शामिल होने की उम्मीद है।

पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विकसित 'मेरी पंचायत मोबाइल ऐप' और मेरी पंचायत मोबाइल ऐप, NCBF के संचालन दिशानिर्देश, सेवा-स्तरीय बेंचमार्क, स्व-मूल्यांकन और मॉडल अनुबंध राष्ट्रीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र के दौरान जारी किए जाएंगे।

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस (NISD) की जनरल काउंसिल की बैठक दिल्ली में हुई

श्री सौरभ गर्ग सचिव, एसजे एंड ई विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार और जीसी, NISD के अध्यक्ष ने अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान (NISD) की सामान्य परिषद की बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक का मुख्य उद्देश्य NISD की संरचना, कार्यों और कार्यक्रमों की स्थिति की समीक्षा करना था।

चर्चा के अग्रदूत के रूप में, निदेशक, NISD ने NISD पर एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी और एक लघु वीडियो फिल्म के माध्यम से NISD के प्रभागों और उनकी गतिविधियों को भी प्रदर्शित किया।

बैठक में वार्षिक रिपोर्ट- 2020-2021, 2021-2022, बैलेंस शीट 2022-23, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रमों की स्थिति, 2023-24 के लिए NISD पाठ्यक्रम कैलेंडर, दिल्ली पुलिस अकादमी के साथ समझौता ज्ञापन, जनशक्ति के साथ अनुसंधान प्रभाग को पुनर्जीवित करना, 2023-24 के दौरान NISD द्वारा नियोजित अनुसंधान गतिविधियों, NISD में प्रसारण स्टूडियो की कमीशनिंग, NISD की प्रस्तावित संरचना को शामिल किया गया।

विस्तृत चर्चा के बाद, NISD को कर्मचारियों की स्थिति को मजबूत करने की सलाह दी गई है जो अनुसंधान और प्रशिक्षण गतिविधियों को बढ़ाने में सहायता करेगी, और देश भर में गतिविधियों को व्यापक आधार देने के लिए राज्य और केंद्रीय संस्थानों के साथ अधिक सहयोग करेगी।

इसके अलावा, वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान NISD के प्रदर्शन की संतोषजनक समीक्षा की गई।

अंत में DoSJE के सचिव ने बताया कि NISD को सामाजिक रक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र की ओर बढ़ने की जरूरत है।

WHO और आयुष मंत्रालय पारंपरिक चिकित्सा पर पहली बार वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा आयोजित और आयुष मंत्रालय द्वारा सह-मेजबानी में पारंपरिक चिकित्सा पर अपनी तरह का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन 17-18 अगस्त, 2023 को गांधीनगर, गुजरात में होने वाला है।
शिखर सम्मेलन देश के विशाल अनुभव और विशेषज्ञता को ध्यान में रखेगा और यह बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम विशेषज्ञों और चिकित्सकों के लिए इस क्षेत्र में नवीनतम वैज्ञानिक प्रगति और साक्ष्य-आधारित ज्ञान में उतरने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा, जिसमें सभी के लिए स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करने का अंतिम लक्ष्य होगा।
WHO के सम्मानित महानिदेशक, डॉ. टेड्रोस एडनोम घेब्येयियस, करेंगे
स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया और आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल की उपस्थिति में कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे।
G20 के स्वास्थ्य मंत्रियों, WHO के क्षेत्रीय निदेशकों और WHO के छह क्षेत्रों के देशों के प्रतिष्ठित आमंत्रित लोगों के साथ-साथ वैज्ञानिकों, पारंपरिक चिकित्सा के चिकित्सकों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और नागरिक समाज संगठनों के सदस्यों के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने की उम्मीद है।
मंत्रालय कन्वेंशन सेंटर में योग और ध्यान सत्र भी आयोजित करेगा।
होटल स्थलों पर योग और ध्यान सत्र भी होंगे, साथ ही सत्रों के बीच महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में लघु योग विश्राम भी होगा।

मध्य प्रदेश के दतिया हवाईअड्डे को मिली हरी झंडी: सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिलान्यास किया

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, श्री शिवराज सिंह चौहान, और केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री, श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया प्रदेश में दतिया हवाई अड्डे की आधारशिला रखने के लिए हाथ मिलाया।
अंत में, दतिया हवाई अड्डे का शिलान्यास समारोह क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने और मध्य प्रदेश की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतीक है, जो परिवहन और बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
लागत और समयरेखा: यह आगामी हवाई अड्डा लगभग रु. की कीमत के साथ आता है। 50 करोड़ और फरवरी 2024 तक चालू होने का अनुमान है।
सुविधा संवर्द्धन: विकास कार्य में कई पहलू शामिल हैं, जिसमें मौजूदा 1810-मीटर रनवे का नवीनीकरण, दो उन्नीस सीटों वाले विमानों को समायोजित करने में सक्षम एप्रन का निर्माण, 750-वर्ग-मीटर टर्मिनल भवन का निर्माण और एक एटीसी टॉवर की स्थापना शामिल है।
यात्री क्षमता: नए टर्मिनल भवन को यात्री सुविधा को बढ़ाते हुए पीक आवर्स के दौरान 100 यात्रियों तक की सुविधा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
लंबे समय से चली आ रही मांग: दतिया हवाई पट्टी को एक पूर्ण हवाई अड्डे में बदलना एक लंबे समय से चली आ रही आकांक्षा थी जो अंततः वास्तविकता बन रही है।
क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा: क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना, उड़ान के अनुरूप, दतिया हवाई अड्डे के परिचालन से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार होगा, जिससे स्थानीय आबादी को आवश्यक सुविधाएं और सेवाएं मिलेंगी।
विकास प्रभाव: हवाई अड्डे की स्थापना से इसमें योगदान होने की उम्मीद है

नवीनतम समाचार

मध्य प्रदेश (MP) की राजधानी भोपाल संयुक्त राष्ट्र (UN) द्वारा अनिवार्य सतत विकास लक्ष्यों (SDG) के स्थानीयकरण को स्वीकार करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है।

मध्य प्रदेश (एमपी) के मुख्यमंत्री (सीएम), श्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री कृषि ऋण ब्याज माफी योजना, जिसका नाम मुख्यमंत्री कृषक ऋण माफी योजना-2023 (मुख्यमंत्री किसान ऋण माफी योजना) है, शुरू की है।
मध्य प्रदेश सरकार (एमपी) ने बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना (सीएम सीखो और कमाओ योजना) नामक नई योजना का अनावरण किया है।

एमपी के बारे में:

राज्यपाल: मंगूभाई सी. पटेल
मुख्यमंत्री: शिवराज सिंह चौहान
पूंजी: भोपाल
राष्ट्रीय उद्यान: सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान
वन्यजीव अभयारण्य: नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य, बोरी वन्यजीव अभयारण्य

श्री गिरिराज सिंह ने पंचायतों में सतत विकास लक्ष्यों (SDG) के स्थानीयकरण पर कार्यशाला का उद्घाटन किया:

केन्द्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने श्रीनगर में पंचायतों में सतत विकास लक्ष्यों (SDG) के स्थानिकीकरण पर तीन दिवसीय राष्ट्रीय विषयगत कार्यशाला का उद्घाटन किया।
इस कार्यक्रम में जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा और केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल की उपस्थिति रही।
मुख्य फोकस: अपने संबोधन में, मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि 2030 तक SDG हासिल करने की भारत की प्रतिबद्धता एक सामूहिक जिम्मेदारी है, न केवल नीति निर्माताओं की बल्कि निर्वाचित प्रतिनिधियों की भी, खासकर पंचायत स्तर पर।
पंचायत की भूमिका: पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए श्री गिरिराज सिंह ने जोर देकर कहा कि 17 सतत विकास लक्ष्यों और 169 संबद्ध लक्ष्यों की प्राप्ति देश भर में पंचायतों के सक्रिय योगदान और भागीदारी पर निर्भर करती है।
मोबाइल ऐप रिलीज: कार्यशाला के दौरान, मंत्री ने पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विकसित 'मेरी पंचायत मोबाइल ऐप' का अनावरण किया। इसके अतिरिक्त, एनसीबीएफ (राष्ट्रीय समुदाय आधारित वन प्रबंधन और आजीविका) के संचालन दिशानिर्देश, सेवा-स्तरीय बेंचमार्क, स्व-मूल्यांकन तंत्र और एक मॉडल अनुबंध भी जारी किए गए।
कार्यशाला का उद्देश्य: कार्यशाला का प्राथमिक उद्देश्य क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, निगरानी ढांचे, प्रोत्साहन और ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (GPDP) में SDG विषयों को एकीकृत करने से संबंधित प्रभावी रणनीतियों, अभिनव मॉडल, अभिसरण दृष्टिकोण और सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रदर्शन करना है।

नवीनतम समाचार

ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने नई दिल्ली में दो दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसमें अमृत काल के दौरान ग्रामीण विकास पर विचार-मंथन करने और ग्रामीण भारत के लिए एक रोडमैप बनाने के लिए सबसे तेज दिमागों को आमंत्रित किया गया।

'NeSDA - राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए आगे की राह मासिक रिपोर्ट' का 5वां संस्करण जारी किया गया

प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (DARPG) ने 'राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन (NeSDA) - राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए मासिक रिपोर्ट' का पांचवां संस्करण जारी किया है, जो राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में ई-सेवा वितरण की स्थिति का विस्तृत विवरण प्रदान करता है।

जुलाई की मासिक रिपोर्ट ई-सेवाओं, अनिवार्य ई-सेवाओं (NeSDA 2021 के अनुसार) की स्थिति प्रस्तुत करती है और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में सर्वोत्तम प्रथाओं पर प्रकाश डालती है।
यह राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के एकल एकीकृत सेवा वितरण पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जाने वाली ई-सेवाओं के संतृप्ति स्तर को भी रेखांकित करता है।
जुलाई, 2023 की रिपोर्ट जारी कर दी गई है और यह यहां उपलब्ध है:
https://darpg.gov.in/sites/default/files/NeSDA_जुलाई.pdf

ई-सर्विसेज

राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 13,867 ई-सेवाएँ प्रदान की जाती हैं, जो जून रिपोर्ट से 6.3% (816) सेवाओं की वृद्धि है।
2,016 अनिवार्य ई-सेवाओं में से 1,397 (56*36 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश) उपलब्ध हैं, जिससे संतृप्ति 69% हो गई है।
ई-सेवाओं की अधिकतम संख्या (5,203) क्षेत्र में है - स्थानीय शासन और उपयोगिता सेवाएँ
58% यानी 36 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में से 21 ने अनिवार्य ई-सेवाओं की संतृप्ति हासिल कर ली है
पर्यटन क्षेत्र. इसके बाद 36 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में से 47% यानि 17% पर्यावरण क्षेत्र का स्थान है

सर्वोत्तम प्रथाएं

गुजरात सरकार ने जी-शाला (गुजरात स्टूडेंट्स होलिस्टिक एडेप्टिव लर्निंग ऐप) विकसित किया है जो ग्रेड I-XII के लिए ई-कंटेंट के साथ एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (LMS) है।
मध्य प्रदेश सरकार देश का पहला राज्य है जिसने अपने शिक्षा का अधिकार (RTE) पोर्टल के माध्यम से 100% सीटों के आवंटन के लिए ऑनलाइन और केंद्रीकृत प्रणाली का उपयोग किया है।
नागालैंड सरकार ने एक सामान्य छात्रवृत्ति पोर्टल स्थापित किया है, जो सभी राज्य छात्रवृत्ति के लिए एक केंद्रीकृत मंच के रूप में कार्य कर रहा है
हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा (एचपीटेक) बोर्ड पोर्टल के माध्यम से पॉलिटेक्निक के साथ-साथ आईटीआई उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन प्रवेश-संबंधित प्रक्रियाएं शुरू की हैं।
कर्नाटक सरकार ने अपने कर्नाटक स्कूल परीक्षा और मूल्यांकन बोर्ड पोर्टल के माध्यम से राज्य में पूरी परीक्षा प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया है

ट्राई ने DTH सेवा लाइसेंस शुल्क और नीति मामलों में बदलाव की सिफारिश की:

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने डायरेक्ट-टू-होम (DTH) सेवाओं के लिए लाइसेंस शुल्क और नीतिगत मामलों से संबंधित सिफारिशें जारी की हैं।
ट्राई की इन सिफारिशों का उद्देश्य DTH सेवाओं के लिए लाइसेंस शुल्क संरचना में बदलाव लाना है, एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा देना है जो देश के व्यापक डिजिटल प्रसारण लक्ष्यों के साथ संरेखित करते हुए क्षेत्र के भीतर वृद्धि और विकास को प्रोत्साहित करता है।
कटौती सत्यापन तंत्र: ट्राई का सुझाव है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय एक एकीकृत पोर्टल के माध्यम से कटौती की पुष्टि के लिए एक मजबूत तंत्र विकसित करे।
वार्षिक लाइसेंस शुल्क: DTH लाइसेंसधारियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के 3 प्रतिशत के बराबर वार्षिक लाइसेंस शुल्क का भुगतान करें।
क्रमिक लाइसेंस शुल्क में कमी: ट्राई ने DTH लाइसेंसधारियों के लिए लाइसेंस शुल्क में चरणबद्ध कटौती की सिफारिश की है। अगले तीन वर्षों में लाइसेंस शुल्क को धीरे-धीरे घटाकर शून्य किया जाना चाहिए।

Click Here to Subscribe Our Yearly Mock Test Package

2026-2027 के बाद शुल्क में छूट: वित्तीय वर्ष 2026-2027 के बाद, ट्राई का प्रस्ताव है कि DTH लाइसेंसधारियों पर कोई लाइसेंस शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

बैंक गारंटी की आवश्यकता: शुरुआत में, लाइसेंसधारियों को मंत्रालय को किसी भी अनुसूचित बैंक से प्रारंभिक बैंक गारंटी प्रदान करनी चाहिए। पहली दो तिमाहियों के लिए यह गारंटी पांच करोड़ रुपये होनी चाहिए।

डीटीएच ऑपरेशन फ्रेमवर्क: भारत में DTH प्रसारण सेवाओं का प्रावधान नीति दिशानिर्देशों द्वारा विनियमित है जो लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करता है। लाइसेंस शुल्क, एक गैर-कर शुल्क, लाइसेंस प्राप्त गतिविधियों के संचालन के विशेषाधिकार के लिए सेवा प्रदाताओं पर लगाया जाता है।

नवीनतम समाचार

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने डायल-अप और लीज्ड लाइन इंटरनेट एक्सेस सेवा, 2001 (2001 का 4) की सेवा की गुणवत्ता पर विनियमन को रद्द करने के लिए 25 जुलाई, 2023 को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण निरसन विनियम, 2023 (2023 का 02) जारी किया, जो आधिकारिक राजपत्र में इसकी अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होगा।

ट्राई के बारे में

स्थापित: 20 फरवरी 1997
मुख्यालय: नई दिल्ली

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने मिजोरम के आइजोल में अपने 100 माइक्रोसाइट्स प्रोजेक्ट के एक हिस्से के रूप में पहला ABDM माइक्रोसाइट लॉन्च किया

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) ने देश भर में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) को त्वरित रूप से अपनाने के लिए 100 माइक्रोसाइट परियोजनाओं की घोषणा की।
मिजोरम अपनी राजधानी आइजोल में ABDM माइक्रोसाइट संचालित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है।
इसके तहत, क्षेत्र में निजी क्लीनिकों, छोटे अस्पतालों और प्रयोगशालाओं सहित सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को ABDM-सक्षम बनाया जाएगा और मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी।
ABDM माइक्रोसाइट्स परिभाषित भौगोलिक क्षेत्र हैं जहां छोटे और मध्यम स्तर के निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को शामिल करने के लिए केंद्रित आउटरीच प्रयास किए जाएंगे।
इन माइक्रोसाइट्स को मुख्य रूप से ABDM के राज्य मिशन निदेशकों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा, जबकि वित्तीय संसाधन और समग्र मार्गदर्शन NHA द्वारा प्रदान किया जाएगा।
मरीज़ इन सुविधाओं पर उत्पन्न स्वास्थ्य रिकॉर्ड को अपने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खातों (ABHA) के साथ लिंक करने में सक्षम होंगे और अपने फोन पर किसी भी ABDM-सक्षम व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड (PHR) एप्लिकेशन का उपयोग करके इन रिकॉर्ड को देख और साझा करने में सक्षम होंगे।**https://phr.abdm.gov.in/uhi/1231**)
NHA ने पहले मुंबई, अहमदाबाद और सूरत में माइक्रोसाइट पायलटों की देखरेख की थी। इन पायलटों से मिली सीख और अनुभवों को एबीडीएम के तहत 100 माइक्रोसाइट्स परियोजना की समग्र संरचना में शामिल किया गया है।
मिजोरम के अलावा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों ने भी ABDM माइक्रोसाइट्स के कार्यान्वयन के संबंध में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

वाराणसी G20 संस्कृति कार्य समूह (CWG) की चौथी बैठक की मेजबानी करेगा:

चौथी जी20 संस्कृति कार्य समूह (CWG) की बैठक वाराणसी में शुरू होगी और संस्कृति मंत्रियों की बैठक (CMM) में समाप्त होगी।

बैठक में जी20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भाग लेंगे।
खजुराहो, भुवनेश्वर और हम्पी में पिछली तीन CWG बैठकों के साथ-साथ चार ग्लोबल थीमैटिक वेबिनार की सफलता के आधार पर, वाराणसी में 23-25 अगस्त 2023 तक चौथी CWG बैठक का उद्देश्य नीति-निर्माण के केंद्र में संस्कृति को रखते हुए कार्रवाई योग्य परिणामों पर पहुंचना है।
CWG के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर विशेषज्ञ-संचालित वैश्विक विषयगत वेबिनार की अंतर्दृष्टि और सिफारिशों को "जी20 संस्कृति: समावेशी विकास के लिए वैश्विक कथा को आकार देना" नामक एक व्यापक रिपोर्ट में एकत्रित किया गया है।
भारत के G20 प्रेसीडेंसी के संस्कृति कार्य समूह की यह व्यावहारिक रिपोर्ट, संस्कृति मंत्रियों की बैठक के एक भाग के रूप में वाराणसी में लॉन्च की जाएगी।
वाराणसी में संस्कृति मंत्रियों की बैठक का उद्देश्य भारतीय राष्ट्रपति पद द्वारा व्यक्त किए गए चार प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर प्रगति में तेजी लाने के लिए सामूहिक कार्यों को उत्प्रेरित करना होगा - सांस्कृतिक संपत्ति का संरक्षण और पुनर्स्थापना, एक सतत भविष्य के लिए जीवित विरासत का दोहन, सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों को बढ़ावा देना और रचनात्मक अर्थव्यवस्था, और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना।

श्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना योजना का शुभारंभ किया

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना का उद्घाटन करेंगे
मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना (मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना) का कार्यान्वयन 22 अगस्त 2023 से शुरू हो रहा है।
इस योजना ने कौशल विकास के साथ-साथ सीखो और कमाओ की तर्ज पर नौकरी पर प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की है
मुख्यमंत्री युवाओं को अनुबंध पत्र बांटकर योजना का शुभारंभ करेंगे।
'मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ' योजना के पहले चरण में एक लाख युवाओं को शामिल करने का लक्ष्य है
इसे 18 से 29 साल के युवाओं के लिए शुरू किया गया है
इस योजना के तहत चयनित युवाओं को उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
चयनित युवाओं को ट्रेनिंग के साथ-साथ 8 से 10 हजार रुपये स्टाइपेंड भी मिलेगा

एमपी के बारे में:

राज्यपाल: मंगूभाई सी. पटेल
मुख्यमंत्री: शिवराज सिंह चौहान
पूंजी: भोपाल
राष्ट्रीय उद्यान: सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान
वन्यजीव अभयारण्य: नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य, बोरी वन्यजीव अभयारण्य।

नवीनतम समाचार

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 'मुख्यमंत्री तीरथ यात्रा योजना' के तहत 32 वरिष्ठ नागरिकों के एक जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें 24 पुरुष और 8 महिलाएं शामिल हैं।

भारत को पशु स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए जी20 महामारी कोष से 25 मिलियन डॉलर का अनुदान मिलेगा

भारत को देश की पशु स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए जी 20 महामारी कोष से 25 मिलियन अमरीकी डालर प्राप्त होंगे।
इंडोनेशिया की जी20 प्रेसीडेंसी के तहत स्थापित फंड का लक्ष्य निम्न-से-मध्यम आय वाले देशों में निगरानी, अनुसंधान और टीकों तक बेहतर पहुंच जैसे प्रयासों को वित्तपोषित करना है।

Click Here to Subscribe Our Yearly Mock Test Package

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अनुसार, जी20 महामारी कोष ने महामारी की तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए देश में पशु स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारत के 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
महामारी कोष को पहली कॉल में लगभग 350 अभिरुचि पत्र (EoI) और 180 पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिसमें केवल 338 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कुल 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के अनुदान अनुरोध शामिल थे।
महामारी कोष के गवर्निंग बोर्ड ने 20 जुलाई को छह क्षेत्रों के 37 देशों में भविष्य की महामारियों के प्रति लचीलापन बढ़ाने के उद्देश्य से धन आवंटन के अपने पहले दौर के तहत "19 अनुदान" को मंजूरी दे दी है।
परियोजना का प्रभाव इस जोखिम को कम करना होगा कि जानवरों (पालतू और वन्य जीवन) से एक रोगज़नक़ निकलकर मानव आबादी में फैल जाएगा जो कमजोर आबादी के स्वास्थ्य, पोषण सुरक्षा और आजीविका को खतरे में डाल देगा।
यह परियोजना विश्व बैंक और खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) के साथ प्रमुख कार्यान्वयन इकाई के रूप में एशियाई विकास बैंक (ADB) के सहयोग से कार्यान्वित की जाएगी।

भारत और आसियान देश 2025 तक वस्तुओं के लिए अपने मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा करने पर सहमत हुए

भारत और आसियान देश 2025 तक वस्तुओं के लिए अपने मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा करने पर सहमत हुए।
आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते (AITIGA) की एक संयुक्त समिति ने समझौते की समीक्षा और नई वार्ताओं के लिए विचारार्थ विषयों को अंतिम रूप देने के लिए एक रोडमैप तैयार किया है।
AITIGA की समीक्षा अब सितंबर की शुरुआत में होने वाले भारत-आसियान नेताओं के शिखर सम्मेलन में होगी।
AITIGA की समीक्षा की भारतीय कारोबार काफी लंबे समय से मांग कर रहे थे।
AITIGA की समीक्षा द्विपक्षीय व्यापार में मौजूदा मुद्दों को संबोधित करते हुए व्यापार को बढ़ाएगी और विविधता लाएगी।
आसियान-भारत माल व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किये गये और 1 जनवरी 2010 को लागू हुआ।
आसियान और भारत ने 2009 में आसियान-भारत माल व्यापार (TIG) समझौते पर हस्ताक्षर किए।
भारत और आसियान निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने पर भी काम कर रहे हैं।

आसियान के बारे में:

दक्षिणपूर्व एशियाई देशों का संगठन (आसियान) एक क्षेत्रीय अंतरसरकारी संगठन है जिसमें 10 दक्षिणपूर्व एशियाई देश शामिल हैं।
इसकी स्थापना 1967 में बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी।
सदस्य: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया और वियतनाम।
आसियान संघ की पहली शिखर बैठक 1976 में इंडोनेशिया के सबसे प्रमुख द्वीप बाली पर आयोजित की गई थी।

नवीनतम समाचार

भारत ने पहले आसियान-भारत समुद्री अभ्यास (AIME-2023) में भाग लेने के लिए दो फ्रंटलाइन युद्धपोत भेजे।
भारत और आसियान (दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ) के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए, भारत "संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना (UNPK) संचालन में महिलाओं" पर एक पहल शुरू करेगा।

बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय (MoSPW) गुजरात के टूना टेकरा में अगली पीढ़ी के कंटेनर टर्मिनल का विकास कर रहा है

गुजरात में भारत के पश्चिमी तट पर एक प्रमुख बंदरगाह दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी (DPA) दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में स्थित एक बहुराष्ट्रीय रसद कंपनी डीपी वर्ल्ड के साथ टूना-टेकरा, गुजरात (कांडला के पास) में एक नए मेगा कंटेनर टर्मिनल के विकास, संचालन और रखरखाव के लिए एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर कर रहा है।

केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग तथा आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल और डीपी वर्ल्ड के समूह अध्यक्ष और सीईओ महामहिम सुल्तान अहमद बिन सुलायम की उपस्थिति में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण और डीपी वर्ल्ड के बीच रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
हस्ताक्षर के दौरान बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग राज्य मंत्री श्री शांतनु ठाकुर और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहेंगे।
इस परियोजना में सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) मोड के माध्यम से 4,243.64 करोड़ रुपये की लागत से कांडला के पास टूना-टेकरा में एक मेगा-कंटेनर टर्मिनल का निर्माण शामिल है।
एक बार पूरा होने पर, टर्मिनल में 2.19 मिलियन कंटेनर इकाइयों (TEU) को संभालने की वार्षिक क्षमता होगी और 18,000 से अधिक TEU ले जाने वाले अगली पीढ़ी के जहाजों को संभालने की क्षमता होगी।
नया टर्मिनल उत्तरी, पश्चिमी और मध्य भारत से भविष्य की व्यापार मांग को पूरा करेगा, जिससे ये क्षेत्र वैश्विक बाजारों से जुड़ जाएंगे।
यह परियोजना बंदरगाह संचालन क्षमता को चौगुना करने के लिए भारत सरकार के विज़न 2047 के अनुरूप है और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे का विकास करना।

केंद्र सरकार नई दिल्ली में टेली-लॉ - 2.0 लॉन्च करेगी जो टेली-लॉ और न्याय बंधु ऐप को एकीकृत करेगी

केंद्र सरकार टेली-लॉ - 2.0 लॉन्च करेगी जो नई दिल्ली में न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए टेली-लॉ और न्याय बंधु ऐप को एकीकृत करता है।
कानून और न्याय मंत्रालय ने कहा कि इससे आम नागरिक एकल पंजीकरण और टेली-लॉ के एकल गेटवे के माध्यम से कानूनी सलाह, कानूनी सहायता और कानूनी प्रतिनिधित्व तक पहुंच प्राप्त कर सकेंगे।
यह आयोजन लाभार्थियों को 50 लाख कानूनी सलाह प्रदान करने की उपलब्धि का प्रतीक है।
कार्यक्रम के दौरान, अग्रिम पंक्ति के पदाधिकारी जो जमीनी स्तर के सैनिक हैं और अपने दरवाजे पर कानूनी सेवाओं की डिलीवरी सुनिश्चित करते हैं, उन्हें सम्मानित किया जाएगा।

ई-गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन इंदौर में शुरू होगा

नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने पर विचार-विमर्श के लिए ई-गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन इंदौर में शुरू हुआ।
सम्मेलन का उद्घाटन मप्र के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा ने किया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के जल संसाधन, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग मंत्री तुलसी राम सिलावट भी उपस्थित थे।
दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।
सम्मेलन में 'विकासशील भारत: नागरिकों को सशक्त बनाना' विषय पर मंथन किया जा रहा है।
सम्मेलन में 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ-साथ उद्योग जगत के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।
सम्मेलन में जिला-स्तरीय पहल, नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों, नागरिक केंद्रित सेवाओं में अनुसंधान एवं विकास की भूमिका सहित ग्यारह विषयों पर चर्चा की जा रही है।
सम्मेलन के दौरान 5 श्रेणियों में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2023 भी प्रदान किए जाएंगे।

B20 समिट इंडिया 2023 नई दिल्ली में शुरू होगा

B20 समिट इंडिया 2023 नई दिल्ली में शुरू होगा।
तीन दिवसीय शिखर सम्मेलन के दौरान, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, धर्मेंद्र प्रधान, डॉ. एस जयशंकर, जी20 इंडिया शेरपा अमिताभ कांत, विभिन्न देशों के व्यापार मंत्री और कई व्यापारिक नेता वैश्विक स्तर पर व्यवसायों से संबंधित मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे।
इस महीने की 27 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष सत्र में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे
शिखर सम्मेलन B20 इंडिया RAISE: जिम्मेदार, त्वरित, अभिनव, टिकाऊ, न्यायसंगत व्यवसाय के विषय पर आधारित है।
लचीले वैश्विक व्यापार और निवेश, काम के भविष्य, कौशल, गतिशीलता, डिजिटल परिवर्तन, वैश्विक आर्थिक सुधार के लिए वित्तपोषण, जलवायु परिवर्तन, प्रौद्योगिकी, नवाचार और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए वित्तीय समावेशन के लिए समावेशी वैश्विक मूल्य श्रृंखला के क्षेत्रों में भारत की अध्यक्षता के लिए सात टास्क फोर्स बनाए गए थे।
बड़े संरचनात्मक एजेंडे पर ध्यान केंद्रित करने और विचार-विमर्श करने के लिए, बी20 इंडिया ने अफ्रीकी आर्थिक एकीकरण पर व्यापार में पर्यावरण, सामाजिक और शासन पर दो कार्य परिषदों के माध्यम से काम किया।

केंद्र सरकार द्वारा 1 सितंबर 2023 से चालान प्रोत्साहन योजना "मेरा बिल मेरा अधिकार" का शुभारंभ

भारत सरकार, राज्य सरकारों के सहयोग से, सभी खरीद के लिए चालान/बिल मांगने वाले ग्राहकों की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए 'मेरा बिल मेरा अधिकार' नाम से एक 'चालान प्रोत्साहन योजना' शुरू कर रही है।
योजना का उद्देश्य आम जनता में 'बिल मांगो' को उनके अधिकार और अधिकार के रूप में सांस्कृतिक और व्यवहारिक परिवर्तन लाना है।

योजना का विवरण इस प्रकार है:

यह योजना 1 सितंबर 2023 को लॉन्च की जाएगी।
यह योजना शुरू में असम, गुजरात और हरियाणा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव में पायलट के रूप में शुरू की जाएगी।
GST-पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं (असम, गुजरात और हरियाणा राज्यों और पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव के केंद्र शासित प्रदेशों में पंजीकृत) द्वारा उपभोक्ताओं को जारी किए गए सभी बी2सी चालान इस योजना के लिए पात्र होंगे।
लकी ड्रा के लिए विचार किए जाने वाले चालान का न्यूनतम मूल्य 200रुपये रखा गया है।
चालान IOS और एंड्रॉइड के साथ-साथ वेब पोर्टल 'web.merabill.gst.gov.in' पर उपलब्ध मोबाइल एप्लिकेशन 'मेरा बिल मेरा अधिकार' पर अपलोड किए जा सकते हैं।
भारत के सभी निवासी अपने राज्य/केंद्रशासित प्रदेश की परवाह किए बिना इस योजना में भाग लेने के पात्र होंगे। लकी ड्रा के लिए विचार किए जाने के लिए एक व्यक्ति द्वारा एक महीने में अधिकतम 25 चालान ऐप/वेब पोर्टल पर अपलोड किए जा सकते हैं।

श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में दो दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन -2023 का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, भारत सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र के सभी पहलुओं को मजबूत करके एक सुरक्षित राष्ट्र सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
इसके अनुसरण में, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में दो दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतियाँ (NSS) सम्मेलन-2023 का उद्घाटन किया।

अत्याधुनिक स्तर पर काम करने वाले अधिकारियों और विषय विशेषज्ञों सहित कुल 750 से अधिक प्रतिभागी, फिजिकल और वर्चुअल मोड के संयोजन में, देश भर से सम्मेलन में शामिल हुए।
दिल्ली में सम्मेलन में भाग लेने वालों में गृह मंत्रालय के दो राज्य मंत्री और केंद्रीय गृह सचिव, उप NSA, सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के महानिदेशक/IGSP और CAPF सहित राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों के प्रबंधन में शामिल शीर्ष अधिकारी शामिल थे। सम्मेलन की शुरुआत से पहले, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने उन गुमनाम शहीदों की याद में बनाए गए शहीद स्तंभ पर पुष्पांजलि अर्पित करके श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए।
गृह मंत्री ने नागरिकों और भारत की सुरक्षा से संबंधित अन्य मुद्दों के अलावा मादक पदार्थों की तस्करी के खतरे से निपटने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
उन्होंने इस क्षेत्र में विभिन्न एजेंसियों द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हुए सभी राज्यों और एजेंसियों से ड्रग डीलरों और नेटवर्क के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रखने का आग्रह किया।

मामल्लापुरम में संरचनात्मक अखंडता पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया

स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी (ICONS 2023) पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन तमिलनाडु के ममल्लापुरम में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के सचिव डॉ. एन कैलाइसेल्वी ने वर्चुअल माध्यम से किया।
आइकॉन्स 2023 का आयोजन इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, कलपक्कम और सोसाइटी फॉर फेलियर एनालिसिस द्वारा संयुक्त रूप से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, इंडियन सोसाइटी फॉर नॉन-डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, कलपक्कम चैप्टर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेटल्स कलपक्कम चैप्टर और इंडियन स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी सोसाइटी के सहयोग से किया जा रहा है।
डॉ. कलैसेल्वी ने अपने उद्घाटन भाषण के दौरान ग्लोबल वार्मिंग के कारण बिजली संयंत्र, पेट्रोकेमिकल उद्योगों और भारत की प्रतिष्ठित संरचनाओं की गिरावट पर प्रकाश डाला है।
ICONS 2023 में भारत और विदेश से लगभग 250 प्रतिनिधियों ने भाग लिया है, जिसमें मैकेनिकल इंजीनियर, सामग्री वैज्ञानिक, शिक्षाविद, उद्योग विशेषज्ञ, संयंत्र प्रबंधक और नियामक कर्मी शामिल हैं।
सम्मेलन में परमाणु, रक्षा, एयरोस्पेस, रसायन और तेल उद्योगों में संरचनाओं और संचालन उपकरणों की संरचनात्मक अखंडता का आकलन और सुनिश्चित करने में हालिया विकास और भविष्य की दिशाओं से संबंधित विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।
सम्मेलन के अगले दो दिनों में क्षेत्र के प्रमुख विशेषज्ञों द्वारा लगभग 35 आमंत्रित व्याख्यान और लगभग 200 अंशदायी पत्र प्रस्तुत किए जाने हैं।

पुणे मिलिट्री कॉलेज भारत का पहला कार्बन-नेगेटिव गैरीसन बन गया

पुणे स्थित सैन्य इंजीनियरिंग कॉलेज (CME) 5-मेगावाट (मेगावाट) सौर ऊर्जा संयंत्र के चालू होने से इसकी सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता 7 मेगावाट हो गई है, जो भारत का पहला कार्बन-नकारात्मक गैरीसन या सैन्य गठन बन गया है।
CME, जिसे 1948 में सशस्त्र बलों के एक प्रमुख संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था, युद्ध के बदलते चरित्र के साथ विभिन्न तकनीकी और सामरिक पहलुओं में मित्र विदेशी देशों सहित भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना के सभी रैंकों को प्रशिक्षित करता है।

संस्थान के कार्बन पदचिह्न को कम करने के लिए, गैरीसन इंजीनियर (CME), खड़की के कार्यालय के माध्यम से सैन्य इंजीनियरिंग सेवाओं (MES) द्वारा हाल ही में CME में कई परियोजनाएं शुरू की गई हैं।
सबसे बड़ी परियोजना CME में दो चरणों में CME में 7 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का कार्यान्वयन है, इसके अलावा CME में सैनिकों के लिए सामुदायिक खाना पकाने के लिए सौर भाप खाना पकाने के संयंत्र और उत्सर्जन को रोकने के लिए डीजल जनरेटर सेट पर रेट्रोफिटिंग उत्सर्जन नियंत्रण उपकरणों (RECD) की स्थापना जैसी कई महत्वपूर्ण पायलट परियोजनाएं हैं।

केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ने AAI हवाई अड्डों के टर्मिनल बिल्डिंग आर्किटेक्चर पर पुस्तक का विमोचन किया

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने AAI हवाई अड्डों पर विभिन्न टर्मिनल भवनों की पारंपरिक और स्थानीय वास्तुकला पर एक कॉफी टेबल बुक जारी की।
इस पुस्तक में टर्मिनल भवनों के अग्रभाग को दर्शाया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और AAI, DGCA और BCAS के प्रमुख के अलावा राष्ट्रीय राजधानी में "आगामी नए टर्मिनल भवनों के उन्नयन और डिजाइन पर पारंपरिक और स्थानीय वास्तुकला" नामक पुस्तक के विमोचन के अवसर पर उपस्थित थे।
AAI के अध्यक्ष संजीव कुमार ने पुस्तक के विमोचन से पहले कहा, नई इमारतों के निर्माण के लिए, भारतीय हवाईअड्डा प्राधिकरण (AAI) बाहरी हिस्से और अंदरूनी हिस्सों में स्थानीय वास्तुकला और संस्कृति को लाने के लिए सचेत प्रयास करता है।
हवाईअड्डा टर्मिनल भवन विमान और जमीनी परिवहन के बीच निर्बाध संक्रमण को व्यवस्थित करता है, जो हवाई यात्रा से जुड़ी विभिन्न सेवाओं के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करता है।
एक टर्मिनल एक प्रवेश द्वार बन जाता है जो किसी शहर के बारे में आगंतुकों की प्रारंभिक धारणा को आकार देता है।
वे अब केवल सुविधा की साधारण संरचनाएं नहीं रह गए हैं और उन्हें शहर के स्थलों, चमत्कारों के रूप में देखा जाना चाहिए, जो शहर में आगंतुकों का स्वागत करते हैं और यात्रियों में विस्मय और आश्चर्य की भावना पैदा करते हैं।

AAI के बारे में:

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, या AAI, भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के स्वामित्व में एक वैधानिक निकाय है। AAI का गठन संसद के एक अधिनियम द्वारा किया गया था और 1 अप्रैल 1995 को तत्कालीन राष्ट्रीय हवाईअड्डा प्राधिकरण और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा प्राधिकरण का विलय करके अस्तित्व में आया।
मुख्यालय: नई दिल्ली
स्थापित: 1 अप्रैल 1995
अध्यक्ष: संजीव कुमार

नवीनतम समाचार

नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA), एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) 'विंग्स इंडिया 2024' के आगामी संस्करण का आयोजन कर रहे हैं।

CBDT ने आयकर विभाग की एक संशोधित राष्ट्रीय वेबसाइट लॉन्च की:

आयकर विभाग ने उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस, मूल्य वर्धित सुविधाओं और नए मॉड्यूल के साथ अपनी राष्ट्रीय वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in को नया रूप दिया है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अध्यक्ष श्री नितिन गुप्ता ने उदयपुर में आयकर निदेशालय (सिस्टम) द्वारा आयोजित 'चिंतन शिविर' में नई वेबसाइट का शुभारंभ किया।
यह वेबसाइट कर और अन्य संबंधित जानकारी के व्यापक भंडार के रूप में कार्य करती है।
यह प्रत्यक्ष कर कानूनों, कई अन्य संबद्ध अधिनियमों, नियमों, आयकर परिपत्रों और अधिसूचनाओं तक पहुंच प्रदान करता है, सभी क्रॉस-संदर्भित और हाइपरलिंक किए गए हैं।
यह साइट एक 'करदाता सेवा मॉड्यूल' भी प्रदान करती है जिसमें करदाताओं को उनके आयकर रिटर्न दाखिल करने में सहायता करने के लिए विभिन्न कर उपकरण शामिल हैं।
पुनर्निर्मित वेबसाइट को मोबाइल-रेस्पॉन्सिव लेआउट के साथ सौंदर्यपूर्ण रूप से नया रूप दिया गया है।
वेबसाइट में नई सुविधाओं और कार्यात्मकताओं के साथ सामग्री के लिए एक 'मेगा मेनू' भी है।
वेबसाइट पर आने वाले आगंतुकों की सुविधा के लिए, इन सभी नई सुविधाओं को एक निर्देशित वर्चुअल टूर और नए बटन संकेतकों के माध्यम से समझाया गया है।

CBDT के बारे में:

स्थापित: 1963
मुख्यालय: नई दिल्ली
अध्यक्ष: नितिन गुप्ता

नवीनतम समाचार

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) दिशानिर्देशों के एक सेट में कहा गया है कि यदि राशि प्रति माह ₹100 से कम है और कुछ निश्चित शर्तों को पूरा करती है, तो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म को खिलाड़ियों द्वारा निकाली गई जीत पर स्रोत पर कर में कटौती करने की आवश्यकता नहीं है।

केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आंध्र प्रदेश में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी

केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र के पार्वतीपुरम मान्यम जिले में एक जनजातीय विश्वविद्यालय शुरू करने का प्रस्ताव किया है।
केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सालुरु में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी
केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में शैक्षिक मानकों में सुधार करेगा।
केंद्रीय मंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय पार्वती पुरम मान्यम जिले के आदिवासी क्षेत्र में स्थित है जो स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीतारामराजू की निशानी के रूप में खड़ा है।
जनजातीय विश्वविद्यालय डिग्री में 24 शैक्षणिक पाठ्यक्रम, कौशल विकास में अल्पकालिक पाठ्यक्रम, व्यावसायिक और नौकरी-उन्मुख पाठ्यक्रम पेश करने और जनजातीय आबादी के व्यक्तिगत, सांस्कृतिक पर्यावरण विकास को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह तैयार है।

आंध्र प्रदेश के बारे में

राजधानी: अमरावती
राज्यपाल: एस. अब्दुल नज़ीर
मुख्यमंत्री: वाईएस जगन मोहन रेड्डी

नवीनतम समाचार

केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक मुफ्त ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम, एआई फॉर इंडिया 2.0 लॉन्च किया।

बहरीन में भारतीय मिशन ने कांसुलर पहुंच को आसान बनाने के लिए एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया

बहरीन में भारतीय दूतावास ने नामित राजदूत विनोद कुरियन जैकब के मार्गदर्शन में एक ओपन हाउस सत्र की मेजबानी की। इस कार्यक्रम में नए मोबाइल एप्लिकेशन, EOIBH-कनेक्ट की शुरुआत की गई, जिसे कांसुलर और वीज़ा सेवाओं के एक स्पेक्ट्रम के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुकिंग की सुविधा के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो मनामा, बहरीन में भारतीय दूतावास दोनों के माध्यम से सुलभ है।

20 अगस्त, 2023 को अपनी शुरुआत करने के बाद, ऐप ने तेजी से अपनी क्षमताओं का विस्तार किया है, जो अब उपयोगकर्ताओं को आईवीएस ग्लोबल के साथ आसानी से नियुक्तियों को शेड्यूल करने में सक्षम बनाता है।

यह एकीकृत दृष्टिकोण उपयोगकर्ताओं को उनकी चुनी गई सेवा के आधार पर उचित सेवा प्रदाता की ओर निर्देशित करता है, जिससे प्रक्रिया सरल हो जाती है।

नामित राजदूत जैकब ने खुले सदन में इस अवसर का लाभ उठाते हुए समुदाय के सदस्यों को नए ऐप को अपनी दिनचर्या में एकीकृत करने और अपॉइंटमेंट बुकिंग के लिए इसका लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया।

उन्होंने स्थानीय अधिकारियों और भारतीय समुदाय को उनके दृढ़ समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।

खुले सदन में 75 से अधिक भारतीय नागरिक उपस्थित थे, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, तमिल और मलयालम में बातचीत की सुविधा थी।

ऐप लॉन्च के साथ-साथ, इस कार्यक्रम में कानूनी विशेषज्ञों का एक पैनल शामिल हुआ, जिन्होंने कांसुलर और कानूनी मामलों पर सामुदायिक प्रश्न पूछे।

श्री अमित शाह गांधीनगर में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष हैं

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के तहत अंतर-राज्य परिषद सचिवालय द्वारा गुजरात सरकार के सहयोग से किया गया था।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन, दीव के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल ने राज्य और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में भाग लिया।

केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अंतर-राज्य परिषद सचिवालय के एक ई-संसाधन वेब पोर्टल का उद्घाटन किया।

इस पोर्टल में अपनी स्थापना के बाद से अंतर-राज्य परिषद, 5 क्षेत्रीय परिषदों और उनकी स्थायी समितियों की विभिन्न बैठकों के कार्यवृत्त और एजेंडे शामिल हैं।

डिजिटल पोर्टल का उपयोग केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के साथ-साथ राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा नीतिगत हस्तक्षेप के लिए किया जा सकता है।

बैठक में बुनियादी ढांचे, जल आपूर्ति, पर्यावरण और वन और सामान्य क्षेत्रीय और राष्ट्रीय हितों के मुद्दों सहित व्यापक मुद्दों पर चर्चा की गई।

पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव शामिल हैं।

गुजरात के बारे में:

राज्यपाल: आचार्य देवव्रत
मुख्यमंत्री: भूपेन्द्रभाई पटेल
राजधानी: गांधीनगर
राष्ट्रीय उद्यान: वंसदा राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, वेलावदर राष्ट्रीय उद्यान
वन्यजीव अभयारण्य: जम्बुघोड़ा वन्यजीव अभयारण्य, बरदा वन्यजीव अभयारण्य, शूलपनेश्वर वन्यजीव अभयारण्य

नवीनतम समाचार

भारत का स्वच्छ हाइड्रोजन मिशन गुजरात में हाइड्रोजन वैली परियोजना से बढ़ावा मिला।
गुजरात कैबिनेट ने स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गुजरात के 13 जिलों में 21 नए औद्योगिक एस्टेट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
भारत की G20 अध्यक्षता के हिस्से के रूप में, तीसरी व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक केवडिया, गुजरात में शुरू हुई।

दूसरी G20-मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों की गोलमेज बैठक गांधीनगर में शुरू हुई

दूसरी G20-मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों की गोलमेज बैठक गांधीनगर में शुरू हुई।
बैठक में जी 20 देशों और आमंत्रित देशों के विज्ञान सलाहकार, वैज्ञानिक, शोधकर्ता भाग ले रहे हैं।
बैठक की शुरुआत भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रो. अजय कुमार सूद के उद्घाटन भाषण से हुई।
'एक स्वास्थ्य में अवसर, विद्वानों के वैज्ञानिक ज्ञान तक पहुंच का विस्तार करने के लिए वैश्विक प्रयासों का समन्वय', विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विविधता, समानता और पहुंच और समावेशी वैश्विक एस एंड टी नीति संवाद के लिए संस्थागत तंत्र जैसे विषयों पर कुल चार सत्र होंगे।
पहले सत्र में, प्रतिनिधियों ने समावेशी वैश्विक विज्ञान सलाह की उन्नति के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।
दिन भर के विचार-विमर्श के बाद समापन सत्र में नीति विज्ञप्ति प्रस्तुत की जाएगी।
बैठक के मौके पर भारत और सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के बीच तीन द्विपक्षीय बैठकें हुईं।

नवीनतम समाचार

भारत के G20 या ग्रुप ऑफ़ 20 प्रेसीडेंसी के तहत चौथी और अंतिम एनर्जी ट्रांज़िशन वर्किंग ग्रुप (ETWG) की बैठक गोवा में आयोजित की गई।
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) गोवा में भारत की G20 प्रेसीडेंसी के तहत तीन दिवसीय SAI20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं।
शिक्षा मंत्रालय पुणे में G20 चौथी शिक्षा कार्य समूह (EDWG) बैठक की मेजबानी करने के लिए तैयारी कर रहा है।
तीसरी G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक तमिलनाडु के चेन्नई के पास महाबलीपुरम में शुरू हुई

भारत ने 2024 में G20 की मेजबानी के लिए ब्राजील को B20 की अध्यक्षता सौंपी

भारत ने 2024 में जी-20 की मेजबानी के लिए ब्राजील को बी-20 की अध्यक्षता सौंपी है।
बी20 इंडिया के अध्यक्ष एन चन्द्रशेखरन कहा कि भारत की बी20 प्रेसीडेंसी ने अपनी जी20 प्रेसीडेंसी के तहत वसुदेव कटुंबकम (एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य) की थीम के तहत काम किया।
इसमें 55 देशों के एक हजार 500 से अधिक वैश्विक व्यापार प्रतिनिधि और विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं।

Click Here to Subscribe Our Yearly Mock Test Package

श्री चन्द्रशेखरन ने कहा कि इस अवधि के दौरान हमने नौ महत्वपूर्ण विषयों पर काम किया जिसमें महिलाओं और युवाओं का सशक्तिकरण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया की ओर परिवर्तन, वैश्विक लचीली आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण और वैश्विक आर्थिक सुधार के लिए वित्तपोषण शामिल है।
भारत के बी20 की अध्यक्षता को पिछले नौ महीनों में 54 नीति सिफारिशें तैयार करने में इसकी प्रभावी प्रक्रिया, भागीदारी और आम सहमति बनाने के लिए मान्यता दी गई है।

ब्राज़ील के बारे में

राजधानी: ब्रासीलिया
मुद्रा: वास्तविक

भारी उद्योग मंत्रालय "PLI-ऑटो योजना की समीक्षा - आत्मनिर्भरता के माध्यम से उत्कृष्टता" पर एक सम्मेलन आयोजित करेगा

भारी उद्योग मंत्रालय (MHI) इंडिया हैबिटेट सेंटर में "PLI-ऑटो योजना की समीक्षा - आत्मनिर्भर के माध्यम से उत्कृष्टता" पर एक सम्मेलन का आयोजन कर रहा है।
सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉ. महेंद्र नाथ पांडे करेंगे।
इस आयोजन का उद्देश्य योजना के प्रदर्शन की समीक्षा करने, अपने ज्ञान और अनुभवों को साझा करने और सभी चिंताओं और चुनौतियों का समाधान करने के लिए हितधारकों जैसे PLI-ऑटो आवेदकों, पीएमए, परीक्षण एजेंसियों आदि को एक साथ लाना है।
इस आयोजन में इस योजना के माध्यम से उपलब्ध अवसरों को समझने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
MHI ने क्लीनर मोबिलिटी को बढ़ावा देने और नवाचार और प्रौद्योगिकी का एक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए विभिन्न पहल की हैं।
ऑटोमोटिव क्षेत्र में, मंत्रालय ने विभिन्न प्रमुख कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिनमें से एक ऑटोमोबाइल और ऑटो घटकों के लिए पीएलआई योजना (₹25,938 करोड़ का परिव्यय) है।
इन योजनाओं के व्यापक प्रभाव से ऑटोमोटिव उद्योग की वृद्धि होगी और यह अनुमान है कि भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग 2030 तक दुनिया में तीसरे नंबर पर होगा।
MHI ऑटोमोटिव उद्योग के PLI-ऑटो आवेदकों को योजना के महत्वपूर्ण हितधारकों में से एक मानता है।
MHI प्रधान मंत्री की परिकल्पना के अनुसार "आत्मनिर्भरता के माध्यम से उत्कृष्टता" के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए उद्योग का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है।
MHI के अनुसार, देश के भीतर उन्नत ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (AAT) उत्पादों के गहन स्थानीयकरण और विकास का लक्ष्य ऑटोमोटिव उद्योग के समर्थन और विकास के बिना हासिल नहीं किया जा सकता है।

केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में दुनिया की पहली 100% इथेनॉल-ईंधन वाली कार लॉन्च की

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली, दिल्ली में दुनिया की पहली 100% इथेनॉल-ईंधन वाली कार लॉन्च की।
श्री गडकरी ने इस दिन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि दुनिया का पहला बीएस-VI (स्टेज-II), विद्युतीकृत फ्लेक्स-ईंधन वाहन लॉन्च किया गया है जो पूरी तरह से इथेनॉल-आधारित ईंधन पर काम कर सकता है।

मंत्री ने वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण पर चिंता जताईकहा किदेश को प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए अधिक टिकाऊ और कड़े कदम उठाने की जरूरत है।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आत्मनिर्भर बनने के लिए देश को तेल आयात पर निर्भरता कम करनी होगी।

मुख्य विचार:

इथेनॉल मिश्रित ईंधन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने कहा, इस कदम को अपनाने के साथ देश के कृषि क्षेत्र में वृद्धि देखी जाएगी और यह बहुत सारे रोजगार के अवसर पैदा करेगा।
पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथनॉल मिश्रण लागू होने से देश को आयात बिल के रूप में सालाना 35,000 करोड़ रुपये की बचत होगी।
उन्होंने कहा कि भारत ने 2022 के प्रारंभिक लक्ष्य से 5 महीने पहले 10% इथेनॉल मिश्रण हासिल कर लिया है।
उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि देश अंतर्राष्ट्रीय जैव ईंधन गठबंधन के लिए एक साझेदारी बनाने का लक्ष्य रख रहा है।
इथेनॉल मिश्रण प्रक्रिया से किसानों ने अब तक 82,000 करोड़ रुपये कमाए हैं और देश का आयात बिल कम हुआ है।
फ्लेक्स ईंधन एक ऐसी तकनीक है जो इंजन को 20% से अधिक इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल या गैसोलीन का उपयोग करने की अनुमति देती है।
इसका उद्देश्य कार्बन पदचिह्न को कम करना, टिकाऊ गतिशीलता में सुधार करना और पारंपरिक ईंधन स्रोतों पर देश की निर्भरता को कम करना है।

नवीनतम समाचार

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने राजस्थान के प्रतापगढ़ में 5600 करोड़ रुपये की 11 एनएच परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने नगांव बाईपास-तेलियागांव और तेलियागांव-रंगागरा के बीच 4-लेन खंड का उद्घाटन किया और मंगलदाई बाईपास और असम में दाबोका-परखुवा के बीच 4-लेन खंड की नींव रखी।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के बुलढाणा के खामगांव में अमरावती-चिखली राष्ट्रीय राजमार्ग 53 पर 816 करोड़ रुपये की लागत वाली शेलाद से नंदुरा परियोजना का उद्घाटन किया।

केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पटियाला में 13 करोड़ रुपये की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का अनावरण किया:

केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री, श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अपनी उपस्थिति से पटियाला में नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान की शोभा बढ़ाई।
उन्होंने खेल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से कई नवीकरण परियोजनाओं का उद्घाटन किया।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में एनएसएनआईएस पटियाला को पिछले 1 साल में खेल विकास के लिए करोड़ों रुपये मिले हैं।
संगठनमंत्री ने किया 5 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन 13 करोड़, जिसमें अत्याधुनिक वेटलिफ्टिंग हॉल, फिटनेस सेंटर, आधुनिक हॉस्टल और गेस्ट हाउस शामिल थे।
उद्घाटन के दौरान भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष श्री सहदेव यादव भी उपस्थित थे।

मुख्य विचार:

नव पुनर्निर्मित भारोत्तोलन हॉल में विश्व स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र के लिए 26 प्रशिक्षण स्टेशन, आधुनिक प्रकार के उपकरण और अन्य सभी सहायक सुविधाएं हैं।

फिटनेस सेंटर विश्व स्तरीय स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग और फिजियोथेरेपी प्रकार के उपकरणों के साथ-साथ भाप, सौना स्नान की सुविधाओं से सुसज्जित है।
सिल्वर जुबली हॉस्टल का लक्ष्य हमारे विशिष्ट एथलीटों और बहुराष्ट्रीय शिविरों के प्रतिभागियों को सर्वोत्तम आवासीय सुविधाएं प्रदान करना है।
गोल्डन जुबली फ्लैट्स या विदेशी कोच हॉस्टल का नवीनीकरण किया गया है और विशिष्ट विदेशी कोचों के लिए सुसज्जित किया गया है और एनआईएस गेस्ट हाउस को आधुनिक सुविधाओं के साथ उन्नत किया गया है।

नवीनतम समाचार

केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ग्रेटर नोएडा में एशियाई युवा और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का उद्घाटन किया।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के व्यापार एवं निर्यात विकास मंत्री के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई

श्री पीयूष गोयल भारत के वाणिज्य और उद्योग, कपड़ा और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और न्यूजीलैंड के व्यापार और निर्यात विकास मंत्री माननीय डेमियन ओ'कॉनर ने नई दिल्ली में एक द्विपक्षीय बैठक की।
यह बैठक 22 मई 2023 को पोर्ट मोरेस्बी में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच उत्कृष्ट बैठक के आधार पर, व्यापक आधार वाले संबंध विकसित करने के लिए दोनों सरकारों के निरंतर प्रयास का हिस्सा है।

मुख्य विचार

न्यूज़ीलैंड और भारत के बीच लोगों के बीच मजबूत संबंध हैं; ये वाणिज्य, शिक्षा और पर्यटन सहित कई गतिविधियों तक विस्तारित हैं।
न्यूजीलैंड में भारतीय मूल के लोग समाज के सभी पहलुओं में मजबूत योगदान दे रहे हैं।
ये संबंध हमारे आर्थिक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं।
मंत्रियों ने दोनों देशों में व्यवसायों के बीच जुड़ाव में मजबूत कदम को स्वीकार किया, और यह सुनिश्चित करने की वांछनीयता सरकार-से-सरकार संवाद को गति प्रदान करती है।
1986 के भारत-न्यूजीलैंड व्यापार समझौते के तहत स्थापित संयुक्त व्यापार समिति (JTC) की वार्षिक बैठक और वरिष्ठ स्तर पर नियमित जुड़ाव के महत्व को भी स्वीकार किया गया।
मंत्री मिलने को राजी हुएनियमित रूप सेव्यापार और निवेश के मुद्दों और सहकारी गतिविधियों पर द्विपक्षीय चर्चा के लिए सुविधाजनक आधार।

न्यूज़ीलैंड के बारे में:

प्रधान मंत्री: क्रिस हिप्किंस
राजधानी: वेलिंग्टन
मुद्रा: डॉलर

नवीनतम समाचार:

न्यूज़ीलैंड सुपरमार्केट ग्राहकों द्वारा अपने फलों और सब्जियों को इकट्ठा करने के लिए उपयोग की जाने वाली पतली प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है।
केंद्रीय कपड़ा, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने 2030 तक कपड़ा उत्पादन में 250 अरब डॉलर और निर्यात में 100 अरब डॉलर का लक्ष्य हासिल करने के रोडमैप पर चर्चा की।

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ISO COPOLCO प्लेनरी के 44वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय बैंकों से कहा है कि वे 2030 तक एक ट्रिलियन डॉलर के व्यापारिक निर्यात के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को किफायती ऋण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एनटी रामाराव के शताब्दी वर्ष पर स्मारक सिक्का जारी किया

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र, नई दिल्ली, दिल्ली में एनटी रामाराव के शताब्दी वर्ष पर उन पर स्मारक सिक्का जारी किया।

एनटी रामाराव के बारे में:

स्वर्गीय एनटी रामा राव ने तेलुगु फिल्मों के माध्यम से भारतीय सिनेमा और संस्कृति को समृद्ध किया।
उन्होंने अपने अभिनय से रामायण और महाभारत के प्रमुख पात्रों में जान फूंक दी।
NTR ने अपनी एक फिल्म 'मानुषुलता ओक्केटे' के माध्यम से सामाजिक न्याय और समानता का संदेश भी फैलाया कि सभी इंसान समान हैं।
राष्ट्रपति ने टिप्पणी की कि NTR की लोकप्रियता एक लोक सेवक और नेता के रूप में समान रूप से व्यापक है।
उन्होंने अपने असाधारण व्यक्तित्व और कड़ी मेहनत से भारतीय राजनीति में एक अनोखा अध्याय रचा।
सुश्री मुर्मू ने एनटीआर पर स्मारक सिक्का लाने के लिए वित्त मंत्रालय की भी सराहना की।
उनका अद्वितीय व्यक्तित्व सदैव लोगों, विशेषकर तेलुगु भाषी लोगों के दिलों में अंकित रहेगा।

नवीनतम समाचार

सूरीनाम ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया- द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार, इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले भारतीय।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2022 और 2023 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए।

खनन प्रहरी ऐप सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से अवैध कोयला खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाने में मदद कर रहा है

अवैध कोयला खनन से पर्यावरण और भारत की अर्थव्यवस्था को गंभीर ख़तरा है।
सरकार ने इस समस्या के जवाब में खनन प्रहरी ऐप लॉन्च किया है।
इस मोबाइल एप्लिकेशन की मदद से, स्थानीय निवासी किसी भी संदिग्ध कोयला खनन गतिविधि की रिपोर्ट कर सकते हैं जो वे देखते हैं, जिससे इस गैरकानूनी अभ्यास को रोकने में मदद मिलती है।
कोयला खदान निगरानी और प्रबंधन प्रणाली (CMSMS) नामक संबंधित वेब पोर्टल भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियोइन्फॉर्मेटिक्स, गांधीनगर और सीएमपीडीआई, रांची के सहयोग से विकसित किया गया है।

ऐप के बारे में:

खनन प्रहरी स्मार्टफोन ऐप कोयला मंत्रालय का एक प्रयास है जो सार्वजनिक समर्थन प्राप्त करके गैरकानूनी कोयला खनन को रोकना चाहता है।
सरकार ई-गवर्नेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करके अवैध कोयला खनन से उत्पन्न विभिन्न मुद्दों को संभालना चाहती है।

प्रमुख विशेषताएं:

सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना: इस खतरे से लड़ने में नागरिकों की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए, ऐप का उद्देश्य गैरकानूनी कोयला खनन के मामलों की रिपोर्टिंग में जनता को शामिल करना है।

पारदर्शिता एवं प्रभावी कार्यवाही: कानून प्रवर्तन को गैरकानूनी खनन गतिविधि को रोकने में मदद करने के लिए ऐप अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और पारदर्शिता का उपयोग करता है।

सार्वजनिक भागीदारी का महत्व: प्रशासन के अनुसार, अवैध कोयला खनन और इसके हानिकारक प्रभावों से निपटने के लिए सभी पक्षों के ठोस प्रयास की आवश्यकता होगी।

श्री परषोत्तम रूपाला ने पशुपालन और डेयरी के लिए दूसरी राष्ट्रीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की:

मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री (FAHD) श्री परषोत्तम रूपाला ने पशुपालन और डेयरी विभाग के तहत गठित पशुपालन और डेयरी के लिए दूसरी राष्ट्रीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की।

मुख्य विचार:

FAHD मंत्री ने पहली राष्ट्रीय सलाहकार बैठक के दौरान लिए गए निर्णय का जायजा लिया और इस बात पर प्रकाश डाला कि मंत्रालय ग्रामीण उद्यमिता बनाने और बेरोजगार युवाओं और मवेशी, डेयरी, पशुधन किसानों के लिए बेहतर आजीविका के अवसर बनाने में मदद करने के लिए सभी हितधारकों के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुर्गी पालन, भेड़, बकरी, सुअर पालन, चारा और चारा क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मार्ग प्रशस्त कर रहा है।

राज्य मंत्री (विदेश राज्य मंत्री) FAHD डॉ. संजीव कुमार बालियान ने इस बात पर जोर दिया कि पुनर्गठित योजनाएं ग्रामीण मुर्गीपालन, भेड़, बकरी और सूअर पालन में उद्यमिता विकास और नस्ल सुधार पर ध्यान केंद्रित करेंगी, जिसमें चारा और चारे का विकास भी शामिल है।

नवीनतम समाचार

आजादी का अमृत महोत्सव और जी-20 के कृषि कार्य समूह (AWG) के तत्वावधान में, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB), आणंद, गुजरात में सतत पशुधन परिवर्तन पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया।

श्री परषोत्तम रूपाला भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ने "रिपोर्ट मछली रोग" के रूप में एक एंड्रॉइड-आधारित मोबाइल ऐप लॉन्च किया।

केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री, श्री परषोत्तम रूपाला ने नई दिल्ली में नई दवा और टीकाकरण प्रणाली पोर्टल के लिए नंदी-एनओसी अनुमोदन लॉन्च किया।

श्री अर्जुन मुंडा ने 'सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन के लिए जागरूकता अभियान और प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण' की शुरुआत की

केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने नई दिल्ली में 'सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन' के एक भाग के रूप में 'जागरूकता अभियान और प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण' की शुरुआत की।

कार्यक्रम में जनता, विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में इस दिशा में जागरूकता पैदा करने के लिए जमीनी स्तर के पदाधिकारियों के प्रशिक्षण की परिकल्पना की गई है।

सरकार ने 2023-24 के बजट में 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए एक मिशन की घोषणा की।

इस मिशन में केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से जागरूकता सृजन, प्रभावित आदिवासी क्षेत्रों में 0-40 वर्ष के आयु वर्ग के 7 करोड़ लोगों की सार्वभौमिक जांच और परामर्श शामिल होगा।

मिशन को औपचारिक रूप से प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में लॉन्च किया गया था।

श्री असित गोपाल, आयुक्त-NESTS, डॉ. नवल जीत कपूर, संयुक्त सचिव, श्री विश्वजीत दास, डीडीजी, श्रीमती। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य सलाहकार विनीता श्रीवास्तव और जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने फिट इंडिया क्विज़ के तीसरे संस्करण की घोषणा की

केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने JLN स्टेडियम में एक कार्यक्रम में अन्य पहलों के अलावा फिट इंडिया क्विज के तीसरे संस्करण का शुभारंभ किया।
इस कार्यक्रम में नई दिल्ली के विभिन्न स्कूलों के लगभग 500 स्कूली बच्चों के साथ-साथ MYAS, SAI और राष्ट्रीय खेल महासंघों के कई विशिष्ट एथलीटों और अधिकारियों ने भाग लिया।
मंत्री ने खेलो इंडिया योजना के तहत स्वीकृत खेल अवसंरचना परियोजनाओं पर एक सूचना पुस्तिका भी लॉन्च की और साथ ही एक राष्ट्रीय खेल महासंघ पोर्टल भी लॉन्च किया, साथ ही बुडापेस्ट में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में एशियाई रिकॉर्ड बनाने के बाद 4x400 मीटर पुरुष रिले टीम को सम्मानित किया।
लॉन्च किया गया राष्ट्रीय खेल महासंघ पोर्टल भारत सरकार के डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो व्यापार में आसानी और सुशासन सुनिश्चित करता है।
यह NSF के लिए एक एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल है, जो NSF की मान्यता के वार्षिक नवीनीकरण, राष्ट्रीय खेल महासंघों के चुनाव आदि की प्रक्रिया के लिए एकल खिड़की प्रणाली होगी।

नवीनतम समाचार

युवा मामले और खेल मंत्री तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, चेन्नई 2023 के लिए प्रतिष्ठित ट्रॉफी का अनावरण किया।
केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ग्रेटर नोएडा में एशियाई युवा और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का उद्घाटन किया।

केंद्र ने राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह और आधार आधारित भुगतान प्रणाली मार्ग सहित वेतन भुगतान के मिश्रित मार्ग को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है

केंद्र ने राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह और आधार आधारित भुगतान प्रणाली-ABPS मार्ग सहित मजदूरी भुगतान के मिश्रित मार्ग को 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ा दिया है।
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों को यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जो भी लाभार्थी काम के लिए आएगा, उससे आधार नंबर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाएगा, लेकिन इस आधार पर उसे काम देने से मना नहीं किया जाएगा।
यदि कोई लाभार्थी काम की मांग नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में एपीबीएस के लिए पात्रता के बारे में उसकी स्थिति काम की मांग को प्रभावित नहीं करती है।

मुख्य विचार:

मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जॉब कार्ड इस आधार पर नहीं बनाए जा सकते कि श्रमिक ABPS के लिए पात्र नहीं है।
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के आंकड़ों का हवाला देते हुए, मंत्रालय ने कहा कि जहां प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिए आधार सक्षम है, वहां 99.55% या उससे अधिक का उच्च सफलता प्रतिशत है।
खाता-आधारित भुगतान के मामले में ऐसी सफलता लगभग 98% है।
आधार-आधारित भुगतान प्रणाली (APBS) यह और कुछ नहीं बल्कि एक मार्ग है जिसके माध्यम से भुगतान लाभार्थियों के खाते में जमा किया जा रहा है।
मंत्रालय ने कहा कि APBS वास्तविक लाभार्थियों को उनका उचित भुगतान दिलाने में मदद कर रहा है और फर्जी लाभार्थियों को बाहर कर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में सहायक है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ने आधार-सक्षम भुगतान को नहीं अपनाया है क्योंकि योजना ने आधार आधारित भुगतान प्रणाली का विकल्प चुना है।

नवीनतम समाचार

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सूचित किया है कि मई, 2023 तक आधार आधारित भुगतान ब्रिज सिस्टम (ABPS) के माध्यम से लगभग 88% मजदूरी भुगतान किया गया है।

राज्य 100% ABPS प्राप्त करने के लिए शिविरों का आयोजन करेंगे और लाभार्थियों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करेंगे।

केंद्र ने तकनीकी कपड़ा स्टार्टअप के लिए 50 लाख रुपये तक अनुदान की घोषणा की

सरकार विशिष्ट तकनीकी कपड़ा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप और व्यक्तियों को 50 लाख रुपये तक की अनुदान सहायता प्रदान करेगी।

टेक्निकल टेक्सटाइल्स के लिए स्टार्टअप दिशानिर्देश - टेक्निकल टेक्सटाइल्स (ग्रेट) में महत्वाकांक्षी इनोवेटर्स के लिए अनुसंधान और उद्यमिता के लिए अनुदान, 18 महीने की अवधि के लिए 50 लाख रुपये तक की अनुदान सहायता प्रदान करने को मंजूरी दे दी गई है।

उन्होंने यहां राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन (NTTM) में महत्वपूर्ण विकास के बारे में संवाददाताओं से कहा कि तकनीकी वस्त्रों में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने पर जोर देने के साथ, दिशानिर्देश व्यावसायीकरण सहित प्रौद्योगिकियों और उत्पादों के लिए प्रोटोटाइप का अनुवाद करने के लिए व्यक्तियों और कंपनियों का समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

कपड़ा मंत्रालय इनक्यूबेटरों को कुल अनुदान सहायता का 10% अतिरिक्त रूप से प्रदान करेगा।

परियोजना के प्रति प्रामाणिकता और प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए, 2 समान किस्तों में इनक्यूबेटर से वित्त पोषण का न्यूनतम 10% निवेश अनिवार्य है।

स्टार्टअप दिशानिर्देश (ग्रेट) का उद्देश्य भारत में तकनीकी वस्त्र स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए बहुत आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करना है, विशेष रूप से बायोडिग्रेडेबल और टिकाऊ वस्त्र, उच्च प्रदर्शन और विशेषता फाइबर, और स्मार्ट वस्त्र जैसे विशिष्ट उप-क्षेत्रों में।

दिशानिर्देशों के अनुसार, चयनित स्टार्टअप और इनक्यूबेटर के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करना होगा

नवीनतम समाचार

भारत सरकार ने बिजली (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020 में संशोधन के माध्यम से प्रचलित बिजली टैरिफ प्रणाली में दो बदलाव पेश किए हैं।

केंद्र ने ऑटो के लिए पीएलआई को वित्त वर्ष 28 तक एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है

भारत सरकार ने ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना की समय सीमा एक और वर्ष, 2027-28 तक बढ़ा दी है।

मूल रूप से 2022-23 से 2026-27 तक चलने वाली इस योजना का उद्देश्य सब्सिडी के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों सहित उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी (AAT) उत्पादों के स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देना है।

सरकार वार्षिक के बजाय त्रैमासिक आधार पर प्रोत्साहन वितरित करने के लिए भी सहमत हुई है, और प्रक्रिया को तेज करने के लिए 2 और परीक्षण एजेंसियों को जोड़ा है।

वर्तमान में, परीक्षण ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) और इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (ICAT) में आयोजित किए जाते हैं, लेकिन ग्लोबल ऑटोमोटिव रिसर्च सेंटर (GARC) और नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक्स (NATRAX) के जुड़ने से सुविधा में मदद मिलेगी।

Click Here to Subscribe Our Yearly Mock Test Package

अब तक इस योजना के तहत 95 कंपनियों को प्रवेश दिया गया है, जिसमें ₹10,755 करोड़ का निवेश बताया गया है। सरकार ने घरेलू मूल्य संवर्धन प्रमाणन के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया प्रकाशित की है, और आने वाले महीनों में अधिक कंपनियों द्वारा प्रमाणन के लिए आवेदन करने की उम्मीद है।

PLI किसे मिलता है?

ऑटोमोटिव PLI योजना के तहत, 1 अप्रैल, 2022 से लगातार 5 वर्षों की अवधि के लिए भारत में निर्मित उन्नत ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (AAT) उत्पादों (वाहनों और घटकों) की निर्धारित बिक्री के लिए प्रोत्साहन लागू हैं।

नवीनतम समाचार

सरकार के प्रमुख विनिर्माण क्षेत्र सहायता कार्यक्रम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना का आकार 1.97 लाख करोड़ रुपये की प्रारंभिक प्रतिबद्धता के मुकाबले 2.05 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ₹17,000 करोड़ के परिव्यय के साथ आईटी हार्डवेयर के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI 2.0) योजना के दूसरे संस्करण को मंजूरी दे दी है।

BPCL अगले 5 वर्षों में पूंजीगत व्यय के रूप में 1.5 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("BPCL"), एक प्रमुख 'महारत्न' और फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी, ने आयोजित 70 वीं वार्षिक आम बैठक (AGM) में अगले 5 वर्षों के लिए अपने महत्वाकांक्षी रोडमैप का अनावरण किया।

कंपनी ने अगले 5 वर्षों में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय परिव्यय की योजना बनाई है।

BPCL के बुनियादी ढांचे के नेटवर्क का विस्तार करने के उद्देश्य से, BPCL लगभग 2,753 करोड़ रुपये के निवेश के साथ रसायनी में रसीद पाइपलाइनों के साथ POL (पेट्रोलियम तेल और स्नेहक) और एलओबीएस (ल्यूब ऑयल बेस स्टॉक) प्रतिष्ठानों की स्थापना करेगा।

इससे मुंबई रिफाइनरी से उत्पादों की निकासी में बाधा उत्पन्न होने और विशेष रूप से उत्तरी बाजारों में निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित होने की उम्मीद है।

स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन दोनों के लिए 2040 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने की दिशा में, BPCL ने एक शुद्ध-शून्य रोडमैप तैयार किया है जिसमें हरित ऊर्जा व्यवसाय, कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण (CCUS), दक्षता में सुधार और ऑफसेट खरीद शामिल हैं।

इसके लिए 2040 तक लगभग 1 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित चरणबद्ध पूंजी परिव्यय की आवश्यकता होगी और BPCL इसके लिए तैयार है।

मुख्य विचार

ई-मोबिलिटी में, BPCL ने अगले 5 वर्षों में 7,000 ऊर्जा स्टेशनों पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग सुविधाएं प्रदान करने की योजना बनाई है।

जैव ईंधन क्षेत्र में, 2022-23 में पेट्रोल में 10.6% इथेनॉल मिश्रण हासिल करने के बाद, BPCL ने वित्त वर्ष 2023-24 में मिश्रण को 12% तक बढ़ाने की योजना बनाई है और 2025 तक 20% मिश्रण तक पहुंचने का प्रयास किया है।

BPCL ओडिशा के बारगढ़ में एक एकीकृत 2जी + 1जी इथेनॉल बायो-रिफाइनरी भी स्थापित कर रहा है, जिसे मार्च 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

नवीकरणीय क्षेत्र में, BPCL जैविक और अकार्बनिक दोनों मार्गों के माध्यम से 2025 तक 1 गीगावाट (GW) और 2040 तक 10 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बनाने की इच्छा रखता है।

BPCL मुंबई और बीना में रिफाइनरियों का समर्थन करने के लिए महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में 50 मेगावाट के दो कैप्टिव पवन ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए लगभग 1,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगा।

नवीनतम समाचार

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (BPCL) मध्य प्रदेश (MP) के सागर जिले के बीना में एक एथिलीन क्रैकर (EC) परियोजना स्थापित करेगा, और लगभग 49,000 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय के साथ अपनी रिफाइनरी क्षमता का विस्तार करेगा।

BPCL के बारे में:

स्थापित: 1952

मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र, भारत

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक: जी कृष्णकुमार

BPCL पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार (GoI) के स्वामित्व के तहत एक भारतीय केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है।

इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स

भूटान ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र ने घोषणा की कि भूटान और तिमोर-लेस्ते ने रूबेला को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है, जो एक अत्यधिक संक्रामक वायरल संक्रमण है जो गर्भावस्था के दौरान अनुबंधित होने पर नवजात शिशुओं में गंभीर बीमारी और अपरिवर्तनीय जन्म दोष पैदा कर सकता है।

इन देशों में व्यापक टीकाकरण प्रयासों के माध्यम से यह उपलब्धि संभव हुई।

भूटान और तिमोर-लेस्ते ने क्रमशः 2017 और 2018 में खसरे को खत्म कर दिया था, और अब 2023 तक खसरे और रूबेला के उन्मूलन को हासिल करने के लिए मालदीव और श्रीलंका में शामिल हो गए हैं।

भूटान में पहली बार 2003 के आसपास रूबेला का प्रकोप हुआ था और टीका 2006 में शुरू हुआ था।

WHO के अनुसार, यूनिसेफ का अनुमान है कि दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में खसरा-रूबेला युक्त टीके की पहली खुराक के साथ कवरेज 2021 में 86% से बढ़कर 2022 में 92% (6% की वृद्धि) हो गई है, जबकि कवरेज टीके की दूसरी खुराक की दर 2021 में 78% से बढ़कर 2022 में 85% (7 प्रतिशत अंक की वृद्धि) हो गई है।

भूटान के बारे में:

प्रधानमंत्री: लोटे शेरिंग

राजधानी: थिम्पू

मुद्रा: भूटानी नगुल्ट्रम

भारत सऊदी अरब द्वारा आयोजित यूक्रेन शांति वार्ता में भाग लेगा

भारत को सऊदी अरब द्वारा आयोजित यूक्रेन शांति वार्ता में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है, जो 5 और 6 अगस्त, 2023 को निर्धारित है।

यह निमंत्रण तब आया है जब सऊदी अरब ने पश्चिमी देशों, यूक्रेन और कुछ प्रमुख विकासशील देशों से यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की द्वारा वर्ष की शुरुआत में पेश की गई शांति योजना पर चर्चा करने के लिए संपर्क किया है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने जेद्दा में होने वाली बैठक में भारत के शामिल होने की पुष्टि की

शांति वार्ता में शामिल होकर भारत का लक्ष्य यूक्रेन में चल रहे संकट का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के प्रयासों का समर्थन करना है।

हालाँकि, रूस को जेद्दाह की बैठक से बाहर रखा गया है।

यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की सक्रिय रूप से अपनी 10-सूत्रीय शांति योजना की वकालत कर रहे हैं, यहां तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन और अन्य विश्व नेताओं के साथ भी इस पर चर्चा कर रहे हैं।

ज़ेलेंस्की अपनी प्रस्तावित योजना के आधार पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय से वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन के लिए एक साथ आने का आग्रह कर रहे हैं।

चल रहे रूस-यूक्रेनी युद्ध और रूस द्वारा क्रीमिया पर कब्जे के कारण यूक्रेन की स्थिति अंतरराष्ट्रीय चिंता का विषय रही है। इस संघर्ष ने क्षेत्र में महत्वपूर्ण मानवीय पीड़ा और भू-राजनीतिक तनाव पैदा कर दिया है।

नवीनतम समाचार

रूस ने उस समझौते का विस्तार करने से इनकार कर दिया जिसने यूक्रेन को पिछले एक साल से अपने काला सागर बंदरगाहों से अनाज निर्यात करने में सक्षम बनाया है, यह शिकायत करते हुए कि भोजन और उर्वरकों के अपने शिपमेंट को मुक्त करने के वादे को पूरा नहीं किया गया था।

जर्मनी ने यूक्रेन को 2.7 बिलियन यूरो (3.0 बिलियन डॉलर) की सैन्य सहायता की घोषणा की। रूस के आक्रमण के बाद से यह अब तक का सबसे बड़ा पैकेज है, और जब तक आवश्यक हो तब तक कीव को और समर्थन देने का वादा किया।

यूक्रेन के बारे में:

अध्यक्ष: वलोडिमिर ज़ेलेंस्की

प्रधानमंत्री: डेनिस श्यामल

राजधानी: कीव

मुद्रा: रिव्निया

सऊदी अरब के बारे में:

प्रधान मंत्री: मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद

राजधानी: रियाद

मुद्रा: सऊदी रियाल

यूनेस्को ने वेनिस को 'विरासत खतरे की सूची' में जोड़ने की सिफारिश की

संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) ने इटली के लोकप्रिय गंतव्य वेनिस को 'विरासत खतरे की सूची' में शामिल करने की सिफारिश की है।

जलवायु परिवर्तन वेनिस की प्रमुख समस्याओं में से एक बन गई है।

यूनेस्को ने इतालवी सरकार को ऐतिहासिक शहर और इसके आसपास के लैगून को सुरक्षित करने के प्रयास बढ़ाने की सिफारिश की है।

यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार, अत्यधिक पर्यटन, अतिविकास और जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र का बढ़ता स्तर वेनिस के लिए प्रमुख जोखिम हैं।

ये जोखिम भवन संरचनाओं और शहरी क्षेत्रों को खराब और क्षतिग्रस्त कर रहे हैं।

हाल के वर्षों में वेनिस में मौसम संबंधी समस्याओं में भी वृद्धि देखी गई है।

यूनेस्को की रिपोर्ट में वेनिस की समस्याओं को हल करने में "रणनीतिक दृष्टि की कमी" के लिए इतालवी अधिकारियों को दोषी ठहराया गया है।

वेनिस को लुप्तप्राय सूची में जोड़ने का प्रस्ताव दो साल पहले यूनेस्को द्वारा लाया गया था लेकिन इतालवी सरकार द्वारा अपनाए गए कुछ उपायों के कारण अंतिम समय में इसे टाल दिया गया था।
बड़े जहाजों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और इतालवी सरकार ने शहर के लिए एक महत्वाकांक्षी संरक्षण योजना शुरू करने का वादा किया था।
हालाँकि, वेनिस के लिए संरक्षण योजना कभी लागू नहीं की गई थी।
वेनिस को "ला सेरेनिसिमा" के नाम से जाना जाता है और इटालियंस इसे एक रत्न मानते हैं।

नवीनतम समाचार:

मई 2023 में, केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि शांतिनिकेतन, वह स्थान जहां नोबेल पुरस्कार विजेता कवि रवींद्रनाथ टैगोर ने एक सदी पहले विश्वभारती का निर्माण किया था, को एक अंतरराष्ट्रीय सलाहकार निकाय द्वारा यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है।

यूनेस्को के बारे में:

स्थापना: 16 नवंबर 1945
मुख्यालय: पेरिस, फ्रांस
महानिदेशक: ऑड्रे अज़ोले

भारत-जापान साझेदारी एशिया, इंडो-पैसिफिक और दुनिया के भविष्य के लिए एक निर्णायक साझेदारी है

केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने टोक्यो में भारतीय दूतावास में आयोजित पहले भारत-जापान स्किल कनेक्ट सम्मेलन को वस्तुतः संबोधित किया।
उन्होंने भारत और जापान के बीच मजबूत साझेदारी पर जोर दिया, जो सुरक्षा, व्यापार और अर्थशास्त्र जैसे पारंपरिक क्षेत्रों से आगे बढ़कर प्रौद्योगिकी और प्रतिभा को भी शामिल कर चुकी है।
सम्मेलन में भारतीय राजदूत सिबी जॉर्ज और भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ जापान सरकार के विभिन्न मंत्रियों, अधिकारियों और जापानी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
मंत्री ने कहा कि आज दुनिया गहरे और निर्णायक संरचनात्मक, वैश्विक और आर्थिक बदलाव के दौर से गुजर रही है।
डिजिटलीकरण और प्रौद्योगिकी की अनुकूलता के साथ, दुनिया भर में आपूर्ति श्रृंखलाएं बदल रही हैं।
भारत-जापान साझेदारी एशिया, हिंद-प्रशांत और विश्व के भविष्य के लिए एक निर्णायक साझेदारी है। प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी और महामहिम प्रधान मंत्री फुमियो किशिदा के तहत, यह साझेदारी सुरक्षा, व्यापार और अर्थशास्त्र तक फैली हुई है और अब प्रौद्योगिकी और प्रतिभा में विस्तार कर रही है।
मंत्री ने अर्धचालकों पर भारत और जापान के बीच हाल ही में हुए समझौता ज्ञापन (MoU) पर प्रकाश डाला। उन्होंने दुनिया भर में विश्वसनीय साझेदारियों के महत्व पर जोर दिया, जहां कौशल और प्रतिभा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि उभरती प्रौद्योगिकियां अधिक प्रमुख होती जा रही हैं।

जापान के बारे में:

प्रधान मंत्री: फुमियो किशिदा
राजधानी: टोक्यो
मुद्रा: जापानी येन

नवीनतम समाचार

जापान सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र के संयुक्त विकास के लिए भारत के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका (US) के बाद दूसरा क्वाड भागीदार बन गया है।
तमिलनाडु और जापानी कंपनियों ने राज्य में ₹818.9 करोड़ का निवेश लाने के लिए छह समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।
जापान के डिजिटल मंत्री कोनो तारो ने दोनों देशों के बीच चल रहे डिजिटल सहयोग का जिक्र करते हुए भारत की एकीकृत भुगतान प्रणाली (UPI) में शामिल होने में गहरी रुचि व्यक्त की है।

भारत श्रीलंका की डिजिटल पहचान परियोजना का समर्थन करने के लिए 45 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करता है

श्रीलंका के डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, भारत ने द्वीप राष्ट्र की अद्वितीय डिजिटल पहचान परियोजना का समर्थन करने के लिए 45 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है।
यह कदम श्रीलंका के डिजिटलीकरण कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और इसे भारतीय अनुदान सहायता के ढांचे के तहत आगे बढ़ाया जाएगा।
कोलंबो में राष्ट्रपति कार्यालय ने भारत सरकार से धन की प्राप्ति की पुष्टि की, जो दोनों देशों के बीच साझेदारी में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त गोपाल बागले ने राष्ट्रपति सचिवालय में राष्ट्रपति स्टाफ के प्रमुख सागला रत्नायका और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री कनक हेराथ को चेक सौंपा।
अद्वितीय डिजिटल पहचान परियोजना श्रीलंका के लिए अपार संभावनाएं रखती है, क्योंकि इसका उद्देश्य देश के प्रशासनिक बुनियादी ढांचे में क्रांति लाना और अपने नागरिकों को अधिक सुव्यवस्थित और कुशल सेवा वितरण का मार्ग प्रशस्त करना है।
भारत की उदार वित्तीय सहायता डिजिटल रूप से सशक्त भविष्य की दिशा में श्रीलंका की यात्रा का समर्थन करने के लिए पड़ोसी देश की अटूट प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

श्रीलंका के बारे में

राजधानियाँ: कोलंबो, श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे
मुद्रा: श्रीलंकाई रुपया
प्रधान मंत्री: दिनेश गुणवर्धने

नवीनतम समाचार

केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग तथा आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने चेन्नई में चेन्नई से श्रीलंका के लिए भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय क्रूज जहाज एमवी एम्प्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
भारत सरकार ने श्रीलंका के लिए 1 बिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन को मार्च 2024 तक एक साल के लिए बढ़ा दिया है, जिससे संकटग्रस्त देश को आवश्यक आयात के भुगतान के लिए बैकअप फंड मिल जाएगा।

जापान के प्रधान मंत्री फुमियो किशिदा ने परमाणु बमबारी की 78वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक समारोह में मौन का क्षण रखा

जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने हिरोशिमा के हिरोशिमा शांति स्मारक पार्क में दुनिया के पहले परमाणु बम विस्फोट की 78वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक समारोह के दौरान कुछ पल का मौन रखा।
श्री किशिदा ने कहा, जापान, युद्ध में परमाणु बमबारी झेलने वाला एकमात्र राष्ट्र होने के नाते, परमाणु मुक्त दुनिया की दिशा में प्रयास जारी रखेगा।

6 अगस्त, 1945 को, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, एक यूएस बी-29 सुपरफ़ोर्ट्रेस एनोला गे ने जापान के हिरोशिमा पर "लिटिल बॉय" कोड-नाम वाला परमाणु बम गिराया, जिसके परिणामस्वरूप अनुमानित 1,40,000 लोगों की मौत हो गई।
हर साल 6 अगस्त को, दुनिया भर के लोग परमाणु युद्ध के प्रभाव और शांति और निरस्त्रीकरण के लिए वैश्विक एकता के आह्वान पर विचार करते हैं।

5वीं भारत-वियतनाम संयुक्त व्यापार उप-आयोग की बैठक नई दिल्ली में

भारत-वियतनाम संयुक्त व्यापार उप-आयोग (JTSC) की 5वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई।
बैठक की सह-अध्यक्षता भारत की ओर से वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव श्री राजेश अग्रवाल और वियतनाम की ओर से उद्योग और व्यापार मंत्रालय की उप मंत्री सुश्री फान थी थांग ने की।
कोविड-19 महामारी और अन्य कारकों के कारण जनवरी 2019 में आयोजित चौथी JTSC बैठक के बाद से चार साल से अधिक के अंतराल के बाद यह बैठक आयोजित की गई थी।
वियतनाम 2022-23 के दौरान 14.70 बिलियन अमरीकी डालर के द्विपक्षीय व्यापार के साथ भारत का 23 वां सबसे बड़ा वैश्विक व्यापार भागीदार और आसियान देशों में 5 वां सबसे बड़ा है।
आसियान के साथ भारत के कुल व्यापार में वियतनाम की हिस्सेदारी 11.2% है। वियतनाम भारत के लौह एवं इस्पात और कृषि एवं पशु उत्पादों, मुख्य रूप से मांस उत्पाद, पशु चारा, अनाज और समुद्री उत्पादों के लिए एक महत्वपूर्ण गंतव्य है।

एपीडा हवा के माध्यम से अमेरिका को ताजा अनार के पहले परीक्षण शिपमेंट के निर्यात की सुविधा प्रदान करता है

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तत्वावधान में काम करने वाली कंपनी ने हवाई मार्ग के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका में ताजा अनार के पहले परीक्षण शिपमेंट के निर्यात की सुविधा प्रदान की है।
अमेरिका को अनार की पहली निर्यात खेप एपीडा ने भारत के राष्ट्रीय पादप संरक्षण संगठन (NPPO), अमेरिका की पशु एवं पादप स्वास्थ्य निरीक्षण सेवा (US-APHIS), महाराष्ट्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड (MSAMB), ICAR-राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र, सोलापुर (NRC-सोलापुर) और अन्य के सहयोग से शुरू की थी।
एपीडा के अध्यक्ष, श्री अभिषेक देव ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में अनार के निर्यात में वृद्धि से अधिक कीमत मिलेगी और किसानों की आय में वृद्धि होगी।
अनार शिपमेंट के आयातकों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है।
अनार का परीक्षण शिपमेंट एपीडा पंजीकृत 'INI फार्म्स' द्वारा किया गया था, जो भारत से फलों और सब्जियों के शीर्ष निर्यातकों में से एक है।
इसने किसानों के साथ सीधे काम करके केले और अनार की एक मूल्य श्रृंखला बनाई है।
एग्रोस्टार समूह के एक हिस्से के रूप में, दुनिया भर के 35 से अधिक देशों में निर्यात किए जाने वाले उत्पादों के साथ किसानों को कृषि विज्ञान, कृषि-इनपुट और ऑफ-टेक की संपूर्ण सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

नेपाल के लुंबिनी में भारतीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र का निर्माण कार्य शुरू

नेपाल में बौद्ध भिक्षुओं के विशेष पाठ के साथ भूमि पूजन समारोह के बाद लुंबिनी में भारतीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र का निर्माण कार्य शुरू हो गया है।

1.60 अरब रुपये की लागत वाला हेरिटेज सेंटर कमल के आकार का होने की उम्मीद है जो जीरो-नेट तकनीक में बनाया जाएगा और डेढ़ साल में पूरा हो सकता है।
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के तत्कालीन प्रधान मंत्री शेर बहादुर देउबा ने 2022 में श्री मोदी की लुंबिनी यात्रा के दौरान संयुक्त रूप से आधारशिला रखी थी।
हमारे काठमांडू संवाददाता की रिपोर्ट है, भारत और नेपाल सांस्कृतिक विरासत साझा करते हैं, और लुंबिनी में अंतरराष्ट्रीय मानकों पर एक मठ का निर्माण आध्यात्मिक और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगा।

फ्रांस ने 2030 तक 30 हजार भारतीय छात्रों को प्रवेश की सुविधा देने का लक्ष्य रखा है:

भारतीय छात्रों और पूर्व छात्रों को एक बड़ा प्रोत्साहन देते हुए, फ्रांस ने दोनों देशों के बीच शैक्षणिक उत्कृष्टता, सांस्कृतिक समझ और दीर्घकालिक मित्रता को बढ़ावा देने के लिए नई पहल की घोषणा की है।
यह तब हुआ है जब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देश के बैस्टिल दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में फ्रांस का दौरा किया था।
फ्रांसीसी दूतावास की एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन ने 2030 तक भारत से 30,000 छात्रों का स्वागत करने के फ्रांस के लक्ष्य की घोषणा की।
इसमें आगे कहा गया है, फ्रेंच मास्टर डिग्री वाले भारतीय छात्रों को भी अपने दो साल के अध्ययन के बाद के कार्य वीजा के दौरान फ्रांस में काम करने और पेशेवर विकल्प तलाशने का अवसर मिलता है।

पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने निवर्तमान प्रधान मंत्री शहबाज शरीफ की सलाह पर नेशनल असेंबली को समय से पहले भंग करने की मंजूरी दे दी

पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने नेशनल असेंबली को समय से पहले भंग करने की मंजूरी दे दी है।
पाकिस्तान के राष्ट्रपति की घोषणा प्रधान मंत्री शहबाज शरीफ द्वारा नेशनल असेंबली को भंग करने के लिए सारांश भेजने के बाद आई।
शहबाज शरीफ के इस कदम से कार्यवाहक सेटअप की नियुक्ति की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई।
पाकिस्तान में चुनी हुई सरकार ने अपना पांच साल का संवैधानिक कार्यकाल पूरा कर लिया है
अब 90 दिनों के भीतर आम चुनाव कराने होंगे
पाकिस्तान चुनाव आयोग चुनाव की तारीख की घोषणा करेगा

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने प्रमुख प्रौद्योगिकी उद्योगों में अमेरिकी निवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है जो चीन की सैन्य क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने प्रमुख प्रौद्योगिकी उद्योगों में अमेरिकी निवेश पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उपयोग चीन की सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है।
राष्ट्रपति बिडेन ने ऐसे देशों की सेना, खुफिया, निगरानी या साइबर-सक्षम क्षमताओं के लिए महत्वपूर्ण संवेदनशील प्रौद्योगिकियों और उत्पादों में चिंता के देशों द्वारा उन्नति के खतरे से निपटने के लिए इस कदम को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया।
यह आदेश उद्यम पूंजी और निजी इक्विटी फर्मों को अर्धचालक और अन्य माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स, क्वांटम कंप्यूटर और कुछ कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुप्रयोगों को बनाने के चीनी प्रयासों में पैसा निवेश करने से प्रतिबंधित करेगा।

प्रशासन के अधिकारियों ने कहा कि यह निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए लिया गया है।

बांग्लादेश में बाढ़ के कारण चट्टोग्राम संभाग का अधिकांश हिस्सा ठप हो गया है

लगातार बारिश और भारत और म्यांमार के पहाड़ी इलाकों से पानी के बहाव के कारण बांग्लादेश का लगभग पूरा चट्टोग्राम डिविजन बाढ़ से जूझ रहा है। बांग्लादेश की सरकार ने देश के सबसे बड़े संभाग, जो 3 करोड़ लोगों का घर है, में बाढ़ के कहर से निपटने के लिए सेना तैनात की है।

सरकारी अधिकारियों के अनुसार, पिछले 24 घंटों में संभाग में भूस्खलन, डूबने और सांप के काटने से कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई है।

ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों ने कहा कि हजारों लोग सुरक्षित पेयजल, बिजली और मोबाइल नेटवर्क तक पहुंच से वंचित हैं और लगभग 35000 लोग शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी सुविधाओं में शरण लिए हुए हैं।

पोलैंड ने अवैध प्रवासियों के प्रवेश पर अंकुश लगाने के लिए सीमा पर सेना भेजना शुरू कर दिया है

बेलारूस और वैगनर लड़ाकों से बढ़ते खतरों के बीच, पोलैंड ने अपने नियंत्रण को मजबूत करने और अवैध प्रवासियों के प्रवेश पर अंकुश लगाने के लिए सीमा पर सेना भेजना शुरू कर दिया है।

अवैध घुसपैठ रोकने और स्थिरता बनाए रखने के लिए पोलैंड बेलारूस के साथ अपनी सीमा पर दो हजार सैनिक भेज रहा है।

रिपोर्टों के अनुसार, पोलैंड में अवैध रूप से पोलैंड के माध्यम से देश में प्रवेश करने की कोशिश करने वाले मध्य पूर्वी और अफ्रीकी प्रवासियों की आमद में वृद्धि देखी गई है।

वारसॉ बेलारूस पर अस्थिरता पैदा करने के लिए अवैध प्रवासियों को पोलैंड भेजने का आरोप लगाता रहा है।

इक्वाडोर के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार फर्नांडो विलाविसेंशियो की राजधानी क्विटो में एक रैली के दौरान हत्या

इक्वाडोर के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार फर्नांडो विलाविसेंशियो राजधानी क्विटो में एक रैली के दौरान मारा गया।

वर्तमान राष्ट्रपति गुइलेर्मो लासो ने घटना की पुष्टि की है।

रिपोर्टों के अनुसार, श्री विलाविसेंशियो एक कार में जा रहे थे तभी एक बंदूकधारी ने आगे बढ़कर उनके सिर में गोली मार दी।

यह घटना दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र में हिंसा के बीच सामने आई है, जिसमें मादक पदार्थों की तस्करी और हिंसक हत्याएं बढ़ रही हैं

राष्ट्रपति चुनाव का पहला दौर 20 अगस्त को होना है।

इक्वाडोर में हिंसक अपराध में हालिया वृद्धि राष्ट्रपति अभियान में एक केंद्रीय मुद्दा रही है।

संगठित अपराध से जुड़ी कई हत्याओं के बाद राष्ट्रपति गुइलेर्मो लासो ने तीन प्रांतों में आपातकाल और रात्रि कर्फ्यू की घोषणा की थी।

भारत और अंगोला के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2020-21 में 2.14 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2022-23 के दौरान 4.22 बिलियन डॉलर हो गया

भारत और अंगोला के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2020-21 में 2.14 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2022-23 के दौरान 4.22 बिलियन डॉलर हो गया है।

भारत अंगोला का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भी है और अंगोला के विदेशी व्यापार का लगभग 10 प्रतिशत हिस्सा साझा करता है।

लुआंडा में पहले भरत-एंग्लो उद्घाटन विदेश कार्यालय परामर्श (FOC) के दौरान दोनों पक्षों ने मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा की।
उन्होंने आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया। बैठक में कच्चे हीरों के व्यापार, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और रक्षा सहयोग के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए उपलब्ध अवसरों पर विस्तृत बातचीत हुई।
इसमें रक्षा खरीद के लिए अंगोला को 100 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन की भारत की पेशकश भी शामिल है।

भारतीय उच्चायोग ने बांग्लादेश में स्वतंत्रता दिवस मनाया

15 अगस्त 2023 को बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग द्वारा भारत का 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया।
ढाका में चांसरी भवन में समारोह में बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के सदस्यों ने भाग लिया।
इस वर्ष, आज़ादी का अमृत महोत्सव के चल रहे उत्सव के हिस्से के रूप में, स्वतंत्रता दिवस समारोह बड़े उत्साह के साथ आयोजित किया गया।
उच्चायुक्त, श्री प्रणय वर्मा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्र के नाम माननीय राष्ट्रपति के संबोधन के अंश पढ़े।
इस अवसर पर इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र (IGCC) के कलाकारों ने देशभक्ति गीत प्रस्तुत किये।
सिलहट, खुलना, चट्टोग्राम और राजशाही में भारत के सहायक उच्चायोग (AHC) ने भी स्वतंत्रता दिवस मनाया।

भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में LAC पर शेष मुद्दों को सुलझाने पर सहमत हुए

भारत-चीन कोर कमांडर स्तर की बैठक का 19वां दौर 13 और 14 अगस्त को भारतीय सीमा पर चुशुल-मोल्डो सीमा बैठक बिंदु पर आयोजित किया गया था।
दोनों पक्षों के बीच पश्चिमी क्षेत्र में LAC पर शेष मुद्दों के समाधान पर सकारात्मक, रचनात्मक और गहन चर्चा हुई।
विदेश मंत्रालय ने कहा कि उन्होंने नेतृत्व द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के अनुरूप खुले और दूरदर्शी तरीके से विचारों का आदान-प्रदान किया।
दोनों पक्ष शेष मुद्दों को शीघ्रता से हल करने और सैन्य और राजनयिक चैनलों के माध्यम से बातचीत और बातचीत की गति बनाए रखने पर सहमत हुए।
अंतरिम में, दोनों पक्ष सीमावर्ती क्षेत्रों में जमीन पर शांति बनाए रखने पर सहमत हुए।
जी20 फिल्म फेस्टिवल में सत्यजीत रे की 1955 की क्लासिक 'पाथेर पांचाली' को शुरुआती फिल्म के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा।
इस कार्यक्रम का आयोजन इंडिया इंटरनेशनल सेंटर और विदेश मंत्रालय के जी20 सचिवालय द्वारा किया जा रहा है।
महोत्सव में अमेरिका, दक्षिण कोरिया, तुर्की और यूके सहित विभिन्न भाग लेने वाले देशों की फिल्में शामिल होंगी।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कैंब्रिज विश्वविद्यालय में भारतीय महाकाव्य रामायण के पाठ में भाग लिया

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भारतीय महाकाव्य 'रामायण' के पाठ में हिस्सा लिया।
कैंब्रिज यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में कार्यक्रम का नेतृत्व आध्यात्मिक नेता मोरारी बापू ने किया।
"जय सिया राम" के उद्घोष के साथ अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए, पीएम सुनक ने भारतीय स्वतंत्रता दिवस पर मोरारी बापू की राम कथा में उपस्थित होने के लिए अपना सम्मान व्यक्त किया।
उन्होंने कहा कि वह इस कार्यक्रम में एक हिंदू के तौर पर शामिल हो रहे हैं, न कि केवल प्रधानमंत्री के तौर पर।
उन्होंने हिंदू भगवान राम को साहस, विनम्रता और निस्वार्थ नेतृत्व का एक स्थायी प्रतीक बताया।

संयुक्त राज्य अमेरिका ने डेनमार्क और नीदरलैंड से यूक्रेन तक F-16 लड़ाकू विमानों के हस्तांतरण को मंजूरी दे दी है:

अमेरिका की मंजूरी: संयुक्त राज्य अमेरिका ने डेनमार्क और नीदरलैंड से यूक्रेन तक एफ-16 लड़ाकू विमानों के हस्तांतरण को मंजूरी दे दी है।

महत्व: रूस के खिलाफ संघर्ष में यूक्रेन के लिए यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

एफ-16 विश्वसनीयता: F-16 को दुनिया के सबसे भरोसेमंद लड़ाकू विमानों में से एक माना जाता है।

यूक्रेन के रक्षा मंत्री की प्रतिक्रिया: यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेज़निकोव ने फैसले का स्वागत किया और यूक्रेन की अपरिहार्य जीत पर विश्वास जताया।

पिछली अमेरिकी स्थिति: प्रारंभ में, रूस के साथ बढ़ते तनाव की चिंताओं के कारण अमेरिका ने यूक्रेन को F-16 प्रदान करने से परहेज किया था।

रूसी राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा:

पुतिन का दौरा: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियान के कमांडर से मुलाकात की.

जगह: बैठक रोस्तोव-ऑन-डॉन में विशेष सैन्य संचालन समूह के मुख्यालय में हुई।

समय: यह यात्रा डोनेट्स्क क्षेत्र के उरोज़ाइन गांव में यूक्रेन की जीत के दावे के बाद हो रही है।

रूसी प्रतिक्रिया: रूस ने इस बैठक को एक विशिष्ट सैन्य अभियान का हिस्सा बताया।

MoS राजीव चन्द्रशेखर ने बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया, फ्रांस और तुर्की के मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडलों के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं

श्री राजीव चन्द्रशेखर केंद्रीय मंत्री ने जी20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप के दौरान बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया, फ्रांस और तुर्की के साथ बैठकें कीं। चर्चाओं में इंडिया स्टैक, साइबर सुरक्षा और बांग्लादेश के साथ कौशल सहयोग शामिल थे।

बांग्लादेश के ICT राज्य मंत्री के साथ बातचीत

मंत्री चंद्रशेखर ने इंडिया स्टैक, साइबर सुरक्षा और स्किलिंग पर भारत-बांग्लादेश सहयोग पर चर्चा की।

उन्होंने दक्षिण एशिया पर साझेदारी के परिवर्तनकारी प्रभाव पर प्रकाश डाला।

डिजिटल मामलों के लिए फ्रांसीसी राजदूत के साथ बैठक

मंत्री ने नागरिकों के जीवन पर एआई के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करते हुए फ्रांस के राजदूत के साथ बातचीत की।

उन्होंने भारत के एआई निवेश और इंडिया स्टैक जैसी पहल के माध्यम से शासन और अर्थव्यवस्था को डिजिटल बनाने के संयुक्त प्रयासों की क्षमता पर जोर दिया।

दक्षिण कोरिया के उप मंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता

मंत्री चन्द्रशेखर ने विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स में मजबूत तकनीकी संबंधों पर चर्चा करने के लिए दक्षिण कोरिया के उप मंत्री से मुलाकात की।

उन्होंने साझेदारी के वैश्विक प्रभाव को रेखांकित किया और सुरक्षित इंटरनेट के महत्व पर जोर दिया।

दुबई ने जीवंत शुरुआत के साथ भारतीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की शुरूआत की

भारत की आजादी की भावना दुबई में प्रज्वलित हो गई है क्योंकि शहर देश की आजादी का जश्न मनाने के लिए जीवंत कार्यक्रमों की एक श्रृंखला शुरू कर रहा है।

इस वर्ष, दुबई ने भारतीय स्वतंत्रता दिवस उत्सव की शुरुआत करने में अग्रणी भूमिका निभाई है, अपनी विविध आबादी और संपन्न भारतीय प्रवासी समुदाय को एक भव्य उत्सव में एकजुट किया है।
भारत के महावाणिज्य दूतावास ने इन उत्सवों का नेतृत्व करने के लिए प्रतिष्ठित बुर्जुमन मॉल के साथ साझेदारी की है। मॉल का केंद्रीय स्थान और शहर के सांस्कृतिक परिदृश्य में महत्व इसे भारत की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करने वाले आकर्षक कार्यक्रमों की एक श्रृंखला की मेजबानी करने के लिए एक उपयुक्त स्थान बनाता है।
विभिन्न भारतीय राज्यों के सार को दर्शाने वाले पारंपरिक नृत्यों से लेकर भारत की संगीत परंपराओं की धुनों तक, यह समारोह 12 अगस्त से हर शाम दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रहा है। भारतीय संस्कृति की विविध टेपेस्ट्री को प्रदर्शित करने वाला रंगारंग प्रदर्शन एक आकर्षण रहा है, जो निवासियों और आगंतुकों दोनों को मंत्रमुग्ध कर रहा है।
वर्तमान में अपने कार्यबल में योगदान देने वाले 3.554 मिलियन भारतीयों के प्रभावशाली आंकड़े के साथ, संयुक्त अरब अमीरात भारतीय प्रवासियों के अग्रणी नियोक्ता के रूप में गर्व से खड़ा है। एकता और सांस्कृतिक प्रशंसा के दिल को छू लेने वाले प्रदर्शन में, संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय संघ स्वतंत्रता की दिशा में भारत की यात्रा को मनाने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं।

विदेश में भारतीयों को रोजगार देने में UAE अग्रणी, MoS वी मुरलीधरन ने खुलासा किया

विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने लोकसभा में यह खुलासा किया कि संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने भारतीय प्रवासियों के प्रमुख नियोक्ता के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है, वर्तमान में इसकी सीमाओं के भीतर काम करने वाले 3.554 मिलियन भारतीयों का प्रभावशाली आंकड़ा है।
मंत्री ने यह भी बताया कि पिछले वर्ष, संयुक्त अरब अमीरात ने 3.419 मिलियन भारतीयों की मेजबानी की थी, जो विदेशी रोजगार में लगातार वृद्धि का संकेत देता है। इस उछाल ने भारतीय प्रवासियों के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में UAE की स्थिति को और मजबूत कर दिया है, जो अन्य खाड़ी देशों में भी देखी गई प्रवृत्ति को दर्शाता है।
खाड़ी क्षेत्र के भीतर, संयुक्त अरब अमीरात की प्रमुखता को चार अन्य देशों - सऊदी अरब, कुवैत, कतर और ओमान - द्वारा भारतीय कार्यबल संख्या के घटते क्रम में पूरक किया जाता है। राज्य मंत्री के बयान के अनुसार, ये पांच देश संयुक्त रूप से 7.932 मिलियन भारतीयों को रोजगार देते हैं।
भारतीय प्रवासियों के समर्थन के महत्व को पहचानते हुए, भारत सरकार ने दुबई, रियाद, जेद्दा और कुआलालंपुर जैसे रणनीतिक स्थानों में प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र स्थापित किए हैं।
इन केंद्रों का लक्ष्य विभिन्न मामलों पर भारतीय श्रमिकों को व्यापक मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान करना है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वे अपने मेजबान देशों में निर्बाध रूप से एकीकृत हों।
मंत्री मुरलीधरन ने यह भी कहा कि खाड़ी देशों में भारतीय राजनयिक मिशनों ने समर्पित श्रमिक विंग की स्थापना की है, जो अपने प्रवासी नागरिकों के अधिकारों और कल्याण की सुरक्षा के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देती है।

भारत ने इंडोनेशिया के सेमारंग में 20वीं आसियान-भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक में भाग लिया

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में अपर सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने इंडोनेशिया के सेमारंग में 21 अगस्त, 2023 को आयोजित 20वीं आसियान-भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया और इंडोनेशिया के व्यापार मंत्री डॉ. जुल्किफली हसन के साथ बैठक की सह-अध्यक्षता की।

सभी 10 आसियान देशों के आर्थिक मंत्री या उनके प्रतिनिधि बैठक में ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम ने भाग लिया। लोकतांत्रिक गणराज्य तिमोर-लेस्ते भी पर्यवेक्षक के रूप में बैठक में शामिल हुआ।

मंत्रियों ने भारत और आसियान के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों की समीक्षा कीभारत और आसियान के बीच आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने और बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आसियान-भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी दोनों पक्षों के लिए सार्थक लाभ प्रदान करे, खासकर महामारी के बाद के युग में।

भारत और आसियान ने 2022-23 में 131.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार दर्ज किया।

2022-23 में आसियान के साथ व्यापार भारत के वैश्विक व्यापार का 11.3% था।

मंत्रियों ने आसियान-भारत व्यापार परिषद (AIBC) के साथ भी बातचीत की और 2023 में AIBC द्वारा की गई गतिविधियों पर ध्यान दिया, जिसमें कुआलालम्पुर में 6 मार्च, 2023 को आयोजित 5वां आसियान-भारत व्यापार शिखर सम्मेलन भी शामिल है।

मंत्रियों ने क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों पर विचारों का आदान-प्रदान किया, जैसे कि COVID-19 महामारी का बहुआयामी प्रभाव, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक वित्तीय बाजार में बढ़ी अस्थिरता, मुद्रास्फीति का दबाव और भू-राजनीतिक तनाव।

इस वर्ष की बैठक का मुख्य एजेंडा आसियान-भारत माल व्यापार समझौते (AITIGA) की समय पर समीक्षा करना था जिस पर 2009 में हस्ताक्षर किए गए थे।

आर्थिक मंत्रियों की बैठक AITIGA संयुक्त समिति की बैठक से पहले हुई, जिसमें समीक्षा के लिए रोडमैप पर विचार-विमर्श किया गया और AITIGA समीक्षा वार्ता के संदर्भ की शर्तों और कार्य योजना को अंतिम रूप दिया गया।

अमेरिका के FDA ने गर्भावस्था के दौरान बच्चे की सुरक्षा के लिए महिलाओं में उपयोग के लिए पहले रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस वैक्सीन को मंजूरी दे दी है

संयुक्त राज्य अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने गर्भावस्था के दौरान बच्चे की सुरक्षा के लिए महिलाओं में उपयोग के लिए पहले रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस (RSV) वैक्सीन को मंजूरी दे दी है।

यह टीका फाइजर द्वारा विकसित किया गया है और मंजूरी से निचले श्वसन पथ के संक्रमण और छह महीने की उम्र तक शिशुओं में गंभीर बीमारी की रोकथाम के लिए गर्भावस्था के 32 से 36 सप्ताह की महिलाओं को टीका देने की अनुमति मिलती है।

वैक्सीन डेवलपर ने कहा है कि मातृ टीकाकरण से RSV के कारण बड़ी संख्या में अस्पताल में भर्ती होने से रोका जा सकता है।

सिंकाइटियल वायरस को बच्चों में बीमारी का एक सामान्य कारण माना जाता है, जबकि शिशुओं में गंभीर बीमारी का खतरा सबसे अधिक होता है।

USA के बारे में:

पूंजी: वाशिंगटन डीसी

मुद्रा: डॉलर

अध्यक्ष: जो बिडेन

फाइजर के बारे में:

फाइजर इंक एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय दवा और जैव प्रौद्योगिकी निगम है जिसका मुख्यालय मैनहट्टन, न्यूयॉर्क शहर में सर्पिल में है।
कंपनी की स्थापना 1849 में न्यूयॉर्क में दो जर्मन उद्यमियों, चार्ल्स फाइजर (1824-1906) और उनके चचेरे भाई चार्ल्स एफ एरहार्ट (1821-1891) द्वारा की गई थी।

पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने आधिकारिक गोपनीयता संशोधन विधेयक 2023 और पाकिस्तान सेना संशोधन विधेयक 2023 पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया

पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने आधिकारिक गोपनीयता संशोधन विधेयक 2023 और पाकिस्तान सेना संशोधन विधेयक 2023 पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया।
राष्ट्रपति अल्वी ने अपने कर्मचारियों पर उनकी इच्छा और आदेश को कमज़ोर करने का आरोप लगाया।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने घोषणा की, उन्होंने अपने कर्मचारियों को बिना हस्ताक्षर किए गए बिलों को निर्धारित समय के भीतर वापस करने का निर्देश दिया, ताकि वे कानूनों से असहमत हों।
हालाँकि, उनके कर्मचारियों ने कथित तौर पर उनकी इच्छा और आदेश को कमज़ोर कर दिया।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राष्ट्रपति के बाद सीनेट और नेशनल असेंबली ने इन विधेयकों को मंजूरी दे दी।
पाक राष्ट्रपति का बयान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरेशी की हालिया गिरफ्तारी के बाद आया है, जो पूर्व विदेश मंत्री और पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान के खिलाफ आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के मामले से जुड़ा है।
पाकिस्तान सेना अधिनियम एक ऐसा अधिनियम है जहां सेवारत अधिकारी को संस्था की आंतरिक जांच, परीक्षण और दंड प्रणाली के माध्यम से दोषी पाए जाने पर कोर्ट मार्शल के माध्यम से सेवाओं से बर्खास्त कर दिया जाता है और अपमानजनक तरीके से बाहर कर दिया जाता है।
सरकारी गोपनीयता अधिनियम किसी के जानबूझकर सार्वजनिक अशांति पैदा करने या सरकार के खिलाफ जाने के मामले में लागू होता है और इसकी धाराएं राजद्रोह, जासूसी और जासूसी के लिए लागू होती हैं, जिसके लिए सजा में मृत्युदंड भी शामिल है।

पाकिस्तान के बारे में:

पूंजी: इस्लामाबाद
मुद्रा: रुपया
अध्यक्ष: आरिफ अल्वी

सऊदी अरब ने मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए एआई-संचालित कार्यक्रम शुरू किया

सऊदी पर्यावरण मंत्रालय कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग करके मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है।
कार्यक्रम, जो मंत्रालय, वनस्पति विकास और मुकाबला मरुस्थलीकरण के लिए राष्ट्रीय केंद्र और किंग अब्दुल्ला विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के बीच एक सहयोग है, का उद्देश्य राज्य में वनस्पति कवर की स्थिति का अध्ययन करना और वनीकरण परियोजनाओं और "ग्रीन सऊदी" पहल के लक्ष्यों में योगदान करना है।

सऊदी अरब के सामने मरुस्थलीकरण एक बड़ी चुनौती है, एक शुष्क देश जो पहले से ही जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना कर रहा है।
कार्यक्रम उन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए उपग्रह इमेजरी और अन्य डेटा का विश्लेषण करने के लिए AI का उपयोग करेगा जो मरुस्थलीकरण के लिए सबसे अधिक संवेदनशील हैं।
रिमोट सेंसिंग प्रौद्योगिकियों का उपयोग वनस्पति आवरण, वर्षा, पौधों के स्वास्थ्य की निगरानी और समय के साथ इसके परिवर्तनों को ट्रैक करने के लिए किया जाएगा
एआई-संचालित कार्यक्रम के अलावा, सऊदी अरब मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए कई अन्य पहल भी लागू कर रहा है। इनमें "ग्रीन सऊदी" पहल शामिल है, जिसका लक्ष्य देश भर में 10 अरब पेड़ लगाना है, और "नेशनल सेंटर फॉर वेजिटेशन डेवलपमेंट एंड कॉम्बेटिंग डेजर्टिफिकेशन", जो सूखा प्रतिरोधी पौधों को विकसित करने और जल प्रबंधन प्रथाओं में सुधार करने के लिए काम कर रहा है।
23-24 अक्टूबर को रियाद में आयोजित होने वाला आगामी सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव (SGI) फोरम, सऊदी अरब की तेल आधारित अर्थव्यवस्था को एक स्वच्छ और अधिक टिकाऊ में बदलने के ऐतिहासिक प्रयास में एक मील का पत्थर साबित होने के लिए तैयार है।
10 अरब पेड़ (कुल भूमि क्षेत्र का 30 प्रतिशत कवर करते हुए) लगाने के अलावा, एसजीआई का लक्ष्य विशाल संरक्षित क्षेत्र बनाना, तटों के आसपास समुद्री जीवन का संरक्षण करना और कृषि के वैकल्पिक रूपों को प्रोत्साहित करना है।
इस बड़े बदलाव का एक प्रमुख पहलू सऊदी अरब की हरियाली में प्रौद्योगिकी का योगदान होगा।

सऊदी अरब के बारे में:

पूंजी: रियाद
मुद्रा: रियाल
राजा: **सलमान बिन अब्दुलअज़ीज़ अल सऊद**

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को ग्रीस के ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया

प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी को ग्रीक राष्ट्रपति कतेरीना एन सकेलारोपोलू द्वारा प्रतिष्ठित ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, यह एक विशेष सम्मान है जो भारत-ग्रीस साझेदारी की ताकत को दर्शाता है।
श्री नरेंद्र मोदी ग्रैंड क्रॉस ऑफ़ द ऑर्डर ऑफ़ ऑनर प्राप्त करने वाले पहले विदेशी शासनाध्यक्ष बने।

ऑर्डर ऑफ ऑनर के ग्रैंड क्रॉस के बारे में:

ग्रैंड क्रॉस ऑफ़ द ऑर्डर ऑफ़ ऑनर, ग्रीस में उनके योगदान के लिए व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए 1975 में स्थापित एक पुरस्कार।
ऑर्डर के स्टार में देवी एथेना का सिर और शिलालेख "केवल धर्मी लोगों का सम्मान किया जाना चाहिए" अंकित है, जो सम्मान और धार्मिकता के मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है।
ग्रैंड क्रॉस प्रधानमंत्रियों सहित प्रतिष्ठित हस्तियों को प्रदान किया जाता है, जिन्होंने विशिष्ट पदों पर रहते हुए ग्रीस की स्थिति और हितों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
मोदी की ग्रीस यात्रा चार दशकों में किसी भारतीय प्रधान मंत्री की पहली यात्रा थी, जिससे दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध मजबूत हुए।

मुख्य विचार:

इसके अलावा, पीएम मोदी ने एथेंस में "अज्ञात सैनिक की कब्र" पर भी श्रद्धांजलि अर्पित की।

वह 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग से ग्रीस पहुंचे।
40 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली ग्रीस यात्रा होगी।
सितंबर 1983 में ग्रीस की आखिरी उच्च स्तरीय यात्रा तत्कालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी ने की थी।

द्विपक्षीय संबंध और समझौते:

सभ्यतागत संबंध: भारत और ग्रीस के बीच गहरे सभ्यतागत संबंध हैं जो समुद्री परिवहन, रक्षा, व्यापार, निवेश और लोगों से लोगों के बीच आदान-प्रदान में सहयोगात्मक प्रयासों से मजबूत हुए हैं।
आर्थिक सहयोग: दोनों देशों का लक्ष्य व्यापार, निवेश, शिपिंग, प्रवासन और रक्षा सहयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करना है। वे रक्षा औद्योगिक सहयोग बढ़ाने की भी योजना बना रहे हैं।
प्रवासन साझेदारी: नेताओं ने कुशल प्रवासन को बढ़ावा देने, दोनों देशों के बीच कार्यबल की मुक्त आवाजाही की सुविधा के लिए गतिशीलता और प्रवासन साझेदारी समझौते (MMPA) पर चर्चा की।
क्षेत्रीय सहयोग: कृषि पर हेलेनिक-भारतीय संयुक्त उप-समिति की स्थापना पारस्परिक लाभ के लिए कृषि में सहयोग को बढ़ावा देने के आपसी प्रयासों का प्रतीक है।

पीएम मोदी को मिले अन्य सम्मान:

2019 में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को बहरीन के राजा हमद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा द्वारा किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां (खाड़ी देश में शीर्ष सम्मान) से सम्मानित किया गया था।
उन्हें 2019 में रूस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अवार्ड से सम्मानित किया गया था।
इसके अलावा 2019 में उन्हें यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद अवॉर्ड भी मिला।
2020 में, प्रधान मंत्री मोदी को तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

नवीनतम समाचार:

जून, 2023 में प्रधान मंत्री मोदी को अरब राष्ट्र की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी द्वारा मिस्र के सर्वोच्च सम्मान 'ऑर्डर ऑफ द नाइल' से सम्मानित किया गया था।

ग्रीस के बारे में:

अध्यक्ष: कतेरीना सकेलारोपोलू
प्रधान मंत्री: किरियाकोस मित्सोटाकिस
पूंजी: एथेंस
मुद्रा: यूरो

ब्रिक्स में शामिल होने के लिए तैयार 6 नए देशों में ईरान, सऊदी अरब और मिस्र शामिल हैं

15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 22 से 24 अगस्त, 2023 तक दक्षिण अफ्रीका के सैंडटन कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया था।
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का एक प्रमुख परिणाम ब्रिक्स नेताओं द्वारा 6 नए सदस्यों को शामिल करने के लिए इसकी सदस्यता का विस्तार करने का निर्णय था।
ये देश हैं - ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, अर्जेंटीना, मिस्र और इथियोपिया 1 जनवरी, 2024 से ब्रिक्स में प्रवेश करने के लिए तैयार थे, वर्तमान सदस्यों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ 11-राष्ट्र ब्लॉक बनाने के लिए।

यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कदम ब्रिक्स के 'वैश्विक दक्षिण की आवाज' होने के दावे को मजबूत कर सकता है।
यह घोषणा जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा द्वारा की गई, जिनका देश वर्तमान ब्रिक्स अध्यक्ष है।
दुनिया के शीर्ष 10 तेल उत्पादकों में से 6 अब ब्रिक्स के सदस्य होंगे, जिनमें सऊदी अरब, रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, ब्राजील और ईरान शामिल हैं।

15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बारे में:

15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका ने की।
1 जनवरी 2023 को दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स का अध्यक्ष बना।
विषय -ब्रिक्स और अफ्रीका: पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी
शिखर सम्मेलन के अंत में, सदस्य देशों ने जोहान्सबर्ग द्वितीय घोषणा को अपनाया।

ब्रिक्स के बारे में:

ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का एक क्षेत्रीय समूह है।
दक्षिण अफ्रीका को 2010 में जोड़ा गया था।
ब्रिक्स के फैसले सर्वसम्मत होते हैं, यानी किसी भी कदम को आगे बढ़ाने के लिए सभी सदस्यों को सहमत होना पड़ता है।

चीन-भूटान ने 'सीमा के परिसीमन' पर पहली बैठक की

चीन और भूटान ने बीजिंग में चीन-भूटान सीमा के परिसीमन पर संयुक्त तकनीकी टीम की पहली बैठक आयोजित की।
वे सीमा समाधान में तेजी लाने पर सहमत हुए और अगली बैठक यथाशीघ्र आयोजित करने का निर्णय लिया।
दोनों देश अपनी बातचीत में सकारात्मक गति बनाए रखने के लिए 25वें दौर की सीमा वार्ता आयोजित करने पर भी सहमत हुए।

चीन और भूटान के बीच सीमा वार्ता का इतिहास:

भूटान और चीन के बीच सीमा वार्ता 1984 में शुरू हुई।
24वें दौर की वार्ता 2016 में हुई थी
बातचीत मुख्य रूप से भूटान के उत्तर और उसके पश्चिम के विवादित क्षेत्रों पर केंद्रित है।
चीन और भूटान तीन-चरणीय रोड मैप के कार्यान्वयन में तेजी लाने और समन्वय करने पर भी सहमत हुए।
भारत भूटान और चीन के बीच किसी भी समझौते को लेकर बहुत चिंतित होगा जिसमें डोकलाम के साथ उत्तर के क्षेत्रों (जमपरलुंग और पासमलुंग घाटियों) के बीच "स्वैप व्यवस्था" शामिल है।
इससे भारत के संकीर्ण "सिलीगुड़ी कॉरिडोर" से चीन की निकटता बढ़ जाएगी जो पूर्वोत्तर राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है।
2020 में चीन ने भूटान के पूर्वी साकतेंग अभयारण्य में नया दावा किया

चीन के बारे में:

पूंजी: बीजिंग
मुद्रा: रॅन्मिन्बी

भूटान के बारे में:

प्रधान मंत्री: लोटे शेरिंग
पूंजी: थिम्पू
मुद्रा: नोंग्त्रुम

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ब्रिक्स बिजनेस फोरम लीडर्स डायलॉग में भाग लिया

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल) बिजनेस फोरम लीडर्स डायलॉग में हिस्सा लिया।

उन्होंने इस संवाद सत्र के दौरान एक संबोधन दिया, जिसमें वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच भारत की आर्थिक लचीलापन और विकास पर प्रकाश डाला गया।

वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद, पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत दुनिया भर में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखे हुए है।

उन्होंने विश्वास जताया कि भारत निकट भविष्य में पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है।

मुख्य विचार:

पीएम मोदी 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 22 अगस्त, 2023 को दक्षिण अफ्रीका पहुंचे।

दक्षिण अफ्रीका के उप राष्ट्रपति पॉल मैशाटाइल ने उनका स्वागत किया।

15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय ब्रिक्स और अफ्रीका: पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी है।

यात्रा के दौरान व्यस्तताएँ:

पीएम मोदी ने बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए ब्रिक्स-अफ्रीका आउटरीच और ब्रिक्स प्लस डायलॉग कार्यक्रम में भाग लिया।

दक्षिण अफ्रीका में अपनी व्यस्तता के बाद, पीएम मोदी की प्रधान मंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस के निमंत्रण पर ग्रीस के एथेंस की यात्रा करने की योजना थी।

यह यात्रा एथेंस की उनकी पहली यात्रा थी

टिप्पणी:

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 23 जून, 2022 को बीजिंग, चीन में 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की

14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय: उच्च गुणवत्ता वाली ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा देना, वैश्विक विकास के लिए एक नए युग की शुरुआत करना।

ब्रिक्स के बारे में:

मुख्यालय: शंघाई, चीन

ब्रिक्स वैश्विक आबादी का 42%, विश्व सकल घरेलू उत्पाद का 23% और वैश्विक व्यापार का 18% प्रतिनिधित्व करता है।

स्टेट करेंट अफेयर्स

एपी-जेनको और NHPC आंध्र प्रदेश में पंप भंडारण जलविद्युत परियोजनाओं को लागू करने के लिए संयुक्त उद्यम स्थापित करेंगे

आंध्र प्रदेश पावर जेनरेशन कॉरपोरेशन (एपी-जेनको) और नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (NHPC) जल्द ही आंध्र प्रदेश (एपी) में 6,000 मेगावाट (मेगावाट) की कुल उत्पादन क्षमता के साथ पंप स्टोरेज हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स (PSPH) को लागू करने के लिए एक संयुक्त उद्यम (जेवी) शुरू करेंगे।

मुख्य विचार:

इनमें से, अल्लूरी सीतारमा राजू (ASR) जिले के जीके विधि मंडल में ऊपरी सिलेरू में 1,350 मेगावाट (9x150 मेगावाट) PSHP को जेवी के तत्वावधान में पहली परियोजना के रूप में प्राथमिकता दी जाएगी।
इसके पूरा होने पर, सिलेरू बेसिन की संयुक्त स्थापित जलविद्युत क्षमता 2,425 मेगावाट से अधिक हो जाएगी।
कंपनियां जल्द ही मसौदा समझौते पर हस्ताक्षर करेंगी और भागीदारों के पास बराबर (50:50) हिस्सेदारी होगी।
कुल मिलाकर, एपी-जेनको ने आने वाले वर्षों में पंप भंडारण जलविद्युत की 33 गीगावाट (GW) (29 परियोजनाएं) उत्पादन का लक्ष्य रखा है।
33 गीगावॉट में से, 11 गीगावॉट की कुल क्षमता वाले PSPH निजी कंपनियों को दिए जा रहे थे और शेष में से अधिकांश एपी-जेनको और कुछ नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NTPC) द्वारा किए जाएंगे।

नवीनतम समाचार:

जुलाई, 2023 में आंध्र प्रदेश (AP) के मुख्यमंत्री (CM) वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने चौथे वर्ष के लिए 'जगन्ना अम्मा वोडी' योजना शुरू की, जिसके तहत आंध्र प्रदेश के पार्वतीपुरम मान्यम जिले के कुरुपम में 43 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में 6,393 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता जमा की जाएगी।

एपी के बारे में:

राज्यपाल: एस अब्दुल नज़ीर
मुख्यमंत्री: वाईएस जगन मोहन रेड्डी
राष्ट्रीय उद्यान: पापिकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी (रामेश्वरम) राष्ट्रीय उद्यान, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान
वन्यजीव अभयारण्य: कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य, कंबलाकोंडा वन्यजीव अभयारण्य, कृष्णा वन्यजीव अभयारण्य, गुंडला ब्रह्मेश्वरम वन्यजीव अभयारण्य

ओडिशा सरकार ने कृषि विकास को बढ़ाने के लिए किसानों के लिए ब्याज मुक्त ₹1 लाख फसल ऋण की घोषणा की

कृषि समुदाय को समर्थन देने और उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में, ओडिशा राज्य सहयोग विभाग ने राज्य क्षेत्र योजना "ब्याज सब्सिडी-अनुदान" के कार्यान्वयन की घोषणा की।
इसके लिए, राज्य मंत्रिमंडल ने 2023-24 से 2027-28 तक 5 वर्षों में राज्य में किसानों को सस्ती ब्याज दर पर कृषि में पर्याप्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 5700 करोड़ रुपये के प्रावधान को मंजूरी दी है।

ब्याज सब्सिडी-अनुदान योजना के बारे में:

योजना के तहत किसानों को एक लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त फसली ऋण मिलेगा।
1 लाख रुपये से 3 लाख रुपये से अधिक के फसल ऋण पर 2% ब्याज दर ली जाएगी।
ये ब्याज दरें 1 अप्रैल, 2022 से पूर्वव्यापी रूप से लागू होंगी।
इससे पहले, किसानों को कालिया (आजीविका और आय संवर्धन के लिए कृषक सहायता) के तहत 50000 रुपये की सीमा तक ब्याज मुक्त फसल ऋण प्रदान किया जा रहा था।
कैबिनेट की 20 लाख रुपये की मंजूरी 5700 करोड़ रुपये सहकारी बैंकों और प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (PACS) को ब्याज सब्सिडी या सबवेंशन प्रदान करने की दिशा में एक कदम है।
अब तक, सहकारी समितियाँ ओडिशा में कुल फसल ऋण का लगभग 55% प्रदान करती हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 17% है।
ओडिशा कैबिनेट ने वन सुरक्षा समितियों (VSS) के लिए भवन बनाने को भी मंजूरी दे दी है।

सरकार 2023-24 से 2026-27 तक 4 वर्षों के दौरान चरणबद्ध तरीके से वीएसएस के लिए राज्य भर में 10,000 भवनों का निर्माण करेगी।

टिप्पणी:

किसानों को मुफ्त फसल बीमा प्रदान करने वाला ओडिशा देश का पहला राज्य है।

ओडिशा के बारे में:

राज्यपाल: गणेशी लाल

मुख्यमंत्री: नवीन पटनायक

पूंजी: भुवनेश्वर

दुनिया में पुरुषों के लिए सबसे बड़ी और सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रतियोगिता, रूबरू मिस्टर इंडिया, अगस्त 2023 में गोवा में आयोजित की जाएगी

भारत के खूबसूरत राज्य गोवा को पुरुषों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रतियोगिता, रुबरू मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता की मेजबानी के लिए चुना गया है।

यह प्रसिद्ध कार्यक्रम इस अगस्त में 5 अगस्त को बोगमैलो बीच रिज़ॉर्ट में होने वाले राष्ट्रीय फाइनल के साथ होगा।

अगस्त के महीने में, गोवा रुबरू मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता के 19वें सीज़न के लिए भारत के विभिन्न हिस्सों से 32 सबसे सुंदर, करिश्माई और प्रतिभाशाली पुरुषों का स्वागत करेगा।

सुंदर उम्मीदवारों के साथ-साथ, फैशन जगत और सौंदर्य प्रतियोगिता उद्योग से कई उल्लेखनीय और प्रमुख हस्तियां भी इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम के लिए गोवा की यात्रा करेंगी।

5 अगस्त, 2023 को प्रतियोगिता के समापन पर, पूरा भारत देश के सबसे खूबसूरत आदमी का नाम सीखेगा।

नवीनतम समाचार

गोवा राज्य के राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई ने गोवा के लेखक दामोदर मौजो को देश के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) गोवा में भारत की G20 प्रेसीडेंसी के तहत तीन दिवसीय SAI20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं।

जी 20 देशों के सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों (SAI) का दूसरा शिखर सम्मेलन गोवा की राजधानी पणजी में शुरू होगा।

नागालैंड को आधिकारिक तौर पर गांठदार त्वचा रोग सकारात्मक राज्य घोषित किया गया है:

नागालैंड को आधिकारिक तौर पर लम्पी स्किन डिजीज पॉजिटिव स्टेट घोषित किया गया है।

यह घोषणा जानवरों में संक्रामक और संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम, 2009 के तहत राज्य के चार जिलों में गांठदार त्वचा रोग का पता चलने के बाद की गई है।

पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवा निदेशालय, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा जारी सलाह और दिशानिर्देशों के अनुसार संबंधित राज्य विभाग के साथ सभी आवश्यक निवारक उपायों को लागू करेगा।

नागालैंड के बारे में:

राजधानी: कोहिमा

आधिकारिक फूल: रोडोडेंड्रोन आर्बोरेटम

मुख्यमंत्री: नेफ्यू रियो
राज्यपाल: श्री ला गणेशन

उत्तर प्रदेश सरकार सभी 75 जिलों को कवर करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना का विस्तार करेगी

5,000 बच्चों तक पहुंचने के लिए, उत्तर प्रदेश (यूपी) सरकार ने सभी 75 जिलों में 'बाल श्रमिक विद्या योजना' का विस्तार करने का निर्णय लिया।

योजना का उद्देश्य:

बाल श्रमिकों को शिक्षित करना।
इसे वर्तमान में 20 जिलों में लागू किया जा रहा है और 2,000 बच्चों को लाभ मिल रहा है।
कृषि, स्वरोजगार, गृह-आधारित प्रतिष्ठानों, घरेलू काम और अन्य प्रकार के श्रम में शामिल 8 से 18 वर्ष की आयु के चयनित बच्चों को वित्तीय सहायता मिलेगी।

मुख्य विचार:

बाल श्रमिक विद्या योजना के तहत लाभार्थी लड़के और लड़कियों को सालाना 12000 रुपये और 14400 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी।
इसके अलावा भूमिहीन परिवारों के कामकाजी बच्चे भी योजना के पात्र हैं।
वित्तीय सहायता प्राप्त करने की एकमात्र शर्त स्कूल में 70% उपस्थिति है।
जिन परिवारों में माता या पिता का निधन हो गया है वे योजना का लाभ लेने के पात्र होंगे।
यदि ये बच्चे कक्षा 8, 9 और 10 पास करते हैं, तो उन्हें प्रत्येक स्तर को पास करने के लिए 6,000 रुपये अतिरिक्त मिलते हैं।
इस योजना की शुरुआत 2020 में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की थी।

नवीनतम समाचार:

जुलाई 2023 में, उत्तर प्रदेश (UP) सरकार ने सब्सिडी पोर्टल, upevsubsidy.in लॉन्च किया, जिससे लोगों को यूपी में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की खरीद पर उपलब्ध सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का मार्ग प्रशस्त हुआ।

यूपी के बारे में:

राज्यपाल: आनंदीबेन पटेल
मुख्यमंत्री: योगी आदित्यनाथ
राजधानी: लखनऊ
राष्ट्रीय उद्यान: दुधवा राष्ट्रीय उद्यानवन्यजीव अभयारण्य: बखिरा वन्यजीव अभयारण्य, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाथियों की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया

झारखंड के मुख्यमंत्री (सीएम) श्री हेमंत सोरेन ने रांची, झारखंड में मानव-हाथी संघर्ष को कम करने के लिए 74वें वन महोत्सव के अवसर पर झारखंड हाथी ट्रैकर, एक मोबाइल एप्लिकेशन-आधारित हाथी आंदोलन ट्रैकिंग प्रणाली लॉन्च की।
मोबाइल ऐप ग्रामीणों और विभागों को हाथियों की गतिविधियों पर नज़र रखने में मदद करेगा ताकि पहले से एहतियाती कदम उठाए जा सकें।

झारखंड हाथी ट्रैकर के बारे में:

ऐप का उपयोग करके ग्रामीण हाथी या झुंड का सटीक स्थान देख सकते हैं।

हाथियों के स्थानों को वन विभाग के फील्ड स्टाफ द्वारा अपने आंतरिक डेटाबेस का उपयोग करके खिलाया जाएगा।
यह ऐप पुलिस और जिला प्रशासनिक अधिकारियों को हाथियों की आवाजाही पर नज़र रखने में भी मदद करेगा।
वन रिकॉर्ड के अनुसार, झारखंड में प्रति वर्ष मानव-हाथी संघर्ष में औसतन 80 लोगों की मौत हो जाती है, जबकि 150 लोग घायल होते हैं।
उन्होंने शिकायत दर्ज करने के लिए राज्य वन विभाग के एक टोल-फ्री नंबर 18008892633 का भी उल्लेख किया।

झारखंड के बारे में:

राज्यपाल: सीपी राधाकृष्णन
मुख्यमंत्री: हेमन्त सोरेन
राजधानी: रांची
टाइगर रिजर्व: पलामू टाइगर रिजर्व
वन्यजीव अभयारण्य: दलमा वन्यजीव अभयारण्य, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य, उधवा झील पक्षी वन्यजीव अभयारण्य

तमिलनाडु में 4,000 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा बिजली परियोजना बनाई जा रही है

केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत मंत्री ने बताया है कि हरित ऊर्जा गलियारा चरण-2 के तहत तमिलनाडु राज्य में लगभग 4000 मेगावाट क्षमता की नवीकरणीय ऊर्जा ऊर्जा की निकासी के लिए वित् त वर्ष 2025-26 तक 624 किलोमीटर पारेषण लाइनें और 2200 मेगावाट क्षमता के सबस्टेशन स्थापित करने की परियोजना को मंजूरी दी गई है।
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा परियोजना लागत के 33% पर 237.52 करोड़ रुपये के केंद्र सरकार के अनुदान के साथ 719.76 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर परियोजना को मंजूरी दी गई है।
यह परियोजना राज्य एजेंसी तमिलनाडु ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (TANTRANSCO) द्वारा कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है।
ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण-1 के तहत, टैनट्रांस्को ने 31 अक्टूबर, 2022 को 1068 सीकेएम ट्रांसमिशन लाइनों और 1910 एमवीए क्षमता के सबस्टेशनों की स्थापना के लिए स्वीकृत परियोजना के पूरा होने की सूचना दी, जिसके लिए मंत्रालय ने पहले ही टैनट्रांस्को को 524.30 करोड़ रुपये का अनुदान जारी कर दिया है।
यह जानकारी केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा मंत्री श्री आरके सिंह ने आज, 1 अगस्त, 2023 को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी है।

नवीनतम समाचार

तमिलनाडु का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात वित्त वर्ष 2023 में लगभग तीन गुना बढ़कर 5.37 अरब डॉलर हो गया, जो पिछले वर्ष 1.86 अरब डॉलर था।
तमिलनाडु (TN) सरकार ने वरिष्ठ नौकरशाह शिव दास मीना को TN का अगला मुख्य सचिव नियुक्त किया है।
तमिलनाडु बास्केटबॉल एसोसिएशन (TNBA) के अध्यक्ष, आधव अर्जुन को नई दिल्ली के नेहरू स्टेडियम में हुए चुनाव में बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया (BFI) के अध्यक्ष के रूप में चुना गया।

तमिलनाडु के बारे में

मुख्यमंत्री: एमके स्टालिन
राजधानी: चेन्नई
राज्यपाल: आरएन रवि
एनपी: गिंडी राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान (अन्नामलाई), और मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान।

भारत पहली बार विश्व कॉफी सम्मेलन की मेजबानी करेगा, आयोजन बेंगलुरु में होगा

भारत पहली बार विश्व कॉफी सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जिसका पांचवां संस्करण अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन द्वारा प्रचारित है, जो 25 सितंबर से 28 सितंबर तक बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा।

ICO प्राथमिक अंतरसरकारी संगठन है जो कॉफी व्यापार को बढ़ावा देने और कॉफी उत्पादक और उपभोग करने वाले देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है।

WCC 2023 के पूर्वावलोकन समारोह में जहां इसके लोगो का अनावरण किया गया, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया के CEO और सचिव केजी जगदीश ने घोषणा की कि टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना इस आयोजन के ब्रांड एंबेसडर होंगे।

ICO इस कार्यक्रम का आयोजन कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया के सहयोग से कर रहा है।

वैश्विक मंच पर भारत की कॉफ़ी को बढ़ावा देकर, यह आयोजन इन किसानों के लिए नए अवसर और बाज़ार तैयार करेगा"।

'सर्कुलर अर्थव्यवस्था और पुनर्योजी कृषि के माध्यम से स्थिरता' केंद्रीय विषय है इस आयोजन के लिए, कार्यक्रमों के बीच सम्मेलनों, प्रदर्शनियों, कौशल-निर्माण कार्यशालाओं, सीईओ और वैश्विक नेताओं के मंच और एक उत्पादक सम्मेलन की विशेषता होगी।

WCC 2023 में 80 से अधिक देशों के उत्पादकों, क्यूरर्स, रोस्टर्स, निर्यातकों, नीति निर्माताओं और शोधकर्ताओं के भाग लेने की उम्मीद है।

WCC के पिछले संस्करण इंग्लैंड (2001), ब्राज़ील (2005), ग्वाटेमाला (2010) और इथियोपिया (2016) में आयोजित किए गए थे।

उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने राज्य को जल पर्यटन, साहसिक खेल गंतव्य बनाने की नीति को मंजूरी दी

उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य को "जल पर्यटन और साहसिक खेल गंतव्य" के रूप में बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नीति को मंजूरी दी।

राज्य को "जल पर्यटन और साहसिक खेल गंतव्य" के रूप में बढ़ावा देने की नीति को हाल ही में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है।

सरकार द्वारा हमें तिथि सूचित करने के बाद, यह नीति दस वर्षों तक प्रभावी रहेगी।

अपने समृद्ध सांस्कृतिक अतीत, विविध भूगोल और विविधता के कारण उत्तर प्रदेश में जल-आधारित पर्यटन और साहसिक खेलों के प्रमुख केंद्र के रूप में महत्वपूर्ण रूप से विकसित होने की क्षमता है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 अगस्त को सरकार द्वारा घोषित तारीख से 10 साल की वैधता अवधि के साथ जल पर्यटन और साहसिक खेलों पर एक नीति को अधिकृत किया।

सभी अंतर्देशीय भूमि-आधारित, वायु-आधारित, और जल मार्ग, बांध, जलाशय, झीलें, नदियाँ और तालाब, साथ ही उत्तर प्रदेश के प्राधिकरण के भीतर विभिन्न जल निकायों और भूमि पार्सल पर आयोजित की जाने वाली सभी साहसिक गतिविधियाँ, जल पर्यटन और साहसिक नीति के अधीन होंगी।

संभागीय स्तर पर नोडल एजेंसी साहसिक खेल इकाइयां स्थापित करेगी।

यूपी सरकार की जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति एक सहायक आर्थिक वातावरण को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी पर केंद्रित होगी।

जल पर्यटन और साहसिक खेल उद्यम बनाने में रुचि रखने वाले निजी निवेशकों को सरकार से प्रोत्साहन और समर्थन प्राप्त होगा।
राज्य को एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाने की दिशा में नीति का कार्यान्वयन एक महत्वपूर्ण कदम है।
इस पहल से अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने, रोजगार सृजित करने और साहसिक पर्यटन के लिए उत्तर प्रदेश की छिपी क्षमता को उजागर करने की उम्मीद है।

नवीनतम समाचार

केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स (KIUG) 2022 का लोगो, जर्सी, शुभंकर, मशाल और गान लॉन्च किया।
उत्तर प्रदेश (UP) पहला राज्य बन गया है जो बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाएगा।
उत्तर प्रदेश (यूपी) सरकार ने तीन महिला स्वामित्व वाली दूध उत्पादक कंपनियों - सामर्थ्य मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी (रायबरेली) के प्रबंधन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी NDDB डेयरी सर्विसेज को शामिल किया है। यूपी में श्री बाबा गोरखनाथ कृपा मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी (गोरखपुर) और सृजनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी (बरेली) की स्थापना की गई।

यूपी के बारे में:

राज्यपाल: आनंदीबेन पटेल
मुख्यमंत्री: योगी आदित्यनाथ
राजधानी: लखनऊ
राष्ट्रीय उद्यान: दुधवा राष्ट्रीय उद्यान
वन्यजीव अभयारण्य: बखिरा वन्यजीव अभयारण्य, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य

अमेज़न इंडिया डल झील में पहला फ्लोटिंग स्टोर खोलेगा

कश्मीर के श्रीनगर में, अमेज़ॅन इंडिया ने डल झील पर अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर खोला।
यह कार्यक्रम अमेज़ॅन इंडिया के ग्राहकों को भरोसेमंद और व्यावहारिक डिलीवरी सेवाएं प्रदान करने के लक्ष्य के अनुरूप है, साथ ही छोटी कंपनियों को आकर्षक कमाई के अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है।
व्यवसाय का 'आई हैव स्पेस' डिलीवरी कार्यक्रम, जो 2015 में शुरू हुआ, उसमें स्टोर भी शामिल है।
स्थानीय व्यवसायों और भागीदारों के माध्यम से, यह पहल उन्हें दूर-दराज के स्थानों में ग्राहकों को पैकेज भेजने में सक्षम बनाती है।
"आई हैव स्पेस" स्टोर उन कई लोगों के लिए एक आवश्यक संसाधन है जो श्रीनगर की डल झील और निगीन झील के क्षेत्रों में रहते हैं और काम करते हैं।, जो आगंतुकों और स्थानीय लोगों दोनों के लिए लोकप्रिय गंतव्य हैं।
अमेज़ॅन इंडिया की "आई हैव स्पेस" लास्ट-माइल डिलीवरी पहल प्रत्येक स्टोर के 2 से 4 किलोमीटर के दायरे में प्रभावी ढंग से सामान पहुंचाने के लिए पड़ोस के खुदरा विक्रेताओं और कंपनी मालिकों के साथ काम करती है, जिससे उन्हें अतिरिक्त पैसे कमाने का मौका मिलता है।
2015 में लॉन्च होने के बाद से, इस कार्यक्रम ने पूरे भारत में लगभग 420 कस्बों और शहरों का एक विस्तृत नेटवर्क तैयार किया है, जिसमें कुल मिलाकर 28,000 से अधिक पड़ोस और किराना भागीदार हैं।

नवीनतम समाचार

अमेज़ॅन वेब सर्विसेज (AWS) ने 2030 तक भारत में क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में 12.7 बिलियन डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है।
भुगतान सेवा प्रदाता पेयू ने अमेज़ॅन वेब सर्विसेज (AWS) इंडिया, एक क्लाउड प्लेटफॉर्म और उद्यम पूंजी फर्म चिराटे वेंचर्स के सहयोग से शुरुआती चरण के भारतीय स्टार्टअप के लिए 45-दिवसीय फिनटेक एक्सेलेरेटर प्रोग्राम, इनफिनिटी लॉन्च किया है।
जम्मू-कश्मीर में भारत के पहले लिथियम भंडार की खोज के महीनों बाद, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) ने राजस्थान के नागौर जिले के डेगाना में महत्वपूर्ण खनिज का एक और भंडार पाया है।

जम्मू-कश्मीर के बारे में:

उपराज्यपाल: मनोज सिन्हा
राजधानी: श्रीनगर, जम्मू
राष्ट्रीय उद्यान: किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड राष्ट्रीय उद्यान, काजीनाग राष्ट्रीय उद्यान, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान
वन्यजीव अभयारण्य: रामनगर वन्यजीव अभयारण्य, गुलमर्ग वन्यजीव अभयारण्य

गोवा के आम और बेबिन्का, राजस्थान और यूपी के शिल्प के लिए GI टैग

चेन्नई में भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा राजस्थान के चार उत्पादों सहित पूरे भारत के सात उत्पादों को भौगोलिक संकेत (GI) टैग दिया गया था।
GI टैग 'जलेसर धातु शिल्प' (एक धातु शिल्प), 'गोवा मनकुरद आम', 'गोवा बेबिंका', 'उदयपुर कोफ्टगारी धातु शिल्प', 'बीकानेर काशीदकारी शिल्प', 'जोधपुर बंधेज शिल्प' और 'बीकानेर उस्ता कला शिल्प' द्वारा सुरक्षित किया गया था।
मानक उड़द आम के लिए आवेदन ऑल-गोवा मैंगो ग्रोअर्स एसोसिएशन, पणजी द्वारा दायर किया गया था।
आम की इस किस्म को मैल्कोराडा, कार्डोज़ो मांकुराड, कोराडो और गोवा मांकुर के नाम से भी जाना जाता है।
पुर्तगालियों ने इस फल का नाम मालकोराडा रखा, जिसका अर्थ है 'खराब रंग', और समय के साथ, यह कोंकणी में मंक उड़द आम (आम) बन गया।
गोवा बेबिंका के लिए आवेदन ऑल-गोवा बेकर्स एंड कन्फेक्शनर्स एसोसिएशन द्वारा दायर किया गया था।
बेबिंका, जिसे 'गोवा डेसर्ट की रानी' के रूप में भी जाना जाता है, एक पारंपरिक इंडो-पुर्तगाली हलवा है।

GI टैग के बारे में:

GI, एक प्रकार का बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR), मुख्य रूप से एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने वाला कृषि, प्राकृतिक या निर्मित उत्पाद (हस्तशिल्प और औद्योगिक सामान) है।
यह टैग 10 वर्ष की अवधि के लिए वैध होता है जिसके बाद इसे नवीनीकृत किया जाता है।
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की एक शाखा जो निवेश और बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) से संबंधित है, ने GI को बढ़ावा देने के लिए पहल करने के लिए वित्तीय सहायता के लिए परिचालन दिशानिर्देश जारी किए हैं।

राजस्थान के बारे में:

राज्यपाल: कलराज मिश्र
मुख्यमंत्री: अशोक गहलोत
राजधानी: जयपुर
राष्ट्रीय उद्यान: केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान

वन्यजीव अभयारण्य: बस्सी वन्यजीव अभयारण्य, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य

नवीनतम समाचार

कांगड़ा चाय हिमाचल प्रदेश (HP) संरक्षित भौगोलिक संकेत (GI) के रूप में यूरोपीय संघ (EU) के साथ पंजीकृत होने वाला देश में बासमती चावल के बाद दूसरा उत्पाद बन गया है, जिससे यूरोपीय देशों में उत्पाद की बिक्री का मार्ग प्रशस्त हो गया है। GI टैग वाले राज्यों में तमिलनाडु (TN) के पास देश में सबसे अधिक GI टैग हैं, इसके बाद उत्तर प्रदेश (UP) का स्थान है।

एलोन मस्क की टेस्ला ने पहले भारत कार्यालय के लिए पुणे में जगह लीज पर ली

एलन मस्क की टेस्ला ने पुणे में पांच साल की अवधि के लिए कार्यालय स्थान पट्टे पर लिया है।

11.65 लाख रुपये के मासिक किराए के साथ, लीज डील में 36 महीने की लॉक-इन अवधि शामिल है, जिसमें 5 प्रतिशत प्रति वर्ष वृद्धि खंड शामिल है।

अमेरिका में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और एलोन मस्क के बीच एक बैठक के महीनों बाद, टेस्ला इंडिया मोटर्स और एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने महाराष्ट्र के पुणे के पंचशील बिजनेस पार्क में कार्यालय स्थान पट्टे पर लिया।

इसे ईवी दिग्गज टेस्ला के भारतीय बाजार में प्रवेश की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है।

CRE मैट्रिक्स ने कहा कि टेस्ला इंडिया मोटर्स एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने टेबलस्पेस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ पांच साल का लीज समझौता भी किया है, जिसमें मासिक किराया 11.65 लाख रुपये और पांच साल के लिए 34.95 लाख रुपये की सुरक्षा जमा राशि होगी।

समझौते में पांच कार पार्क और 10 बाइक पार्क भी शामिल हैं।

CRE मैट्रिक्स के अनुसार, लीज डील में 36 महीने की लॉक-इन अवधि शामिल है, जिसमें 5 प्रतिशत प्रति वर्ष वृद्धि खंड शामिल है।

किराये का भुगतान 1 अक्टूबर 2023 से शुरू होगा।

इससे पहले 2021 में, टेस्ला इंडिया मोटर एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को बेंगलुरु में टेस्ला की भारतीय सहायक कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया था

भारत में टेस्ला की प्रगति

जुलाई में, टेस्ला ने सालाना 500,000 ईवी का उत्पादन करने की योजना का संकेत दिया, जिसकी कीमतें 20 लाख रुपये से शुरू होंगी। यदि पूरा हो गया, तो यह विकास भारत के उभरते ईवी बाजार को काफी बढ़ावा दे सकता है।

यदि पूरा हो गया, तो यह विकास भारत के उभरते ईवी बाजार को काफी बढ़ावा दे सकता है।

इससे पहले मई में, इलेक्ट्रिक कार निर्माता टेस्ला ने घरेलू बिक्री और निर्यात के लिए अपने इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण के लिए भारत में एक कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव रखा था।

नवीनतम समाचार

ट्विटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) एलन मस्क ने घोषणा की कि लिंडा याकारिनो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की अगली CEO होंगी।

एलोन मस्क के स्वामित्व वाली स्पेसएक्स की स्टारशिप, दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट, टेक्सास में बोका चिका से अंतरिक्ष के लिए अपनी पहली परीक्षण उड़ान के दौरान विस्फोट हो गया।

ट्विटर के मालिक एलोन मस्क ने एक व्यापक रीब्रांडिंग प्रयास के हिस्से के रूप में सोशल मीडिया सेवा के प्रसिद्ध ब्लू बर्ड को बदलने के लिए एक नया लोगो - एकल अक्षर "X" लॉन्च किया है।

आदि पेरुक्कू, एक सांस्कृतिक त्योहार, तमिलनाडु में मनाया जाता है

आदि पेरुक्कू, जिसे पाथिनेट्टम पेरुक्कू के नाम से भी जाना जाता है, मानसून के मौसम और मिट्टी की उर्वरता का सम्मान करने वाला एक त्योहार है जिसे तमिल सांस्कृतिक समुदाय द्वारा मनाया जाता है।

3 अगस्त को, जो तमिल महीने आदि का 18वां दिन भी होता है, आदि पेरुक्कु मनाया जाता है।

यह त्योहार, जो परंपरागत रूप से जुलाई के अंत या अगस्त की शुरुआत में आयोजित किया जाता है, जल स्रोतों के प्रति आभार व्यक्त करने पर केंद्रित है क्योंकि आदि का पूरा महीना मानसून के मौसम की शुरुआत का संकेत माना जाता है।

तमिलनाडु के बारे में

मुख्यमंत्री: एमके स्टालिन

राजधानी: चेन्नई

राज्यपाल: आरएन रवि

एनपी: गिंडी राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान (अन्नामलाई), और मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान।

निर्मला सीतारमण ने तमिलनाडु के आदिचनल्लूर पुरातात्विक स्थल पर 'प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय' की आधारशिला रखी

केंद्रीय वित्त मंत्री टी.एम.टी. निर्मला सीतारमण ने तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में स्थित एक प्राचीन और ऐतिहासिक लौह युग के दफन स्थल आदिचनल्लूर का दौरा किया, जो तमिराबरानी (पोरुनई) नदी के किनारे स्थित है और आदिचनल्लूर स्थल पर 'प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय' की आधारशिला भी रखी।

यह पुरातात्विक स्थल केंद्रीय बजट 2020-21 में 'प्रतिष्ठित स्थलों' के रूप में विकसित किए जाने के लिए घोषित पांच में से एक था।

विशिष्ट अतिथियों में टीएमटी कनिमोझी करुणानिधि, संसद सदस्य, थूथुकुडी निर्वाचन क्षेत्र; तिरु अनिता राधाकृष्णन, मत्स्य-मछुआरा कल्याण और पशुपालन मंत्री - तमिलनाडु सरकार; थूथुकुडी के जिला कलेक्टर डॉ. के. सेंथिल राज और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के महानिदेशक थिरु केके बाशा, निदेशक (पुरातत्व) ASI डॉ. टी. अरुण राज ने भाग लिया।

तमिलनाडु के बारे में:

राज्यपाल: आरएन रवि

मुख्यमंत्री: एमके स्टालीएन

राजधानी: चेन्नई

नृत्य: भरतनाट्यम, करकट्टम

राष्ट्रीय उद्यान: मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान, गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान

वन्यजीव अभयारण्य: कलाकाड वन्यजीव अभयारण्य, कारिकिली पक्षी अभयारण्य, वेदांथंगल पक्षी अभयारण्य

टाइगर रिजर्व: अनामलाई टाइगर रिजर्व

बायोस्फीयर रिजर्व: अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व

नवीनतम समाचार

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त मंत्रालय के सचिवों और कॉर्पोरेट मामलों के सचिव के साथ बजट योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST परिषद की 50वीं बैठक नई दिल्ली में चल रही है।

श्री अमित शाह पुणे में सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज (CRCS) कार्यालय का डिजिटल पोर्टल लॉन्च करेंगे

केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह पुणे में सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार (CRCS) कार्यालय का डिजिटल पोर्टल लॉन्च करेंगे।
प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के "सहकार से समृद्धि" के दृष्टिकोण में दृढ़ विश्वास दिखाते हुए, सहकारिता मंत्रालय ने देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए कई पहल की हैं।
इस दिशा में, सहकारी क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार के कार्यालय को कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है।
नया पोर्टल MSCS अधिनियम, 2002 और इसके नियमों में हाल ही में पारित संशोधनों को भी शामिल करेगा।
पोर्टल में इलेक्ट्रॉनिक वर्कफ़्लो के माध्यम से समयबद्ध तरीके से अनुप्रयोगों/सेवा अनुरोधों का प्रसंस्करण होगा।
इसमें OTP-आधारित उपयोगकर्ता पंजीकरण, MSCS अधिनियम और नियमों के अनुपालन के लिए सत्यापन जांच, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई, पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करना और इलेक्ट्रॉनिक संचार के प्रावधान भी होंगे।
कम्प्यूटरीकरण की यह परियोजना नये MSCS के पंजीकरण में मददगार साबित होगी और उनके कामकाज को आसान बनाएगी।
केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय के कम्प्यूटरीकरण के मुख्य उद्देश्य हैं:
पूरी तरह से कागज रहित आवेदन और प्रसंस्करण
सॉफ्टवेयर के माध्यम से बहु-राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम (MSCS अधिनियम) और नियमों का स्वचालित अनुपालन
व्यवसाय करने में आसानी बढ़ाना
अंकीय संचार
पारदर्शी प्रसंस्करण
बेहतर एनालिटिक्स और एमआईएस (प्रबंधन सूचना प्रणाली)

महाराष्ट्र के बारे में

राज्यपाल: रमेश बाई
मुख्यमंत्री: एकनाथ शिंदे
राजधानी: मुंबई
राष्ट्रीय उद्यान: ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान
वन्यजीव अभयारण्य: भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य, करनाला पक्षी अभयारण्य, नागज़ीरा वन्यजीव अभयारण्य
यूनेस्को विरासत स्थल: छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई का विक्टोरियन और आर्ट डेको पहनावा, अजंता गुफाएं, एलीफेंटा गुफाएं, एलोरा गुफाएं

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने असम के कोकराझार में 132वें डूरंड कप का उद्घाटन किया

डूरंड कप का 132वां संस्करण असम के कोकराझार में शुरू हुआ, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने उद्घाटन समारोह की शोभा बढ़ाई, जिसने असमिया शहर में पहली बार वार्षिक फुटबॉल प्रतियोगिता की भव्य शुरुआत की।
टूर्नामेंट सशस्त्र बलों द्वारा आयोजित किया जाता है और असम सरकार द्वारा समर्थित है।

साई स्टेडियम में उत्साही भीड़ को संबोधित करते हुए, रक्षा मंत्री ने कोकराझार में सकारात्मक माहौल बनाने के लिए सशस्त्र बलों और बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद (BTC) के प्रयासों की सराहना की, जिसके परिणामस्वरूप शहर में पहली बार यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। उन्होंने फुटबॉल के प्रति उत्साह और प्रेम के लिए पूर्वोत्तर के लोगों की सराहना की और 'खूबसूरत खेल' को सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि एक भावना करार दिया।

उद्घाटन समारोह के बाद बोडोलैंड एफसी और राजस्थान यूनाइटेड एफसी के बीच टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच हुआ।

कोकराझार में आठ ग्रुप मैच और एक क्वार्टर फाइनल 24 अगस्त 2023 को खेला जाएगा।

टूर्नामेंट के दौरान नेपाल और बांग्लादेश की दो विदेशी टीमों, भारतीय सशस्त्र बलों की सभी तीन टीमों और बोडोलैंड एफसी की स्थानीय टीम सहित कुल 24 टीमें कोलकाता, गुवाहाटी और कोकराझार में तीन स्थानों पर भिड़ेंगी।

असम के बारे में:

राज्यपाल: गुलाब चंद कटारिया

मुख्यमंत्री: हिमंत बिस्वा सरमा

राजधानी: गुवाहाटी

राष्ट्रीय उद्यान: काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान

वन्यजीव अभयारण्य: गरमपानी वन्यजीव अभयारण्य, लाओखोवा वन्यजीव अभयारण्य, बोर्नाडी वन्यजीव अभयारण्य

नवीनतम समाचार

असम सरकार ने 2 अक्टूबर, 2023 से एक लीटर से कम की पैकेज्ड पीने के पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने नगांव बाईपास-तेलियागांव और तेलियागांव-रंगागरा के बीच 4-लेन खंड का उद्घाटन किया और मंगलदाई बाईपास और असम में दाबोका-परखुवा के बीच 4-लेन खंड की नींव रखी।

असम में मवेशियों के अवैध परिवहन को रोकने के लिए, असम सरकार के पशुपालन और पशु चिकित्सा विभाग ने मवेशी परिवहन के लिए एक वेब पोर्टल का उद्घाटन किया।

जी-20 सदस्य देशों को समर्पित विशेष कला प्रदर्शनी बिहार में शुरू होगी

बिहार में G-20 सदस्य देशों को समर्पित एक विशेष कला प्रदर्शनी बिहार संग्रहालय, पटना में शुरू होगा।

दो महीने तक चलने वाली इस प्रदर्शनी का शीर्षक टुगेदर वी आर्ट है और इसका समापन 7 अक्टूबर 2023 को होगा।

बिहार संग्रहालय के महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह ने कहा कि प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे.

महानिदेशक ने कहा कि जी-20 देशों की भारत की अध्यक्षता के हिस्से के रूप में केंद्रीय कला और संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रदर्शनी में भारत सहित 29 देश भाग ले रहे हैं।

श्री सिंह ने कहा कि स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में पांच महीने तक चलने वाला बिहार संग्रहालय बिनाले 2023 भी शुरू होगा

महाराष्ट्र में 126 स्टेशनों को विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशनों के रूप में विकसित किया जाएगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देशभर में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 24 हजार 470 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी।

मुंबई में, मध्य रेलवे ने परेल, विक्रोली और कांजुरमार्ग स्टेशनों पर कार्यक्रम आयोजित किए।

महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में 126 स्टेशनों को विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशनों के रूप में विकसित करने की योजना है।

Click Here to Subscribe Our Yearly Mock Test Package

उन्होंने कहा कि इनमें से 44 स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी जाएगी।
उन्होंने इस बात पर खुशी जताई कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत मुंबई डिवीजन के 15 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है।
महाराष्ट्र के राज्यपाल ने टिप्पणी की कि भारतीय रेलवे में आमूलचूल परिवर्तन आया है क्योंकि रेल यात्रा बहुत सुखद और आरामदायक हो गई है।

गुजरात सरकार 58 करोड़ रुपये के अनुदान के साथ एक जिला एक उत्पाद (ODOP) योजना लागू करती है

गुजरात सरकार ने अपने स्वदेशी उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए 58 करोड़ रुपये के अनुदान के साथ एक जिला एक उत्पाद (ODOP) योजना लागू की है।
गुजरात राज्य हस्तशिल्प और हस्तशिल्प विकास निगम (GSHHDC) ने इस योजना का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है।
इस पर जानकारी देते हुए GSHHDC के प्रबंध निदेशक ललित नारायण संदू ने कहा, बाजार में इसे बढ़ावा देने के लिए गुजरात में ODOP के तहत सुजानी हैंडलूम, जामनगर के बंधनी और पाटन के पटोला जैसे विशिष्ट उत्पादों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
इस योजना के तहत, राज्य के 21 जिलों से 25 से अधिक हस्तशिल्प उत्पादों और हस्तशिल्प क्षेत्र से उत्पादों का चयन किया गया है, जिनमें गमठी ब्लॉक प्रिंट और माता-नी-पछेड़ी जैसे पारंपरिक हस्तशिल्प शामिल हैं।
ODOP पहल का उद्देश्य देश के सभी जिलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है, जिससे सभी क्षेत्रों में समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास संभव हो सके।
इसका उद्देश्य जिले में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों की पहचान करके विनिर्माण और निर्यात केंद्र में परिवर्तित करने के लिए देश के जिले पर एक इकाई के रूप में ध्यान केंद्रित करना है।

केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने पुणे में सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार का डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया

केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि पारदर्शिता के बिना सहकारी आंदोलन आगे नहीं बढ़ सकता और डिजिटल पोर्टल उस उद्देश्य को पूरा करेगा।
उन्होंने जोर देकर कहा कि डिजिटल पोर्टल सहकारिता आधारित आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने के साथ-साथ देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने में उपयोगी होगा।
श्री शाह सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार के डिजिटल पोर्टल को लॉन्च करने के बाद पुणे में बोल रहे थे
इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस और अजीत पवार, केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा और महाराष्ट्र के सहकारिता मंत्री दिलीप वालसे पाटिल भी उपस्थित थे।

तमिलनाडु में NLCIL द्वारा दिए गए भूमि अधिग्रहण और मुआवजे का विवरण

NLC इंडिया के लिए अपेक्षित भूमि का अधिग्रहण जिला प्रशासन द्वारा अधिग्रहण के समय प्रचलित भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार किया जाता है।
भूमि मालिकों को उचित मुआवजा और अन्य पुनर्वास और पुनर्वास लाभ पूरी तरह से प्रदान किए जाते हैं और आजीविका की रक्षा की जाती है।

वर्तमान में, भूमि का अधिग्रहण "औद्योगिक प्रयोजनों के लिए तमिलनाडु भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1997" के अनुसार किया जाता है, जिसमें पहली अनुसूची में निर्दिष्ट मुआवजे के निर्धारण, दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट पुनर्वास और पुनर्स्थापन और RFCTLARR अधिनियम, 2013 की तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट बुनियादी सुविधाओं से संबंधित प्रावधान हैं।
निरंतर बिजली उत्पादन बनाए रखने के लिए अगले 5 वर्षों के लिए खदान उन्नति के लिए आवश्यक लगभग 1054 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है जो राज्य के विकास में योगदान देगा।
नेवेली क्षेत्र के लिए संशोधित NLCIL की बढ़ी हुई मुआवजा और R&R नीति के अनुसार, जहां भी RFCTLARR की अनुसूची-। के प्रावधान के अनुसार एलएओ द्वारा भूमि मुआवजा प्राप्त किया जाता है, न्यूनतम मुआवजे का भुगतान किया जाता है (गुणन कारक, सोलेटियम और अतिरिक्त बाजार मूल्य सहित) अधिनियम निम्नलिखित से कम है:
कृषि भूमि के लिए, 25 लाख रुपये प्रति एकड़ (एक विशेष जीओ एमएस नंबर 185 दिनांक 25.08.2022 को GoTN द्वारा न्यूनतम भूमि मुआवजा भुगतान 23 लाख रुपये प्रति एकड़ करने के लिए जारी किया गया है और शेष 2 लाख रुपये प्रति एकड़ दिया जा रहा है।
ग्रामीण क्षेत्रों से अर्जित गृह स्थल भूमि के लिए, 40 लाख रुपये प्रति एकड़।
शहरी क्षेत्रों से प्राप्त मकान भूमि के लिए 75 लाख रुपये प्रति एकड़।

राजस्थान में 17 नए जिले और 3 नए संभाग अस्तित्व में आए

17 नये जिले और 3 नये संभाग राजस्थान में अस्तित्व में आये हैं।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नए जिलों और संभागों का उद्घाटन किया
सभी नए जिलों और संभागों में भी उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां प्रभारी मंत्री शामिल हुए
मुख्यमंत्री ने सभी नये जिलों की वेबसाइट भी लॉन्च की
उद्घाटन कार्यक्रम से पहले सभी जिलों में हवन, पूजन और यज्ञ किया गया, कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश ने इतिहास रचा है
उन्होंने कहा कि बढ़ती जनसंख्या के साथ प्रशासनिक व्यवस्था का विकेंद्रीकरण जरूरी है
उन्होंने कहा कि ये नए जिले राज्य के विकास को नई गति देंगे

भूमि घोटाला मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय ने तलब किया

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित भूमि घोटाला मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तलब किया है।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने मुख्यमंत्री को 14 अगस्त को अपने रांची कार्यालय में उपस्थित होने को कहा है
इससे पहले ईडी ने नवंबर 2022 में मुख्यमंत्री को तलब किया था
एजेंसी ने 18 नवंबर, 2022 को अवैध खनन मामले के संबंध में श्री सोरेन से 10 से अधिक घंटों तक पूछताछ की।
इस बीच इस मामले में निलंबित IAS अधिकारी और रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन समेत कई कारोबारियों को ईडी ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है

BSF के महानिदेशक नितिन अग्रवाल ने जम्मू के सांबा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का दौरा किया

सीमा सुरक्षा बल (BSF) के महानिदेशक, नितिन अग्रवाल जम्मू संभाग के सांबा जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा का दौरा किया।
उन्हें पाकिस्तान से ड्रोन और तस्करी गतिविधियों को विफल करने के लिए सैनिकों की सतर्कता के बारे में जानकारी दी गई।

आकाशवाणी जम्मू संवाददाता ने खबर दी है कि श्री अग्रवाल केन्द्र शासित प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए तीन दिन के दौरे पर सीमा सुरक्षा बल के जम्मू फ्रंटियर मुख्यालय पहुंचे।
BSF प्रमुख को BSF जम्मू फ्रंटियर के महानिरीक्षक द्वारा अंतरराष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा (LOC) पर सीमा सुरक्षा और प्रभुत्व के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल करते हुए एक विस्तृत प्रस्तुति दी गई।

हरियाणा सरकार ने नूंह जिले में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं का अस्थायी निलंबन बढ़ाया:

हरियाणा सरकार ने नूंह जिले में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं के अस्थायी निलंबन को 11 अगस्त तक बढ़ा दिया है।
एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि मोबाइल फोन और SMS पर व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर आदि जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से गलत सूचना और अफवाहों के प्रसार को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।
हरियाणा के सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है और उपरोक्त आदेश के उल्लंघन का दोषी पाया गया कोई भी व्यक्ति संबंधित प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

हरियाणा सरकार 6,134 करोड़ रुपये में बांध बनाने की योजना बना रही है

हरियाणा सरकार 6,134 करोड़ रुपये में बांध बनाने की योजना बना रही है
इसमें 14 किलोमीटर लंबा जलाशय होगा और इसे यमुनानगर जिले में हथिनीकुंड बैराज से 4.5 किलोमीटर ऊपर की ओर बनाया जाएगा।
एक बार परियोजना पूरी हो जाने पर, राज्य को 250 मेगावाट बिजली के उत्पादन के अलावा, सिंचाई जल, भूजल पुनर्भरण और जलीय कृषि की अधिक उपलब्धता होगी।
इसके जलाशय की क्षमता 10.82 लाख क्यूसेक होगी।
इससे दिल्ली और हरियाणा में नदी के आसपास के इलाकों में यमुना के कारण आने वाली बाढ़ को रोकने की संभावना है।
बांध क्षेत्र की सीमा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से भी लगती है।
पिछले महीने मुख्यमंत्री ने बताया था कि पीछे बांध बनाने का प्रस्ताव है
हथिनीकुंड बैराज पर हिमाचल सरकार से विचार किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि इससे अत्यधिक बारिश के कारण आने वाली बाढ़ को रोकने में मदद मिलेगी

राज्य पर्यटन विभाग ने लद्दाख में जागरूकता-सह-स्वच्छता अभियान का आयोजन किया

लद्दाख में, राज्य पर्यटन विभाग रूट्स लद्दाख, ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग (आरडी और पीआरडी), वन्यजीव विभाग, शिक्षा विभाग और स्थानीय महिला स्वयं सहायता समूहों के सहयोग से होलियाल द्रास में मिशन ट्रैवल फॉर लाइफ और मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत जागरूकता-सह-स्वच्छता अभियान का आयोजन कर रहा है।
जागरूकता कार्यक्रम वन्य जीवन, वनों के महत्व और पर्यावरण-अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
जागरूकता कार्यक्रम में ग्रामीणों, स्कूली छात्रों, शिक्षकों, ग्रामीणों, पर्यटन हितधारकों और विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।
गौरतलब है कि द्रास की मुश्को घाटी पर्यटकों और वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य बनती जा रही है।

हालाँकि, यह क्षेत्र मानव-वन्यजीव संघर्ष की गंभीर समस्या का भी सामना कर रहा है।
विभाग द्वारा आयोजित हर घर तिरंगा अभियान के तहत ग्रामीणों को 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।
इसी तरह के कार्यक्रम 15 अगस्त तक अन्य स्थानों पर भी आयोजित किये जायेंगे।

पश्चिम बंगाल को मिलेगा निवेश समुद्री क्षेत्र में 1 ट्रिलियन; शीघ्र ही इसे एक क्षेत्रीय व्यापार केंद्र में परिवर्तित करना

केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग (MOPSW) और आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कोलकाता में आगामी ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट, 2023 (GMIS) के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट (SMPK) द्वारा आयोजित रोड शो में भाग लिया।
रोड शो में शहर में इंडिया इंक के कप्तानों के साथ-साथ शीर्ष अधिकारियों, टेक्नोक्रेट्स के साथ-साथ सामाजिक नेताओं ने भी भाग लिया, जिसका उद्देश्य न्यू में आगामी शिखर सम्मेलन में वैश्विक निवेशकों के साथ "कनेक्ट, सहयोग और निर्माण" के लिए सार्थक भागीदारी को प्रोत्साहित करना था।
निजी क्षेत्र भारत के समुद्री क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने में एक आवश्यक भागीदार है और सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) ने नए बंदरगाहों के विकास और मौजूदा बंदरगाहों में क्षमता बढ़ाने में बहुत योगदान दिया है।
PPP टर्मिनल, जो वर्तमान में प्रमुख बंदरगाहों पर लगभग 50% कार्गो संभाल रहे हैं, आने वाले दशकों में अपनी हिस्सेदारी 100% तक बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं।
पश्चिम बंगाल समुद्री क्षेत्र में ₹1 ट्रिलियन का निवेश प्राप्त करने के लिए तैयार है और यह राज्य को जल्द ही एक समुद्री केंद्र बना देगा।

तेलंगाना सरकार ने 99999 रुपये तक के कृषि ऋण माफी की घोषणा की

तेलंगाना सरकार ने 99 हजार 999 रुपये तक के कृषि ऋण माफ करने की घोषणा की है। इसे अगले 45 दिनों के भीतर साफ कर दिया जाएगा।
सरकार ने इस मद में 5,800 करोड़ रुपये से अधिक जारी किये हैं। इस फैसले से 9 लाख से ज्यादा किसानों को फायदा होगा
यह मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव द्वारा एक लाख रुपये तक के कृषि ऋण माफ करने की चुनावी प्रतिबद्धता को पूरा करेगा।
यह राशि सीधे किसानों के ऋण खातों में स्थानांतरित की जाएगी।
ताजा फैसले से 16 लाख 66 हजार से ज्यादा किसानों के 99,999 यानी 7753.43 करोड़ रुपये तक के कृषि ऋण का भुगतान हो जाएगा
2014 और 2018 के बीच अपने पिछले कार्यकाल के दौरान, बीआर की सरकार ने 16,144 करोड़ रुपये के वितरण के माध्यम से 1 लाख रुपये तक के फसल ऋण माफ कर दिए, जिससे राज्य में 35 लाख से अधिक किसानों को लाभ हुआ।
2018 के विधानसभा चुनावों के दौरान, चंद्रशेखर राव ने चरणबद्ध तरीके से एक लाख रुपये तक के ऋण के लिए फसल ऋण माफी योजना लागू करने का वादा किया था।
एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि कार्यान्वयन में बाहरी कारकों जैसे COVId महामारी और उसके बाद के लॉकडाउन के कारण देरी हुई।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए एक मोबाइल ऐप और व्हाट्सएप हेल्पलाइन लॉन्च की

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए एक मोबाइल ऐप और व्हाट्सएप हेल्पलाइन लॉन्च की।

मुंबई के सह्याद्री गेस्ट हाउस में उन मरीजों के लिए एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जो पुरानी और गंभीर बीमारियों पर सफलतापूर्वक काबू पा चुके हैं।

एक हेल्पलाइन नंबर 8650567567 मरीजों और उनके परिजनों के लिए शुरू किया गया है

सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि पिछले वर्ष 12 हजार 500 से अधिक मरीजों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से लाभ मिला है

इस अवसर पर चिकित्सा सहायता नियमावली के पांचवें संस्करण और बालासाहेब ठाकरे की विचारधारा पर आधारित पुस्तक 'रोखथोक' का विमोचन किया गया।

इस अवसर पर विधान परिषद की उपाध्यक्ष डॉ. नीलम गोरे, कौशल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा और अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

DMRC ने यात्रियों को CO2 उत्सर्जन में कमी के बारे में जागरूक करने के लिए कार्बनलाइट मेट्रो ट्रैवल पहल का अनावरण किया

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने यात्रियों को मेट्रो ट्रेनों का चयन करके कार्बन उत्सर्जन को कम करने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में शिक्षित करने के लिए कार्बनलाइट मेट्रो ट्रैवल नामक एक अग्रणी पहल का अनावरण किया।

कार्बनलाइट मेट्रो यात्रा के बारे में:

यह लोगों को मेट्रो रेल सेवाओं का चयन करके CO2 उत्सर्जन को कम करने में उनके योगदान को समझने में मदद करने के लिए DMRC की एक नई पहल है।

इस पहल के साथ, दैनिक यात्री अब मेट्रो को अपने परिवहन के साधन के रूप में चुनने के अपने सरल कदम से कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) उत्सर्जन की औसत मात्रा को समझने और जानने में सक्षम होंगे।

CO2 की मात्रा की गणना सड़क आधारित मोटर वाहनों की तुलना के आधार पर की जाएगी।

इसका उद्देश्य यात्रियों को मोटर चालित विकल्पों के बजाय परिवहन का पर्यावरण अनुकूल तरीका चुनने के लिए राजी करना है, जिससे स्वच्छ और अधिक पारिस्थितिक रूप से संतुलित वातावरण का समर्थन किया जा सके।

यह पहल भारत सरकार के मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट (LiFE) के अनुरूप है।

इस सुविधा का लाभ कौन उठा सकता है?

QR कोड आधारित टिकट से यात्रा करने वाले लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।

मेट्रो यात्रा के कारण CO2 उत्सर्जन में कमी की जानकारी मोबाइल QR कोड टिकट और भौतिक टिकट दोनों पर प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी।

द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (TERI), दिल्ली द्वारा किए गए व्यापक शोध द्वारा समर्थित, यह पहल इस बात को रेखांकित करती है कि सड़क वाहनों के बजाय मेट्रो ट्रेन द्वारा यात्रा की गई प्रत्येक किलोमीटर के परिणामस्वरूप 32.38 ग्राम CO2 उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आती है।

DMRC के बारे में:

स्थापित: 3 मई 1995

मुख्यालय: नई दिल्ली, दिल्ली, भारत
अध्यक्ष: मनोज जोशी
प्रबंध निदेशक: विकास कुमार
DMRC एक केंद्र-राज्य संयुक्त उद्यम है जो दिल्ली मेट्रो और नोएडा मेट्रो का संचालन करता है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यूथ 20 समिट का उद्घाटन किया

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने संयुक्त रूप से वाराणसी के रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कन्वेंशन सेंटर में यूथ 20 शिखर सम्मेलन -2023 का उद्घाटन किया।
उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित चार दिवसीय Y20 शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन।
यूथ 20 (Y20) शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत के G20 प्रेसीडेंसी के ढांचे के तहत युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा किया गया है।
Y20 शिखर सम्मेलन गुवाहाटी में स्थापना बैठक, लेह, लद्दाख में पूर्व शिखर सम्मेलन और इस मुख्य शिखर सम्मेलन से पहले देश भर में आयोजित विभिन्न जन भागीदारी कार्यक्रमों सहित विभिन्न बैठकों का समापन है।
चार दिवसीय शिखर सम्मेलन में G20 देशों, अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लगभग 125 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।
केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि Y20 शिखर सम्मेलन विभिन्न देशों के युवाओं को एक साथ लाता है, जो अद्वितीय आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय समस्याओं और चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और वे किसी एक देश तक सीमित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि यह चुनौतियों से निपटने के लिए समाधान खोजने के लिए मिलकर काम करने का मंच प्रदान करता है।

प्रधानमंत्री ने कैंब्रिज लेआउट, बेंगलुरु में भारत के पहले 3डी मुद्रित डाकघर की सराहना की

प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कैंब्रिज लेआउट, बेंगलुरु में भारत के पहले 3डी मुद्रित डाकघर को हमारे देश के नवाचार और प्रगति का एक प्रमाण कहा है।
इससे पहले केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 3डी प्रिंटिंग तकनीक से निर्मित भारत के पहले डाकघर का उद्घाटन किया।
1100 वर्ग फुट के डाकघर का उद्घाटन बेंगलुरु के उल्सूर बाजार के पास कैम्ब्रिज लेआउट में आयोजित किया गया था।
3डी प्रिंटिंग तकनीक संरचनाओं के निर्माण का एक तेजी से उभरता हुआ तरीका है।
यह लेयरिंग विधि के माध्यम से त्रि-आयामी वस्तुओं को बनाने के लिए कंप्यूटर-सहायता प्राप्त डिज़ाइन का उपयोग करता है।
लगभग एक साल पहले, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), गुवाहाटी ने एक स्वदेशी अनुसंधान और विकास कार्यक्रम के हिस्से के रूप में भारतीय सेना के लिए एक 3डी-मुद्रित संतरी पोस्ट का निर्माण किया था।

NLC इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के साथ 300 मेगावाट सौर परियोजना के लिए दीर्घकालिक बिजली उपयोग समझौता किया है

कोयला मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम NLC इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान में CPSU योजना के तहत 300 मेगावाट सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के साथ दीर्घकालिक विद्युत उपयोग समझौता किया है।
NLCIL के पास वर्तमान में 1,421 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है
कंपनी की कॉर्पोरेट योजना के अनुसार, वह 2030 तक 6,031 मेगावाट क्षमता स्थापित करने पर विचार कर रही है।

कंपनी ने प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (IREDA) द्वारा शुरू की गई CPSU योजना चरण- II ट्रेंच- III में 510 मेगावाट सौर परियोजना क्षमता हासिल की है। राजस्थान के बीकानेर जिले के बरसिंगसर में 300 मेगावाट की सौर परियोजना क्षमता का कार्यान्वयन चल रहा है।
परियोजना के लिए EPC अनुबंध प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से मेसर्स टाटा पावर सोलर सिस्टम को प्रदान किया गया है।
परियोजना से प्रतिवर्ष 750 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया जाएगा और उत्पादित कुल हरित बिजली राजस्थान राज्य को आपूर्ति की जाएगी।
यह परियोजना राजस्थान राज्य को अपने नवीकरणीय खरीद दायित्व लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेगी।
परियोजना से उत्पन्न बिजली से हर साल 0.726 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलेगी।
नवीकरणीय ऊर्जा के मोर्चे पर, तमिलनाडु में वर्तमान 1.40 गीगावॉट क्षमता के अलावा, यह पहली बार है कि NLCIL अन्य राज्यों में इस क्षमता का विस्तार कर रहा है।

श्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में CRPF ग्रुप सेंटर में गृह मंत्रालय के अखिल भारतीय वृक्षारोपण अभियान के तहत 4 करोड़वां पेड़ लगाया

केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में CRPF ग्रुप सेंटर में गृह मंत्रालय के अखिल भारतीय वृक्षारोपण अभियान के तहत 4 करोड़वां पौधारोपण किया।
श्री अमित शाह ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के 8 विभिन्न परिसरों में 165 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 15 नवनिर्मित भवनों का भी उद्घाटन किया।
इनमें 102 रैपिड टास्क फोर्स में 220 पारिवारिक आवासों का निर्माण शामिल है। 57 करोड़ रूपये से ग्रुप सेंटर रायपुर में 50 बिस्तरीय अस्पताल का निर्माण। 17 करोड़ रुपये में रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर जोधपुर में प्रशासनिक भवन, क्वार्टर गार्ड और परेड ग्राउंड। ग्रुप सेंटर रायपुर में 240 पुरूष बैरक का निर्माण 16 करोड़ रूपये से निर्मित। 11 करोड़ रुपये, और देश के विभिन्न हिस्सों में अस्पतालों, जिम, मेस, सीवेज उपचार संयंत्र, कैंटीन आदि का निर्माण। इस अवसर पर केंद्रीय गृह सचिव और CRPF, CISF, NSG, NDRF, ITBP, SSB, BSF और असम राइफल्स के महानिदेशकों सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

श्री सर्बानंद सोनोवाल समुद्री राज्य की दो दिवसीय 19वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे

केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल 18 और 19 अगस्त को गुजरात के केवडिया में होने वाली समुद्री राज्य विकास परिषद (MSDC) की 19वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
इस दौरान समुद्री क्षेत्र की समग्र प्रगति से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा केंद्रित होगी।
बैठक में मुख्यमंत्री, तटीय राज्यों के संबंधित वरिष्ठ मंत्री और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासक भाग लेंगे।
केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सभी 9 तटीय राज्यों और 4 केंद्रशासित प्रदेशों के संबंधित सचिव और वरिष्ठ अधिकारी भी वहां उपस्थित रहेंगे।
समुद्री राज्य विकास परिषद (MSDC) का गठन वर्ष 1997 में किया गया था और यह समुद्री क्षेत्र के विकास के लिए एक शीर्ष सलाहकार निकाय है, जिसका उद्देश्य राज्य सरकारों के परामर्श से प्रमुख और गैर-प्रमुख बंदरगाहों के विकास को सुनिश्चित करना है।

Click Here to Subscribe Our Yearly Mock Test Package

MSDC का गठन बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री की अध्यक्षता में किया गया था, जिसमें सभी समुद्री राज्यों के बंदरगाहों के प्रभारी मंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, नौसेना, तटरक्षक बल और सभी संबंधित हितधारकों के प्रतिनिधि शामिल थे।

MSDC समुद्री क्षेत्र के विकास के लिए एक शीर्ष सलाहकार निकाय है और इसका लक्ष्य प्रमुख और गैर-प्रमुख बंदरगाहों का एकीकृत विकास सुनिश्चित करना है। इसका गठन राज्य सरकारों के परामर्श से, संबंधित समुद्री राज्यों द्वारा सीधे या कैप्टिव उपयोगकर्ताओं और निजी भागीदारी के माध्यम से मौजूदा और नए छोटे बंदरगाहों के भविष्य के विकास का आकलन करने के लिए किया गया था।

श्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में 800 करोड़ रुपये की लागत वाले नंदूर से चिखली राष्ट्रीय राजमार्ग 53 खंड का अनावरण किया

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के मलकापुर में 800 करोड़ रुपये की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग 53 पर 45 किलोमीटर लंबे नांदुरा से चिखली खंड के चतुर्भुज का उद्घाटन किया।

परियोजना विवरण:

यह खंड 45 किलोमीटर लंबा है।

परियोजना की लागत रुपये अनुमानित है। 800 करोड़.

उद्घाटन समारोह महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के मलकापुर में हुआ।

प्रतिभागी:

नितिन गडकरी के अलावा, बुलढाणा के संसद सदस्य (सांसद) श्री प्रतापराव जाधव और सांसद श्री रक्षाताई खडसे उपस्थित थे। कई विधायक और अधिकारी भी उपस्थित थे।

भारतमाला योजना:

यह परियोजना भारतमाला योजना पहल के अंतर्गत आती है।

भारतमाला भारत में एक प्रमुख सड़क और राजमार्ग विकास कार्यक्रम है।

इसका उद्देश्य पूरे देश में सड़क संपर्क में सुधार करना और आर्थिक विकास को बढ़ाना है।

बुनियादी ढांचे की मुख्य विशेषताएं:

इस परियोजना में चार लेन की सड़क का निर्माण शामिल है।

परियोजना के उल्लेखनीय तत्व 6 किमी लंबे नंदुरा ग्रीनफील्ड बाईपास और मलकापुर रेलवे ओवरब्रिज (ROB) हैं।

इस परियोजना में 4 प्रमुख पुल, 18 छोटे पुल, 11 पुलिया, 3 सर्कुलर अंडरपास और 4 पैदल यात्री अंडरपास शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, 11.53 किमी की डबल-लेन सर्विस रोड, 20 बस शेड और 1 ट्रक ले-बाय है।

आर्थिक प्रभाव:

परियोजना के पूरा होने से व्यापार और वाणिज्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।

इससे गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और ओडिशा जैसे राज्यों के बीच व्यापार संबंध बढ़ेंगे।

ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर से कनेक्टिविटी में सुधार होगा, जिससे रायपुर, नागपुर और सूरत जैसे शहरों को फायदा होगा।

केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने NTPC के 660 मेगावाट के सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया

केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री आरके सिंह ने बिहार में बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की 660 मेगावाट की इकाई का उद्घाटन किया।

केंद्रीय मंत्री ने यूनिट #2 को पूरा करने में शामिल इंजीनियरों और श्रमिकों को सम्मानित किया (660MW) बाढ़ परियोजना की।

परियोजना विवरण:

समर्पित इकाई, स्टेज I की यूनिट #2, बड़े बा आरएच सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है।
यह कमीशनिंग देश को विश्वसनीय और सस्ती बिजली प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

विद्युत क्षेत्र में उपलब्धियाँ और परिवर्तन:

सरकार ने पिछले नौ वर्षों में भारत को बिजली की कमी से बिजली अधिशेष वाले देश में बदल दिया है।
राष्ट्र अब एकल आवृत्ति पर संचालित एक एकीकृत ग्रिड के माध्यम से जुड़ा हुआ है।
रुपये से अधिक लागत वाली योजनाओं के साथ वितरण प्रणालियों को बड़े पैमाने पर मजबूत किया गया है। वितरण बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए 2 लाख करोड़ रुपये लागू किए गए।
बिजली की औसत उपलब्धता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 20.5 घंटे और शहरी क्षेत्रों में 23.5 घंटे की औसत बिजली उपलब्धता है।

विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020:

विद्युत मंत्रालय ने विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020 पेश किए हैं।
ये नियम उपभोक्ताओं को नए बिजली कनेक्शन, रिफंड और अन्य सेवाओं का समय पर प्रावधान सुनिश्चित करते हैं।

उपस्थित गणमान्य व्यक्ति एवं अधिकारी:

इस कार्यक्रम में एनटीपीसी के सीएमडी श्री गुरदीप सिंह, पावरग्रिड के सीएमडी श्री के श्रीकांत और बिहार सरकार, एनटीपीसी और संबंधित क्षेत्रों के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

प्रमुख बिंदु:

केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने बिहार में बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की 660 मेगावाट इकाई का उद्घाटन किया।
यह परियोजना विश्वसनीय और किफायती बिजली प्रदान करने में योगदान देती है।
सफल समापन के लिए एनटीपीसी के इंजीनियरों और श्रमिकों की सराहना की जाती है।
सरकार की उपलब्धियों में भारत को बिजली अधिशेष राष्ट्र में बदलना, वितरण प्रणालियों को मजबूत करना और बिजली की उपलब्धता बढ़ाना शामिल है।
विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020, उपभोक्ताओं को समय पर सेवाएं सुनिश्चित करते हैं।
कार्यक्रम के दौरान परियोजना से जुड़े इंजीनियरों और श्रमिकों को सम्मानित किया गया।
उद्घाटन में विभिन्न गणमान्य व्यक्ति और अधिकारी शामिल हुए।

पश्चिम बंगाल, पंजाब, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, हरियाणा, बिहार और राजस्थान के कुछ जिले अभी भी प्रति जिले 75 अमृत सरोवर का लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए हैं

राज्यों ने पश्चिम बंगाल, पंजाब, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, हरियाणा, बिहार और राजस्थान के मामले को छोड़कर राज्य के प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर के जिला स्तरीय लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास किए हैं, जिनमें से कुछ जिलों को अभी भी प्रति जिले 75 अमृत सरोवरों का लक्ष्य हासिल करना बाकी है।

भारतीय राज्यों में अमृत सरोवर पहल:

शामिल राज्य: पश्चिम बंगाल, पंजाब, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, हरियाणा, बिहार और राजस्थान।
उद्देश्य: जल संरक्षण के लिए प्रति जिले 75 अमृत सरोवर (जल निकाय) स्थापित करना।

स्थिति: उल्लिखित राज्यों के कुछ जिले अभी तक 75 अमृत सरोवर लक्ष्य तक नहीं पहुंचे हैं।

प्रगति अद्यतन:

अमृत सरोवरों की संख्या: कुल 1,12,277 अमृत सरोवरों की पहचान की गई।

कार्य आरंभ: 81,425 अमृत सरोवरों का काम शुरू हो गया है।

पूर्ण/पुनर्जीवित: 66,278 अमृत सरोवरों का निर्माण या पुनर्जीवन किया गया है।

मिशन पृष्ठभूमि:

प्रक्षेपण की तारीख: प्रधानमंत्री ने 24 अप्रैल, 2022 को मिशन अमृत सरोवर का शुभारंभ किया।

उद्देश्य: प्रत्येक जिले में न्यूनतम 75 अमृत सरोवरों के साथ टिकाऊ जल स्रोत बनाएं।

राष्ट्रीय लक्ष्य: मिशन दिशानिर्देशों का पालन करते हुए 50,000 अमृत सरोवर का लक्ष्य हासिल किया।

कार्यान्वयन दृष्टिकोण:

सरकारी सहयोग: इसमें ग्रामीण विकास, भूमि संसाधन, पेयजल और स्वच्छता, जल संसाधन, पंचायती राज, वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, रेलवे, सड़क, परिवहन और राजमार्ग जैसे 8 केंद्रीय मंत्रालय/विभाग शामिल हैं।

तकनीकी भागीदार: भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना विज्ञान संस्थान (बीआईएसएजी-एन)।

उपयोग की गई योजनाएं: महात्मा गांधी नरेगा, XV वित्त आयोग अनुदान, पीएमकेएसवाई उप-योजनाएं (वाटरशेड विकास घटक, हर खेत को पानी), और राज्य-विशिष्ट योजनाओं सहित विभिन्न योजनाओं का उपयोग करता है।

समुदाय की भागीदारी: नागरिक भागीदारी और गैर-सरकारी संसाधन जुटाने को प्रोत्साहित करता है।

KVIC के अध्यक्ष ने तमिलनाडु में कई KVI गतिविधियों का उद्घाटन किया

श्री मनोज कुमार खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) के अध्यक्ष ने तमिलनाडु की अपनी यात्रा के दौरान कई खादी और ग्रामोद्योग (KVI) पहल का उद्घाटन किया।

वह खादी कार्यकर्ताओं से सीधे जुड़े, उनके काम के साथ घनिष्ठ संबंध को बढ़ावा दिया।

इस यात्रा और बातचीत ने न केवल अध्यक्ष और कारीगरों के बीच संबंधों को मजबूत किया, बल्कि रोजगार सृजन, कौशल विकास और टिकाऊ प्रथाओं के माध्यम से ग्रामीण समुदायों के उत्थान में केवीआईसी की पहल के महत्वपूर्ण प्रभाव को भी रेखांकित किया।

खादी कारीगर सम्मेलन: 19 अगस्त, 2023 को SITRA, कोयंबटूर में श्री मनोज कुमार ने खादी कारीगर सम्मेलन की अध्यक्षता की। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान तमिलनाडु के लोगों द्वारा दिखाए गए गर्मजोशी भरे आतिथ्य और देखभाल के लिए अपनी सराहना व्यक्त की।

इंटरेक्शन प्लेटफार्म: यह आयोजन सिर्फ खादी कारीगर सम्मेलन से कहीं अधिक था; यह श्री मनोज कुमार और ग्रामीण कारीगरों के बीच हार्दिक बातचीत ("मन की बात") का अवसर था। इस संवाद में ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण में योगदान करते हुए गरीबी, बेरोजगारी और भूख से निपटने में खादी के महत्व पर जोर दिया गया।

मान्यता एवं पुरस्कार: चेयरमैन ने उच्च प्रदर्शन करने वाले स्पिनरों और बुनकरों को प्रमाण पत्र और मोमेंटम देकर उनके अनुकरणीय प्रयासों को मान्यता दी।

कौशल संवर्धन: इसके अतिरिक्त, वुड क्राफ्ट में विशेषज्ञता रखने वाले लगभग 40 कारीगरों, जिन्होंने वेस्ट वुड क्राफ्ट पर प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया था, को टूल किट और उपकरण प्रदान किए गए। इस प्रशिक्षण में 800 ग्रामीण कारीगरों ने भाग लिया।

खादी की भूमिका: अध्यक्ष ने दोहराया कि खादी ग्रामीण विकास, गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने और महिलाओं को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

अरुणाचल सरकार ने तीन केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को 12 'रुकी हुई' जलविद्युत परियोजनाएं आवंटित कीं

अरुणाचल प्रदेश सरकार ने तीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ समझौता ज्ञापन (MoA) पर हस्ताक्षर करके 12 'रुकी हुई' जल विद्युत परियोजनाओं को आवंटित किया है।

केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और राज्य के उपमुख्यमंत्री सह बिजली और जलविद्युत के प्रभारी मंत्री चाउना मीन की उपस्थिति में MoA पर हस्ताक्षर किए गए।

निजी कंपनियों से वापस ली गई इन 12 परियोजनाओं की कुल परिचालन क्षमता 11,523 मेगावाट होगी।

तीन CPSU नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (SJVN) और नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NEEPCO) हैं।

12 जलविद्युत परियोजनाओं में से, NEEPCO को पांच परियोजनाएं आवंटित की गई हैं, SJVN को पांच और जलविद्युत दिग्गज NHPC लिमिटेड दो परियोजनाएं शुरू करेगी।

ये परियोजनाएं शुरू में लगभग 15 साल पहले स्वतंत्र बिजली डेवलपर्स को आवंटित की गई थीं, लेकिन विभिन्न कारणों से रुकी हुई हैं।

पश्चिम बंगाल: ममता बनर्जी ने दुर्गा पूजा समितियों को अनुदान ₹70,000 बढ़ाया

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुर्गा पूजा समितियों के साथ बैठक करने के बाद राज्य में पूजा समितियों को 70,000 रुपये के अनुदान में वृद्धि की घोषणा की।

मीडिया को संबोधित करते हुए ममता ने कहा कि पूजा समितियों को दुर्गा पूजा के दौरान खपत होने वाली कुल बिजली का केवल 1/4 हिस्सा ही देना होगा।

ममता ने कहा, "दुर्गा पूजा एक भव्य आयोजन है और इस दौरान कई करोड़ रुपये का कारोबार होता है। सभी को इसे व्यापक रूप से मनाना चाहिए क्योंकि दुर्गा पूजा के दौरान विदेशी तटों से भी लोग पश्चिम बंगाल आते हैं।"

ममता ने संबंधित विभागों से उत्सव के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा और आपात स्थिति का ध्यान रखने को भी कहा।

मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि दुर्गा कार्निवल (प्रतिमा निर्माण जुलूस का वार्षिक विसर्जन) 27 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा।

पश्चिम बंगाल के बारे में:

पूंजी: कोलकाता

मुख्यमंत्री: ममता बनर्जी

राज्यपाल: सीवी अनंत बोस

राष्ट्रीय उद्यान: नेओरा वैली राष्ट्रीय उद्यान, बक्सा टाइगर रिजर्व, जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान

उत्तराखंड सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 का आयोजन करने जा रही है

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगामी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, 2023 के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने के उद्देश्य से गठित अपने सलाहकार समूह के अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की।
सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नवंबर 2023 में उत्तराखंड में होने वाले शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करने का अनुरोध किया है
उत्तराखंड सरकार इस साल ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 का आयोजन करने जा रही है।
सीएम ने फिक्की और CII से भी चर्चा की और उनके सुझाव लिये
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार उद्यमियों को हर तरह की सुविधाएं दे रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर बनाने का लक्ष्य रखा है।
इसे ध्यान में रखते हुए, उत्तराखंड राज्य ने राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सशक्त उत्तराखंड मिशन शुरू किया है, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में राज्य की GSDP को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है।
सेतु राज्य में बेहतर योजना संरचना, प्रभावी नीति निर्माण, नवाचारों को बढ़ावा देने तथा अंतर्विभागीय समन्वय तथा विकास कार्यों की निगरानी एवं मूल्यांकन के लिए नीति आयोग की तरह राज्य में (स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड) की स्थापना की गई है।
सीएम ने यह भी कहा कि राज्य ने वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है
इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम सामूहिक प्रयासों से प्रधानमंत्री की "सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास" की अवधारणा को साकार करने की दिशा में काम कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में अपराध दर राष्ट्रीय औसत से 22 प्रतिशत कम है।
नीति आयोग द्वारा जारी वर्ष 2022 के निर्यात तैयारी सूचकांक में हिमालयी राज्यों में उत्तराखण्ड राज्य पहले स्थान पर है, जबकि पूरे देश में 9वें स्थान पर है।
उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की "लीड्स" रैंकिंग में वर्ष 2022 की रैंकिंग में उत्तराखंड को स्टेट अचीवर्स श्रेणी में शामिल किया गया है।

उत्तराखंड के बारे में:

पूंजी: देहरादून
मुख्यमंत्री: पुष्कर सिंह धामी
राज्यपाल: गुरमित सिंह
राष्ट्रीय उद्यान: गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान

केरल का पहला AI स्कूल तिरुवनंतपुरम में लॉन्च किया गया

केरल को तिरुवनंतपुरम के शांतिगिरी विद्याभवन में अपना पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्कूल मिला।
उद्घाटन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने किया

स्कूल के अधिकारियों के अनुसार, अल स्कूल को वेधीक ईस्कूल के सहयोग से दुनिया के सबसे उन्नत शैक्षिक प्लेटफार्मों में से एक आईलर्निंग इंजन (IILE) USA द्वारा डिजाइन और ढाला गया है, जिसका प्रबंधन पूर्व मुख्य सचिवों, DGP और कुलपतियों सहित अनुभवी पेशेवरों की एक समिति द्वारा किया जाता है।
वैदिक ईस्कूल अधिकारियों के अनुसार, यह एक अभिनव शिक्षण विधि है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी की मदद से छात्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों और गुणवत्ता सीखने के अवसरों को सुनिश्चित करती है।
AI स्कूल स्कूलों को उच्च ग्रेड प्राप्त करने में सक्षम बनाता है क्योंकि सामग्री और शिक्षाशास्त्र नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के आधार पर राष्ट्रीय स्कूल मान्यता मानकों के अनुसार तैयार किए जाते हैं।

केरल के बारे में:

पूंजी: तिरुवनंतपुरम
मुख्यमंत्री: पिनाराई विजयन
राज्यपाल: आरिफ मोहम्मद खान
राष्ट्रीय उद्यान: पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, मथिकेट्टन राष्ट्रीय उद्यान, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान

तमिलनाडु सरकार ने 31 हजार स्कूलों में नाश्ता योजना शुरू की

तमिलनाडु सरकार ने 31 हजार स्कूलों में नाश्ता योजना शुरू की। इससे पहली से पांचवीं कक्षा तक पढ़ने वाले 17 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को फायदा होगा।
राज्य के मुख्यमंत्री एम.के.स्टालिन ने नागपट्टिनम जिले के थिरुक्कुवलाई में एक पंचायत स्कूल में कार्यक्रम का उद्घाटन किया।
राज्य के मंत्रियों, संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों ने सभी जिलों में योजना का उद्घाटन किया।
यह योजना शुरुआत में 1545 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में एक लाख से अधिक छात्रों को नाश्ता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी, लेकिन अब इसे सभी राज्य सरकारी स्कूलों तक बढ़ा दिया गया है।
तमिलनाडु में 1956 से ही दोपहर का भोजन योजना लागू थी।
योजना का दायरा सरकारी स्कूलों में बच्चों का नामांकन बढ़ाना है।
पिछले साल नाश्ता योजना शुरू होने के बाद उपस्थिति में 40 प्रतिशत का सुधार हुआ।
नाश्ता सभी स्कूल दिवसों पर उपलब्ध कराया जाएगा और मेनू में 13 प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं।

मेरी माटी मेरा देश: गुजरात के मुख्यमंत्री ने पंचायती राज संस्थाओं के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया

पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, गुजरात सरकार ने एक नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया जो राज्य में पंचायती राज संस्थानों के लिए ऑनलाइन भुगतान अनिवार्य कर देगा, जिससे ठेकेदारों और विक्रेताओं को चेक भुगतान की प्रथा समाप्त हो जाएगी।
मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने गांधीनगर में 'मेरी माटी मेरा देश' के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पंचायती राज लेखा सूचना प्रणाली स्वचालन या PRAISA का शुभारंभ किया।
PRAISA राज्य पंचायत विभाग के प्रशासन को कागज रहित और अधिक प्रभावी बनाएगा क्योंकि सभी 33 जिलों और 248 तालुका पंचायतों के वित्तीय और लेखा लेनदेन को इस ऑनलाइन मंच के माध्यम से नियंत्रित किया जाएगा।

अब से, PRAISA के माध्यम से इन पंचायती राज संस्थाओं, स्थानीय स्वशासित निकायों के 34,000 करोड़ रुपये के वित्तीय लेनदेन को पारदर्शी तरीके से नियंत्रित किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों की गतिविधियों को सार्वजनिक डोमेन में लाने के लिए 'मानव सम्पदा पोर्टल' लॉन्च किया

उत्तर प्रदेश (UP) सरकार ने राज्य के सभी 74 विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही पैदा करने के उद्देश्य से 'मानव सम्पदा पोर्टल' की शुरुआत की।

इन परिचालनों की देखरेख और पोर्टल का प्रबंधन करने के लिए, कार्मिक विभाग के भीतर एक नया प्रभाग (धारा-5) स्थापित किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) स्तर पर परियोजना प्रबंधन इकाई (PMU) संचालित होगी।

'मानव सम्पदा पोर्टल' के बारे में:

व्यापक सेवा विवरण:

1 अक्टूबर, 2023 तक, पोर्टल कर्मियों की व्यापक सेवा-संबंधित जानकारी होस्ट करेगा, जिसमें नियुक्ति, ज्वाइनिंग, बर्खास्तगी, छुट्टी प्रबंधन, योग्यता के आधार पर ऑनलाइन स्थानांतरण प्रणाली, वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट प्रबंधन, वेतन निकासी और सेवा पुस्तिका जैसे विभिन्न पहलू शामिल होंगे।

प्रोफ़ाइल विवरण पोस्ट करना:

पोर्टल कर्मियों की विस्तृत पोस्टिंग प्रोफाइल पेश करेगा, जिसमें विकलांगता, पति-पत्नी के सरकारी रोजगार और गंभीर बीमारियों जैसे कारक शामिल होंगे।

ये विवरण उचित सत्यापन के साथ उपलब्ध होंगे।

वेतन प्रबंधन:

अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन 'मानव संपदा पोर्टल' और डीडीओ (आहरण एवं संवितरण अधिकारी) पोर्टल दोनों से निकाले गए सटीक और मान्य डेटा के आधार पर वितरित किया जाएगा, जिससे सटीकता सुनिश्चित होगी और विसंगतियां कम होंगी।

संपत्ति घोषणा:

यूपी सरकार ने दिसंबर 2023 तक अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी चल और अचल संपत्ति वेबसाइट पर घोषित करने का आदेश दिया।

नवीनतम समाचार:

जुलाई 2023 में, उत्तर प्रदेश (यूपी) सरकार ने सब्सिडी पोर्टल, upevsubsidy.in लॉन्च किया, जिससे लोगों को यूपी में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की खरीद पर उपलब्ध सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का मार्ग प्रशस्त हुआ।

यूपी के बारे में:

राज्यपाल: आनंदीबेन पटेल

मुख्यमंत्री: योगी आदित्यनाथ

पूंजी: लखनऊ

राष्ट्रीय उद्यान: दुधवा राष्ट्रीय उद्यानवन्यजीव अभयारण्य: बखिरा वन्यजीव अभयारण्य, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य

तेलंगाना सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नैतिकता पर सिफारिश को लागू करने के लिए यूनेस्को के साथ भागीदारी की

तेलंगाना सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार (ITE&C) विभाग ने प्रयासों और कार्रवाई को चलाने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की नैतिकता पर यूनेस्को की सिफारिश को लागू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) के साथ हाथ मिलाया है।

यह सहयोग एआई जागरूकता बढ़ाने, क्षमता निर्माण और एआई नैतिकता पर यूनेस्को की वैश्विक वेधशाला में योगदान के नैतिक विकास और उपयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

साझेदारी एआई-संचालित भविष्य के लिए एक साझा प्रतिबद्धता को सक्षम बनाती है जो सामाजिक अच्छे और न्यायसंगत विकास को प्राथमिकता देती है।

तेलंगाना के बारे में:

राजधानी: हैदराबाद

राज्यपाल: तमिलिसाई सौंदर्यराजन

मुख्यमंत्री: के.चंद्रशेखर राव

यूनेस्को के बारे में:

स्थापना: 16 नवंबर 194

मुख्यालय: पेरिस, फ्रांस

महानिदेशक: ऑड्रे अज़ोले

यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसका उद्देश्य शिक्षा, कला, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है।

श्रीलंका अपने पहले कर्नाटक सांस्कृतिक उत्सव की मेजबानी करता है

श्रीलंका स्वामी विवेकानन्द सांस्कृतिक केन्द्र और एमई ग्लोबल पीस फाउंडेशन के सहयोग से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक परिषद द्वारा आयोजित अपने पहले कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव की मेजबानी की।

उद्देश्य: कर्नाटक की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता का जश्न मनाना और भारत और श्रीलंका के बीच साझा सांस्कृतिक विरासत को स्वीकार करना।

महोत्सव की मुख्य विशेषताएं:

विविध प्रदर्शन: इस महोत्सव में कर्नाटक के 30 से अधिक कलाकारों द्वारा मनमोहक प्रदर्शन प्रस्तुत किया गया। इन प्रदर्शनों में पारंपरिक नृत्य, लोक गीत, बहुभाषी कविताएं, बैले प्रदर्शन और आकर्षक कठपुतली शो सहित सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल थी।

कर्नाटक की विरासत का जश्न: इस महोत्सव ने कर्नाटक की सांस्कृतिक विरासत का सार प्रदर्शित किया, जो इसके पारंपरिक कला रूपों, संगीत, नृत्य और कलात्मक रचनात्मकता को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।

सांस्कृतिक विनियमन: इस उत्सव ने कर्नाटक और श्रीलंका के बीच अंतर-सांस्कृतिक आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान की, जिससे दोनों देशों को एक-दूसरे की कलात्मक अभिव्यक्तियों और परंपराओं की सराहना करने और सीखने का मौका मिला।

मध्य प्रदेश ने लाडली बहना योजना सहायता वृद्धि की घोषणा की, महिलाओं के लिए 35% नौकरी आरक्षण

मध्य प्रदेश (एमपी) सरकार ने लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को दी जाने वाली वित्तीय सहायता 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,250 रुपये प्रति माह कर दी है।
इस योजना का उद्देश्य मध्य प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक सहायता और सशक्तिकरण प्रदान करना है।

लाडली बहना योजना के बारे में:

अक्टूबर से शुरू होने वाली इस योजना के तहत लगभग 1.25 करोड़ महिलाओं को प्रति माह 1,250 रुपये मिलेंगे और धीरे-धीरे यह राशि बढ़ाकर ₹3,000 प्रति माह कर दी जाएगी ताकि महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाने का लक्ष्य पूरा हो सके।
10 जून, 2023 को शुरू की गई लाडली बहना योजना पहले ही पात्र महिलाओं को 3,628.85 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान कर चुकी है।

पात्रता मापदंड:

लाडली बहना योजना के तहत 23 से 60 वर्ष की आयु की महिलाएं प्रति माह 1,000 रुपये की वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं।
यह सहायता उन महिलाओं को दी जाती है जो आयकर दाता नहीं हैं और 2.5 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों से आती हैं।

अन्य पहल:

उन्होंने सरकारी नौकरियों में महिला आरक्षण को मौजूदा 30% से बढ़ाकर 35% करने की भी घोषणा की।
गौरतलब है कि शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण 50 फीसदी निर्धारित किया जाएगा

कम कीमत पर गैस सिलेंडर:

सरकार ने महिलाओं की आर्थिक खुशहाली में योगदान करते हुए उन्हें 450 रुपये की कम कीमत पर गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए भी कदम उठाए हैं।

एमपी के बारे में:

राज्यपाल: मंगूभाई सी. पटेल
मुख्यमंत्री: शिवराज सिंह चौहान
पूंजी: भोपाल
राष्ट्रीय उद्यान: कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान
वन्यजीव अभयारण्य: करेरा वन्यजीव अभयारण्य, घाटीगांव वन्यजीव अभयारण्य, रातापानी वन्यजीव अभयारण्य

रैंकिंग और रिपोर्ट

श्रीलंका में पर्यटन के स्रोत बाजार के रूप में भारत शीर्ष स्थान पर बना हुआ है

भारत ने श्रीलंका में पर्यटन के स्रोत बाजार के रूप में शीर्ष स्थान बनाए रखा है
श्रीलंका पर्यटन विकास प्राधिकरण द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत से पर्यटकों का आगमन 1 लाख 39 हजार से अधिक हो गया है।
इसका मतलब द्वीप राष्ट्र में आने वाले 7.67 लाख पर्यटकों में से 18 प्रतिशत से अधिक बाजार हिस्सेदारी है।
जुलाई में भारत में 23461 पर्यटक आये जो अन्य देशों से आगे थे।
पिछले साल दिसंबर में जाफना और चेन्नई के बीच हवाई यात्रा फिर से शुरू होने से पिछले कुछ महीनों में दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है।

पिछले महीने सेवाएँ दैनिक कर दी गईं।
सेक्टर में दैनिक उड़ानें संचालित होने से कोलंबो और मुंबई के बीच कनेक्टिविटी में भी सुधार हुआ है।
इसके अलावा, समुद्र के द्वारा यात्री परिवहन पर एक MoU के तहत स्थापित भारत-श्रीलंका संयुक्त समिति ने पिछले महीने एक आभासी बैठक की, जिसमें दोनों देशों के बीच पारस्परिक रूप से सहमत बिंदुओं को जोड़ने वाली नौका सेवाओं को फिर से शुरू करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
नागपट्टिनम और कांकेसंथुराई के बीच नौका सेवाएं जल्द ही शुरू होने की संभावना है।

श्रीलंका के बारे में:

राष्ट्रपति: रानिल विक्रमसिंघे
प्रधान मंत्री: दिनेश गुणवर्धने
राजधानी: श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे (विधायी), कोलंबो (कार्यकारी और न्यायिक)
मुद्रा: श्रीलंकाई रुपया (रुपये)

नवीनतम समाचार

भारत मार्च 2024 तक श्रीलंका के लिए 1 बिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन को एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है, जिससे संकटग्रस्त देश को आवश्यक आयात के भुगतान के लिए बैकअप फंड मिल जाएगा।
बहुप्रतीक्षित 67वां ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (TAAI) सम्मेलन कोलंबो में शुरू होगा।
केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग तथा आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने चेन्नई में चेन्नई से श्रीलंका के लिए भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय क्रूज जहाज एमवी एम्प्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में हरियाणा के नूंह ने दूसरा स्थान हासिल किया है

आकांक्षी जिला कार्यक्रम के हरियाणा के नूंह जिले में सकारात्मक परिणाम मिले हैं क्योंकि जिला नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में 30वें स्थान से दूसरे स्थान पर आ गया है।
इस संबंध में विवरण साझा करते हुए, उपायुक्त, श्री. धीरेंद्र खड़गटा ने कहा कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम का लक्ष्य भारत में सबसे अधिक सामाजिक-आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण जिलों का उत्थान और विकास करना है और नूंह जिले में यह प्रगति निश्चित रूप से सही दिशा में एक कदम है।
उन्होंने कहा कि आकांक्षी जिलों के अन्य मानकों पर भी जिले की रैंकिंग में सुधार के लिए लगातार प्रयास जारी हैं
उन्होंने आगे बताया कि कृषि एवं जल संसाधन के मापदण्डों में जिला प्रथम स्थान पर है।
इसका स्कोर 26.2 से बढ़कर 30.7 हो गया है
इसी प्रकार स्वास्थ्य एवं पोषण मापदण्डों में जिला 64.9 से 71.3 की वृद्धि के साथ दूसरे स्थान पर है।
अन्य विभागों की रैंकिंग में लगातार सुधार के चलते जिले ने ओवरऑल दूसरा स्थान हासिल किया है।
धीरेंद्र खड़गटा ने कहा कि नीति आयोग ने देशभर के 112 आकांक्षी जिलों की सूची साझा की थी, जिसमें करीब 87 पैरामीटर तय किए गए थे

खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी (IOAA) पर 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में भारत का प्रदर्शन:

भारत ने 10 से 20 अगस्त, 2023 तक पोलैंड के चोरज़ो में आयोजित खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी (IOAA) पर 16 वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में दूसरी रैंक हासिल की।

यह उपलब्धि अंतरराष्ट्रीय मंच पर खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के क्षेत्र में भारतीय छात्रों की असाधारण प्रतिभा और ज्ञान को प्रदर्शित करती है।
उनकी सफलता न केवल उनके समर्पण को दर्शाती है बल्कि वैज्ञानिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करती है।
मेडल टैली: भारतीय टीम ने प्रतियोगिता में उल्लेखनीय रूप से चार स्वर्ण पदक और एक रजत पदक अर्जित किया।
नेतृत्व: यूनाइटेड किंगडम ने पांच स्वर्ण पदकों के साथ पहला स्थान हासिल किया, जिससे भारत सराहनीय दूसरे स्थान पर रहा।
वैश्विक भागीदारी: ओलंपियाड में 50 देशों के कुल 236 छात्रों ने भाग लिया, और विभिन्न श्रेणियों में सामूहिक रूप से 27 स्वर्ण, 41 रजत और 50 कांस्य पदक अर्जित किए।
भारतीय पुरस्कार विजेता: भारत के स्वर्ण पदक विजेताओं में कोटा, राजस्थान के राजदीप मिश्रा; कुरनूल, आंध्र प्रदेश से कोदुरू तेजेश्वर; कोलकाता, पश्चिम बंगाल से मोहम्मद साहिल अख्तर; और नागपुर, महाराष्ट्र से आकर्ष राज सहाय। बेंगलुरु, कर्नाटक के साईनवनीत मुकुंद ने रजत पदक हासिल किया।
टीम के नेता: भारतीय टीम का नेतृत्व IUCAA, पुणे के प्रोफेसर सुरहुद मोरे और HBCSE-TIFR, मुंबई के प्रीतेश रणदिवे ने किया।

ICICI प्रूडेंशियल लाइफ को भारतीय सूचीबद्ध बीमा कंपनियों में सर्वश्रेष्ठ ESG रेटिंग प्राप्त है

ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने पर्यावरण (हरित और सतत संचालन की ओर संक्रमण), सामाजिक (कर्मचारियों को सशक्त बनाना, ग्राहक केंद्रितता को अपनाना और समुदायों की मदद करना) और शासन (मजबूत शासन संरचना को सक्षम करना और जोखिमों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना) स्तंभों के तहत ESG ढांचे के प्रत्येक आयाम के लिए पहल पर ध्यान केंद्रित किया है।
इन पहलों के परिणामस्वरूप, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस को 16.9 की ESG जोखिम रेटिंग प्राप्त हुई और सस्टेनलिटिक्स द्वारा ईएसजी कारकों से उत्पन्न होने वाले भौतिक वित्तीय प्रभाव का अनुभव करने के कम जोखिम पर मूल्यांकन किया गया।
ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस को MSCI ESG रेटिंग मूल्यांकन में A (AAA-CCC के पैमाने पर) रेटिंग मिली है।
कंपनी का मानना है कि स्थिरता जीवन बीमा में अंतर्निहित है क्योंकि कंपनी दीर्घकालिक बचत और सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करती है।
ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस अपनी व्यावसायिक प्रक्रियाओं और व्यवसाय करने के तरीके के साथ स्थिरता को एकीकृत करने के लिए प्रतिबद्ध है।
2020 में हमारी ESG यात्रा शुरू होने के बाद से वे महत्वपूर्ण प्रगति कर रहे हैं।
इस वर्ष उन्होंने स्थिरता गतिविधियों और प्रमुख ईएसजी-संबंधित खुलासों की समीक्षा को शामिल करने के लिए अपनी बोर्ड CSR समिति के संदर्भ की शर्तों का विस्तार किया।
कंपनी के स्थिरता ढांचे के 3 स्तंभ
पर्यावरण - ग्रह को अगली पीढ़ी के लिए एक बेहतर स्थान छोड़ना
सामाजिक - समाज को वापस देना
शासन-कार्य में पारदर्शिता

अमूल को दुनिया का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड और दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत खाद्य ब्रांड का दर्जा दिया गया

ब्रांड फाइनेंस फूड एंड ड्रिंक रिपोर्ट 2023 द्वारा अमूल को दुनिया के सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड के रूप में स्थान दिया गया है। रिपोर्ट सबसे मजबूत और सबसे मूल्यवान भोजन, डेयरी और गैर-अल्कोहल पेय ब्रांडों का मूल्यांकन और रैंकिंग करती है। दुनिया की अग्रणी ब्रांड वैल्यूएशन कंसल्टेंसी, यूके स्थित ब्रांड फाइनेंस द्वारा संचालित रिपोर्ट, गुणवत्ता, नवाचार और उपभोक्ता विश्वास के प्रति अमूल की अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है।

अमूल को न केवल विश्व स्तर पर सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड के रूप में स्थान दिया गया है, बल्कि प्रसिद्ध अमेरिकी चॉकलेट ब्रांड, हर्षे के बाद यह दुनिया भर में दूसरा सबसे मजबूत खाद्य ब्रांड भी है।

अमूल ब्रांड को दुनिया के 5000 ब्रांडों में से शीर्ष 30 सबसे मूल्यवान खाद्य ब्रांडों में भी स्थान दिया गया है।

अमूल गर्व से दुनिया के शीर्ष 100 ब्रांडों में से एकमात्र किसान-स्वामित्व वाला ब्रांड है।

अमूल ने 3 अरब डॉलर के प्रभावशाली मूल्यांकन के साथ दुनिया के सबसे मूल्यवान डेयरी ब्रांडों की सूची में सातवां स्थान हासिल किया है।

इस प्रतिष्ठित सूची में भारत के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में, अमूल अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश को गौरवान्वित कर रहा है। रिपोर्ट सस्टेनेबिलिटी परसेप्शन वैल्यूज़ (SPV) के मामले में इसे सातवें स्थान पर रखकर स्थिरता और जिम्मेदार प्रथाओं के प्रति अमूल की प्रतिबद्धता की भी पुष्टि करती है।

अमूल के बारे में:

72,000 करोड़ रुपये (9 बिलियन अमेरिकी डॉलर) के वार्षिक बिक्री कारोबार के साथ अमूल भारत का सबसे बड़ा एफएमसीजी ब्रांड है और किसान सहकारी आंदोलन की शक्ति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसका जन्म 1946 में हुआ था, भारत को आज़ादी मिलने से पहले, और हाल ही में इसकी 75वीं वर्षगांठ मनाई गई।

स्मार्ट सिटी पुरस्कार: मध्य प्रदेश सर्वश्रेष्ठ राज्य, इंदौर शीर्ष स्थान पर बरकरार

केंद्र सरकार ने इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड प्रतियोगिता (ISAC) के चौथे संस्करण के 66 विजेताओं की घोषणा की, जिसे अप्रैल 2022 में सूरत में स्मार्ट सिटीज़-स्मार्ट शहरीकरण कार्यक्रम में लॉन्च किया गया था।

देश के शहरों को उन्नत करने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत आयोजित इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड प्रतियोगिता (ISAC) के चौथे संस्करण के तहत मध्य प्रदेश शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य बनकर उभरा है।

राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार जीतकर इंदौर ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा

राज्यों में, तमिलनाडु दूसरे स्थान पर था, और राजस्थान और उत्तर प्रदेश संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर थे।

शहरों में, सूरत और आगरा क्रमशः इंदौर के बाद दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे।

2020 में आयोजित प्रतियोगिता के पिछले संस्करण में, उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया था जबकि सूरत और इंदौर शहर श्रेणी में संयुक्त विजेता थे।

पुरस्कार का नाम	विजेता
निर्मित पर्यावरण	1. कोयंबटूर: मॉडल सड़कें, झीलों का जीर्णोद्धार और कायाकल्प
निर्मित पर्यावरण	2. इंदौर: रिवरफ्रंट डेवलपमेंट (रामबाग से विस्तार 1)।पुलकृष्णपुरा छतरी से)
निर्मित पर्यावरण	3. न्यू टाउन कोलकाता: नीम बनानी पार्क और अन्य हरे खुले स्थानों का लैंडस्केप पुनर्विकास

निर्मित पर्यावरण	3. कानपुर: पालिका स्पोर्ट्स स्टेडियम का आधुनिकीकरण एवं विकास
संस्कृति	1. अहमदाबाद: पुनरुद्धार औरमरम्मतप्रौद्योगिकी का उपयोग करके विरासत संरचना और विरासत पर्यटन का विकास
संस्कृति	2. भोपाल: हेरिटेज वॉक परियोजना के तहत सदर मंजिल परिसर के पास विरासत भवनों का जीर्णोद्धार
संस्कृति	3. तंजावुर: तालाबों का संरक्षण - अय्यनकुलम
अर्थव्यवस्था	1. जबलपुर: इन्क्यूबेशन सेंटर
अर्थव्यवस्था	2. इंदौर: वैल्यू कैप्चर फाइनेंसिंग (VCF)
अर्थव्यवस्था	3. लखनऊ: रोजगार प्रशिक्षण केंद्र
शासन	1. चंडीगढ़:ई-शासनचंडीगढ़ स्मार्ट सिटी के लिए सेवाएँ
शासन	2. पिंपरी चिंचवड़: स्मार्ट सारथी ऐप
शासन	3. जबलपुर: 311 ऐप का कार्यान्वयन
शासन	3. उदयपुर: स्मार्ट सिटी एप्लीकेशन
ICCC बिजनेस मॉडल	1. अहमदाबाद: ICCC के माध्यम से यातायात प्रबंधन
ICCC बिजनेस मॉडल	2. सूरत: ICCC के माध्यम से विभिन्न स्रोतों से राजस्व सृजन
ICCC बिजनेस मॉडल	3. आगरा: ICCC और कार्बन उत्सर्जन में कमी के माध्यम से राजस्व सृजन
ICCC बिजनेस मॉडल	3. ग्वालियर: इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम
राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार	1. इंदौर
राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार	2. सूरत
राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार	3. आगरा
यूटी पुरस्कार	1. चंडीगढ़
राज्य पुरस्कार	1. मध्य प्रदेश
राज्य पुरस्कार	2. तमिलनाडु
राज्य पुरस्कार	3. राजस्थान
राज्य पुरस्कार	3. उत्तर प्रदेश

क्या है पीएम नरेंद्र मोदी का स्मार्ट सिटी मिशन?

जून 2015 में लॉन्च किए गए स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य स्मार्ट समाधानों के माध्यम से अपने नागरिकों को मुख्य बुनियादी ढांचा, स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण और जीवन की सभ्य गुणवत्ता प्रदान करना है।

यह एक परिवर्तनकारी मिशन है जिसका उद्देश्य देश में शहरी विकास के अभ्यास में आमूल-चूल बदलाव लाना है।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कुल प्रस्तावित परियोजनाओं में से 1,10,635 करोड़ रुपये की 6,041 (76 प्रतिशत) परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 60,095 करोड़ रुपये की शेष 1,894 परियोजनाएं 30 जून, 2024 तक पूरी हो जाएंगी।

इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता उन शहरों, परियोजनाओं और अभिनव विचारों को पहचानती है और पुरस्कृत करती है जो 100 स्मार्ट शहरों में सतत विकास को बढ़ावा दे रहे हैं, जिन्होंने गतिशीलता, ऊर्जा, पानी, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जीवंत सार्वजनिक स्थानों, सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्मार्ट शासन जैसे क्षेत्रों से संबंधित कई क्षेत्रों में परियोजनाएं शुरू की हैं।

जल शक्ति मंत्रालय ने लघु सिंचाई योजनाओं पर छठी जनगणना पर रिपोर्ट जारी की

जल शक्ति मंत्रालय ने लघु सिंचाई योजनाओं पर छठी जनगणना पर रिपोर्ट जारी की।
रिपोर्ट के अनुसार, देश में 23.14 मिलियन लघु सिंचाई (MI) योजनाएं बताई गई हैं। जिनमें से 21.93 मिलियन भूजल (GW) और 1.21 मिलियन सतही जल (SW) योजनाएं हैं।
पहली बार, व्यक्तिगत स्वामित्व के मामले में MI योजना के मालिक के लिंग के बारे में भी जानकारी एकत्र की गई।
सभी व्यक्तिगत स्वामित्व वाली योजनाओं में से 18.1 प्रतिशत का स्वामित्व महिलाओं के पास है।
देश में सबसे अधिक MI योजनाएं उत्तर प्रदेश में हैं, इसके बाद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु का स्थान है
GW योजनाओं के लिए राज्यों की समान रैंकिंग इस प्रकार है।
SW योजनाओं में महाराष्ट्र सबसे आगे है, उसके बाद कर्नाटक, तेलंगाना, ओडिशा और झारखंड हैं।
रिपोर्ट से यह भी पता चला कि पिछली जनगणना की तुलना में MI योजनाओं में लगभग 1.42 मिलियन की वृद्धि हुई है।

समझौता और समझौता ज्ञापन

शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने नई दिल्ली में विभिन्न प्रतिष्ठित संगठनों और संस्थानों के साथ 106 समझौता ज्ञापनों (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं

शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने नई दिल्ली में विभिन्न प्रतिष्ठित संगठनों और संस्थानों के साथ 106 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।
यह आयोजन अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर हुआ।
MoU का उद्देश्य कई क्षेत्रों में नवाचार, अनुसंधान और ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना, शिक्षा और उद्योग-अकादमिक संबंधों में सहयोग को बढ़ावा देना है।
इन साझेदारियों में सार्वजनिक और निजी दोनों संस्थाएँ शामिल हैं और स्कूली शिक्षा, साक्षरता और उच्च शिक्षा को कवर करती हैं।
CBSE के तहत, कौशल विकास और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अटल इनोवेशन मिशन, IBM, इंटेल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे संगठनों के साथ 15 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NiOS) ने भारतीय सांकेतिक भाषा को बढ़ावा देने के लिए 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें से एक भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र (ISLRTC) के साथ भी है।
NCERT ने गुणवत्तापूर्ण ई-सामग्री विकास और प्रसार के लिए 20 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, भारतीय ज्ञान प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए 6 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।
6 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी मजबूत हुआ।
इसके अतिरिक्त, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने युवाओं को अत्याधुनिक कौशल और ज्ञान से लैस करने के लिए 14 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।
ये साझेदारियाँ भारत में शैक्षणिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

उभरती प्रौद्योगिकियों पर कौशल कार्यक्रम पेश करने के लिए डीजीटी ने अमेज़ॅन वेब सर्विसेज इंडिया के साथ सहयोग किया है

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) के तत्वावधान में प्रशिक्षण महानिदेशालय (DGT) क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा एनोटेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), और मशीन लर्निंग (ML) में छात्रों को उनकी क्षमताओं और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अमेजन वेब सर्विसेज (AWS) इंडिया के साथ सहयोग कर रहा है।

इस पहल से पूरे भारत में लगभग 15,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) और 33 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (NSTI) के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से दीर्घकालिक संस्थागत कौशल प्रशिक्षण को लागू करने के लिए जिम्मेदार शीर्ष संगठन DGT के तहत संस्थानों में नामांकित छात्रों को लाभ होगा।

इस सहयोग के हिस्से के रूप में, AWS इंडिया व्यक्तियों को उभरती प्रौद्योगिकियों में बिना किसी लागत के स्व-गति से ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम प्रदान करेगा।

यह शिक्षण सामग्री DGT के भारत कौशल मंच (https://bharatskills.gov.in) पर पेश की जाएगी, जो शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (CTS) और शिल्प प्रशिक्षक प्रशिक्षण योजना (CITS) के तहत सभी पाठ्यक्रमों के अद्यतन पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम सामग्री, डिजिटल रूप से मिश्रित सामग्री, प्रश्न बैंक और सीखने के वीडियो का एक केंद्रीय भंडार है।

नवीनतम समाचार

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR), नई दिल्ली ने इष्टतम उपज और आय के लिए विभिन्न फसलों की वैज्ञानिक खेती पर किसानों का मार्गदर्शन करने के लिए दोनों संगठनों की ताकत को संयोजित करने और तालमेल बनाने के लिए अमेज़ॅन किसान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

भुगतान सेवा प्रदाता पेयू ने अमेज़ॅन वेब सर्विसेज (AWS) इंडिया, एक क्लाउड प्लेटफॉर्म और उद्यम पूंजी फर्म चिराटे वेंचर्स के सहयोग से शुरुआती चरण के भारतीय स्टार्टअप के लिए 45-दिवसीय फिनटेक एक्सेलेरेटर प्रोग्राम, इनफिनिटी लॉन्च किया है।

अमेज़न के बारे में

CEO: एंडी जेसी
स्थापित: 5 जुलाई 1994
CFO: ब्रायन टी. ओल्साव्स्की
संस्थापक: जेफ बेजोस, मैकेंज़ी स्कॉट
मुख्यालय: सिएटल, वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका

दूरसंचार में तकनीकी और संस्थागत सहयोग तंत्र स्थापित करने के लिए ट्राई और सी-डॉट ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (C-DoT) ने एक "समझौता ज्ञापन" (MOU) पर हस्ताक्षर किए।

समझौता ज्ञापन पर दूरसंचार विभाग के सचिव, ट्राई के सचिव, सी-DoT के CEO और ट्राई तथा सी-DoT के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में डीजी (ट्राई CSR) श्री अनिल कुमार भार द्वाज और सी-DoT के रजिस्ट्रार श्री राजीव कुमार ने हस्ताक्षर किए।

ट्राई सेंटर ऑफ स्टडीज एंड रिसर्च (ट्राई CSR) को दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्रों में तकनीकी अध्ययन की अवधारणा, समन्वय और सक्षम करने के लिए ट्राई के भीतर एक इकाई के रूप में स्थापित किया गया था।
इसका लक्ष्य क्रॉस-सेक्टर पहलों को समन्वित करके और ज्ञान साझा करने की सुविधा प्रदान करके भारत में प्रौद्योगिकी-संचालित विकास को सक्षम करना है।
ट्राई CSR और सी-डॉट ने हस्ताक्षरित एमओयू के माध्यम से सहयोग किया है और पार्टियां दूरसंचार के क्षेत्र में इसके विकास में योगदान करने के लिए तकनीकी और संस्थागत सहयोग का एक तंत्र स्थापित करने के उद्देश्य से आम मान्यता तक पहुंच गई हैं।
एक एकीकृत दृष्टिकोण के साथ, उद्देश्य उभरती प्रौद्योगिकियों की क्षमता का पता लगाना है, यह समझौता ज्ञापन सहयोग और ज्ञान साझा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा देता है जो नियामक प्रथाओं, नियामक अंतर अध्ययनों और महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि के प्रसार पर शोध को बढ़ावा देता है।

एम्स ने नई दिल्ली के एम्स के सोलराइजेशन के लिए IREDA के साथ साझेदारी की:

भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (IREDA) और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली (एम्स) ने एम्स नई दिल्ली परिसर को सौर ऊर्जा से संचालित कैंपस में बदलने के लिए तकनीकी मूल्यांकन शुरू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।
इस दिशा में, IREDA एम्स परिसर का तकनीकी-व्यावसायिक मूल्यांकन करेगा।
MoU में दिए गए मूल्यांकन में वित्तीय मॉडल बनाना, पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन करना, एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करना, परियोजना विकास से संबंधित तकनीकी और वाणिज्यिक पहलुओं के विश्लेषण में सहायता करना, वाणिज्यिक और अनुबंध व्यवस्था को अंतिम रूप देना और प्रदर्शन को परिभाषित करना शामिल है।
इस साझेदारी में शामिल होकर और सौर ऊर्जा परियोजनाओं को लागू करके, एम्स का लक्ष्य IREDA की मदद से अपने बिजली व्यय को काफी हद तक कम करना है, साथ ही साथ अपने कार्बन पदचिह्न को भी कम करना है।
दोनों संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में, IREDA के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (CMD), श्री प्रदीप कुमार दास और एम्स निदेशक डॉ. एम श्रीनिवास द्वारा एम्स, नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

इरेडा के बारे में

भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड का गठन 1987 में भारत सरकार के तहत एक मिनी रत्न सरकार उद्यम के रूप में किया गया था और प्रशासनिक रूप से नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा नियंत्रित किया गया था।
स्थापित: 1987
मुख्यालय: नई दिल्ली

एम्स के बारे में

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, जिसे एम्स दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है, नई दिल्ली, भारत में एक सार्वजनिक चिकित्सा अनुसंधान विश्वविद्यालय और अस्पताल है। संस्थान 1956 के एम्स अधिनियम द्वारा शासित है और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्वायत्त रूप से संचालित होता है।

NHPC और एलिम्को ने दिव्यांगजनों को सहायता और सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

NHPC लिमिटेड और भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (एलिम्को) ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत NHPC उत्तर और उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थित NHPC परियोजनाओं के आसपास के क्षेत्र में लगभग 1,000 दिव्यांगजनों (विकलांग व्यक्तियों) को सहायता और सहायक उपकरणों के वितरण के लिए CSR सहायता प्रदान करेगा।
NHPC की CSR पहल के तहत NHPC कॉर्पोरेट कार्यालय, फरीदाबाद में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
समझौता ज्ञापन पर एनएचपीसी के निदेशक (कार्मिक), श्री उत्तम लाल, निदेशक (कार्मिक), कार्यकारी निदेशक (CSR और SD), NHPC और NHPC CSR&SD डिवीजन और एलिम्को के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में समूह उप महाप्रबंधक (मानव संसाधन), CSR और SD, NHPC और महाप्रबंधक- विपणन, एलिम्को ने हस्ताक्षर किए।

NHPC के बारे में:

NHPC लिमिटेड एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की जलविद्युत कंपनी है जिसे 1975 में जलविद्युत ऊर्जा के एकीकृत और कुशल विकास की योजना बनाने, बढ़ावा देने और व्यवस्थित करने के लिए शामिल किया गया था। हाल ही में इसका विस्तार सौर, भूतापीय, ज्वारीय और पवन जैसे ऊर्जा के अन्य स्रोतों को शामिल करने के लिए किया गया है।
स्थापना: 7 नवंबर 1975
मुख्यालय: फ़रीदाबाद, भारत

एलिम्को के बारे में:

मुख्यालय: कानपुर
स्थापित: 1972

भारतीय मानक ब्यूरो ने मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 35 संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

भारतीय मानक ब्यूरो भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय ने मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए देश भर के 35 प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।
संस्थानों में देश भर के विभिन्न राज्यों के कुछ प्रमुख NIT, सरकारी और निजी इंजीनियरिंग कॉलेज शामिल थे।
समझौता ज्ञापन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्यूरो की तकनीकी समितियों के साथ जुड़कर, प्रासंगिक अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के लिए बुनियादी ढांचा सहायता प्राप्त करके, संयुक्त रूप से मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन पर कार्यक्रमों का आयोजन करके, प्रकाशनों का आदान-प्रदान करके, शिक्षाविदों में मानकीकरण पाठ्यक्रम शुरू करके, मानकीकरण के लिए उत्कृष्टता केंद्र की खोज करके मानकीकरण गतिविधियों में भाग लेने के लिए भागीदार संस्थानों का मार्ग प्रशस्त करेगा। परीक्षण, और अनुरूपता मूल्यांकन, और प्रयोगशाला सुविधाओं को साझा करना।
कार्यक्रम के दौरान, BIS के महानिदेशक श्री प्रमोद कुमार तिवारी ने इस बात पर जोर दिया कि इन प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन मानक निर्माण गतिविधियों को बढ़ावा और समृद्ध करेगा।
कार्यक्रम की रूपरेखा और भविष्य के प्रक्षेप पथ पर विस्तृत जानकारी प्रदान करते हुए, बीआईएस के उप महानिदेशक श्री चंदन बहल ने स्पष्ट रूप से बताया कि यह साझेदारी कैसे विकसित होगी।

BIS के बारे में:

भारतीय मानक ब्यूरो भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के उपभोक्ता मामले विभाग के तहत भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है। इसकी स्थापना भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 द्वारा की गई है जो 12 अक्टूबर 2017 को लागू हुआ।
स्थापना: 23 दिसंबर 1986

संस्थापक: भारत की संसद

नवीनतम समाचार

1 जुलाई 2023 से 24 फुटवियर उत्पादों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो, BIS लाइसेंस अनिवार्य होगा।

भारतीय मानक ब्यूरो ने प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने और स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि उप-उत्पादों से बने भोजन परोसने वाले बर्तन - विशिष्टता प्रकाशित की है।

अटल इनोवेशन मिशन (AIM), नीति आयोग ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और नवर्स एडुटेक के सहयोग से राष्ट्रीय अंतरिक्ष नवाचार चुनौती 2023 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया

NSIC 2023 एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान है जिसे अगली पीढ़ी के अंतरिक्ष उत्साही लोगों को बढ़ती भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था और भविष्य के अंतरिक्ष कार्यबल को समझने और योगदान करने के लिए प्रज्वलित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

यह उद्योग जगत के नेताओं से प्रेरित होने, अन्वेषण के अवसर तलाशने और अपने नवाचार को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का एक राष्ट्रीय मंच है।

देश भर के स्कूली छात्रों के बीच नवाचार और जिज्ञासा को बढ़ावा देने के लिए, अटल इनोवेशन मिशन को देश भर के सभी स्कूली छात्रों के लिए खुले राष्ट्रीय अंतरिक्ष नवाचार चुनौती (NSIC) की घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है।

कक्षा 5 से 12 के छात्रों को 11 अगस्त से 20 सितंबर, 2023 तक एक खुला मंच दिया गया है जहां वे नवाचार कर सकते हैं और आधुनिक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी समस्याओं को हल करने में खुद को सक्षम बना सकते हैं।

छात्र (ATL और गैर-ATL स्कूलों से) लिंक -https://navarsedutech.com/nsic/ के माध्यम से नवार्स एडुटेक द्वारा कार्यान्वित स्वचालित प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रविष्टियां जमा कर सकते हैं।

प्रत्येक छात्र को अपनी रुचि और समझ के आधार पर, एक समस्या का चयन करना होगा जो चुनौती विषयों में से किसी एक के अंतर्गत आती है।

NSIC जूनियर वैज्ञानिकों (ग्रेड 5-8) और वरिष्ठ वैज्ञानिकों (ग्रेड 9-12) के लिए उद्योग संरक्षक वीडियो, संसाधनों और चुनौतियों से एकीकृत सामग्री प्रदान करता है, जिसका उपयोग छात्र अंतरिक्ष जंक संग्रह रोबोट, पुन: प्रयोज्य रॉकेट डिजाइन, उपग्रह डिजाइन, मंगल ग्रह के लिए भारतीय अंतरिक्ष यान डिजाइन आदि जैसे विभिन्न विषयों में समाधान पर एक लघु शोध रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कर सकते हैं।

14 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना बाकी है

केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल उन 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हैं, जिन्होंने अभी तक केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, जो राज्य द्वारा संचालित उच्च शिक्षा के लिए केंद्र की प्रमुख योजना के तहत अगले तीन वर्षों के लिए लगभग 13,000 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन को अनिवार्य करता है।

प्रधान मंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) बजट का 40% राज्यों द्वारा स्वयं वहन किया जाना चाहिए, और NEP सुधारों के लिए कोई अतिरिक्त धनराशि निर्धारित नहीं की गई है

राज्य विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए मंत्रालय की योजना का नया नाम PM-USHA है- पाठ्यक्रम और कार्यक्रम में बदलाव, शिक्षक प्रशिक्षण, भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे, मान्यता और रोजगार क्षमता को बढ़ाने के माध्यम से - समानता, पहुंच और समावेशन सुनिश्चित करते हुए।
यह 2023-24 और 2025-26 के बीच 12,926.10 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रदान करता है।
पीएम-उषा योजना में भाग लेने के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की इच्छा दिखाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं और इससे योजना के बेहतर कार्यान्वयन में मदद मिलेगी।

भारत ने इंडिया स्टैक साझा करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

भारत और त्रिनिदाद और टोबैगो इंडिया स्टैक को साझा करने पर एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं - खुले API और डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर पहचान, डेटा और भुगतान सेवाओं को सुविधाजनक बनाना है।
दोनों पक्ष क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान, सार्वजनिक अधिकारियों और विशेषज्ञों के आदान-प्रदान, पायलट या डेमो समाधानों के विकास आदि का उपयोग करके डिजिटल परिवर्तन के क्षेत्रों में सहयोग करने पर सहमत हुए।
यह सहयोग केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर की त्रिनिदाद और टोबैगो के डिजिटल परिवर्तन मंत्री, सीनेटर श्री हेसल बाचस से मुलाकात के बाद आया है।
बैठक के दौरान, उन्होंने आईटी, उभरती प्रौद्योगिकियों और भारत स्टैक के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की।
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन, MeitY और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
जून 2023 से, भारत ने पहले ही इंडिया स्टैक साझा करने के लिए आर्मेनिया, सिएरा लियोन, सूरीनाम और एंटीगुआ और बारबुडा जैसे देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जबकि मॉरीशस और सऊदी अरब जैसे कई देशों ने रुचि दिखाई है और इंडियास्टैक पर सहयोग को अंतिम रूप देने के उन्नत चरण में हैं।
पिछले महीने पापुआ न्यू गिनी के साथ भी इसी तरह के एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो वैश्विक स्तर पर इस पहल की बढ़ती रुचि और स्वीकृति को दर्शाता है।
UPI जो इंडिया स्टैक का भी हिस्सा है, फ्रांस, UAE, सिंगापुर और श्रीलंका में स्वीकार किया गया है।

IREDA और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन:

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के तहत मिनी रत्न (श्रेणी -1) उद्यम के रूप में वर्गीकृत भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (IREDA) ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ एक प्रदर्शन-आधारित समझौता ज्ञापन (MoU) में प्रवेश किया है।
MoU वित्त मंत्रालय के सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप है।
यह रणनीतिक लक्ष्य निर्धारित करता है जिन्हें IREDA का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान पूरा करना है।
यह समझौता ज्ञापन देश में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास और कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने के लिए IREDA और भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
निर्दिष्ट लक्ष्य और प्रदर्शन पैरामीटर नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सतत विकास प्राप्त करने की दिशा में अभियान को रेखांकित करते हैं।

राजस्व लक्ष्य: समझौता ज्ञापन के अनुरूप, भारत सरकार ने IREDA के लिए परिचालन लक्ष्यों से महत्वाकांक्षी राजस्व लक्ष्य निर्धारित किए हैं: वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ₹4,350 करोड़ और 2024-25 के लिए ₹5,220 करोड़।
यह उल्लेखनीय है कि IREDA ने पिछले वित्तीय वर्ष में परिचालन से 3,482 करोड़ रुपये का राजस्व हासिल किया था, जो 3,361 करोड़ रुपये के लक्षित आंकड़े को पार कर गया था।
प्रदर्शन पैरामीटर: MoU विभिन्न प्रमुख प्रदर्शन मापदंडों को भी रेखांकित करता है, जिसमें नेट वर्थ पर रिटर्न, नियोजित पूंजी पर रिटर्न, एनपीए से कुल ऋण अनुपात, एसेट टर्नओवर अनुपात और प्रति शेयर आय शामिल है।
हस्ताक्षर कार्यक्रम: समझौता ज्ञापन पर आधिकारिक तौर पर MNRE के सचिव श्री भूपिंदर सिंह भल्ला और IREDA के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (CMD) श्री प्रदीप कुमार दास ने हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर 21 अगस्त, 2023 को नई दिल्ली के अटल अक्षय ऊर्जा भवन में हुए। इस अवसर पर MNRE और IREDA दोनों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

NHA और IRDAI ने संयुक्त रूप से ABDM और राष्ट्रीय स्वास्थ्य दावा एक्सचेंज के साथ पूर्ण एकीकरण में मदद के लिए बीमा कंपनियों और TPA के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) और IRDAI (भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण) ने संयुक्त रूप से बीमा कंपनियों को अपने ABDM एकीकरण को पूरा करने में मदद करने और बीमा कंपनियों और तीसरे पक्ष के प्रशासकों (TPA) के लिए स्वास्थ्य दावा विनिमय (HCX) विनिर्देशों और ई-क्लेम मानकों को अपनाने की सुविधा के लिए एक विशेष तीन दिवसीय त्वरक कार्यशाला का आयोजन किया।
कार्यशाला 10 से 12 अगस्त 2023 तक नई दिल्ली में आयोजित की गई और इसमें 29 बीमा कंपनियों और 16 टीपीए का प्रतिनिधित्व करने वाले 150 से अधिक पेशेवरों ने भाग लिया।
IRDAI ने जून 2023 में एक परिपत्र जारी कर सभी बीमा कंपनियों को बीमा कवरेज चाहने वाले सभी व्यक्तियों के ABHA (आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता) नंबर को कैप्चर करना शुरू करने और ABHA के माध्यम से बीमाकर्ताओं/TPA के साथ मेडिकल रिकॉर्ड साझा करने के लिए उनकी सहमति प्राप्त करने की सलाह दी।
ABHA नंबर डिजिटल वातावरण में बीमाधारक की पहचान करने में मदद करेगा और निर्बाध स्वास्थ्य देखभाल और बीमा सेवा वितरण की सुविधा प्रदान करेगा।
इसके अलावा, IRDAI ने बीमाकर्ताओं और प्रदाताओं को राष्ट्रीय स्वास्थ्य दावा एक्सचेंज (NHCX) में शामिल होने की सलाह देते हुए एक परिपत्र भी जारी किया।
NHCX बीमाकर्ताओं, टीपीए, दावेदारों, लाभार्थियों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं आदि सहित स्वास्थ्य देखभाल और स्वास्थ्य बीमा पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूद हितधारकों के बीच दावों से संबंधित जानकारी के आदान-प्रदान के लिए एक प्रवेश द्वार के रूप में काम करेगा।
NHCX के साथ एकीकरण स्वास्थ्य दावों के प्रसंस्करण की निर्बाध अंतरसंचालनीयता को सक्षम करेगा। एनएचसीएक्स पर अधिक जानकारी यहां उपलब्ध है: https://sbxhcx.abdm.gov.in/

NHPC और राइट्स ने दिबांग बहुउद्देश्यीय परियोजना में रेलवे साइडिंग के लिए सहयोग किया:

भारत की अग्रणी जल विद्युत कंपनी NHPC लिमिटेड ने रेल मंत्रालय के तहत एक मिनीरत्न अनुसूची 'ए' केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम राइट्स के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) में प्रवेश किया है।
MoU NHPC की 2,880 मेगावाट दिबांग बहुउद्देश्यीय परियोजना का समर्थन करने के लिए पासीघाट, अरुणाचल प्रदेश में रेलवे साइडिंग के निर्माण पर केंद्रित है।

यह सहयोगात्मक प्रयास न केवल दिबांग बहुउद्देश्यीय परियोजना के बुनियादी ढांचे को बढ़ाता है बल्कि देश की वृद्धि और विकास के लिए महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को साकार करने में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के बीच साझेदारी की प्रभावशीलता को भी प्रदर्शित करता है।

साझा विशेषज्ञता: यह साझेदारी दोनों संगठनों की ताकत का लाभ उठाती है। एक कुशल परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रूप में राइट्स न केवल एनएचपीसी की दिबांग परियोजना के लिए बल्कि अरुणाचल प्रदेश में आगामी परियोजनाओं के लिए रेल बुनियादी ढांचा सुविधाओं के विकास के लिए व्यापक समाधान प्रदान करेगा।

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर: समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर फरीदाबाद में NHPC कॉर्पोरेट कार्यालय में किए गए थे। हस्ताक्षर में महाप्रबंधक (सिविल) दिबांग, राइट्स के कार्यकारी निदेशक, NHPC के निदेशक (परियोजना) श्री बिस्वजीत बसु और NHPC के कार्यकारी निदेशक (दिबांग) सहित प्रमुख हितधारकों की भागीदारी शामिल थी।

NHPC की प्रोफ़ाइल: NHPC लिमिटेड नवीकरणीय ऊर्जा में 7,097.2 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता के साथ भारत की प्रमुख जलविद्युत कंपनी है, जिसमें पवन और सौर स्रोत शामिल हैं। यह क्षमता 25 बिजली स्टेशनों में वितरित की गई है, जिसमें सहायक कंपनियों के माध्यम से उत्पन्न 1,520 मेगावाट भी शामिल है।

राइट्स लिमिटेड: राइट्स लिमिटेड, जिसे मिनीरत्न (श्रेणी-I) अनुसूची 'ए' सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया गया है, भारत में परिवहन परामर्श और इंजीनियरिंग क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह विभिन्न क्षेत्रों में फैली विविध सेवाओं का दावा करता है और इसकी व्यापक भौगोलिक पहुंच है।

NHPC लिमिटेड के बारे में:

स्थापना: 1975

मुख्यालय: फरीदाबाद, हरयाणा, भारत

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक: राजीव कुमार विश्नोई

NHPC लिमिटेड (पूर्व में नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन) भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (GoI) के स्वामित्व के तहत एक भारतीय सरकार का जल विद्युत बोर्ड है।

नवीनतम समाचार

महाराष्ट्र राज्य में पंप भंडारण योजनाओं और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत परियोजनाओं के विकास के लिए NHPC लिमिटेड और ऊर्जा विभाग, महाराष्ट्र सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

NHPC लिमिटेड भारत में सबसे बड़े जलविद्युत विकास संगठन ने "ओडिशा राज्य में पंप भंडारण परियोजनाओं (PSP) और नवीकरणीय ऊर्जा के विकास" के लिए ग्रिडको ओडिशा, ओडिशा सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

भारतीय तटरक्षक बल और फिलीपीन तटरक्षक बल ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए एक पहली बार समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और दोनों सरकारों ने इसके लिए मुलाकात की

भारत और फिलीपींस के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में, भारतीय तट रक्षक ने समुद्री सहयोग बढ़ाने पर फिलीपीन तट रक्षक (PCG) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।

समझौता ज्ञापन पर 22 अगस्त 2023 को तटरक्षक मुख्यालय, नई दिल्ली में महानिदेशक राकेश पाल, महानिदेशक भारतीय तटरक्षक और सीजी एडमिरल आर्टेमियो एम अबू, कमांडेंट, पीसीजी द्वारा हस्ताक्षर किए गए।

हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य समुद्री कानून प्रवर्तन (MLE), समुद्री खोज और बचाव (M-SAR) और समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया (MPR) के क्षेत्र में दोनों तटरक्षकों के बीच पेशेवर जुड़ाव को बढ़ाना है।

इस समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन से क्षेत्र में सुरक्षित, संरक्षित और स्वच्छ समुद्र सुनिश्चित करने के लिए दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय समुद्री सहयोग बढ़ेगा।

दोनों समुद्री एजेंसियों के बीच पहली द्विपक्षीय बैठक सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने, संयुक्त अभ्यास आयोजित करने और प्रशिक्षण सहयोग बढ़ाने के द्वारा पेशेवर संबंधों को मजबूत करने के समर्पण का प्रतीक है।
इससे पहले, प्रतिनिधिमंडल ने 21 अगस्त को गोवा का दौरा किया था, जहां उन्होंने 'आत्मनिर्भर भारत' के तहत भारतीय तटरक्षक जहाजों और विमानों की परिचालन क्षमताओं को देखा था।
यात्रा के दौरान, प्रतिनिधिमंडल को भारतीय तटरक्षक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर एमके-III पर एक ग्राहक प्रदर्शन उड़ान भी प्रदान की गई।
प्रतिनिधियों ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित भारतीय तटरक्षक जहाज सुजीत का भी दौरा किया।

ICG के बारे में:

स्थापित: फरवरी 1977
भारत की संसद के तटरक्षक अधिनियम 1978 द्वारा।
यह रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है।

नवीनतम समाचार

लोथल (गुजरात) के ऐतिहासिक सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्र में बनाए जा रहे राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (NMHC) में "भारतीय नौसेना और भारतीय तट रक्षक का विकास" विषय पर एक गैलरी की योजना, विकास, निर्माण और कमीशनिंग के लिए गांधीनगर में भारतीय तटरक्षक और भारतीय नौसेना के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और UNDP के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय ने सहयोग को औपचारिक रूप देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) ने भारत के सतत विकास लक्ष्यों (SDG) को गति देने के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (MDoNER) को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है।
इस सहयोग को एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर के माध्यम से DoNER मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय दोनों के लिए राज्य मंत्री बीएल वर्मा के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र के सहायक महासचिव और UNDP ब्यूरो ऑफ एक्सटर्नल रिलेशंस एंड एडवोकेसी (BERA) के निदेशक उलरिका मोडर की उपस्थिति में औपचारिक रूप दिया गया।
इस MoU में UNDP ने कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में MDoNER को तकनीकी सहायता प्रदान करने की प्रतिबद्धता जताई है।
इसमें SDG की दिशा में प्रगति में तेजी लाना, परियोजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन करने की क्षमता बढ़ाना और क्षमता निर्माण शामिल है।
यह साझेदारी आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों को भी सहायता प्रदान करेगी।
इसके अलावा, UNDP शासन के भीतर अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को लागू करने और सफल दृष्टिकोण का विस्तार करने में सहायता करेगा।

नवीनतम समाचार

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) ने एक स्वस्थ और लचीले महासागर के लिए समुद्री स्थानिक योजना (MSP), समुद्री संरक्षित क्षेत्रों (MPA) और नई पर्यावरणीय और सामाजिक रूप से टिकाऊ आर्थिक गतिविधियों की आकर्षक भूमिकाओं को प्रदर्शित करने के लिए 4 महासागर नवप्रवर्तकों के अपने तीसरे समूह को लॉन्च किया।
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) ने एक सहयोगात्मक साझेदारी में प्रवेश किया, जिसका उद्देश्य महिलाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में अच्छी तरह से सूचित करियर विकल्प चुनने के लिए सशक्त बनाना है।

UNDP के बारे में:

स्थापना: 22 नवंबर 1965
मुख्यालय: न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका
प्रशासक: अचिम स्टीनर
UNDP संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जिसे देशों को गरीबी को खत्म करने और सतत आर्थिक विकास और मानव विकास प्राप्त करने में मदद करने का काम सौंपा गया है।
इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र विस्तारित तकनीकी सहायता कार्यक्रम (EPTA) और विशेष कोष के विलय के साथ की गई थी।

ऑस्ट्रेलियाई सरकार के सहयोग से कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने "स्वास्थ्य कार्यबल प्रशिक्षण और कौशल मार्गों को बढ़ाने" पर एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया

भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार के सहयोग से 21 अगस्त, 2023 को नई दिल्ली में "स्वास्थ्य कार्यबल प्रशिक्षण और कौशल मार्गों को बढ़ाने" पर एक गोलमेज सम्मेलन की सफलतापूर्वक मेजबानी की।
इस विशिष्ट कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया सरकार के स्वास्थ्य और वृद्ध देखभाल मंत्री श्री मार्क बटलर सांसद के साथ-साथ भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) के सचिव श्री अतुल कुमार तिवारी की भागीदारी देखी गई।
श्री अतुल कुमार तिवारी MSDE के सचिव ने इस गोलमेज चर्चा के लिए ऑस्ट्रेलियाई मंत्री बटलर और उनकी टीम का स्वागत किया।
उन्होंने कौशल पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर वर्तमान विकास को साझा किया जहां 2021 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने शिक्षा और कौशल के बीच सामंजस्य प्रदान करने और छात्रों की क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर गतिशीलता सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा (NSQF) बनाया।
इसके अलावा, उन्होंने योग्य पेशेवरों के लिए हेल्थकेयर क्षेत्र में वैश्विक कमी की स्थिति पर प्रकाश डाला और बताया कि कैसे भारत भारत में कौशल के साथ इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए तैयार है, साथ ही पीएम श्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में भारत में 157 नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना को मंजूरी दी गई है।

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) ने नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग तथा आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुवाहाटी, असम में बांग्लादेश और अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग-2 (ब्रह्मपुत्र) और भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग (IBPR) का उपयोग करने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) और नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (NRL) के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर समारोह में भाग लिया।
MoU का उद्देश्य भारत की एक्ट ईस्ट नीति को बढ़ावा देने के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को सशक्त बनाना है।
NRL IWAI जोगीघोपा मल्टी-मोडल टर्मिनल से प्रति माह लगभग 10,000 मीट्रिक टन पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों का निर्यात करेगा।
NRL रेल कनेक्टिविटी के साथ जोगीघोपा लॉजिस्टिक्स पार्क में पीओएल ऑयल टर्मिनल स्थापित करेगा।
इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य NW2 और IBPR के माध्यम से अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन को सक्षम करके 'पूर्वोत्तर के लिए हाइड्रोकार्बन विजन 2030' को पूरा करना है, जिससे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक्जिम व्यापार का एक नया अध्याय शुरू होगा।

MoU का उद्देश्य क्षेत्र के लिए कार्गो आंदोलन में परिवर्तनकारी बदलाव लाने के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को सशक्त बनाना है।
प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गतिशील नेतृत्व में, दूरदर्शी एक्ट ईस्ट नीति हाइड्रोकार्बन विजन 2030 की पूर्ण क्षमता को अनलॉक करने की दिशा में पूर्वोत्तर भारत को सशक्त बना रही है।
इससे पहले, NRL और IWAI ने राष्ट्रीय जलमार्गों का उपयोग करके समुद्री मार्ग के माध्यम से ओडीसी और ओडब्ल्यूसी के परिवहन के लिए 26 अगस्त, 2021 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। इस तरह की पहली खेप इस साल जून में नुमालीगढ़ के पास एक घाट पर प्राप्त हुई थी।

NHPC और एपीजेनको ने आंध्र प्रदेश में पंप स्टोरेज जलविद्युत परियोजनाओं और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए हाथ मिलाया

भारत की प्रमुख जल विद्युत कंपनी NHPC लिमिटेड ने आंध्र प्रदेश राज्य में पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजनाओं और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आंध्र प्रदेश पावर जनरेशन कॉरपोरेशन (APGENCO) लिमिटेड (आंध्र प्रदेश सरकार का एक उपक्रम) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
पहले चरण में, MoU में 1,950 मेगावाट की कुल क्षमता के साथ दो पहचाने गए पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजनाओं के कार्यान्वयन की परिकल्पना की गई है।
ये परियोजनाएँ कमलापाडु (950 मेगावाट) और यागंती (1,000 मेगावाट) हैं।
इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन से रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर पैदा होने और क्षेत्र में स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
परियोजनाओं को संयुक्त उद्यम मोड के तहत कार्यान्वित किया जाएगा।
23 अगस्त 2023 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी की उपस्थिति में ताडेपल्ली, गुंटूर, आंध्र प्रदेश में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
समझौते पर NHPC के निदेशक (वित्त), श्री आरपी गोयल और प्रबंध निदेशक, एपीजेनको, श्री KVN चक्रधर बाबू ने दोनों संगठनों के अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

भारत और ग्रीस 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने और रणनीतिक स्तर तक अपनी साझेदारी बढ़ाने के लिए एक समझौते पर पहुंच गए हैं।

भारत और ग्रीस ने 2030 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने की योजना बनाई है, प्रधान मंत्री मोदी ने देश की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान घोषणा की।
2022-23 में द्विपक्षीय व्यापार लगभग 2 बिलियन डॉलर रहा।
40 वर्षों के बाद ग्रीस की पहली प्रधान मंत्री स्तरीय यात्रा में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और ग्रीक प्रधान मंत्री क्यारीकोस मित्सोटाकिस ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया, 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का वादा किया और जल्द ही एक प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की।
40 साल के अंतराल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली ग्रीस यात्रा है।
भारत अन्य चीजों के अलावा ग्रीस को मुख्य रूप से एल्यूमीनियम, कार्बनिक रसायन, मछली और क्रस्टेशियंस और लोहा और इस्पात का निर्यात करता है।

इस बीच, भारत को ग्रीस का शीर्ष निर्यात खनिज ईंधन, खनिज तेल और उत्पाद, सल्फर और एल्यूमीनियम फ़ॉइल हैं।
दोनों पक्ष दोनों देशों के बीच लोगों और प्रतिभा के प्रवाह में सुधार के लिए एक प्रवासन और गतिशीलता समझौते पर भी हस्ताक्षर करेंगे। मिंट ने अगस्त में इस विकास पर रिपोर्ट दी थी।
दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को "रणनीतिक साझेदारी" के स्तर तक बढ़ाने पर भी सहमत हुए।

नवाचार आधारित हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए IIT बॉम्बे ने HSBC के साथ साझेदारी की

IIT बॉम्बे ने ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को अधिक कुशल, लागत प्रभावी और स्केलेबल बनाने की दिशा में तकनीकी प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए HSBC के साथ भागीदारी की है।
मीडिया विज्ञप्ति के अनुसार, संयुक्त पहल का ध्यान नवीन परियोजनाओं पर होगा जो हरित हाइड्रोजन को रणनीतिक वैकल्पिक ईंधन के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा; एक मजबूत, हरित हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था के निर्माण में मदद करना और ऊर्जा-स्वतंत्र राष्ट्र के सरकार के दृष्टिकोण को प्राप्त करना।
यह साझेदारी सरकार के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को बढ़ावा देने में मदद करेगी जो हरित हाइड्रोजन संक्रमण में वैश्विक नेतृत्व हासिल करने की दिशा में नीतिगत सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है।
इस सहयोग के बारे में बोलते हुए, आईआईटी बॉम्बे के निदेशक, प्रोफेसर सुभासिस चौधरी ने कहा कि ऊर्जा के टिकाऊ और स्वच्छ स्रोतों की ओर बढ़ना जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम है। ग्रीन हाइड्रोजन - परिवहन सहित उद्योगों में अपने अनुप्रयोगों के साथ - वैश्विक ऊर्जा में एक महत्वपूर्ण स्थान पर कब्जा कर लेगा।
श्री हितेंद्र दवे, CEO, HSBC भारत ने कहा कि स्थिरता हमारे व्यवसाय, संचालन और सामुदायिक निवेश का एक प्रमुख तत्व है।

HSBC बैंक इंडिया के बारे में:

भारत में निगमित: 1 जनवरी 1983
मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र, भारत
CEO: हितेंद्र दवे

दीनदयाल पोर्ट, डीपी वर्ल्ड ने मेगा-कंटेनर टर्मिनल के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए

दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी और डीपी वर्ल्ड नई दिल्ली में बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल की उपस्थिति में एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
इस परियोजना में मौजूदा दीनदयाल बंदरगाह के पास टूना-टेकरा में सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से 4,243 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से एक मेगा-कंटेनर टर्मिनल का निर्माण शामिल है।
एक बार पूरा होने पर टर्मिनल की वार्षिक क्षमता 2.19 मिलियन बीस-फुट समकक्ष इकाइयों (TEU) की होगी और इसमें 1,100 मीटर की बर्थ शामिल होगी जो 18,000 से अधिक TEU ले जाने वाले अगली पीढ़ी के जहाजों को संभालने में सक्षम होगी।
यह रियायत समझौता ग्लोबल मैरीटाइम समिट 2023 से पहले भारतीय समुद्री क्षेत्र में 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के अवसरों की पहचान करने के श्री सोनोवाल के लक्ष्य का हिस्सा है।

नवीनतम समाचार

केन्द्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग तथा आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम के डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी (राष्ट्रीय जलमार्ग 2) के तट पर डिब्रूगढ़ के बोगीबील में विकसित किए जाने वाले अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन (IWT) टर्मिनल की आधारशिला रखी।

केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग और आयुष मंत्री, श्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट (GIMS), 2023 का उद्घाटन किया।
केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग और आयुष मंत्री, श्री सर्बानंद सोनोवाल ने 75 ऐतिहासिक लाइटहाउसों को पर्यटन स्थलों में बदलने के लिए एक अभियान शुरू किया, जब उन्होंने द्वारका, गोपनाथ और वेरावल में तीन संशोधित लाइटहाउसों का उद्घाटन किया, जिन्हें द्वारका, गुजरात में पर्यटन स्थलों के रूप में बदल दिया गया था।

नीति आयोग और UNDP ने फास्ट-ट्रैकिंग SDG पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

NITI आयोग और UNDP इंडिया ने SDG स्थानीयकरण, डेटा-संचालित निगरानी, आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों सहित कई क्षेत्रों में सहयोग के ढांचे को औपचारिक रूप देने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।
नीति आयोग के CEO श्री बीवीआर सुब्रमण्यम की उपस्थिति में नीति आयोग के वरिष्ठ सलाहकार (SDG) डॉ. योगेश सूरी और UNDP इंडिया की स्थानीय प्रतिनिधि सुश्री शोको नोडा ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
समझौता ज्ञापन पर 5 साल की अवधि के लिए हस्ताक्षर किए गए थे।
नीति आयोग राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तर पर एसडीजी को अपनाने और निगरानी के समन्वय के लिए नोडल मंत्रालय है।
UNDP संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर SDG पर तेजी से प्रगति के प्रयासों के समन्वय में एकीकरणकर्ता की भूमिका निभाता है।

नवीनतम समाचार

8नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में न्यू कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया था।
2020-21 के कोविड वर्ष के लिए नीति आयोग के वार्षिक 'राज्य स्वास्थ्य सूचकांक' (5 वें संस्करण) के अनुसार, 3 दक्षिणी राज्य केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना 'बड़े राज्यों' में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों के रूप में उभरे हैं।
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और कृषि-तकनीक में विशेषज्ञता वाली अग्रणी बायोसाइंस कंपनी एब्सोल्यूट फूड्स ने भारत सरकार की प्रमुख प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) को मजबूत करने और किसानों की लचीलापन बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।

नीति आयोग के बारे में

गठित: 1 जनवरी 2015
मुख्यालय: नई दिल्ली
अध्यक्ष: नरेंद्र मोदी

UNDP के बारे में:

स्थापना: 22 नवंबर 1965
मुख्यालय: न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका
प्रशासक: अचिम स्टीनर
UNDP संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जिसे देशों को गरीबी को खत्म करने और सतत आर्थिक विकास और मानव विकास प्राप्त करने में मदद करने का काम सौंपा गया है।
इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र विस्तारित तकनीकी सहायता कार्यक्रम (EPTA) और विशेष कोष के विलय के साथ की गई थी।

भारत और न्यूजीलैंड ने नागरिक उड्डयन में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

भारत सरकार और न्यूजीलैंड सरकार ने नागरिक उड्डयन में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।

इसमें नए मार्गों का निर्धारण, कोड शेयर सेवाएं, यातायात अधिकार और क्षमता पात्रता शामिल होगी।
भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया और व्यापार और निर्यात विकास मंत्री, कृषि मंत्री, जैव सुरक्षा मंत्री, भूमि सूचना मंत्री और न्यूजीलैंड के ग्रामीण समुदाय मंत्री श्री डेमियन ओ'कॉनर की उपस्थिति में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव श्री राजीव बंसल और न्यूजीलैंड के उच्चायुक्त श्री डेविड पाइन ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

मुख्य विचार:

1 मई 2016 को ऑकलैंड में न्यूजीलैंड और भारत के बीच एक हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
न्यूजीलैंड सरकार और भारत सरकार ने दोनों देशों के बीच हवाई सेवा से संबंधित मौजूदा व्यवस्थाओं की समीक्षा की है।
हस्ताक्षरित MoU से दोनों देशों के बीच नागरिक उड्डयन में द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
समझौता ज्ञापन के अनुसार, न्यूजीलैंड की नामित एयरलाइन (एयरलाइन्स) भारत में 6 बिंदुओं, अर्थात् नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता से तीसरे और चौथे स्वतंत्रता यातायात अधिकारों के साथ किसी भी प्रकार के विमान के साथ किसी भी संख्या में सेवाएं संचालित कर सकती हैं।

नवीनतम समाचार

न्यूजीलैंड पतली प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है जो सुपरमार्केट ग्राहक अपने फल और सब्जियों को इकट्ठा करने के लिए उपयोग करते हैं।
नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा) के वैज्ञानिक गुब्बारा कार्यक्रम ने पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में 100 दिनों या उससे अधिक की उड़ान के उद्देश्य से एक प्रौद्योगिकी मिशन पर न्यूजीलैंड के वानाका हवाई अड्डे से दूसरा फुटबॉल-स्टेडियम के आकार का, भारी-लिफ्ट सुपर प्रेशर बैलून (SPB) लॉन्च किया है।

न्यूज़ीलैंड के बारे में:

प्रधान मंत्री: क्रिस हिप्किंस
राजधानी: वेलिंग्टन
मुद्रा: डॉलर

पुरस्कार और सम्मान

इस्पात मंत्रालय ने राष्ट्रीय धातुकर्म पुरस्कार-2023 के लिए उद्योग अनुसंधान और शिक्षा जगत के व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं

इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार ने संचालन, अनुसंधान और विकास, अपशिष्ट प्रबंधन और ऊर्जा संरक्षण को कवर करते हुए धातुकर्म क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए राष्ट्रीय धातुकर्म पुरस्कार 2023 प्रदान किए।
मेटलर्जिस्ट अवार्ड्स (NMA) - 2023 के लिए उद्योग अनुसंधान और शिक्षा जगत के व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

राष्ट्रीय धातुकर्मी पुरस्कार योजना का उद्देश्य

NMA योजना विनिर्माण, अनुसंधान, डिजाइन, शिक्षा, अपशिष्ट प्रबंधन और ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्रों को कवर करने वाले लौह और इस्पात क्षेत्र में काम करने वाले धातुकर्मियों के उत्कृष्ट योगदान और आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्यों को प्राप्त करने में उनके विशिष्ट योगदान को मान्यता देती है।

पुरस्कार निम्नलिखित चार श्रेणियों में दिए जाएंगे:-

लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार
राष्ट्रीय धातुकर्मी पुरस्कार
युवा धातुकर्मी पुरस्कार

पर्यावरण
धातु विज्ञान
लौह एवं इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिए पुरस्कार
राष्ट्रीय मेटलर्जिस्ट पुरस्कारों से संबंधित पात्रता मानदंड और अन्य नियम और शर्तों के बारे में दिशानिर्देश उपरोक्त वेबसाइट लिंक पर भी उपलब्ध हैं।
यह योजना केवल उन भारतीय नागरिकों के लिए है जिन्होंने उद्योग, अनुसंधान एवं विकास या शिक्षा क्षेत्र में अपने काम के माध्यम से भारत में धातु विज्ञान के क्षेत्र में योगदान दिया है।
उम्मीदवार की पात्रता पर 01/01/2023 से विचार किया जाएगा।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्वर्ण पुरस्कार जीतने के लिए NCRB की NAFIS टीम की सराहना की

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) के डिजिटल परिवर्तन श्रेणी -1 के लिए सरकारी प्रक्रिया पुनर्रचना में उत्कृष्टता के तहत स्वर्ण पुरस्कार जीतने के लिए एनसीआरबी की राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली (NAFIS) की टीम की सराहना की।
नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम (NAFIS) ने कुशल प्रशासन के चमकदार उदाहरण के रूप में अपनी पहचान बनाई है क्योंकि इसने श्रेणी-1 में DAPRG का स्वर्ण पुरस्कार जीता है।
ई-गवर्नेंस प्रदान करने में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सुरक्षित भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए, एक फुल-प्रूफ फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली बनाने में पूरी NAFIS टीम के समर्पण की मान्यता है।
गृह मंत्रालय की विज्ञप्ति में कहा गया है कि NAFIS ने अपराधियों की उंगलियों के निशान का एक केंद्रीय डेटाबेस बनाया है, जिसे सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों के उपयोगकर्ताओं द्वारा एक्सेस किया जा सकता है।
इसके परिणामस्वरूप आपराधिक पहचान और जांच प्रक्रिया की दक्षता और प्रभावशीलता में गुणात्मक सुधार हुआ है।

राष्ट्रपति ने भारतीय तटरक्षक कर्मियों के लिए एक राष्ट्रपति तटरक्षक पदक और पांच तटरक्षक पदक को मंजूरी दी

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर विशिष्ट वीरता, कर्तव्य के प्रति असाधारण समर्पण और विशिष्ट/सराहनीय सेवा के लिए भारतीय तटरक्षक कर्मियों को एक राष्ट्रपति तटरक्षक पदक (PTM) और पांच तटरक्षक पदक (TM) प्रदान करने की मंजूरी दी है।
कर्मियों की सूची इस प्रकार है:
राष्ट्रपति तटरक्षक पदक (विशिष्ट सेवा)
आईजी मनोज वसंत बाडकर, टीएम
तटरक्षक पदक (वीरता)
कमांडेंट (जेजी) अनुराग शुक्ला
सुलतान सिंह
तटरक्षक पदक (सराहनीय सेवा)
मनोज भाटिया
केआर दीपक कुमार
देवब्रत कुमार मिश्र
ये पुरस्कार 26 जनवरी 1990 से हर साल गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय तटरक्षक बल के कर्मियों को दिए जाते हैं।

राष्ट्रपति ने सशस्त्र बलों और CAPF कर्मियों को नौ मरणोपरांत सहित 76 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस 2023 पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए 76 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दे दी है।

इनमें चार कीर्ति चक्र (मरणोपरांत), पांच मरणोपरांत सहित 11 शौर्य चक्र, दो बार टू सेना पदक (वीरता), 52 सेना पदक (वीरता), तीन नौसेना पदक (वीरता) और चार वायु सेना पदक (वीरता) शामिल हैं।

राष्ट्रपति ने सेना के लिए 30 मेंशन-इन-डिस्पैच को भी मंजूरी दे दी है, जिसमें सेना के कुत्ते मधु (मरणोपरांत) और वायु सेना कर्मियों के लिए एक को विभिन्न सैन्य अभियानों में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए मंजूरी दी गई है।

ऑपरेशन में ऑपरेशन रक्षक, ऑपरेशन स्नो लेपर्ड, ऑपरेशन कैजुअल्टी इवैक्यूएशन, ऑपरेशन माउंट चोमो, ऑपरेशन पंगसौ पास, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन ऑर्किड, ऑपरेशन कालीशम वैली, रेस्क्यू ऑपरेशन और ऑपरेशन इवैक्यूएशन शामिल हैं।

वयोवृद्ध उद्यमी पद्म विभूषण रतन टाटा को उद्योग क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए महाराष्ट्र सरकार का उद्घाटन 'उद्योग रत्न' पुरस्कार मिला, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा प्रदान किया गया

महाराष्ट्र सरकार का पहला 'उद्योग रत्न' पुरस्कार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा अनुभवी उद्यमी पद्म विभूषण आर अतन टाटा को प्रदान किया गया।

पुरस्कार समारोह मुंबई के कोलाबा में रतन टाटा के आवास पर हुआ, जिसमें उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस और अजीत पवार, उद्योग मंत्री उदय सामंत और शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर की उपस्थिति थी।

पुरस्कार विवरण:

'उद्योग रत्न पुरस्कार उद्योग क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है।

यह पुरस्कार राष्ट्रीय और वैश्विक दोनों औद्योगिक क्षेत्रों पर रतन टाटा के उल्लेखनीय प्रभाव का प्रतीक है।

नमक से लेकर वाहन और विमान तक टाटा समूह के उत्पादों की विविध श्रृंखला को विश्वास और औद्योगिक उत्कृष्टता के प्रतीक के रूप में उजागर किया गया था।

पुरस्कार में 25 लाख रुपये का नकद पुरस्कार, एक बैज और सम्मान प्रमाण पत्र शामिल था।

यह प्रस्तुति रतन टाटा के घर पर हुई क्योंकि उनकी स्वास्थ्य स्थिति के कारण उन्हें आधिकारिक पुरस्कार समारोह में भाग लेने से रोक दिया गया था।

मुख्य विशेषताएं:

कार्यक्रम के दौरान राज्य के उद्योग और विकास परियोजनाओं के बारे में चर्चा हुई।

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के औद्योगिक विकास में योगदानकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए 'महाराष्ट्र उद्योग पुरस्कार' पुरस्कार शुरू किए।

उद्योग मित्र पुरस्कार, उद्योगिनी पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ मराठी उद्यमी पुरस्कार सहित विभिन्न श्रेणियों के पुरस्कारों की घोषणा की गई।

अगले दिन अलग पुरस्कार समारोह निर्धारित किया गया था, जिसमें राज्यपाल रमेश बैस पुरस्कार प्रदान करने वाले थे।

पल्लाथुरुथी बोट क्लब ने नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का 69वां संस्करण जीता

केरल के अलप्पुझा जिले में पुन्नामादा झील पर आयोजित नेहरू ट्रॉफी बोट रेस के 69वें संस्करण में पल्लाथुरुथी बोट क्लब द्वारा संचालित वीयापुरम चुंदन (स्नेक बोट) ने जीत हासिल की।
यह क्लब की लगातार चौथी जीत है, जिसने 2018, 2019 और 2022 में ट्रॉफी जीती थी।
कोविड 19 महामारी के कारण 2020 और 2021 में दौड़ आयोजित नहीं की गई थी।
देश के पहले प्रधानमंत्री के नाम पर आयोजित इस नौका दौड़ में 70 से अधिक नौकाओं ने भाग लिया।

स्वतंत्रता दिवस, 2023 के अवसर पर 954 पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया

स्वतंत्रता दिवस, 2023 के अवसर पर कुल 954 पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है।
वीरता के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक (PPMG) से 01 CRPF कर्मियों को, वीरता के लिए पुलिस पदक (PMG) से 229 को सम्मानित किया गया है, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक (PPM) से 82 को सम्मानित किया गया है और सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक (PM) 642 को प्रदान किया गया है।
230 वीरता पुरस्कारों में से अधिकांश में, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के 125 कर्मियों, जम्मू और कश्मीर क्षेत्र के 71 कर्मियों और उत्तर पूर्व क्षेत्र के 11 कर्मियों को उनकी वीरतापूर्ण कार्रवाई के लिए सम्मानित किया जा रहा है।
वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले कर्मियों में 28 CRPF से, 33 महाराष्ट्र से, 55 जम्मू-कश्मीर पुलिस से, 24 छत्तीसगढ़ से, 22 तेलंगाना से और 18 आंध्र प्रदेश से हैं, शेष अन्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और CAPF से हैं।
राष्ट्रपति का वीरता के लिए पुलिस पदक (PPMG) और वीरता के लिए पुलिस पदक (PMG) जीवन और संपत्ति को बचाने, या अपराध को रोकने या अपराधियों को गिरफ्तार करने में विशिष्ट वीरता के आधार पर प्रदान किया जाता है।
विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक (PPM) पुलिस सेवा में एक विशेष प्रतिष्ठित रिकॉर्ड के लिए प्रदान किया जाता है और सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक (पीएम) संसाधन और कर्तव्य के प्रति समर्पण की विशेषता वाली मूल्यवान सेवा के लिए प्रदान किया जाता है।

वर्ष 2021 के लिए 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा; रॉकेट्री: द नंबी इफेक्ट को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला

69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की जूरी ने वर्ष 2021 के विजेताओं की घोषणा की।
जूरी में भारतीय सिने-जगत के प्रख्यात फिल्म निर्माता और फिल्मी हस्तियाँ शामिल थीं।

फिल्म का शीर्षक	पुरस्कारी
रॉकेट्री: द नंबी इफ़ेक्ट (हिंदी)	**निर्माता:** रॉकेट्री एंटरटेनमेंट LLP **निदेशक:** आर माधवन
मेप्पाडियन (उपर्युक्त व्यक्ति) (मलयालम)	**निर्माता**: उन्नी मुकुंदन फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड **निदेशक:** विष्णु मोहन
RRR (तेलुगु)	**निर्माता:** डीवीवी एंटरटेनमेंट्स एलएलपी **निदेशक:** एसएस राजामौली
कश्मीर फाइल्स (हिंदी)	**निर्माता:** ज़ी स्टूडियोज़ लिमिटेड **निदेशक:** विवेक रंजन अग्निहोत्री
अनुनाद- द रेजोनेंस	**निर्माता:** असम राज्य फिल्म निगम लिमिटेड

Click Here to Subscribe Our Yearly Mock Test Package

(असमिया)	**निदेशक:** रीमा बोरा
आवासव्यूहम् (मलयालम)	**निर्माता:** कृष्णंद फिल्म्स **निदेशक:** कृषंड
गांधी एंड कंपनी (गुजराती)	**निर्माता:** एमडी मीडिया कॉर्पोरेशन **निदेशक:** मनीष सैनी
गोदावरी (द होली वॉटर) (मराठी)	**निदेशक:** निखिल महाजन
पुष्पा (द राइज पार्ट I) (तेलुगु)	**मुख्य अभिनेता:** अल्लू अर्जुन
गंगूबाई काठियावाड़ी (हिन्दी) 2. मिमी (हिन्दी)	**मुख्य अभिनेत्री:** आलिया भट्ट **मुख्य अभिनेत्री:** कृति सेनन
मिमी (हिन्दी)	**सहायक अभिनेता:** पंकज त्रिपाठी
कश्मीर फाइल्स (हिंदी)	**सहायक अभिनेत्री:** पल्लवी जोशी
लास्ट फ़िल्म शो (छेल्लो शो) (गुजराती)	**बाल कलाकार:** भाविन रबारी
RRR (तेलुगु)	**गायक:** कालभैरव (गीत: कोमुराम भीमुडो)
इराविन निज़ल (रात की छाया) (तमिल)	**गायक:** श्रेया घोषाल (गीत: मयावा चयावा)
सरदार उधम (हिंदी)	**कैमरामैन:** अविक मुखोपाध्याय
नयट्टु (द हंट) (मलयालम) गंगूबाई काठियावाड़ी (हिंदी) गंगूबाई काठियावाड़ी (हिंदी)	**पटकथा लेखक (मूल):** शाही कबीर **पटकथा लेखक (अनुकूलित):** संजय लीला भंसाली और उत्कर्षिनी वशिष्ठ **संवाद लेखक:** उत्कर्षिनी वशिष्ठ और प्रकाश कपाड़िया
चविट्टू (मलयालम)	**सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन साउंड रिकॉर्डिस्ट (लोकेशन/सिंक साउंड):** अरुण अशोक और सोनू केपी

झिल्ली (डिस्कॉर्डेस) (बंगाली) सरदार उधम (हिंदी)	**ध्वनि डिजाइनर:** अनीश बसु **पुन: रिकॉर्डिंग (अंतिम मिश्रण):** सिनॉय जोसेफ
गंगूबाई काठियावाड़ी (हिंदी)	**संपादक:** संजय लीला भंसाली
सरदार उधम (हिंदी)	**प्रोडक्शन डिजाइनर:** दिमित्री मलिक और मानसी ध्रुव मेहता
सरदार उधम (हिंदी)	**पोशाक बनाने वाला:** वीरा कपूर ई
गंगूबाई काठियावाड़ी (हिंदी)	**मेकअप कलाकार:** प्रीतिशील सिंह डिसूजा
पुष्पा (द राइज पार्ट I) (तेलुगु) RRR (तेलुगु)	**संगीत निर्देशक (गीत):** देवी श्री प्रसाद **संगीत निर्देशक (पृष्ठभूमि स्कोर):** एमएम केरावनी
कोंडा पोलम (तेलुगु)	**गीतकार:** चैंद्रबोस (गीत : ढम ढम ढम)
शेरशाह	**निदेशक:** विष्णु वर्धन
RRR (तेलुगु)	**विशेष प्रभाव निर्माता:**वी श्रीनिवास मोहन
RRR (तेलुगु)	**कोरियोग्राफर:** प्रेम रक्षित
RRR (तेलुगु)	**स्टंट कोरियोग्राफर:** राजा सोलोमन
अनुर (आईज ऑन द सनशाइन)	**निर्माता:** गोपेन्द्र मोहन दास **निदेशक:**मोंजुल बरुआ
कल्कोक्खो - हाउस ऑफ़ टाइम	**निर्माता:** ऑरोरा फिल्म कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड **निदेशक:** राजदीप पॉल और सर्मिष्ठा मैती
सरदार उधम (हिंदी)	**निर्माता:** किनो एलएलपी काम करता है **निदेशक:** सुजीत सरकार
लास्ट फ़िल्म शो (छेल्लो शो)	**निर्माता:** जुगाड़ मोशन पिक्चर्स **निदेशक:** पैन नलिन

777 चार्ली	**निर्माता:** परमवाह स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड **निदेशक:** किरणराज के
समानान्तर (द पैरेलल)	**निर्माता:** अनिरति फिल्म्स **निदेशक:**-नीरज कुमार मिश्रा
एकदा काय जाला	**निर्माता:** गजवदना शोबॉक्स LLP **निदेशक:** सलिल श्रीनिवास कुलकर्णी
होम	**निर्माता**: फ्राइडे फिल्म हाउस प्रा.लि. **निदेशक:** रोजिन.पी.थॉमस
इखोइगी यम (आवर होम)	**निर्माता:** चिंगसुबम शीतल **निदेशक:** मयांग्लाम्बम रोमी मेइतेई
प्रत्यक्ष (द वेट)	**निर्माता:** अमिया पटनायक प्रोक्यूशन **निदेशक:** अनुपम पटनायक
कदैसी विवासयि (द लास्ट फार्मर)	**निर्माता:** जनजातीय कला **निदेशक:** एम. मणिकंदन

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में अपर सचिव सुश्री नीरजा शेखर की उपस्थिति में फीचर फिल्म जूरी के अध्यक्ष श्री केतन मेहता, गैर-फीचर फिल्म जूरी के अध्यक्ष श्री वसंत एस साई, सिनेमा जूरी पर सर्वश्रेष्ठ लेखन श्री यतींद्र मिश्रा ने पुरस्कारों की घोषणा की।

सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार रॉकेट्री: द नांबी इफेक्ट को दिया गया है और सर्वश्रेष्ठ गैर-फीचर फिल्म का पुरस्कार सृष्टि लखेरा द्वारा निर्देशित एक था गांव को दिया गया है।

द कश्मीर फाइल्स को राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जबकि आरआरआर को संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार मिला है।

सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का पुरस्कार:

पुस्तक का शीर्षक	भाषा	लेखक का नाम	प्रकाशक का नाम
लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत: अविश्वसनीय मधुर यात्रा	अंग्रेज़ी	राजीव विजयकर	रूपा पब्लिकेशंस इंडिया प्रा. लिमिटेड

पीएम मोदी ग्रीक सरकार द्वारा 'द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर' से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी सरकार प्रमुख बन गए

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीस सरकार द्वारा 'द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर' से सम्मानित होने वाले सरकार के पहले विदेशी प्रमुख बन गए हैं।

यह सम्मान प्रधानमंत्री मोदी की ग्रीस की आधिकारिक यात्रा के दौरान दिया गया

प्रधान मंत्री मोदी की ग्रीस यात्रा पर एथेंस में मीडिया को संबोधित करते हुए, विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कहा कि पुरस्कार के साथ प्रशस्ति पत्र भारत की आर्थिक प्रगति और समृद्धि के साथ-साथ ग्रीस के साथ द्विपक्षीय संबंधों की मित्रता को बढ़ावा देने में प्रधान मंत्री के योगदान को मान्यता देता है।

श्री क्वात्रा ने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का असाधारण गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया और ग्रीक प्रधान मंत्री के साथ चर्चा व्यापक रही और इसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण और उत्पादक परिणाम सामने आए।

ग्रीस के बारे में:

अध्यक्ष: कतेरीना सकेलारोपोलू

प्रधान मंत्री: क्यारीकोस मित्सोटाकिस

पूंजी: एथेंस

मुद्रा: यूरो

नवीनतम समाचार

ग्रीस की रूढ़िवादी न्यू डेमोक्रेसी (ND) पार्टी के प्रमुख क्यारीकोस मित्सोटाकिस राष्ट्रीय चुनाव जीता और ग्रीस के प्रधान मंत्री (पीएम) के रूप में दूसरा चार साल का कार्यकाल हासिल किया।

पंचायती राज मंत्रालय की स्वामित्व योजना ने ई-गवर्नेंस 2023 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता

पंचायती राज मंत्रालय की स्वामित्व (ग्रामीण आबादी का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण) योजना ने नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग के लिए ई-गवर्नेंस 2023 (गोल्ड) के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता।

यह टीम स्वामित्व द्वारा किए गए उत्कृष्ट और अनुकरणीय कार्य की मान्यता है और टीम NIC-MOPR द्वारा समर्थित है। प्रौद्योगिकी बहुत तेजी से विकसित हो रही है और शासन सुधारों के साथ प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने की पहल ने परिणाम देना शुरू कर दिया है, स्वामित्व योजना के तहत प्रौद्योगिकी के उपयोग ने नागरिक-केंद्रित शासन को काफी सुविधाजनक बनाया है और ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यापक ग्राम योजना बनाने में मदद की है।

प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से, स्वामित्व योजना ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करने, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की वित्तीय स्थिरता में सुधार करने और ग्रामीण भारत में जीवन को बदलने में सफल रही है।

समाचार में आवेदन

IAS अधिकारी लोकेश एम ने नोएडा प्राधिकरण के CEO का पदभार संभाला

2005 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी लोकेश एम ने रितु माहेश्वरी से नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) का पदभार संभाला।

इस बीच, भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के 2003 बैच के अधिकारी माहेश्वरी, IAS अधिकारी आलोक गुप्ता की जगह आगरा के मंडलायुक्त के रूप में शामिल होंगे, जो कानपुर के मंडलायुक्त के रूप में शामिल होंगे।

लोकेश एम के बारे में:

वह 2009 से 2016 तक मैनपुरी, कुशीनगर, एटा, ग़ाज़ीपुर, अमरोहा और कौशांबी जिलों के जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर थे। वह 2016 से 2021 तक कर्नाटक में प्रतिनियुक्ति पर थे, जिसके बाद 31 मई, 2023 को आगरा आयुक्त के रूप में तैनात होने से पहले उन्हें सहारनपुर का मंडलायुक्त बनाया गया था।

नोएडा प्राधिकरण के CEO के रूप में शामिल होने से पहले, उन्होंने कानपुर आयुक्त के रूप में कार्य किया।

आशीष देसाई ने केरल उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली

न्यायमूर्ति आशीष जे.देसाई केरल उच्च न्यायालय के 38वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।
केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राजभवन में आयोजित एक समारोह में नए मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ दिलाई।
वह न्यायमूर्ति एसवी भट्टी का स्थान लेंगे जिन्हें हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत किया गया था।
केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होने से पहले, न्यायमूर्ति देसाई गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे।

भारतीय-अमेरिकी नीति विशेषज्ञ निशा बिस्वाल को US DFC का नया उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया

संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट ने भारतीय-अमेरिकी नीति विशेषज्ञ और व्यवसायी महिला निशा देसाई बिस्वाल को अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम (DFC) के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पुष्टि की।
मार्च 2023 में, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने DFC के डिप्टी सीईओ के रूप में बिस्वाल के नामांकन की घोषणा की थी।

निशा देसाई बिस्वाल के बारे में:

बिस्वाल के पास अमेरिकी विदेश नीति और कार्यकारी शाखा, कांग्रेस और निजी क्षेत्र के भीतर अंतर्राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों में 30 वर्षों से अधिक का अनुभव है।
उन्होंने 2013 से 2017 तक अमेरिकी विदेश विभाग में दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के सहायक सचिव के रूप में कार्य किया और वह इस पद को संभालने वाली पहली दक्षिण-एशियाई अमेरिकी थीं।
वह स्वैच्छिक विदेशी सहायता पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करती हैं और नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट और यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस इंटरनेशनल एडवाइजरी काउंसिल दोनों के बोर्ड में हैं।
उन्होंने यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (USAID) में एशिया के लिए सहायक प्रशासक के रूप में भी काम किया है, जो दक्षिण, मध्य और दक्षिण पूर्व एशिया में संस्था के कार्यक्रमों और संचालन का निर्देशन और पर्यवेक्षण करती है।
बिस्वाल वर्तमान में यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स में अंतर्राष्ट्रीय रणनीति और वैश्विक पहल के लिए वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर हैं, और यूएस-इंडिया बिजनेस काउंसिल और यूएस-बांग्लादेश बिजनेस काउंसिल की देखरेख करते हैं।

पुरस्कार एवं सम्मान:

बिस्वाल को जनवरी 2017 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रतिष्ठित सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के बारे में:

स्थापना: 20 दिसंबर, 2019
मुख्यालय: वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका
CEO: स्कॉट नाथन
यह संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय सरकार की एक विकास वित्त संस्था और एजेंसी है।
इसका गठन ओवरसीज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन (OPIC) को यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (USAID) के डेवलपमेंट क्रेडिट अथॉरिटी (DCA) के साथ-साथ कई अन्य छोटे कार्यालयों और फंडों के साथ विलय करके किया गया था।

प्रोफेसर गणेशन कन्नाबीरन को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया

राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (NAAC) ने शिक्षाविद् प्रोफेसर गणेशन कन्नाबिरन को 5 वर्षों के लिए अपना नया निदेशक नियुक्त किया है।

गणेशन कन्नाबिरन के बारे में:

प्रोफेसर कन्नाबिरन राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT), तिरुचिरापल्ली में सूचना प्रणाली के वरिष्ठ प्रोफेसर हैं, और उन्होंने 30 से अधिक वर्षों तक शिक्षा क्षेत्र में सेवा की है।

वह अनुसंधान और परामर्श के डीन और NIT त्रिची और NIT पुडुचेरी के प्रभारी निदेशक भी थे।

वह 2018 से 2023 तक भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, आंध्र प्रदेश के संस्थापक निदेशक भी थे।

इस दौरान उन्होंने संस्थान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण योगदान दिया और पड़ोसी गांवों को गोद लेने को बढ़ावा दिया।

उन्होंने कंप्यूटर-आधारित शिक्षा, उद्योग 4.0, उद्यमिता विकास, लैंगिक समानता और डेटा गोपनीयता सहित अन्य क्षेत्रों में परियोजनाएं चलायी हैं।

NAAC के बारे में:

स्थापित: 1994

मुख्यालय: बैंगलोर, कर्नाटक, भारत

NAAC भारत में एक सरकारी संगठन है जो उच्च शिक्षा संस्थानों (HEIs) का आकलन और मान्यता देता है।

यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्त पोषित एक स्वायत्त निकाय है।

NAAC मूल्यांकन के परिणामस्वरूप संस्थान को 'A++' (उच्चतम) से लेकर 'C' (निम्नतम) तक ग्रेड दिया जाता है।

जो संस्थान न्यूनतम मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं उन्हें 'गैर-मान्यता प्राप्त' दर्जा प्राप्त होता है।

शिवेंद्र नाथ को इंजीनियरिंग परियोजनाओं के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया

1994 बैच के प्रतिष्ठित IAS अधिकारी शिवेंद्र नाथ को प्रतिष्ठित सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड (PSEB) पैनल द्वारा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड (EPIL) में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए चुना गया है, जो भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के तत्वावधान में काम करने वाला एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (PSU) है।

भूमिकायें और उत्तरदायित्व:

अपनी नई भूमिका में, नाथ कंपनी के मुख्य कार्यकारी होंगे और बोर्ड और निदेशकों के अधीन काम करेंगे।

वह संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कंपनी के सुचारू कामकाज के लिए जिम्मेदार होगा।

वर्तमान में, वह भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) में वरिष्ठ महाप्रबंधक के पद पर हैं, जो दूरसंचार विभाग के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम भी है।

PSEB के बारे में:

PSEB को सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (PSE) में अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक और कार्यात्मक निदेशक सहित प्रमुख कर्मियों की पहचान करने और नियुक्त करने के साथ-साथ निर्दिष्ट अन्य निर्दिष्ट स्तरों पर पदों की पहचान करने और नियुक्त करने का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है।
बोर्ड उपरोक्त स्तरों पर कर्मियों के लिए नियुक्तियों, पुष्टिकरण, कार्यकाल के विस्तार और सेवाओं की समाप्ति से संबंधित मामलों के संबंध में सरकार को सलाहकार सेवाएं भी प्रदान करता है।

इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (EIL) के बारे में:

स्थापना: 1965
मुख्यालय: नयी दिल्ली
EIL एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की इंजीनियरिंग परामर्श और प्रौद्योगिकी लाइसेंसिंग कंपनी है।

उद्देश्य:

हाइड्रोकार्बन परियोजनाओं में स्वदेशी प्रौद्योगिकी समाधान प्रदान करना

भारतीय-अमेरिकी शोहिनी सिन्हा को साल्ट लेक सिटी में FBI की विशेष एजेंट प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया

भारतीय-अमेरिकी शोहिनी सिन्हा FBI निदेशक क्रिस्टोफर रे द्वारा यूटा राज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका (US) में साल्ट लेक सिटी फील्ड कार्यालय के प्रभारी संघीय जांच ब्यूरो (FBI) के विशेष एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया है।
वह प्रसिद्ध वेस्टमिंस्टर एब्बे में प्रतिष्ठित राज्याभिषेक समारोह से गुजरने वाली चालीसवीं संप्रभु बन गईं।

शोहिनी सिन्हा के बारे में:

सिन्हा ने एक चिकित्सक के रूप में और बाद में इंडियाना के लाफायेट में एक निजी, गैर-लाभकारी क्लिनिक में प्रशासक के रूप में काम किया।
वह 2001 में एक विशेष एजेंट के रूप में FBI में शामिल हुईं।
उन्हें सबसे पहले मिल्वौकी फील्ड ऑफिस में नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने आतंकवाद विरोधी जांच में काम किया।
उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के सम्मान में, उन्हें 2009 में पर्यवेक्षी विशेष एजेंट के रूप में पदोन्नति मिली और उन्हें वाशिंगटन, डीसी में आतंकवाद विरोधी प्रभाग में स्थानांतरित कर दिया गया।
हाल ही में, उन्होंने वाशिंगटन डीसी में FBI मुख्यालय में निदेशक के कार्यकारी विशेष सहायक के रूप में कार्य किया

FBI के बारे में:

मुख्यालय: वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका
FBI संयुक्त राज्य अमेरिका की घरेलू खुफिया और सुरक्षा सेवा और इसकी प्रमुख संघीय कानून प्रवर्तन एजेंसी है।

MFIN ने उदय कुमार हेब्बार को अध्यक्ष, मनोज नांबियार को उपाध्यक्ष चुना

माइक्रोफाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क (MFIN), माइक्रोफाइनेंस उद्योग के लिए प्रमुख संघ और RBI द्वारा मान्यता प्राप्त स्व-नियामक संगठन (SRO) ने दिल्ली में अपनी 14वीं वार्षिक आम बैठक (AGM) में उदय कुमार हेब्बर को अध्यक्ष और मनोज कुमार नांबियार को संगठन का उपाध्यक्ष चुना।
हेब्बर ने अपना कार्यकाल पूरा होने पर फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक (MD) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) देवेश सचदेव से पदभार संभाला, जबकि नांबियार ने सत्या माइक्रोकैपिटल लिमिटेड के MD और CEO विवेक तिवारी से पदभार संभाला।

उदय कुमार हेब्बार क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड के MD और CEO हैं जबकि मनोज कुमार नांबियार आरोहण फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के MD हैं।

MFIN के बारे में:

स्थापित: 2009

मुख्यालय: गुरुग्राम, हरियाणा, भारत

CEO और निदेशक: आलोक मिश्रा

MFIN एक प्रमुख उद्योग संघ है जिसमें 55 NBFC-MFI और बैंक, लघु वित्त बैंक (SFB) और NBFC सहित 44 सहयोगी शामिल हैं।

कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को एक साल का और विस्तार मिला

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (ACC) ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के लिए 30 अगस्त, 2023 के बाद एक वर्ष की अवधि के लिए सेवा विस्तार को मंजूरी दे दी है।

गौबा के लिए यह तीसरा विस्तार है, जो अब देश में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले कैबिनेट सचिव बन जाएंगे।

यह विस्तार AIS (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1958 और मौलिक नियमों के नियम 56 (डी) में छूट देते हुए दिया गया था।

गौबा के बारे में:

पंजाब जन्मे गौबा 2016 में केंद्र सरकार में लौटने से पहले 15 महीने तक झारखंड के मुख्य सचिव थे।

उन्हें व्यापक रूप से जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के पीछे प्रमुख वास्तुकार के रूप में पहचाना जाता है। इस अधिनियम ने संविधान के अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

उन्होंने केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय में सचिव और गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में भी काम किया था, जहां वे अन्य चीजों के अलावा महत्वपूर्ण वामपंथी उग्रवाद प्रभाग के प्रभारी थे।

पूर्व केंद्रीय गृह सचिव गौबा को 2019 में दो साल के लिए देश की सर्वोच्च प्रशासनिक नौकरी पर नियुक्त किया गया था। उन्हें 2021 में एक साल का विस्तार दिया गया, उसके बाद अगस्त, 2023 में एक और साल का विस्तार दिया गया।

गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को 22 अगस्त 2024 तक एक साल का विस्तार मिला

केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को 22 अगस्त 2024 तक एक साल का विस्तार दिया गया है।

कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने उनके विस्तार को मंजूरी दे दी है

उनका कार्यकाल 22 अगस्त को ख़त्म होने वाला था

अजय कुमार भल्ला के बारे में

असम-मेघालय कैडर के 1984 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी भल्ला को अगस्त 2019 में गृह सचिव नियुक्त किया गया था।

उन्हें 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद नवंबर 2020 में सेवानिवृत्त होना था।

उनका कार्यकाल पहली बार 17 अक्टूबर, 2020 को 22 अगस्त, 2021 तक बढ़ाया गया था।

कम्बोडियन राजा नोरोडोम सिहामोनी ने हुन मैनेट को कंबोडिया का नया प्रधान मंत्री नियुक्त किया

कंबोडिया के राजा नोरोदोम सिहामोनी ने पूर्व प्रधानमंत्री हुन सेन के बेटे हुन मानेट को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है।
राजा द्वारा एक शाही फरमान जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि वह संसद के 7वें जनादेश के लिए डॉ हुन मैनेट को सीए कंबोडिया साम्राज्य के प्रधान मंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं।
जबकि राजा ने हुन मानेट को प्रधान मंत्री नियुक्त किया है, नेता और उनके मंत्रिमंडल को पद ग्रहण करने के लिए 22 अगस्त को विश्वास मत जीतना होगा।
कंबोडियन चुनाव 2023 के दौरान, हुन सेन की पार्टी - कंबोडियन पीपुल्स पार्टी - ने भारी जीत हासिल की।
उनकी जीत के कुछ दिनों बाद, पूर्व प्रधान मंत्री हुन सेन ने घोषणा की कि वह 1998 में पद संभालने के बाद प्रधान मंत्री के रूप में पद छोड़ देंगे।

टेस्ला ने भारतीय मूल के वैभव तनेजा को अपना नया CFO नियुक्त किया है

टेस्ला ने वैभव तनेजा को अपना नया मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया।
45 वर्षीय व्यक्ति इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी के मुख्य लेखा अधिकारी (CAO) के रूप में अपनी भूमिका के अलावा, नया पद संभालेंगे, जिसे 'मास्टर ऑफ कॉइन' भी कहा जाता है।
ज़ाचरी किरखोर्न, जो पहले इस पद पर थे, के पद छोड़ने के बाद वैभव तनेजा को नए CFO के रूप में घोषित किया गया था।
तनेजा की नियुक्ति ऐसे समय हुई है जब एलन मस्क की टेस्ला भारतीय बाजार में पैर जमाने की कोशिश कर रही है।
कंपनी ने हाल ही में पुणे में अपना पहला कार्यालय स्थान पट्टे पर लिया है।
इससे पहले, 45 वर्षीय व्यक्ति अपने लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार, जुलाई 1999 और मार्च 2016 के बीच भारत और अमेरिका दोनों में प्राइसवाटरहाउसकूपर्स में कार्यरत थे।
उनके पास प्रौद्योगिकी, खुदरा और दूरसंचार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ काम करने का 17 वर्षों से अधिक का अनुभव है।

कमांडर (पूर्वी समुद्री तट) एस परमेश को अतिरिक्त महानिदेशक तटरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया

कमांडर (पूर्वी समुद्री तट) एस परमेश को भारतीय तटरक्षक मुख्यालय, नई दिल्ली में अतिरिक्त महानिदेशक तटरक्षक बल के रूप में नियुक्त किया गया है।
अतिरिक्त महानिदेशक तटरक्षक बल बनने से पहले फ्लैग ऑफिसर तटरक्षक क्षेत्र (पूर्व), तटरक्षक क्षेत्र (पश्चिम) और तटरक्षक कमांडर (पूर्वी समुद्री तट) के शीर्ष पर थे।
फ्लैग ऑफिसर नेशनल डिफेंस कॉलेज, नई दिल्ली और डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन के पूर्व छात्र हैं।
फ्लैग ऑफिसर नेविगेशन और डायरेक्शन में विशेषज्ञ हैं और उनके समुद्री कमांड में ICG के सभी प्रमुख जहाज शामिल हैं जिनमें उन्नत ऑफशोर पेट्रोल वेसल समर और ऑफशोर पेट्रोल वेसल विश्वस्त शामिल हैं।
उनके प्रमुख स्टाफ कार्यों में उप महानिदेशक (संचालन और तटीय सुरक्षा), तटरक्षक मुख्यालय, नई दिल्ली में प्रधान निदेशक (संचालन), और तटरक्षक क्षेत्रीय मुख्यालय (पूर्व), चेन्नई में मुख्य कर्मचारी अधिकारी (संचालन) शामिल हैं।
वह विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के तटरक्षक पदक, तटरक्षक पदक के प्राप्तकर्ता हैं और उन्हें 2012 में महानिदेशक तटरक्षक प्रशस्ति और 2009 में FOCINC (पूर्व) प्रशस्ति से भी सम्मानित किया गया था।

सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे, सैंडहर्स्ट अकादमी में 201वीं सॉवरेन परेड की समीक्षा करने के लिए यूनाइटेड किंगडम के लिए रवाना हुए

सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे संप्रभु प्रतिनिधि के रूप में प्रतिष्ठित रॉयल मिलिट्री एकेड, सैंडहर्स्ट में 201 वें सॉवरेन परेड ऑफ कमीशनिंग कोर्स 223 की समीक्षा करने के लिए यूनाइटेड किंगडम के लिए रवाना हुए।
रॉयल मिलिट्री अकादमी सैंडहर्स्ट में सॉवरेन परेड एक प्रतिष्ठित कार्यक्रम है, जो अपने शानदार इतिहास और दुनिया भर से अधिकारी कैडेटों के पास होने के लिए जाना जाता है।
जनरल मनोज पांडे परेड के लिए संप्रभु प्रतिनिधि होने वाले भारत के पहले सेना प्रमुख हैं।
अपनी यात्रा के दौरान, जनरल भारतीय सेना स्मारक कक्ष का भी दौरा करेंगे, जो रॉयल मिलिट्री अकादमी में गौरव का स्थान रखता है।
अपनी यूके यात्रा के दौरान, जनरल मनोज पांडे ब्रिटिश सेना के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल सर पैट्रिक सैंडर्स और यूके सशस्त्र बलों के वाइस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल ग्विन जेनकिंस से बातचीत करेंगे।

न्यायमूर्ति सुभासिस तलपात्रा ने उड़ीसा उच्च न्यायालय के 33वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली

न्यायमूर्ति सुभासिस तालापात्रा ने उड़ीसा उच्च न्यायालय के 33वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।
ओडिशा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल ने उन्हें शपथ दिलाई।
न्यायमूर्ति तालापात्रा, जो उड़ीसा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे, ने न्यायमूर्ति डॉ. एस मुरलीधर की सेवानिवृत्ति के बाद उनका स्थान लिया।
मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति तालापात्रा के नाम की सिफारिश पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की थी जिसे बाद में केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी थी।

भारत सरकार ने आर दोराईस्वामी को LIC का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया

भारत सरकार (GoI) ने आर दुरईस्वामी को 1 सितंबर 2023 को या उसके बाद पद ग्रहण करने की तारीख से और 31 अगस्त 2026 को उनकी सेवानिवृत्ति तक, या अगले निर्देशों तक, जो भी पहले हो, भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के प्रबंध निदेशक (MD) के रूप में नियुक्त किया है।
उन्हें आईपे मिनी की जगह LIC का MD नियुक्त किया गया है।
दोरईस्वामी वर्तमान में मुंबई में केंद्रीय कार्यालय के कार्यकारी निदेशक हैं।
वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (FSIB), जो राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए निदेशकों की भर्ती करता है, ने जून, 2023 में दोरईस्वामी को एमडी के रूप में प्रस्तावित किया।

FSIB के बारे में:

FSIB 2022 में केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय सेवा विभाग के तहत स्थापित एक सरकारी निकाय है।
इसने बैंक बोर्ड ब्यूरो (BBB) का स्थान ले लिया।
भानु प्रताप शर्मा, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DOPT) के पूर्व सचिव, FSIB का नेतृत्व करते हैं।
इसे राज्य संचालित वित्तीय सेवाओं/सार्वजनिक क्षेत्र संगठन के निदेशकों और गैर-कार्यकारी अध्यक्ष की पूर्णकालिक नियुक्ति और संस्थान में कार्मिक प्रबंधन से संबंधित अन्य मामलों पर सिफारिशें करने का काम सौंपा गया है।

LIC के बारे में:

स्थापना: 1956
मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र
अध्यक्ष: सिद्धार्थ मोहंती

वर्तमान MD: आईपे मिनी, एम जगन्नाथ, तबलेश पांडे, सत पाल भानु

कमलेश वार्ष्णेय और अमरजीत सिंह को SEBI का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने दो नए पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त किए हैं।
सरकार ने कमलेश चंद्र वार्ष्णेय और अमरजीत सिंह को पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है।
घोषणा के अनुसार, उनकी नियुक्ति जिम्मेदारी संभालने की तारीख से तीन साल या भविष्य के आदेशों तक, जो भी पहले आए, वैध होगी।
वार्ष्णेय वर्तमान में राजस्व विभाग में संयुक्त सचिव हैं, और सिंह सेबी के कार्यकारी निदेशक हैं।
सेबी में अब दो पूर्णकालिक सदस्य, अश्वनी भाटिया और अनंत नारायण जी, और चार अंशकालिक सदस्य, अजय सेठ, मनोज गोविल, एम. राजेश्वर राव और डॉ. वी. रवि अंशुमान हैं।
माधबी पुरी बुच, जिन्होंने 2 मार्च 2022 को अध्यक्ष का पद संभाला, बोर्ड की अध्यक्षता करती हैं।
बुच ने 4 अक्टूबर 2021 तक सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्य किया।
वह बाजार विनियमन, बाजार मध्यस्थों के विनियमन और पर्यवेक्षण, एकीकृत निगरानी, निवेश प्रबंधन, आर्थिक और नीति विश्लेषण विभाग, निवेशक सहायता और शिक्षा कार्यालय, राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान और सूचना प्रौद्योगिकी विभागों की प्रभारी थीं।

एक्सिस बैंक के नीलकंठ मिश्रा को UIDAI का अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया

नीलकंठ मिश्रा को कथित तौर पर केंद्र सरकार ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है, जो आधार संख्या जारी करने के प्रभारी नोडल निकाय हैं।
वह एक्सिस बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री और एक्सिस कैपिटल में वैश्विक अनुसंधान के प्रमुख हैं
इस बीच, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक नीलेश शाह और IIT दिल्ली में कंप्यूटर विज्ञान विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर प्रोफेसर मौसम को अंशकालिक UIDAI सदस्यों के रूप में नामित किया गया है।
तीन नियुक्तियाँ तीन वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, के लिए हैं।
मिश्रा, जिन्हें अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है, ने क्रेडिट सुइस में दो दशक से अधिक समय बिताने के बाद मई 2023 में एक्सिस बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री और वैश्विक अनुसंधान के प्रमुख का पद संभाला, जहां उन्होंने एपीएसी रणनीति, इंडिया इक्विटी रणनीति और भारत अनुसंधान प्रमुख के सह-प्रमुख के रूप में कार्य किया।

मिश्रा के बारे में:

उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), कानपुर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की।
वह कई सरकारी समितियों के सलाहकार रहे हैं और 15वें वित्त आयोग की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य भी रहे हैं।
इसके अलावा, रिपोर्ट के अनुसार, वह सरकार की उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं के भी प्रबल समर्थक रहे हैं।

UIDAI के बारे में:

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) एक वैधानिक प्राधिकरण है जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत भारत सरकार द्वारा 12 जुलाई, 2016 को आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 (आधार अधिनियम 2016) के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया है।

आधार अधिनियम 2016 को 25 जुलाई, 2019 से आधार और अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का 14) द्वारा संशोधित किया गया है।

एक्सिस बैंक के बारे में:

पूर्व नाम: UTI बैंक
स्थापना: 1993
मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र
टैगलाइन: बढ़ती का नाम जिंदगी
MD और CEO: अमिताभ चौधरी

SBI प्रमुख दिनेश खारा को 10 महीने का विस्तार मिलने की संभावना है

SBI के चेयरमैन दिनेश खारा को अगस्त 2024 तक विस्तार मिलने की संभावना है, जिससे उन्हें पद पर लगभग एक और साल मिल जाएगा क्योंकि उनका वर्तमान कार्यकाल अक्टूबर में समाप्त होना है।
मौजूदा नियमों के तहत, एसबीआई चेयरमैन को 63 साल तक का कार्यकाल दिया जाता है, लेकिन खारा अगले अगस्त में इस उम्र तक पहुंच जाएंगे।
ऐसे अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रमुख हैं जिन्हें सेवानिवृत्ति की आयु से कई महीने दूर होने के बावजूद कार्यालय में अतिरिक्त समय नहीं दिया गया।
अश्विनी कुमार तिवारी, MD के रूप में जिनका कार्यकाल जनवरी, 2024 में समाप्त होने वाला है, उन्हें भी नौकरी पर दो साल और मिलने की संभावना है।

SBI के बारे में:

स्थापित: 1 जुलाई, 1955
मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र

दक्षिण एशिया और भारत के लिए सिटी डीलमेकिंग प्रमुख रवि कपूर सेवानिवृत्त हो गए

सिटीग्रुप ने कहा कि रवि कपूर अमेरिकी बैंक में 18 साल तक काम करने के बाद दक्षिण एशिया और भारत के लिए बैंकिंग, पूंजी बाजार और सलाहकार (BCMA) के प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त होंगे।
के बालासुब्रमण्यम, वर्तमान में सिटी इंडिया के कॉर्पोरेट बैंक के प्रमुख, कपूर की भूमिका निभाएंगे।
कपूर, जो पिछले साल सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंच गए थे, लेकिन सिटी के अनुरोध पर अपनी भूमिका में बने रहे, "पेशेवर और उद्यमशीलता के अवसरों के बारे में सक्रिय रूप से सोच रहे हैं।

सिटी बैंक के बारे में:

स्थापित: 1812
मुख्यालय: न्यूयॉर्क, हम
CEO: सुनील गर्ग
अध्यक्ष: बारबरा डेसोएर

श्रेथा थाविसिन वोट जीतकर थाईलैंड की 30वीं प्रधानमंत्री बनीं

फू थाई पार्टी (PTP) के पूर्व रियल एस्टेट टाइकून श्रेथा थाविसिन को थाईलैंड के 30वें प्रधान मंत्री के रूप में चुना गया है, वे प्रयुथ चान-ओचा की जगह लेंगे, जिन्होंने जुलाई 2022 में राजनीति से संन्यास ले लिया था।

चुनाव परिणाम:

705 सांसदों और सीनेटरों की संयुक्त भागीदारी के साथ, श्रेथा थाविसिन के लिए अंतिम वोट पक्ष में 482, विरोध में 165 और 81 अनुपस्थित थे।

पक्ष में पड़े 482 वोटों में से 330 संसद सदस्यों (सांसदों) के थे और 152 सीनेटरों के थे।

उनके ख़िलाफ़ पड़े 164 वोटों में से 152 सांसदों के और 12 सीनेटरों के थे।

81 अनुपस्थित रहने वालों में 13 सांसद और 68 सीनेटर शामिल थे।

श्रेथा थाविसिन के बारे में:

स्रेथा थाविसिन का जन्म 15 फरवरी 1962 को बैंकॉक, थाईलैंड में हुआ था।

रियल एस्टेट क्षेत्र में जाने से पहले, उन्होंने उपभोक्ता सामान की दिग्गज कंपनी P&G थाईलैंड में सहायक उत्पाद प्रबंधक के रूप में अपना करियर शुरू किया।

श्रेथा रियल एस्टेट डेवलपर संसिरी PLC के पूर्व अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी हैं, जो थाईलैंड की दूसरी सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है।

थाईलैंड के बारे में:

राजधानी: बैंकॉक

मुद्रा: थाई बात (THB)

एक्सिस बैंक के नीलकंठ मिश्रा को UIDAI का अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया

नीलकंठ मिश्र एक्सिस बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री और एक्सिस कैपिटल में वैश्विक अनुसंधान के प्रमुख को आधार जारी करने वाली संस्था भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।

अध्यक्ष और सदस्य अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि तक या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, सेवा करेंगे।

मिश्रा UIDAI के चौथे अध्यक्ष और नोडल प्राधिकरण में शीर्ष पद पर नियुक्त होने वाले दूसरे गैर-नौकरशाह हैं।

UIDAI के पहले अध्यक्ष, नंदन नीलेकणि, एकमात्र अन्य गैर-नौकरशाह थे, जिन्होंने अपने 4 साल से अधिक के कार्यकाल के दौरान इस संस्था का नेतृत्व किया था, जिसे उन्होंने मार्च, 2014 में छोड़ दिया था।

अन्य नियुक्तियाँ:

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) के प्रबंध निदेशक नीलेश शाह और कंप्यूटर विज्ञान के एसोसिएट प्रोफेसर और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), दिल्ली में यार्डी स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के संस्थापक मौसम को UIDAI बोर्ड के अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया है।

नीलकंठ मिश्रा के बारे में:

मिश्रा कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट के प्रबंध निदेशक (MD) हैं।

एक्सिस बैंक से पहले, उन्होंने ज्यूरिख स्थित क्रेडिट सुइस में दो दशकों तक काम किया, जहां उनकी भूमिकाओं में APAC रणनीति के सह-प्रमुख, भारत इक्विटी रणनीति प्रमुख और भारत के अनुसंधान प्रमुख शामिल थे।

मिश्रा अब 15वें वित्त आयोग की सलाहकार परिषद के सदस्य, प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति (PM-EAC) के अंशकालिक सदस्य और भारत सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में भी कार्य करते हैं।)

नवीनतम समाचार:

जून 2023 में, 1993 बैच के IAS अधिकारी अमित अग्रवाल ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के रूप में कार्यभार संभाला।

UIDAI के बारे में:

UIDAI एक वैधानिक प्राधिकरण है जिसे 12 जुलाई 2016 को भारत सरकार द्वारा MeitY के तहत आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं की लक्षित डिलीवरी) अधिनियम, 2016 (आधार अधिनियम 2016) के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया है।

मुख्यालय: नई दिल्ली, दिल्ली

UIDAI को भारत के सभी निवासियों को विशिष्ट पहचान संख्या (UID) जारी करने के लिए बनाया गया था, जिसे "आधार" नाम दिया गया था।

प्राधिकरण में एक अध्यक्ष, दो अंशकालिक सदस्य और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) शामिल हैं, जो प्राधिकरण के सदस्य-सचिव भी हैं।

टेनिस आइकन राफेल नडाल इंफोसिस के ब्रांड एंबेसडर हैं

इंफोसिस ने टेनिस आइकन राफेल नडाल को इंफोसिस ब्रांड और इसके डिजिटल इनोवेशन के लिए एक राजदूत के रूप में शामिल किया है।

ATP (एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स) टूर, रोलैंड-गैरोस, ऑस्ट्रेलियन ओपन और द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए डिजिटल इनोवेशन पार्टनर के रूप में, ब्रांड इंफोसिस ने एआई, क्लाउड, डेटा एनालिटिक्स और डिजिटल अनुभवों का लाभ उठाते हुए वैश्विक स्तर पर एक अरब प्रशंसकों के लिए टेनिस पारिस्थितिकी तंत्र को फिर से तैयार करने में मदद की है।

इसमें दावा किया गया है कि इन्फोसिस ने प्रशिक्षण में क्रांति लाने के लिए खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के लिए वीडियो और सांख्यिकी विश्लेषण प्लेटफार्मों का बीड़ा उठाया है, प्रसारकों के लिए आकर्षक सामग्री पोस्ट करने के लिए एआई-सहायक पत्रकारिता प्लेटफार्मों के साथ मैच विश्लेषण को मजबूत किया है और प्रशंसकों के लिए खेल से जुड़ने के नए तरीके पेश किए हैं।

इन्फोसिस ने एक अरब वैश्विक प्रशंसकों के लिए टेनिस अनुभव को बदल दिया है और वास्तव में दौरे पर सभी खिलाड़ियों को विश्लेषण के साथ सशक्त बनाया है, जिसका वे कुछ साल पहले केवल सपना देख सकते थे।

टाटा कैपिटल ने शुबमन गिल को अपना ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया है

टाटा कैपिटल, टाटा समूह के तहत एक प्रमुख वित्तीय सेवा इकाई ने एक होनहार युवा क्रिकेट प्रतिभा शुबमन गिल को अपने ब्रांड एंबेसडर के रूप में चुनने की घोषणा की है।

यह रणनीतिक कदम भारत की विविध और गतिशील युवा आबादी की सेवा करने के लिए टाटा कैपिटल की प्रतिबद्धता के साथ शुबमन गिल की महत्वाकांक्षी छवि के संरेखण को उजागर करता है।

टाटा कैपिटल भारत की सबसे बड़ी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) में से एक है, जो ऋण और धन प्रबंधन उत्पादों की एक विविध श्रृंखला द्वारा समर्थित है और ग्राहक क्षेत्रों में काम कर रही है।

न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में शपथ ली

कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (CJ) न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

इसके बाद निवर्तमान कार्यवाहक अध्यक्ष न्यायमूर्ति शेओ कुमार सिंह आए।

न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव के बारे में:

न्यायमूर्ति श्रीवास्तव को 18 जनवरी, 2008 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया और 15 जनवरी, 2010 को स्थायी न्यायाधीश बने।

वह 11 अक्टूबर, 2021 से 30 मार्च, 2023 तक कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे।

केंद्र सरकार भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के परामर्श से NGT के अध्यक्ष की नियुक्ति करती है।

स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक हिस्सा माना गया है।

नवीनतम समाचार:

जुलाई, 2023 में, केंद्र ने न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की सेवानिवृत्ति के बाद न्यायमूर्ति शेओ कुमार सिंह को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया था।

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) के बारे में:

स्थापित: 2010 (के तहत)राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम2010 में)

मुख्यालय: नई दिल्ली, दिल्ली

NGT भारत में एक वैधानिक निकाय है जो पर्यावरण संरक्षण और अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान से संबंधित है।

ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद भारत पर्यावरण संरक्षण के लिए एक वैधानिक निकाय स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश है।

कार्तिक आर्यन डाबर रेड बा फ्रेश जेल का नया चेहरा हैं

भारतीय बहुराष्ट्रीय उपभोक्ता सामान कंपनी, डाबर इंडिया लिमिटेड ने अपने नए लॉन्च किए गए जेल टूथपेस्ट- डाबर रेड बे फ्रेश जेल के चेहरे के रूप में युवा सनसनी कार्तिक आर्यन को साइन किया है।

पावरहाउस मदर ब्रांड 'डाबर रेड' का यह विस्तार, जो भारत में हर 3 में से 1 घर में मौजूद दुनिया का नंबर 1 आयुर्वेदिक टूथपेस्ट ब्रांड है, विशेष रूप से युवा भारतीय आबादी के बीच फ्रेंचाइजी पैठ को और मजबूत करेगा।

डाबर लिमिटेड के बारे में:

मुख्यालय: गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत

CEO: मोहित मल्होत्रा

अध्यक्ष: मोहित बर्मन

अमेरिका के गार्जियन लाइफ इंश्योरेंस ने शाइनी प्रसाद को कंट्री हेड नियुक्त किया है

न्यूयॉर्क स्थित दुनिया की सबसे बड़ी पारस्परिक जीवन बीमा कंपनियों में से एक, अमेरिका की गार्जियन लाइफ इंश्योरेंस ने शाइनी प्रसाद को कंट्री हेड - भारत नियुक्त किया है, जो मुख्य सूचना और संचालन अधिकारी डीन डेल वेचियो को रिपोर्ट करेंगे।

शाइनी प्रसाद के बारे में:

उन्होंने पहले सन लाइफ फाइनेंशियल, AIG, मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ, जीई कैपिटल और अमेरिकन एक्सप्रेस में काम किया है।

इस नई नियुक्ति से पहले, वह EY में इंडिया बिजनेस कंसल्टिंग पार्टनर और इंश्योरेंस सेक्टर लीडर थे।

इमर्सन मनांगाग्वा ने जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति के रूप में दूसरा कार्यकाल जीता

जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति एमर्सन मनांगाग्वा दूसरे और अंतिम 5-वर्षीय कार्यकाल (2023-2028) के लिए फिर से चुना गया।
जिम्बाब्वे चुनाव आयोग (ZEC) ने 52.6% वोट के साथ मनांगाग्वा को विजेता घोषित किया, उन्होंने सिटीजन्स कोएलिशन फॉर चेंज (CCC) के नेल्सन चामिसा को हराया, जो 44% से पीछे थे।
लंबे समय तक शासक रॉबर्ट मुगाबे को सैन्य तख्तापलट में सत्ता से हटाए जाने के 6 साल बाद यह चुनाव हुआ है।
80 वर्षीय की पार्टी ने 136 सीटों के साथ संसदीय चुनाव भी जीता, जबकि सीसीसी ने 73 सीटें हासिल कीं।

एमर्सन मनांगाग्वा के बारे में:

एमर्सन मनांगाग्वा का जन्म 15 सितंबर, 1942 को दक्षिणी रोडेशिया के शबानी में हुआ था, जिसे अब ज़विशावेन, ज़िम्बाब्वे के नाम से जाना जाता है।
वह जिम्बाब्वे अफ्रीकन नेशनल यूनियन - पैट्रियटिक फ्रंट (जेडएएनयू-पीएफ) के सदस्य हैं।
एक चतुर और क्रूर राजनेता के रूप में उनकी प्रतिष्ठा के कारण उन्हें "द क्रोकोडाइल" उपनाम मिला।

ज़िम्बाब्वे के बारे में:

अध्यक्ष: एमर्सन मनांगाग्वा
पूंजी: हरारे
मुद्रा: जिम्बाब्वे डॉलर

श्रीराम फाइनेंस के उमेश रेवनकर ने वित्त उद्योग विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला

भारत में गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (NBFC) की संपत्ति और ऋण वित्तपोषण के प्रतिनिधि निकाय, वित्त उद्योग विकास परिषद (FIDC) ने उमेश रेवनकर को 2 साल के कार्यकाल के लिए अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है।
प्रबंध समिति ने मुंबई, महाराष्ट्र में आयोजित एक बैठक के दौरान सर्वसम्मति से रेवनकर को चुना।
कमलेश गांधी एमएएस फाइनेंशियल सर्विसेज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (CMD) और प्रोफेक्टस कैपिटल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी केवी श्रीनिवासन एफआईडीसी के सह-अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

उमेश रेवनकर के बारे में:

रेवनकर 1987 में श्रीराम ग्रुप के साथ एक कार्यकारी प्रशिक्षु के रूप में शामिल हुए।
अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी को भारत में सबसे बड़ा वाणिज्यिक वाहन फाइनेंसर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
वह श्रीराम समूह के भीतर कई कंपनियों के निदेशक के रूप में भी कार्य करते हैं, जिनमें श्रीराम ऑटोमॉल इंडिया, श्रीराम जनरल इंश्योरेंस और श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस शामिल हैं।
वह वर्तमान में श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के कार्यकारी उपाध्यक्ष के पद पर हैं, और उनके पास वित्तीय सेवा उद्योग में तीन दशकों से अधिक का अनुभव और विशेषज्ञता है।

वित्त उद्योग विकास परिषद (FIDC) के बारे में:

स्थापना: 2004
मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र
महानिदेशक: महेश ठक्कर

काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को पहली महिला फील्ड निदेशक मिलेगी - सोनाली घोष

भारतीय वन सेवा अधिकारी और मुख्य वन संरक्षक डॉ सोनाली घोष 1 सितंबर, 2023 से असम में 118 साल पुराने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की पहली महिला क्षेत्र निदेशक बनने के लिए तैयार हैं।
वह जतींद्र सरमा की जगह लेंगी, जो 31 अगस्त, 2023 को सेवानिवृत्त होंगे।

काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में:

काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य के गोलाघाट और नागांव जिलों में एक राष्ट्रीय उद्यान है।
इसे 1974 में राष्ट्रीय उद्यान, 1985 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) विश्व धरोहर स्थल और 2006 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था।
4 मुख्य नदियाँ - ब्रह्मपुत्र, डिफ्लू, मोरा डिफ्लू और मोरा धनसिरी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती हैं।

डिफेन्स करेंट अफेयर्स

भारतीय सेना ब्रिगेडियर, उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों के लिए सामान्य वर्दी लागू करती है

भारतीय सेना ने मूल कैडर और नियुक्ति की परवाह किए बिना ब्रिगेडियर और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों के लिए एक सामान्य वर्दी लागू की।
हाल ही में संपन्न सेना कमांडरों के सम्मेलन के दौरान विस्तृत विचार-विमर्श और सभी हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया।

उद्देश्य:

रेजीमेंटेशन की सीमाओं से परे, वरिष्ठ नेतृत्व के बीच सेवा मामलों में आम पहचान और दृष्टिकोण को बढ़ावा देना और मजबूत करना।

मुख्य विचार:

फ्लैग रैंक (ब्रिगेडियर और उससे ऊपर) के वरिष्ठ अधिकारियों के हेडगियर, शोल्डर रैंक बैज, गोरगेट पैच, बेल्ट और जूते अब मानकीकृत और सामान्य होंगे।
ध्वज-रैंक अधिकारी अब कोई डोरी नहीं पहनेंगे।
कर्नल और उससे नीचे के रैंक के अधिकारियों द्वारा पहनी जाने वाली वर्दी में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

भारतीय सेना के बारे में:

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ: अनिल चौहान
थल सेनाध्यक्ष: मनोज पांडे

चीन और UAE की वायु सेनाएं अगस्त 2023 में पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास फाल्कन शील्ड-2023 आयोजित करेंगी

चीन और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की वायु सेनाएं अगस्त 2023 में चीन के शिनजियांग में अपना पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास फाल्कन शील्ड-2023 आयोजित करेंगी।

उद्देश्य:

दोनों सेनाओं के बीच व्यावहारिक आदान-प्रदान और सहयोग को गहरा करना और आपसी समझ और विश्वास को बढ़ाना।
प्रशिक्षण की सटीक तारीखें, दल का आकार, या प्रशिक्षण का दायरा
अभी तक ज्ञात नहीं हैं

झिंजियांग पहले भी संयुक्त सैन्य अभ्यास की मेजबानी कर चुका है।
चीन की पैदल सेना और शंघाई सहयोग संगठन ब्लॉक के अन्य सदस्यों ने 2016 में कोरला में प्रशिक्षण लिया।

चीन के बारे में:

राजधानी: बीजिंग
मुद्रा: रॅन्मिन्बी

UAE के बारे में:

अध्यक्ष : मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान
प्रधानमंत्री: मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम
राजधानी: आबू धाबी
मुद्रा: संयुक्त अरब अमीरात दिरहम

म्यांमार जुंटा ने आपातकाल की स्थिति अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दी है

म्यांमार की राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा परिषद (NDSC) के सदस्यों ने देश में आपातकाल की स्थिति और मिन आंग ह्लाइंग के नेतृत्व वाले जुंटा के कार्यकाल को अगले 6 महीने के लिए बढ़ाने का फैसला किया।
इस कदम से उन चुनावों में देरी होने की उम्मीद है जिन्हें जुंटा ने अगस्त 2023 तक कराने का वादा किया था।
आपातकाल की स्थिति को बढ़ाने के निर्णय की घोषणा कार्यवाहक राष्ट्रपति माइंट स्वे ने की।

मुख्य विचार:

म्यांमार में फरवरी 2021 में आपातकाल की घोषणा की गई थी।
म्यांमार के संविधान के अनुसार, शुरुआत में 1 वर्ष के लिए आपातकाल की घोषणा की जा सकती है और आमतौर पर NDSC के विवेक पर इसे अधिकतम दो छमाही अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।
हालाँकि, जनवरी 2023 में जुंटा प्रमुख मिन आंग ह्लाइंग ने तीसरी बार आपातकाल की घोषणा की।
उस समय जुंटा ने पहली बार संविधान का उल्लंघन किया।
यह दूसरी बार है कि जुंटा ने आपातकाल की स्थिति के संबंध में संविधान का उल्लंघन किया है।

सैन्य जुंटा के बारे में:

सैन्य जुंटा एक ऐसी सरकार है जिसका नेतृत्व सैन्य नेताओं की एक समिति करती है।
जुंटा शब्द का अर्थ है "बैठक" या "समिति"।
जुंटा अक्सर तख्तापलट के परिणामस्वरूप सत्ता में आता है, जो मौजूदा नेता को पद से हटाने का एक प्रयास है।

म्यांमार के बारे में:

अध्यक्ष: माइंट स्वे
राजधानी: नेपीडॉ
मुद्रा: क्यात

राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा सेवा थिंक टैंक सैन्य विरासत निर्देशित यात्रा का आयोजन करेगा

राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा सेवा थिंक टैंक, यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया (USI), नागरिकों के बीच देश की समृद्ध सैन्य विरासत को रोशन करने के लिए एक ऐतिहासिक सैन्य विरासत निर्देशित दौरे का आयोजन कर रहा है।
इस दौरे का पहला चरण 12 अगस्त को पंजाब के फिरोजपुर जिले के हुसैनीवाला में शुरू होने वाला है।

दौरे के लिए समर्पित एक वेबसाइट उसी दिन लॉन्च की जाएगी जहां इच्छुक व्यक्ति अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए, USI और उसके सहयोगियों ने बताया कि यह दौरा सभी आयु वर्ग के सभी भारतीय और विदेशी व्यक्तियों के लिए खुला है।
आगामी दौरों में पूरे देश में सैन्य संस्कृति को शामिल किया जाएगा, जिसमें असम, नागालैंड और मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और तवांग सर्किट, लेह, लद्दाख और कश्मीर सर्किट, लोंगेवाला सर्किट और अंडमान और निकोबार सर्किट शामिल हैं।

INS विशाखापत्तनम और INS त्रिकंद द्विपक्षीय अभ्यास के लिए दुबई पहुंचे

भारतीय नौसेना के दो जहाज, INS विशाखापत्तनम और INS त्रिकंद, UAE नौसेना के साथ द्विपक्षीय अभ्यास के लिए दुबई के पोर्ट रशीद पहुंचे।
8 से 11 अगस्त तक चलने वाले इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना और तालमेल बढ़ाना है।
रियर एडमिरल विनीत मैक्कार्टी की कमान के तहत, जहाज समुद्री संचालन पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूएई नौसेना बल के साथ पेशेवर बातचीत में संलग्न होंगे।
'ज़ायद तलवार', एक द्विपक्षीय अभ्यास, क्षेत्रीय सुरक्षा में योगदान करते हुए, दोनों नौसेनाओं के बीच अंतरसंचालनीयता और तालमेल को बढ़ाने के लिए निर्धारित है।
कैप्टन अशोक राव और प्रमोद जी थॉमस के नेतृत्व में, INS विशाखापत्तनम और INS त्रिकंद उन्नत समुद्री क्षमताओं का प्रदर्शन करते हैं।
यह यात्रा भारतीय और UAE नौसेनाओं के बीच बढ़ते राजनयिक सहयोग को रेखांकित करती है।

भारतीय और संयुक्त अरब अमीरात की नौसेनाओं ने द्विपक्षीय समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू किया

भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने संयुक्त अरब अमीरात के तट पर एक द्विपक्षीय नौसेना समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू किया है।
11 अगस्त को आयोजित होने वाले इस अभ्यास में दो भारतीय नौसेना जहाजों, INS विशाखापत्तनम और INS त्रिकंद की भागीदारी शामिल है।
8 अगस्त को पोर्ट रशीद दुबई में जहाजों के आगमन के बाद से दो दिनों में सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध इस संयुक्त प्रयास का उद्देश्य भारतीय और संयुक्त अरब अमीरात की नौसेनाओं के बीच अंतरसंचालनीयता और तालमेल को बढ़ाना, रणनीति, तकनीकों और प्रक्रियाओं पर क्रॉस-ट्रेनिंग को बढ़ावा देना है।
पश्चिमी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग रियर एडमिरल विनीत मैक्कार्टी की कमान के तहत, यह अभ्यास समुद्री चुनौतियों से संयुक्त रूप से निपटने के लिए दोनों देशों की पुष्टि पर प्रकाश डालता है।
जैसा कि रियर एडमिरल मैक्कार्टी ने संयुक्त अरब अमीरात के नौसेना बलों के उप कमांडर ब्रिगेडियर अब्दुल्ला फर्ज अल महैरबी और संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत संजय सुधीर सहित उच्च पदस्थ अधिकारियों से मुलाकात की, चर्चा में समुद्री डकैती, तस्करी का मुकाबला करने के लिए साझा प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया।
यह अभ्यास भविष्य में संभावित संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों का पता लगाने के लिए एक मंच के रूप में भी कार्य करता है।
भारतीय राजदूत ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि नौसैनिक अभ्यास के लिए इन दो जहाजों की उपस्थिति हमारे दोनों देशों के नेताओं के बीच मित्रता द्वारा निर्देशित संयुक्त अरब अमीरात के साथ हमारे बढ़ते रक्षा संबंधों का संकेत है।

Click Here to Subscribe Our Yearly Mock Test Package

INS विशाखापत्तनम, जिसकी कमान कैप्टन अशोक राव के पास है, भारतीय नौसेना के सबसे बड़े ऑपरेशनल विध्वंसकों में से एक है और यह मझगांव डॉक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित पूरी तरह से स्वदेशी युद्धपोत है।
INS त्रिकंद की कमान कैप्टन प्रमोद जी थॉमस ने संभाली, 2013 में कमीशन किया गया एक उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट है।
यह जहाज एक समसामयिक युद्धपोत है जिसमें इसे स्थिर, गुप्त, तेज और दुर्जेय बनाने के लिए इसके डिजाइन के हर पहलू में अत्याधुनिक तकनीक शामिल की गई है।

भारतीय नौसेना के स्वदेशी सीमावर्ती युद्धपोत INS सह्याद्रि और INS कोलकाता अभ्यास मालाबार 2023 में भाग लेंगे

भारतीय नौसेना के स्वदेशी फ्रंटलाइन युद्धपोत INS सह्याद्रि और INS कोलकाता अभ्यास मालाबार 2023 में भाग लेंगे।
11 दिवसीय अभ्यास सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में शुरू होगा।
रक्षा मंत्रालय ने कहा, अमेरिकी नौसेना, जापान मैरीटाइम सेल्फ-डिफेंस फोर्स और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के जहाज और विमान भी अभ्यास में भाग लेंगे।
समुद्री अभ्यास की मालाबार श्रृंखला 1992 में भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू हुई।
पिछले कुछ वर्षों में इसका कद इतना बढ़ गया है कि इसमें हिंद-प्रशांत क्षेत्र की चार प्रमुख नौसेनाएं शामिल हो गई हैं।
यह अभ्यास भारतीय नौसेना को अंतरसंचालनीयता को बढ़ाने और प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करता है और अपने साझेदार देशों से समुद्री सुरक्षा संचालन में सर्वोत्तम प्रथाओं से लाभ भी प्राप्त करता है।

पारादीप पोर्ट अथॉरिटी चालू वित्त वर्ष (2023) में 50 MMT कार्गो को संभालने वाला सबसे तेज़ प्रमुख बंदरगाह बन गया है

पारादीप पोर्ट अथॉरिटी चालू वित्त वर्ष (2023) में 50 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो को संभालने वाला सबसे तेज प्रमुख बंदरगाह बन गया है।
पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि की तुलना में इसने 6.5 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित की है।
बंदरगाह ने पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि में संभाले गए 812 जहाजों की तुलना में रिकॉर्ड 942 जहाजों को संभाला है।
पारादीप पोर्ट अथॉरिटी के अध्यक्ष पीएल हरनाध ने कहा कि समर्पित कार्यबल के अटूट समर्थन के साथ, पारादीप पोर्ट ने आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, स्थिरता और एक उज्जवल कल की कहानी का उदाहरण पेश किया है।

राष्ट्रपति मुर्मू 17 अगस्त को कोलकाता में युद्धपोत 'विंध्यगिरि' का शुभारंभ करेंगे

भारतीय नौसेना 17 अगस्त 2023 को गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (GRSE), कोलकाता, पश्चिम बंगाल (WB) में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों विंध्यगिरि का शुभारंभ करेगी, जिसका नाम कर्नाटक में एक पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है।

विंध्यगिरि युद्धपोत के बारे में:

विंध्यगिरि प्रोजेक्ट 17ए फ्रिगेट्स का छठा जहाज है।
ये युद्धपोत प्रोजेक्ट 17 क्लास फ्रिगेट्स (शिवालिक क्लास) के फॉलो-ऑन हैं, जिनमें बेहतर स्टील्थ फीचर्स, उन्नत हथियार और सेंसर और प्लेटफ़ॉर्म प्रबंधन सिस्टम हैं।
यह तकनीकी रूप से उन्नत फ्रिगेट है और अपने पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती INS विंध्यगिरि, लिएंडर क्लास ASW फ्रिगेट की विशिष्ट सेवा के लिए एक उपयुक्त श्रद्धांजलि देता है।

Click Here to Subscribe Our Yearly Mock Test Package

प्रोजेक्ट 17ए कार्यक्रम के तहत, मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) द्वारा 4 जहाज और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (GRSE) द्वारा तीन जहाज निर्माणाधीन हैं।
परियोजना के पहले 5 जहाज 2019-2022 के बीच MDL और GRSE द्वारा लॉन्च किए गए थे।
इन जहाजों को भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा इन-हाउस डिजाइन किया गया है, जो सभी युद्धपोत डिजाइन गतिविधियों के लिए अग्रणी संगठन है।
प्रोजेक्ट 17ए जहाजों के उपकरणों और प्रणालियों के लिए 75% ऑर्डर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) सहित स्वदेशी फर्मों से हैं।

पुराने INS विंध्यगिरि के बारे में:

8 जुलाई 1981 से 11 जून 2012 तक अपनी लगभग 31 वर्षों की सेवा में यह नीलगिरि वर्ग का छठा और आखिरी युद्धपोत था, इसने कई बहुराष्ट्रीय अभ्यास देखे थे और समुद्री निगरानी, तटीय गश्त और समुद्री डकैती विरोधी अभियान चलाए थे।
2011 में एक व्यापारिक जहाज के साथ दुर्घटना में क्षतिग्रस्त होने के बाद इसे सेवामुक्त कर दिया गया था।

भारतीय नौसेना के बारे में:

मुख्यालय: नई दिल्ली, दिल्ली
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ: सामान्य अनिल चौहान
नौसेना स्टाफ के प्रमुख: एडमिरल आर. हरि कुमार

राष्ट्रपति मुर्मू ने कोलकाता में देश के स्टील्थ युद्धपोत 'INS विंध्यगिरि' को लॉन्च किया

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता के किडरपोर में हुगली नदी के तट पर गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (GRSE) सुविधा में भारत के नवीनतम युद्धपोत 'INS विंध्यगिरि' का शुभारंभ किया।
कर्नाटक में पर्वत श्रृंखला के नाम पर, उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट INS विंध्यगिरि प्रोजेक्ट 17ए फ्रिगेट्स का छठा जहाज है।
अत्याधुनिक जहाज को नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित किया जाएगा और सेवा में शामिल करने के लिए भारतीय नौसेना को सौंपे जाने से पहले व्यापक परीक्षणों से गुजरना होगा।
P17A जहाज निर्देशित मिसाइल फ्रिगेट हैं
ये युद्धपोत बेहतर स्टेल्थ सुविधाओं, उन्नत हथियारों और सेंसर और प्लेटफ़ॉर्म प्रबंधन प्रणालियों के साथ शिवालिक क्लास प्रोजेक्ट 17 फ्रिगेट्स के अनुवर्ती हैं और हवा, सतह और उपसतह के सभी तीन आयामों में खतरों को बेअसर करने में सक्षम हैं।
विंध्यगिरि भारतीय नौसेना के लिए रक्षा PSU GRSE द्वारा बनाए जा रहे तीन जहाजों में से आखिरी है।
परियोजना के पहले पांच जहाज 2019 और 2022 के बीच लॉन्च किए गए थे।

BRO ने पूर्वी लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण शुरू किया

सीमा सड़क संगठन (BRO) ने पूर्वी लद्दाख में हानले के करीब दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क, लिकारू-मिगला-फुकचे सड़क का निर्माण शुरू कर दिया है।
64 किलोमीटर लंबी सड़क लिकारू को फुकचे से जोड़ेगी जो पूर्वी लद्दाख में LAC से तीन किलोमीटर दूर स्थित है।
नया उच्चतम मोटर योग्य दर्रा 19,400 फीट की ऊंचाई पर मोटर योग्य सड़क होने का एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित करेगा।
वर्तमान में, 19,024 फीट की ऊंचाई पर उमलिंगला दर्रा दुनिया का सबसे ऊंचा मोटर योग्य दर्रा है, जिसका निर्माण वर्ष 2021 में बीआरओ द्वारा किया गया है।

उमलिंगला दर्रा 52 किमी लंबी सड़क है जो चिशुमले को डेमचोक से जोड़ती है, जो एलएसी पर ठीक है, और भारत और चीन के बीच एक घर्षण बिंदु भी है।
लिकारू-मिगला-फुकचे के बीच प्रस्तावित सड़क हानले को फुकचे में सीडीएफडी सड़क से जोड़ने वाली एक धुरी प्रदान करेगी।
रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण यह सड़क मिगला से होकर गुजरेगी, जो 19400 फीट की ऊंचाई पर है।
इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए लगभग 520 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।

भारतीय नौसेना का जहाज INS विशाखापत्तनम कुवैत में तीन दिवसीय प्रवास के हिस्से के रूप में अल-शुवैख बंदरगाह पर पहुंचा

भारतीय नौसेना का जहाज INS विशाखापत्तनम कुवैत में तीन दिवसीय प्रवास के हिस्से के रूप में अल-शुवैख बंदरगाह पर रुका।
यह यात्रा न केवल नौसैनिक संबंधों को बढ़ाती है बल्कि भारत और कुवैत के बीच सांस्कृतिक और लोगों के बीच संबंधों को भी मजबूत करती है।
यह जुड़ाव आपसी सम्मान और सहयोग को दर्शाता है।
आने का उद्देश्य: भारतीय नौसेना जहाज INS विशाखापत्तनम हाल ही में भारत और कुवैत के बीच नौसैनिक सहयोग को बढ़ावा देते हुए तीन दिवसीय प्रवास के लिए कुवैत के अल-शुवैख बंदरगाह पर पहुंचा।
द्विपक्षीय सहयोग: यह यात्रा दोनों देशों के बीच नौसेना-से-नौसेना सहयोग को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो एक मजबूत साझेदारी को दर्शाता है।
सामुदायिक व्यस्तता: यह यात्रा कुवैत में भारतीय समुदाय और जहाज के चालक दल के बीच बातचीत का अवसर प्रदान करती है। प्रवास के दौरान जहाज के दौरे और चालक दल की व्यस्तताओं से सकारात्मक माहौल बनने की उम्मीद है।
राजदूत का दौरा: कुवैत में भारत के राजदूत आदर्श स्वाइका ने जहाज का दौरा किया और उन्हें रियर एडमिरल मैक्कार्थी और कैप्टन राव द्वारा इसके संचालन और उन्नत प्रणालियों के बारे में जानकारी दी गई।
योग सत्र: जहाज के चालक दल के लिए भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित योग सत्र ने शांति और सद्भाव को बढ़ावा दिया। चालक दल ने इस शांत अभ्यास को अपनाया और कल्याण और एकता में अपनी भूमिका के लिए आभार व्यक्त किया।

रक्षा संवाददाता पाठ्यक्रम - 2023 ENC, विशाखापत्तनम में शुरू हुआ

रक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मीडिया संगठनों के चुनिंदा पत्रकारों के लिए आयोजित तीन सप्ताह का पाठ्यक्रम, रक्षा संवाददाता पाठ्यक्रम (DCC) का 2023 संस्करण 21 अगस्त 2023 को पूर्वी नौसेना कमान (ENC), विशाखापत्तनम में शुरू हुआ।
वाइस एडमिरल समीर सक्सेना AVSM, एनएम चीफ ऑफ स्टाफ, ईएनसी ने उद्घाटन भाषण दिया और श्री ए भारत भूषण बाबू, प्रवक्ता (MoD) और अतिरिक्त महानिदेशक (मीडिया और संचार) ने मैरीटाइम वारफेयर सेंटर में पाठ्यक्रम की रक्षा पत्रकारिता के बारे में जानकारी दी।
DCC का उद्देश्य मीडिया और सेना को करीब लाना है और सभी स्तरों पर पत्रकारों के एक समूह को सशस्त्र बलों की बेहतर सराहना करने और समुद्री पर्यावरण से संबंधित कहानियों पर रिपोर्टिंग करते समय डोमेन के बारे में जानकारी रखने में सक्षम बनाना है।

इसरो ने कहा कि चंद्रयान-3 चंद्रमा पर 23 अगस्त के बजाय 27 अगस्त को उतरने के लिए तैयार है

इसरो के अध्यक्ष डॉ. एस. सोमनाथ ने परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात की और उन्हें चंद्रमा लैंडिंग के लिए चंद्रयान -3 की स्थिति और तैयारी के बारे में अवगत कराया।

डॉ. सोमनाथ ने कहा कि चंद्रयान-3 की सभी प्रणालियाँ पूरी तरह से काम कर रही हैं और लैंडिंग के दौरान किसी भी आकस्मिकता की आशंका नहीं है।

उन्होंने कहा, अगले दो दिनों में चंद्रयान-3 की सेहत लगातार ठीक रहेगी

निगरानी की गई

डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस बार चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग पर भरोसा जताया और उम्मीद जताई कि यह ग्रहों की खोज का एक नया इतिहास लिखेगा।

संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश होगा, लेकिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत दुनिया का एकमात्र देश होगा।

चंद्रयान-3 मिशन को जुलाई महीने की 14 तारीख को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जीएसएलवी मार्क 3 (LVM 3) हेवी-लिफ्ट लॉन्च वाहन के माध्यम से लॉन्च किया गया था।

इसरो के बारे में:

गठन: 15 अगस्त 1969

मुख्यालय: बेंगलुरु, कर्नाटक

DAC ने सशस्त्र बलों की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 7,800 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आयोजित रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) की बैठक में लगभग 7,800 करोड़ रुपये के पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए आवश्यकता की स्वीकृति (AoN) प्रदान की गई।

भारतीय वायु सेना की दक्षता बढ़ाने के लिए, DAC ने खरीद (भारतीय-IDDM) श्रेणी के तहत MI -17 वी 5 हेलीकॉप्टरों पर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर (EW) सूट की खरीद और स्थापना के लिए AoN प्रदान किया है जो हेलीकॉप्टरों की बेहतर उत्तरजीविता को बढ़ाएगा।

EW सुइट भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) से खरीदा जाएगा।

DAC ने मशीनीकृत पैदल सेना और बख्तरबंद रेजिमेंटों के लिए ग्राउंड-आधारित स्वायत्त प्रणाली की खरीद के लिए AoN भी प्रदान किया है जो मानवरहित निगरानी, गोला-बारूद, ईंधन और पुर्जों की रसद डिलीवरी और युद्ध के मैदान पर हताहतों की निकासी जैसे विभिन्न कार्यों को सक्षम करेगा।

7.62x51 मिमी लाइट मशीन गन (LMG) और ब्रिज लेइंग टैंक (BLT) की खरीद के प्रस्ताव को भी डीएसी द्वारा आगे बढ़ा दिया गया है।

जहां LMG के शामिल होने से पैदल सेना बलों की लड़ने की क्षमता में वृद्धि होगी, वहीं बीएलटी के शामिल होने से मशीनीकृत बलों की आवाजाही में तेजी आएगी।

प्रोजेक्ट शक्ति के तहत भारतीय सेना के लिए मजबूत लैपटॉप और टैबलेट की खरीद के लिए एओएन भी प्रदान किया गया है।

भारतीय नौसेना के INS विशाखापत्तनम की कुवैत यात्रा सफल रही

समुद्री सहयोग को मजबूत करने और मजबूत संबंधों को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय नौसेना के INS विशाखापत्तनम ने हाल ही में कुवैत की सफल यात्रा संपन्न की।

इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों की नौसेना बलों के बीच सहयोग बढ़ाना और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान करना है।
यात्रा के दौरान, INS विशाखापत्तनम और कुवैत नौसेना के बीच समुद्री संचालन के विभिन्न क्षेत्रों को शामिल करते हुए पेशेवर बातचीत हुई।
मूल्यवान अंतर्दृष्टि और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया गया, जो पारस्परिक विकास और विशेषज्ञता के आदान-प्रदान के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
INS विशाखापत्तनम ने कुवैत के अल-शुवैख बंदरगाह में प्रवेश किया, जिसका कुवैती नौसेना बल के प्रशिक्षण प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अल-ओरैफी के नेतृत्व में गर्मजोशी से स्वागत किया गया।
इस हार्दिक स्वागत ने दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को रेखांकित किया और उनके सहयोग के महत्व पर प्रकाश डाला।
अपनी कुवैत यात्रा से पहले, INS विशाखापत्तनम ने बहरीन साम्राज्य और संयुक्त अरब अमीरात का भी दौरा किया था, जो क्षेत्रीय साझेदारी को मजबूत करने और समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने में भारत की सक्रिय भागीदारी को प्रदर्शित करता है।

भारतीय वायुसेना 2024 में बहुराष्ट्रीय अभ्यास 'तरंग शक्ति' आयोजित करेगी

भारतीय वायु सेना (IAF) आगामी वर्ष (2024) में 'तरंग शक्ति' नामक एक महत्वपूर्ण बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास की मेजबानी करने के लिए तैयार है।
मूल रूप से अक्टूबर, 2023 के लिए निर्धारित अभ्यास को कई वायु सेनाओं की भागीदारी बाधाओं के कारण 2024 के मध्य में पुनर्निर्धारित किया गया है।

प्राथमिक ध्यान:

भाग लेने वाली वायु सेनाओं के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना।
यह भारत में आयोजित होने वाला सबसे बड़ा हवाई अभ्यास होगा।

'तरंग शक्ति' के बारे में:

बहुपक्षीय भागीदारी:
इस अभ्यास में लगभग 12 वायु सेनाओं के शामिल होने की उम्मीद है, जिससे यह सहयोग के लिए एक बड़ा मंच बन जाएगा।
यह व्यापक भागीदारी राष्ट्रों के बीच बेहतर संबंधों और आपसी समझ को बढ़ावा देने में अभ्यास के महत्व को रेखांकित करती है।

भाग लेने वाले राष्ट्र:
फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम (UK), ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका (US) और जापान जैसे देशों की वायु सेनाओं के इस अभ्यास का हिस्सा बनने की उम्मीद है।
ये 6 देश अपनी हवाई संपत्ति लाते हैं, जिसमें लड़ाकू जेट, सैन्य परिवहन विमान और मध्य हवा में ईंधन भरने की क्षमताएं शामिल हैं।

पर्यवेक्षक राष्ट्र:
इसके अतिरिक्त, 6 अन्य देशों को अभ्यास का अवलोकन करने के लिए आमंत्रित किया गया है, जो अभ्यास के समावेशी दृष्टिकोण और ज्ञान साझा करने की क्षमता को प्रदर्शित करता है।

नवीनतम समाचार:

अप्रैल, 2023 में भारतीय वायु सेना (IAF) ने फ्रांस के मोंट-डे-मार्सन सैन्य अड्डे पर लगभग 3 सप्ताह के बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास के लिए 4 राफेल जेट, 2 सी-17 विमान और 2 IL-78 मिड-एयर रिफ्यूलर भेजे।

Click Here to Subscribe Our Yearly Mock Test Package

कोप इंडिया-2023 का छठा संस्करण, भारतीय वायु सेना (IAF) और संयुक्त राज्य वायु सेना (USAF) के बीच वायु सेना स्टेशनों कलाईकुंडा, पानागढ़ और आगरा में आयोजित एक हवाई अभ्यास, 24 अप्रैल 2023 को समाप्त हुआ।

भारतीय वायुसेना के बारे में:

स्थापना: 1932
मुख्यालय: नई दिल्ली, दिल्ली
वायुसेनाध्यक्ष: एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी

ईरान ने अमेरिका के एमक्यू-9 रीपर जैसा दिखने वाला सशस्त्र ड्रोन मोहजेर-10 का अनावरण किया

रक्षा उद्योग दिवस के उपलक्ष्य में एक सम्मेलन के दौरान, ईरान के रक्षा मंत्रालय ने मोहजेर-10 नामक अपने नए घरेलू निर्मित ड्रोन का अनावरण किया, जो अमेरिका के सशस्त्र एमक्यू-9 रीपर जैसा दिखता है।
फ़ारसी में "मोहाजेर" का अर्थ "आप्रवासी" होता है और यह 1985 से इस्लामिक रिपब्लिक द्वारा निर्मित एक ड्रोन लाइन है।

प्रमुख विशेषताएं:

मोहजेर-10 में अधिक ऊंचाई पर उड़ान भरने, लंबी अवधि तक उड़ान भरने और अधिक पेलोड ले जाने की क्षमता जैसी उन्नत क्षमताएं हैं।

उड़ान की अवधि और सीमा:

ड्रोन 2,000 किलोमीटर की परिचालन सीमा के साथ 7,000 मीटर की ऊंचाई पर अधिकतम 24 घंटे तक उड़ान भर सकता है।

भार क्षमता:

ड्रोन 210 किलोमीटर प्रति घंटे (130 मील प्रति घंटे) की गति के साथ 24,000 फीट तक उड़ान भरने में सक्षम है, जो 300 किलोग्राम (660 पाउंड) तक का बम पेलोड ले जाता है, जो "मोहाजेर -6" ड्रोन की क्षमता से दोगुना है।

निगरानी और टोही:

ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक निगरानी उपकरण और एक कैमरा ले जाने से सुसज्जित है, जो इसकी खुफिया जानकारी एकत्र करने की क्षमताओं को बढ़ाता है।

उन्नत संस्करण:

मोहाजेर-10 को "मोहाजेर-6" ड्रोन का उन्नत संस्करण माना जाता है, यह 150 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकता है, 12 घंटे तक काम कर सकता है और 5,400 मीटर (17,716 फीट) की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच सकता है।

ईरान के बारे में:

अध्यक्ष: इब्राहिम रायसी
पूंजी: तेहरान
मुद्रा: ईरानी रियाल

भारतीय वायु सेना मिस्र के काहिरा एयर बेस पर अभ्यास ब्राइट स्टार-23 में भाग लेगी

27 अगस्त से 16 सितंबर 2023 तक काहिरा (पश्चिम) एयर बेस, मिस्र में आयोजित होने वाले द्विवार्षिक बहुपक्षीय त्रि-सेवा अभ्यास ब्राइट स्टार-23 में भाग लेने के लिए भारतीय वायु सेना (IAF) की एक टुकड़ी रवाना हुई।
यह पहली बार है कि भारतीय वायुसेना एक्स ब्राइट स्टार-23 में भाग ले रही है।

उद्देश्य:

संयुक्त अभियानों की योजना और कार्यान्वयन का अभ्यास करना, रणनीतिक संबंधों को बढ़ावा देना और सीमाओं के पार संबंधों को प्रोत्साहित करना।

यह संयुक्त अभ्यास मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी के इस साल के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में नई दिल्ली में भाग लेने के कुछ ही महीने बाद हुआ है।

भारतीय प्रतिभागी:

भारतीय वायुसेना के दल में पांच मिग-29, दो आईएल-78, दो सी-130 और दो सी-17 विमान शामिल होंगे।

भारतीय वायुसेना के गरुड़ विशेष बल के कर्मियों के साथ-साथ नंबर 28, 77, 78 और 81 स्क्वाड्रन के कर्मी अभ्यास में भाग लेंगे।

IAF परिवहन विमान भारतीय सेना के लगभग 150 कर्मियों को एयरलिफ्ट भी प्रदान करेगा।

भाग लेने वाले राष्ट्र:

इस अभ्यास में संयुक्त राज्य अमेरिका (USA), सऊदी अरब, ग्रीस और कतर की टुकड़ियों की भी भागीदारी देखी जाएगी।

1960 के दशक में, भारत और मिस्र ने विमान और एयरो इंजन बनाने के लिए निकटता से सहयोग किया और उनके उल्लेखनीय संबंध और करीबी सहयोग के परिणामस्वरूप भारतीय सहयोगियों ने मिस्र के पायलटों को प्रशिक्षित किया।

पहला अभ्यास, ब्राइट स्टार 81, अक्टूबर से दिसंबर 1980 (वित्तीय वर्ष 1981) तक आयोजित किया गया था।

मिस्र के बारे में:

अध्यक्ष: अब्देल फतह अल-सीसी

प्रधान मंत्री: मुस्तफ़ा मदबौली

पूंजी: काहिरा

मुद्रा: मिस्री पाउण्ड

रक्षा मंत्रालय के बारे में:

रक्षा मंत्री: राजनाथ सिंह

राज्य मंत्री: रक्षा मंत्रालय

रक्षा सचिव: गिरिधर अरमाने

रक्षा मंत्रालय और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने 5 बेड़े समर्थन जहाजों के लिए 19,000 करोड़ रुपये के सौदे पर हस्ताक्षर किए

स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए, रक्षा मंत्रालय (MoD) ने लगभग 19,000 करोड़ रुपये की कुल लागत से भारतीय नौसेना के लिए 5 स्वदेशी निर्मित फ्लीट सपोर्ट शिप (FSS) के अधिग्रहण के लिए हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (HSL), विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश (AP) के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।

इन फ्लीट सपोर्ट जहाजों के अधिग्रहण का समर्थन कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 16 अगस्त, 2023 को अपनी एक बैठक के दौरान किया था।

FSS के बारे में:

फ्लीट सपोर्ट शिप ऐसे जहाज हैं जिन्हें समुद्र में रहने के दौरान नौसेना के बेड़े को महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

इन सेवाओं में जहाजों को ईंधन, पानी, गोला-बारूद और आपूर्ति से फिर से भरना शामिल है।

इससे भारतीय नौसेना बेड़ा लंबे समय तक काम कर सकेगा।
परिणामस्वरूप, बेड़े की रणनीतिक पहुंच और गतिशीलता में वृद्धि होगी।
आयाम और विशेषताएं: 225 मीटर लंबे और 32 मीटर चौड़े इन जहाजों का विस्थापन 44,000 टन होगा।
स्वदेशी निर्माण: विशेष रूप से, ये एफएसएस किसी भारतीय शिपयार्ड द्वारा भारत के भीतर निर्मित किया जाने वाला अपनी तरह का पहला होगा, जो आत्मनिर्भरता और घरेलू जहाज निर्माण क्षमताओं की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति है।
'आत्मनिर्भर भारत' का प्रचार: ये स्वदेशी फ्लीट सपोर्ट जहाज 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के प्रमाण के रूप में खड़े हैं, जो घरेलू उत्पादन और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार के 'मेक इन इंडिया' अभियान के साथ संरेखित हैं।
विविध क्षमताएँ: नौसैनिक अभियानों का समर्थन करने के अलावा, ये जहाज़ निकासी प्रयासों और मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) संचालन सहित मानवीय मिशनों में योगदान देने की क्षमता रखते हैं।
जहाज अधिग्रहण अनुबंध के अलावा, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (HSL) ने नए फ्लीट सपोर्ट जहाजों के लिए संचार और नेविगेशन उपकरण प्रदान करने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 1,100 करोड़ रुपये के अनुबंध पर भी हस्ताक्षर किए।

HSL के बारे में:

स्थापना: 21 जून 1941
मुख्यालय: विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश, भारत
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक: हेमन्त खत्री

भारतीय नौसेना ने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित 5वें 'AUSINDEX-23' में भाग लिया

भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना (RAN) के बीच एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास AUSINDEX का 5वां संस्करण 22-25 अगस्त 2023 तक सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था।

प्रतिभागी:

भारतीय नौसेना: भारतीय नौसेना जहाज (INS) सह्याद्री और INS कोलकाता भारत की ओर से भाग लेने वाले जहाज थे।
रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना: HMAS चौल्स और HMAS ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलियाई पक्ष से भाग लेने वाले जहाज थे।
लड़ाकू विमान और समुद्री गश्ती विमान भी अभ्यास का हिस्सा थे।

AUSINDEX के बारे में:

AUSINDEX भारत और ऑस्ट्रेलिया द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, जिसे पहली बार 2015 में शुरू किया गया था।
AUSINDEX ने समुद्री संचालन के सभी 3 डोमेन: सतह, उप-सतह और वायु में अभ्यास शामिल किया।

उद्देश्य:

भारतीय नौसेना और RAN के बीच घनिष्ठ संबंधों और अंतरसंचालनीयता की पुष्टि करना।
यह अभ्यास दोनों नौसेनाओं को अंतरसंचालनीयता को और मजबूत करने, सर्वोत्तम प्रथाओं से लाभ उठाने और समुद्री सुरक्षा संचालन के लिए प्रक्रियाओं की एक आम समझ विकसित करने का अवसर प्रदान करेगा।

ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच आयोजित अन्य अभ्यास:

अभ्यास AUSTRA HIND (सेना के साथ द्विपक्षीय अभ्यास)
व्यायाम पिच ब्लैक (ऑस्ट्रेलिया का बहुपक्षीय वायु युद्ध प्रशिक्षण अभ्यास)

ऑस्ट्रेलिया के बारे में:

प्रधान मंत्री - एंथोनी अल्बानीज़
राजधानी - कैनबरा
मुद्रा: ऑस्ट्रेलियाई डॉलर

स्पोर्ट्स करेंट अफेयर्स

टेरसा में आयोजित 100वीं वर्षगांठ स्पेनिश हॉकी फेडरेशन-अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भारतीय महिला टीम विजयी हुई

हॉकी में, भारतीय महिला टीम ने मेजबान स्पेन पर 3-0 से जीत के साथ टेरासा में 100वीं वर्षगांठ स्पेनिश हॉकी फेडरेशन - अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीता।
वंदना कटारिया 22वें मिनट में मोनिका, 48वें मिनट में मोनिका और 58वें मिनट में उदिता ने गोल किये जिससे टीम टूर्नामेंट में अजेय रही।
इससे पहले भारत ने अपने तीसरे मैच में कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन इंग्लैंड को 3-0 से हराया था
भारत के लिए लालरेम्सियामी ने हैट्रिक बनाई
इस जीत के साथ, भारत ने तीन मैचों में पांच अंक अर्जित करते हुए स्टैंडिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया।
इंग्लैंड ने चार मैचों में चार अंकों के साथ अपना अभियान समाप्त किया।
मेज़बान स्पेन दूसरे स्थान पर रहा, चार अंकों के साथ।

स्पेन के बारे में

राजधानी: मैड्रिड
राजा: स्पेन के फेलिप VI
प्रधान मंत्री: पेड्रो सांचेज़

नवीनतम समाचार

टेनिस में, भारत के युकी भांबरी ने एटीपी वर्ल्ड टूर पर अपना पहला खिताब जीता, स्पेन में दक्षिण अफ्रीकी साथी लॉयड हैरिस के साथ मैलोर्का चैंपियनशिप में युगल ट्रॉफी जीती।

चीन के चेंगदू में विश्व विश्वविद्यालय खेलों में भारत ने चार स्वर्ण सहित छह पदक जीते

भारतीय निशानेबाजों और तीरंदाजों ने चीन के चेंगदू में विश्व विश्वविद्यालय खेलों में चार स्वर्ण सहित छह पदक जीते।
निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, दिव्यांश सिंह पंवार और अर्जुन बाबुता ने स्थानीय प्रबल दावेदार चीन को हराकर 10 मीटर एयर राइफल पुरुष टीम का स्वर्ण पदक जीता।
ऐश्वर्या ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष व्यक्तिगत स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक हासिल किया।
अवनीत कौर ने रोमांचक मुकाबले में यूएसए की एलिसा ग्रेस स्टर्गिल को हराया
-+++9 शूट-ऑफ में कंपाउंड महिला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता।
संगमप्रीत बिस्ला और अमन सैनी ने पुरुषों की व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण और कांस्य पदक जीते।
भारत ने नौ स्वर्ण, तीन रजत और पांच कांस्य सहित 17 पदक जीते हैं और टूर्नामेंट में दूसरे स्थान पर है।
मेजबान चीन 21 पदकों के साथ शीर्ष पर है।

चीन के बारे में:

राष्ट्रपति: शी जिनपिंग
पूंजी: बीजिंग

मुद्रा: रॅन्मिन्बी

नवीनतम समाचार

संयुक्त राष्ट्र (UN) खाद्य और कृषि संगठन (FAO) के प्रमुख, क्व डोंग्यू को एफएओ के प्रमुख के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया।

भारत की दीपिका पल्लीकल और हरिंदर पाल संधू ने सितंबर में हांगझू में एशियाई मिश्रित युगल स्क्वैश टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता, जो आगामी हांगझू एशियाई खेलों के लिए एक परीक्षण प्रतियोगिता थी।

चीन के चेंगदू में विश्व विश्वविद्यालय खेलों में भारत ने चार स्वर्ण सहित छह पदक जीते:

भारतीय निशानेबाजों और तीरंदाजों ने छह पदक जीते जिसमें चीन के चेंगदू में विश्व विश्वविद्यालय खेलों में चार स्वर्ण शामिल हैं।

निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, दिव्यांश सिंह पंवार और अर्जुन बाबुता ने स्थानीय प्रबल दावेदार चीन को हराकर 10 मीटर एयर राइफल पुरुष टीम का स्वर्ण पदक जीता।

ऐश्वर्या ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष वर्ग में भी स्वर्ण पदक हासिल किया।

अवनीत कौर ने रोमांचक शूट-ऑफ में USA की एलिसा ग्रेस स्टर्गिल को हराकर कंपाउंड महिला स्वर्ण पदक जीता।

संगमप्रीत बिस्ला और अमन सैनी ने पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण और कांस्य पदक जीते।

भारत ने 17 पदक जीते हैं, नौ स्वर्ण, तीन रजत और पांच कांस्य, और टूर्नामेंट में दूसरे स्थान पर हैं।

मेजबान चीन 21 पदकों के साथ शीर्ष पर है।

चीन के बारे में:

राष्ट्रपति: शी जिनपिंग

राजधानी: बीजिंग

मुद्रा: रॅन्मिन्बी

नवीनतम समाचार

संयुक्त राष्ट्र (UN) खाद्य और कृषि संगठन (FAO) के प्रमुख, क्व डोंग्यू को एफएओ के प्रमुख के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया।

भारत की दीपिका पल्लीकल और हरिंदर पाल संधू ने सितंबर में हांगझू में एशियाई मिश्रित युगल स्क्वैश टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता, जो आगामी हांगझू एशियाई खेलों के लिए एक परीक्षण प्रतियोगिता थी।

नॉर्वेजियन महिला, नेपाली शेरपा दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली 'सबसे तेज़' बन गईं

घटनाओं के एक रोमांचक मोड़ में, 37 वर्षीय नॉर्वेजियन महिला क्रिस्टिन हारिला और उनके गाइड, नेपाल के 35 वर्षीय तेनजेन (लामा) शेरपा ने दुनिया की सभी 14 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे तेज़ पर्वतारोही के रूप में रिकॉर्ड हासिल किया है।

दोनों ने पाकिस्तान में अपनी आखिरी चोटी, माउंट K2 पर चढ़ाई की और अपना रिकॉर्ड केवल तीन महीने और एक दिन में पूरा किया।

द गार्जियन की एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछला रिकॉर्ड निर्मल "निम्स" पुर्जा के नाम था, जिन्होंने तीन महीने और पांच दिनों में यह उपलब्धि हासिल की थी।

नेपाल स्थित आयोजन कंपनी सेवन समिट ट्रेक्स (SST) के ताशी लकपा शेरपा ने कहा कि 8,000 मीटर या 26,246 फीट से ऊपर की सभी चोटियों पर चढ़ने की जोड़ी की उपलब्धि उन्हें आठ अन्य गाइडों के साथ सबसे कम समय में चढ़ने में पहले स्थान पर रखती है।
इसके अतिरिक्त, शेरपाओं में से एक, 17 वर्षीय नीमा रिनजिन शेरपा भी K2 पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के बन गए।
वे सभी 14 चोटियों पर सबसे तेज चढ़ने वाले बन गए हैं। कुछ महीनों में सभी 14 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ना एक चुनौतीपूर्ण उपलब्धि है, जो आमतौर पर कई पर्वतारोही वर्षों में करते हैं।

7वीं पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी चेन्नई में शुरू होगी: हॉकी

हॉकी में, 7वीं पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी चेन्नई में शुरू होगा
छह टीमें - भारत, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, जापान, चीन और मलेशिया प्रतिष्ठित 10 दिवसीय टूर्नामेंट में प्रतिस्पर्धा करेंगी।
तीन मैच खेले जायेंगे
भारत जहां चीन से भिड़ेगा वहीं पाकिस्तान मलेशिया से भिड़ेगा
दक्षिण कोरिया को जापान के खिलाफ खेलना है

नवीनतम समाचार

युवा मामले और खेल मंत्री तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, चेन्नई 2023 के लिए प्रतिष्ठित ट्रॉफी का अनावरण किया।
ओडिशा सरकार ने पुरुष और महिला दोनों भारतीय हॉकी टीमों (सीनियर और जूनियर) के लिए अपने प्रायोजन को 2023 से 2033 तक अगले दस वर्षों के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया।
13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 में हॉकी हरियाणा टीम को विजेता घोषित किया गया।

FIH के बारे में:

मुख्यालय: लॉज़ेन, स्विट्जरलैंड
स्थापित: 7 जनवरी 1924, पेरिस, फ्रांस
सदस्यता: 140 राष्ट्रीय संघ

एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप शुरू हो गया है

एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप शुरू हो गया है
असम और पश्चिम बंगाल में चार स्थानों पर कुल 43 मैच खेले जाएंगे, जिनमें गुवाहाटी, कोकराझार और कोलकाता शामिल हैं।
डूरंड कप में 24 टीमें भाग लेंगी।
रोस्टर में इंडियन सुपर लीग, आई-लीग और सशस्त्र बलों की टीमें शामिल हैं।
नेपाल और बांग्लादेश से सेना की टीमें को भी इस सीज़न में शामिल किया गया है।

फीफा के बारे में:

फेडरेशन इंटरनेशनेल डी फुटबॉल एसोसिएशन एसोसिएशन फुटबॉल, बीच सॉकर और फुटसल की अंतरराष्ट्रीय शासी निकाय है।
राष्ट्रपति: गियानी इन्फैनटिनो,
मुख्यालय: ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड,
स्थापना: 21 मई 1904

नवीनतम समाचार

भारतीय फुटबॉल टीम के मिडफील्डर लालियांजुआला छांगटे को 2022-23 के लिए AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर नामित किया गया, जबकि मनीषा कल्याण ने लगातार दूसरी बार अपना दूसरा महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता।

महान मैक्सिकन गोलकीपर एंटोनियो फेलिक्स "टोटा" कार्बाजल रोड्रिग्ज, जो 5 फेडरेशन इंटरनेशनेल डी फुटबॉल एसोसिएशन (फीफा) विश्व कप में खेलने वाले पहले फुटबॉलर थे, का 93 वर्ष की आयु में लियोन, मैक्सिको में निधन हो गया।

सुब्रतो मुखर्जी स्पोर्ट्स एजुकेशन सोसाइटी ने फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए AIFF के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

पहली बार, सुब्रतो मुखर्जी स्पोर्ट्स एजुकेशन सोसाइटी (SMSES) ने आज जमीनी स्तर पर फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

SMSES, जो 1960 से सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कर रहा है, इस संस्करण से जूनियर लड़कों (अंडर-17) के तहत एक सुब्रतो XI (ग्यारह) टीम बनाएगा।

नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए, एयर वाइस मार्शल और SMSES सदस्य आलोक शर्मा ने घोषणा की कि टीम 2023-24 सीज़न से AIFF युवा प्रतियोगिता में भी भाग लेगी।

उन्होंने कहा कि अंतिम दौर की टीमों के कोचों को अपडेट और शिक्षित करने के लिए AIFF द्वारा एक शिक्षा कार्यशाला भी आयोजित की जाएगी।

इंडियन सुपर लीग, इंडियन विमेंस लीग और आई-लीग के क्लब भी सुब्रतो कप से खिलाड़ियों को चुनेंगे।

AIFF के बारे में

अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) का मुख्यालय नई दिल्ली में है।

कल्याण चौबे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के वर्तमान अध्यक्ष हैं

नवीनतम समाचार

अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय फुटबॉल आइकन प्रदीप कुमार बनर्जी के सम्मान में 23 जून को 'AIFF ग्रासरूट दिवस' के रूप में मनाने का फैसला किया है।

डीडी स्पोर्ट्स फिट इंडिया क्विज़ 2022 के राज्य फाइनल राउंड शुरू करेगा

डीडी स्पोर्ट्स फिट इंडिया क्विज़ 2022 के राज्य फाइनल राउंड शुरू करेगा

युवा मामले और खेल मंत्रालय ने कहा है कि प्रत्येक राज्य के लिए कुल 36 एपिसोड प्रसारित किए जाएंगे।

पिसोड प्रत्येक दिन सुबह 11 बजे प्रसारित किया जाएगा, जिसमें पहले एपिसोड के रूप में मध्य प्रदेश फाइनल निर्धारित किया जाएगा।

एपिसोड प्रसार भारती स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड किए जाएंगे।

फिट इंडिया क्विज़ के दूसरे संस्करण के राज्य फाइनल राउंड में प्रत्येक राज्य से कुल चार टीमों ने प्रतिस्पर्धा की।

राज्य फाइनल के लिए क्वालीफाई करने वाली टीमें जिला और जोनल राउंड में शीर्ष प्रदर्शन करने वाली टीमें थीं।

केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इस महीने की 23 तारीख को 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 72 स्कूली छात्रों को राष्ट्रीय दौर में आगे बढ़ने के लिए सम्मानित किया।

प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के विजेता स्कूल को कुल 2.5 लाख रुपये की पुरस्कार राशि मिली।

Click Here to Subscribe Our Yearly Mock Test Package

643.34 करोड़ रुपये की कुल स्वीकृत लागत पर पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय देखा गया:

युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले नौ वर्षों में पूर्वोत्तर क्षेत्र में खेल बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय परिवर्तन देखा गया है।
श्री अनुराग ठाकुर ने कहा, 'लुक ईस्ट पॉलिसी' से 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' में बदलाव के साथ, सरकार ने उत्तर-पूर्व क्षेत्र में खेल के बुनियादी ढांचे पर विशेष जोर और प्रोत्साहन दिया है।
उन्होंने यह भी कहा कि देश का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर को 643.34 करोड़ रुपये की कुल स्वीकृत लागत पर आवंटित किया गया है।
उन्होंने आगे कहा कि इसी साल 1000 खेलो इंडिया केंद्र देश को समर्पित कर दिए जाएंगे, जिनमें से 227 खेलो इंडिया केंद्र पूर्वोत्तर में स्थापित किए जा रहे हैं
मंत्रालय ने 520.60 करोड़ रुपये की संयुक्त स्वीकृत लागत पर 75 खेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
3 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र, 12 SAI प्रशिक्षण केंद्र और 22 खेलो इंडिया मान्यता प्राप्त खेल अकादमियां उत्तर-पूर्वी राज्यों में पहले से ही कार्यरत हैं।

FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स: भारत ने 11 स्वर्ण, पांच रजत और 10 कांस्य सहित 26 पदक जीते:

चेंगदू में FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारत ने 11 स्वर्ण, पांच रजत और 10 कांस्य सहित 26 पदक जीते हैं।
भारत अब पदक तालिका में चौथे स्थान पर है।
चीन के छठे सबसे बड़े शहर में चल रहे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स द्विवार्षिक बहु-खेल आयोजन का 31वां संस्करण है।
2021 संस्करण को COVID-19 के कारण स्थगित कर दिया गया था।
मल्टी-स्पोर्ट मीट 28 जुलाई से 8 अगस्त तक चलेगी।
भारतीय दल प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं - तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, तलवारबाजी, जूडो, शूटिंग, तैराकी, टेबल टेनिस, तायक्वोंडो, टेनिस और वॉलीबॉल।

चीन के बारे में:

राष्ट्रपति: शी जिनपिंग
राजधानी: बीजिंग
मुद्रा: रॅन्मिन्बी

नवीनतम समाचार

भारत ने चेंगदू, चीन में पदक स्पर्धाओं के शुरुआती दिन तीन स्वर्ण पदकों के साथ FISU समर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में अपना खाता खोला।

अदिति स्वामी विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनीं

अदिति स्वामी बर्लिन में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के फाइनल में व्यक्तिगत विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रचा।
जूनियर विश्व खिताब जीतने के दो महीने से भी कम समय में, 17 वर्षीय अदिति, कंपाउंड महिला स्पर्धा के शिखर मुकाबले में मैक्सिको की एंड्रिया बेसेरा को 149-147 से हराकर सीनियर विश्व चैंपियन बन गईं।

इस जीत के साथ, सतारा का किशोर सीनियर विश्व चैंपियनशिप में व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला भारतीय विश्व चैंपियन बन गया। महिलाओं की स्पर्धा में अदिति स्वामी के स्वर्ण पदक के तुरंत बाद, भारत के ओजस डेओटाले ने इतिहास रच दिया जब उन्होंने रोमांचक फाइनल में पोलैंड के लुकाज़ प्रिज़ीबिल्स्की को 150-149 से हराकर पुरुषों की कंपाउंड स्पर्धा में नया विश्व चैंपियन बन गए।

इससे पहले दिन में, अदिति ने अखिल भारतीय सेमीफाइनल में अपनी 'आदर्श' ज्योति सुरेखा वेन्नम को 149-145 से हरा दिया।

हालाँकि, ज्योति ने कांस्य पदक जीता जब उन्होंने तीसरे स्थान के प्ले-ऑफ में तुर्की की इपेक टोमरुक को चार अंकों से हराकर परफेक्ट 150 का स्कोर किया।

अदिति ने परनीत कौर और ज्योति सुरेखा वेन्नम के साथ मिलकर भारत के लिए पहला स्थान हासिल किया कंपाउंड महिला टीम फाइनल जीतकर विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता।

नवीनतम समाचार

भारत जर्मनी के सुहल में अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप में छह स्वर्ण, छह रजत और तीन कांस्य पदक सहित 15 पदक जीतकर शीर्ष पर रहा।

भारतीय साइकिलिस्ट एसो अल्बेन ने जर्मनी के डुडेनहोफेन में UCI क्लास 1 इवेंट-फिनाले बाहनीन-टूर्न 2023 साइकिलिंग प्रतियोगिता में एलीट पुरुष कीरिन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता।

जर्मनी के बर्लिन में विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 में भारत ने अपने कल के पदकों की संख्या में 21 पदक जोड़े जिससे उसके कुल पदकों की संख्या 76 (26 स्वर्ण, 30 रजत और 20 कांस्य) हो गई।

SAI ने एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों की यात्रा पर लघु फिल्म श्रृंखला 'हल्ला बोल' लॉन्च की

भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) ने अम्ब्रेला अभियान 'चीयर4इंडिया' के तहत एशियाई खेलों के लिए जाने वाले खिलाड़ियों की यात्रा पर एक लघु फिल्म श्रृंखला 'हल्ला बोल' शुरू की है ताकि उन्हें हांग्जो एशियाई खेलों के लिए प्रेरित किया जा सके और आगामी एशियाई खेलों के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके।

SAI ने कहा कि आने वाले हफ्तों में कुल 12 लघु फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी।

SAI ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह पहल न केवल एशियाई खेलों के लिए जाने वाले एथलीटों को बल्कि देश के युवाओं को भी खेल अपनाने के लिए प्रेरित करेगी।

युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि भारतीय दल एशियाई खेलों के 19वें संस्करण के लिए तैयारी कर रहा है।

उन्होंने देशवासियों से देश के प्रतिभाशाली एथलीटों की प्रेरक यात्रा को प्रदर्शित करने वाली हल्ला बोल श्रृंखला देखने की अपील की।

श्री ठाकुर ने कहा कि ये एथलीट एक बार फिर देश को गौरव और गौरव दिलाने के मिशन पर हैं। ऐसी ही एक फिल्म श्रृंखला, 'ओलंपिक की आशा', टोक्यो ओलंपिक से पहले लॉन्च की गई थी।

SAI के बारे में:

भारतीय खेल प्राधिकरण भारत की सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल संस्था है, जिसकी स्थापना भारत में खेलों के विकास के लिए भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा 1984 में की गई थी।

स्थापित: 1984

मुख्यालय: दिल्ली, भारत

भारतीय पुरुष टीम ने चेन्नई में चल रही एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी प्रतियोगिता में मलेशिया को हराकर शीर्ष स्थान हासिल किया

चेन्नई के मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम में खेले गए एशियाई चैम्पियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में भारतीय पुरूष टीम ने मलेशिया को 5-0 से हराकर एक बार फिर शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है।
भारत ने जापान से 1-1 से ड्रा खेला था
उन्होंने घरेलू मैदान पर चीन पर 7-2 की बड़ी जीत के साथ अभियान की शुरुआत की थी।
भारत तीन मैचों में दो जीत और एक ड्रॉ के साथ कुल सात अंक लेकर शीर्ष स्थान पर है।
पाकिस्तान के खिलाफ ग्रुप चरण समाप्त करने से पहले भारत आज शाम 8:30 बजे दक्षिण कोरिया से भिड़ेगा।
मलेशिया तीन मैचों में दो जीत और एक हार और कुल छह अंक के साथ दूसरे स्थान पर है और गत चैंपियन दक्षिण कोरिया चार अंक के साथ तीसरे स्थान पर है।

टेनिस: प्रार्थना थोम्बारे ने बार्सिलोना, स्पेन में महिला युगल का खिताब जीता

प्रार्थना थोम्बरे ने बार्सिलोना, स्पेन में महिला टेनिस हार्डकोर्ट इवेंट में युगल खिताब जीता है।
एशियाई खेलों की कांस्य पदक विजेता, रूसी अनास्तासिया तिखोनोवा के साथ संयुक्त फाइनल में फ्रांस की एस्टेले कैसिनो और लातविया की डायना मार्सिंकेविका को 3-6, 6-1, 10-7 से हराया।
प्रार्थना के लिए यह साल का दूसरा और कुल मिलाकर 26वां खिताब है, जिन्होंने 2014 में इंचियोन में सानिया मिर्जा के साथ कांस्य पदक जीता था।
सिद्धांत बांथिया और साई कार्तिक रेड्डी ने कजाखस्तान के अस्ताना में आईटीएफ पुरुष स्पर्धा में इस सत्र में अपना दूसरा खिताब जीता।
उन्होंने हार्ड-कोर्ट इवेंट में ट्रॉफी जीतने के लिए एस्टोनिया के डेनियल ग्लिंका और कार्ल किउर सार को 7-5, 6-7, 10-4 से हराया।
जून में जकार्ता में एक कार्यक्रम में एक टीम के रूप में अपनी पहली उपस्थिति में जीत हासिल करने वाले दोनों खिलाड़ियों के लिए यह पहला ताज है।
ब्रिटेन के फॉक्सहिल्स में ITF महिला स्पर्धा में, रुतुजा भोसले ने ऑस्ट्रेलिया की डेस्टेनी अयावा के साथ साझेदारी में युगल फाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त ऑस्ट्रेलिया की तालिया गिब्सन और पेट्रा ह्यूले को हराया।
27 वर्षीय रुतुजा के लिए यह करियर का 22वां युगल खिताब था।

विश्व नंबर 1 पुरुष युगल जोड़ी प्रमोद भगत और सुकांत कदम ने SL3-SL4 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता

प्रमोद भगत और सुकांत कदम की दुनिया की नंबर एक पुरुष युगल जोड़ी ने इंग्लैंड के शेफील्ड में चार देशों के पैरा-बैडमिंटन इंटरनेशनल-2023 में एसएल3-एसएल4 वर्ग में हमवतन दीप रंजन बिसोयी और मनोज सरकार को 21-17, 21-17 से हराकर स्वर्ण पदक जीता।
भगत ने एकल एसएल3 वर्ग में रजत और मिश्रित युगल एसएल3-एसयू5 वर्ग में मनीषा रामदास के साथ रजत पदक भी हासिल किया।
कदम ने एकल एसएल4 वर्ग में कांस्य पदक जीता।

भारत को गुयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना तीसरा टी-20 इंटरनेशनल मैच खेलना है

क्रिकेट में, भारत गुयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में अपने तीसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में वेस्टइंडीज से भिड़ेगा।
पांच मैचों की सीरीज में अब तक वेस्टइंडीज ने भारत के खिलाफ 2-0 की बढ़त बना ली है
आखिरी दो मैच संयुक्त राज्य अमेरिका में खेले जाएंगे।
चौथा मैच 12 अगस्त को फ्लोरिडा में और सीरीज का 5वां मैच इसी महीने की 13 तारीख को उसी स्थान पर खेला जाएगा

भारत ने अंतिम ग्रुप स्टेज मैच में पाकिस्तान को 4-0 से हराकर चेन्नई में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में प्रवेश किया

हॉकी में, भारत ने ग्रुप चरण के अंतिम गेम में पाकिस्तान को 4-0 से हराकर चेन्नई में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में प्रवेश किया।
भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने दो गोल किए, जबकि जुगराज सिंघा और मनदीप सिंह ने एक-एक गोल किया, जिससे भारत टूर्नामेंट में एकमात्र अजेय टीम के रूप में ग्रुप चरण में समाप्त हुआ।
भारत अब चार जीत और एक ड्रा के बाद 13 अंकों के साथ शीर्ष पर है जबकि पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो गया है।
इससे पहले मलेशिया ने कोरिया को 1-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की थी।
सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला जापान से होगा, जबकि मलेशिया का मुकाबला कोरिया से होगा

विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023: भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे

आगामी विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे।
चैंपियनशिप 19 अगस्त को बुडापेस्ट में शुरू हो रही है।
एक बयान में, युवा मामले और खेल मंत्रालय ने घोषणा की कि वह मेगा इवेंट के लिए 28 भारतीय एथलीटों को फंड देगा।
इस महीने की 27 तारीख तक मैच खेले जाएंगे
28 प्रतिस्पर्धी एथलीटों में से 15 पहली बार विश्व चैंपियनशिप में प्रतिस्पर्धा करेंगे।
पूर्व अंडर 20 रजत पदक विजेता, शैली सिंह, दल की सबसे कम उम्र की सदस्य हैं।

विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 डेनमार्क के कोपेनहेगन में शुरू होगी

विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 डेनमार्क में 21 अगस्त, 2023 को कोपेनहेगन में शुरू होगी।
भारतीय शटलर पीवी सिंधु को मलेशिया के कुआलालंपुर में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन मुख्यालय में आयोजित चैंपियनशिप के महिला एकल ड्रा में पहले दौर में बाई मिली।
पुरुष एकल में भारतीय शटलरों को अनुकूल ड्रॉ मिला।
नौवीं वरीयता प्राप्त एचएस प्रणय अपने अभियान की शुरुआत फिनलैंड के कैले कोलजोनेन के खिलाफ करेंगे।
लक्ष्य सेन मॉरीशस के जॉर्जेस जूलियन पॉल के खिलाफ अभियान शुरू करेंगे
किदाम्बी श्रीकांत को ड्रॉ में गैरवरीयता दी गई और उनका सामना जापान के केंता निशिमोतो से होगा।
पुरुष युगल में दूसरी वरीयता प्राप्त चिराग शेट्टी और सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी को शुरुआती दौर में बाई मिली और महिला युगल में 15वीं वरीयता प्राप्त गायत्री गोपीचंद और ट्रीसा जॉली को भी बाई मिली।

शाकिब अल हसन को तमीम इकबाल की जगह बांग्लादेश क्रिकेट टीम का वनडे कप्तान बनाया गया है

काफी प्रत्याशा के बाद, शाकिब अल हसन को तमीम इकबाल की जगह बांग्लादेश वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है।
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन पापोन ने ढाका में पत्रकारों को बोर्ड के फैसले की घोषणा की।
शाकिब वर्तमान में टीम के टेस्ट और टी20ई कप्तान हैं और उनके पास 50 ओवर के प्रारूप में बांग्लादेश का नेतृत्व करने का अनुभव भी है।

भारत ने मलेशिया को 4-3 से हराकर एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 फाइनल जीता:

भारतीय हॉकी टीम ने 12 अगस्त को चेन्नई के मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के फाइनल में मलेशिया को 4-3 से हराकर चौथी बार जीत हासिल की।
चार एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी खिताब के साथ, भारत टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे सफल टीम है।
तीन खिताबों के साथ पाकिस्तान अब दूसरे स्थान पर है।
इससे पहले, भारत के गुरजंत ने स्कोर बराबर किया, जिससे मलेशिया के खिलाफ रोमांचक मुकाबला 3-3 से बराबर हो गया।
भारत की ओर से जुगराज सिंह ने पहले क्वार्टर में गोल करके भारत को शुरुआती बढ़त दिलाई, लेकिन मलेशिया के कमाल अबू अरजई ने स्कोर 1-1 कर दिया।
इसके बाद तीसरे क्वार्टर में भारत के हरमनप्रीत सिंह ने पेनल्टी स्ट्रोक को गोल में बदलकर स्कोर 2-3 कर दिया, जिसके बाद गुरजंत ने बराबरी का गोल दागा।
जैसे ही स्कोर बराबर हुआ, आकाशदीप ने देर से विजेता बनकर भारत को रिकॉर्ड चौथी बार एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी खिताब दिलाने में मदद की।
इससे पहले जापान ने दक्षिण कोरिया को 3 के मुकाबले 5 गोल से हराकर कांस्य पदक जीता था।
टीमें चैंपियनशिप में तीसरे और चौथे स्थान के लिए खेल रही थीं।

भारतीय पुरुष हॉकी टीम FIH पुरुष हॉकी विश्व रैंकिंग में तीसरे स्थान पर पहुंच गई है

भारतीय पुरुष हॉकी टीम चेन्नई में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी खिताब जीतने के बाद FIH पुरुष हॉकी विश्व रैंकिंग में तीसरे स्थान पर पहुंच गई है।
भारत 2771.35 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गया है।
अपनी जीत के बाद उन्हें 8.61 अंक प्राप्त हुए।
रैंकिंग में तीन बार के विश्व चैंपियन नीदरलैंड्स 3095.90 अंकों के साथ शीर्ष पर हैं। बेल्जियम 2917.87 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है।
इस बीच, भारतीय जूनियर पुरुष और महिला हॉकी टीम बेंगलुरु से अपने यूरोपीय दौरे के लिए रवाना हो गई।
वे 4 देशों के टूर्नामेंट - डसेलडोर्फ 2023 के लिए जर्मनी के लिए उड़ान भरेंगे, जहां वे इंग्लैंड, स्पेन और मेजबान जर्मनी के खिलाफ एक्शन में नजर आएंगे।
यह टूर्नामेंट आगामी प्रतिष्ठित FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 की तैयारियों का हिस्सा होगा, जो मलेशिया में 5 दिसंबर से 16 दिसंबर 2023 तक खेला जाएगा और महिला FIH हॉकी जूनियर विश्व कप 2023 के लिए, जो 29 नवंबर से 10 दिसंबर 2023 तक सैंटियागो, चिली में खेला जाएगा।
विष्णुकांत सिंह भारतीय जूनियर पुरुष टीम की कप्तानी करेंगे
भारतीय जूनियर महिला टीम की कप्तानी प्रीति करेंगी और रुतुजा दादासो पिसल उपकप्तान हैं।

जूनियर पुरुष टीम 18 अगस्त से 22 अगस्त 2023 तक एक्शन में रहेगी, जबकि भारतीय जूनियर महिला टीम 19 अगस्त से 23 अगस्त 2023 तक एक्शन में रहेगी।

युवा मामले एवं खेल मंत्रालय वाराणसी में यूथ 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है

युवा मामले और खेल मंत्रालय उत्तर प्रदेश के वाराणसी में यूथ 20 समिट-2023 का आयोजन कर रहा है।
शिखर सम्मेलन 20 अगस्त तक चलेगा
G20 देशों, अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 100 से अधिक प्रतिनिधि Y20 के पांच चिन्हित विषयों पर चर्चा करेंगे।
इन विषयों में कार्य का भविष्य: उद्योग 4.0, नवाचार और 21वीं सदी के कौशल, शांति निर्माण और सुलह: युद्ध रहित युग की शुरुआत, और जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण शामिल हैं।
वाई 20 शिखर सम्मेलन गुवाहाटी में स्थापना बैठक, प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में आयोजित 14 युवा -20 परामर्श, लेह, लद्दाख में प्री-शिखर सम्मेलन, विचार मंथन सत्र, वाई 20 चौपाल और मुख्य वाई 20 शिखर सम्मेलन से पहले देश भर में आयोजित विभिन्न जन भागीदारी कार्यक्रमों का समापन है।
Y20 शिखर सम्मेलन पिछले कुछ महीनों के दौरान हुई चर्चाओं के निष्कर्षों से बनाई गई Y20 विज्ञप्ति पर बातचीत करने, अंतिम रूप देने और हस्ताक्षर करने के लिए G20 देशों के युवा विशेषज्ञों, निर्णय निर्माताओं और युवा प्रतिनिधियों को एक साथ लाएगा।

इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज स्टीवन फिन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की

इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज स्टीवन फिन ने घुटने की चोट के कारण क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है।
घुटने में चोट लगने के कारण वह इस साल अधिकतर गतिविधियों से दूर रहे।
फिन का इंग्लैंड के साथ अच्छा करियर रहा है, उन्होंने 36 टेस्ट, 69 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और 21 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं।
2010 में पदार्पण करते हुए, उन्होंने 2010-11 एशेज के दौरान 14 विकेट हासिल किए, जिसे उनकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया में 3-1 से जीता था।

भारतीय राष्ट्रीय निशानेबाजी दल ने बाकू, अजरबैजान में शुरू हो रही ISSF विश्व चैंपियनशिप में अपना अभियान शुरू किया

भारतीय राष्ट्रीय शूटिंग टीम ने बाकू, अजरबैजान में शुरू होने वाली अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन (ISSF) विश्व चैंपियनशिप में अपना अभियान शुरू किया।
सभी कार्यक्रम आधिकारिक तौर पर 17 अगस्त को शुरू होंगे।
53 सदस्यीय भारतीय दल में से 34 निशानेबाज 15 ओलंपिक स्पर्धाओं में भाग लेंगे जबकि 19 गैर-ओलंपिक स्पर्धाओं में प्रतिस्पर्धा करेंगे।
18 भारतीय निशानेबाजों का पहला बैच पहले ही बाकू पहुंच चुका है और प्रशिक्षण शुरू कर चुका है।
शॉटगन निशानेबाजों का इटली में 11 दिवसीय शिविर था, जबकि राइफल और पिस्टल निशानेबाजों का आयोजन से पहले दिल्ली में आठ दिवसीय राष्ट्रीय शिविर था।

भारत के मोहित कुमार पुरुषों के 61 किलोग्राम फ्रीस्टाइल वर्ग में अंडर 20 विश्व चैंपियन बने

भारतीय पहलवान मोहित कुमार जॉर्डन के अम्मान सिटी में पुरुषों के 61 किलोग्राम फ्रीस्टाइल वर्ग में अंडर 20 विश्व चैम्पियनशिप बन गए हैं।
मोहित ने फाइनल में रूस के एल्दार अखमादुदिनोव को 9-8 से हराकर जूनियर विश्व चैंपियनशिप जीतने वाले चौथे भारतीय फ्रीस्टाइल पहलवान बने।
मोहित अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के चौथे पुरुष पहलवान हैं, इससे पहले 2001 में पलविंदर चीमा, 2001 में रमेश कुमार और 2019 में दीपक पूनिया ने अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था।
जयदीप ने किर्गिस्तान के झाकशिलिक रुस्लानोविच बैताशोव पर जीत के साथ 74 किग्रा में कांस्य पदक जीता। प्रतियोगिता के दूसरे दिन सागर जगलान ने फ्रीस्टाइल 79 किग्रा वर्ग में रजत पदक जीता, जबकि दीपक चहल ने फ्रीस्टाइल 97 किग्रा वर्ग में कांस्य पदक जीता।
भारतीय पुरुष फ्रीस्टाइल टीम ने अब तक पांच पदक जीते हैं।

ICC पुरुष T20I खिलाड़ी रैंकिंग: स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव शीर्ष स्थान पर बरकरार, शुबमन गिल 25वें स्थान पर पहुंचे

ICC पुरुषों की T20I खिलाड़ी रैंकिंग में, स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव ने शीर्ष स्थान बरकरार रखा है, जबकि शुबमन गिल 43 स्थानों की बढ़त के साथ 25वें स्थान पर पहुंच गए हैं।
जबकि सूर्यकुमार 907 अंकों के साथ सूची में शीर्ष पर हैं, वह पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान से काफी ऊपर हैं जो 811 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर हैं।
पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम 756 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर हैं जबकि दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर एडेन मार्कराम 748 अंकों के साथ चौथे स्थान पर हैं।
शीर्ष 10 में कोई अन्य भारतीय बल्लेबाज नहीं है

इंग्लैंड के हरफनमौला खिलाड़ी बेन स्टोक्स ने भारत में होने वाले विश्व कप से पहले वनडे से संन्यास ले लिया है

क्रिकेट में इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स भारत में अक्टूबर में होने वाले ICC वनडे विश्व कप से पहले वनडे इंटरनेशनल से संन्यास लेने के अपने फैसले को पलट दिया।
स्टोक्स सितंबर में न्यूजीलैंड के खिलाफ श्रृंखला के लिए 50 ओवरों की टीम में वापसी करेंगे।
इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) के बयान के अनुसार, स्टोक्स ने प्रारूप से संन्यास लेने के अपने फैसले को पलटने का फैसला करने के बाद इंग्लैंड की पुरुष वनडे टीम में वापसी की है, जबकि अनकैप्ड सरे के तेज गेंदबाज गस एटकिंसन को 15-खिलाड़ियों की टीम में शामिल किया गया है।
स्टोक्स ने इंग्लैंड के लिए आखिरी वनडे मैच 19 जुलाई 2022 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला था। 105 वनडे मैचों में उन्होंने 38.98 की औसत और 95 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से 2,924 रन बनाए हैं।
उनके नाम 90 पारियों में तीन शतक और 21 अर्धशतक हैं। उन्होंने इस फॉर्मेट में 74 विकेट भी लिए हैं

प्रिया मलिक ने जॉर्डन में 2023 U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता

भारतीय पहलवान प्रिया मलिक ने जॉर्डन में 2023 अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता।
प्रिया अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप जीतने वाली भारत की दूसरी महिला पहलवान बन गई हैं।
अंतिम पंघाल पिछले साल कुश्ती में जूनियर विश्व खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी थीं।

Click Here to Subscribe Our Yearly Mock Test Package

महिलाओं की 76 किग्रा फ्रीस्टाइल कुश्ती के फाइनल में प्रिया मलिक ने जर्मा की लौरा सेलीन कुहेन को 5-0 से हराया। अधिकार की सच्ची मुहर लगाते हुए, प्रिया ने अपने किसी भी मैच में एक भी अंक गँवाए बिना पूरे टूर्नामेंट में जीत हासिल की। प्रिया ने अब अपने छोटे लेकिन आशाजनक करियर में U17 2021 और 2022 और U20 दोनों विश्व खिताब जीते हैं।

भारत ने पेरिस में विश्व कप चरण 4 में पुरुषों और महिलाओं की कंपाउंड तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीते:

भारत ने पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप चरण 4 में पुरुष और महिला दोनों कंपाउंड स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीते।
पुरुष टीम ने अमेरिकी टीम को 236-232 से हराया, जबकि महिला टीम ने मेक्सिको को 234-233 के स्कोर से हराया।
ज्योति वेन्नम ने सेमीफाइनल में एला गिब्सन से हारने के बाद महिलाओं की कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता।
वेनम ने सारा लोपेज के खिलाफ टाईब्रेकर में सेंटर के सबसे करीब निशाना लगाकर कांस्य पदक हासिल किया।

पुरुष टीम कंपाउंड:

भारतीय टीम: अभिषेक वर्मा, ओजस देवतले, प्रथमेश जावकर।
पराजित: क्रिस शेफ़, जेम्स लुत्ज़ और सॉयर सुलिवन की अमेरिकी टीम।
स्कोर: भारत 236, यूएसए 232।
परिणाम: भारत ने सटीकता और टीम वर्क के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया।

महिला टीम कंपाउंड:

भारतीय टीम: ज्योति वेन्नम, परनीत कौर, अदिति स्वामी।
पराजित: मैक्सिकन टीम.
स्कोर: भारत 234, मेक्सिको 233.
परिणाम: भारत ने करीबी मुकाबले में स्वर्ण पदक जीता।

महिला कम्पाउंड:

ज्योति वेन्नम सेमीफाइनल में पहुंची लेकिन एला गिब्सन (ग्रेट ब्रिटेन) से हार गईं।
स्कोर: वेन्नम 148, गिब्सन 150।
कांस्य मैच: वेन्नम बनाम सारा लोपेज।
नतीजा: वेन्नम ने केंद्र के सबसे नजदीक शूटिंग करके कांस्य पदक जीता।

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने गुरुग्राम में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान आगामी वनडे विश्व कप के लिए शुभंकर पेश किए हैं

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने गुरुग्राम में एक कार्यक्रम में आगामी वनडे विश्व कप के लिए शुभंकर का अनावरण किया।
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने हाल ही में आगामी एकदिवसीय विश्व कप के लिए शुभंकर पेश किया है, जो लैंगिक समानता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
ये शुभंकर क्रिकेट में समावेशिता और एकता के प्रतीक के रूप में काम करते हैं और इसका उद्देश्य क्रिकेट प्रशंसकों की अगली पीढ़ी को शामिल करना और प्रेरित करना है।
यहां ICC एकदिवसीय विश्व कप शुभंकर के अनावरण से कुछ परीक्षा-दृष्टिकोण मुख्य अंश दिए गए हैं:

शुभंकर का उद्देश्य:

ICC ने क्रिकेट में लैंगिक समानता और विविधता को बढ़ावा देने के लिए वनडे विश्व कप के लिए पुरुष और महिला शुभंकर पेश किए। ये शुभंकर खेल की समावेशी प्रकृति का प्रतीक हैं और इसका उद्देश्य बच्चों सहित व्यापक दर्शकों से जुड़ना है।

मूल्यों का प्रतिनिधित्व:
नर और मादा शुभंकर जुनून, ताकत और दृढ़ संकल्प जैसे गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो क्रिकेट की भावना का अभिन्न अंग हैं। वे रूढ़ियों को तोड़ते हैं और क्रिकेट को सभी के लिए सुलभ बनाने के आईसीसी के प्रयासों के साथ जुड़कर एकता और समानता का संदेश देते हैं।

प्रमोशन में भूमिका:
शुभंकर एकदिवसीय विश्व कप को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्हें मार्केटिंग अभियानों में दिखाया जाएगा, जिससे क्रिकेट प्रेमियों के बीच उत्साह और प्रत्याशा पैदा होगी। उनके आकर्षक और भरोसेमंद किरदार सभी उम्र के प्रशंसकों को पसंद आएंगे।
शुभंकर का उद्देश्य बच्चों में क्रिकेट के प्रति आजीवन प्रेम पैदा करना है। युवा पीढ़ी के साथ जुड़कर ICC का लक्ष्य खेल के भविष्य को सुरक्षित करना और इसकी निरंतर लोकप्रियता सुनिश्चित करना है।

समावेशिता का महत्व:
शुभंकर का अनावरण बाधाओं को तोड़ने और क्रिकेट में महिलाओं की अधिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए आईसीसी की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। शुभंकर लैंगिक मानदंडों को चुनौती देते हैं और खेल में समान प्रतिनिधित्व को प्रोत्साहित करते हैं।
शुभंकर के माध्यम से, ICC का लक्ष्य सामान्य रूप से एकदिवसीय विश्व कप और क्रिकेट के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। पात्रों को ध्यान आकर्षित करने और टूर्नामेंट में रुचि पैदा करने, मौजूदा और नए दोनों प्रशंसकों को आकर्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
शुभंकर बच्चों पर स्थायी प्रभाव डालने, ICC आयोजनों से परे क्रिकेट के प्रति आजीवन प्रेम को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। यह खेल की स्थिरता सुनिश्चित करने के ICC के लक्ष्य के अनुरूप है।

प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व:
शुभंकर केवल पात्रों से कहीं अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं; वे क्रिकेट के मूल्यों, विविधता और एकता का प्रतीक हैं। वनडे विश्व कप में उनकी उपस्थिति ICC की समावेशिता और लैंगिक समानता के प्रति प्रतिबद्धता की याद दिलाएगी।

भारत ने बाकू, अजरबैजान में आयोजित ISSF विश्व चैंपियनशिप में मिश्रित टीम एयर पिस्टल वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया

भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह और शिव नरवाल ने अजरबैजान के बाकू में आयोजित ISSF विश्व चैम्पियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता।

प्रमुख बिंदु:
ईशा सिंह और शिवा नरवाल की जीत:
भारतीय जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में देश का प्रतिनिधित्व किया।
उन्होंने 16-10 के अंतिम स्कोर के साथ तुर्की टीम, इलायदा तारहान और यूसुफ डिकेक पर विजय प्राप्त करके अपनी जीत सुनिश्चित की।
यह उपलब्धि चैंपियनशिप में भारत की ताकत को रेखांकित करती है।

पदक तालिका:
इस स्वर्ण पदक ने चैंपियनशिप में भारत के पदकों की संख्या दो कर दी।
पदक लीडरबोर्ड पर भारत की वर्तमान स्थिति दूसरे स्थान पर है।

पदक तालिका में सबसे आगे चीन है, जिसके पास पांच स्वर्ण पदक और दो कांस्य पदक हैं।

निष्कर्ष:

ISSF विश्व चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में भारत की सफलता भारतीय निशानेबाजों की असाधारण क्षमताओं और अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यह जीत न केवल वैश्विक शूटिंग मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को मजबूत करती है बल्कि चैंपियनशिप के पदक पदानुक्रम में इसकी रैंकिंग को भी मजबूत करती है।

प्रिया मलिक ने जॉर्डन में आयोजित U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया

भारतीय पहलवान प्रिया मलिक जॉर्डन में आयोजित U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में विजयी हुई हैं, अपनी कुश्ती यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की।

उनकी उपलब्धि अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारतीय एथलीटों के कौशल को दर्शाती है।

प्रमुख बिंदु:

स्वर्ण पदक की जीत:

प्रिया मलिक ने जॉर्डन में चल रही U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया।

76 किग्रा वर्ग में प्रतिस्पर्धा करते हुए, उन्होंने स्वर्ण पदक मुकाबले में 5-0 की शानदार जीत के साथ अपने प्रतिद्वंद्वी, जर्मनी की लॉरा कुहेन को पछाड़ दिया।

यह उपलब्धि उन्हें इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बनाती है।

विशेष रूप से, वह उसी चैंपियनशिप में भारत के पिछले स्वर्ण पदक विजेता के रूप में अंतिम पंघाल के साथ शामिल हो गईं।

टॉप्स का प्रतिनिधित्व:

प्रिया मलिक टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (टॉप्स) का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय सफलता के लिए विशिष्ट एथलीटों का पोषण और समर्थन करना है।

उनकी सफलता भारतीय एथलीटों को वैश्विक मानक तक ऊपर उठाने में TOPS जैसे कार्यक्रमों की प्रभावशीलता को रेखांकित करती है।

ऐतिहासिक दोहरी स्वर्ण जीत:

प्रिया मलिक की जीत ने मौजूदा चैंपियनशिप में भारत की दोहरी स्वर्ण जीत में योगदान दिया।

यह उपलब्धि भारत द्वारा U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में दो स्वर्ण पदक हासिल करने का केवल दूसरा उदाहरण है, पहली घटना 2001 की है।

यह उपलब्धि अंतरराष्ट्रीय कुश्ती में भारत के बेहतर प्रदर्शन और बढ़ते प्रभुत्व को उजागर करती है।

खेलो इंडिया एथलीट का योगदान:

खेलो इंडिया की एथलीट आरजू ने 68 किलोग्राम वर्ग में अपना दमखम दिखाया।

आरजू के सराहनीय प्रदर्शन की परिणति तुर्की की एलिफ कर्ट पर उनकी जीत के साथ हुई और उन्होंने भारत के लिए कांस्य पदक हासिल किया।

यह विभिन्न भार श्रेणियों में भारत की सर्वांगीण दक्षता पर जोर देता है।

मेडल टैली:

भारत की वर्तमान पदक संख्या सात है, जिसमें दो स्वर्ण, एक रजत और चार कांस्य पदक शामिल हैं।

यह वैश्विक कुश्ती मंच पर भारत की बढ़ती उपस्थिति और प्रतिस्पर्धात्मकता को दर्शाता है।

आगामी एशिया कप 2023 के लिए भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम की घोषणा, रोहित शर्मा संभालेंगे टीम की कमान

एशिया कप 2023 के लिए भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है, जिसमें रोहित शर्मा को कप्तान और हार्दिक पंड्या को उपकप्तान बनाया गया है।
टीम बल्लेबाजों, ऑलराउंडरों, स्पिनरों और तेज गेंदबाजों के मिश्रण से सुसज्जित है।
शुबमन गिल, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और ईशान किशन जैसे खिलाड़ी बल्लेबाजी को गहराई प्रदान करते हैं।
अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और शार्दुल ठाकुर गेंदबाजी विकल्प में शामिल हैं।
टीम में अनुभवी खिलाड़ियों और उभरती प्रतिभाओं का संतुलित मिश्रण शामिल है।

मुख्य खिलाड़ी:

रोहित शर्मा (कप्तान): अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए मशहूर रोहित का नेतृत्व और अनुभव टीम के प्रदर्शन में अहम भूमिका निभाएगा।
हार्दिक पंड्या (उप कप्तान)): एक बहुमुखी ऑलराउंडर, हार्दिक की बल्लेबाजी और गेंदबाजी कौशल उन्हें टीम की सफलता के लिए एक मूल्यवान संपत्ति बनाती है।
विराट कोहली: एक अनुभवी प्रचारक और पूर्व कप्तान, कोहली का लगातार प्रदर्शन टीम के मध्य क्रम को मजबूत करने में महत्वपूर्ण होगा।
सूर्यकुमार यादव: आक्रामक बल्लेबाजी के साथ उभरते सितारे, सूर्यकुमार के शामिल होने से बल्लेबाजी लाइनअप में गहराई और मारक क्षमता जुड़ गई है।
जसप्रित बुमरा: मुख्य तेज गेंदबाज, बुमराह की विकेट लेने और गति को नियंत्रित करने की क्षमता महत्वपूर्ण मैच स्थितियों में महत्वपूर्ण होगी।
रवीन्द्र जड़ेजा: अपनी स्पिन गेंदबाजी और निचले क्रम की बल्लेबाजी के लिए जाने जाने वाले ऑलराउंडर, जडेजा का योगदान विभिन्न मैच परिदृश्यों में महत्वपूर्ण होगा।

विश्वनाथन आनंद के बाद आर प्रागनानंद सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय हैं

विश्वनाथन आनंद के बाद फिडे विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय आर प्रागनानंदा ने अजरबेजान के बाकू में अपने से ऊंची रैंकिंग के प्रतिद्वंद्वी फैबियानो कारूआना से ड्रा खेला।
यह उपलब्धि शतरंज की दुनिया में प्रगनानंद के असाधारण कौशल और क्षमता को दर्शाती है।

मैग्नस कार्लसन की जीत:

पूर्व विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन ने फिडे विश्व कप सेमीफाइनल में निजात अबासोव के खिलाफ अपना गेम जीता।
कार्लसन की जीत शतरंज की दुनिया में उनके निरंतर प्रभुत्व और कौशल को दर्शाती है।
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में उनकी सफलता आधुनिक शतरंज इतिहास के सबसे मजबूत खिलाड़ियों में से एक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को मजबूत करती है।

क्वार्टरफ़ाइनल में भारतीय प्रतिनिधित्व:

चार भारतीय खिलाड़ी FIDE वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे।
इनमें आर प्रगनानंद एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं जो सेमीफाइनल में पहुंचे हैं।
यह प्रगनानंद के असाधारण प्रदर्शन को उजागर करता है और अंतरराष्ट्रीय शतरंज में अपनी छाप छोड़ने की उनकी क्षमता को रेखांकित करता है।

महिला फ़ाइनल:

FIDE विश्व कप के महिला फाइनल में रूस की एलेक्जेंड्रा गोर्याचकिना और बुल्गारिया की नर्ग्युल सालिमोवा शामिल थीं।
फ़ाइनल का पहला गेम 33 चालों के बाद बराबरी पर समाप्त हुआ।
यह एक करीबी मुकाबले का संकेत देता है और महिला चैंपियनशिप के रोमांचक समापन का मंच तैयार करता है।

फीफा महिला विश्व कप: स्पेन इंग्लैंड को 1-0 से हराकर विश्व चैंपियन बना

फुटबॉल में, स्पेन ने पहली बार सिंडी में फीफा महिला विश्व कप का खिताब जीतकर इंग्लैंड को 1-शून्य से हराकर इतिहास रच दिया।
29वें मिनट में कप्तान ओल्गा कार्मोना का लाजवाब स्ट्राइक विजेता साबित हुआ।
इंग्लैंड अपने दृष्टिकोण में प्रभावी था लेकिन स्पेन के शानदार प्रयास ने उन्हें जीत के करीब नहीं पहुंचने दिया।
स्पेन की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम, जिसे ला रोजा के नाम से भी जाना जाता है, जर्मनी के बाद पुरुष और महिला दोनों विश्व कप जीतने वाला दूसरा देश बन गया।
पूरे टूर्नामेंट में राष्ट्रीय टीम पर छाए विवादों और मतभेदों के बावजूद स्पेनिश टीम ने मौजूदा यूरोपीय चैंपियन और प्री-मैच पसंदीदा के खिलाफ जीत हासिल की, जिससे यह उपलब्धि असाधारण हो गई।

भारत के अनाहत सिंह ने एशियाई जूनियर स्क्वैश में स्वर्ण पदक जीता

भारत की अनाहत सिंह ने 16 से 20 अगस्त तक चीन के डालियान में आयोजित एशियाई जूनियर स्क्वैश व्यक्तिगत चैंपियनशिप के अंडर -17 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता।
15 वर्षीय अनाहत ने 20 अगस्त 2023 को फाइनल में हांगकांग की एना क्वांग को 3-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता।
उन्होंने क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में क्रमश: मलेशियाई खिलाड़ी डॉयस ली और व्हिटनी इसाबेल विल्सन को हराया था।
पिछले साल थाईलैंड में दिल्ली की अनाहत ने इस स्पर्धा का अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था।
भारतीय खिलाड़ी 2019 में तब सुर्खियों में आईं जब उन्होंने ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश के दौरान अंडर-11 खिताब जीता और डच जूनियर ओपन स्क्वैश में अंडर-13 खिताब जीता।
इस साल की शुरुआत में, अनाहत ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश के अंडर-15 वर्ग में फाइनल में मिस्र की सोहैला हाज़ेम को हराकर विजेता बनीं।

लियोनेल मेस्सी ने संयुक्त राज्य फुटबॉल में अपना स्वर्णिम प्रदर्शन जारी रखा है और इंटर मियामी के लिए फिर से चमके हैं

लियोनेल मेसी पिछले साल अपने देश को तीसरा फीफा विश्व कप खिताब दिलाने के बाद, लियोनेल मेस्सी इंटर मियामी के लिए फिर से चमके, उन्होंने नैशविले एससी के खिलाफ तनावपूर्ण पेनल्टी शूटआउट में नेट हासिल किया और अपनी टीम को अपना पहला लीग कप खिताब दिलाने में मदद की।
इसके साथ ही मेसी ने संयुक्त राज्य फुटबॉल में अपना स्वर्णिम सफर जारी रखा।
उन्होंने न केवल सात मैचों में यूएस क्लब के लिए अपना 10वां गोल किया है, बल्कि अपने नए क्लब के लिए खेला गया एक भी मैच नहीं हारा है।
जिस गोल ने उनके क्लब को अपना पहला लीग कप खिताब दिलाने में मदद की, वह मेसी के करियर में कप फाइनल में 37वां गोल था।

23वें मिनट में, मेस्सी ने दो रक्षकों को ड्रिबल करके और अपने प्रशंसकों की खुशी के लिए बॉक्स के किनारे से गेंद को गोल के ऊपरी-बाएँ कोने में भेजकर अपनी टीम को बढ़त दिला दी।
इसके साथ ही मेसी ने संयुक्त राज्य फुटबॉल में अपना स्वर्णिम सफर जारी रखा।
उन्होंने न केवल सात मैचों में यूएस क्लब के लिए अपना 10वां गोल किया है, बल्कि अपने नए क्लब के लिए खेला गया एक भी मैच नहीं हारा है।

युवा मामले और खेल मंत्रालय ने बाकू में ISSF शूटिंग विश्व चैंपियनशिप 2023 के लिए 34 भारतीय निशानेबाजों को फंड दिया

युवा मामले और खेल मंत्रालय (MYAS) बाकू, अजरबैजान में आगामी ISSF विश्व चैंपियनशिप के लिए भारतीय दल की भागीदारी का वित्तपोषण कर रहा है, जहां 17 पुरुष और 17 महिलाओं सहित कुल 34 भारतीय निशानेबाज भाग लेंगे।
भागीदारी के लिए वित्तीय सहायता में 57 सदस्यीय शूटिंग टीम की फंडिंग शामिल होगी जिसमें 34 निशानेबाज, 15 कोच और HPD सहित सहायक स्टाफ के 8 सदस्य शामिल हैं।
टीम की बोर्डिंग/आवास लागत, हवाई किराया, वीजा लागत और जेब से भत्ता (OPA) सहित अन्य खर्चों को प्रशिक्षण और प्रतिस्पर्धा के लिए एमवायएएस वार्षिक कैलेंडर (ACTC) योजना के तहत कवर किया जाएगा। इस आयोजन में भाग लेने वाले 34 निशानेबाजों में से 24 टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (टॉप्स) एथलीट हैं और 7 खेलो इंडिया एथलीट हैं।
यह आयोजन 14 अगस्त, 2023 को शुरू होगा और 1 सितंबर, 2023 को समाप्त होगा।
पेरिस ओलंपिक वर्ष में भारत के लिए प्रतिष्ठित कार्यक्रम महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें 15 आयोजनों में कुल 48 ओलंपिक कोटा उपलब्ध हैं।
ISSF शूटिंग विश्व चैंपियनशिप के 2022 संस्करण में, भारत ने 12 स्वर्ण, नौ रजत और 13 कांस्य पदक सहित 34 पदक जीते और चीन के बाद समग्र पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा।

भारत की जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने चार देशों के टूर्नामेंट में इंग्लैंड पर जीत हासिल की:

भारत की जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी के डसेलडोर्फ में आयोजित चार देशों के टूर्नामेंट में 4-0 के स्कोर के साथ विजयी होकर इंग्लैंड पर शानदार जीत हासिल की।
गोल स्कोरर: भारत के लिए राजिंदर सिंह, अमीर अली, अमनदीप लाकड़ा और अरजीत सिंह हुंदल ने गोल किए, जिनमें से प्रत्येक ने एक-एक गोल का योगदान दिया।
अभियान प्रारंभ: भारत ने स्पेन के खिलाफ 6-2 की प्रभावशाली जीत के साथ अपने टूर्नामेंट अभियान की शुरुआत की, जिससे उनकी भागीदारी के लिए मजबूत माहौल तैयार हुआ।
मिश्रित परिणाम: जबकि उनका पहला मैच विजयी रहा, भारत को मेजबान देश जर्मनी के खिलाफ अपने मुकाबले में झटका लगा, जहां वे 2-3 के स्कोर से हार गए।
टेबल टॉपर्स: इंग्लैंड के खिलाफ जीत ने भारत को लीग चरण में शीर्ष पर पहुंचा दिया, जिससे टूर्नामेंट में उनकी शक्ति की पुष्टि हुई।
आगामी फाइनल: पूरे लीग चरण में अपने प्रभावशाली प्रदर्शन के परिणामस्वरूप, भारत ने फाइनल में जगह पक्की कर ली, जहां उसका सामना जर्मनी से होना है, जो टूर्नामेंट के बहुप्रतीक्षित समापन का प्रतीक है।

खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राजस्थान भर में 33 खेलो इंडिया केंद्रों का उद्घाटन किया

केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री श्री. अनुराग सिंह ठाकुर ने आज सुबह जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान राज्य में 33 खेलो इंडिया केंद्रों का उद्घाटन किया।
केंद्रीय मंत्री ने घोषणा की कि राजस्थान में अतिरिक्त 18 खेलो इंडिया केंद्रों के साथ एक समर्पित खेल विज्ञान केंद्र के साथ एक राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा, इस प्रकार राज्य में खेलो इंडिया केंद्रों की कुल संख्या 51 हो जाएगी।
यह भी घोषणा की गई कि खेलो इंडिया केंद्रों के बीच प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी जबकि कोचिंग द कोच कार्यक्रम को खेलो इंडिया केंद्रों तक भी बढ़ाया जाएगा।
प्रशिक्षकों के साथ-साथ KIC प्रशिक्षकों को भी हमारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षकों के साथ जोड़कर प्रशिक्षित किया जाएगा।
इस अवसर पर राजस्थान सरकार के युवा मामले और खेल मंत्री श्री अशोक चांदना के साथ-साथ राज्य, YAS मंत्रालय और साई के अन्य प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

राजस्थान के बारे में:

राज्यपाल: कलराज मिश्र
मुख्यमंत्री: अशोक गेहलोत
पूंजी: जयपुर
राष्ट्रीय उद्यान: केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान
वन्यजीव अभ्यारण्य: बस्सी वन्यजीव अभयारण्य, कुम्भलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य

महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय आइकन घोषित किया

भारत रत्न से सम्मानित, महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को मतदाताओं के बीच जागरूकता पैदा करने और चुनावी प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय चुनाव आयोग (ECI) का राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया है।
नई दिल्ली के अकावानी भवन में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, श्री तेंदुलकर ने कहा कि क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद यह उनके लिए एक नई पारी है।
उन्होंने कहा कि देश के विकास में एक-एक वोट महत्वपूर्ण है। उन्होंने मतदाताओं विशेषकर युवा नागरिकों को वोट डालने के लिए प्रोत्साहित किया।
कार्यक्रम के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की मौजूदगी में सचिन तेंदुलकर के साथ तीन साल के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये
इस साझेदारी के माध्यम से, ECI का लक्ष्य मतदान के प्रति शहरी और युवाओं की उदासीनता की चुनौतियों का समाधान करना है।
चुनाव आयोग लगातार विभिन्न क्षेत्रों के प्रसिद्ध भारतीयों के साथ जुड़ा हुआ है और मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए उन्हें अपने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में नामित करता है।
पिछले साल आयोग ने मशहूर अभिनेता पंकज त्रिपाठी को नेशनल आइकॉन के रूप में मान्यता दी थी
इससे पहले, 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान, क्रिकेटर एमएस धोनी, अभिनेता आमिर खान और बॉक्सिंग चैंपियन मैरी कॉम ईसीआई के राष्ट्रीय प्रतीक थे।

भारत के हनी डबास और राहुल जोगराजिया ने विश्व पैरा पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप में पहला ऐतिहासिक स्वर्ण और रजत पदक जीता

भारतीय पावरलिफ्टर हनी डबास और राहुल जोगराजिया ने दुबई 2023 विश्व पैरा पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप में शानदार शुरुआत करते हुए क्रमश: स्वर्ण और रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया।

डबास ने 132 किलोग्राम और फिर 135 किलोग्राम वजन उठाकर अद्भुत धैर्य, दृढ़ संकल्प और ताकत का प्रदर्शन करते हुए देश का पहला स्वर्ण पदक जीता।
इस बीच, जोगराजिया ने अपने हमवतन के बाद कड़े मुकाबले वाले पुरुषों के -72 किलोग्राम जूनियर भार वर्ग में 132 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक हासिल किया।
डबास के पास दुबई 2022 फ़ैज़ा विश्व कप से दो स्वर्ण पदक हैं।
विश्व चैंपियनशिप में भारत का एकमात्र पदक परमजीत कुमार (पुरुष -49 किग्रा) ने त्बिलिसी 2021 विश्व चैंपियनशिप में जीता है।

नई दिल्ली में अरुणाचल प्रदेश लीग का शुभारंभ हुआ

अरुणाचल प्रदेश लीग नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है
एक नए बॉल गेम का लक्ष्य उत्तर पूर्व में फुटबॉल के मैदान से लेकर क्रिकेट पिच तक प्रशंसकों के उत्साह को दोहराना है।
इसे BCCI, अरुणाचल क्रिकेट एसोसिएशन और विभिन्न राज्य निकायों का समर्थन प्राप्त है, जिसका लक्ष्य पहाड़ों में क्रिकेट को बहुत जरूरी बढ़ावा देना है।
8 सितंबर से शुरू होने वाले इसमें पांच टीमें 13 मैच खेलेंगी और शिखर मुकाबला अगले महीने की 16 तारीख को होगा।
लीग को काफी उम्मीदें हैं, वह अरुणाचल प्रदेश और उत्तर पूर्व की प्रतिभाओं को निखारना चाहती है।

विश्व कुश्ती संस्था ने चुनाव न कराने के कारण भारतीय कुश्ती महासंघ को निलंबित कर दिया है

यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग (UWW) ने समय पर चुनाव कराने में विफल रहने के कारण भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
इस कदम से भारतीय पहलवानों को आगामी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय ध्वज के नीचे प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति नहीं मिलेगी।
भारतीय पहलवानों को 16 सितंबर से शुरू होने वाली ओलंपिक-क्वालीफाइंग विश्व चैंपियनशिप में 'तटस्थ एथलीट' के रूप में प्रतिस्पर्धा करनी होगी।
भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) ने 27 अप्रैल को तदर्थ पैनल नियुक्त किया था और समिति को 45 दिनों के भीतर चुनाव कराने थे।
लेकिन तदर्थ पैनल चुनाव कराने के लिए 45 दिन की समय सीमा का पालन करने में विफल रहा।

भारतीय निशानेबाज अमनप्रीत सिंह ने अजरबैजान में ISSF विश्व चैम्पियनशिप 2023 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता

भारतीय निशानेबाज अमनप्रीत सिंह ने अजरबैजान के बाकू में आईएसएसएफ विश्व चैम्पियनशिप 2023 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता।
महिलाओं की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल शूटिंग स्पर्धा में, जबकि तियाना, याशिता शौकीन और कृतिका शर्मा व्यक्तिगत प्रतियोगिता में पदक दौर में जगह बनाने में असफल रहीं, वे 1601 के संयुक्त स्कोर के साथ टीम कांस्य जीतने में सफल रहीं।
उस दिन दो पदकों से चैंपियनशिप में भारत की कुल संख्या नौ हो गई - पांच स्वर्ण और चार कांस्य पदक।

खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने घोषणा की कि खेलो इंडिया महिला लीग को आधिकारिक तौर पर अस्मिता महिला लीग के नाम से जाना जाएगा

केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने घोषणा की है कि खेलो इंडिया महिला लीग को आधिकारिक तौर पर अस्मिता महिला लीग के नाम से जाना जाएगा।
अस्मिता का तात्पर्य कार्रवाई के माध्यम से महिलाओं को प्रेरित करके खेल में उपलब्धि हासिल करना है।
एक सोशल मीडिया पोस्ट में, श्री ठाकुर ने इस विचार की संकल्पना करने और अस्मिता पोर्टल और नया लोगो विकसित करने के लिए खेलो इंडिया की पूरी टीम की सराहना करते हुए कहा कि यह भारतीय खेलों के डिजिटलीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
अस्मिता पोर्टल एक व्यापक संसाधन के रूप में कार्य करता है, जो अन्य सुविधाओं के अलावा आगामी लीगों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।
यह किसी भी स्कूल, कॉलेज, सरकारी या निजी संगठन को 'अस्मिता महिला लीग' की मेजबानी करने और खेल उत्कृष्टता की दिशा में खेलो इंडिया के मार्च का हिस्सा बनने में सक्षम बनाएगा।
श्री ठाकुर ने कहा कि महिलाओं के खेल को बढ़ावा देने के लिए सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता ने विशिष्ट और जमीनी स्तर पर बेहतर अवसरों, सुविधाओं और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का मार्ग प्रशस्त किया है।

राजेश्वरी कुमारी ने पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत के लिए एक और शूटिंग स्थान सुरक्षित किया

शूटिंग में राजेश्वरी कुमारी ने पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत के लिए एक और शूटिंग स्थान सुरक्षित कर लिया है।
वह बाकू, अजरबैजान में ISSF विश्व चैम्पियनशिप 2023 में महिला ट्रैप फाइनल में पांचवें स्थान पर रही, और महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा में भारत को पहला स्थान दिलाया।
ISSF विश्व चैम्पियनशिप 2023 पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालीफाइंग इवेंट के रूप में कार्य करती है।
12 ओलंपिक व्यक्तिगत शूटिंग स्पर्धाओं में से प्रत्येक में सर्वश्रेष्ठ चार फिनिशर, प्रत्येक देश से एक, को उनकी राष्ट्रीय टीमों में एक सीट मिलती है, जिससे कुल 48 निशानेबाज मिलते हैं।

विश्व कप फाइनल 2023 में नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन से हारने के बाद भारत के आर. प्रगनानंद को रजत पदक से संतोष करना पड़ा

शतरंज में, नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने भारत के आर. प्रागनानंदा को टाई-ब्रेक में हराकर अजरबैजान के बाकू में फिडे शतरंज विश्व कप 2023 का खिताब जीता।
फाइनल में, कार्लसन ने प्रगनानंधा के खिलाफ दूसरा टाई-ब्रेक ड्रा करने के बाद विश्व कप जीता।
अंतिम स्कोर कार्लसन 1.5 और प्रग्गनानंद 0.5 था। जहां कार्लसन को स्वर्ण पदक मिला, वहीं प्रगनानंद को रजत पदक मिला।
मैग्नस कार्लसन अंततः अपने करियर में पहली बार FIDE विश्व कप जीतने में सफल रहे।
उन्होंने फाइनल में भारत के प्रगनानंद को हराया, लेकिन इससे पहले कि 18 वर्षीय किशोर प्रतिभा ने उसे टाई-ब्रेकर के माध्यम से खींच लिया था।
टाईब्रेकर के दूसरे गेम के बाद कार्लसन की जीत पक्की हो गई।
फाइनल में मिली हार के बावजूद फिडे विश्व कप चेन्नई के इस युवा खिलाड़ी के लिए यादगार रहा क्योंकि उन्होंने प्रतिष्ठित कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में भी जगह पक्की की जो विश्व चैंपियन डिंग लिरेन के लिए अगले विश्व शतरंज चैंपियनशिप मुकाबले में चुनौती पेश करने के लिए आयोजित किया जाता है।

Click Here to Subscribe Our Yearly Mock Test Package

प्राग, जो विश्व कप के दौरान 18 वर्ष के हो गए, अब तक के सबसे कम उम्र के विश्व कप फाइनलिस्ट थे और सबसे कम उम्र के विश्व कप विजेता हैं।
प्राग विश्व कप के फाइनल में जगह बनाने वाले सबसे कम वरीयता प्राप्त खिलाड़ी भी हैं।
प्रग्गनानंद ने भारतीय शतरंज के इतिहास की किताबों में अपना नाम दर्ज कराया।
वह विश्वनाथन आनंद के बाद फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए थे और शीर्ष पर भारतीय दिग्गज में शामिल होने से एक जीत दूर थे।

दृष्टिबाधित भारतीय महिला टीम ने बर्मिंघम में ऑस्ट्रेलिया को हराकर IBSA विश्व कप फाइनल जीता

भारतीय महिला दृष्टिबाधित टीम ने बर्मिंघम में अंतर्राष्ट्रीय नेत्रहीन खेल महासंघ (IBSA) विश्व खेलों के T-20 फाइनल में जीत हासिल की।
भारतीय टीम ने बारिश से बाधित मैच में ऑस्ट्रेलिया को नौ विकेट से हराया।
ऑस्ट्रेलिया ने 115 रन का लक्ष्य रखा था, लेकिन बारिश के कारण मैच 9 ओवर का कर दिया गया और लक्ष्य को संशोधित कर 42 रन कर दिया गया
भारत ने महज 3.3 ओवर में एक विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया
इस बीच, भारतीय पुरुष दृष्टिबाधित टीम इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन (IBSA) वर्ल्ड गेम्स 2023 के फाइनल में पाकिस्तान से भिड़ेगी।

यूके के बारे में:

प्रधान मंत्री: ऋषि सुनक
पूंजी: लंडन
मुद्रा: पौंड स्टर्लिंग

IBSA के बारे में

इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन एक गैर-लाभकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1981 में पेरिस, फ्रांस में की गई थी। इसे पहले इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था।
स्थापित: 1981
मुख्यालय: बॉन, जर्मनी
राष्ट्रपति: सैंड्रो डि गिरोलामो

यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट न्यूयॉर्क में शुरू होगा

सीज़न का चौथा और अंतिम ग्रैंड स्लैम, यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट न्यूयॉर्क में शुरू होगा।
महिला एकल में, दुनिया की नंबर 1 पोलैंड की इगा स्विएटेक अपनी 2022 की जीत का बचाव करना चाहती हैं।
महिलाओं की प्रतियोगिता में, गत चैंपियन इगा अपने अभियान की शुरुआत करने के लिए आर्थर ऐश स्टेडियम में स्वीडन की रेबेका पीटरसन से भिड़ेंगी।
पुरुष एकल में सर्बियाई नोवाक जोकोविच की वापसी हुई है।
दुनिया का नंबर 2 खिलाड़ी अपने चौथे यूएस ओपन पुरुष एकल टेनिस खिताब के लिए प्रयास कर रहा है और मार्गरेट कोर्ट के 24 ग्रैंड स्लैम के रिकॉर्ड की बराबरी करना चाहेगा, जो इतिहास में किसी भी खिलाड़ी द्वारा सबसे अधिक है।
2023 विंबलडन के फाइनल में जोकोविच को हराने वाले स्पेन के कार्लोस अल्कराज प्रतियोगिता में शीर्ष वरीयता प्राप्त हैं।

अलकराज अपने खिताब की रक्षा की शुरुआत जर्मनी के डोमिनिक कोएफ़र के खिलाफ करेंगे।

नीरज चोपड़ा हंगरी के बुडापेस्ट में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने

भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने हंगरी के बुडापेस्ट में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता।
पुरुषों के भाला फेंक फाइनल में, नीरज चोपड़ा ने 88.17 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता।
पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 87.82 मीटर के थ्रो से रजत पदक जीता।
चेक खिलाड़ी जैकब वाडलेज्च को कांस्य पदक मिला, भाला फेंक स्पर्धा में किशोर जेना 5वें और डीपी मनु 6वें स्थान पर रहे।
महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपलचेज़ स्पर्धा में, भारत की पारुल चौधरी 11वें स्थान पर रहीं, लेकिन उन्होंने अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालीफाई कर लिया।
उन्होंने महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपलचेज़ फ़ाइनल में 9:15:31 का समय निकाला।
इस प्रदर्शन के साथ पारुल ने महिलाओं की स्टीपलचेज़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया।
पुरुषों की 4x400 मीटर रिले में, मुहम्मद अनस याहिया, अमोज जैकब, मुहम्मद अजमल वरियाथोडी और राजेश रमेश की भारतीय टीम 2:59.92 के प्रभावशाली समय के साथ पांचवें स्थान पर रही।
इसी चौकड़ी ने फाइनल के लिए क्वालीफाई करने के लिए 2.59.05 सेकेंड का नया एशियाई और राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था।

नवीनतम समाचार

स्टार भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने 87.66 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ लॉज़ेन डायमंड लीग 2023 का खिताब जीता।

हंगरी के बारे में

राजधानी: बुडापेस्ट
राष्ट्रपति: कैटालिन नोवाक
प्रधान मंत्री: विक्टर ओर्बन
मुद्रा: फ़ोरिंट

ओमान के सलालाह में महिला एशियाई हॉकी 5एस विश्व कप क्वालीफायर में भारत ने थाईलैंड को हराया

ओमान के सलालाह में महिला एशियाई हॉकी फाइव्स विश्व कप क्वालीफायर में भारत ने थाईलैंड को 5-4 से हरा दिया।
भारत के लिए नवजोत कौर, मोनिका दीपी टोप्पो, महिमा चौधरी और अजमीना कुजूर ने गोल किये।
थाईलैंड के लिए पिरेसराम अनोंगनाट, औंजई नत्थाकर्ण और सुवापत कोनथोंग ने गोल किए।
भारत के लिए मोनिका डिपी टोप्पो ने दो गोल किए, जबकि थाईलैंड के लिए औंजई नत्थाकर्ण ने दो गोल किए।

ओमान के बारे में:

राजधानी: मस्कट
मुद्रा: ओमानी रियाल

थाईलैंड के बारे में:

राजधानी: बैंकॉक
मुद्रा: थाई बात

नवीनतम समाचार

ओडिशा सरकार ने पुरुष और महिला दोनों भारतीय हॉकी टीमों (सीनियर और जूनियर) के लिए 2023 से 2033 तक अगले दस वर्षों के लिए अपने प्रायोजन का विस्तार करने का फैसला किया।
13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 में हॉकी हरियाणा टीम को विजेता घोषित किया गया।
हॉकी में, भारत ने नीदरलैंड के आइंडहोवन में अपने अंतिम FIH प्रो लीग 2022-23 मैच में अर्जेंटीना को 2-1 से हराया।
भारत ने चार बार के चैंपियन दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराकर जापान के काकामिगाहारा में अपना पहला महिला जूनियर हॉकी एशिया कप जीता।

एचएस प्रणय ने कोपेनहेगन में BWF विश्व चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक जीता

बैडमिंटन में, भारत के शीर्ष शटलर एचएस प्रणय को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा क्योंकि उन्हें मौजूदा बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन (BWF) विश्व चैंपियनशिप 2023 के सेमीफाइनल में कुनलावुत विटिडसर्न से हार का सामना करना पड़ा।
प्रणॉय दुनिया के तीसरे नंबर के खिलाड़ी और तीन बार के जूनियर चैंपियन विटिडसर्न से 21-18, 13-21, 14-21 से हार गए।
प्रणय ने कुआलालंपुर में वर्ल्ड नंबर 2 और मौजूदा चैंपियन विक्टर एक्सेलसन को हराकर BWF विश्व चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया।
इस जीत के साथ, वर्ल्ड नंबर 7 प्रणॉय ने घरेलू पसंदीदा एक्सेलसन को तीन गेमों में 21-13, 15-21, 16-21 से हराकर भारत के लिए कांस्य पदक पक्का कर लिया।
यह विश्व चैंपियनशिप में भारत का 14वां पदक है, इसमें एक स्वर्ण, चार रजत और नौ कांस्य पदक शामिल हैं।
टूर्नामेंट के इतिहास में चीन सबसे सफल टीम है, जिसमें 69 स्वर्ण, 48 रजत और 79 रजत सहित 196 पदक हैं।
BWF विश्व चैंपियनशिप 2023 21 से 27 अगस्त तक डेनमार्क के कोपेनहेगन में आयोजित की जा रही है।

BWF के बारे में

मुख्यालय: कुआलालंपुर, मलेशिया
गठन: 1934
राष्ट्रपति: पॉल-एरिक होयर लार्सन
सदस्यता: 194 सदस्य संघ

नवीनतम समाचार

एचएस प्रणय ने 420,000 डॉलर इनामी मलेशिया मास्टर्स में पुरुष एकल का खिताब जीता जो छह साल में उनका पहला व्यक्तिगत खिताब है जिससे वह इस साल कई BWF विश्व टूर टूर्नामेंट में 10वें अलग चैंपियन बने।

पाकिस्तान से हार के बाद भारतीय पुरुष ब्लाइंड क्रिकेट टीम को रजत पदक से संतोष करना पड़ा

बर्मिंघम के एजबेस्टन में चल रहे इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन (IBSA) वर्ल्ड गेम्स 2023 में पुरुषों की टी-20 क्रिकेट स्पर्धा के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ हार के बाद भारतीय पुरुष दृष्टिबाधित टीम को रजत पदक से संतोष करना पड़ा।
भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित बीस ओवर में 3 विकेट पर 184 रन बनाए।
पाकिस्तान ने दमदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए 15वें ओवर में 185 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया।
क्रिकेट खेल को पहली बार आईबीएसए विश्व खेलों में शामिल किया गया और भारत की पुरुष और महिला दोनों नेत्रहीन टीमों ने फाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का किया।
इससे पहले, भारतीय महिला टीम ने डीएलएस पद्धति के आधार पर ऑस्ट्रेलिया को नौ विकेट से हराकर भारत के लिए ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता था।

श्रीलंका फुटबॉल फेडरेशन अब फीफा द्वारा प्रतिबंधित नहीं है:

श्रीलंका फुटबॉल महासंघ (FFSL) पर अब विश्व फुटबॉल नियामक संस्था फीफा द्वारा प्रतिबंध नहीं है।
महासंघ की गतिविधियों में सरकार के हस्तक्षेप के कारण जनवरी 2023 में प्रतिबंध लगाया गया।
फीफा के महासचिव फातमा समौरा के 28 अगस्त के एक पत्र के अनुसार, FFSL का निलंबन तुरंत हटा लिया जाएगा, जिसमें कहा गया है कि निर्णय 27 अगस्त को किया गया था।
अपनी कार्यकारी समिति के लिए, FFSL नए चुनाव कराने पर भी सहमत हो गया है।
श्रीलंकाई फुटबॉल के लिए प्रतिबंध हटाना एक बड़ी जीत है।
यह इंगित करता है कि FFSL की विकास पहल के साथ-साथ देश की राष्ट्रीय टीम की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता बहाल की जाएगी।
यह निलंबन गुटीय लड़ाई और खेल निकाय के प्रशासन में राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण हुआ था।
हालाँकि, विभिन्न गुटों ने एक बैठक में खेल के विकास के सामान्य लक्ष्य के लिए काम करने का निर्णय लिया2कुछ हफ़्ते पहले, उनके बीच मतभेदों को ख़त्म कर दिया गया था।
फीफा ने मौजूदा राष्ट्रीय खेल कानून से स्थानीय फुटबॉल प्रशासन को बाहर करने की मांग की थी, जो खेल मंत्री को इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का अधिकार देता है।

फीफा के बारे में

राष्ट्रपति: गियानी इन्फैनटिनो,
मुख्यालय: ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड.
स्थापना: 21 मई 1904

श्रीलंका के बारे में

राजधानियाँ: कोलंबो, श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे
मुद्रा: श्रीलंकाई रुपया
प्रधान मंत्री: दिनेश गुणवर्धने

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

Pixxel ने भारतीय वायु सेना के लिए लघु बहु-पेलोड उपग्रह बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय का अनुदान जीता

बेंगलुरु आधारित अंतरिक्ष स्टार्टअप Pixxel ने भारतीय वायु सेना (IAF) के लिए छोटे मल्टी-पेलोड उपग्रहों के निर्माण के लिए रक्षा मंत्रालय (MoD) के तहत इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस (iDEX) से कई करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त किया।

अनुदान का उद्देश्य:

अंतरिक्ष मिशन के हर चरण को संबोधित करने वाली प्रौद्योगिकियों को विकसित करना, मिशन योजना और विनिर्माण से लेकर उपग्रह डेटा विश्लेषण और बहुत कुछ।
हाइपरस्पेक्ट्रल उपग्रह निर्माण के क्षेत्र में अपनी अग्रणी तकनीक के कारण, Pixxel कई कंपनियों के बीच अनुदान के विजेता के रूप में उभरा।
यह पिक्सेल के रक्षा क्षेत्र में प्रवेश का प्रतीक है।
यह अनुदान स्पार्क्स पहल का हिस्सा है, जो 2022 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए मिशन डेफस्पेस के अंतर्गत आता है।

अनुदान के लाभ:

यह अनुदान Pixxel को 150 किलोग्राम तक वजन वाले छोटे उपग्रह विकसित करने में सक्षम करेगा।

इन उपग्रहों को इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल, इन्फ्रारेड, सिंथेटिक एपर्चर रडार और हाइपरस्पेक्ट्रल उद्देश्यों के लिए डिज़ाइन किया जाएगा।

Pixxel पहली बार बाहरी उपग्रहों के निर्माण के लिए इन-हाउस माइक्रोसैटेलाइट बनाने की अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करेगा।

मिशन डेफस्पेस के बारे में:

मिशन डेफस्पेस को 75 रक्षा अंतरिक्ष चुनौतियों के साथ लॉन्च किया गया था जिन्हें 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: लॉन्च सिस्टम, सैटेलाइट सिस्टम, संचार और पेलोड सिस्टम, ग्राउंड सिस्टम और सॉफ्टवेयर सिस्टम।

उद्देश्य:

iDEX सहित रक्षा मंत्रालय की विभिन्न पहलों के माध्यम से स्टार्टअप और युवा उद्यमियों द्वारा रक्षा अनुप्रयोगों के लिए अंतरिक्ष में प्रौद्योगिकी विकास को प्रोत्साहित करना।

स्पार्क अनुदान - iDEX (प्राइम) और DISC पहल के माध्यम से चयनित स्टार्टअप्स को प्रदान किया जाता है - जिसका उद्देश्य भारतीय इनोवेटर्स और उद्यमियों को तकनीकी रूप से उन्नत समाधान प्रदान करने के साथ-साथ भारत में गहन-तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा देने में सक्षम बनाने के लिए नवाचार को उत्प्रेरित करना है।

अब तक, Pixxel ने वाणिज्यिक हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रह लॉन्च किए हैं जो अपने ग्राहकों को पृथ्वी-इमेजिंग सेवाएं प्रदान करते हैं जिनमें यूएस "राष्ट्रीय टोही कार्यालय (NRO) शामिल है।

पिक्सल के बारे में:

स्थापित: फरवरी 2019

मुख्यालय: बैंगलोर, कर्नाटक, भारत

सह संस्थापक और CEO: अवैस अहमद

एलन मस्क की स्पेसएक्स ने दुनिया का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह ज्यूपिटर-3 लॉन्च किया

ह्यूजेस नेटवर्क सिस्टम, एक इकोस्टार (नैस्डेक:सैट्स) कंपनी ने घोषणा की है कि उसके जुपिटर 3 अल्ट्रा हाई-डेंसिटी उपग्रह को संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) के फ्लोरिडा में ऐतिहासिक कैनेडी स्पेस सेंटर लॉन्च पैड 39 ए से स्पेसएक्स फाल्कन हेवी रॉकेट पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है।

इसे इकोस्टार XXIV के नाम से भी जाना जाता है, JUPITER 3 को पालो ऑल्टो, CA में मैक्सार टेक्नोलॉजीज द्वारा बनाया गया था, और इसे उत्तरी और दक्षिण अमेरिका में ग्राहकों को गीगाबाइट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए इंजीनियर किया गया है। यह स्पेसएक्स के ट्रिपल-बूस्टर रॉकेट के लिए 7वां लॉन्च होगा, जो 2018 में बहुत धूमधाम से शुरू हुआ था।

उपग्रह बृहस्पति-3 के बारे में:

JUPITER-3 नामक उपग्रह, कैलिफोर्निया के पालो अल्टो में मैक्सार टेक्नोलॉजीज के स्वामित्व में है, और यह इतिहास का सबसे बड़ा वाणिज्यिक संचार उपग्रह है।

ज्यूपिटर 3 का आकार एक वाणिज्यिक विमान के पंखों के फैलाव को टक्कर देगा, जो 130-160 फीट तक हो सकता है। माना जाता है कि उपग्रह 500 अतिरिक्त GBPS के साथ मैक्सार के उपग्रह बेड़े की सीमा को दोगुना कर देगा, जिससे यह अधिक ग्राहकों को सेवा देने में सक्षम हो जाएगा, खासकर उन क्षेत्रों में जहां केबल और फाइबर की उपलब्धता दुर्गम या अविश्वसनीय है।

संचार उपग्रह इन-फ्लाइट वाई-फाई, समुद्री संघों, उद्यम नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटरों (MNO) के लिए बैकहॉल और उत्तरी और दक्षिण अमेरिका में सामुदायिक वाई-फाई समाधान जैसी सेवाओं को बढ़ावा देगा।
फाल्कन हेवी उपग्रह को पृथ्वी के चारों ओर भूस्थैतिक कक्षा में पहुंचाएगा।

नवीनतम समाचार:

जुलाई 2023 में, स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन, जिसे आमतौर पर स्पेसएक्स कहा जाता है, ने संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्लोरिडा में केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन के स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 40 से लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) में 22 स्टारलिंक V2 'मिनी' उपग्रह लॉन्च किए।

स्पेसएक्स के बारे में:

स्थापित: 14 मार्च 2002
मुख्यालय: हॉथोर्न, कैलिफ़ोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका
CEO एवं अध्यक्ष: एलोन मस्क
SpaceX, एक अमेरिकी अंतरिक्ष यान निर्माता, प्रक्षेपण सेवा प्रदाता और उपग्रह संचार कंपनी है।

NASA ने स्ट्रीमिंग सेवा NASA+ लॉन्च की

नासा (नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन) ने एक ऑन-डिमांड स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पेश किया है, जिसका नाम नासा + है।
नासा का नया प्लेटफ़ॉर्म अंतरिक्ष घटनाओं, मूल सामग्री और वृत्तचित्रों का लाइव कवरेज प्रदान करेगा, जो विशेष रूप से प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध होगा जहां सामग्री विज्ञापन-मुक्त और बिना किसी शुल्क के होगी।
इसके अलावा, नासा अपनी विज्ञान वेबसाइटों का भी नवीनीकरण कर रहा है।
अभी के लिए, यह एक बीटा वेबसाइट है जिसे बीटा वेबसाइट के पूर्वावलोकन के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है।
नासा ने जनता को वेबसाइट देखने और beta.nasa.gov पर फीडबैक देने के लिए आमंत्रित किया है।
इन फीडबैक के आधार पर, नासा बीटा साइट को निरंतर आधार पर अद्यतन और सुधारना जारी रखेगा।

नवीनतम समाचार:

जुलाई 2023 में, नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA) ने टेलीस्कोप के विज्ञान के पहले वर्ष के पूरा होने का जश्न मनाने के लिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ली गई एक छोटे सितारा बनाने वाले क्षेत्र की एक नई छवि जारी की।

नासा के बारे में:

स्थापना: 29 जुलाई, 1958
मुख्यालय: वाशिंगटन, डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका
प्रशासक: बिल नेल्सन

संयुक्त राज्य अमेरिका 2025 तक ऑस्ट्रेलिया को निर्देशित मिसाइलें विकसित करने में मदद करेगा

संयुक्त राज्य अमेरिका (US) ऑस्ट्रेलिया को 2025 तक गाइडेड मल्टीपल-लॉन्च रॉकेट सिस्टम तैयार करने में मदद करेगा।
ऑस्टिन और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्षों रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस और विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ वार्षिक ऑस्ट्रेलिया-अमेरिका मंत्रिस्तरीय वार्ता (AUSMIN) के लिए ऑस्ट्रेलियाई राज्य क्वींसलैंड में हैं।
यह पहली बार है कि ऑस्ट्रेलिया ने 2019 के बाद से COVID-19 व्यवधान के कारण उच्च स्तरीय बैठक की मेजबानी की है।

संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में:

अध्यक्ष: जो बिडेन
राजधानी: वाशिंगटन डीसी
मुद्रा: अमेरिकी डॉलर

भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने आकाश का पहला रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर DRDO को सौंप दिया

भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) ने अपने नए अत्याधुनिक सीकर फैसिलिटी सेंटर (SFC) में निर्मित अगली पीढ़ी की हथियार प्रणाली आकाश के पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी (RF) सीकर को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) को सौंप दिया है।

BDL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, कमोडोर ए माधवराव ने इस सुविधा में BDL द्वारा निर्मित पहला आरएफ सीकर रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और DRDO के अध्यक्ष डॉ. समीर वी कामत को सौंपा।

साधक के बारे में:

सीकर एक महत्वपूर्ण और प्रौद्योगिकी गहन उपप्रणाली है जिसका उपयोग टर्मिनल चरण में लक्ष्य ट्रैकिंग के लिए सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों में किया जाता है।

आरएफ सीकर को DRDO के अनुसंधान केंद्र इमारत द्वारा डिजाइन किया गया है, और BDL द्वारा हैदराबाद में BDL, कंचनबाग यूनिट में स्थापित अपने अत्याधुनिक सीकर सुविधा केंद्र में निर्मित किया गया है।

आकाश-एनजी के बारे में:

आकाश-एनजी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है।

यह का एक नया संस्करण है, आकाश मिसाइल जो लगभग 60 किमी की दूरी पर लक्ष्य पर हमला कर सकता है और 2.5 मैक तक की गति से उड़ सकता है।

इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला (DRDL), हैदराबाद द्वारा अन्य DRDO प्रयोगशालाओं के सहयोग से विकसित किया गया है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) द्वारा उत्पादित किया जा रहा है।

आकाश भारत की पहली स्वदेश निर्मित मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जो कई दिशाओं से कई लक्ष्यों पर निशाना साध सकती है

BDL के बारे में:

स्थापना: 1970
मुख्यालय: हैदराबाद, तेलंगाना
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक: ए माधवराव,

भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित अगली पीढ़ी के चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग (MRI) स्कैनर का नई दिल्ली में अनावरण किया गया

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित, किफायती, हल्का, अल्ट्राफास्ट, हाई फील्ड (1.5 टेस्ला), नेक्स्ट जेनरेशन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग (MRI) स्कैनर लॉन्च किया।

इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार से MRI स्कैनर खरीदने में होने वाला पूंजी निवेश भी काफी हद तक कम हो जाएगा, जिससे काफी विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी।

मुख्य विचार:

वोक्सेलग्रिड्स इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के तहत देश की अधूरी जरूरत को पूरा करने के लिए एक पूर्ण (कॉम्पैक्ट), हल्का, अगली पीढ़ी का MRI स्कैनर विकसित किया गया है।
विश्व स्तरीय MRI विकसित करने के लिए खर्च किए गए 17 करोड़ रुपये में से 12 करोड़ रुपये जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) द्वारा जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (BIRAC) के माध्यम से प्रदान किए गए थे।
70% विश्व की अधिकांश आबादी के पास चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग (MRI) की निदान पद्धति तक पहुंच नहीं है।
MRI स्कैनर तक पहुंच आमतौर पर अन्य इमेजिंग तौर-तरीकों जैसे कंप्यूटेड टोमोग्राफी (सीटी), एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड की तुलना में 3 गुना से भी कम है।
इसका कारण इसकी अत्यधिक उच्च पूंजी लागत है जो भारत जैसे विकासशील देशों में एक समस्या है।
अब, भारत में MRI स्कैनर का स्थापित आधार सीटी स्कैनर की तुलना में 3 गुना कम है, जिसका मुख्य कारण MRI मशीनों की उच्च लागत और आयात निर्भरता है।
स्वास्थ्य देखभाल पहुंच और समावेशन में सुधार लाने के उद्देश्य से आयुष्मान भारत जैसी पहल के साथ MRI मशीनों की वार्षिक मांग 2030 तक दोगुनी से अधिक होने की उम्मीद है।

इसरो चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान के चंद्र कक्षा इंजेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार है

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान के चंद्र कक्षा इंजेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार है।
चंद्रमा पर जाने वाला अंतरिक्ष यान चंद्रमा की लगभग दो-तिहाई दूरी तय कर चुका है।
इसरो ने कई रणनीतिक कदम उठाए हैं, जिससे पृथ्वी से अंतरिक्ष यान की दूरी उत्तरोत्तर बढ़ रही है।
विशेष रूप से, 1 अगस्त को, यान को पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की ओर ले जाने के लिए एक महत्वपूर्ण स्लिंगशॉट पैंतरेबाज़ी को सफलतापूर्वक नियोजित किया गया था।
ट्रांस-लूनर इंजेक्शन के बाद, चंद्रयान -3 अंतरिक्ष यान पृथ्वी की कक्षा से स्थानांतरित हो गया और चंद्रमा की ओर अपना प्रक्षेप पथ शुरू कर दिया। 5 अगस्त को एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम निर्धारित है, जहां चंद्र कक्षा इंजेक्शन (एलओआई) को चंद्रमा के निकटतम बिंदु (पेरिल्यून) के दौरान निष्पादित किया जाएगा।

नवीनतम समाचार

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने भौतिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के स्नातकोत्तर और अंतिम वर्ष के स्नातक छात्रों के लिए अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण (START) नामक एक नया परिचयात्मक स्तर का ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) एक्स-रे पोलारिमीटर सैटेलाइट (XPoSat) बनाने के लिए रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट (RRI), बेंगलुरु, कर्नाटक के साथ सहयोग कर रहा है, जिसे बाद में 2023 में लॉन्च किया जाना है।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने आंध्र प्रदेश (एपी) के श्रीहरिकोटा में हेवी लिफ्ट LVM3-M4 रॉकेट पर अपना तीसरा चंद्र मिशन - चंद्रयान 3 लॉन्च किया।

इसरो के बारे में:

स्थापना: 15 अगस्त 1969
मुख्यालय: बैंगलोर, कर्नाटक, भारत
अध्यक्ष: एस. सोमनाथ

इसरो ने चंद्रमा मिशन चंद्रयान-3 की कक्षा में कमी लाने की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने भारत के तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान-3 को चंद्रमा की कक्षा में स्थापित करने के एक दिन बाद इसे चंद्रमा की कक्षा में कम करने की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक अंजाम दिया।
इसरो ने कहा कि अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक एक योजनाबद्ध कक्षा कटौती प्रक्रिया से गुजरा, जिसने इसे चंद्रमा की सतह के करीब 170 किमी x 4313 किमी की कक्षा में ला दिया, जिसका मतलब है कि अंतरिक्ष यान का चंद्रमा से सबसे दूर बिंदु 4313 किमी है और निकटतम बिंदु केवल 170 किमी है।
अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि वह इस तरह का अगला ऑपरेशन 9 अगस्त को दोपहर 1 से 2 बजे के बीच करेगी।
17 अगस्त तक चंद्रमा पर तीन और युद्धाभ्यास होंगे, जिसके बाद लैंडिंग मॉड्यूल, जिसमें लैंडर और रोवर शामिल होंगे, प्रणोदन मॉड्यूल से अलग हो जाएंगे।
इसके बाद, चंद्रमा पर अंतिम लैंडिंग से पहले लैंडर पर डी-ऑर्बिटिंग युद्धाभ्यास किया जाएगा।
इसरो के मुताबिक, यह 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेगा।

जीसैट-24 का सफल संचालन आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और कदम है: सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा

न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL ने टाटा प्ले के साथ सहयोग किया है और जून 2022 में जीसैट -24 उपग्रह लॉन्च किया है जो सरकार के मेक इन इंडिया विजन के साथ संरेखित है।
टाटा प्ले ने इस उपग्रह का उपयोग शुरू किया, अब अपनी कक्षीय स्थिति में, प्रारंभ हो रहा है।
नई दिल्ली में उद्घाटन समारोह में, सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने खुशी व्यक्त की और कहा, यह आयोजन आत्मानिर्भर भारत और अंतरिक्ष और संचार के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और कदम बढ़ाता है।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष एस.सोमनाथ कहा, DTH सेवाएं प्रदान करने के लिए इसरो द्वारा निर्मित 4-टन श्रेणी का संचार उपग्रह जीसैट-24 कक्षा में विस्तृत परीक्षण के बाद अपनी अधिकतम उपग्रह क्षमता पर पूरी तरह से चालू है।
उन्होंने कहा, यह उपलब्धि अत्याधुनिक स्वदेशी प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित भारत के दूरसंचार क्षेत्र में एक क्रांति का प्रतीक है।
श्री सोमनाथ ने कहा, यह देश की एयरोस्पेस शक्ति को श्रद्धांजलि के रूप में कार्य करता है और मांग प्रेरित मिशन खंड में भारत की सफल प्रविष्टि की शुरुआत करता है।
NSIL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक राधाकृष्णन दुरईराज ने कहा, जीसैट-24 अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों के बाद NSIL द्वारा शुरू किया गया पहला मांग संचालित संचार उपग्रह मिशन है।
टाटा प्ले के MD और CEO हरित नागपाल ने कहा, NSIL के साथ सहयोग अपने DTH ग्राहकों को और भी बेहतर वीडियो और ऑडियो गुणवत्ता और कई अन्य चैनल और सेवाएं प्रदान करेगा।

रूस ने कई देरी के बाद इस सप्ताह एक चंद्र लैंडर लॉन्च करने की योजना की घोषणा की, जिससे 50 से अधिक वर्षों में पहली बार चंद्रमा पर लौटने की उम्मीद है

रूस ने घोषणा की है कि उसने कई देरी के बाद इस सप्ताह एक चंद्र लैंडर लॉन्च करने की योजना बनाई है, जो 50 से अधिक वर्षों में पहली बार चंद्रमा पर लौटने की उम्मीद कर रहा है।
रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोस्मोस ने कहा, लूना-25 लैंडर को तड़के लॉन्च किया जाएगा।

यह प्रक्षेपण मॉस्को के नए चंद्र कार्यक्रम का पहला मिशन है, और यह तब हो रहा है जब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पिछले साल यूक्रेन में मॉस्को के हमले की शुरुआत के बाद पश्चिम के साथ संबंध खराब होने के बाद चीन के साथ अंतरिक्ष सहयोग को बढ़ावा देना चाहते हैं।

भारत ने मानवयुक्त वैज्ञानिक पनडुब्बी MATSYA6000 विकसित किया

भारत ने एक मानवयुक्त वैज्ञानिक पनडुब्बी MATSYA6000 विकसित किया है।
यह गहरे समुद्र में खनन और मानवयुक्त पनडुब्बी के लिए समुद्र में 60,000 मीटर की गहराई तक 12 घंटे की अवधि के लिए तीन मनुष्यों को ले जा सकता है।
केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि समुद्र तल से पॉली-मेटालिक नोड्यूल के खोजपूर्ण खनन के लिए एक एकीकृत खनन मशीन विकसित की गई है और मध्य भारत महासागर में लोकोमोशन परीक्षण का प्रदर्शन किया गया था।
उन्होंने आगे कहा कि डीप ओशन मिशन के तहत गहरे समुद्र में खनन के लिए प्रौद्योगिकी के विकास में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।

सरकार ने इसरो द्वारा विकसित लघु उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों (SSLV) के प्रक्षेपण को पूरा करने के लिए तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम में एक नए स्पेसपोर्ट की स्थापना को मंजूरी दे दी है

केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी; पीएमओ, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज कहा, भारतीय अंतरिक्ष नीति - 20 23 को मंजूरी दे दी गई है और सार्वजनिक डोमेन में जारी कर दिया गया है।
यह नीति अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में गैर-सरकारी संस्थाओं (NGE) की भागीदारी बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र को खोलती है, जबकि विभिन्न हितधारकों अर्थात इन-स्पेस, इसरो, NSIL और DOS की भूमिकाओं को रेखांकित करती है।
सरकार ने अंतरिक्ष गतिविधियों के प्रचार और प्राधिकरण के लिए एकल-खिड़की एजेंसी के रूप में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) की स्थापना की है। IN-SPACe के लिए बजट आवंटन:
2021-22 रु. 10 करोड़
2022-23 रु. 33 करोड़
2023-24 रु. 95 करोड़
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने यह भी बताया कि लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल-वेव ऑब्जर्वेटरी-इंडिया (LIGO-इंडिया) परियोजना को भारत सरकार द्वारा 2600 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से मंजूरी दी गई है, जिसमें परमाणु ऊर्जा विभाग प्रमुख एजेंसी है।
चंद्रयान-3 के मुद्दे पर डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया

इसरो का चंद्रयान 3 मिशन निकट-गोलाकार कक्षा में है

इसरो के चंद्रयान 3 मिशन ने एक निकट-गोलाकार कक्षा ग्रहण कर ली है।
अंतरिक्ष यान जो चंद्रमा के चारों ओर 174 किमी गुणा 1437 किमी की अण्डाकार कक्षा में घूम रहा था, कल रात 151 किमी गुणा 179 किमी की लगभग गोलाकार कक्षा लेने के लिए जहाज पर इंजनों को रेट्रोफिट करके एम चंद्रमा के करीब ले जाया गया।

बेंगलुरु में इसरो टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क 16 अगस्त 2023 को लगभग 08:30 बजे अगली कक्षा कटौती प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
इसके बाद, अंतरिक्ष यान 100 किमी से 100 किमी की चंद्र गोलाकार कक्षा में प्रवेश करेगा।
इसरो का लक्ष्य चंद्रयान 3 को 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर दक्षिणी ध्रुव पर धीरे से उतारना है।
भारत चंद्रमा पर अपना पेलोड उतारने वाला चौथा देश बन जाएगा
11 अगस्त को लॉन्च किया गया रूस का लूना 25 अंतरिक्ष यान भी चंद्रमा की ओर बढ़ रहा है और 21 अगस्त को चंद्र दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की उम्मीद है।
जिस देश का अंतरिक्ष यान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले उतरेगा वह यह उपलब्धि हासिल करने वाला पहला देश बन जाएगा।

चंद्रयान-3 के लिए पांचवां और अंतिम चंद्र बाउंड ऑर्बिट पैंतरेबाज़ी सफलतापूर्वक संपन्न हुई

चंद्रयान-3 अंतरिक्ष यान के लिए चंद्रमा की कक्षा में अंतिम और पांचवीं प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न की गई।
जैसा कि इरादा था, अंतरिक्ष यान अब 153 किमी x 163 किमी की कक्षा में घूम रहा है।
इसरो के ट्वीट में कहा गया है कि लैंडर मॉड्यूल को प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग करने की योजना 17 अगस्त 2023 को बनाई गई है।
प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद, रोवर ले जाने वाला लैंडर 23 अगस्त को शाम 5.47 बजे धीरे-धीरे चंद्रमा की सतह पर उसके दक्षिणी ध्रुव के पास उतरेगा।
चंद्रयान 3 का मिशन उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन करना और रोवर को सतह पर ले जाना और यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोग करना है।

नासा का अंतरिक्ष यान 17 साल की यात्रा के बाद पृथ्वी से पहली बार गुजरा

नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA) के सोलर टेरेस्ट्रियल रिलेशंस ऑब्जर्वेटरी (STEREO-A) अंतरिक्ष यान ने लॉन्च के लगभग 17 साल बाद पृथ्वी पर अपनी पहली उड़ान भरी।

स्टीरियो अंतरिक्ष यान के बारे में:

स्टीरियो अंतरिक्ष यान की जोड़ी को 25 अक्टूबर 2006 को फ्लोरिडा के केप कैनावेरल वायु सेना स्टेशन से लॉन्च किया गया था।
दो अंतरिक्ष यान सूर्य की कक्षा में स्थित थे, स्टीरियो-ए ("आगे") और स्टीरियो-बी ("पीछे")।
दोहरे अंतरिक्ष यान मिशन ने हमारे तारे का पहला त्रिविम दृश्य प्रदान करके अपना प्रमुख लक्ष्य पूरा किया।
6 फरवरी, 2011 को, एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया गया जब स्टीरियो-ए और -बी दोनों अपनी कक्षाओं में उल्लेखनीय 180-डिग्री अलगाव पर पहुंच गए, जिससे हमें सूर्य की पूर्ण गोलाकार छवि मिली।

स्टीरियो-ए का महत्व:

स्टीरियो-ए नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के सौर और हेलिओस्फेरिक वेधशाला (SOHO) और नासा के सौर डायनेमिक्स वेधशाला (SDO) के विचारों के साथ अपने विचारों को संश्लेषित करेगा।
आगामी फ्लाईबाई 2006 में सौर न्यूनतम के दौरान स्टीरियो-ए के शुरुआती दिनों के बिल्कुल विपरीत है, जब सूर्य अपेक्षाकृत शांत था।

अब, जैसे-जैसे सूर्य 2025 के लिए अनुमानित सौर अधिकतम के करीब पहुंचता है, यह कहीं अधिक सक्रिय होता है, जो स्टीरियो-ए के अवलोकनों के लिए एक मौलिक रूप से अलग परिप्रेक्ष्य पेश करता है।

नासा के बारे में:

स्थापना: 29 जुलाई, 1958
मुख्यालय: वाशिंगटन, डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका
प्रशासक: बिल नेल्सन

TDB-DST ने इनोवेटिव बायो-ट्रेस मिनरल्स प्रोजेक्ट के लिए केमलाइफ इनोवेशन के साथ साझेदारी की है

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के तहत काम करने वाला प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (TDB) कर्नाटक के बेंगलुरु में मुख्यालय वाली मैसर्स केमलाइफ इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी की घोषणा करने के लिए रोमांचित है।

यह सहयोग "जानवरों के लिए फ़ीड में प्रयुक्त बायो-ट्रेस खनिजों का व्यावसायीकरण और विनिर्माण" नामक परियोजना को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है, एक दूरदर्शी प्रयास जो प्रभावशाली वैज्ञानिक नवाचार को बढ़ावा देने के लिए TDB की प्रतिबद्धता के साथ सहजता से मेल खाता है।

सतत प्रगति को बढ़ावा देने वाले नवीन समाधानों की वर्तमान तात्कालिकता के बीच, इस सहयोग का एक महत्वपूर्ण आयाम राष्ट्रीय पशुधन मिशन के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से संरेखित होता है - जो भारत के रणनीतिक ढांचे की आधारशिला है। प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण से प्रेरित, मिशन का उद्देश्य पशुधन उत्पादकता को बढ़ाना, चारा और चारा संसाधनों का अनुकूलन करना और पशुधन प्रबंधन में प्रौद्योगिकी को शामिल करना है।

इस राष्ट्रीय रोडमैप के साथ जुड़कर, TDB और मेसर्स केमलाइफ इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड ने एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू की है, जो "जानवरों के लिए फ़ीड में उपयोग किए जाने वाले बायो-ट्रेस खनिजों के व्यावसायीकरण और निर्माण" परियोजना में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

टीडीबी का अटूट समर्थन ₹84 की प्रतिबद्धता से स्पष्ट है, जो ₹142.60 लाख की कुल परियोजना लागत में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

लूना-25 के चंद्रमा से टकराने के बाद रूस का चंद्रमा मिशन विफल हो गया

रूस का चंद्रमा मिशन विफल हो गया क्योंकि उसका अंतरिक्ष यान, लूना -25 नियंत्रण से बाहर हो गया और चंद्रमा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोस्मोस ने कहा कि लूना 25 मिशन के प्रारंभिक विश्लेषण से पता चलता है कि प्रणोदन प्रक्रिया के वास्तविक और गणना किए गए मापदंडों के बीच विचलन के कारण अंतरिक्ष यान एक अनपेक्षित कक्षा में चला गया, जिसके परिणामस्वरूप यह चंद्रमा की सतह से टकरा गया और बाद में नुकसान हुआ।

रोस्कोस्मोस ने कहा, लूना-25 उड़ान कार्यक्रम के अनुसार, इसकी पूर्व-लैंडिंग अण्डाकार कक्षा बनाने के लिए एक आवेग प्रदान किया गया था।

लगभग 14:57 मास्को समय पर, लूना-25 तंत्र के साथ संचार बाधित हो गया।

डिवाइस की खोज करने और उससे संपर्क करने के लिए कल और आज उठाए गए कदमों का कोई नतीजा नहीं निकला।

एक विशेष रूप से गठित अंतरविभागीय आयोग चंद्रमा के नुकसान के कारणों को स्पष्ट करने के मुद्दों से निपटेगा।

भारतीय नौसेना की पनडुब्बी, INS वागिर ऑस्ट्रेलिया के फ्रेमेंटल पहुंचेगी

भारतीय नौसेना की पनडुब्बी, INS वागिर, एक कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी, ने जून 2023 में शुरू होने वाली विस्तारित दूरी की तैनाती शुरू कर दी है।

इसका ऑस्ट्रेलिया के फ्रेमेंटल पहुंचने का कार्यक्रम है।

यह तैनाती न केवल भारतीय नौसेना की नौसैनिक शक्ति और परिचालन दक्षता को उजागर करती है बल्कि समुद्री क्षेत्र में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सहयोग और साझेदारी को भी मजबूत करती है।

कमीशनिंग और आधार: कलवरी क्लास की पांचवीं पनडुब्बी आईएनएस वागिर को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। इसका घरेलू आधार मुंबई है।

ऑस्ट्रेलिया सगाई: ऑस्ट्रेलिया में अपने प्रवास के दौरान, INS वागिर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना (RAN) की इकाइयों के साथ विभिन्न अभ्यासों में शामिल होगा।

चल रहे अभ्यास: वर्तमान में, भारतीय नौसेना के जहाज और विमान ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर मालाबार 23 (11-21 अगस्त) और AUSINDEX 23 (22-24 अगस्त) अभ्यास में भाग ले रहे हैं।

पनडुब्बी रोधी अभ्यास: तैनाती में बुनियादी, मध्यवर्ती और उन्नत स्तर के पनडुब्बी रोधी अभ्यास शामिल हैं। ये अभ्यास पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं और समन्वय को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

सहयोगात्मक अभ्यास: INS वागिर अपनी तैनाती के दौरान एक RAN पनडुब्बी और भारतीय नौसेना P8i विमान के साथ अभ्यास करने के लिए तैयार है। ये संयुक्त अभ्यास भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के बीच सहयोग को और मजबूत करते हैं।

क्षमता का प्रदर्शन: यह विस्तारित-रेंज तैनाती ऑस्ट्रेलिया में भारतीय नौसेना पनडुब्बी की 67वीं पहली तैनाती है। यह विस्तारित अवधि के लिए अपने बेस पोर्ट से महत्वपूर्ण दूरी पर निरंतर संचालन करने की भारतीय नौसेना की क्षमता और पेशेवर विशेषज्ञता को रेखांकित करता है।

इसरो ने चंद्रयान-3 अंतरिक्ष यान की नई कक्षा कटौती प्रक्रिया का सफलतापूर्वक संचालन किया

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन - इसरो ने चंद्रयान -3 अंतरिक्ष यान की एक ताज़ा कक्षा कटौती प्रक्रिया का सफलतापूर्वक संचालन किया, इसे चंद्रमा की सतह के करीब ला रहा है।

चंद्रयान-3 को पिछले महीने की 14 तारीख को लॉन्च किया गया था और यह 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया था

चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने के बाद से, चंद्रयान -3 अंतरिक्ष यान कक्षा युद्धाभ्यास की एक श्रृंखला में लगा हुआ है।

17 अगस्त तक चंद्रमा पर अधिक गतिविधियों के बाद, लैंडिंग मॉड्यूल, जिसमें लैंडर और रोवर शामिल हैं, प्रणोदन मॉड्यूल से अलग हो जाएगा।

इसके बाद, चंद्रमा पर अंतिम लैंडिंग से पहले लैंडर पर डी-ऑर्बिटिंग युद्धाभ्यास किया जाएगा।

इसरो ने 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करने की योजना बनाई है।

चंद्रमा की सतह पर इस सहज लैंडिंग के साथ, अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा।

सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली अंतरिक्ष-आधारित भारतीय वेधशाला - आदित्य-एल1, सितंबर 2023 में लॉन्च के लिए तैयार है

सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली अंतरिक्ष-आधारित भारतीय वेधशाला - आदित्य-एल1, अगले महीने इसके लॉन्च की तैयारी हो रही है।
इसरो ने कहा कि यूआर राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु में विकसित उपग्रह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में अपने स्पेसपोर्ट पर पहुंच गया है।
अंतरिक्ष यान को सूर्य-पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु - L1 के आसपास एक प्रभामंडल कक्षा में रखे जाने की उम्मीद है, जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है।
L1 बिंदु के चारों ओर प्रभामंडल कक्षा में रखे गए उपग्रह को सूर्य को बिना किसी ग्रहण के लगातार देखने का प्रमुख लाभ होता है।
इससे वास्तविक समय में सौर गतिविधियों और अंतरिक्ष मौसम पर उनके प्रभाव को देखने में अधिक लाभ मिलेगा।
अंतरिक्ष यान विद्युत चुम्बकीय और कण क्षेत्र डिटेक्टरों का उपयोग करके प्रकाशमंडल, क्रोमोस्फीयर और सूर्य के कोरोना की सबसे बाहरी परतों का निरीक्षण करने के लिए सात पेलोड ले जाएगा।
अपने विशेष सुविधाजनक बिंदु का उपयोग करते हुए, चार पेलोड सीधे सूर्य को देखेंगे और अन्य तीन पेलोड इसके चारों ओर कणों और क्षेत्रों का इन-सीटू अध्ययन करेंगे, इस प्रकार अंतरग्रहीय माध्यम में सौर गतिशीलता के प्रसारक प्रभाव का महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अध्ययन प्रदान करेंगे।

चंद्रयान-3: भारत का चंद्र रोवर प्रज्ञान चंद्रमा पर सैर कर रहा है

भारत ने इतिहास रच दिया है क्योंकि वह चंद्रमा की सतह के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया है।
विक्रम लैंडर 23 अगस्त 2023 को शाम 6.04 बजे योजना के अनुसार सफलतापूर्वक नीचे उतर गया।
अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ और चीन के बाद भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने वाले देशों के विशिष्ट क्लब में शामिल हो गया है।
अब तक, विक्रम लैंडर सुरक्षित रूप से चंद्रमा की सतह पर उतर आया है, इसके साथ ही प्रज्ञान रोवर भी लैंडर के रैंप पर तैनात हो गया है। मिशन के अगले चरणों में, रोवर चंद्रमा की सतह पर उसके वातावरण के बारे में प्रासंगिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए अपनी यात्रा शुरू करेगा।
विक्रम लैंडर के पेट में 26 किलोग्राम का रोवर जिसे प्रज्ञान (ज्ञान के लिए संस्कृत शब्द) कहा जाता है, चंद्रमा पर ले जाया गया था।
लैंडिंग चंद्र दिवस की शुरुआत के साथ मेल खाती है - चंद्रमा पर एक दिन पृथ्वी पर चार सप्ताह से थोड़ा अधिक के बराबर होता है और इसका मतलब यह होगा कि लैंडर और रोवर के पास अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए 14 दिनों की धूप होगी।
यह लैंडिंग रूस के लूना-25 अंतरिक्ष यान के नियंत्रण से बाहर हो जाने और चंद्रमा पर दुर्घटनाग्रस्त होने के कुछ ही दिनों बाद हुई।
भारत का दूसरा चंद्र मिशन, जिसने 2019 में वहां सॉफ्ट-लैंडिंग का प्रयास भी किया था, असफल रहा - इसके लैंडर और रोवर नष्ट हो गए, हालांकि इसका ऑर्बिटर बच गया।
चंद्रयान का पहला मिशन 2008 में था।
चंद्रयान 3 के परियोजना निदेशक: पी वीरमुथुवेल.
परियोजना की लागत: रु. 615 करोड़

विक्रम लैंडर के बारे में:

अंतरिक्ष यान का 'विक्रम' लैंडर मॉड्यूल 17 अगस्त को प्रोपल्शन मॉड्यूल से सफलतापूर्वक अलग हो गया। विक्रम लैंडर लगभग 2 मीटर लंबा है और इसका द्रव्यमान 1,700 किलोग्राम से अधिक है। इसका नाम विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है - जिन्हें व्यापक रूप से भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है।

प्रज्ञान रोवर के बारे में:

छह पहियों वाला रोबोटिक वाहन संस्कृत में 'प्रज्ञान' का अनुवाद 'बुद्धि' होता है। 26 किलोग्राम वजनी, रोवर में चंद्रमा की सतह से संबंधित डेटा प्रदान करने के लिए पेलोड के साथ कॉन्फ़िगर किए गए उपकरण हैं और यह वायुमंडल की मौलिक संरचना का अध्ययन करेगा।

संयुक्त राज्य अमेरिका के खाद्य और औषधि प्रशासन ने शिशुओं में आरएसवी को रोकने के लिए गर्भवती व्यक्तियों के लिए पहली फाइजर की मातृ वैक्सीन को मंजूरी दी

संयुक्त राज्य अमेरिका (US) फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने एब्रीस्वो (रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस वैक्सीन) को मंजूरी दे दी है, जो गर्भवती व्यक्तियों में कम श्वसन पथ की बीमारी (LRTD) और जन्म से 6 महीने की उम्र तक शिशुओं में श्वसन सिंसाइटियल वायरस (RSV) के कारण होने वाले गंभीर एलआरटीडी को रोकने के लिए गर्भवती व्यक्तियों में उपयोग के लिए अनुमोदित पहला टीका है।

फाइजर ने यह रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस वैक्सीन विकसित की है।

इसके साथ, संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) गर्भवती महिलाओं के लिए एक टीके को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया जो उनके शिशुओं में आरएसवी के कारण होने वाली गंभीर बीमारी को रोकता है।

मुख्य विचार:

फाइजर शॉट, जिसे पहले से ही वृद्ध वयस्कों में उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया था, अब शिशुओं को जन्म से 6 महीने तक बचाने के लिए गर्भावस्था के 32 से 36 सप्ताह तक एकल इंजेक्शन के रूप में उपयोग के लिए हरी झंडी दे दी गई है।

यह अनुमोदन स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और गर्भवती व्यक्तियों को शिशुओं को इस संभावित जीवन-घातक बीमारी से बचाने के लिए एक विकल्प प्रदान करता है।

क्लिनिकल परीक्षण परिणाम:

FDA की मंजूरी लगभग 7,000 गर्भवती महिलाओं के नैदानिक परीक्षण के बाद दी गई।

क्लिनिकल परीक्षण से पता चला कि फाइजर के एब्रिस्वो वैक्सीन ने 0-3 महीने के शिशुओं में आरएसवी से संबंधित गंभीर बीमारी को 82% और 0-6 महीने के शिशुओं में 69% तक कम कर दिया।

सावधानियां एवं दुष्प्रभाव:

एक उल्लेखनीय विचार प्री-एक्लेमप्सिया की घटना है, जो एक खतरनाक रक्तचाप विकार है।

एब्रिस्वो प्राप्त करने वाले गर्भवती व्यक्तियों में, प्री-एक्लेमप्सिया की घटना 1.8% थी, जो प्लेसबो पर 1.4% से थोड़ी अधिक थी।

RSV क्या है?

RSV एक अत्यधिक संक्रामक वायरस है जो सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों में श्वसन संक्रमण का कारण बनता है।

यह दुनिया भर में शिशुओं में निचले श्वसन पथ की बीमारी का सबसे आम कारण है

नवीनतम समाचार:

जुलाई 2023 में, FDA ने एक निवारक उपचार के रूप में सनोफी और एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित बेफोर्टस नामक एक एंटीबॉडी उपचार को मंजूरी दी, जो शिशुओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए एक टीके की तरह काम करता है।

FDA के बारे में:

स्थापना: 30 जून, 1906

मुख्यालय: संयुक्त राज्य अमेरिका

संयुक्त राज्य खाद्य और औषधि प्रशासन (FDA या US FDA) स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग की एक संघीय एजेंसी है।

चीन ने पृथ्वी अवलोकन के लिए नया उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया

चीन उत्तर पश्चिमी चीन में जिउक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गाओफेन-12 04 सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है।

उपग्रह को लॉन्ग मार्च-4सी वाहक रॉकेट का उपयोग करके अंतरिक्ष में ले जाया गया और उसने अपनी नियोजित कक्षा हासिल की।

यह प्रक्षेपण लॉन्ग मार्च श्रृंखला वाहक रॉकेट के 484वें उड़ान मिशन का प्रतीक है।

गाओफेन-12 04 उपग्रह के बारे में:

अनुप्रयोग:

गाओफेन-12 04 उपग्रह को विविध अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो मुख्य रूप से भूमि सर्वेक्षण, शहरी नियोजन, सड़क नेटवर्क डिजाइन, फसल उपज अनुमान, साथ ही आपदा रोकथाम और कटौती जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है।

2022 में चीन की अंतरिक्ष उपलब्धियाँ:

वर्ष 2022 में, चीन ने वैश्विक अंतरिक्ष क्षेत्र में अपनी प्रमुखता की पुष्टि करते हुए, कुल 64 अंतरिक्ष प्रक्षेपण सफलतापूर्वक करके एक उल्लेखनीय रिकॉर्ड बनाया।

इस उपलब्धि ने चीन को अंतरिक्ष प्रक्षेपण में केवल संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दूसरे सबसे सक्रिय देश के रूप में स्थान दिया।

लॉन्ग मार्च-4सी रॉकेट के बारे में:

लॉन्ग मार्च-4सी रॉकेट एक तरल-प्रणोदक प्रक्षेपण यान है जिसमें तीन चरण होते हैं।

विशेष रूप से, इसमें विभिन्न कक्षीय आवश्यकताओं वाले विभिन्न प्रकार के उपग्रहों को समायोजित करने की क्षमता है लॉन्ग मार्च-4सी 3 टन तक वजन वाले पेलोड को 700 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित सूर्य-तुल्यकालिक कक्षा में ले जा सकता है।

चीन के बारे में:

पूंजी: बीजिंग

मुद्रा: रॅन्मिन्बी

IIT मद्रास ने ऑप्टिकल तरीकों के माध्यम से रेडियो फ्रीक्वेंसी के परिवहन के लिए अगली पीढ़ी के फोटोनिक एनालॉग-टू-डिजिटल कन्वर्टर्स विकसित किए हैं

अगली पीढ़ी के फोटोनिक एनालॉग-टू-डिजिटल कन्वर्टर्स (NG-PADC) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) मद्रास द्वारा IMPRINT कार्यक्रम के समर्थन से विकसित किया गया था, जो टाइम-स्ट्रेच्ड फोटोनिक ADC से सुसज्जित है।

ADC क्या हैं?

अगली पीढ़ी के उन्नत डिजिटल रिसीवर विकसित करने के लिए एनालॉग-टू-डिजिटल कन्वर्टर्स (ADC) महत्वपूर्ण घटक हैं। इलेक्ट्रॉनिक एडीसी (EADC) की सीमा यह है कि उच्च बैंडविड्थ पर उनके ऊर्ध्वाधर रिज़ॉल्यूशन से समझौता किया जाता है। फोटोनिक्स के माध्यम से इस समस्या को हल करने के 2 संभावित दृष्टिकोण हैं।

स्ट्रेचिंग आरएफ सिग्नल: आरएफ, जब एक वर्णक्रमीय रूप से समृद्ध ऑप्टिकल स्पंदित स्रोत पर मॉड्यूलेट किया जाता है, तो इसे एक फैलाने वाले माध्यम के माध्यम से ऑप्टिकल डोमेन में बढ़ाया जा सकता है, इस प्रकार उच्च आवृत्ति आरएफ संकेतों को प्रभावी ढंग से कम आवृत्ति संकेतों में परिवर्तित किया जा सकता है।
यह बैक-एंड एडीसी की इनपुट बैंडविड्थ आवश्यकताओं को ऑप्टिकल पल्स के खिंचाव कारक के बराबर कम कर देता है।
स्थिर ऑप्टिकल घड़ियाँ: फोटोनिक्स लघु-स्पंदित लेजर द्वारा उत्पन्न ऑप्टिकल घड़ियों का उपयोग कर सकता है।
इन ऑप्टिकल घड़ियों में इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों की तुलना में समय में उतार-चढ़ाव (टाइमिंग जिटर) बहुत कम होता है।
उच्च बैंडविड्थ आरएफ सिग्नल, जब स्थिर ऑप्टिकल घड़ियों के साथ नमूना किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों की तुलना में बिट्स (ENOB) की बहुत अधिक प्रभावी संख्या प्रदान कर सकता है।
इसमें EADC की तुलना में 12 गुना अधिक प्रभावी बैंडविड्थ के साथ समय-विस्तारित फोटोनिक एडीसी है, जो बहुत अधिक सटीकता के साथ संकेतों के डिजिटलीकरण को सक्षम बनाता है।

NG-PADC के बारे में:

अगली पीढ़ी के फोटोनिक एनालॉग-टू-डिजिटल कन्वर्टर्स (NG-PADC) प्रोजेक्ट में एक नया डिजाइन किया गया प्रोटोटाइप ऑप्टिकल तरीकों के माध्यम से रेडियो फ्रीक्वेंसी (RF) की तात्कालिक आवृत्ति माप, उत्पादन और परिवहन कर सकता है।
यह विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति ला सकता है, जिससे तेज़ डिजिटल संचार, बेहतर उपग्रह संचार, बेहतर चिकित्सा इमेजिंग और फोटोनिक रडार सक्षम हो सकते हैं।

अधिग्रहण और विलय

फ्यूचर जेनराली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस ने व्यापक बीमा पहुंच के लिए जेएम फाइनेंशियल के साथ साझेदारी की

फ्यूचर जेनराली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (FGILI) ने अपने बीमा उत्पाद की पेशकश को बढ़ाने और देश भर में बाजार में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के उद्देश्य से एक प्रमुख वित्तीय सेवा समूह जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ समझौता किया है।
यह सहयोग बीमाकर्ता को अपने उत्पाद पोर्टफोलियो में विविधता लाने और नवीन उत्पादों की पेशकश करने के लिए जेएम फाइनेंशियल की वितरण और वित्तीय सलाहकार क्षमताओं का लाभ उठाने में मदद करेगा।
जेएम फाइनेंशियल के वितरण नेटवर्क में 54 शाखाएं, 725 व्यावसायिक सहयोगी, 9,000 से अधिक सक्रिय वित्तीय वितरक और 2.2 लाख ग्राहकों का आधार शामिल है जिसमें व्यक्ति, निगम और वित्तीय संस्थान शामिल हैं।

फ्यूचर जेनराली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बारे में:

स्थापित: 2006
मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र, भारत
MD और CEO: ब्रूस डी ब्रोइज़
केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति से पहले, न्यायमूर्ति देसाई गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे।

मारुति सुजुकी जापानी मूल कंपनी सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन से सुजुकी मोटर गुजरात का अधिग्रहण करेगी

देश की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने अपनी जापानी मूल कंपनी सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन (SMC) से सुजुकी मोटर गुजरात (SMG) का अधिग्रहण करने के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम की घोषणा की है।

मारुति सुजुकी के बोर्ड ने 31 जुलाई, 2023 को इस अधिग्रहण को मंजूरी दे दी और इसे 31 मार्च, 2024 से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा।
वर्तमान में, सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन (SMC) के पास सुजुकी मोटर गुजरात (SMG) में 100% हिस्सेदारी है जो मारुति सुजुकी को अपना पूरा उत्पादन आपूर्ति करती है।
इस संपूर्ण हिस्सेदारी का मारुति सुजुकी इंडिया को हस्तांतरण एक संबंधित पक्ष लेनदेन माना जाता है और इसे प्रचलित कानूनों और विनियमों के अनुसार किया जाएगा।
सुजुकी मोटर ने 2014 में अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में गुजरात में एक अलग विनिर्माण सुविधा स्थापित करने का निर्णय लिया और सालाना 750,000 इकाइयों का उत्पादन किया।
मारुति सुजुकी की 2030 तक स्थानीय बाजार में 6 ईवी चलाने की योजना है।
अलग से, बोर्ड ने निदेशक के रूप में युकिहिरो यामाशिता की नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी और 1 अगस्त से तीन साल के लिए संयुक्त प्रबंध निदेशक के रूप में नामित किया गया।

मारुति सुजुकी के बारे में:

स्थापना: 24 फरवरी 1981
मुख्यालय: नई दिल्ली, दिल्ली, भारत
अध्यक्ष: आर.सी.भार्गव
MD और CEO: हिसाशी टेकुची

CCI ने कोपवूर्न बीवी, मॉस इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, इन्फिनिटी पार्टनर्स और डेफैटी इन्वेस्टमेंट्स होल्डिंग बीवी द्वारा HDFC क्रेडिला फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की 90% शेयरधारिता और वोटिंग अधिकारों के अधिग्रहण से जुड़े प्रस्तावित संयोजन को मंजूरी दे दी है

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने कोपवूर्न बीवी, मॉस इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, इन्फिनिटी पार्टनर्स और डेफैटी इन्वेस्टमेंट्स होल्डिंग बीवी द्वारा HDFC क्रेडिला फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की 90% शेयरधारिता और वोटिंग अधिकारों के अधिग्रहण से जुड़े प्रस्तावित संयोजन को मंजूरी दे दी है।
प्रस्तावित संयोजन अधिग्रहणकर्ताओं द्वारा सामूहिक रूप से इक्विटी शेयरों के अधिग्रहण से संबंधित है, जिसमें HDFC क्रेडिला की शेयरधारिता और मतदान अधिकारों का लगभग 90% शामिल है, जो HDFC लिमिटेड से इक्विटी शेयरों के प्रत्येक अधिग्रहणकर्ता द्वारा खरीद के साथ-साथ प्रत्येक अधिग्रहणकर्ता द्वारा HDFC क्रेडिला (प्रस्तावित संयोजन) के इक्विटी शेयरों की सदस्यता के माध्यम से शामिल है।

कोपवूर्न बी.वी. के बारे में

कोपवूर्न बीवी (बीपीईए ईक्यूटी एक्वायरर) नीदरलैंड के कानूनों के तहत निगमित एक निजी सीमित देयता कंपनी है।
यह अंततः निवेश फंड BPEA प्राइवेट इक्विटी फंड VIII (BPEA फंड VIII) बनाने वाली संस्थाओं के स्वामित्व में है, जो एक EQT निवेश फंड है और इसे EQT AB से संबद्ध संस्थाओं द्वारा नियंत्रित, प्रबंधित और सलाह दी जाती है। तदनुसार, बीपीईए ईक्यूटी एक्वायरर निवेश फंडों के ईक्यूटी समूह का हिस्सा है, जो अपनी सहायक कंपनियों और फंडों के साथ मिलकर एक वैश्विक निवेश संगठन है।

मॉस इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, इन्फिनिटी पार्टनर्स और डेफैटी इन्वेस्टमेंट्स होल्डिंग बी.वी. के बारे में

मॉस इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड (मॉस), इन्फिनिटी पार्टनर्स (इन्फिनिटी) और डेफैटी इन्वेस्टमेंट्स होल्डिंग बीवी (डिफैटी) (मॉस, इन्फिनिटी और डेफैटी सामूहिक रूप से क्रिसकैपिटल एक्वायरर्स हैं) में से प्रत्येक निजी इक्विटी निवेशक हैं जो सामान्य पाठ्यक्रम में निवेश करते हैं।

BPEA EQT एक्वायरर और क्रिसकैपिटल एक्वायरर्स को व्यक्तिगत रूप से एक्वायरर और सामूहिक रूप से एक्वायरर के रूप में जाना जाता है।

HDFC क्रेडिला फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बारे में

HDFC क्रेडिला फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (HDFC क्रेडिला) 1956 के कंपनी अधिनियम के तहत निगमित एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है।

HDFC क्रेडिला भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत एक व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है।

यह मुख्य रूप से उन भारतीयों को खुदरा शिक्षा ऋण प्रदान करने के व्यवसाय में लगा हुआ है जो भारत और विदेशों दोनों में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं।

CCI ने टाटा क्लीनटेक कैपिटल लिमिटेड (TCCL) और टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (TCFSL) के टाटा कैपिटल लिमिटेड (TCL) में विलय को मंजूरी दे दी

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने टाटा क्लीनटेक कैपिटल लिमिटेड (TCCL) और टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (TCFSL) के टाटा कैपिटल लिमिटेड (TCL) में विलय को मंजूरी दे दी है।

प्रस्तावित संयोजन TCFSL और TCCL का TCL में विलय है।

TCL भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के साथ एक व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा स्वीकार करने वाली कोर निवेश कंपनी (CIC) के रूप में पंजीकृत है और मुख्य रूप से इसकी सहायक कंपनियों में निवेश रखती है, जो ऋण देने और सेवाओं और उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश करने में लगी हुई हैं। वित्तीय सेवा क्षेत्र, जिसमें निजी इक्विटी फंडों को सलाह देना और/या प्रबंधन करना शामिल है, जैसा कि समय-समय पर CIC के लिए RBI द्वारा जारी निर्देशों और दिशानिर्देशों के तहत अनुमति है।

TCFSL के बारे में

TCFSL टीसीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और RBI के साथ प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में पंजीकृत है और मुख्य रूप से वित्तीय सेवा क्षेत्र में उधार सेवाएं देने और सेवाओं और उत्पादों की पेशकश करने में लगी हुई है।

TCL के बारे में

TCCL TCL की सहायक कंपनी है और आरबीआई के साथ प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में पंजीकृत है। TCCL नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, अपशिष्ट प्रबंधन, जल प्रबंधन और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए नकदी प्रवाह-आधारित वित्त और सलाहकार सेवाएं प्रदान करने के व्यवसाय में संलग्न है।

HDFC कैपिटल, अभिनंदन लोढ़ा ग्रुप ने कम वृद्धि परियोजना में 1,500 करोड़ रुपये का निवेश करने के लिए संयुक्त उद्यम पर हस्ताक्षर किया

HDFC कैपिटल एडवाइजर्स और अभिनंदन लोढ़ा का घर (HoABL) ने भारत में प्रमुख संपत्ति बाजारों में प्लॉट किए गए विकास और कम वृद्धि वाली परियोजनाओं सहित भूमि परियोजनाओं को शुरू करने के लिए 1,500 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के साथ एक संयुक्त उद्यम मंच स्थापित करने के लिए एक गठबंधन बनाया है।
HDFC कैपिटल एडवाइजर्स HDFC कैपिटल अफोर्डेबल रियल एस्टेट फंड-3 के माध्यम से इस नए प्लेटफॉर्म में निवेश करेंगे और इस निवेश से 4,500 करोड़ रुपये से अधिक का सकल विकास मूल्य (GDV) प्राप्त होने की उम्मीद है।

HDFC कैपिटल के बारे में:

स्थापित: 2016
मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र
CEO: विपुल रूंगटा

सारस्वत सहकारी बैंक बैंकएश्योरेंस समझौते के तहत LIC उत्पाद बेचेगा

भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) और मुंबई मुख्यालय वाले सारस्वत सहकारी बैंक ने एक साझेदारी में प्रवेश किया है जिसके तहत बैंक बीमा प्रमुख के उत्पाद बेचेगा।
यह साझेदारी बैंकएश्योरेंस चैनल के माध्यम से जीवन बीमा की पहुंच बढ़ाने के प्रयासों का हिस्सा है।
LIC के पास वार्षिकी, यूलिप, टर्म इंश्योरेंस से लेकर बचत योजनाओं तक समाज के सभी वर्गों के लिए बीमा उत्पाद हैं।
इसकी क्लोज एंडेड गारंटीड लाभ योजना धन वृद्धि, 90 दिन से 60 वर्ष की आयु वालों के लिए, 30 सितंबर, 2023 तक उपलब्ध है।

शोक सन्देश

शीर्ष बॉलीवुड कला निर्देशक नितिन देसाई का निधन

प्रसिद्ध बॉलीवुड प्रोडक्शन डिजाइनर और प्रसिद्ध कला निर्देशक नितिन चंद्रकांत देसाई का 58 वर्ष की आयु में निधन हो गया है।

नितिन चंद्रकांत देसाई के बारे में:

देसाई का जन्म 9 अगस्त 1965 को मुलुंड, बॉम्बे, महाराष्ट्र में हुआ था।
उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टेलीविजन फिल्म तमस (1987) में सहायक कला निर्देशक के रूप में की।
उन्हें मराठी और हिंदी फिल्मों, दिल्ली में विश्व सांस्कृतिक महोत्सव 2016 और हम दिल दे चुके सनम (1999), लगान (2001), देवदास (2002), जोधा अकबर (2008) और प्रेम रतन धन पायो (2015) जैसी फिल्मों में उनके काम के लिए जाना जाता था।
अपने 20 साल के करियर के दौरान, उन्होंने आशुतोष गोवारिकर, विधु विनोद चोपड़ा, राजकुमार हिरानी और संजय लीला भंसाली जैसे निर्देशकों के साथ काम किया।
उन्होंने महाराष्ट्र के कर्जत में एक फिल्म और टेलीविजन उत्पादन सुविधा एनडी स्टूडियो की स्थापना की और फिल्म देश देवी (2002) का निर्माण किया।

पुरस्कार एवं सम्मान:

उन्हें 4 बार सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला:

वर्ष	फिल्म
1999	डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर

2000	हम दिल दे चुके सनम
2002	लगान
2003	देवदास

उन्हें 3 बार फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन मिला:

वर्ष	**फिल्म**
1995	1942: ए लव स्टोरी
1997	खामोशी
2003	देवदास

2016 में, उन्हें भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म श्री से सम्मानित किया गया।

प्रसिद्ध मराठी कवि नामदेव धोंडो महानोर का निधन

प्रसिद्ध मराठी कवि और गीतकार नामदेव धोंडो महानोर, जिन्हें ना धो महानोर के नाम से जाना जाता है, का 81 वर्ष की आयु में पुणे, महाराष्ट्र में निधन हो गया।

नामदेव धोंडो महानोर के बारे में:

महानोर का जन्म 1942 में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के पलासखेड़ा में हुआ था।
वह 1978 में महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य भी रहे थे।
उन्होंने कला और कृषि के साथ प्रयोग किये।

उनके उल्लेखनीय कार्य:

उन्होंने कई लोकप्रिय कविताएँ और गीत लिखे, जिनमें "जगला प्रेम अरपावे", "गंगा वाहू दे निर्मल" और "दिवेलागनिची वेल" शामिल हैं, और उन्होंने "एक होता विदुषक", "जैत रे जैत", "सरजा" जैसी मराठी फिल्मों के लिए भी गीत लिखे।

पुरस्कार एवं सम्मान:

1991 में, महानोर को भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म श्री से सम्मानित किया गया था।
वह महाराष्ट्र सरकार के कृषि भूषण पुरस्कार के प्राप्तकर्ता थे।

दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ के पूर्व सचिव सुनील देव का निधन

दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (DDCA) के पूर्व सचिव टी20 विश्व कप 2007 में टीम इंडिया के प्रशासनिक प्रबंधक सुनील देव का 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया

सुनील देव के बारे में:

सुनील देव ने 1969/70 में दिल्ली के लिए एक प्रथम श्रेणी मैच खेला था।
सुनील देव 70 के दशक से लेकर 2015 तक DDCA का पर्याय रहे।
वह दक्षिण अफ्रीका में 2007 का पहला टी20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम के प्रशासनिक प्रबंधक बने।

उन्होंने 1996 में भारत के दक्षिण अफ्रीका दौरे और 2014 के इंग्लैंड दौरे पर प्रशासनिक प्रबंधक के रूप में भी काम किया। खेल प्रशासनिक प्रबंधक के अलावा, वह बीसीसीआई की विभिन्न उप-समितियों का हिस्सा थे।

केरल कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष वक्कोम पुरूषोत्तमन का निधन हो गया

पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता वक्कोम पुरूषोतमन का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया।

वक्कोम पुरूषोत्तमन के बारे में:

पुरुषोत्तम का जन्म 12 अप्रैल 1928 को केरल के तिरुवनंतपुरम के वक्कोम में हुआ था।
वह अट्टिंगल विधानसभा क्षेत्र से 5 बार केरल विधानसभा के लिए चुने गए और तीन बार मंत्री बने।
1971 से 1977 तक, उन्होंने सी अच्युत मेनन की अध्यक्षता वाले मंत्रालय में कृषि और श्रम विभाग संभाला।
1980 से 1981 तक, वह नयनार मंत्रालय में स्वास्थ्य और पर्यटन मंत्री थे।
वह 1982 से 1984 और फिर 2001 से 2004 तक केरल विधानसभा के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे।
वह अलाप्पुझा निर्वाचन क्षेत्र से दो बार लोकसभा के लिए भी चुने गए और 1984 से 1991 तक सेवा की।
उन्होंने 1993 से 1996 तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के छठे उपराज्यपाल, 2011 से 2014 तक मिजोरम के राज्यपाल और 2014 में 2 महीने के लिए त्रिपुरा के राज्यपाल के रूप में कार्य किया।

फिल्म निर्माता सिद्दीकी का कोच्चि में निधन हो गया

प्रमुख फिल्म निर्माता सिद्दीकी कोच्चि के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया।
वह 63 वर्ष के थे

सिद्दीकी के बारे में

मलयालम सिनेमा की दुनिया में सिद्दीकी की यात्रा उनके दोस्त लाल के साथ उनके निर्देशन की पहली फिल्म "रामजी राव स्पीकिंग" से शुरू हुई।
इस जोड़ी ने मलयालम फिल्म उद्योग की कुछ सबसे बड़ी कॉमेडी ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाईं, जिनमें "इन हरिहर नगर," "गॉडफादर," "वियतनाम कॉलोनी," "रामजी राव स्पीकिंग," और "फ्रेंड्स" शामिल हैं। उन्होंने तमिल, तेलुगु और हिंदी में फिल्मों का निर्देशन भी किया।
सिद्दीकी ने अपनी नवीन कहानी कहने और बहुमुखी फिल्म निर्माण शैली से फिल्म प्रेमियों के दिलों में अपने लिए जगह बनाई। उन्होंने हास्य और भावनाओं का कुशलता से मिश्रण करते हुए, संबंधित पात्रों के इर्द-गिर्द जटिल कथाएँ बुनीं।

तेलुगु, संस्कृत विद्वान कांडलाकुंटा अलाहा सिंगाराचार्युलु का निधन

प्रख्यात लेखक, विद्वान और शिक्षाविद् कांडलाकुंटा अलाहा सिंगाराचार्युलु का उम्र संबंधी बीमारियों के कारण हैदराबाद स्थित उनके आवास पर निधन हो गया।
वह 93 वर्ष के थे
अंतिम संस्कार एलबी नगर के पास ऑटोनगर श्मशान घाट पर किया गया।
उनके चार बेटे और दो बेटियों सहित छह बच्चे जीवित हैं।
वरिष्ठ पत्रकार और आंध्र ज्योति के संपादक के श्रीनिवास उनके दूसरे बेटे हैं।

सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक और सामाजिक कार्यकर्ता बिंदेश्वर पाठक का निधन

'सुलभ इंटरनेशनल' के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक का दिल का दौरा पड़ने से दिल्ली के एम्स में निधन हो गया।
वह 80 वर्ष के थे
उन्होंने 1970 में सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस की स्थापना की और मैला ढोने की प्रथा के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाया।
1991 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।

पुरस्कार और वैश्विक मान्यता

बिंदेश्वर पाठक ने 1970 में बिहार से सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गनाइजेशन की स्थापना की।
तब से, पाठक मलिन बस्तियों, ग्रामीण क्षेत्रों और शहरों में लोगों की पुरानी, अस्वच्छ शौचालय की आदतों को देखने के तरीके को बदलने के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने किफायती शौचालय प्रणालियाँ बनाईं जिससे लाखों लोगों का जीवन बेहतर और स्वस्थ हो गया है।
वह भारत में बाल्टी वाले शौचालयों से मानव अपशिष्ट को मैन्युअल रूप से साफ करने की प्रथा को समाप्त करने का भी प्रयास कर रहे थे।
स्वच्छता के प्रति पाठक के अभिनव दृष्टिकोण के कारण 1749 कस्बों में शुष्क शौचालयों को दो गड्ढों वाले फ्लश शौचालयों में परिवर्तित किया गया और 160,835 से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया।
पाठक भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण के प्राप्तकर्ता हैं।
2003 में, उन्हें ग्लोबल 500 रोल ऑफ ऑनर में शामिल किया गया और 2009 में, उन्हें प्रतिष्ठित स्टॉकहोम वॉटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी अन्य प्रशंसाओं में एनर्जी ग्लोब अवार्ड, सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए दुबई इंटरनेशनल अवार्ड और पेरिस में फ्रांसीसी सीनेट से लीजेंड ऑफ प्लैनेट अवार्ड शामिल हैं।
2020 में, एक सामाजिक नवप्रवर्तक के रूप में उनके काम का विवरण देने वाली एक पुस्तक, 'नमस्ते, बिंदेश्वर पाठक!' प्रकाशित किया गया था।
न्यूयॉर्क में उनके नाम पर एक दिन भी मनाया गया। 2016 में, मेयर बिल डी ब्लासियो ने 14 अप्रैल को बिंदेश्वर पाठक दिवस के रूप में घोषित किया।

सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक और सार्वजनिक शौचालय के प्रणेता बिंदेश्वर पाठक का निधन

सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक और सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण में अग्रणी सामाजिक कार्यकर्ता बिंदेश्वर पाठक का 80 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन हो गया।

बिंदेश्वर पाठक के बारे में:

बिंदेश्वर पाठक का जन्म 2 अप्रैल 1943 को बिहार के हाजीपुर में हुआ था।
उन्हें पहली बार 1968 में सफाईकर्मियों की दुर्दशा का एहसास हुआ जब वह बिहार गांधी शताब्दी समारोह समिति के भंगी-मुक्ति (सफाईकर्मियों की मुक्ति) सेल में शामिल हुए।
1970 में, उन्होंने सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की, जो एक गैर-लाभकारी संगठन है, जिसने 17,00 से अधिक शहरों में शुष्क शौचालयों को आधुनिक शौचालयों में बदलने पर व्यापक काम किया है, और 160,835 से अधिक शौचालयों के निर्माण में मदद की है।
वह भारतीय रेलवे के स्वच्छ रेल मिशन के ब्रांड एंबेसडर थे।
2016 में, न्यूयॉर्क शहर ने "सबसे अमानवीय स्थिति" में लगे लोगों के जीवन में सुधार के लिए उनके और उनके संगठन द्वारा किए गए योगदान की मान्यता में 14 अप्रैल को 'बिंदेश्वर पाठक दिवस' के रूप में घोषित किया।

प्रसिद्ध पुस्तकें:

उन्होंने कई किताबें लिखीं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध है द रोड टू फ्रीडम, और दुनिया भर में स्वच्छता, स्वास्थ्य और सामाजिक प्रगति पर सम्मेलनों में लगातार भाग लेते थे।

पुरस्कार एवं सम्मान:

1991 में, पाठक को मैला ढोने वालों की मुक्ति और पुनर्वास के लिए उनके काम के लिए और साथ ही पोर-फ्लश टॉयलेट तकनीक प्रदान करके पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।

2009 में उन्हें स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार मिला।

उन्हें वर्ष 2017 के लिए लोक प्रशासन, शैक्षणिक और प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया।

जून 2018 में उन्हें टोक्यो, जापान में निक्केई इंक द्वारा संस्कृति और समुदाय के लिए निक्केई एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

सुलभ इंटरनेशनल के बारे में:

सुलभ इंटरनेशनल एक भारत स्थित सामाजिक सेवा संगठन है जो शिक्षा के माध्यम से मानव अधिकारों, पर्यावरण स्वच्छता, ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोतों, अपशिष्ट प्रबंधन और सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए काम करता है।

जून 1996 में इस्तांबुल, तुर्की में आयोजित हैबिटैट-II सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र मानव बस्तियों के केंद्र ने सुलभ की स्वच्छता प्रणाली को वैश्विक "शहरी सर्वोत्तम अभ्यास" के रूप में प्रशंसा की है।

संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद ने सुलभ को उसके काम की मान्यता में विशेष सलाहकार का दर्जा दिया।

प्रसिद्ध परमाणु भौतिक विज्ञानी और पद्म श्री और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित विकास सिन्हा का निधन हो गया

प्रसिद्ध परमाणु भौतिक विज्ञानी विकास सिन्हा का 78 वर्ष की आयु में कोलकाता में निधन हो गया।

बिकास सिन्हा के बारे में:

बिकाश सिन्हा का जन्म 16 जून 1945 को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के कांडी में हुआ था।

वह साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स एंड वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर के पूर्व निदेशक थे।

सिन्हा ने परमाणु भौतिकी, उच्च ऊर्जा भौतिकी, क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा और प्रारंभिक ब्रह्मांड विज्ञान में विशेषज्ञता हासिल की।

पहली बार उन्होंने जिनेवा में यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन के प्रयोगों में भाग लेने के लिए भारतीय दल का नेतृत्व किया।

पुरस्कार एवं सम्मान:

सिन्हा 1994 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन के एसएन बोस जन्म शताब्दी पुरस्कार के प्राप्तकर्ता थे।

उन्हें नवंबर 2005 में अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट फाउंडेशन, जर्मनी द्वारा हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया था।

उन्हें 2002 में भौतिकी में उत्कृष्टता के लिए आरडी बिड़ला पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

उन्हें द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज, भारत से मेघनाद साहा मेमोरियल लेक्चर अवार्ड (2007) से सम्मानित किया गया।

उन्हें पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 2022 में राज्य के सर्वोच्च पुरस्कार 'बंगबिभूषण' और 2022 में 'रवींद्र स्मृति पुरस्कार' से भी सम्मानित किया गया था।

सिन्हा को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए 2010 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

उन्हें 2001 में पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया था।

पद्मश्री वैज्ञानिक मंचनहल्ली रंगास्वामी सत्यनारायण राव का निधन

एक प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिक और पद्म श्री पुरस्कार विजेता मंचनहल्ली रंगास्वामी सत्यनारायण राव, जिन्हें एमआरएस राव के नाम से जाना जाता है, का बेंगलुरु, कर्नाटक में निधन हो गया।

एमआरएस राव के बारे में:

एमआरएस राव का जन्म 21 जनवरी, 1948 को मैसूर, कर्नाटक में हुआ था।

वह भारत में क्रोमैटिन जीवविज्ञान अनुसंधान शुरू करने वाले पहले वैज्ञानिक थे।

वह जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च में मानद प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थे और संस्थान में सक्रिय रूप से क्रोमैटिन जीवविज्ञान प्रयोगशाला चला रहे थे।

2003-2013 तक वह बैंगलोर, भारत में जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च (JNCASR) के अध्यक्ष थे।

पुरस्कार एवं सम्मान:

उन्हें 2010 में विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, पद्म श्री से सम्मानित किया गया था।

विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा सर एमवी विश्वेश्वरैया पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था।

जिम्बाब्वे क्रिकेट के दिग्गज हीथ स्ट्रीक का 49 वर्ष की उम्र में निधन

जिम्बाब्वे के क्रिकेट आइकन हीथ स्ट्रीक का कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद 49 वर्ष की आयु में निधन हो गया है

हीथ स्ट्रीक के बारे में:

हीथ स्ट्रीक, एक बहुमुखी क्रिकेटर, जिन्होंने न केवल राष्ट्रीय टीम की कप्तानी की, बल्कि बांग्लादेश की पुरुष राष्ट्रीय क्रिकेट टीम को भी कोचिंग दी, ने महत्वाकांक्षी क्रिकेटरों, विशेषकर अपनी मातृभूमि से आने वाले क्रिकेटरों पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा है।

उनका करियर राजनीतिक अशांति के दौर के साथ मेल खाता था जिसने जिम्बाब्वे में खेल को गहराई से प्रभावित किया।

गायक राजू पंजाबी का 40 साल की उम्र में निधन, सीएम खट्टर ने कहा हरियाणवी संगीत उद्योग के लिए 'अपूरणीय क्षति'

मशहूर हरियाणवी गायक राजू पंजाबी (40 वर्ष) का पीलिया से जूझने के बाद हिसार के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया।

राजू पंजाबी के बारे में:

राजू पंजाबी एक जाने-माने हरियाणवी गायक और संगीतकार थे।

वह 'देसी देसी ना बोलया कर', 'सॉलिड बॉडी', 'सेंडेल' और 'अच्छा लगे से' जैसे गानों के लिए जाने जाते थे।

वह हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में काफी लोकप्रिय थे।

उन्हें अपने प्रशंसकों द्वारा प्यार से "धुनों का राजा" कहा जाता था।

विश्व के सबसे प्रतिष्ठित सांख्यिकीविद् कैल्यामपुडी राधाकृष्ण राव का निधन

एक प्रतिष्ठित भारतीय-अमेरिकी गणितज्ञ और सांख्यिकीविद् कैलीमपुडी राधाकृष्ण राव, जिन्हें आमतौर पर सीआर राव के नाम से जाना जाता है, का 102 वर्ष की आयु में निधन हो गया।

डॉ. सीआर राव के बारे में:

डॉ. सीआर राव का जन्म 10 सितंबर, 1920 को भारत के वर्तमान कर्नाटक राज्य के एक शहर हदगली में हुआ था।

डॉ. राव ने कई मौलिक सांख्यिकीय अवधारणाओं जैसे कि क्रैमर-राव असमानता और राव-ब्लैकवेलाइज़ेशन की शुरुआत की, ये अवधारणाएँ सांख्यिकी और अर्थमिति पर स्नातक पाठ्यपुस्तकों में दिखाई देती हैं।
उन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान (ISI) में अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
उन्होंने कई प्रतिष्ठित संगठनों के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, जिनमें द इंडियन इकोनोमेट्रिक सोसाइटी (TIES), इंटरनेशनल बायोमेट्रिक सोसाइटी (IBS), गणितीय सांख्यिकी संस्थान (IMS), और इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट (ISI) शामिल हैं।
उन्होंने सांख्यिकी समिति (1962-69) के अध्यक्ष, जनसंख्या नियंत्रण के लिए जनसांख्यिकीय और संचार (1968-69) के अध्यक्ष, गणित पर समिति के अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा आयोग, एईसी (1969-78), विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति के सदस्य, कॉस्ट (1969-71) के रूप में कार्य किया।
अमेरिकन स्टैटिस्टिकल एसोसिएशन ने उन्हें एक "जीवित किंवदंती" के रूप में सम्मानित किया, जिनके काम ने अर्थशास्त्र, आनुवंशिकी, मानव विज्ञान, जनसांख्यिकी और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों को प्रभावित किया।
वह इंडियन हार्ट एसोसिएशन गैर-लाभकारी संगठन के लिए एक वरिष्ठ नीति और सांख्यिकी सलाहकार भी थे, जो दक्षिण एशियाई कार्डियोवैस्कुलर रोग जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित थे।

उल्लेखनीय कार्य:

सीआर राव ने सांख्यिकी और गणित में विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करते हुए 14 किताबें और लगभग 350 शोध पत्र लिखे।

पुरस्कार एवं सम्मान:

2023 में, उन्हें सांख्यिकी में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसे अक्सर "सांख्यिकी" नोबेल पुरस्कार के समकक्ष कहा जाता है।
उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, प्रतिष्ठित पद्म भूषण (1969) और पद्म विभूषण (2001) पुरस्कार प्राप्त हुए।
वह नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज (USA) के फेलो बन गए और उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार, नेशनल मेडल ऑफ साइंस प्राप्त हुआ।
संयुक्त गणित संस्थान और उसके अनुप्रयोगों ने उन्हें सांख्यिकीय डिजाइन सिद्धांत में उनकी विशेषज्ञता के लिए मानद सदस्य के रूप में मान्यता दी।

दिग्गज बॉलीवुड गीतकार देव कोहली का निधन हो गया

प्रसिद्ध गीतकार और कवि देव कोहली का 80 वर्ष की आयु में मुंबई, महाराष्ट्र में निधन हो गया।

देव कोहली के बारे में:

देव कोहली का जन्म 2 नवंबर 1942 को रावलपिंडी, पाकिस्तान में हुआ था।
शंकर-जयकिशन से लेकर विशाल-शेखर तक, उन्होंने 1969 से 2013 तक के करियर में विभिन्न पीढ़ियों के संगीतकारों के साथ काम किया।
उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में सैकड़ों गाने लिखे और कई हिट गाने लिखे जैसे माये नी माये, ये काली काली आंखें, गीत गाता हूं, ओ साकी साकी आदि।
देव कोहली ने 'मैंने प्यार किया', 'बाजीगर', 'जुड़वा 2', 'मुसाफिर', 'शूट आउट एट लोखंडवाला' और 'टैक्सी नंबर 911' जैसी 100 से अधिक हिट फिल्मों के लिए गाने लिखे।
उन्होंने अनु मलिक, राम लक्ष्मण, आनंद राज आनंद, आनंद मिलिंद और अन्य जैसे संगीत निर्देशकों के साथ कई हिट फिल्मों में भी काम किया।

उन्होंने आखिरी बार कंगना रनौत-स्टारर रज्जो के लिए गाने लिखे थे, जिसमें उत्तम सिंह का संगीत था।

वैगनर प्रमुख येवगेनी प्रिगोझिन की विमान दुर्घटना में मौत

जून में रूस के सैन्य नेतृत्व के खिलाफ एक संक्षिप्त सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने वाले भाड़े के नेता येवगेनी प्रिगोझिन एक विमान दुर्घटना में मारे गए थे।
23 अगस्त, 2023 को मॉस्को के उत्तरी क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान में प्रिगोझिन समेत 10 यात्री सवार थे।
मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग जा रहा एक विमान टवर क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 3 पायलटों सहित सभी यात्रियों की मौत हो गई।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, भाड़े के समूह वैगनर के कमांडर और समूह के संस्थापकों में से एक दिमित्री उत्किन भी इस घटना में मारे गए।
तकनीकी खराबी से लेकर विमान में विस्फोट तक की आशंका जताई जा रही है.
राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सत्ता में आने के बाद से इसे शासन के खिलाफ सबसे बड़ी चुनौती माना गया।

अंग्रेजी कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कवि जयंत महापात्रा का निधन हो गया

प्रसिद्ध ओडिशा में जन्मे अंग्रेजी कवि और 1981 में अंग्रेजी कविता के लिए साहित्य अकादमी (भारत में चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान) पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कवि का 95 वर्ष की आयु में कटक, ओडिशा में निधन हो गया।

जयंत महापात्रा के बारे में:

जयंत महापात्रा का जन्म 22 अक्टूबर 1928 को कटक, ओडिशा में हुआ था।
उन्होंने अंग्रेजी में भारतीय लेखन पर केंद्रित एक वार्षिक साहित्यिक पत्रिका 'चंद्रभागा' के संपादक के रूप में कार्य किया।

उल्लेखनीय कार्य:

वह "इंडियन समर" और "हंगर" जैसी कविताओं के लेखक हैं, जिन्हें आधुनिक भारतीय अंग्रेजी साहित्य में क्लासिक्स माना जाता है।
कवि की गद्य की प्रकाशित कृतियों में 'ग्रीन गार्डेनर' और 'डोर ऑफ पेपर: निबंध और संस्मरण' की सूची शामिल है।
उन्होंने कविताओं पर 27 किताबें लिखीं, जिनमें से सात उड़िया में और बाकी अंग्रेजी में हैं।

पुरस्कार एवं सम्मान:

उन्हें साहित्य और शिक्षा के लिए 2009 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म श्री से सम्मानित किया गया था।
उन्हें दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) साहित्यिक पुरस्कार, नई दिल्ली, 2009 मिला।
उन्हें द सेवानी रिव्यू से 2009 के लिए एलन टेट पोएट्री प्राइज से भी सम्मानित किया गया था।